Forum PCS

UPPSC PRELIMS

QRS QUICK REVISION SERIES

Last-Minute Revision Notes

समसामयिकी

एवं UPPSC विशेष संस्करण

राजव्यवस्था • अर्थव्यवस्था • पर्यावरण • विज्ञान • उत्तर प्रदेश

01 राजव्यवस्था, शासन एवं न्यायपालिका
02 अंतर्राष्ट्रीय समाचार
03 अर्थव्यवस्था
04 पर्यावरण
05 भूगोल
06 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
07 संस्कृति एवं पर्यटन
08 खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व, रिपोर्ट
09 उत्तर प्रदेश विशेष
10 स्मरणीय तिथियाँ
11 255 MCQ उत्तर कुंजी सहित

अवधि: 1 दिसंबर 2025 – 16 अक्तूबर 2026

अनुक्रमणिका

त्वरित पुनरावृत्ति बिंदु (QRP)..... 15

राजव्यवस्था, शासन एवं न्यायपालिका..... 15
अंतरराष्ट्रीय समाचार..... 30
अर्थव्यवस्था..... 39
पर्यावरण..... 51
भूगोल..... 54
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी..... 57
संस्कृति एवं पर्यटन..... 62
खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व, पुस्तकें एवं रिपोर्ट..... 64
उत्तर प्रदेश विशेष..... 68

1. राजव्यवस्था, शासन एवं न्यायपालिका..... 72

परिसीमन और दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ..... 72
प्रगति प्लेटफ़ॉर्म की 50वीं बैठक पूरी..... 72
रोमियो-जूलियट खंड और पॉक्सो अधिनियम..... 72
लैंड स्टैक, पंखुड़ी और ईसीआईनेट की शुरुआत..... 73
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया..... 73
16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2026-31)..... 73
NDMA ने पहली आपदा पीड़ित पहचान SOP जारी की..... 75
PAC ने संकल्प योजना के कमजोर क्रियान्वयन को रेखांकित किया..... 75
अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मासिक धर्म स्वच्छता..... 75
उच्च न्यायपालिका में विविधता लाने हेतु विधेयक..... 76
क्या ED अनुसूचित-भिन्न अपराधों के लिए संपत्ति कुर्क कर सकता है?..... 76
खेल शासन: बिंद्रा टास्क फोर्स, राष्ट्रीय खेल बोर्ड और ट्रिब्यूनल नियम..... 77
चार धाम मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की योजना..... 78
प्रहार: भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी रणनीति..... 78
फ्रंटियर नगालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण समझौता..... 78
भारत का मानसिक स्वास्थ्य बोझ और बजट की प्रतिक्रिया..... 78
भारत में विकेंद्रीकरण और ग्रामीण रूपांतरण..... 79
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए..... 79
मुफ्त सौगात संस्कृति पर सर्वोच्च न्यायालय..... 80
लैंगिक बजट का हिस्सा बढ़कर 9.37 प्रतिशत हुआ..... 80
लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव..... 80
वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम-II और सीमा प्रौद्योगिकी..... 81
विमुक्त जनजातियों की जनगणना में अलग कॉलम की माँग..... 81
शहरीकरण और बजट 2026-27 के शहरी उपाय..... 81
समाचारों में संसदीय और चुनावी अवधारणाएँ..... 82
सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप-मेटा डेटा साझाकरण पर सवाल उठाए..... 82
सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक रूढ़िवादिता पुस्तिका पर पुनर्विचार कर रहा है..... 82
CEC नियुक्ति अधिनियम: मुख्य न्यायाधीश का अलग होना और बड़ी पीठ को संदर्भ..... 83
IVFRT योजना 2031 तक बढ़ाई गई..... 83
उच्चतम न्यायालय का निर्देश: कोविड टीके से हुई क्षति के लिए बिना-दोष मुआवज़ा..... 83
उच्चतम न्यायालय का महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश..... 84
उच्चतम न्यायालय ने दत्तक माताओं को भी सवेतन मातृत्व अवकाश दिया..... 84
उच्चतम न्यायालय: धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त..... 84
कुकी और हमार समूहों के साथ असम शांति समझौता..... 85
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026..... 85
क्या न्यायालय व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं: शरीयत अधिनियम याचिका..... 85
गिलोटिन और अनुदान की माँगें 2026-27..... 85
ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति मिली..... 86
नक्सल-मुक्त भारत: घोषणा और राज्य..... 86
भारत-म्यांमार सीमा: बाड़बंदी और मुक्त आवागमन व्यवस्था..... 86
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का पहला नोटिस..... 87
रक्षा बल विज़न 2047 जारी..... 87
सर्वोच्च न्यायालय का अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर परीक्षण पर निर्णय..... 87
हरीश राणा मामला: कॉमन कॉज़ के अंतर्गत पहली निष्क्रिय इच्छामृत्यु..... 88
25% कोटे पर RTE धारा 12(1)(c) का निर्णय..... 88
CBI अभय, प्रॉक्सी सरपंच अभियान और सेवा तीर्थ..... 88
FCRA संशोधन विधेयक और नियम, 2026..... 89
NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया..... 89
अनुच्छेद 142 के अंतर्गत राजमार्ग सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश..... 89
अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अधिसूचित..... 90
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2026..... 90
खाप पंचायत के फरमानों पर राजस्थान उच्च न्यायालय..... 90
गृह मंत्रालय ने LWE प्रभावित जिलों का पुनर्वर्गीकरण किया..... 91
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026..... 91
दल-बदल विरोधी कानून और AAP राज्य सभा विलय विवाद..... 91
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का त्यागपत्र और न्यायाधीशों का महाभियोग..... 91
पहलगाम के एक वर्ष बाद: आतंकवाद-रोधी रणनीति में बदलाव..... 92
पोषण अभियान: पोषण मिशन के आठ वर्ष..... 92
संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 और लोक सभा का विस्तार..... 92
सत्तानकुलम हिरासत में मौतों पर फैसला..... 93
NSO का 80वाँ चक्र स्वास्थ्य सर्वेक्षण..... 93
UAPA जमानत और के.ए. नजीब निर्णय..... 93
उच्चतम न्यायालय ने एसिड हमला पीड़ितों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया..... 94
केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पोर्टल और समाधान दीदी..... 94
त्रिशंकु विधानसभा की स्थितियों में राज्यपाल का विवेकाधिकार..... 94
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): चरण, फॉर्म 6 और निर्वाचन आयोग के कदम..... 94
मतदान से मतगणना तक EVM की यात्रा..... 95
राजद्रोह कानून: धारा 124A और BNS की धारा 152..... 95
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और NEET-UG 2026 का रद्द होना..... 96
वृद्धजन कल्याण: जीवन ऐप, शतायु और पेंशन अध्ययन..... 96
NEET-UG पुनः परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर प्रतिबंध..... 96
NeSDA 2025 और दिव्यांगजन अधिकारों पर COSP19..... 97
उच्च न्यायपालिका में लैंगिक कोटा पर बहस..... 97
उच्चतम न्यायालय का मानव-तस्करी विरोधी ढाँचा और पीड़ित संरक्षण योजना..... 97
उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता कहा..... 98
ऊपरी यमुना जल पर हरियाणा-राजस्थान समझौता..... 98
कावेरी और अन्य अंतर-राज्यीय जल मामले..... 98
जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति..... 99

ट्रॉमा केयर, PM राहत और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित राजमार्ग 99
तुंगभद्रा विवाद और अंतर-राज्यीय जल कानून 100
धर्मांतरित जनजातीय लोगों को ST सूची से हटाने पर बहस 100
नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक 100
न्यायालयों में AI के उपयोग पर मसौदा विनियम 101
पंचायत सुधारों के 12 वर्ष रिपोर्ट 101
पासपोर्ट, आधार और नागरिकता का प्रमाण 101
पीसीपीएनडीटी अधिनियम और पुत्र-प्राथमिकता: उच्चतम न्यायालय 101
पैदल चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में 102
ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की भारत से तुलना 102
भूल जाने का अधिकार: दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस 102
विदेशी विश्वविद्यालय परिसर: बेंगलुरु में लिवरपूल 103
BNSS की धारा 356 के अंतर्गत अनुपस्थिति में सुनवाई (ट्रायल इन एब्सेंशिया) 103
CCI विनियमों पर अधीनस्थ विधान समिति की रिपोर्ट 104
PM-AJAY को 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव 104
PM-विद्यालक्ष्मी का 1,425 संस्थानों तक विस्तार 104
UDISE+ 2025-26, PGI 2.0 और AISHE 104
असम में नागरिकता निर्धारण पर सर्वोच्च न्यायालय 105
उल्लास के अंतर्गत उत्तराखंड पूर्ण साक्षर 105
कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 और EPFO 3.0 106
केंद्र ने UAPA के अंतर्गत 23 और आतंकवादी नामित किए 106
ग्राम सभा में कम भागीदारी पर अध्ययन और महिला-नेतृत्व वाली पंचायतें 106
ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल और सामाजिक अंकेक्षण 107
नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2024 107
भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 100 करोड़ के पार 107
महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म और CBFC की न्यायिक समीक्षा 107
राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम लागू किए गए 108
राष्ट्रीय सम्मान संशोधन अधिनियम, 2026 और वंदे मातरम पर सर्वोच्च न्यायालय 108
विरोध प्रदर्शन का अधिकार और BNSS की धारा 163 109
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन अधिनियम, 2026 109
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर और अत्याचार नियम सुधार 110
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विद्यालय में हिजाब की याचिका खारिज की 110
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 110
गोरखालैंड: स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए समिति 111
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 111
दिशा 2.0: प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय तक पहुँच 111
न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग 112
पुलिस हिरासत और FIR तक पहुँच पर सर्वोच्च न्यायालय 112
बीसीआई-नालसार नामांकन विवाद और बीसीआई की शक्तियाँ 112
भारतीय न्यायपालिका का डिजिटल रूपांतरण और ई-कोर्ट्स 113
भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 113
भूमिका ट्रस्ट वाद: न्यायिक सेवा के लिए बार प्रैक्टिस 114
मानसून सत्र 2026 में संसद की उत्पादकता 114
मिशन समृद्ध गाँव और नशा मुक्त युवा अभियान 114
लाइवस्ट्रीम की गई न्यायालयी कार्यवाही: हर्षिता ग्रोवर आदेश 115
विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंज़ूरी 115
संसद के अधिनियम द्वारा केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया 115
सर्वोच्च न्यायालय ने फाँसी को मृत्युदंड के तरीके के रूप में बरकरार रखा 115
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 को लिव-इन साझेदारों तक विस्तारित किया 116
अनुच्छेद 124(3) और प्रतिष्ठित विधिवेत्ता की नियुक्ति 116
अनुच्छेद 142 और जेन ज़ी प्रदर्शन मामलों को रद्द करना 116
ईवीएम टोटलाइज़र और उच्चतम न्यायालय का नोटिस 117
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में संशोधन 117
काम का अधिकार और वीबी-जी राम जी अधिनियम 117
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के नए फ़िल्म प्रमाणन दिशानिर्देश 117
केंद्रीय सतर्कता आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2025 के निष्कर्ष 118
गिरफ़्तारी के आधार और पुनः गिरफ़्तारी पर उच्चतम न्यायालय 118
ग्राम सभा की सहमति और वन मंज़ूरी विवाद 118
जनगणना 2027: जाति गणना के साथ भारत की पहली डिजिटल जनगणना 119
नाबालिगों के सोशल मीडिया खाते और संविदात्मक क्षमता 119
निर्वाचन आयोग (ECI) के समक्ष TMC के नाम और चुनाव चिह्न का विवाद 120
पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और चंदा 120
मणिपुर की 1951 को आधार वर्ष मानकर एनआरसी की माँग 120
मातृत्व अवकाश और कार्य-भूमिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय 120
मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन दस्तावेज 2026-29 और नशा मुक्त भारत 121
लद्दाख: पर्वतीय परिषदें और प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) 121
शुद्धिकरण अनुष्ठान और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता 122
हिंदी दिवस और मुंशी-अयंगर फ़ॉर्मूला 122

2. अंतरराष्ट्रीय समाचार 123

2026 के लिए UNSC सदस्य और IMO परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन 123
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की वापसी 123
अमेरिका और नाटो के बीच ग्रीनलैंड विवाद 123
तृतीय पथ सिद्धांत और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 123
दिल्ली में उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक जारी 124
भारत का मुक्त व्यापार समझौता नेटवर्क 124
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न 124
भारत-विश्व बैंक देश साझेदारी ढाँचा 2026-31 125
यूएई, जर्मनी और वाइमर त्रिकोण के साथ भारत की भागीदारी 125
यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र शुरू 126
वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले: ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व 126
वैश्विक न्यूनतम कर पर OECD साइड-बाय-साइड पैकेज 126
AI इम्पैक्ट समिट 2026 और नई दिल्ली घोषणा 127
BNP की जीत और भारत-बांग्लादेश संबंध 127
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने IEEPA शुल्कों पर अंकुश लगाया 127
आर्कटिक सेंट्री और समाचारों में संघर्ष क्षेत्र 128
इज़राइल-अमेरिका के ईरान पर हमले और भारत का रुख 128
गाज़ा के लिए शांति बोर्ड 128
न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति 128
प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा 129
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढाँचा और भारत-GCC FTA 129
भारत-इज़राइल विशेष रणनीतिक साझेदारी 129
भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक साझेदारी 130
भारत-ब्राज़ील दुर्लभ मृदा समझौता और व्यापार लक्ष्य 130
वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार 130
समुद्री मंच और महत्वपूर्ण खनिज पहलें 131
सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 131
अमेरिका-इज़राइल-ईरान संघर्ष: खामेनेई मारे गए, खाड़ी की ऊर्जा पर प्रहार 131
ईरान की सत्ता संरचना और वेलायत-ए-फकीह 131

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा....132
डिजिटलीकरण और सततता में भारत-फिनलैंड सामरिक साझेदारी....132
प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत: पड़ोसियों को ईंधन और सहायता....132
बालेन्द्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली....133
भारत के विरुद्ध अमेरिकी धारा 301 जाँचें....133
याउंडे में WTO की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (MC14) बिना सहमति के समाप्त....133
संयुक्त राष्ट्र महासभा का दास व्यापार प्रस्ताव और अरब लीग के नए प्रमुख....133
BRICS 2026: भारत की अध्यक्षता, अध्यक्ष का सार-कथन और सदस्यता....134
UAE का OPEC और OPEC+ से बाहर निकलना....134
अमेरिका-ईरान दो सप्ताह का युद्धविराम और भारत पर प्रभाव....134
ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा....135
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत यात्रा....135
श्रीलंका में OCI छठी पीढ़ी तक विस्तारित....135
ट्रंप-शी बीजिंग शिखर सम्मेलन 2026....135
नीदरलैंड में मोदी: चोल ताम्रपत्र लौटाए गए....136
प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा और 5 अरब डॉलर का निवेश....136
प्रोजेक्ट फ्रीडम और होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट....136
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और SAI शिखर सम्मेलन....137
भारत-इटली विशेष सामरिक साझेदारी....137
भारत-वियतनाम उन्नत व्यापक सामरिक साझेदारी....137
भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी....138
रूस-चीन संबंध और पुतिन की बीजिंग यात्रा....138
लिपुलेख दर्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा विवाद....138
संयुक्त राष्ट्र महासचिव चुनाव 2026....138
स्ट्रोक पर विश्व स्वास्थ्य सभा का संकल्प....138
स्वीडन, नॉर्वे में मोदी और भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन....139
हिंद महासागर संवाद और IORA....139
IMEC, CPEC 2.0 और चर्चित क्षेत्र....139
एवियन में 52वाँ G7 शिखर सम्मेलन और भारत की साझेदारी भूमिका....140
कृषि पर ब्रिक्स इंदौर घोषणा-पत्र....140
गाज़ा पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट....141
तीस्ता परियोजना पर चीन-बांग्लादेश वार्ता....141
नई दिल्ली में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक....141
पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने वाला अमेरिका-ईरान ज्ञापन....142
पीओके में विरोध प्रदर्शन और आरक्षित सीटों का विवाद....142
प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स की राजकीय यात्रा....143
भारत-ओमान CEPA लागू हुआ....143
भारत-फ्रांस नीस शिखर सम्मेलन और नवाचार रोडमैप 2030....143
भारत-स्लोवाकिया व्यापक साझेदारी....144
महत्वपूर्ण खनिज: भारत-अमेरिका ढाँचा, भारत-यूके वेधशाला....144
म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा....144
वैश्विक शांति सूचकांक 2026 और मानवाधिकार गठबंधन....145
16वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन....145
59वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक, ARF और EAS....146
अमेरिका-इज़राइल-लेबनान त्रिपक्षीय रूपरेखा....146
अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में चाबहार बंदरगाह....146
अवसर के महासागर के रूप में हिंद महासागर....147
एक्ट ईस्ट नीति और आसियान केंद्रीयता....147
ऑपरेशन अमिस्ताद और भारत-वेनेज़ुएला संबंध....147
नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन....148
पैक्स सिलिका और हिंद-प्रशांत महासागर पहल....148
प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा....148
भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ....149
भारत-ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन और यूरेनियम समझौता....149
भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी और 2030 तक का रोडमैप....149
भारत-ब्रिटेन CETA लागू हुआ....150
मनीला में क्वाड विदेश मंत्री और बिम्सटेक NSA बैठक....150
मादक पदार्थ तस्करी पर ब्रिक्स गुवाहाटी घोषणा....150
विश्व संक्षेप में: कंबोडिया में UPI, ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया प्रतिबंध और अन्य....151
अगस्त 2026 में भारत की द्विपक्षीय गतिविधियाँ....151
भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठकें....151
भारत-उज़्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी....152
भारत-चीन 25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता....152
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता....152
होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा....152
18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और नई दिल्ली घोषणा....153
26वाँ SCO शिखर सम्मेलन और बिश्केक घोषणा....153
अमेरिका का रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम, 2026....153
पाकिस्तान-चीन सीमा समझौता और शक्सगाम घाटी....154
पीएनएस हुनैन की भारतीय युद्धपोत से टक्कर....154
बेल्जियम के प्रधानमंत्री की यात्रा और भारत-बेल्जियम रक्षा संबंध....154
ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दी....155
भारत की विदेशी सैन्य और सामरिक उपस्थिति....155
राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा और रक्षा समझौता ज्ञापन....155
संयुक्त राष्ट्र ने इक्वल अर्थ मानचित्र प्रस्ताव अपनाया....155
सिंधु जल संधि पर हेग न्यायालय का निर्णय....155
सम्मेलन, शिखर सम्मेलन और बैठकें 2025-26: वर्षवार सूची....156
सैन्य अभ्यास 2025-26: संपूर्ण वर्षवार सूची....159

3. अर्थव्यवस्था....162

RB-IOS 2026: जुलाई से एकीकृत लोकपाल योजना....162
RBI ने PSL मानदंड संशोधित किए; बैंकों की NPA कई दशकों के निचले स्तर पर....162
किफायती आवास पर नीति आयोग का ढाँचा....162
कोकिंग कोयला महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज घोषित....163
त्रि-वर्षीय PPP परियोजना पाइपलाइन....163
निर्यात तैयारी सूचकांक 2024....164
निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत ऋण-संबद्ध उप-योजनाएँ....164
बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025....165
भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना....165
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा 5.0 और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 5.0....165
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का एफडीआई प्रवाह....166
सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: APY, NPS वात्सल्य, PM स्वनिधि....166
अनाज भंडारण और PACS का विस्तार....167
आधार वर्ष 2022-23 के साथ भारत की नई GDP श्रृंखला....167
आधार वर्ष 2024 के साथ नई CPI श्रृंखला....167
केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी....168
केंद्रीय बजट 2026-27: राजकोषीय आँकड़े और तीन कर्तव्य....168
गिग श्रमिक और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था....168
दुर्लभ मृदा गलियारे और रसायन पार्क....169
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति....169
बजट 2026-27 के अंतर्गत चैंपियन MSME....169

बजट 2026-27: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव 169
बजट 2026-27: विनिर्माण, MSME और अवसंरचना संबंधी उपाय 170
बजट 2026-27: सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और पर्यटन संबंधी घोषणाएँ 171
बायोफार्मा शक्ति मिशन 171
भारत में कारोबार सुगमता सुधार 172
महिला श्रम बल भागीदारी और लखपति दीदी 172
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 172
वस्त्र, पूंजीगत वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक 173
सीएजी की राज्य वित्त रिपोर्ट 2023-24 173
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास के लिए एमएसपी सहायता हेतु ₹1,718.56 करोड़ को मंजूरी दी 173
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 173
एनएमडीसी का लौह अयस्क रिकॉर्ड और एनआईआईएफ का दूसरा कोष 174
नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 174
पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत चावल का पोषक-संवर्धन (फोर्टिफिकेशन) निलंबित 174
प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश और एलपीजी की कमी 175
भव्य (BHAVYA): 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क 175
राहत (RELIEF) योजना, लघु जलविद्युत योजना और पीएम ई-ड्राइव में संशोधन 175
आईएमएफ के आउटलुक में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना 175
आयकर अधिनियम, 2025 लागू हुआ 176
आरबीआई के मसौदा मानदंड: डिजिटल धोखाधड़ी, बीसी, फंसे हुए ऋण 176
ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 और नवीकरणीय क्षमता 176
टाटा धोलेरा फैब एसईजेड और सेमीकंडक्टर एसईजेड 177
दस वर्ष का स्टार्टअप इंडिया: मान्यता, फंड ऑफ फंड्स 2.0 और डीप-टेक मानदंड 177
पीएमजीएसवाई-III का विस्तार और नई मंत्रिमंडलीय अवसंरचना मंजूरियाँ 178
SRS बुलेटिन 2024: जन्म, मृत्यु और शिशु मृत्यु दरें 178
आरबीआई द्वारा स्वर्ण वापसी 2025-26 179
ईसीएलजीएस 5.0 ऋण गारंटी योजना 179
खरीफ MSP 2026-27: 14 फसलें अधिसूचित 179
गन्ना एफआरपी 2026-27 और चीनी निर्यात प्रतिबंध 180
तृतीय अग्रिम अनुमान 2025-26: खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर 180
थूथुकुडी मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड 180
दक्षिण तट रेलवे जोन अधिसूचित 181
पुडुचेरी एसईजेड, एनपीएस सुनिश्चित भुगतान पैनल और केरल की गरीबी संबंधी उपलब्धि 181
भगोड़े आर्थिक अपराधी: ईडी के आँकड़े 181
वाडिनार जहाज मरम्मत सुविधा और कपास उत्पादकता मिशन 181
सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना 182
समुद्री खाद्य निर्यात के लिए यूरोपीय संघ की सूची में भारत बरकरार 182
सेबी का PaRRVA और आरबीआई की Q-SAFE समिति 182
2025-26 के लिए GDP के अनंतिम अनुमान 183
RBI और वित्त मंत्रालय के उपाय संक्षेप में 183
अल नीनो जोखिम के बीच खरीफ की तैयारी 183
असम-नगालैंड तेल और गैस अन्वेषण समझौता ज्ञापन 183
आधार वर्ष 2022-23 के साथ नई IIP और WPI श्रृंखला 184
एआरसी और बैंक ऋण बिक्री पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता 184
कृषि-खाद्य योजनाएँ: SARTHAK-PDS, बीज भंडार, स्मार्ट वेयरहाउसिंग 185
कोयला एक्सचेंज नियम 2026 185
डिजिटल धोखाधड़ी के लिए RBI का क्षतिपूर्ति ढाँचा 185
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम 2026 और संहिता का एक दशक 185
पर्यटन रिपोर्ट और सरकारी योजनाएँ 186
पीएसी ने पीएमकेवीवाई में कमियों को उजागर किया 186
भारत का मध्यम वर्ग और घरेलू ऋण 186
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 187
रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 187
लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और जहाज पुनर्चक्रण 187
विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जी-सेक सुधार 188
विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 188
विश्व बैंक, हुरुन यूनिकॉर्न और मत्स्य पालन रिपोर्टें 189
सीएजी राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25 189
ISP और संशोधित कोर उद्योग सूचकांक जारी 189
LokOS, SHE-LEAPS और लखपति दीदी लक्ष्य 190
MSMED (संशोधन) अधिनियम 2026 190
NIIF के लिए अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ 190
PMKSY के दस वर्ष पूरे 191
SDG राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा प्रगति रिपोर्ट 2026 191
SOFI 2026: खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 191
नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक 192
प्लेटफ़ॉर्म कार्य पर ILO अभिसमय 193 192
भारत WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते में शामिल 192
भारत दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता 192
मसालों के लिए कोडेक्स मानक और मिशन गोल्डन स्पाइस 193
मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंज़ूरी 193
यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति 2026 193
रासायनिक पार्कों के लिए भव्य-रसायन योजना 194
विश्व बैंक आय वर्गीकरण वित्त वर्ष 2027 194
संशोधित उड़ान (Modified UDAN) को 2026-36 के लिए मंजूरी 194
संसदीय समिति की PDS आधुनिकीकरण रिपोर्ट 194
सहकारिता मंत्रालय के पाँच वर्ष 195
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति में परिवर्तन 195
सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (सेमीकॉन 2.0) अधिसूचित 195
PMJDY के 12 वर्ष पूरे 196
UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 196
आईआईएचटी सूत्र 2026: हथकरघा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 196
उद्योग और सहकारिता के लिए योजनाएँ और अधिनियम 196
कौशल, AI और विकास पर रिपोर्टें 197
खान और खनिज संशोधन अधिनियम, 2026 और धारा 9D 197
गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना 197
ग्रामोद्यम, मखाना निर्यात और अन्य आर्थिक पहलें 198
बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 198
बैंकिंग कवरेज, CBDC DBT और ई-श्रम 198
भारत में आय गतिशीलता, 2014-2025 199
भूमि-सीमावर्ती देशों के लिए FDI ढाँचा (प्रेस नोट 3) 199
व्यावसायिक सेवाओं के विनियमन पर नीति आयोग की रिपोर्ट 199
समुद्र मंथन: राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना 200
₹10 और ₹20 के लिए पॉलीमर बैंकनोट 200
EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की गई 200
FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर 201
FCNR(B) स्वैप विंडो और रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार 201

GeM के सार्वजनिक खरीद के 10 वर्ष पूरे 201
JCR ने भारत की संप्रभु रेटिंग को A- में उन्नत किया....201
UPI के दस वर्ष पूरे....201
अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI की VRRR नीलामियाँ....202
अरबपति सूचियाँ 2026: फॉर्च्यून, फोर्ब्स और हुरुन....202
कांडला में भारत का पहला ग्रीन (ई-)मेथनॉल संयंत्र....202
क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध FIU-IND की कार्रवाई 203
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 3.0 203
डिजिटल गिग श्रमिक शिकायत प्रणाली, मोबाइल फूड लैब और मृदा कार्बन भुगतान 203
तैरती सौर ऊर्जा के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना 204
भारत का पहला ब्लू बॉन्ड और सागरमाला फाइनेंस....204
भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 204
भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता....204
भारतीय रेलवे में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का प्रवेश....205
वैश्विक बॉन्ड बिकवाली और बढ़ती प्रतिफल दरें....205
वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 2026 205
57वीं GST परिषद बैठक....206
ADB वित्तपोषण: चेन्नई जल, ग्रीन अमोनिया और विकास अनुमान 206
IDBI बैंक की फेयरफैक्स से जुड़े खरीदार को रणनीतिक बिक्री....207
NSAP जारी रहेगा और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया....207
RBI मौद्रिक नीति अक्टूबर 2026: रेपो दर बढ़ाकर 5.50%....207
आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2026 207
पारादीप मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित; ITLA को मंजूरी....208
पीजीआई-डी 2024-25: जिला विद्यालय प्रदर्शन 208
बैंकिंग अपडेट: RBI डेटा सेंटर, फिनो SFB और बैंक ऑफ बड़ौदा NPS 209
महिला रोज़गार और उद्यम के आँकड़े....209
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2026 209

4. पर्यावरण 211

BBNJ उच्च सागर संधि लागू हुई 211
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026....211
विस्तारित कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के लक्ष्य....211
हिमालय में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)....212
CCUS और हरित अमोनिया: भारत का विकार्बनीकरण अभियान 212
पूर्वोत्तर भारत में वनाग्नि और ऑपरेशन वालोंग 213
संक्षेप में पर्यावरण: मछुआरा बिल्ली, बीकॉरिडोर और अन्य....213
सर्वोच्च न्यायालय ने नदी प्रदूषण मामला बंद किया....213
2031-2035 के लिए भारत के अद्यतन NDC 214
पर्यावरणीय संस्थाएँ: आवरण, भवसागर, NH हरित आवरण सूचकांक....214
प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट और CMS COP15....214
भारत की नागोया प्रोटोकॉल रिपोर्ट और सातवीं CBD राष्ट्रीय रिपोर्ट....214
सर्वोच्च न्यायालय ने चंबल में रेत खनन पर स्वतः संज्ञान लिया....215
सुखना आर्द्रभूमि: चंडीगढ़ का पहला रामसर स्थल 215
जम्मू-कश्मीर की लुप्त होती झीलों पर CAG रिपोर्ट....215
दिल्ली वायु प्रदूषण शमन योजना, 2026....215
भारत COP33 की मेज़बानी से पीछे हटा....216
भूजल प्रबंधन पर लोक लेखा समिति (PAC) की 41वीं रिपोर्ट 216
चर्चा में प्रजातियाँ: बिल्ली, कछुआ, बगुला, व्हेल....216
चर्चा में प्रजातियाँ और समुद्री संरक्षण....216
तैरता सौर, कोयला गैसीकरण और स्वच्छ ऊर्जा समाचार 217
बॉन SB64 जलवायु लक्ष्य और मीथेन पर कार्रवाई का आह्वान....217
भारत के 103 रामसर स्थल: राज्यवार मानचित्र और तथ्य 218
भारत में पहुँच और लाभ साझाकरण ढाँचा....219
वैश्विक रसायन निगरानी कार्यक्रम शुरू 219
सौज झील (मैनपुरी): उत्तर प्रदेश का 14वाँ रामसर स्थल....220
CAFE-III मानदंडों का मसौदा....220
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और E20 पर बहस....220
चर्चा में हिमालयी पैंगोलिन और मालवी ऊँट....221
थार में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्थिति....221
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 221
पश्चिमी घाट में प्रस्तावित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 221
पुगा घाटी में भारत के पहले भूतापीय कुएँ 222
बाघों के सक्रिय प्रबंधन हेतु रोड मैप जारी....222
बोरजुली आर्द्रभूमि जैव विविधता विरासत स्थल बनी....222
भारतीय कार्बन बाजार और उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 222
राज्य मूल्यांकन निकायों के लिए EIA अधिसूचना में संशोधन....223
UNCCD COP17 में घास के मैदानों की मार्गदर्शिका और संबंधित संरक्षण समाचार 223
आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व के लिए 10 किमी का खनन बफ़र....223
गंगा बाढ़ मैदान: प्रतिबंध की जगह त्रि-स्तरीय क्षेत्र-निर्धारण....223
ग्लॉ झील: भारत का 101वाँ रामसर स्थल 224
FAO की वानिकी समिति (COFO 28) में भारत....224
NCR के लिए पराली जलाने पर सख़्त नियम प्रस्तावित 224
UNEP की सीमित ओवरशूट रिपोर्ट 2026 225
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और ओडिशा का ओरांगउटान....225
विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति रिपोर्ट 225
IBCA: सऊदी अरब, घाना और बांग्लादेश शामिल हुए....225
पर्यावरण पहलें: वनजीवी दीदी और हरित दिवाली....226

5. भूगोल 227

जलमार्ग और बंदरगाह: वाराणसी, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और कामराजर में पहली उपलब्धियाँ....227
शक्सगाम घाटी और डिएगो गार्सिया 227
ग्रेट निकोबार मेगा अवसंरचना परियोजना....227
थ्वाइट्स ग्लेशियर: प्रलय का ग्लेशियर....228
प्रौद्योगिकी और उद्योग में पहली उपलब्धियाँ: चिप, बैटरी और AI सुविधाएँ....228
भारत की अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली 228
समाचारों में स्थान: राष्ट्रीय स्थल....229
समाचारों में खाड़ी स्थल और जलडमरूमध्य 229
समाचारों में राष्ट्रीय स्थान....230
समाचारों में स्थान: होकरसर, पचपदरा, लोअर लेक और अन्य....230
किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध और चिनाब परियोजनाएँ....231
मानसून में विराम और सुपर अल नीनो की आशंकाएँ....231
वेनेज़ुएला भूकंपीय युग्म (डबलेट)....232
कृषि, निर्यात और स्वास्थ्य में स्थान-वार पहली उपलब्धियाँ....232
पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े चर्चित स्थान 2025-26....232
ब्रह्मपुत्र महाबाँध के नीचे पाइझेन भ्रंश....233
विरासत और संस्कृति से जुड़े चर्चित स्थान: संग्रहालय, स्मारक और नाम परिवर्तन....233
समाचारों में महत्वपूर्ण स्थान: मोंगला, सबांग, मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया....233
समाचारों में स्थान: अंतरराष्ट्रीय....234
समाचारों में स्थान: राष्ट्रीय 234

स्लीमनाबाद सुरंग और नर्मदा नदी....235
कोलंबिया भूकंप और ज़ांस्कर हिमनदों की धीमी गति....235
चर्चित स्थान: अगस्त 2026....235
लांगटांग हिमनद का ध्वस्त होना और नेपाल की अचानक बाढ़ें....235
राष्ट्रीय चर्चित स्थान: त्सो कर, बखिरा और अन्य....236
लटकते हिमनद और उत्तराखंड की GLOF पूर्व चेतावनी प्रणाली....236
अंतरराष्ट्रीय चर्चित स्थान: कुरील द्वीपसमूह, लेबनान, कैलिफ़ोर्निया और अन्य....236
समाचारों में लद्दाख: नए जिले, उच्च न्यायालय पीठ और सीमावर्ती गाँव....237

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी....238

DRDO ने पूर्ण-स्तरीय स्क्रैमजेट इंजन का भू-परीक्षण किया....238
PSLV-C62 विसंगति और भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल....238
भारत का रक्षा उद्योग: उत्पादन, निर्यात, सुधार....238
समाचारों में रक्षा प्रणालियाँ: प्रलय, LR-AShM, सूर्यास्त्र....239
सैन्य क्वांटम मिशन नीति रूपरेखा....239
AI सामग्री लेबलिंग और 3 घंटे में हटाने के नियम....240
DRDO ने ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट का प्रदर्शन किया....240
INS अंजदीप और सैन्य अभ्यास....240
LIGO-इंडिया और लद्दाख दूरबीनें....240
चंद्रयान-4 अवतरण क्षेत्र: मॉन्स मूटन....240
भारत का संप्रभु AI पारितंत्र: भारत जेनएआई, सर्वम, वॉइसेरा और इंडिया AI स्टैक....241
स्वास्थ्य विज्ञान समाचार: राज्य सूक्ष्मजीव और अंगदान....241
LPG के विकल्प के रूप में डाइमिथाइल ईथर....241
अंतरिक्ष संक्षेप: DART, क्षुद्रग्रह 2024 YR4 और आकाशा300....241
आंतरिक सुरक्षा में AI और डिजिटल अरेस्ट ठगी....242
महासागर प्रौद्योगिकी संक्षेप: डार्क ऑक्सीजन, LTTD और फ़्लोटिंग लिडार....242
INS अरिधमान: तीसरी SSBN सेवा में शामिल....242
IOS सागर और भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा रणनीति 2026....242
आर्टेमिस II: चालक दल सहित चंद्र फ्लाईबाई पूरी हुई....243
जैव-विनिर्माण के लिए BioE3 नीति....243
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली क्रांतिकता प्राप्त की....243
भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ पर पहुँचा....244
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन: क्वांटम वैली और 1,000 किमी नेटवर्क....244
विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपलब्धियाँ: कुष्ठ रोग, ट्रेकोमा, मलेरिया और अमेरिका का बाहर निकलना....244
DRDO के परीक्षण: तारा (TARA), NASM-SR और ULPGM-V3....244
ICMR और ICAR का मिशन सेहत (SEHAT)....245
अंतरिक्ष विज्ञान: स्माइल (SMILE), साइकी और चंद्रयान-3 हॉप....245
ऑपरेशन सिंदूर का एक वर्ष: रक्षा प्राथमिकताएँ....245
गैलेक्सआई का दृष्टि और प्रोजेक्ट गरुड़....246
पाकिस्तान ने पहली हंगोर-श्रेणी की पनडुब्बी शामिल की....246
बच्चों में मधुमेह संबंधी दिशानिर्देश और जननी (JANANI) प्लेटफ़ॉर्म....246
भारत सेमीकंडक्टर मिशन: गुजरात में दो और इकाइयों को मंज़ूरी....246
मिशन मौसम: C-ART, स्काईकास्ट, ब्लॉक मानसून पूर्वानुमान....247
रक्षा अपडेट: नए CDS, आईएनएस महेंद्रगिरि और अभ्यास....247
रोग प्रकोप: इबोला PHEIC, हंटावायरस, CDV और बेबेसिया....248
स्वास्थ्य विज्ञान: उम्मीद (UMMID), इंडियाAI-ICMR समझौता ज्ञापन और PMOS....248
DRDO के बहु-स्तरीय BMD और NASM-MR परीक्षण....248
SIPRI ईयरबुक 2026 के निष्कर्ष....248
नौसेना के तीन पोतों का एक साथ कमीशन और चौथी S-400 स्क्वाड्रन....249
भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएँ: प्रमुख योजनाएँ....249
भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहन और E100....249
रक्षा प्रौद्योगिकी: नेत्र FOC, ब्रह्मोस, रुद्रएम-II, LRLACM....250
विज्ञान अपडेट: सिंथेटिक बायोलॉजी, IMI सरसों, स्काईकास्ट, JWST....250
विश्व की सबसे बड़ी BESS और हाइड्रोजन संबंधी घटनाक्रम....250
सेमीकंडक्टर के लिए नीति आयोग का रोडमैप....250
2035 तक जैव-अर्थव्यवस्था के लिए नीति आयोग का रोडमैप....251
BFSI के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26....251
DRDO ने कुशा लंबी दूरी की SAM का परीक्षण किया....251
GAGAN के माध्यम से भारत की पहली उपग्रह-आधारित लैंडिंग....252
INS महेंद्रगिरि और INS मालवण कमीशन किए गए....252
ISRO का SOLVE मोटर परीक्षण....252
WAICO और AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन....252
अंतरिक्ष क्षेत्र: IN-SPACe का पुनः-प्रवेश नियम और पुनरुपयोगी रॉकेट....253
आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए नीति आयोग का रोडमैप....253
कलपक्कम में नाभिकीय प्रक्रिया ऊष्मा हाइड्रोजन सुविधा....253
क्यूडेंगा, ज़ायनिच और कोशिका-जीन थेरेपी नियम....254
डेंगू टीके को मंज़ूरी, निजी टर्बोफैन और क्वांटम चिप....254
पिनाका LRGR, अस्त्र और नौसेना अभ्यास....254
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन....255
विक्रम-1: भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट....255
संशोधित एनीमिया मुक्त भारत और SUMAN रोडमैप 2030....255
इसरो को नासा का मून बेस निमंत्रण....255
जीसैट-1ए और इसरो की उड़ान में वापसी....256
निजी अंतरिक्ष उपलब्धियाँ: एवरेस्ट और पावरबैंक-50....256
भारत से विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार....256
रक्षा खरीद और स्वदेशीकरण संबंधी अद्यतन....256
आईएनएस निपुण और डाइविंग सपोर्ट वेसल....257
एआई-जनित कृतियों और लेखकत्व पर कॉपीराइट कार्यालय....257
ऑस्ट्रेल बेसिन: चंद्रमा का छिपा प्रभाव बेसिन....257
तृष्णा मिशन और सागर मंथन अनुसंधान पोत....258
दूरसंचार विभाग का वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक....258
राष्ट्रीय औषधि संग्रह (नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया) का 7वाँ संस्करण और जैव-सतर्कता कार्यक्रम....258
रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर आईसीएमआर का अध्ययन....258
वैध माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026....259

7. संस्कृति एवं पर्यटन....260

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और भद्रकाली अभिलेख....260
2026-2029 के लिए घोषित संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वर्ष....260
देवनीमोरी अवशेष, ओल चिकी शताब्दी समारोह और बस्तर पंडुम....260
भारत के राष्ट्रीय दिवस: तिथियाँ और विषय....260
भारत जीआई, मिस्र में तमिल ब्राह्मी और ओल चिकी....261
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल: एक नज़र में....262
चपचार कुट और तिरुमंगई आळवार की प्रतिमा की वापसी....262
विश्व दिवस जनवरी-मार्च 2026: तिथियाँ और विषय....262
पिपरहवा अवशेष और कपिलवस्तु....263
भारत की शैलकृत गुफाएँ....264
चर्चा में जीआई-टैग वाले उत्पाद: पीलीभीत बाँसुरी से सेलम साबूदाना तक....264
रू-सोम बेंत पुल, अलगोज़ा और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व....265
उदंत मार्तंड, ह्वेनसांग और सांस्कृतिक पुरस्कार....265
ज्ञान भारतम मिशन और पांडुलिपि सर्वेक्षण....265

झारखंड के 11 नए जीआई टैग 265
राखीगढ़ी उत्खनन के निष्कर्ष 266
विश्व दिवस अप्रैल-जून 2026: तिथियाँ और विषय 266
हड़प्पाई कलाकृतियाँ और नर्तकी की मूर्ति 267
जोधपुर मोजड़ी और हिमाचल के उत्पादों को जीआई टैग 268
देवरिया ताल से हड़प्पा के पतन पर पराग अध्ययन 268
समरस्य संकल्प अभियान: संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष 268
प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेख 268
विश्व दिवस जून-अगस्त 2026: तिथियाँ और विषय 269
समाचारों में स्वतंत्रता सेनानी और बौद्ध विरासत 270
नामे डोगरा अक्खर लिपि का पुनरुद्धार 270
शेखावाटी हवेलियाँ यूनेस्को की संभावित सूची में 270
कला प्रदर्शनी और साक्षरता पुरस्कार 2026 271
विश्व दिवस सितंबर-दिसंबर 2026: तिथियाँ और विषय 271

8. खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व, पुस्तकें एवं रिपोर्ट 273

56वाँ IFFI गोवा और अन्य फ़िल्म महोत्सव सम्मान 273
नए लोगो: MoSPI और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 273
पद्म पुरस्कार 2026 और वीरता पुरस्कार 273
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 और डेफलिम्पिक्स 2025 274
वैश्विक रिपोर्टें: GEP, ILO ट्रेंड्स और UNCTAD इन्वेस्टमेंट मॉनिटर 274
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 और यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 274
ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 और बूंग के लिए बाफ्टा 275
भारत में मृत्युदंड: वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट 275
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 और पावर गैप इंडेक्स 275
सी. राजगोपालाचारी: राष्ट्रपति भवन में प्रतिमा 275
आईसीसी प्रतियोगिताएँ 2025-26: टी20 विश्व कप, अंडर-19 और महिला विश्व कप 276
ऑस्कर 2026 (98वाँ अकादमी पुरस्कार) 276
खाद्य सुरक्षा सूचकांक और मार्च 2026 की अन्य रिपोर्टें 276
खेल पुरस्कार 2025-26: नमन, हॉकी इंडिया, लॉरियस, फीफा, विजडन, एफपीएआई 277
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और IOC पात्रता नीति 277
पुस्तकें और लेखक: संस्मरण और राजनीतिक जीवनियाँ 277
मार्च 2026 में नियुक्त राज्यपाल और उपराज्यपाल 278
वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन 278
साहित्य पुरस्कार 2025: ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी 278
चंद्रशेखर शताब्दी का आरंभ; भारत ट्राइब्स फेस्ट; ब्रेकथ्रू पुरस्कार 279
पुस्तकें और लेखक: राजनीति, शासन और रक्षा 279
NCRB की भारत में अपराध 2024 और ADSI रिपोर्ट 280
नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष 2025-26 280
पर्यावरण एवं विज्ञान पुरस्कार 2026 281
पुस्तकें और लेखक: कथा-साहित्य, अध्यात्म और अन्य कृतियाँ 281
भारत के शतरंज ग्रैंडमास्टर 2026 और युवा उपलब्धिधारी 282
भारत में जेल सांख्यिकी 2024 282
भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025 282
भारतीय फुटबॉल 2025-26: आईएसएल, आईएफएल, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी 283
यूरोपीय और विश्व फुटबॉल 2025-26: यूएफा कप और फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 283
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 283
स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट 284
AB-PMJAY ने राष्ट्रव्यापी कवरेज हासिल किया 284
NFHS-6: प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य के निष्कर्ष 284
PMSMA के 10 वर्ष, डिजिटल स्वास्थ्य और NHA अनुमान 285
QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 285
अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियाँ: कॉर्पोरेट, सुरक्षा और वैश्विक निकाय 285
क्रिकेट लीग और घरेलू 2026: आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, एशिया कप, दलीप ट्रॉफी 286
खेल श्रद्धांजलि 2026: रणधीर सिंह, जसपाल राणा और अन्य 286
छात्र मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा पर पैनल की रिपोर्टें 287
बिमल पटेल ITLOS के न्यायाधीश निर्वाचित; विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष 287
भारत और क्षेत्र में एशियाई आयोजन 2026: फेंसिंग, ब्रिज, सांडा, बीच गेम्स 287
मुक्केबाजी 2025-26: वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, फ्यूचर्स कप और एशियाई चैंपियनशिप 288
विस्थापन पर UNHCR की वैश्विक प्रवृत्ति रिपोर्ट (ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट) 288
सेना प्रमुख की नियुक्ति और NDA की महिला अधिकारी 288
23वें राष्ट्रमंडल खेल, ग्लासगो 2026 288
72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 288
ICC ने मॉरीशस को 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया 289
UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट और WIPO अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026 289
फीफा विश्व कप 2026 के कीर्तिमान और मेसी का संन्यास 289
फीफा विश्व कप 2026: स्पेन बना चैंपियन 289
फील्ड्स मेडल 2026 के विजेता 290
भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय GDP के 0.8 प्रतिशत के पार 290
भारतीय खेल उपलब्धिधारी 2026 290
शूटिंग विश्व कप 2025-26 291
समुद्र प्रदक्षिणा: त्रि-सेवा महिला परिक्रमा 291
साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार 2026 291
2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 291
80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 पर शौर्य पुरस्कार 292
अन्य टेनिस 2026: मास्टर्स, डेविस कप और भारतीय आयोजन 292
एथलेटिक्स 2026: U20 विश्व चैंपियनशिप, एशियाई U23, एशियाई रिले और 24 घंटे की दौड़ 292
कुश्ती 2026: U20 विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप और पीडब्ल्यूएल 293
भारोत्तोलन, राष्ट्रमंडल फेंसिंग और विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 293
राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष: 2026 के बदलाव 294
विज्ञान पुरस्कार 2025 294
शतरंज प्रतियोगिताएँ 2025-26: परिणाम तालिका 294
समाचारों में भारतीय हस्तियाँ: सम्मान, प्रथम और कीर्तिमान 294
स्कैश 2025-26: विश्व कप और अन्य आयोजन 295
हॉकी 2025-26: विश्व कप, प्रो लीग और अन्य प्रतियोगिताएँ 295
PMRBP 2025, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और शासन पुरस्कार 296
V-Dem लोकतंत्र रिपोर्ट 2026 और भारत 296
गोल्डन ग्लोब, ग्रैमी, बाफ्टा और एमी 2026 296
टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026: युगल और मिश्रित युगल 297
टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026: विजेता तालिका 297
टेबल टेनिस 2026: डब्ल्यूटीटी श्रृंखला और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 297
तीरंदाजी 2026: विश्व कप चरण, फाइनल और एशिया कप 298
दादासाहेब फाल्के 2024, तेनज़िंग नोर्गे पुरस्कार और तीरंदाज़ी में स्वर्ण 298
बैडमिंटन 2025-26: टूर्नामेंट विजेता 298
भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्तियाँ 2026 299
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 के विजेता 299
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026: भारत की स्थिति 299

शतरंज 2025-26: विश्व कप, कैंडिडेट्स और ओलंपियाड 300
सिविल सेवा और अर्थव्यवस्था संबंधी नियुक्तियाँ 2025-26....300
सौंदर्य प्रतियोगिताएँ 2025-26....300
अंतरराष्ट्रीय श्रद्धांजलि 2025-26 301
आगामी प्रमुख खेल आयोजन और मेज़बान....301
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 और 2025 301
एशियाई खेल 2026 में भारत: रिकॉर्ड और स्वर्ण पदक विजेता....302
एशियाई खेल 2026: आइची-नागोया....302
प्रधानमंत्री मोदी: सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित सरकार प्रमुख और विदेशी सम्मान....302
प्रमुख मैराथन 2026: विजेता 303
भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान 2026....303
रक्षा और सुरक्षा प्रमुखों की नियुक्तियाँ 2026 304
श्रद्धांजलि 2025-26: कला, साहित्य और सार्वजनिक जीवन 304
संवैधानिक और वैधानिक नियुक्तियाँ 2025-26 305

9. उत्तर प्रदेश विशेष....306

2026 में शिक्षा और कौशल विकास में उत्तर प्रदेश के प्रथम....306
उत्तर प्रदेश दिवस 2026: गौरव सम्मान और एक जनपद-एक व्यंजन....306
उत्तर प्रदेश में खेल आयोजन: वॉलीबॉल, सांसद खेल महाकुंभ, विश्व मुक्केबाजी कप, एवरेस्ट साइक्लिंग....306
दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में 'सोलर ऑन ट्रैक' 307
पटना पक्षी विहार और छारी-ढांड रामसर स्थल बने....307
पद्म श्री 2026 और अन्य सम्मानों में उत्तर प्रदेश....307
पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित....307
फिरोजाबाद काँच संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक परियोजनाएँ....308
लखनऊ में राज भवन का नाम बदलकर जन भवन किया गया....308
लखनऊ: उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताज़ा कचरा डंप शहर 308
वाराणसी में भारत की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी....308
उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: क्षेत्रक और अवसंरचना....308
उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: समष्टि चित्र 309
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: प्रमुख आँकड़े 309
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग में दहेज संबंधी निर्देश....310
एनजीटी ने सुआव को नदी के रूप में बहाल करने का आदेश दिया....310
नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम....310
बजट 2026-27: उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजनाएँ....311
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और कृषि के प्रथम: एआई क्लिनिक, बासमती फार्म, बरेली हवाई अड्डा....311
कालिंजर किले की पहाड़ियाँ राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित....311
निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर सांसद निधि कार्य: 84% निधि उत्तर प्रदेश को....311
निवेश मित्र 3.0 और औद्योगिक योजनाएँ....311
उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी संशोधन, 2026 312
गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन....312
नवयुग पालिका योजना 312
नोएडा के फैक्ट्री श्रमिकों के प्रदर्शन और वेतन असंतोष 313
शेखा झील रामसर स्थल घोषित; उत्तर प्रदेश में अब 12....313
उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर: पीएम सूर्य घर में अग्रणी....313
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ और प्रकृति ज्ञान धाम....313
लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग और शहरी अग्नि जोखिम....313
लखनऊ: गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर और ईट राइट एयरपोर्ट....314
सुरहा ताल: भारत का 100वाँ रामसर स्थल 314
उत्तर प्रदेश की सामाजिक कल्याण योजनाएँ: पीएमएमवीवाई, विधवा पेंशन, शिक्षक कैशलेस योजना....314
उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पुलिसिंग: प्रतिबिंब और ऑपरेशन साइ-वज्र....315
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और स्टार्टअप खरीद योजना....315
कौशल सेतु, कौशल सारथी और कौशल संपर्क 315
डिजी रोवर भूमि सर्वेक्षण और प्रोजेक्ट गंगा....316
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना....316
राम मंदिर दान प्रबंधन और बार का बहिष्कार....316
लखनऊ में भारत का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग....316
उत्तर प्रदेश में रक्षा: एके-203 शेर, ड्रोन हब और अग्निवीर आरक्षण....317
परिछा बैराज को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता....317
बुलंदशहर मामले से पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पर निर्णय 317
लखनऊ के आयोजन: नौसेना शौर्य वाटिका और ब्रिक्स सांख्यिकी बैठक 317
सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित....318
उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में अग्रणी; विजिट माई स्टेट और नीम करोली सर्किट....318
लखनऊ में रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण 318
9 अक्टूबर 2026 के उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय: खरीद और माफी 319
UP AI मिशन (UP-AIM) और लखनऊ AI सिटी....319
भदोही: इंडिया कार्पेट एक्सपो और नाम परिवर्तन योजना....320
वाराणसी में भारतीय वायुसेना का विंग्स ओवर गंगा एयर शो 320
सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति, 2026 320

255 समसामयिकी MCQ एवं उत्तर कुंजी....321

Q.R.P.

त्वरित पुनरावृत्ति बिंदु

राजव्यवस्था एवं शासन

- भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? (जनवरी 2026)
  – चार (1952, 1963, 1973, 2002)
- प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का उपबंध किन अनुच्छेदों में है? (जनवरी 2026)
  – अनुच्छेद 82 और 170
- 2022 के जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने कितनी विधानसभा सीटें बनाईं? (जनवरी 2026)
  – 90 (43 जम्मू, 47 कश्मीर)
- प्रगति को किस वर्ष शुरू किया गया था? (जनवरी 2026)
  – 2015
- प्रगति समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? (जनवरी 2026)
  – प्रधानमंत्री
- 1994 में स्वीकृत कौन-सा रेल संपर्क प्रगति के प्रयास से 2025 में खोला गया? (जनवरी 2026)
  – जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल संपर्क
- रोमियो-जूलियट खंड के संबंध में किस अधिनियम पर चर्चा हुई? (जनवरी 2026)
  – पॉक्सो अधिनियम
- रोमियो-जूलियट खंड का उद्देश्य किसकी रक्षा करना है? (जनवरी 2026)
  – कम आयु अंतर वाले सहमति-आधारित किशोर संबंध
- लैंड स्टैक किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया? (जनवरी 2026)
  – DILRMP
- पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया? (जनवरी 2026)
  – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- ईसीआईनेट किस सम्मेलन में शुरू किया गया? (जनवरी 2026)
  – IICDEM 2026
- VBSA विधेयक, 2025 का आधार संघ सूची की कौन-सी प्रविष्टि है? (जनवरी 2026)
  – प्रविष्टि 66
- VBSA विधेयक किन तीन अधिनियमों को निरस्त करता है? (जनवरी 2026)
  – यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई अधिनियम
- VBSA विधेयक किस समिति को भेजा गया? (जनवरी 2026)
  – संयुक्त संसदीय समिति
- क्या VBSA संस्थानों के वित्तपोषण को नियंत्रित करता है? (जनवरी 2026)
  – नहीं
- 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल का कितना हिस्सा राज्यों को दिया? (फरवरी 2026)
  – 41 प्रतिशत
- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? (फरवरी 2026)
  – डॉ. अरविंद पनगढ़िया
- कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद आयोग की सलाह पर राज्यों को सहायता अनुदान का प्रावधान करता है? (फरवरी 2026)
  – अनुच्छेद 275
- 16वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि क्या है? (फरवरी 2026)
  – 2026-27 से 2030-31
- 16वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए जनसंख्या वृद्धि की कौन-सी अवधि प्रयुक्त की गई है? (फरवरी 2026)
  – 1971 से 2011
- किस मानदंड ने कर प्रयास पैमाने का स्थान लिया? (फरवरी 2026)
  – GDP में योगदान
- करों का विभाज्य पूल किस अनुच्छेद के अंतर्गत साझा किया जाता है? (फरवरी 2026)
  – अनुच्छेद 270
- 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल सहायता अनुदान कितना है? (फरवरी 2026)
  – ₹9.47 लाख करोड़
- राष्ट्रीय आपदा का दर्जा देने के लिए कौन-से दो संकट अनुशंसित किए गए हैं? (फरवरी 2026)
  – लू (ताप लहरें) और आकाशीय बिजली
- आपदा निधियों के लिए हिमालयी राज्यों पर केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण कितना लागू होता है? (फरवरी 2026)
  – 90:10
- विभाज्य पूल का कितना हिस्सा राज्यों को जाता है? (फरवरी 2026)
  – 41 प्रतिशत
- किस मानदंड का भारांश सबसे अधिक है? (फरवरी 2026)
  – आय अंतर (42.5%)
- वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? (फरवरी 2026)
  – अनुच्छेद 280
- किस निकाय ने भारत के पहले DVI दिशानिर्देश जारी किए? (फरवरी 2026)
  – NDMA
- दंत पहचान में सहायता के लिए कौन-सी रजिस्ट्री प्रस्तावित है? (फरवरी 2026)
  – राष्ट्रीय दंत डेटा रजिस्ट्री

➤ DVI दिशानिर्देशों के अंतर्गत तीन प्राथमिक पहचानकर्ताओं के नाम बताइए। (फरवरी 2026)

– अंगुलियों के निशान, दंत अभिलेख, DNA

➤ कौन-सा संस्थान संकल्प के लिए स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी है? (फरवरी 2026)

– IIM इंदौर

➤ संकल्प का कुल परिव्यय कितना है? (फरवरी 2026)

– ₹4,455 करोड़

➤ किस समिति ने संकल्प के क्रियान्वयन की आलोचना की? (फरवरी 2026)

– लोक लेखा समिति

➤ मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन के अधिकार का भाग माना गया? (फरवरी 2026)

– अनुच्छेद 21

➤ विद्यालय मासिक धर्म स्वच्छता नीति किन कक्षाओं के लिए लागू होती है? (फरवरी 2026)

– कक्षा 6 से 12

➤ शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुपालन न करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द की जा सकती है? (फरवरी 2026)

– धारा 19

➤ कौन-सा अनुच्छेद 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? (फरवरी 2026)

– अनुच्छेद 21ए

➤ कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित करता है? (फरवरी 2026)

– अनुच्छेद 130

➤ किस विधि आयोग रिपोर्ट ने कैसेशन पीठों की अनुशंसा की थी? (फरवरी 2026)

– 229वीं रिपोर्ट (2009)

➤ विधेयक के अनुसार केंद्र को कॉलेजियम के नाम कब तक अधिसूचित करने होंगे? (फरवरी 2026)

– 90 दिन

➤ किस सर्वोच्च न्यायालय मामले ने 2022 में PMLA के प्रमुख प्रावधानों को वैध ठहराया? (फरवरी 2026)

– विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ

➤ PMLA की धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति को कितने दिनों के लिए अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है? (फरवरी 2026)

– 180 दिन

➤ NDPS-संबंधित धन शोधन के लिए धारा 4 के अंतर्गत अधिकतम दंड क्या है? (फरवरी 2026)

– 10 वर्ष

➤ खेल प्रशासकों की क्षमता निर्माण पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? (फरवरी 2026)

– अभिनव बिंद्रा

➤ राष्ट्रीय खेल निकाय नियम, 2026 किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए? (फरवरी 2026)

– राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025

➤ राष्ट्रीय खेल बोर्ड की खोज-सह-चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? (फरवरी 2026)

– कैबिनेट सचिव

➤ भारत के शीर्ष 10 खेल राष्ट्र बनने का लक्ष्य वर्ष क्या है? (फरवरी 2026)

– 2036

➤ राष्ट्रीय खेल बोर्ड के सदस्य? (फरवरी 2026)

– अध्यक्ष और दो सदस्य

➤ कौन-सा सिद्धांत तय करता है कि कोई प्रथा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संरक्षित है या नहीं? (फरवरी 2026)

– अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण

➤ इस बहस में 2018 के किस निर्णय का उल्लेख किया जाता है? (फरवरी 2026)

– सबरीमाला निर्णय

➤ कौन-सा अनुच्छेद आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? (फरवरी 2026)

– अनुच्छेद 19(1)(d)

➤ प्रहार के कितने स्तंभ हैं? (फरवरी 2026)

– सात

➤ कौन-सी एजेंसी नोडल राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी बल है? (फरवरी 2026)

– राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

➤ किस मंत्रालय ने प्रहार जारी किया? (फरवरी 2026)

– गृह मंत्रालय

➤ FNTA को कितने विषय हस्तांतरित किए गए हैं? (फरवरी 2026)

– 46

➤ कौन-सा अनुच्छेद नगालैंड को विशेष उपबंध प्रदान करता है? (फरवरी 2026)

– अनुच्छेद 371(क)

➤ समझौते में पूर्वी नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व कौन-सा संगठन करता है? (फरवरी 2026)

– ENPO

➤ टेली मानस हेल्पलाइन का नंबर क्या है? (फरवरी 2026)

– 14416

➤ दूसरा निमहांस कहाँ प्रस्तावित है? (फरवरी 2026)

– उत्तर भारत

➤ कौन-से दो संस्थान क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों में उन्नत किए जाने हैं? (फरवरी 2026)

– रांची और तेजपुर

➤ 1957 में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की? (फरवरी 2026)

– बलवंत राय मेहता समिति

➤ ग्यारहवीं अनुसूची में कितने कार्य सूचीबद्ध हैं? (फरवरी 2026)

– 29

➤ 2025 का ग्रामीण अधिनियम कितने दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है? (फरवरी 2026)

– 125 दिन

➤ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कौन-सी धारा लोक सेवक के विरुद्ध जाँच के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करती है? (फरवरी 2026)

– धारा 17ए

➤ धारा 17ए किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? (फरवरी 2026)
– भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018

➤ किस न्यायाधीश ने कहा कि धारा 17ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है? (फरवरी 2026)
– न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना

➤ भारत ने किस वर्ष UNCAC की पुष्टि की? (फरवरी 2026)
– 2011

➤ 2013 के किस मामले में किसी राज्य द्वारा रंगीन टीवी के वितरण को वैध ठहराया गया? (फरवरी 2026)
– एस. सुब्रमण्यम बालाजी मामला

➤ अधिनियम की कौन-सी धारा भ्रष्ट चुनावी आचरण के रूप में रिश्वतखोरी से संबंधित है? (फरवरी 2026)
– धारा 123, RPA 1951

➤ मुफ्त सौगात पर 2026 की टिप्पणियाँ किस मामले में की गईं? (फरवरी 2026)
– तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ

➤ भारत ने किस वर्ष से लैंगिक बजटिंग अपनाई है? (फरवरी 2026)
– 2004-05

➤ किसी योजना के आवंटन का कितना हिस्सा भाग ख के लिए अर्हता रखता है? (फरवरी 2026)
– कम से कम 30 प्रतिशत

➤ केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा अब कितना है? (फरवरी 2026)
– 9.37 प्रतिशत

➤ हटाने के प्रस्ताव को अनुमति देने के लिए न्यूनतम कितना समर्थन आवश्यक है? (फरवरी 2026)
– 50 सदस्य

➤ 1954 में अध्यक्ष को हटाने के पहले प्रस्ताव का सामना किसने किया? (फरवरी 2026)
– जी.वी. मावलंकर

➤ अध्यक्ष को हटाने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? (फरवरी 2026)
– तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत

➤ VVP-II की शुरुआत कहाँ की गई? (फरवरी 2026)
– असम

➤ VVP-II कितने बुनियादी ढाँचा विषयों को संतृप्त करता है? (फरवरी 2026)
– चार

➤ VVP-I कब शुरू किया गया था? (फरवरी 2026)
– 2023

➤ CIBMS के चरण II और III कितने किमी को कवर करते हैं? (फरवरी 2026)
– लगभग 1,955 किमी

➤ VVP-II की शुरुआत किस जिले में हुई? (फरवरी 2026)
– कछार, असम

➤ 1871 के किस अधिनियम ने कुछ जनजातियों को अपराधी घोषित किया था? (फरवरी 2026)
– 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम

➤ सीड (SEED) के अंतर्गत प्रति परिवार स्वास्थ्य कवर कितना है? (फरवरी 2026)
– ₹5 लाख

➤ सीड (SEED) योजना कौन-सा मंत्रालय चलाता है? (फरवरी 2026)
– सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

➤ पाँच वर्षों में प्रति नगर आर्थिक क्षेत्र कितनी राशि आवंटित की गई है? (फरवरी 2026)
– ₹5,000 करोड़

➤ जनगणना शहरी क्षेत्र के लिए कितने जनसंख्या घनत्व की अपेक्षा करती है? (फरवरी 2026)
– 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

➤ शहरी चुनौती कोष का आकार कितना है? (फरवरी 2026)
– ₹1 लाख करोड़

➤ 2013 के किस मामले से EVM पर NOTA आया? (फरवरी 2026)
– PUCL बनाम भारत संघ

➤ कौन-सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान करता है? (फरवरी 2026)
– अनुच्छेद 87(1)

➤ विधानसभा चुनावों में NOTA का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? (फरवरी 2026)
– छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली (2013)

➤ नवंबर 2024 में CCI ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया? (फरवरी 2026)
– ₹213.14 करोड़

➤ किस अधिकरण ने पाँच वर्ष के डेटा-साझाकरण प्रतिबंध को रद्द किया? (फरवरी 2026)
– राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT)

➤ 2023 का कौन-सा अधिनियम अब डेटा संरक्षण को नियंत्रित करता है? (फरवरी 2026)
– डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम

➤ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? (फरवरी 2026)
– भोपाल

➤ किस निर्णय ने टू-फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाया? (फरवरी 2026)
– स्टेट ऑफ झारखंड बनाम शैलेंद्र कुमार राय (2022)

➤ लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने संबंधी पुस्तिका किस वर्ष जारी की गई? (फरवरी 2026)
– 2023

➤ किस अधिनियम को चुनौती के कारण मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्वयं को अलग किया? (मार्च 2026)
– CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023

➤ कौन-सा सिद्धांत न्यायालय से तब मामले की सुनवाई की अपेक्षा करता है जब कोई अन्य मंच उपलब्ध न हो? (मार्च 2026)
– आवश्यकता का सिद्धांत

➤ कौन-सा अनुच्छेद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का नियमन करता है? (मार्च 2026)
– अनुच्छेद 324(5)

➤ हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के कितने सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? (मार्च 2026)
– 100

➤ अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की सिफारिश कौन करता है? (मार्च 2026)
– मुख्य निर्वाचन आयुक्त

➤ 2026-31 के लिए IVFRT का परिव्यय कितना है? (मार्च 2026)
– ₹1,800 करोड़

➤ IVFRT का संचालन कौन-सा मंत्रालय करता है? (मार्च 2026)
– गृह मंत्रालय

➤ बिना-दोष योजना में दावेदार को क्या सिद्ध करना होता है? (मार्च 2026)
– केवल कार्य-कारण

➤ कौन-सी समितियाँ टीके की प्रतिकूल घटनाओं को देखती हैं? (मार्च 2026)
– AEFI समितियाँ

➤ थल सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन अनिवार्य करने वाला 2020 का कौन-सा मामला था? (मार्च 2026)
– बबीता पुनिया मामला

➤ पेंशन का बकाया किस तिथि से देय है? (मार्च 2026)
– 1 जनवरी 2025

➤ निर्णय के बाद दत्तक माताओं के लिए सवेतन अवकाश के कितने सप्ताह हैं? (मार्च 2026)
– 12 सप्ताह

➤ पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश कितना है? (मार्च 2026)
– 15 दिन

➤ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में कौन-से धर्म शामिल हैं? (मार्च 2026)
– हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म

➤ कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? (मार्च 2026)
– अनुच्छेद 341

➤ कुकी और हमार परिषदों का मुख्यालय कहाँ होगा? (मार्च 2026)
– गुवाहाटी

➤ 2026 का विधेयक कितने CAPF को शामिल करता है? (मार्च 2026)
– पाँच

➤ विधेयक के अंतर्गत DG स्तर पर IPS प्रतिनियुक्ति का हिस्सा कितना है? (मार्च 2026)
– 100%

➤ विरासत के नियमों पर 1937 का कौन-सा अधिनियम चुनौती के अधीन है? (मार्च 2026)
– मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम

➤ याचिका में किस राज्य की UCC का उल्लेख किया गया है? (मार्च 2026)
– उत्तराखंड

➤ अनुदान की माँगों पर कौन-सा सदन मतदान करता है? (मार्च 2026)
– लोक सभा

➤ गिलोटिन कौन लागू करता है? (मार्च 2026)
– अध्यक्ष

➤ 2014 के किस निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी? (मार्च 2026)
– नालसा बनाम भारत संघ

➤ 2026 के संशोधन विधेयक के अंतर्गत प्रस्तावित चिकित्सा बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? (मार्च 2026)
– मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी

➤ विधेयक के अंतर्गत किसी बच्चे को ट्रांसजेंडर पहचान के लिए विवश करने पर क्या दंड है? (मार्च 2026)
– आजीवन कारावास और ₹5 लाख का जुर्माना

➤ माओवादी हिंसा समाप्त करने के लिए तय की गई समय-सीमा क्या थी? (मार्च 2026)
– 31 मार्च 2026

➤ छत्तीसगढ़ में माओवादियों का गढ़ कौन-सा क्षेत्र था? (मार्च 2026)
– बस्तर

➤ विदर्भ का कौन-सा गाँव महाराष्ट्र का पहला नेट-ज़ीरो गाँव बना? (मार्च 2026)
– बेला ग्राम (भंडारा)

➤ भारत-म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? (मार्च 2026)
– 1,643 किमी

➤ सीमा बाड़बंदी परियोजना की लागत कितनी है? (मार्च 2026)
– ₹31,000 करोड़

➤ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध नोटिस पर लोकसभा के कितने सांसदों ने हस्ताक्षर किए? (मार्च 2026)
– 130

➤ RP अधिनियम 1950 की कौन-सी धारा चुनाव कर्मचारियों को ECI में प्रतिनियुक्ति पर मानती है? (मार्च 2026)
– धारा 13CC

➤ नोटिस में नामित मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? (मार्च 2026)
– ज्ञानेश कुमार

➤ विज़न 2047 किस मुख्यालय ने तैयार किया? (मार्च 2026)
– एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय

➤ अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर परीक्षण पर 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का नाम बताइए। (मार्च 2026)
– भारत संघ बनाम रोहित नाथन

➤ क्रीमी लेयर निर्धारण को कौन-सा कार्यालय ज्ञापन नियंत्रित करता है? (मार्च 2026)
– 1993 का कार्यालय ज्ञापन

➤ क्या सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आय अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर का एकमात्र मानदंड है? (मार्च 2026)
– नहीं, यह स्थिति-आधारित है

➤ CANH का पूरा नाम क्या है? (मार्च 2026)
– क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन (नैदानिक रूप से सहायता प्राप्त पोषण और जलयोजन)

➤ गरिमा के साथ मरने के अधिकार का आधार कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद है? (मार्च 2026)
– अनुच्छेद 21

➤ RTE धारा 12(1)(c) के अंतर्गत सीटों का कितना अंश आरक्षित है? (अप्रैल 2026)
– 25%

➤ कौन-सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? (अप्रैल 2026)
– अनुच्छेद 21ए

➤ मई 2026 में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त हुआ? (अप्रैल 2026)

– सिक्किम

➤ NGO को विदेशी अंशदान को कौन-सा अधिनियम विनियमित करता है? (अप्रैल 2026)

– FCRA, 2010

➤ संपत्ति का अधिकार कौन-सा अनुच्छेद प्रदान करता है? (अप्रैल 2026)

– अनुच्छेद 300A

➤ NGO को विदेशी अंशदान कौन-सा अधिनियम नियंत्रित करता है? (अप्रैल 2026)

– FCRA, 2010

➤ 2020 के संशोधन ने प्रशासनिक व्यय की कौन-सी सीमा निर्धारित की? (अप्रैल 2026)

– 20 प्रतिशत

➤ निर्दिष्ट FCRA खाता कौन-सा बैंक रखता है? (अप्रैल 2026)

– भारतीय स्टेट बैंक

➤ उचित गतिविधि दर्शाने के लिए दो वर्षों में उपयोग किया जाने वाला न्यूनतम विदेशी अंशदान? (अप्रैल 2026)

– ₹10 लाख

➤ किस मामले में माना गया कि प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है? (अप्रैल 2026)

– रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977)

➤ UGC अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया? (अप्रैल 2026)

– धारा 3, UGC अधिनियम 1956

➤ NCERT के साथ कितनी घटक इकाइयाँ शामिल की गईं? (अप्रैल 2026)

– छह

➤ उच्चतम न्यायालय ने राजमार्ग सुरक्षा निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किए? (अप्रैल 2026)

– अनुच्छेद 142

➤ राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेंस और क्रेन के लिए अधिकतम अंतराल? (अप्रैल 2026)

– 75 किमी

➤ राजमार्ग निर्देशों को लागू करने की समय-सीमा? (अप्रैल 2026)

– 60 दिन

➤ अमरावती राजधानी कानून किस तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है? (अप्रैल 2026)

– 2 जून 2024

➤ किस अधिनियम ने अमरावती को स्थायी राजधानी बनाया? (अप्रैल 2026)

– आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026

➤ भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? (अप्रैल 2026)

– अपर सचिव, MeitY

➤ 2026 के ऑनलाइन गेमिंग नियम किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए? (अप्रैल 2026)

– PROG अधिनियम, 2025

➤ ई-स्पोर्ट्स के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अधिकतम वैधता कितनी है? (अप्रैल 2026)

– अधिकतम 10 वर्ष

➤ 2026 में किस उच्च न्यायालय ने खाप के फरमानों को असंवैधानिक घोषित किया? (अप्रैल 2026)

– राजस्थान उच्च न्यायालय

➤ सामाजिक बहिष्कार की किस प्रथा की आलोचना की गई? (अप्रैल 2026)

– हुक्का-पानी बंद

➤ कौन-से दो जिले LWE प्रभावित के रूप में वर्गीकृत हैं? (अप्रैल 2026)

– बीजापुर और पश्चिमी सिंहभूम

➤ जन विश्वास विधेयक 2026 कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करता है? (अप्रैल 2026)

– 79

➤ जन विश्वास अधिनियम 2023 ने कितने प्रावधानों में संशोधन किया? (अप्रैल 2026)

– 42 अधिनियमों में 183 प्रावधान

➤ संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून शामिल है? (अप्रैल 2026)

– दसवीं अनुसूची

➤ संरक्षित विलय के लिए विधायिका दल के कितने अंश का सहमत होना आवश्यक है? (अप्रैल 2026)

– दो-तिहाई

➤ राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? (अप्रैल 2026)

– राज्यसभा के सभापति

➤ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत त्यागपत्र देता है? (अप्रैल 2026)

– अनुच्छेद 217(1)(a)

➤ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा किस उच्च न्यायालय से थे? (अप्रैल 2026)

– इलाहाबाद उच्च न्यायालय

➤ किस ऑपरेशन में पहलगाम के हमलावरों को मार गिराया गया? (अप्रैल 2026)

– ऑपरेशन महादेव

➤ पहलगाम के बाद किस संधि को स्थगित किया गया? (अप्रैल 2026)

– सिंधु जल संधि

➤ पोषण अभियान किस तिथि को शुरू किया गया था? (अप्रैल 2026)

– 8 मार्च 2018

➤ PM पोषण किस योजना का पुनर्गठित रूप है? (अप्रैल 2026)

– मध्याह्न भोजन योजना

➤ पोषण के अंतर्गत वास्तविक समय की निगरानी के लिए किस ऐप/उपकरण का उपयोग होता है? (अप्रैल 2026)

– पोषण ट्रैकर

➤ 131वें संशोधन विधेयक में लोक सभा की अधिकतम कितनी संख्या का प्रस्ताव था? (अप्रैल 2026)

– 850 सदस्य

➤ लोक सभा में विधेयक पर मतदान का परिणाम क्या था? (अप्रैल 2026)

– 298 पक्ष में, 230 विपक्ष में

➤ किस संशोधन ने 1971 की जनगणना पर परिसीमन को स्थगित (फ्रीज़) किया? (अप्रैल 2026)

– 42वाँ संशोधन (1976)

➤ कौन-सा अधिनियम विधायिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है? (अप्रैल 2026)

– 106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023

➤ अंतरिम परिसीमन के लिए कौन-सी जनगणना प्रयुक्त होगी? (अप्रैल 2026)

– 2011 की जनगणना

➤ 'दुर्लभतम में दुर्लभ' सिद्धांत किस मामले से आया? (अप्रैल 2026)

– बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य

➤ किस संविधान पीठ के निर्णय ने निचली अदालतों को निश्चित अवधि के आजीवन कारावास से रोका है? (अप्रैल 2026)

– UoI बनाम वी. श्रीहरन (2015)

➤ NSO के 80वें दौर के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कितने परिवार शामिल थे? (मई 2026)

– 1.39 लाख

➤ सर्वेक्षण के अनुसार कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं? (मई 2026)

– 1.84 लाख से अधिक

➤ UAPA की कौन-सी धारा जमानत को प्रतिबंधित करती है? (मई 2026)

– धारा 43D(5)

➤ देरी के आधार पर UAPA जमानत की अनुमति देने वाला 2021 का कौन-सा मामला है? (मई 2026)

– भारत संघ बनाम के.ए. नजीब

➤ किस अधिनियम की एसिड हमले की परिभाषा का विस्तार किया गया? (मई 2026)

– RPwD अधिनियम, 2016

➤ BNS की कौन-सी धारा एसिड हमले से संबंधित है? (मई 2026)

– धारा 124

➤ CPO पोर्टल किस निकाय ने लॉन्च किया? (मई 2026)

– नीति आयोग

➤ समाधान दीदी किस भाषा प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करती है? (मई 2026)

– भाषिणी

➤ मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान कौन-सा अनुच्छेद करता है? (मई 2026)

– अनुच्छेद 164(1)

➤ दलों को आमंत्रित करने के वरीयता क्रम की अनुशंसा किन दो आयोगों ने की? (मई 2026)

– सरकारिया और पुंछी

➤ 2026 के तमिलनाडु चुनाव में TVK ने कितनी सीटें जीतीं? (मई 2026)

– 108

➤ SIR चरण II के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम सूची में मतदाता? (मई 2026)

– 13.39 करोड़

➤ SIR चरण II के बाद कुल मतदाता सूची? (मई 2026)

– 45.81 करोड़

➤ मतदाता सूचियों पर निर्वाचन आयोग की शक्ति का आधार कौन-सा अनुच्छेद है? (मई 2026)

– अनुच्छेद 324

➤ SIR चरण III किस तिथि से शुरू होता है? (मई 2026)

– 30 मई 2026

➤ क्या SIR के अंतर्गत आधार नागरिकता सिद्ध करता है? (मई 2026)

– नहीं, केवल पहचान

➤ नए मतदाता नामांकन के लिए कौन-सा फॉर्म प्रयोग होता है? (मई 2026)

– फॉर्म 6

➤ माता-पिता के SIR की आवश्यकता कहाँ से शुरू हुई? (मई 2026)

– बिहार SIR

➤ फॉर्म 6 किन नियमों के अंतर्गत निर्धारित है? (मई 2026)

– निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960

➤ निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए निर्वाचन आयोग के केंद्रीकृत डिजिटल मंच का क्या नाम है? (मई 2026)

– ECINet

➤ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अतिरिक्त अन्य दो निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? (मई 2026)

– सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी

➤ EVM के संचालन को कौन-सी ECI नियमावली नियंत्रित करती है? (मई 2026)

– EVM पर नियमावली, 2023

➤ मतदान से पहले EVM गोदामों का नियंत्रण कौन करता है? (मई 2026)

– जिला निर्वाचन अधिकारी

➤ BNS की कौन-सी धारा ने राजद्रोह का स्थान लिया? (मई 2026)

– धारा 152

➤ 1962 का कौन-सा मामला सीमाओं के साथ राजद्रोह को वैध ठहराता है? (मई 2026)

– केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य

➤ NTA किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है? (मई 2026)

– सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

➤ 2024 की किस समिति ने NTA सुधार प्रस्तावित किए? (मई 2026)

– राधाकृष्णन समिति

➤ जीवन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? (मई 2026)

– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

➤ केंद्र का NSAP पेंशन अंश कब से स्थिर है? (मई 2026)

– 2012

➤ टेलीग्राम को किस प्रावधान के अंतर्गत अवरुद्ध किया गया? (जून 2026)

– धारा 69A, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

➤ किस एजेंसी ने प्रतिबंध का अनुरोध किया? (जून 2026)

– राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

➤ टेलीग्राम का संदेश संपादन कब तक बंद रखा गया? (जून 2026)

– 30 जून 2026

➤ भारत ने UNCRPD का अनुसमर्थन कब किया? (जून 2026)

– अक्टूबर 2007

➤ RPwD अधिनियम, 2016 कितनी दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? (जून 2026)

– 21

➤ NeSDA का संचालन कौन-सी संस्था करती है? (जून 2026)

– DARPG

➤ बार से सीधे उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत की गई पहली महिला कौन थीं? (जून 2026)

– इंदु मल्होत्रा (2018)

➤ उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब महिलाएँ हैं? (जून 2026)

– 37 में से 2

➤ कौन-सा देश अपने संवैधानिक न्यायालय में प्रत्येक लिंग के एक-तिहाई न्यायाधीश अनिवार्य करता है? (जून 2026)

– बेल्जियम

➤ 2004 की तस्करी संबंधी जनहित याचिका किस गैर-सरकारी संगठन ने दायर की? (जून 2026)

– प्रज्वला

➤ कौन-सा अनुच्छेद तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? (जून 2026)

– अनुच्छेद 23(1)

➤ कौन-सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल तस्करी को परिभाषित करता है? (जून 2026)

– पालेर्मो प्रोटोकॉल

➤ पीड़ित संरक्षण योजना कब तक लागू रहेगी? (जून 2026)

– जब तक संसद कानून नहीं बना लेती

➤ AHTU का प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम रैंक क्या है? (जून 2026)

– पुलिस उपाधीक्षक

➤ किस मामले में गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता के रूप में मान्यता दी गई? (जून 2026)

– शीश राम बनाम सुरजीत

➤ गृहिणी के लिए निर्धारित न्यूनतम काल्पनिक मासिक मूल्य क्या है? (जून 2026)

– ₹30,000

➤ यह मूल्य किन दावों में लागू किया जाता है? (जून 2026)

– मोटर दुर्घटना प्रतिकर

➤ ऊपरी यमुना जल के एमओयू पर हस्ताक्षर कब हुए? (जून 2026)

– 12 मई 1994

➤ कौन-सा अनुच्छेद अंतर-राज्यीय जल विवादों से संबंधित है? (जून 2026)

– अनुच्छेद 262

➤ ऊपरी यमुना जल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस राज्य की है? (जून 2026)

– हरियाणा (47.82%)

➤ कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को राज्यों के बीच मूल विवादों की सुनवाई की अनुमति देता है? (जून 2026)

– अनुच्छेद 131

➤ 2018 के कावेरी निर्णय के बाद किस बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया गया? (जून 2026)

– कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड

➤ मुल्लापेरियार बाँध का संचालन कौन करता है? (जून 2026)

– तमिलनाडु

➤ जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? (जून 2026)

– न्यायमूर्ति पी. पी. नवलेकर

➤ समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत है? (जून 2026)

– गृह मंत्रालय

➤ 2025 के अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवेश पर अधिकतम कारावास कितना है? (जून 2026)

– पाँच वर्ष

➤ क्या भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार है? (जून 2026)

– नहीं

➤ एकीकृत किया जाने वाला एकल आपातकालीन नंबर कौन-सा है? (जून 2026)

– 112

➤ PM राहत क्या प्रदान करती है? (जून 2026)

– सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद-रहित उपचार

➤ PM राहत के अंतर्गत नकद-रहित उपचार की सीमा क्या है? (जून 2026)

– ₹1.5 लाख

➤ PM राहत कौन-सा मंत्रालय चलाता है? (जून 2026)

– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

➤ किस मामले ने ट्रॉमा केयर के अधिकार को मान्यता दी? (जून 2026)

– सेवलाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ

➤ कौन-सा अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का अधिकार देता है? (जून 2026)

– अनुच्छेद 262

➤ तुंगभद्रा कृष्णा से कहाँ मिलती है? (जून 2026)

– संगमेश्वरम, आंध्र प्रदेश

➤ तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या है? (जून 2026)

– पंपा

➤ 1956 का कौन-सा अधिनियम अंतर-राज्यीय बेसिनों के लिए संघ बोर्डों की अनुमति देता है? (जून 2026)

– नदी बोर्ड अधिनियम, 1956

➤ कौन-सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों की सूची से संबंधित है? (जून 2026)

– अनुच्छेद 342

➤ झारखंड के समूह किस धर्म को पृथक रूप से मान्यता दिलाना चाहते हैं? (जून 2026)

– सरना

➤ क्या अनुच्छेद 342 में कोई धार्मिक अर्हता है? (जून 2026)

– नहीं

➤ नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का विषय क्या था? (जून 2026)

– विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास

➤ पहली बार कितने राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हुए? (जून 2026)

– सभी 28

➤ महिलाओं के लिए किस योजना का उदाहरण दिया गया? (जून 2026)

– लखपति दीदी

➤ न्यायालयों में AI के उपयोग के लिए मसौदा विनियम, 2026 किस संस्था ने जारी किए? (जून 2026)

– भारत का उच्चतम न्यायालय

➤ क्या मसौदे के अंतर्गत न्यायिक निर्णय-प्रक्रिया में AI की अनुमति है? (जून 2026)

– नहीं, निषिद्ध है

➤ मसौदे के अंतर्गत किन उद्देश्यों के लिए AI की अनुमति है? (जून 2026)
– प्रशासनिक और अनुसंधान उद्देश्य

➤ किस योजना ने लगभग 3.18 करोड़ संपत्ति कार्ड दिए? (जून 2026)
– स्वामित्व

➤ कौन-सा पोर्टल ग्राम पंचायत नियोजन को एकीकृत करता है? (जून 2026)
– ई-ग्रामस्वराज

➤ भारत का पहला रैंकिंग ढाँचा किस अधिनियम के लिए शुरू किया गया? (जून 2026)
– पेसा अधिनियम, 1996

➤ क्या पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है? (जून 2026)
– नहीं

➤ मतदाता सूची और नागरिकता से संबंधित मामला कौन-सा था? (जून 2026)
– लाल बाबू हुसैन मामला (1995)

➤ पासपोर्ट अधिनियम की कौन-सी धारा गैर-नागरिकों को पासपोर्ट देने की अनुमति देती है? (जून 2026)
– धारा 20

➤ 2003 के किस परिवर्तन ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम का दायरा बढ़ाया? (जून 2026)
– गर्भधारण-पूर्व लिंग चयन

➤ जनगणना 2011 में बाल लिंगानुपात कितना था? (जून 2026)
– 919

➤ विज्ञापनों पर रोक लगाने वाली धारा कौन-सी है? (जून 2026)
– धारा 22

➤ पैदल चलने के अधिकार का आधार कौन-से अनुच्छेद हैं? (जून 2026)
– 19(1)(d) और 21

➤ किस अधिनियम के उपाय इस अधिकार से स्वतंत्र हैं? (जून 2026)
– मोटर वाहन अधिनियम, 1988

➤ न्यायालय के अनुसार फुटपाथों का रखरखाव किसे करना चाहिए? (जून 2026)
– स्थानीय निकाय और प्राधिकरण

➤ भारत और ब्रिटेन कौन-सी शासन प्रणाली साझा करते हैं? (जून 2026)
– वेस्टमिंस्टर मॉडल

➤ कोई भारतीय मंत्री संसद सदस्य हुए बिना कितने समय तक पद पर रह सकता है? (जून 2026)
– छह माह

➤ किस देश में दल-बदल विरोधी कानून नहीं है? (जून 2026)
– यूनाइटेड किंगडम

➤ BNSS की कौन-सी धारा अनुपस्थिति में सुनवाई का प्रावधान करती है? (जुलाई 2026)
– धारा 356

➤ दो वारंटों के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? (जुलाई 2026)
– 30 दिन

➤ BNSS की कौन-सी धारा उद्घोषित अपराधियों से संबंधित है? (जुलाई 2026)
– धारा 84

➤ अधीनस्थ विधान समिति का अधिकतम आकार कितना होता है? (जुलाई 2026)
– 15 सदस्य

➤ CCI के आदेशों के विरुद्ध अपीलें कौन-सा निकाय सुनता है? (जुलाई 2026)
– राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT)

➤ CCI की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? (जुलाई 2026)
– प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

➤ PM-AJAY बनाने के लिए किन तीन योजनाओं का विलय किया गया? (जुलाई 2026)
– PMAGY, SCA to SCSP, BJRCY

➤ आदर्श ग्राम की जनसंख्या का कितना हिस्सा अनुसूचित जाति का होना चाहिए? (जुलाई 2026)
– 40 प्रतिशत से अधिक

➤ PM-विद्यालक्ष्मी के लिए कौन-सा बैंक नोडल बैंक है? (जुलाई 2026)
– केनरा बैंक

➤ PM-विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत 3 प्रतिशत ब्याज सहायता के लिए पारिवारिक आय की सीमा क्या है? (जुलाई 2026)
– ₹8 लाख

➤ योजना अब कितने संस्थानों को कवर करती है? (जुलाई 2026)
– 1,425

➤ PGI 2.0 2025-26 में शीर्ष अंक पाने वाला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कौन है? (जुलाई 2026)
– चंडीगढ़

➤ सर्वोच्च PGI ग्रेड कौन-सा है? (जुलाई 2026)
– उत्कर्ष

➤ UDISE+ 2025-26 में माध्यमिक GER क्या है? (जुलाई 2026)
– 71.7%

➤ PGI-S के कुल अंक कितने हैं? (जुलाई 2026)
– 1,000 अंक

➤ 2023-24 में भारत में उच्च शिक्षा में GER कितना था? (जुलाई 2026)
– 30.0

➤ असम में विदेशी घोषित किए जाने से संबंधित 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का नाम बताइए। (जुलाई 2026)
– सबित्री डे बनाम भारत संघ

➤ कितने व्यक्ति प्रभावित हुए? (जुलाई 2026)
– 27

➤ प्राकृतिक न्याय के किस सिद्धांत पर बल दिया गया? (जुलाई 2026)
– ऑडी अल्टरम पार्टेम (दूसरे पक्ष को सुनने का सिद्धांत)

➤ पूर्ण साक्षर कहलाने के लिए कितनी साक्षरता दर आवश्यक है? (जुलाई 2026)
– 95% या अधिक

➤ उल्लास के शिक्षार्थियों का मूल्यांकन कौन-सी परीक्षा करती है? (जुलाई 2026)
– FLNAT

➤ उल्लास की अवधि क्या है? (जुलाई 2026)
– 2022-27

➤ EPF योजना 2026 किस संहिता पर आधारित है? (जुलाई 2026)
– सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

➤ उल्लिखित वर्तमान EPF ब्याज दर क्या है? (जुलाई 2026)
– 8.25%

➤ EPS कब शुरू की गई थी? (जुलाई 2026)

– 1995

➤ EPF योजना 2026 किस संहिता से जुड़ी है? (जुलाई 2026)

– सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

➤ व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने के लिए UAPA की कौन-सी धारा है? (जुलाई 2026)

– धारा 35

➤ अब नामित व्यक्तिगत आतंकवादियों की कुल संख्या कितनी है? (जुलाई 2026)

– 80

➤ किस वर्ष UAPA में संशोधन कर इसकी अनुमति दी गई? (जुलाई 2026)

– 2019

➤ ग्राम सभा में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन किस संस्थान ने तैयार किया? (जुलाई 2026)

– NIRD&PR

➤ सशक्त पंचायत नेत्री अभियान ने कितनी महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया है? (जुलाई 2026)

– लगभग 1.5 लाख

➤ किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ 744 महिला-हितैषी ग्राम पंचायतें विकसित की जा रही हैं? (जुलाई 2026)

– UNFPA

➤ ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर किस एजेंसी ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल विकसित किया? (जुलाई 2026)

– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

➤ VB-G RAM G अधिनियम 2025 के अनुसार कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कितने अंतराल पर आवश्यक है? (जुलाई 2026)

– कम से कम हर छह महीने में एक बार

➤ CRS 2024 में जन्म पंजीकरण का स्तर क्या है? (जुलाई 2026)

– 99.1%

➤ जन्म और मृत्यु पंजीकरण को कौन-सा अधिनियम नियंत्रित करता है? (जुलाई 2026)

– RBD अधिनियम, 1969

➤ RGI का पर्यवेक्षण कौन-सा मंत्रालय करता है? (जुलाई 2026)

– गृह मंत्रालय

➤ ILO के अनुसार, भारत 2026 में सामाजिक सुरक्षा के कितने प्रतिशत कवरेज तक पहुँचा? (जुलाई 2026)

– 68.4 प्रतिशत

➤ गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कौन-सी संहिता में शामिल है? (जुलाई 2026)

– सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

➤ फिल्म प्रमाणन किस कानून द्वारा शासित है? (जुलाई 2026)

– सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952

➤ भारत के डोपिंग-रोधी कानून यूनेस्को के किस अभिसमय को लागू करते हैं? (जुलाई 2026)

– खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2005

➤ 2022 का अधिनियम डोपिंग-रोधी नियम उल्लंघनों की कितनी श्रेणियाँ सूचीबद्ध करता है? (जुलाई 2026)

– 11

➤ भारत में प्रमुख डोप परीक्षण सुविधा कौन-सा निकाय है? (जुलाई 2026)

– राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला

➤ डोपिंग-रोधी अधिनियम कब से लागू किए गए? (जुलाई 2026)

– 15 जुलाई 2026

➤ भारत ने यूनेस्को डोपिंग-रोधी अभिसमय की पुष्टि किस वर्ष की? (जुलाई 2026)

– 2007

➤ वंदे मातरम की रचना किसने की?

– बंकिम चंद्र चटर्जी

➤ गृह मंत्रालय (MHA) के दिशानिर्देशों के अनुसार वंदे मातरम का कौन-सा संस्करण आधिकारिक है? (जुलाई 2026)

– छह-पद वाला संस्करण

➤ वंदे मातरम किस उपन्यास में उद्धृत है? (जुलाई 2026)

– आनंदमठ

➤ विधेयक 1971 के किस अधिनियम में संशोधन करता है? (जुलाई 2026)

– राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम

➤ कौन-सा मूल कर्तव्य संबंधी अनुच्छेद राष्ट्रगान का उल्लेख करता है? (जुलाई 2026)

– अनुच्छेद 51A(a)

➤ वंदे मातरम को शामिल करने के लिए 2026 में 1971 के किस अधिनियम में संशोधन किया गया? (जुलाई 2026)

– राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1971

➤ संशोधित अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिकतम कारावास कितना है? (जुलाई 2026)

– तीन वर्ष

➤ BNSS की कौन-सी धारा ने CrPC की धारा 144 का स्थान लिया? (जुलाई 2026)

– धारा 163

➤ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन प्रतिबंध से संबंधित मामला कौन-सा था? (जुलाई 2026)

– मजदूर किसान शक्ति संगठन (2018)

➤ शाहीन बाग का निर्णय कौन-सा मामला है? (जुलाई 2026)

– अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020)

➤ सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) अधिनियम 2026 कब लागू होगा? (जुलाई 2026)

– 31 जुलाई 2026

➤ संशोधित अधिनियम के अंतर्गत जाँच कितने महीनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए? (जुलाई 2026)

– दो महीने

➤ NEET 2024 में पेपर लीक के बाद किस समिति ने 101 सिफारिशें दीं? (जुलाई 2026)

– राधाकृष्णन समिति

➤ विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील किस पीठ में जाती है? (जुलाई 2026)

– उच्च न्यायालय की खंडपीठ

➤ परीक्षा सुधारों पर कार्यबल (टास्क फोर्स) का प्रमुख कौन है? (जुलाई 2026)
– नंदन नीलेकणि

➤ 2024 के किस निर्णय ने अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी? (अगस्त 2026)
– पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह

➤ जनवरी 2026 में केंद्रीय पदों में अनुसूचित जातियों की कितनी हिस्सेदारी थी? (अगस्त 2026)
– 17.14 प्रतिशत

➤ किस वाद से अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण का जन्म हुआ? (अगस्त 2026)
– शिरूर मठ वाद (1954)

➤ हिजाब पहनने के अधिकार के लिए किस अनुच्छेद का सहारा लिया गया? (अगस्त 2026)
– अनुच्छेद 25

➤ 2022 के उच्चतम न्यायालय के किस हिजाब वाद में खंडित निर्णय आया? (अगस्त 2026)
– आइशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य

➤ CJI सहित उच्चतम न्यायालय की नई स्वीकृत संख्या कितनी है? (अगस्त 2026)
– 38 न्यायाधीश

➤ 2026 का संशोधन किस तिथि से प्रभावी माना गया है? (अगस्त 2026)
– 16 मई 2026

➤ कौन-सा अनुच्छेद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का अधिकार देता है? (अगस्त 2026)
– अनुच्छेद 312

➤ विधि आयोग का न्यायाधीश-जनसंख्या मानक क्या है? (अगस्त 2026)
– प्रति दस लाख पर 50

➤ गोरखालैंड समाधान समिति का प्रमुख कौन है? (अगस्त 2026)
– पंकज कुमार सिंह

➤ GTA की स्थापना किस वर्ष हुई? (अगस्त 2026)
– 2011

➤ सिलीगुड़ी गलियारे को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? (अगस्त 2026)
– चिकन नेक

➤ 2026 में 1969 के अधिनियम की कौन-सी धारा में संशोधन किया गया? (अगस्त 2026)
– धारा 13(3)

➤ दो वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरण का आदेश किसे देना होगा? (अगस्त 2026)
– प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

➤ दिशा 2.0 की अवधि क्या है? (अगस्त 2026)
– 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031

➤ योजना का कौन-सा घटक मुकदमे से पूर्व निःशुल्क परामर्श देता है? (अगस्त 2026)
– टेली-लॉ

➤ दिशा का क्रियान्वयन कौन-सा मंत्रालय करता है? (अगस्त 2026)
– विधि और न्याय मंत्रालय

➤ दिशा 2.0 का परिव्यय कितना है? (अगस्त 2026)
– ₹255 करोड़

➤ विधि-संजीवनी से कौन-सा चैटबॉट एकीकृत है? (अगस्त 2026)
– न्याय सेतु

➤ राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग में कितने सदस्य हैं? (अगस्त 2026)
– पाँच

➤ किस 2025 के निर्णय ने एक स्वतंत्र NTC का निर्देश दिया? (अगस्त 2026)
– मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ

➤ 2026 के अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण सदस्यों के लिए आयु की ऊपरी सीमा क्या है? (अगस्त 2026)
– 67 वर्ष

➤ BNSS की धारा 187(2) के अंतर्गत कुल कितनी पुलिस हिरासत की अनुमति है? (अगस्त 2026)
– 15 दिन

➤ किस 2016 के वाद में FIR को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन अपलोड करने की अपेक्षा की गई? (अगस्त 2026)
– यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ

➤ अधिवक्ता अधिनियम की कौन-सी धारा बीसीआई को नियम-निर्माण की शक्ति देती है? (अगस्त 2026)
– धारा 49

➤ उच्चतम न्यायालय ने 1995 में आयु पर आधारित कौन-सा नियम रद्द किया? (अगस्त 2026)
– 45 वर्ष से अधिक आयु पर नामांकन की रोक

➤ ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? (अगस्त 2026)
– 2007

➤ कौन-सा उपकरण GPS-सक्षम समन तामील उपलब्ध कराता है? (अगस्त 2026)
– NSTEP

➤ कौन-सा राज्य पहली कागज-रहित न्यायपालिका वाला राज्य बना? (अगस्त 2026)
– सिक्किम

➤ ई-कोर्ट्स चरण III किन वर्षों को कवर करता है? (अगस्त 2026)
– 2023-2027

➤ 2026 के विधेयक के अंतर्गत ISI के विज़िटर कौन हैं? (अगस्त 2026)
– भारत के राष्ट्रपति

➤ ISI के शासी मंडल में कितने सदस्य हैं? (अगस्त 2026)
– 11

➤ ISI विधेयक, 2026 किस अधिनियम का स्थान लेना चाहता है? (अगस्त 2026)
– ISI अधिनियम, 1959

➤ 2026 में न्यायालय ने बार प्रैक्टिस की अनिवार्यता को कितने वर्ष तक घटाया? (अगस्त 2026)
– एक वर्ष

➤ 1996 में किस आयोग ने 3 वर्ष के प्रैक्टिस नियम को समाप्त करने की अनुशंसा की? (अगस्त 2026)
– न्यायमूर्ति के.जे. शेट्टी आयोग

➤ भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2026) में किसने असहमति जताई? (अगस्त 2026)
– न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन

➤ 2026 के मानसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता कितनी थी? (अगस्त 2026)

– 15 प्रतिशत

➤ किस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 148 प्रतिशत दर्ज की गई? (अगस्त 2026)

– बजट सत्र 2024

➤ काशी घोषणा-पत्र कहाँ अपनाया गया था? (अगस्त 2026)

– वाराणसी

➤ राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? (अगस्त 2026)

– स्वयं से पहले आप

➤ नशा मुक्त युवा कार्य योजना कितने सप्ताह की है? (अगस्त 2026)

– 100 सप्ताह

➤ 2026 के किस वाद में लाइवस्ट्रीम की गई कार्यवाही की सीमाओं पर विचार किया गया? (अगस्त 2026)

– हर्षिता ग्रोवर बनाम भारत संघ

➤ कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार देता है? (अगस्त 2026)

– अनुच्छेद 129

➤ कौन-सा मंत्रालय विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंज़ूरी देता है? (अगस्त 2026)

– विदेश मंत्रालय

➤ राज्यसभा सांसदों को विदेश यात्राओं के लिए किसकी मंज़ूरी चाहिए? (अगस्त 2026)

– राज्यसभा के सभापति

➤ कौन-सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार देता है? (अगस्त 2026)

– अनुच्छेद 3

➤ नाम परिवर्तन विधेयक को पारित करने के लिए कौन-सा बहुमत आवश्यक है? (अगस्त 2026)

– साधारण बहुमत

➤ किस अशोकन अभिलेख में केरलपुत्र का उल्लेख है? (अगस्त 2026)

– शिलालेख II

➤ किस अधिनियम ने केरल का नाम बदला? (अगस्त 2026)

– केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026

➤ किस वाद ने फाँसी को मृत्युदंड की संवैधानिक विधि के रूप में बरकरार रखा? (अगस्त 2026)

– दीना बनाम भारत संघ (1983)

➤ किस वाद ने दुर्लभतम से दुर्लभ सिद्धांत प्रतिपादित किया? (अगस्त 2026)

– बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980)

➤ किस विधि आयोग रिपोर्ट ने घातक इंजेक्शन की अनुशंसा की? (अगस्त 2026)

– 187वीं रिपोर्ट (2003)

➤ IPC की धारा 498A के समकक्ष BNS की कौन-सी धारा है? (अगस्त 2026)

– धारा 85

➤ लिव-इन संबंधी क्रूरता मामलों में 2026 के लोकेश बी.एच. निर्णय ने कौन-सी अतिरिक्त शर्त जोड़ी? (अगस्त 2026)

– विवाह का आशय

➤ किस अधिनियम की धारा 2(f) विवाह की प्रकृति वाले संबंध पद का स्रोत है? (अगस्त 2026)

– घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

➤ कौन-सा अनुच्छेद किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अनुमति देता है? (सितंबर 2026)

– अनुच्छेद 124(3)

➤ बीसीआई का कौन-सा नियम शिक्षक-अधिवक्ताओं को अपना लाइसेंस सौंपने के लिए बाध्य करता है? (सितंबर 2026)

– नियम 49

➤ इस प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का मुद्दा किसने उठाया? (सितंबर 2026)

– न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ

➤ कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है? (सितंबर 2026)

– अनुच्छेद 142

➤ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की कौन-सी धारा प्राथमिकी रद्द करने को नियंत्रित करती है? (सितंबर 2026)

– धारा 528

➤ 1962 के किस वाद ने अनुच्छेद 142 को सीमित किया? (सितंबर 2026)

– प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त

➤ टोटलाइज़र किन दो सार्वजनिक उपक्रमों ने विकसित किया? (सितंबर 2026)

– बीईएल और ईसीआईएल

➤ एक टोटलाइज़र कितनी ईवीएम कंट्रोल यूनिटों से जुड़ता है? (सितंबर 2026)

– 14

➤ कौन-सा फ़ॉर्म बूथ-वार ईवीएम परिणाम दर्ज करता है? (सितंबर 2026)

– फ़ॉर्म 17C

➤ संशोधित ई-कॉमर्स नियम किस तिथि से लागू होंगे? (सितंबर 2026)

– 1 जनवरी 2027

➤ 2023 के कौन-से दिशानिर्देश डार्क पैटर्न को संबोधित करते हैं? (सितंबर 2026)

– डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के दिशानिर्देश, 2023

➤ 2025 में NCH की शिकायतों में ई-कॉमर्स से संबंधित शिकायतों का हिस्सा कितना था? (सितंबर 2026)

– लगभग 29%

➤ कौन-सा नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद काम के अधिकार को शामिल करता है? (सितंबर 2026)

– अनुच्छेद 41

➤ मनरेगा कितने दिनों के गारंटीशुदा रोज़गार का प्रावधान करता था? (सितंबर 2026)

– 100 दिन

➤ वीबी-जी राम जी का पूर्ण रूप क्या है? (सितंबर 2026)

– विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)

➤ सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए? (सितंबर 2026)

– धारा 5B(2)

➤ 2016 में किस समिति ने सिफारिश की कि CBFC केवल एक प्रमाणन निकाय हो? (सितंबर 2026)

– श्याम बेनेगल समिति

➤ दिशानिर्देशों में कौन-से UA आयु चिह्न हैं? (सितंबर 2026)
– 7+, 13+ और 16+

➤ केंद्रीय सतर्कता आयोग रिपोर्ट 2025 में सीबीआई की दोषसिद्धि दर कितनी थी? (सितंबर 2026)
– 71.71%

➤ कौन-सी धारा लोक सेवकों के निर्णयों की जाँच के लिए पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करती है? (सितंबर 2026)
– धारा 17A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

➤ सीबीआई की स्वीकृत संख्या कितनी है? (सितंबर 2026)
– 7,300

➤ कौन-सा अनुच्छेद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है? (सितंबर 2026)
– अनुच्छेद 22(2)

➤ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की कौन-सी धारा गिरफ़्तारी के आधार से संबंधित है? (सितंबर 2026)
– धारा 47

➤ 2023 के किस वाद ने गिरफ़्तारी के लिखित आधार अनिवार्य किए? (सितंबर 2026)
– पंकज बंसल बनाम भारत संघ

➤ वन अधिकार अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय कौन-सा है? (सितंबर 2026)
– जनजातीय कार्य मंत्रालय

➤ 2013 के किस निर्णय ने वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा की भूमिका को सुदृढ़ किया? (सितंबर 2026)
– नियमगिरि वाद

➤ वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन की अपेक्षा करने वाले वन भूमि-परिवर्तन नियम किस अधिनियम के तहत बनाए गए हैं? (सितंबर 2026)
– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

➤ कौन-सी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी? (सितंबर 2026)
– जनगणना 2027 (16वीं जनगणना)

➤ सभी समुदायों की अंतिम राष्ट्रव्यापी जाति गणना कब हुई थी? (सितंबर 2026)
– 1931

➤ जनगणना 2027 के डिजिटल उपकरण किसने विकसित किए? (सितंबर 2026)
– सी-डैक

➤ जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना में कितने प्रश्न हैं? (सितंबर 2026)
– 40

➤ भारत में जनगणना किस अधिनियम द्वारा शासित है? (सितंबर 2026)
– जनगणना अधिनियम, 1948

➤ संविदा अधिनियम की कौन-सी धारा नाबालिगों को संविदा करने के लिए अक्षम बनाती है? (सितंबर 2026)
– धारा 11

➤ कौन-सा अधिनियम बच्चों के डेटा के लिए सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करता है? (सितंबर 2026)
– डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

➤ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन-सी धारा इलेक्ट्रॉनिक संविदाओं को मान्यता देती है? (सितंबर 2026)
– धारा 10A

➤ चुनाव चिह्न आदेश का कौन-सा पैरा किसी दल की पहचान पर प्रतिद्वंद्वी दावों को संभालता है? (सितंबर 2026)
– पैरा 15

➤ कौन-सा अनुच्छेद ECI को चुनावों का अधीक्षण प्रदान करता है? (सितंबर 2026)
– अनुच्छेद 324

➤ NCP का घड़ी चिह्न किस गुट को दिया गया? (सितंबर 2026)
– अजीत पवार गुट

➤ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की कौन-सी धारा दलों के पंजीकरण का प्रावधान करती है? (सितंबर 2026)
– धारा 29A

➤ विधि आयोग की कौन-सी रिपोर्ट दलों के पंजीकरण रद्द करने से संबंधित थी? (सितंबर 2026)
– 255वीं रिपोर्ट

➤ निर्वाचन आयोग को दाताओं का खुलासा किस वार्षिक राशि से अधिक पर लागू होता है? (सितंबर 2026)
– ₹20,000

➤ मणिपुर एनआरसी के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाने का प्रस्ताव है? (सितंबर 2026)
– 1951

➤ कौन-सा संघीय विषय नागरिकता और एनआरसी को शामिल करता है? (सितंबर 2026)
– नागरिकता (संघ सूची)

➤ मणिपुर ने 2022 में अपने आईएलपी ढाँचे के लिए कौन-सा आधार वर्ष अपनाया? (सितंबर 2026)
– 1961

➤ कौन-सा नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद मातृत्व सहायता को शामिल करता है? (सितंबर 2026)
– अनुच्छेद 42

➤ मातृत्व वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कितना मुआवज़ा प्रदान किया? (सितंबर 2026)
– ₹10 लाख

➤ भारत में मातृत्व अवकाश किस अधिनियम द्वारा शासित है? (सितंबर 2026)
– मातृत्व लाभ अधिनियम

➤ मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन दस्तावेज की अवधि क्या है? (सितंबर 2026)
– 2026-2029

➤ कौन-सा देश अफीम स्रोत के रूप में अफगानिस्तान से आगे निकला? (सितंबर 2026)
– म्यांमार

➤ मानस हेल्पलाइन नंबर क्या है? (सितंबर 2026)
– 1933

➤ NCB की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? (सितंबर 2026)
– एनडीपीएस अधिनियम, 1985

➤ कौन-सा मंच 195 देशों के साथ इंटरपोल से सीधा संपर्क देता है? (सितंबर 2026)
– भारतपोल

➤ लद्दाख की पर्वतीय परिषदें किस अधिनियम के अंतर्गत गठित की जाती हैं? (सितंबर 2026)

– लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1997

➤ लद्दाख कब से केंद्र शासित प्रदेश है? (सितंबर 2026)

– 31 अक्टूबर 2019

➤ छठी अनुसूची की परिषदें किन अनुच्छेदों से शक्ति प्राप्त करती हैं? (सितंबर 2026)

– 244(2) और 275(1)

➤ अनुच्छेद 371 से 371J संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? (सितंबर 2026)

– भाग XXI

➤ गृह मंत्रालय (MHA) के साथ वार्ता में लद्दाख का प्रतिनिधित्व कौन-से दो समूह करते हैं? (सितंबर 2026)

– लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस

➤ संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? (सितंबर 2026)

– अनुच्छेद 17

➤ 2024 के उच्चतम न्यायालय के किस वाद ने अस्पृश्यता को शुचिता और अपवित्रता की धारणाओं से जोड़ा? (सितंबर 2026)

– सुकन्या शांता बनाम भारत संघ

➤ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम का कौन-सा प्रावधान सार्वजनिक दृष्टि के भीतर के स्थान पर अपमान की अपेक्षा करता है? (सितंबर 2026)

– धारा 3(1)(r)

➤ हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? (सितंबर 2026)

– 14 सितंबर

➤ संविधान का कौन-सा भाग राजभाषा से संबंधित है? (सितंबर 2026)

– भाग XVII

➤ किस अधिनियम ने हिंदी के साथ अंग्रेज़ी के निरंतर प्रयोग की अनुमति दी? (सितंबर 2026)

– राजभाषा अधिनियम, 1963

अंतरराष्ट्रीय

➤ UNSC में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? (जनवरी 2026)

– दस, जो दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

➤ भारत IMO परिषद में किस श्रेणी के अंतर्गत पुनः निर्वाचित हुआ? (जनवरी 2026)

– श्रेणी ख

➤ अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की कितनी संस्थाओं से बाहर निकलने का निर्णय लिया? (जनवरी 2026)

– 31

➤ अमेरिका 1984 और 2017 में किस एजेंसी से हट गया था? (जनवरी 2026)

– UNESCO

➤ USAID का 2024 का बजट कितना था? (जनवरी 2026)

– 44.2 अरब डॉलर

➤ GIUK गैप क्या है? (जनवरी 2026)

– ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूके समुद्री मार्ग

➤ ग्रीनलैंड में अमेरिका का कौन-सा बेस स्थित है? (जनवरी 2026)

– पिटुफिक स्पेस बेस

➤ नाटो सहयोगियों ने उच्च उत्तर (हाई नॉर्थ) के लिए कौन-सा मिशन प्रस्तावित किया? (जनवरी 2026)

– आर्कटिक सेंट्री

➤ किस रिपोर्ट ने 2026 में भू-आर्थिक टकराव को शीर्ष जोखिम बताया? (जनवरी 2026)

– WEF वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026

➤ अलग-अलग मुद्दों के लिए अलग-अलग गठबंधन बनाने की नीति क्या कहलाती है? (जनवरी 2026)

– परिवर्तनशील ज्यामिति

➤ उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक किस संगठन ने जारी किया? (जनवरी 2026)

– वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन

➤ RNI कितने देशों का आकलन करता है? (जनवरी 2026)

– 154

➤ RNI में भारत का रैंक क्या था? (जनवरी 2026)

– 16वाँ

➤ RNI में कौन-सा देश शीर्ष पर रहा? (जनवरी 2026)

– सिंगापुर

➤ भारत का RCEP के किस सदस्य के साथ FTA होना अभी बाकी है? (जनवरी 2026)

– चीन

➤ भारत-ओमान CEPA पर कब हस्ताक्षर हुए? (जनवरी 2026)

– दिसंबर 2025

➤ FTA पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह की अध्यक्षता किसने की? (जनवरी 2026)

– सुरजीत भल्ला

➤ भारत का 22वाँ FTA साझेदार कौन था? (जनवरी 2026)

– यूरोपीय संघ

➤ भारत-यूरोपीय संघ FTA किस शिखर सम्मेलन में संपन्न हुआ? (जनवरी 2026)

– 16वाँ भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन

➤ यूके ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ कब छोड़ा? (जनवरी 2026)

– 31 जनवरी 2020

➤ यूरोपीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? (जनवरी 2026)

– ब्रसेल्स

➤ विश्व बैंक का नया साझेदारी ढाँचा किस अवधि के लिए है? (जनवरी 2026)

– 2026-2031

➤ भारत के लिए कितनी सहायता परिकल्पित है? (जनवरी 2026)
– 8-10 अरब डॉलर

➤ 2050 तक भारत की अनुमानित शहरी जनसंख्या कितनी होगी? (जनवरी 2026)
– 80 करोड़

➤ भारत और यूएई किस वर्ष तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं? (जनवरी 2026)
– 2032

➤ फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से कौन-सा समूह बना है? (जनवरी 2026)
– वाइमर त्रिकोण

➤ 2025 का भारत का कौन-सा अधिनियम यूएई के साथ परमाणु साझेदारी पर चर्चा को सक्षम बनाता है? (जनवरी 2026)
– SHANTI अधिनियम, 2025

➤ CBAM किस तिथि से शुरू हुआ? (जनवरी 2026)
– 1 जनवरी 2026

➤ CBAM किसे रोकने का लक्ष्य रखता है? (जनवरी 2026)
– कार्बन रिसाव

➤ CBAM द्वारा कवर किए गए दो क्षेत्रों के नाम बताइए। (जनवरी 2026)
– इस्पात और सीमेंट

➤ वेनेज़ुएला में अमेरिकी अभियान का नाम क्या था? (जनवरी 2026)
– ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व

➤ 1823 में मुनरो सिद्धांत की घोषणा किसने की? (जनवरी 2026)
– राष्ट्रपति जेम्स मुनरो

➤ वेनेज़ुएला का कौन-सा क्षेत्र उसके अधिकांश तेल भंडार रखता है? (जनवरी 2026)
– ओरिनोको बेल्ट

➤ वैश्विक न्यूनतम कर किन मॉडल नियमों पर आधारित है? (जनवरी 2026)
– GloBE मॉडल नियम

➤ BEPS का पूर्ण रूप क्या है? (जनवरी 2026)
– आधार क्षरण और लाभ अंतरण

➤ साइड-बाय-साइड पैकेज के कितने घटक हैं? (जनवरी 2026)
– पाँच

➤ नई दिल्ली घोषणा को कितने हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनाया? (फरवरी 2026)
– 88

➤ 2027 का AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? (फरवरी 2026)
– जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

➤ भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस आपूर्ति श्रृंखला समूह में शामिल हुआ? (फरवरी 2026)
– पैक्स सिलिका

➤ कितने देशों ने नई दिल्ली घोषणा का समर्थन किया? (फरवरी 2026)
– 92

➤ MANAV ढाँचे में M का क्या अर्थ है? (फरवरी 2026)
– नैतिक और आचारगत प्रणाली

➤ वाचना किस कंपनी ने लॉन्च किया? (फरवरी 2026)
– ज्ञानी.ai

➤ अब BNP का नेतृत्व कौन करता है? (फरवरी 2026)
– तारिक रहमान

➤ BNP की स्थापना कब हुई थी? (फरवरी 2026)
– 1978

➤ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क संबंधी निर्णय में मतदान का अनुपात क्या था? (फरवरी 2026)
– 6-3

➤ शुल्कों के लिए किस अधिनियम का सहारा लिया गया था? (फरवरी 2026)
– IEEPA, 1977

➤ चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? (फरवरी 2026)
– डिएगो गार्सिया

➤ कौन-सा नाटो कमांड आर्कटिक सेंट्री का नेतृत्व करता है? (फरवरी 2026)
– ज्वाइंट फोर्स कमांड नॉरफ़ॉक

➤ अमेरिका-इज़राइल के अभियान का नाम क्या था? (फरवरी 2026)
– ऑपरेशन एपिक फ्यूरी

➤ किस देश ने परमाणु वार्ता में मध्यस्थता की? (फरवरी 2026)
– ओमान

➤ कौन-सा UNSC प्रस्ताव शांति बोर्ड का समर्थन करता है? (फरवरी 2026)
– प्रस्ताव 2803 (2025)

➤ NCAG का पूर्ण रूप क्या है? (फरवरी 2026)
– गाज़ा के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति

➤ बोर्ड की उद्घाटन बैठक किस शहर में हुई? (फरवरी 2026)
– वाशिंगटन DC

➤ न्यू स्टार्ट किस तिथि को समाप्त हुई? (फरवरी 2026)
– 5 फरवरी 2026

➤ न्यू स्टार्ट के अंतर्गत परमाणु हथियारों की सीमा कितनी है? (फरवरी 2026)
– 1,550

➤ न्यू स्टार्ट पर हस्ताक्षर किसने किए? (फरवरी 2026)
– ओबामा और मेदवेदेव

➤ भारत-मलेशिया का कौन-सा अभ्यास अपने 5वें संस्करण में पहुँचा? (फरवरी 2026)
– हरिमाऊ शक्ति

➤ भारत पर अमेरिकी शुल्क किस स्तर तक घट गए? (फरवरी 2026)
– 18 प्रतिशत

➤ कौन-सा GATT अनुच्छेद FTA और सीमा शुल्क संघों की अनुमति देता है? (फरवरी 2026)
– अनुच्छेद XXIV

➤ भारत ने पाँच वर्षों में अमेरिका से कितने मूल्य का आयात करने की योजना बनाई? (फरवरी 2026)
– 500 अरब डॉलर

➤ GCC का मुख्यालय कहाँ है? (फरवरी 2026)
– रियाद

➤ GCC के कितने सदस्य हैं? (फरवरी 2026)
– छह

➤ भारत-इज़राइल राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए? (फरवरी 2026)
– 1992

➤ इज़राइल में कौन-सी भुगतान प्रणाली सक्षम की जाएगी? (फरवरी 2026)
– UPI

➤ वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार का उच्चतम स्तर क्या था? (फरवरी 2026)
– 10.77 अरब डॉलर

➤ भारत-इज़राइल साझेदारी को अब क्या कहा जाता है? (फरवरी 2026)
– शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी

➤ भारत-फ्रांस साझेदारी को किस स्तर तक बढ़ाया गया? (फरवरी 2026)
– विशेष वैश्विक सामरिक साझेदारी

➤ कौन-सा संयुक्त उद्यम हैमर गोला-बारूद का उत्पादन करेगा? (फरवरी 2026)
– BEL और सफ्रान

➤ कौन-सा उपग्रह ISRO-CNES का संयुक्त मिशन है? (फरवरी 2026)
– तृष्णा

➤ H125 अंतिम असेंबली लाइन कहाँ है? (फरवरी 2026)
– वेमगल, कर्नाटक

➤ भारत-फ्रांस का कौन-सा अभ्यास नौसेनाओं से संबंधित है? (फरवरी 2026)
– वरुण

➤ 2030 के लिए भारत-ब्राज़ील व्यापार लक्ष्य क्या है? (फरवरी 2026)
– 30 अरब डॉलर

➤ भारतीयों के लिए ब्राज़ील के नए व्यावसायिक वीज़ा की वैधता कितनी है? (फरवरी 2026)
– 10 वर्ष

➤ भारत ने सेशेल्स के लिए किस पैकेज की घोषणा की? (फरवरी 2026)
– 175 मिलियन डॉलर

➤ दोहा दौर किस वर्ष से चल रहा है? (फरवरी 2026)
– 2001

➤ यूरोपीय संघ का कौन-सा उपाय हरित संरक्षणवाद कहलाता है? (फरवरी 2026)
– कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

➤ अवरुद्ध नियुक्तियों के कारण WTO का कौन-सा निकाय पंगु हो गया है? (फरवरी 2026)
– अपीलीय निकाय

➤ IONS की स्थापना किस वर्ष हुई? (फरवरी 2026)
– 2008

➤ किस मंच ने खनिज सुरक्षा साझेदारी का स्थान लिया? (फरवरी 2026)
– FORGE

➤ भारत ने CMF में सबसे पहले किस टास्क फोर्स की कमान संभाली? (फरवरी 2026)
– संयुक्त टास्क फोर्स-154

➤ सेशेल्स के शामिल होने के बाद कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के कितने सदस्य होंगे? (फरवरी 2026)
– छह

➤ भारत ने सेशेल्स के लिए किस पैकेज की घोषणा की? (फरवरी 2026)
– 175 मिलियन डॉलर

➤ अली खामेनेई का उत्तराधिकारी कौन बना? (मार्च 2026)
– मोज्तबा खामेनेई

➤ किस ईरानी मिसाइल ने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया? (मार्च 2026)
– खोर्रमशहर-4

➤ कौन-सा सिद्धांत ईरान की राजनीतिक व्यवस्था का आधार है? (मार्च 2026)
– वेलायत-ए-फकीह

➤ 1989 में ईरान में कौन-सा पद समाप्त किया गया? (मार्च 2026)
– प्रधानमंत्री

➤ भारत की यात्रा करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? (मार्च 2026)
– मार्क कार्नी

➤ भारत की यूरेनियम आवश्यकताओं का कितना हिस्सा आयात से पूरा होता है? (मार्च 2026)
– 70% से अधिक

➤ भारत की यात्रा पर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन हैं? (मार्च 2026)
– अलेक्जेंडर स्टब

➤ महासागर (MAHASAGAR) क्या है? (मार्च 2026)
– क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions)

➤ बांग्लादेश को डीजल भेजने के लिए किस पाइपलाइन का उपयोग किया गया? (मार्च 2026)
– भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन

➤ नेपाल में प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई? (मार्च 2026)
– राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल

➤ नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? (मार्च 2026)
– सुशीला कार्की

➤ कौन-सी अमेरिकी एजेंसी धारा 301 की जाँच करती है? (मार्च 2026)
– USTR

➤ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को रद्द किया? (मार्च 2026)
– IEEPA

➤ WTO MC14 कहाँ आयोजित हुआ? (मार्च 2026)
– याउंडे, कैमरून

➤ कितने सदस्यों ने IFD समझौते का समर्थन किया? (मार्च 2026)
– 166 में से 129

➤ संयुक्त राष्ट्र महासभा के दास व्यापार प्रस्ताव को किस देश ने प्रस्तावित किया? (मार्च 2026)
– घाना

➤ अरब लीग के अगले प्रमुख कौन हैं? (मार्च 2026)
– नबील फहमी

➤ भारत किस वर्ष BRICS की अध्यक्षता करता है? (अप्रैल 2026)
– 2026

➤ रिपोर्ट के अनुसार BRICS के कितने सदस्य हैं? (अप्रैल 2026)
– 11

➤ UAE का OPEC से बाहर निकलना कब प्रभावी हुआ? (अप्रैल 2026)
– 1 मई

➤ OPEC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? (अप्रैल 2026)
– 1960

➤ UAE किस वर्ष OPEC में शामिल हुआ? (अप्रैल 2026)
– 1967

➤ किस ईरानी मंत्री ने युद्धविराम पर सहमति जताई? (अप्रैल 2026)
– सैयद अब्बास अराघची

➤ भारत के आयातित LPG का कितना हिस्सा होर्मुज़ से होकर आता है? (अप्रैल 2026)
– लगभग 90%

➤ अमेरिका-ईरान वार्ता कहाँ आयोजित हुई? (अप्रैल 2026)
– इस्लामाबाद

➤ 2026 में भारत आने वाले ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर कौन हैं? (अप्रैल 2026)
– क्रिश्चियन स्टॉकर

➤ किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की पिछली भारत यात्रा को कितने वर्ष हुए? (अप्रैल 2026)
– 42 वर्ष

➤ किस वर्ष भारत-दक्षिण कोरिया संबंध विशेष सामरिक साझेदारी बने? (अप्रैल 2026)
– 2015

➤ कौन-सी तोप भारत-कोरिया का सह-उत्पादन है? (अप्रैल 2026)
– के9 वज्र-टी

➤ भारत-कोरिया CEPA कब से लागू है? (अप्रैल 2026)
– 2010

➤ श्रीलंका के लिए OCI पात्रता किस पीढ़ी तक बढ़ाई गई है? (अप्रैल 2026)
– छठी पीढ़ी

➤ भारत में कुल आप्रवासन जाँच चौकियाँ कितनी हैं? (अप्रैल 2026)
– 114

➤ 2026 से पहले किसी पदासीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतिम बार चीन की यात्रा कब की थी? (मई 2026)
– 2017

➤ दोनों पक्ष किस जलडमरूमध्य को खुला रखना चाहते थे? (मई 2026)
– होर्मुज़ जलडमरूमध्य

➤ 10 चीनी कंपनियों के लिए एनवीडिया की कौन-सी चिप्स को मंजूरी दी गई? (मई 2026)
– H200

➤ लौटाई गई पट्टिकाएँ किस चोल शासक के शासनकाल की हैं? (मई 2026)
– राजराज चोल प्रथम

➤ कौन-सी डच कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की साझेदार है? (मई 2026)
– ASML

➤ डच प्रधानमंत्री कौन हैं? (मई 2026)
– रॉब जेटेन

➤ यूएई द्वारा घोषित कुल निवेश? (मई 2026)
– 5 अरब डॉलर

➤ एमिरेट्स एनबीडी का निवेश किस भारतीय बैंक को मिलेगा? (मई 2026)
– आरबीएल बैंक

➤ होर्मुज़ से होकर गुजरने वाले वैश्विक तेल का अंश? (मई 2026)
– लगभग 20 प्रतिशत

➤ 1987-88 का अमेरिकी अनुरक्षण अभियान? (मई 2026)
– ऑपरेशन अर्नेस्ट विल

➤ 5वाँ ब्रिक्स SAI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (मई 2026)
– बेंगलुरु

➤ भारत के CAG कौन हैं? (मई 2026)
– के. संजय मूर्ति

➤ भारत-इटली संबंधों की नई स्थिति क्या है? (मई 2026)
– विशेष सामरिक साझेदारी

➤ टाटा मोटर्स ने किस इतालवी कंपनी का अधिग्रहण किया? (मई 2026)
– इवेको ग्रुप

➤ इटली किस गलियारे का पश्चिमी आधार है? (मई 2026)
– IMEC

➤ भारत-वियतनाम का 2030 का व्यापार लक्ष्य क्या है? (मई 2026)
– 25 अरब डॉलर

➤ भारत आने वाले वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम बताइए। (मई 2026)
– तो लाम

➤ किस केंद्रीय बैंक ने RBI के साथ भुगतान संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? (मई 2026)
– स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम

➤ साइप्रस के राष्ट्रपति कौन हैं? (मई 2026)
– निकोस क्रिस्टोडुलिडेस

➤ साइप्रस किस गलियारे का समर्थन करता है? (मई 2026)
– IMEC

➤ 2025 में रूस के व्यापार में चीन की हिस्सेदारी? (मई 2026)
– लगभग 32 प्रतिशत

➤ पुतिन की यात्रा में कितने समझौते हुए? (मई 2026)
– 40 से अधिक

➤ नेपाल 1816 की किस संधि का हवाला देता है? (मई 2026)
– सुगौली संधि

➤ भारत यात्रा के लिए लिपुलेख का उपयोग कब से कर रहा है? (मई 2026)
– 1954

➤ उम्मीदवारों की सूची के अनुसार अंकटाड (UNCTAD) का प्रमुख कौन है? (मई 2026)
– रेबेका ग्रिनस्पैन

➤ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? (मई 2026)
– महासभा

➤ स्ट्रोक पर पहला संकल्प किस सभा के सत्र में पारित हुआ? (मई 2026)
– 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा

➤ इसे कार्यकारी बोर्ड के किस सत्र में प्रस्तावित किया गया? (मई 2026)
– 158वाँ सत्र

➤ किस नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री ने मोदी के साथ वार्ता की? (मई 2026)
– योनास गार स्तोरे

➤ भारत के आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? (मई 2026)
– हिमाद्रि

➤ तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (मई 2026)
– ओस्लो

➤ 2025-27 में IORA की अध्यक्षता कौन करता है? (मई 2026)
– भारत

➤ IORA के सदस्य देशों की संख्या? (मई 2026)
– 23

➤ IMEC की घोषणा कब की गई थी? (जून 2026)
– G20 शिखर सम्मेलन 2023

➤ उत्तराखंड के किस दर्रे से भारत-चीन व्यापार फिर से शुरू होगा? (जून 2026)
– लिपुलेख दर्रा

➤ 1996 की गंगा जल संधि कब समाप्त होती है? (जून 2026)
– दिसंबर 2026

➤ 52वाँ G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (जून 2026)
– एवियन-ले-बैंस, फ्रांस

➤ G7 2026 का विषय क्या था? (जून 2026)
– नई साझेदारियाँ गढ़ना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण

➤ भारत ने किस हैसियत से भाग लिया? (जून 2026)
– विशेष आमंत्रित अतिथि

➤ G7 ने इबोला के किस प्रकार के प्रकोप पर ध्यान दिया? (जून 2026)
– बुंदीबुग्यो

➤ समुद्री मादक पदार्थ तस्करी को लक्षित करने वाला नया नेटवर्क कौन-सा है? (जून 2026)
– G7+ पोर्ट्स नेटवर्क

➤ 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? (जून 2026)
– इंदौर

➤ ब्रिक्स का पहला दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्य कौन-सा है? (जून 2026)
– इंडोनेशिया

➤ BRIC संक्षिप्त नाम किसने गढ़ा? (जून 2026)
– जिम ओ'नील

➤ इंदौर घोषणा-पत्र में कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? (जून 2026)
– चार

➤ ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? (जून 2026)
– वाराणसी

➤ OPT पर संयुक्त राष्ट्र जाँच आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? (जून 2026)
– न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर

➤ 1948 में कौन-सा अभिसमय नरसंहार को परिभाषित करता है? (जून 2026)
– नरसंहार अभिसमय

➤ आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? (जून 2026)
– 2021

➤ तीस्ता का उद्गम कहाँ से होता है? (जून 2026)
– चोलामू झील, सिक्किम

➤ कौन-सी चीनी कंपनी इस परियोजना से जुड़ी है? (जून 2026)
– पावरचाइना (POWERCHINA)

➤ पश्चिम बंगाल में तीस्ता के प्रवाह को कौन-सा भारतीय बैराज नियंत्रित करता है? (जून 2026)
– गजोलडोबा

➤ 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ने कौन-सा ढाँचा शुरू किया? (जून 2026)
– हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा ढाँचा

➤ छठा क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? (जून 2026)
– विल्मिंगटन, डेलावेयर

➤ उपस्थित ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री का नाम बताइए। (जून 2026)
– पेनी वोंग

➤ क्वाड महत्वपूर्ण खनिज पहल का आकार कितना है? (जून 2026)
– 20 अरब डॉलर

➤ 2007 में क्वाड को औपचारिक रूप से किसने प्रस्तावित किया? (जून 2026)
– शिंजो आबे

➤ अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन (MoU) में कितने खंड हैं? (जून 2026)
– 14

➤ अमेरिका ने MoU पर कहाँ हस्ताक्षर किए? (जून 2026)
– वर्साय का महल, फ्रांस

➤ 1949 के किस मामले ने अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से गुज़रने के अधिकार की पुष्टि की? (जून 2026)
– कोर्फू चैनल मामला

➤ पीओके विधानसभा में कितनी सीटें हैं? (जून 2026)
– 53

➤ शरणार्थियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? (जून 2026)
– 12

➤ पीओके के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कौन-सा गठबंधन कर रहा है? (जून 2026)
– संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी

➤ सेशेल्स के लिए भारत के विशेष आर्थिक पैकेज का मूल्य कितना है? (जून 2026)
– 175 मिलियन डॉलर

➤ मोदी को कौन-सा सम्मान प्रदान किया गया? (जून 2026)
– गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न

➤ IOR के लिए भारत के किस दृष्टिकोण को बल मिला? (जून 2026)
– महासागर (MAHASAGAR)

➤ भारत-ओमान CEPA किस तिथि को लागू हुआ? (जून 2026)
– 1 जून 2026

➤ ओमान की कितनी टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच है? (जून 2026)
– 98.08%

➤ ओमान का कौन-सा बंदरगाह भारतीय SEZ पहुँच की मेज़बानी करता है? (जून 2026)
– दुक़्म

➤ CEPA के अंतर्गत भारत के कितने निर्यात पर ओमान में शून्य शुल्क लगता है? (जून 2026)
– 99.38 प्रतिशत

➤ भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030 कब अपनाया गया? (जून 2026)
– 14 जून 2026

➤ उत्तर प्रदेश में वैमानिकी परिसर कहाँ प्रस्तावित है? (जून 2026)
– कानपुर

➤ फ्रांस 2030 तक कितने भारतीय छात्रों की मेजबानी का लक्ष्य रखता है? (जून 2026)
– 30,000

➤ भारत-फ्रांस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (जून 2026)
– नीस

➤ दोनों देशों का व्यापार लक्ष्य? (जून 2026)
– 32 अरब डॉलर

➤ स्लोवाकिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? (जून 2026)
– 1993

➤ यात्रा के बाद संबंधों की स्थिति क्या है? (जून 2026)
– व्यापक साझेदारी

➤ 2024 में द्विपक्षीय व्यापार कितना था? (जून 2026)
– 1.28 अरब यूरो

➤ IUPAC के अनुसार कितने दुर्लभ मृदा तत्व हैं? (जून 2026)
– 17

➤ धनबाद का कौन-सा संस्थान भारत-यूके GSCO का हिस्सा है? (जून 2026)
– IIT (ISM) धनबाद

➤ चीन दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण के कितने हिस्से को नियंत्रित करता है? (जून 2026)
– 90 प्रतिशत

➤ कालादान परियोजना मिज़ोरम को किस बंदरगाह से जोड़ती है? (जून 2026)
– सित्तवे

➤ मेकांग गंगा के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ बढ़ाकर कितनी की गईं? (जून 2026)
– 100

➤ किस निपटान तंत्र पर चर्चा हुई? (जून 2026)
– रुपया-क्यात

➤ रुपया-क्यात तंत्र कब क्रियाशील किया गया? (जून 2026)
– 2024

➤ भारत-म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? (जून 2026)
– 1,643 किमी

➤ GPI 2026 में भारत की रैंक क्या थी? (जून 2026)
– 127वीं

➤ लगातार 19वें वर्ष GPI में कौन-सा देश शीर्ष पर रहा? (जून 2026)
– आइसलैंड

➤ मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन किस निकाय ने शुरू किया? (जून 2026)
– OHCHR

➤ जुलाई 2026 में भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की कौन-सी संख्या वाला सम्मेलन आयोजित हुआ? (जुलाई 2026)
– 16वाँ

➤ किस वर्ष को भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष (Year of Shared Horizons) घोषित किया गया है? (जुलाई 2026)
– 2027

➤ मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल के लिए किस शिंकानसेन मॉडल की योजना है? (जुलाई 2026)
– E10

➤ 16वें शिखर सम्मेलन में कौन-सी जापानी प्रधानमंत्री शामिल हुईं? (जुलाई 2026)
– साने ताकाइची

➤ पहली भारत-जापान रक्षा सह-विकास परियोजना का नाम बताइए। (जुलाई 2026)
– यूनिकॉर्न (UNICORN) नौसैनिक रेडियो एंटीना

➤ 2026 में आसियान की अध्यक्षता कौन कर रहा है? (जुलाई 2026)
– फिलीपींस

➤ आसियान का 12वाँ संवाद साझेदार कौन है? (जुलाई 2026)
– तुर्किये

➤ ARF की स्थापना कब हुई थी? (जुलाई 2026)
– 1994

➤ किस समूह ने अमेरिका-इज़राइल-लेबनान रूपरेखा को अस्वीकार किया है? (जुलाई 2026)
– हिज़बुल्लाह

➤ UNIFIL किन दो भौगोलिक विशेषताओं के बीच कार्य करता है? (जुलाई 2026)
– ब्लू लाइन और लितानी नदी

➤ अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौते पर किस अमेरिकी कानून के अंतर्गत हस्ताक्षर हुए? (जुलाई 2026)
– धारा 123, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954

➤ चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी पर स्थित है? (जुलाई 2026)
– ओमान की खाड़ी

➤ INSTC नेटवर्क की लंबाई कितनी है? (जुलाई 2026)
– 7,200 किमी

➤ भारत चाबहार में कौन-सा टर्मिनल संचालित करता है? (जुलाई 2026)
– शहीद बेहेश्ती

➤ चाबहार के निकट कौन-सा चीन-संचालित बंदरगाह स्थित है? (जुलाई 2026)
– ग्वादर

➤ किस देश की राजकीय यात्रा में 'अवसर का महासागर' दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया? (जुलाई 2026)
– सेशेल्स

➤ महासागर (MAHASAGAR) का पूर्ण रूप क्या है? (जुलाई 2026)
– क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति

➤ हिंद महासागर के तीन मुख्य अवरोध-बिंदुओं के नाम बताइए। (जुलाई 2026)
– मलक्का, होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब

➤ हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक किस वर्ष अपनाया गया? (जुलाई 2026)
– 2019

➤ किस नीति ने 1991 की लुक ईस्ट नीति का स्थान लिया? (जुलाई 2026)
– एक्ट ईस्ट नीति

➤ आसियान केंद्रीयता को सर्वप्रथम किस दस्तावेज़ में संहिताबद्ध किया गया था? (जुलाई 2026)

– 2008 का आसियान चार्टर

➤ 'अमिस्ताद' का क्या अर्थ है? (जुलाई 2026)

– मित्रता

➤ ऑपरेशन अमिस्ताद के लिए राहत सामग्री किस विमान ने पहुँचाई? (जुलाई 2026)

– भारतीय वायु सेना का C-17

➤ किस ऑपरेशन ने तुर्किये और सीरिया की सहायता की? (जुलाई 2026)

– ऑपरेशन दोस्त

➤ 2026 का नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (जुलाई 2026)

– अंकारा

➤ 2035 तक रक्षा व्यय का लक्ष्य क्या है? (जुलाई 2026)

– GDP का 5%

➤ नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? (जुलाई 2026)

– स्वीडन (2024)

➤ किस देश ने पैक्स सिलिका पहल शुरू की? (जुलाई 2026)

– संयुक्त राज्य अमेरिका

➤ भारत किस माह और वर्ष में पैक्स सिलिका में शामिल हुआ? (जुलाई 2026)

– फरवरी 2026

➤ AI अवसर पर संयुक्त वक्तव्य पर भारत सहित कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? (जुलाई 2026)

– 35

➤ IPOI कब शुरू किया गया? (जुलाई 2026)

– 2019

➤ IPOI भारत के 2015 के किस दृष्टिकोण पर आधारित है? (जुलाई 2026)

– सागर (SAGAR)

➤ मोदी को दिया गया इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है? (जुलाई 2026)

– बिंतांग अदिपुर्णा

➤ आईआईएम-बैंगलोर का विदेशी परिसर कहाँ होगा? (जुलाई 2026)

– सिंघासरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मलंग

➤ भारत ने किस बंदरगाह को विकसित करने में रुचि दिखाई? (जुलाई 2026)

– सबांग बंदरगाह

➤ भारत-इज़राइल BIA किस 1996 के समझौते का स्थान लेता है? (जुलाई 2026)

– भारत-इज़राइल BIT, 1996

➤ भारत ने किस वर्ष अपने मॉडल BIT पाठ को मंज़ूरी दी? (जुलाई 2026)

– 2015

➤ भारत-ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? (जुलाई 2026)

– 2014

➤ 2047 के लिए भारत का परमाणु क्षमता लक्ष्य क्या है? (जुलाई 2026)

– 100 गीगावाट-विद्युत (GWe)

➤ भारत-ऑस्ट्रेलिया की नई साइबर और प्रौद्योगिकी साझेदारी का नाम बताइए। (जुलाई 2026)

– PACTS

➤ न्यूज़ीलैंड के साथ रोडमैप किस वर्ष तक चलेगा? (जुलाई 2026)

– 2030

➤ रोडमैप के कितने स्तंभ हैं? (जुलाई 2026)

– छह

➤ न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? (जुलाई 2026)

– क्रिस्टोफर लक्सन

➤ CETA कब प्रभावी हुआ? (जुलाई 2026)

– 15 जुलाई 2026

➤ CETA में कितने अध्याय हैं? (जुलाई 2026)

– 30

➤ उत्पत्ति संबंधी कौन-सी नई प्रथा शुरू की गई? (जुलाई 2026)

– उत्पत्ति की स्व-घोषणा

➤ 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की इतर बैठक कहाँ हुई? (जुलाई 2026)

– मनीला

➤ बिम्सटेक NSA बैठक की मेज़बानी किसने की? (जुलाई 2026)

– अजीत डोभाल

➤ कौन-सी क्वाड पहल फिजी के बंदरगाहों को कवर करती है? (जुलाई 2026)

– हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग

➤ ब्रिक्स की मादक पदार्थ-रोधी बैठक कहाँ आयोजित हुई? (जुलाई 2026)

– गुवाहाटी

➤ MANAS हेल्पलाइन का नंबर क्या है? (जुलाई 2026)

– 1933

➤ भारत के मादक पदार्थ-रोधी रोडमैप की अवधि क्या है? (जुलाई 2026)

– 2026-29

➤ किस देश ने सबसे पहले 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? (जुलाई 2026)

– ऑस्ट्रेलिया

➤ ई-वीज़ा प्रवेश के लिए अब कितने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह खुले हैं? (अगस्त 2026)

– 88

➤ नाउरू का नया नाम क्या है? (अगस्त 2026)

– रिपब्लिक ऑफ नाओरो

➤ 2030 के लिए भारत-रूस व्यापार लक्ष्य क्या है? (अगस्त 2026)

– 100 अरब डॉलर

➤ 14वीं ब्रिक्स STI मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? (अगस्त 2026)

– चेन्नई

➤ ब्रिक्स विश्व GDP का कितना हिस्सा है? (अगस्त 2026)

– 40 प्रतिशत

➤ भारत-उज़्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? (अगस्त 2026)

– दुस्तलिक

➤ 26वाँ SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (अगस्त 2026)

– बिश्केक, किर्गिस्तान

➤ उज़्बेकिस्तान के साथ 2030 के लिए कौन-सा व्यापार लक्ष्य तय किया गया है? (अगस्त 2026)

– 5 अरब डॉलर

➤ बीजिंग में SR वार्ता का कौन-सा दौर आयोजित हुआ? (अगस्त 2026)

– 25वाँ

➤ भारत ने अपने आधिकारिक मानचित्र पर अरुणाचल के कितने स्थानों को नाम दिया? (अगस्त 2026)

– 27

➤ मक्का समझौते का निवारण खंड संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद का अनुसरण करता है? (अगस्त 2026)

– अनुच्छेद 51

➤ मक्का समझौते पर किन तीन देशों ने हस्ताक्षर किए? (अगस्त 2026)

– सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान

➤ भारत की LPG का कितना हिस्सा अब अमेरिका से आता है? (अगस्त 2026)

– 67 प्रतिशत

➤ संकट से पहले भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन-सा देश था? (अगस्त 2026)

– कतर

➤ 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (सितंबर 2026)

– भारत मंडपम, नई दिल्ली

➤ ब्रिक्स मानसिक कल्याण केंद्रों का समन्वय कौन-सा संस्थान करता है? (सितंबर 2026)

– निम्हांस (NIMHANS), बेंगलुरु

➤ भारत का प्रस्तावित ब्रिक्स रिस्क लैब कहाँ स्थापित किया जाना है? (सितंबर 2026)

– गिफ्ट सिटी

➤ 26वाँ SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? (सितंबर 2026)

– बिश्केक, किर्गिस्तान

➤ अगला SCO अध्यक्ष कौन-सा देश बनेगा? (सितंबर 2026)

– पाकिस्तान

➤ 26वें SCO शिखर सम्मेलन में कौन-सी घोषणा अपनाई गई? (सितंबर 2026)

– बिश्केक घोषणा

➤ अमेरिका के रूस प्रतिबंध अधिनियम में अधिकतम शुल्क कितना है? (सितंबर 2026)

– 100%

➤ लक्षित देशों को आमतौर पर कितने दिन मिलते हैं? (सितंबर 2026)

– 180 दिन

➤ भारत के कच्चे तेल का कितना हिस्सा विदेश से आयात होता है? (सितंबर 2026)

– 88% से अधिक

➤ शक्सगाम घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? (सितंबर 2026)

– ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट

➤ पाकिस्तान ने शक्सगाम क्षेत्र किस वर्ष चीन को सौंपा? (सितंबर 2026)

– 1963

➤ शक्सगाम घाटी के ठीक दक्षिण में कौन-सा ग्लेशियर स्थित है? (सितंबर 2026)

– सियाचिन ग्लेशियर

➤ कौन-सा पाकिस्तानी जहाज़ भारतीय युद्धपोत से टकराया? (सितंबर 2026)

– पीएनएस हुनैन

➤ भारत ने 1991 के समझौते के किस अनुच्छेद का हवाला दिया? (सितंबर 2026)

– अनुच्छेद 10

➤ पीएनएस बाबर से जुड़ी 2011 की कौन-सी घटना थी? (सितंबर 2026)

– आईएनएस गोदावरी से रगड़

➤ भारत की यात्रा करने वाले बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन हैं? (सितंबर 2026)

– बार्ट डी वेवर

➤ 2025-26 में भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय व्यापार कितना था? (सितंबर 2026)

– 13.01 अरब अमेरिकी डॉलर

➤ रक्षा सहयोग में कौन-सा भारतीय हल्का टैंक शामिल है? (सितंबर 2026)

– ज़ोरावर

➤ ब्रिटेन ने CBAM के अंतर्गत भारत की किस योजना को मान्यता दी? (सितंबर 2026)

– कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

➤ 2025-26 में भारत-ब्रिटेन वस्तु व्यापार कितना था? (सितंबर 2026)

– 25.1 अरब डॉलर

➤ भारत-ब्रिटेन व्यापार साझेदारी कब लागू हुई? (सितंबर 2026)

– जुलाई 2026

➤ भारत की पहली विदेशी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुविधा कौन-सी है? (सितंबर 2026)

– मेडागास्कर तटीय निगरानी रडार स्टेशन

➤ IMTRAT कहाँ स्थित है? (सितंबर 2026)

– हा, पश्चिमी भूटान

➤ अगालेगा द्वीप किस देश में है? (सितंबर 2026)

– मॉरीशस

➤ चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका को भारत की सहायता कौन-सा अभियान है? (सितंबर 2026)

– ऑपरेशन सागर बंधु

➤ श्रीलंकाई वायुसेना के लिए किस तोप के उन्नयन पर सहमति बनी? (सितंबर 2026)

– L70 तोपें

➤ भारत का पुनर्निर्माण पैकेज कितना बड़ा है? (सितंबर 2026)

– 45 करोड़ डॉलर

➤ 'मानचित्र सुधारें' प्रस्ताव का नेतृत्व किस देश ने किया? (सितंबर 2026)

– टोगो

➤ 1569 में मर्केटर प्रक्षेपण किसने प्रस्तुत किया? (सितंबर 2026)

– गेरार्डस मर्केटर

➤ कितने देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया? (सितंबर 2026)

– 164

➤ सिंधु जल संधि की मध्यस्थता किस संस्था ने की? (सितंबर 2026)

– विश्व बैंक

➤ रातले परियोजना किस नदी पर है? (सितंबर 2026)

– चिनाब

➤ भारत ने IWT को कब स्थगित रखा? (सितंबर 2026)

– 23 अप्रैल 2025

➤ सिंधु जल संधि के संबंध में भारत की स्थिति क्या है? (सितंबर 2026)

– स्थगित

➤ भारत ने किस निकाय को अवैध रूप से गठित बताया? (सितंबर 2026)

– मध्यस्थता न्यायालय

➤ नवंबर 2025 में किस अभ्यास में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ आए (29वाँ संस्करण)? (अक्टूबर 2026)

– मालाबार

➤ SIMBEX भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास है? (अक्टूबर 2026)

– सिंगापुर

अर्थव्यवस्था

➤ RB-IOS 2026 किस तिथि से प्रभावी होगी? (जनवरी 2026)

– 1 जुलाई 2026

➤ RBI लोकपाल अधिकतम कितना मुआवज़ा प्रदान कर सकता है? (जनवरी 2026)

– ₹30 लाख

➤ अपील कितने दिनों के भीतर दायर की जा सकती है? (जनवरी 2026)

– 30 दिन

➤ CRPC का पूर्ण रूप क्या है? (जनवरी 2026)

– केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र

➤ लघु वित्त बैंकों के लिए संशोधित PSL लक्ष्य क्या है? (जनवरी 2026)

– ANBC का 60 प्रतिशत

➤ भुगतान न होने के कितने दिनों बाद कोई ऋण NPA बन जाता है? (जनवरी 2026)

– 90 दिन

➤ किस वर्ष सकल NPA अनुपात 11.18 प्रतिशत के शिखर पर था? (जनवरी 2026)

– 2018

➤ किस एजेंसी के सहकारी समितियों को दिए गए ऋण को अब PSL माना जाता है? (जनवरी 2026)

– NCDC

➤ नीति आयोग के अनुसार महानगरों में किफायती आवास का अधिकतम मूल्य कितना है? (जनवरी 2026)

– ₹60 लाख

➤ किफायती आवास के लिए आरक्षित की जाने वाली आवासीय भूमि का हिस्सा कितना है? (जनवरी 2026)

– कम से कम 10 प्रतिशत

➤ किस योजना में किफायती किराया आवास घटक है? (जनवरी 2026)

– PMAY-U 2.0

➤ कोकिंग कोयला अब MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के किस भाग में सूचीबद्ध है? (जनवरी 2026)

– भाग D

➤ इस्पात क्षेत्र की कोकिंग कोयले की आवश्यकता का कितना हिस्सा आयात से पूरा होता है? (जनवरी 2026)

– लगभग 95 प्रतिशत

➤ भारत में कोकिंग कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? (जनवरी 2026)

– 37.37 अरब टन

➤ केंद्रीय क्षेत्र की PPP परियोजनाओं का मूल्यांकन कौन-सा निकाय करता है? (जनवरी 2026)

– PPPAC

➤ त्रि-वर्षीय PPP पाइपलाइन में कितनी परियोजनाएँ हैं? (जनवरी 2026)

– 852

➤ आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अधिकतम VGF कितना है? (जनवरी 2026)

– पूंजीगत व्यय का 40 प्रतिशत

➤ निर्यात तैयारी सूचकांक किस निकाय ने जारी किया? (जनवरी 2026)

– नीति आयोग

➤ EPI में उत्तर प्रदेश की किस योजना को नीतिगत शक्ति के रूप में उद्धृत किया गया है? (जनवरी 2026)

– एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

➤ EPI 2024 में बड़े राज्यों में कौन-सा राज्य शीर्ष पर है? (जनवरी 2026)

– महाराष्ट्र

➤ नई उप-योजना के अंतर्गत आधार ब्याज सहायता दर क्या है? (जनवरी 2026)

– 2.75 प्रतिशत

➤ सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए गारंटी कवर कितना है? (जनवरी 2026)

– 85 प्रतिशत तक

➤ संपार्श्विक सहायता उप-योजना में कौन-सा ट्रस्ट भागीदार है? (जनवरी 2026)

– CGTMSE

➤ BAHS 2025 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन-सा है? (जनवरी 2026)

– उत्तर प्रदेश (15.66%)

➤ ऊन उत्पादन में कौन-सा राज्य अग्रणी है? (जनवरी 2026)

– राजस्थान (47.85%)

➤ भारत के चावल उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? (जनवरी 2026)

– उत्तर प्रदेश

➤ 2024-25 में भारत का चावल निर्यात कितना था? (जनवरी 2026)

– 20.1 मिलियन मीट्रिक टन

➤ कौन-सा चावल मौसम जून-जुलाई में बोया जाता है और नवंबर-दिसंबर में काटा जाता है? (जनवरी 2026)

– अमन

➤ SRF 5.0 की श्रेणी A में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन था? (जनवरी 2026)

– गुजरात

➤ 2024-25 में किस राज्य को सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुई? (जनवरी 2026)

– महाराष्ट्र (39%)

➤ अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? (जनवरी 2026)

– 2030-31

➤ APY के अंतर्गत मासिक पेंशन की सीमा क्या है? (जनवरी 2026)

– ₹1,000 से ₹5,000

➤ नए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा कितनी है? (जनवरी 2026)

– ₹30,000

➤ NPS वात्सल्य के दिशानिर्देश किस नियामक ने जारी किए? (जनवरी 2026)

– PFRDA

➤ कृषि अवसंरचना कोष कब शुरू किया गया था? (फरवरी 2026)

– 2020

➤ 2014 में किस समिति ने गोदाम रसीदों का सुझाव दिया था? (फरवरी 2026)

– शांता कुमार समिति

➤ 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन (तीसरा अग्रिम अनुमान)? (फरवरी 2026)

– 353.96 मिलियन टन

➤ भारत की GDP श्रृंखला का नया आधार वर्ष क्या है? (फरवरी 2026)

– 2022-23

➤ कौन-सी पद्धति एकल अपस्फीतिक दृष्टिकोण का स्थान लेती है? (फरवरी 2026)

– दोहरा अपस्फीतिकरण

➤ भारत आगे कौन-सा अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाएगा? (फरवरी 2026)

– SNA 2025

➤ नई CPI श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? (फरवरी 2026)

– 2024

➤ जनवरी 2026 के लिए अखिल भारतीय CPI मुद्रास्फीति कितनी थी? (फरवरी 2026)

– 2.75 प्रतिशत

➤ कौन-सा सर्वेक्षण CPI 2024 के लिए भारांश प्रदान करता है? (फरवरी 2026)

– HCES 2023-24

➤ नई CPI टोकरी में कितनी मदें हैं? (फरवरी 2026)

– 358

➤ नई CPI कौन-सा वर्गीकरण अपनाती है? (फरवरी 2026)

– COICOP 2018

➤ ऑरेंज इकोनॉमी शब्द किसने गढ़ा? (फरवरी 2026)

– इवान डूके मार्केज़ और फेलिपे बुइट्रागो

➤ कितने विद्यालयों में AVGC लैब स्थापित की जाएँगी? (फरवरी 2026)

– 15,000

➤ रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन-सा था? (फरवरी 2026)

– 2021

➤ BE 2026-27 के लिए कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है? (फरवरी 2026)

– GDP का 4.3%

➤ 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य क्या है? (फरवरी 2026)

– ₹12.2 लाख करोड़

➤ ऋण-GDP अनुपात किस वर्ष तक 50% तक पहुँचना चाहिए? (फरवरी 2026)

– वित्त वर्ष 31

➤ भारत में किस संहिता ने सबसे पहले गिग श्रमिकों को परिभाषित किया? (फरवरी 2026)

– सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

➤ ई-श्रम पंजीकृत श्रमिकों को कौन-सा पहचानकर्ता देता है? (फरवरी 2026)

– सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN)

➤ नीति आयोग के अनुसार 2029-30 तक कितने गिग श्रमिक होने का अनुमान है? (फरवरी 2026)

– 2.35 करोड़

➤ किन चार राज्यों को दुर्लभ मृदा गलियारे मिलेंगे? (फरवरी 2026)

– ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु

➤ REPM योजना का परिव्यय कितना है? (फरवरी 2026)

– ₹7,280 करोड़

➤ कितने रसायन पार्क प्रस्तावित हैं? (फरवरी 2026)

– तीन

➤ घरों का लक्ष्य कितना है? (फरवरी 2026)

– एक करोड़

➤ योजना के अंतर्गत अधिकतम सब्सिडी कितनी है? (फरवरी 2026)

– ₹78,000

➤ इसे कौन-सा मंत्रालय संचालित करता है? (फरवरी 2026)

– MNRE

➤ TReDS किस वर्ष बनाया गया था? (फरवरी 2026)

– 2018

➤ भारत के निर्यात में MSME की कितनी हिस्सेदारी है? (फरवरी 2026)

– 48.58 प्रतिशत

➤ आयकर अधिनियम, 2025 किस तिथि से प्रभावी होगा? (फरवरी 2026)

– 1 अप्रैल 2026

➤ आईटी सेवाओं के लिए नया सेफ हार्बर मार्जिन क्या है? (फरवरी 2026)

– 15.5%

➤ भारतीय डेटा केंद्रों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को किस वर्ष तक कर अवकाश मिलता है? (फरवरी 2026)

– 2047

➤ LRS की वार्षिक सीमा क्या है? (फरवरी 2026)

– 2,50,000 डॉलर

➤ ECMS का संशोधित परिव्यय कितना है? (फरवरी 2026)

– ₹40,000 करोड़

➤ कितने पुराने औद्योगिक समूहों (क्लस्टरों) को पुनर्जीवित किया जाएगा? (फरवरी 2026)

– 200

➤ SME ग्रोथ फंड का आकार कितना है? (फरवरी 2026)

– ₹10,000 करोड़

➤ बजट 2026-27 में घोषित CCUS परिव्यय कितना है? (फरवरी 2026)

– ₹20,000 करोड़

➤ 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों में से पहला कौन-सा जलमार्ग है? (फरवरी 2026)
– NW-5 (ओडिशा)

➤ कौन-सी योजना महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक खुदरा आउटलेट स्थापित करती है? (फरवरी 2026)
– शी-मार्ट (SHE-Mart)

➤ डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन कहाँ किया जाएगा? (फरवरी 2026)
– जामनगर

➤ कितने पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाना है? (फरवरी 2026)
– 15

➤ बायोफार्मा शक्ति का परिव्यय कितना है? (फरवरी 2026)
– ₹10,000 करोड़

➤ राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन को कौन-सा निकाय क्रियान्वित करता है? (फरवरी 2026)
– BIRAC

➤ भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का 2030 का लक्ष्य क्या है? (फरवरी 2026)
– 300 अरब डॉलर

➤ कितने नए NIPER की योजना है? (फरवरी 2026)
– तीन

➤ 2019 में जारी डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DB 2020) में भारत की रैंक क्या थी? (फरवरी 2026)
– 63

➤ जन विश्वास अधिनियम 2023 ने कितने प्रावधानों को अपराधमुक्त किया? (फरवरी 2026)
– 183

➤ 2014 में BRAP किस एजेंसी ने शुरू किया? (फरवरी 2026)
– DPIIT

➤ मार्च 2029 के लिए लखपति दीदी का नया लक्ष्य क्या है? (फरवरी 2026)
– 6 करोड़

➤ वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? (फरवरी 2026)
– 131

➤ लखपति दीदी किस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई? (फरवरी 2026)
– DAY-NRLM

➤ NMP 2.0 का लक्ष्य क्या है? (फरवरी 2026)
– ₹16.72 लाख करोड़

➤ NMP 2.0 को किस निकाय ने विकसित किया? (फरवरी 2026)
– नीति आयोग

➤ किस समिति ने सबसे पहले परिसंपत्ति मुद्रीकरण का प्रस्ताव रखा? (फरवरी 2026)
– विजय केलकर समिति

➤ परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के कोर समूह की अध्यक्षता कौन करता है? (फरवरी 2026)
– कैबिनेट सचिव

➤ ECMS किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? (फरवरी 2026)
– MeitY

➤ अब निर्यात दायित्व अवधि क्या है? (फरवरी 2026)
– 12 माह

➤ इंजीनियरों के लिए भारत किस समझौते में स्थायी रूप से शामिल हुआ? (फरवरी 2026)
– वाशिंगटन समझौता

➤ सीएजी की राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट में कितने राज्य शामिल हैं? (फरवरी 2026)
– 28

➤ 2023-24 में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी? (फरवरी 2026)
– 29.77 प्रतिशत

➤ 2023-24 में कितने राज्यों का राजकोषीय घाटा GSDP के 3 प्रतिशत से अधिक था? (फरवरी 2026)
– 18

➤ कपास के एमएसपी संचालन की नोडल एजेंसी कौन-सी है? (मार्च 2026)
– भारतीय कपास निगम

➤ आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन-सा थिंक टैंक प्रकाशित करता है? (मार्च 2026)
– हेरिटेज फाउंडेशन

➤ भारत की एकमात्र यंत्रीकृत हीरा खदान कहाँ है? (मार्च 2026)
– पन्ना, मध्य प्रदेश

➤ NIIF में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? (मार्च 2026)
– 49%

➤ FHI कितने उप-सूचकांकों का उपयोग करता है? (मार्च 2026)
– पाँच

➤ FHI में सर्वश्रेष्ठ राजकोषीय श्रेणी कौन-सी है? (मार्च 2026)
– उपलब्धिकर्ता (अचीवर्स)

➤ पोषक-संवर्धित चावल की भंडारण अवधि का अध्ययन किस संस्थान ने किया? (मार्च 2026)
– आईआईटी खड़गपुर

➤ गैस आदेश के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? (मार्च 2026)
– आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

➤ भारत की एलपीजी गुफाएँ (कैवर्न) कहाँ हैं? (मार्च 2026)
– मंगलुरु और विशाखापत्तनम

➤ BHAVYA का परिव्यय कितना है? (मार्च 2026)
– ₹33,660 करोड़

➤ BHAVYA के अंतर्गत पार्कों की संख्या कितनी है? (मार्च 2026)
– 100

➤ राहत (RELIEF) योजना का परिव्यय कितना है? (मार्च 2026)
– ₹497 करोड़

➤ लघु जलविद्युत योजना की लक्षित क्षमता कितनी है? (मार्च 2026)
– लगभग 1,500 मेगावाट

➤ आईएमएफ के अनुसार भारत का अनुमानित 2026 GDP क्या है? (अप्रैल 2026)
– 4.15 ट्रिलियन डॉलर

➤ भारत के किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? (अप्रैल 2026)

– 2031

➤ आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत कौन-सा फॉर्म फॉर्म 16 का स्थान लेता है? (अप्रैल 2026)

– फॉर्म 130

➤ 2025 में दर्ज साइबर धोखाधड़ियाँ (लगभग)? (अप्रैल 2026)

– ₹22,931 करोड़ मूल्य की 28 लाख

➤ फंसे हुए ऋणों के संशोधित नियमों की प्रभावी तिथि क्या है? (अप्रैल 2026)

– 1 अप्रैल 2027

➤ वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी पवन क्षमता जोड़ी गई? (अप्रैल 2026)

– 6.05 गीगावाट

➤ 2030 के लिए भारत का गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य क्या है? (अप्रैल 2026)

– 500 गीगावाट

➤ स्थापित नवीकरणीय क्षमता में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? (अप्रैल 2026)

– तीसरा

➤ भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब एसईजेड कहाँ अधिसूचित हुआ है? (अप्रैल 2026)

– धोलेरा, गुजरात (टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग)

➤ राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? (अप्रैल 2026)

– 16 जनवरी

➤ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स का प्रबंधन कौन करता है? (अप्रैल 2026)

– SIDBI

➤ डीप-टेक स्टार्टअप के लिए कारोबार सीमा क्या है? (अप्रैल 2026)

– ₹300 करोड़

➤ वित्त वर्ष 2025-26 में कितने स्टार्टअप को मान्यता दी गई? (अप्रैल 2026)

– 55,200 से अधिक

➤ पीएमजीएसवाई-III को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? (अप्रैल 2026)

– मार्च 2028

➤ भारत समुद्री बीमा पूल के लिए संप्रभु गारंटी कितनी है? (अप्रैल 2026)

– ₹12,980 करोड़

➤ जलविद्युत परियोजनाओं से अरुणाचल को निःशुल्क बिजली का कितना हिस्सा मिलेगा? (अप्रैल 2026)

– 12%

➤ SRS 2024 में किस राज्य की जन्म दर सर्वाधिक है? (मई 2026)

– बिहार (26.8)

➤ SRS 2022-24 में भारत का MMR क्या था? (मई 2026)

– प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 87

➤ आरबीआई 2025-26 में कितना सोना देश में लाया? (मई 2026)

– 168.06 मीट्रिक टन

➤ आरबीआई के सोने का कितना हिस्सा देश में रखा है? (मई 2026)

– 77 प्रतिशत

➤ ECLGS 5.0 के अंतर्गत लक्षित कुल ऋण प्रवाह कितना है? (मई 2026)

– ₹2.55 लाख करोड़

➤ MSME के लिए गारंटी कवर कितना है? (मई 2026)

– 100 प्रतिशत

➤ गारंटी कौन-सी संस्था देती है? (मई 2026)

– NCGTC

➤ 2026-27 के लिए किस खरीफ फसल का MSP सबसे अधिक है? (मई 2026)

– तिल (₹10,346 प्रति क्विंटल)

➤ खरीफ MSP 2026-27 में किस फसल में लागत के ऊपर सर्वाधिक अनुमानित मार्जिन है? (मई 2026)

– मूंग (61%)

➤ 2026-27 के लिए गन्ने का FRP कितना है? (मई 2026)

– ₹365 प्रति क्विंटल

➤ FRP के भुगतान को कौन-सा आदेश नियंत्रित करता है? (मई 2026)

– गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966

➤ 2025-26 में भारत का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना है? (मई 2026)

– 376.563 मिलियन टन (रिकॉर्ड)

➤ 2025-26 के अनुमानों में कौन-सा राज्य चावल और गेहूँ दोनों के उत्पादन में अग्रणी है? (मई 2026)

– उत्तर प्रदेश

➤ मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ प्रस्तावित है? (मई 2026)

– थूथुकुडी, तमिलनाडु

➤ MoU में शामिल कोरियाई कंपनी कौन-सी है? (मई 2026)

– एचडी केएसओई (HD KSOE)

➤ भारत का 18वाँ रेलवे जोन कौन-सा है? (मई 2026)

– दक्षिण तट रेलवे

➤ इसका मुख्यालय कहाँ है? (मई 2026)

– विशाखापत्तनम

➤ एनपीएस के सुनिश्चित भुगतान पर पीएफआरडीए पैनल की अध्यक्षता कौन करता है? (मई 2026)

– डॉ. एम. एस. साहू

➤ कितने व्यक्तियों को FEO घोषित किया गया है? (मई 2026)

– 21

➤ किसी व्यक्ति को FEO कौन घोषित करता है? (मई 2026)

– विशेष न्यायालय

➤ कपास उत्पादकता मिशन का परिव्यय कितना है? (मई 2026)

– ₹5,659.22 करोड़

➤ वाडिनार सुविधा का निर्माण कौन-सी दो एजेंसियाँ करेंगी? (मई 2026)

– दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड

➤ 2030 के लिए कोयला गैसीकरण का लक्ष्य क्या है? (मई 2026)

– 100 मिलियन टन

➤ कोयला लिंकेज की बढ़ाई गई अवधि कितनी है? (मई 2026)

– 30 वर्ष तक

➤ 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन कितना रहा? (मई 2026)

– 197.75 लाख टन

➤ मुख्य समुद्री खाद्य निर्यात वस्तु कौन-सी है? (मई 2026)

– जमे हुए झींगे

➤ आरबीआई की Q-SAFE समिति के अध्यक्ष कौन हैं? (मई 2026)
– प्रो. अनिल प्रभाकर

➤ किस फर्म को PaRRVA के रूप में मान्यता प्राप्त है? (मई 2026)
– केयर रेटिंग्स (CARE Ratings)

➤ भारत की नई GDP श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? (जून 2026)
– 2022-23

➤ CSR व्यय में ZCZP की सीमा क्या है? (जून 2026)
– 10 प्रतिशत

➤ ATF मूल्य स्थिरीकरण कोष का कोष कितना है? (जून 2026)
– ₹10,000 करोड़ तक

➤ किस देश ने पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया? (जून 2026)
– सेशेल्स

➤ कितने जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं? (जून 2026)
– 111

➤ ICAR के साथ जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएँ किस संस्थान ने तैयार कीं? (जून 2026)
– ICAR-CRIDA

➤ असम-नगालैंड समझौता ज्ञापन में साझाकरण सूत्र? (जून 2026)
– 50:50

➤ अन्वेषण कितने वर्ष तक रुका रहा? (जून 2026)
– तीन दशक

➤ समझौता ज्ञापन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र? (जून 2026)
– 1,000 वर्ग किमी से अधिक

➤ IIP का नया आधार वर्ष क्या है? (जून 2026)
– 2022-23

➤ नई WPI टोकरी में कितनी मदें हैं? (जून 2026)
– 957

➤ पाँच वर्ष में कौन-सा सूचकांक WPI का स्थान लेगा? (जून 2026)
– उत्पादक मूल्य सूचकांक

➤ नए IIP में विनिर्माण का भार कितना है? (जून 2026)
– 76.062%

➤ DDP के दिशानिर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए? (जून 2026)
– MoSPI

➤ ARC का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? (जून 2026)
– SARFAESI अधिनियम, 2002

➤ भारत की पहली ARC कौन-सी थी? (जून 2026)
– ARCIL

➤ 2025 के निर्देशों के अंतर्गत ARC के लिए न्यूनतम NOF कितना है? (जून 2026)
– ₹300 करोड़

➤ SARTHAK-PDS का परिव्यय कितना है? (जून 2026)
– ₹25,530 करोड़

➤ राष्ट्रीय बीज भंडार के बीजों के पोर्टल का नाम क्या है? (जून 2026)
– SATHI

➤ कौन-सा रेशम भारत का पहला GI-टैग प्राप्त रेशम है? (जून 2026)
– मूगा रेशम

➤ कोयला एक्सचेंजों का विनियमन कौन-सी संस्था करती है? (जून 2026)
– कोयला नियंत्रक संगठन

➤ पंजीकरण की वैधता? (जून 2026)
– 25 वर्ष

➤ किस 2025 के संशोधन ने खनिज एक्सचेंजों को सक्षम बनाया? (जून 2026)
– MMDR संशोधन अधिनियम, 2025

➤ RBI पायलट की प्रारंभ तिथि? (जून 2026)
– 1 जनवरी 2027

➤ पायलट के तहत अधिकतम क्षतिपूर्ति? (जून 2026)
– ₹25,000

➤ शिकायत की समय सीमा? (जून 2026)
– पाँच कैलेंडर दिन

➤ CIIRP शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय लेनदारों की सहमति आवश्यक है? (जून 2026)
– कम से कम 51%

➤ आईबीसी (IBC) किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? (जून 2026)
– 2016

➤ आईबीसी (IBC) को आकार देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? (जून 2026)
– टी. के. विश्वनाथन

➤ PPIRP की समय-सीमा क्या है? (जून 2026)
– 120 दिन

➤ 2026 के अधिनियम के अंतर्गत चूक के बाद NCLT को कितने दिनों के भीतर आवेदन स्वीकार करना होगा? (जून 2026)
– 14 दिन

➤ WEF TTDI 2024 में भारत की रैंक क्या है? (जून 2026)
– 39वीं

➤ SASCI 2024-25 का परिव्यय कितना है? (जून 2026)
– ₹3,295.76 करोड़

➤ कौन-सा मिशन 51 क्रूज सर्किट का लक्ष्य रखता है? (जून 2026)
– क्रूज भारत मिशन

➤ कौन-सी एजेंसी PMKVY को लागू करती है? (जून 2026)
– NSDC

➤ प्रशिक्षुओं के कितने हिस्से को नियुक्ति मिली? (जून 2026)
– 41 प्रतिशत

➤ किस समिति ने PMKVY पर चिंता जताई? (जून 2026)
– लोक लेखा समिति

➤ नई व्यवस्था में शून्य-कर सीमा कितनी है? (जून 2026)
– ₹12 लाख

➤ मार्च 2026 में GDP के अनुपात में घरेलू ऋण कितना था? (जून 2026)
– 45.5 प्रतिशत

➤ कौन-सा कोष रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करता है? (जून 2026)
– स्वामीह (SWAMIH)

➤ 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय GDP का कितना हिस्सा था? (जून 2026)
– 3.37%

➤ रुपये द्वारा छुआ गया सर्वकालिक निचला स्तर? (जून 2026)
– 96.96 प्रति डॉलर

➤ भारत की विनिमय दर कब से बाजार-निर्धारित है? (जून 2026)
– 1993

➤ वित्त वर्ष 2025-26 में व्यापार घाटा? (जून 2026)
– 119.3 अरब डॉलर

➤ LPPI में शुष्क थोक में कौन-सा बंदरगाह शीर्ष पर रहा? (जून 2026)
– पारादीप

➤ कौन-सा यार्ड भारत के लगभग 98 प्रतिशत जहाज पुनर्चक्रण को संभालता है? (जून 2026)
– अलंग-सोसिया

➤ समुद्री विकास कोष का आकार कितना है? (जून 2026)
– ₹25,000 करोड़

➤ LPPI का आधार कौन-सा ढाँचा है? (जून 2026)
– सागर आंकलन

➤ LPPI में कंटेनर श्रेणी में कौन-सा बंदरगाह शीर्ष पर रहा? (जून 2026)
– मुंद्रा

➤ सूचीबद्ध इक्विटी में व्यक्तिगत PROI के लिए नई सीमा क्या है? (जून 2026)
– 24 प्रतिशत

➤ कौन-सा मार्ग विदेशियों को चुनिंदा जी-सेक तक खुली पहुँच देता है? (जून 2026)
– पूर्ण सुलभ मार्ग

➤ जी-सेक नीलामी किस प्लेटफ़ॉर्म पर होती है? (जून 2026)
– ई-कुबेर

➤ डब्ल्यूईएफ ईटीआई 2026 में भारत की रैंक क्या है? (जून 2026)
– 70वीं

➤ GEP 2026 में 2026 के लिए अनुमानित वैश्विक वृद्धि कितनी है? (जून 2026)
– 2.5 प्रतिशत

➤ हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? (जून 2026)
– चौथा

➤ SOFIA कौन-सा संगठन प्रकाशित करता है? (जून 2026)
– FAO

➤ 2024-25 में कितने राज्यों ने GSDP के 3 प्रतिशत की राजकोषीय घाटा सीमा को पार किया? (जून 2026)
– 18

➤ किस राज्य में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज हुआ? (जून 2026)
– मेघालय (GSDP का 8.69 प्रतिशत)

➤ मार्च 2025 तक राज्यों की संयुक्त देनदारियाँ कितनी थीं? (जून 2026)
– ₹90.51 लाख करोड़

➤ राज्यों का संयुक्त सार्वजनिक ऋण कितना था? (जून 2026)
– ₹75.52 लाख करोड़

➤ कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी कितनी थी? (जून 2026)
– 16.59%

➤ किस उद्योग को नौवें कोर उद्योग के रूप में जोड़ा गया? (जुलाई 2026)
– लौह अयस्क

➤ संशोधित ICI का आधार वर्ष क्या है? (जुलाई 2026)
– 2022-23

➤ ISP कितने उप-क्षेत्रों को कवर करता है? (जुलाई 2026)
– 19

➤ अब कोर क्षेत्रों की संख्या? (जुलाई 2026)
– नौ

➤ लखपति दीदी का नया लक्ष्य क्या है? (जुलाई 2026)
– 6 करोड़ महिलाएँ

➤ SHE-LEAPS को किस एजेंसी ने विकसित किया? (जुलाई 2026)
– डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन

➤ LokOS किस मिशन से संबंधित है? (जुलाई 2026)
– DAY-NRLM

➤ लखपति दीदी का नया लक्ष्य? (जुलाई 2026)
– 6 करोड़

➤ SHE-LEAPS कब शुरू किया गया? (जुलाई 2026)
– जून 2026

➤ CPSE को MSME चालानों के निपटान के लिए अब कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म उपयोग करना होगा? (जुलाई 2026)
– TReDS

➤ 2026 के अधिनियम के तहत मध्यस्थता कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? (जुलाई 2026)
– 90 दिन

➤ मध्यस्थता से हुए समझौतों की वसूली कैसे की जा सकती है? (जुलाई 2026)
– भू-राजस्व के बकाया के रूप में

➤ NIIF के लिए नई मंत्रिमंडलीय मंज़ूरी? (जुलाई 2026)
– ₹30,000 करोड़

➤ अब सरकार की कुल प्रतिबद्धता? (जुलाई 2026)
– ₹60,000 करोड़

➤ मुख्य लाभार्थी कोष कौन-सा है? (जुलाई 2026)
– NIIF अवसंरचना कोष II

➤ PMKSY कब शुरू की गई थी? (जुलाई 2026)
– 1 जुलाई 2015

➤ उत्तर प्रदेश की कौन-सी परियोजना 2016 में PMKSY के अंतर्गत लाई गई? (जुलाई 2026)
– सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना

➤ अधिकांश राज्यों के लिए PMKSY का वित्तपोषण अनुपात क्या है? (जुलाई 2026)
– 60:40

➤ SDG राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा कौन-सा मंत्रालय विकसित करता है? (जुलाई 2026)
– MoSPI

➤ रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी दर क्या थी? (जुलाई 2026)
– 14.96 प्रतिशत

➤ SOFI 2026 का विषय? (जुलाई 2026)
– स्वस्थ आहार की ऊँची लागत

➤ बड़े राज्यों में निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन-सा राज्य शीर्ष पर रहा? (जुलाई 2026)
– गुजरात

➤ सूचकांक में कितने संकेतकों का उपयोग किया गया है? (जुलाई 2026)
– 84

➤ नए ILO प्लेटफ़ॉर्म कार्य अभिसमय की संख्या क्या है? (जुलाई 2026)
– अभिसमय संख्या 193

➤ ILO ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता? (जुलाई 2026)
– 1969

➤ भारत ने ILO के किन मूल अभिसमयों का अनुसमर्थन नहीं किया है? (जुलाई 2026)
– संख्या 87 और संख्या 98

➤ ILO अभिसमय 193 पर भारत का रुख क्या था? (जुलाई 2026)
– मतदान से अनुपस्थित रहा

➤ WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता किस वर्ष अपनाया गया? (जुलाई 2026)
– 2022

➤ कौन-से मत्स्य खंड इसके दायरे से बाहर हैं? (जुलाई 2026)
– जलकृषि और अंतर्देशीय मत्स्य पालन

➤ नाविक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वैश्विक रैंक? (जुलाई 2026)
– दूसरी

➤ मसालों संबंधी कोडेक्स समिति का सचिवालय कहाँ स्थित है? (जुलाई 2026)
– मसाला बोर्ड, कोच्चि

➤ लाकाडोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है? (जुलाई 2026)
– मेघालय

➤ मिशन गोल्डन स्पाइस का परिव्यय कितना है? (जुलाई 2026)
– ₹175.45 करोड़

➤ MPMS का बजट कितना है? (जुलाई 2026)
– ₹62,500 करोड़

➤ MPMS किस योजना की उत्तराधिकारी है? (जुलाई 2026)
– बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI

➤ योजना की अवधि? (जुलाई 2026)
– वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31

➤ मोबाइल विनिर्माण में भारत का स्थान? (जुलाई 2026)
– दूसरा सबसे बड़ा

➤ NIPU-2026 किस नीति में संशोधन करती है? (जुलाई 2026)
– नई निवेश नीति 2012

➤ 45 किलो यूरिया बोरी का खुदरा मूल्य क्या है? (जुलाई 2026)
– ₹266.50

➤ संचालित यूरिया इकाइयों की संख्या? (जुलाई 2026)
– 33

➤ NIPU-2026 को किस निकाय ने मंज़ूरी दी? (जुलाई 2026)
– CCEA

➤ BHAVYA-Rasayan के अंतर्गत रासायनिक पार्कों की संख्या? (जुलाई 2026)
– तीन

➤ प्रति पार्क अधिकतम केंद्रीय अनुदान? (जुलाई 2026)
– ₹1,000 करोड़

➤ प्रत्येक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल? (जुलाई 2026)
– 2,000 एकड़

➤ वित्त वर्ष 2027 के लिए कितनी अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है? (जुलाई 2026)
– 218

➤ भारत की आय श्रेणी? (जुलाई 2026)
– निम्न-मध्यम आय

➤ वर्गीकरण का आधार? (जुलाई 2026)
– प्रति व्यक्ति GNI, एटलस पद्धति

➤ संशोधित उड़ान का परिव्यय कितना है? (जुलाई 2026)
– ₹28,840 करोड़

➤ संशोधित उड़ान के अंतर्गत कितने आधुनिक हेलीपैड की योजना है? (जुलाई 2026)
– 200

➤ कौन-सी एजेंसी उड़ान (UDAN) को क्रियान्वित करती है? (जुलाई 2026)
– भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

➤ उड़ान (UDAN) किस वर्ष शुरू की गई? (जुलाई 2026)
– 2016

➤ जनगणना 2011 के आधार पर TPDS कितने व्यक्तियों को कवर करती है? (जुलाई 2026)
– 81.35 करोड़

➤ कौन-सा AI उपकरण PDS आपूर्ति श्रृंखला मार्गों को अनुकूलित करता है? (जुलाई 2026)
– अन्न चक्र

➤ PMGKAY के तहत खाद्यान्न किस मूल्य पर दिया जाता है? (जुलाई 2026)
– निःशुल्क

➤ 50,000 PACS को किस डिजिटल रूप में बदला जा रहा है? (जुलाई 2026)
– e-PACS

➤ भारत टैक्सी क्या है? (जुलाई 2026)
– सहकारी राइड प्लेटफ़ॉर्म

➤ कौन-सा 27वाँ नवरत्न CPSE था? (जुलाई 2026)
– नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

➤ सेमीकॉन 2.0 का परिव्यय कितना है? (जुलाई 2026)
– ₹1,27,500 करोड़

➤ अर्धचालक योजनाओं की नोडल एजेंसी कौन-सी संस्था है? (जुलाई 2026)
– इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन

➤ सेमीकॉन 1.0 का परिव्यय कितना था? (जुलाई 2026)
– ₹76,000 करोड़

➤ स्तंभों की संख्या? (जुलाई 2026)
– छह

➤ PMJDY कब शुरू की गई थी? (अगस्त 2026)

– 28 अगस्त 2014

➤ UPI MDR की अनुमति देने के लिए भुगतान प्रणालियों से संबंधित किस अधिनियम में संशोधन किया गया? (अगस्त 2026)

– भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

➤ MDR कौन चुकाता है? (अगस्त 2026)

– व्यापारी

➤ भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ बनेगा? (अगस्त 2026)

– ग्वालियर, मध्य प्रदेश

➤ कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना का परिव्यय कितना है? (अगस्त 2026)

– ₹10,000 करोड़

➤ विश्व बैंक की WDR 2026 का शीर्षक क्या है? (अगस्त 2026)

– आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा (The Promise of Artificial Intelligence)

➤ कौशल के संदर्भ में NEET का क्या अर्थ है? (अगस्त 2026)

– शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं (Not in Education, Employment or Training)

➤ कौन-सी नई धारा खनिजों पर राज्यों के उपकरों को सीमित करती है? (अगस्त 2026)

– धारा 9D

➤ जुलाई 2024 में 1989 का कौन-सा निर्णय पलटा गया? (अगस्त 2026)

– इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य

➤ गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना का परिव्यय कितना है? (अगस्त 2026)

– ₹23,731 करोड़

➤ अब CBG योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? (अगस्त 2026)

– पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

➤ गोबरधन किस वर्ष शुरू किया गया था? (अगस्त 2026)

– 2018

➤ कौन-सा GI-टैग प्राप्त उत्पाद पहली बार समुद्र मार्ग से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया? (अगस्त 2026)

– मिथिला मखाना

➤ बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? (अगस्त 2026)

– बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891

➤ PMGKAY के तहत CBDC आधारित DBT का उपयोग सबसे पहले किन दो केंद्रशासित प्रदेशों ने किया? (अगस्त 2026)

– चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली

➤ ई-श्रम UAN में कितने अंक होते हैं? (अगस्त 2026)

– 12

➤ स्वचालित मार्ग के लिए अनुमत अधिकतम गैर-नियंत्रक LBC स्वामित्व कितना है? (अगस्त 2026)

– 10 प्रतिशत

➤ किस प्रेस नोट ने 2026 का FDI सुधार लागू किया? (अगस्त 2026)

– 2026 का प्रेस नोट 2

➤ ऐसे FDI प्रस्तावों के निपटान की समय-सीमा क्या है? (अगस्त 2026)

– 60 दिन

➤ सचिवों की समिति की अध्यक्षता कौन करता है? (अगस्त 2026)

– कैबिनेट सचिव

➤ समुद्र मंथन का परिव्यय कितना है? (अगस्त 2026)

– ₹84,084 करोड़

➤ नामित गहरे जल के बेसिनों में कौन-सा बेसिन शामिल नहीं है: कावेरी, महानदी, अंडमान या कैम्बे? (अगस्त 2026)

– कैम्बे

➤ पॉलीमर बैंकनोट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? (अगस्त 2026)

– द्विअक्षीय अभिविन्यस्त पॉलीप्रोपाइलीन (BOPP)

➤ किन दो मूल्यवर्गों को पॉलीमर नोट मिलेंगे? (अगस्त 2026)

– ₹10 और ₹20

➤ EPFO की नई वेतन सीमा क्या है? (सितंबर 2026)

– ₹25,000 प्रति माह

➤ ₹15,000 तक का पिछला संशोधन किस वर्ष हुआ था? (सितंबर 2026)

– 2014

➤ EPFO के तीन घटकों के नाम बताइए। (सितंबर 2026)

– EPF, EPS और EDLI

➤ अगस्त 2026 में FAO खाद्य मूल्य सूचकांक क्या था? (सितंबर 2026)

– 133.3 अंक

➤ FAO सूचकांक ने किस महीने में अपना शिखर दर्ज किया? (सितंबर 2026)

– मार्च 2022

➤ FAO का 2026 का वैश्विक अनाज उत्पादन अनुमान क्या है? (सितंबर 2026)

– 2.980 अरब टन

➤ भारत का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार आँकड़ा क्या है? (सितंबर 2026)

– 785.706 अरब अमेरिकी डॉलर

➤ FCNR(B) जमाएँ कौन खोल सकता है? (सितंबर 2026)

– NRI और OCI

➤ FCNR(B) जमाकर्ताओं को किससे सुरक्षा देता है? (सितंबर 2026)

– विनिमय दर जोखिम

➤ GeM सहाय ऋणों के लिए कौन-सा बैंक GeM का भागीदार है? (सितंबर 2026)

– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

➤ पायलट चरण में कितने GeM सुविधा केंद्र प्रस्तावित हैं? (सितंबर 2026)

– 50

➤ GeM की कौन-सी पहल महिला उद्यमियों को लक्षित करती है? (सितंबर 2026)

– वुमनिया (Womaniya)

➤ JCR ने भारत को किस रेटिंग तक उन्नत किया? (सितंबर 2026)

– A-

➤ JCR की ओर से भारत की पहले की रेटिंग क्या थी? (सितंबर 2026)

– BBB+

➤ JCR किस देश में स्थित है? (सितंबर 2026)

– जापान

➤ UPI का संचालन कौन-सी संस्था करती है? (सितंबर 2026)
– भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India)

➤ UPI किस वर्ष शुरू किया गया था? (सितंबर 2026)
– 2016

➤ वित्त वर्ष 2025-26 में डिजिटल भुगतान लेनदेन में UPI की हिस्सेदारी कितनी थी? (सितंबर 2026)
– 84%

➤ VRRR की ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है? (सितंबर 2026)
– नीलामी बोली के माध्यम से

➤ FCNR(B) का पूर्ण रूप क्या है? (सितंबर 2026)
– विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [Foreign Currency Non-Resident (Bank)]

➤ नवीनतम VRRR परिचालन में RBI ने कितना अवशोषित किया? (सितंबर 2026)
– लगभग ₹2.9 लाख करोड़

➤ हुरुन 2026 के अनुसार भारत का शीर्ष अरबपति केंद्र कौन-सा शहर है? (सितंबर 2026)
– मुंबई (95)

➤ भारत का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ है? (सितंबर 2026)
– दीनदयाल बंदरगाह, कांडला

➤ ई-मेथनॉल संयंत्र की क्षमता कितनी है? (सितंबर 2026)
– 150 टन प्रतिदिन

➤ एलएनजी ट्रेन की पावर कारों को कहाँ परिवर्तित किया गया? (सितंबर 2026)
– साबरमती डिपो

➤ कांडला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र को कौन-सा खरपतवार कच्चा माल उपलब्ध कराता है? (सितंबर 2026)
– प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा

➤ संयंत्र की दैनिक क्षमता कितनी है? (सितंबर 2026)
– 5 टन

➤ FIU-IND की स्थापना किस वर्ष हुई? (सितंबर 2026)
– 2004

➤ आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? (सितंबर 2026)
– वित्त मंत्री

➤ VDA प्रदाताओं को नोटिस PMLA की किस धारा के तहत जारी किए गए? (सितंबर 2026)
– धारा 13

➤ DILRMP 3.0 का परिव्यय कितना है? (सितंबर 2026)
– ₹565.50 करोड़

➤ DILRMP को कौन-सा विभाग लागू करता है? (सितंबर 2026)
– भूमि संसाधन विभाग

➤ DILRMP 3.0 की अवधि क्या है? (सितंबर 2026)
– 2026-2031

➤ पीएम-एसएसवाई का क्षमता लक्ष्य क्या है? (सितंबर 2026)
– 5,000 मेगावाट

➤ पीएम-एसएसवाई का परिव्यय कितना है? (सितंबर 2026)
– ₹5,070 करोड़

➤ तैरती सौर ऊर्जा को भूमि-तटस्थ क्यों कहा जाता है? (सितंबर 2026)
– यह भूमि के बजाय जल निकायों का उपयोग करती है

➤ भारत के पहले ब्लू बॉन्ड की योजना किस संस्था ने बनाई थी? (सितंबर 2026)
– सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

➤ सागरमाला कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? (सितंबर 2026)
– 2015

➤ ब्लूवाशिंग क्या है? (सितंबर 2026)
– आय के महासागर-अनुकूल उपयोग के भ्रामक दावे

➤ IEMI 2025 में कौन-सा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? (सितंबर 2026)
– दिल्ली

➤ परिवहन विद्युतीकरण प्रगति का भारांश कितना है? (सितंबर 2026)
– 50%

➤ चार्जिंग तैयारी में सर्वाधिक अंक किसने पाए? (सितंबर 2026)
– कर्नाटक

➤ एफटीए के अंतर्गत न्यूज़ीलैंड ने भारत में कितने निवेश का वचन दिया है? (सितंबर 2026)
– 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर

➤ प्रतिवर्ष कितने वर्किंग हॉलिडे वीज़ा प्रदान किए जाते हैं? (सितंबर 2026)
– 1,000

➤ किस एफटीए को भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला एफटीए कहा जाता है? (सितंबर 2026)
– भारत-न्यूज़ीलैंड FTA

➤ भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए किस तिथि से प्रभावी होगा? (सितंबर 2026)
– 20 अक्टूबर 2026

➤ भारत ने किस संवेदनशील क्षेत्र को एफटीए की रियायतों से बाहर रखा? (सितंबर 2026)
– डेयरी

➤ किस समिति ने रेलवे HAM परियोजनाओं को मंजूरी दी? (सितंबर 2026)
– PPP मूल्यांकन समिति

➤ छह लाइनों की कुल बोली परियोजना लागत कितनी है? (सितंबर 2026)
– ₹15,976 करोड़

➤ किस राज्य में छह में से चार लाइनें हैं? (सितंबर 2026)
– ओडिशा

➤ जब बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं तो बॉन्ड प्रतिफल का क्या होता है? (सितंबर 2026)
– प्रतिफल बढ़ता है

➤ ब्रिटेन के सरकारी बॉन्ड को क्या कहा जाता है? (सितंबर 2026)
– गिल्ट्स

➤ भारत का सामान्य सरकारी ऋण GDP का लगभग कितना हिस्सा है? (सितंबर 2026)
– 80-84%

➤ जीएफसीआई 40 में कौन-सा भारतीय केंद्र सबसे ऊँची रैंक पर है? (सितंबर 2026)

– गिफ्ट सिटी (37वाँ)

➤ GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? (अक्टूबर 2026)

– केंद्रीय वित्त मंत्री

➤ IMF और विश्व बैंक ने डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध कौन-सी रूपरेखा जारी की? (अक्टूबर 2026)

– बैंकॉक ब्लूप्रिंट

➤ IDBI बैंक में कितनी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी गई? (अक्टूबर 2026)

– 60.72%

➤ NSAP का नया नाम क्या है? (अक्टूबर 2026)

– प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

➤ अक्टूबर 2026 की MPC के बाद रेपो दर क्या है? (अक्टूबर 2026)

– 5.50%

➤ आईएमएफ डब्ल्यूईओ अक्टूबर 2026 का शीर्षक क्या है? (अक्टूबर 2026)

– रेज़िलिएंस अंडर स्ट्रेन, अर्जेंट चॉइसेज़

➤ पूर्वी तट का एकमात्र मेगा पोर्ट कौन-सा है? (अक्टूबर 2026)

– पारादीप

➤ पीजीआई-डी 2024-25 में कौन-सा जिला शीर्ष पर रहा? (अक्टूबर 2026)

– दीव

➤ SBI के बाद पेंशन फंड व्यवसाय में प्रवेश करने वाला दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (PSB) कौन-सा बना? (अक्टूबर 2026)

– बैंक ऑफ बड़ौदा

➤ वैश्विक एमपीआई कितने आयामों और संकेतकों का उपयोग करता है? (अक्टूबर 2026)

– 3 आयाम और 10 संकेतक

➤ 2026 में किस देश का एमपीआई सबसे अधिक है? (अक्टूबर 2026)

– चाड (0.517)

पर्यावरण

➤ अब तक कितने देशों ने BBNJ समझौते का अनुसमर्थन किया है? (जनवरी 2026)

– 83

➤ BBNJ समझौता किस कन्वेंशन का तीसरा क्रियान्वयन समझौता है? (जनवरी 2026)

– UNCLOS

➤ क्या भारत ने संधि का अनुसमर्थन किया है? (जनवरी 2026)

– नहीं, केवल हस्ताक्षर किए हैं

➤ SWM नियम, 2026 किस तिथि से पूर्ण रूप से लागू होंगे? (जनवरी 2026)

– 1 अप्रैल 2026

➤ इन्होंने किन नियमों का स्थान लिया? (जनवरी 2026)

– SWM नियम, 2016

➤ EBWGR का पूर्ण रूप क्या है? (जनवरी 2026)

– विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व

➤ किस शहर के मॉडल ने उसे लगातार 7 वर्षों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाया? (जनवरी 2026)

– इंदौर

➤ नए उत्सर्जन तीव्रता नियमों के अंतर्गत कितनी औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं? (जनवरी 2026)

– 208

➤ कौन-से नए क्षेत्र जोड़े गए? (जनवरी 2026)

– रिफाइनरियाँ, पेट्रोरसायन, वस्त्र, द्वितीयक एल्युमीनियम

➤ 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कटौती का भारत का NDC लक्ष्य क्या है? (जनवरी 2026)

– 45 प्रतिशत

➤ पर्यावरण संरक्षण निधि का राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा? (जनवरी 2026)

– 75 प्रतिशत

➤ हिमालयी हिमनद झीलों पर अध्ययन किस संस्थान ने किया? (जनवरी 2026)

– आईआईटी रुड़की

➤ 2023 के दक्षिण ल्होनक GLOF से कौन-सा बाँध नष्ट हुआ? (जनवरी 2026)

– तीस्ता-III

➤ केंद्रीय जल आयोग कितनी हिमनद झीलों की निगरानी करता है? (जनवरी 2026)

– 900 से अधिक

➤ CCUS के लिए बजट आवंटन? (फरवरी 2026)

– ₹20,000 करोड़

➤ भारत का CCUS कैप्चर लक्ष्य? (फरवरी 2026)

– 75 करोड़ टन प्रतिवर्ष (mtpa)

➤ CCU उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? (फरवरी 2026)

– आईआईटी बॉम्बे

➤ SIGHT का पूर्ण रूप क्या है? (फरवरी 2026)

– हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप

➤ हरित अमोनिया नीलामियाँ किस एजेंसी ने संचालित कीं? (फरवरी 2026)

– SECI

➤ अरुणाचल की आग से लड़ने वाला भारतीय वायुसेना का अभियान कौन-सा था? (फरवरी 2026)

– ऑपरेशन वालोंग

➤ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए FPM पर कौन-सा वित्तपोषण अनुपात लागू होता है? (फरवरी 2026)

– 90:10

➤ FSI आग की चेतावनी के लिए किन उपग्रह सेंसरों का उपयोग करता है? (फरवरी 2026)

– MODIS और VIIRS

➤ कौन-सा उद्यान मछुआरा बिल्ली का गढ़ पाया गया? (फरवरी 2026)

– काजीरंगा

➤ NGT ने रैट-होल खनन पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया? (फरवरी 2026)
– 2014

➤ अनुच्छेद 6 का कौन-सा खंड गैर-बाज़ार सहयोग से संबंधित है? (फरवरी 2026)
– अनुच्छेद 6.8

➤ अब नदी प्रदूषण की निगरानी कौन-सा निकाय करता है? (फरवरी 2026)
– राष्ट्रीय हरित अधिकरण

➤ CPCB द्वारा पहचाने गए प्रदूषित खंड? (फरवरी 2026)
– 296

➤ गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू हुई? (फरवरी 2026)
– 1986

➤ 2035 तक गैर-जीवाश्म क्षमता का नया लक्ष्य? (मार्च 2026)
– 60%

➤ 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता कटौती का लक्ष्य? (मार्च 2026)
– 2005 के स्तर से 47%

➤ भवसागर रेफरल केंद्र कहाँ स्थित है? (मार्च 2026)
– कोच्चि

➤ CMS COP15 कहाँ आयोजित हुआ? (मार्च 2026)
– कैम्पो ग्रांदे, ब्राज़ील

➤ NR-7 में रामसर स्थलों की संख्या? (मार्च 2026)
– 98

➤ NR-7 में उद्धृत बाघों की संख्या? (मार्च 2026)
– 3,682

➤ चंबल अभयारण्य किन तीन राज्यों में साझा है? (मार्च 2026)
– राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश

➤ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन-सा है? (मार्च 2026)
– सुखना आर्द्रभूमि

➤ जम्मू-कश्मीर की 697 झीलों में से कितनी लुप्त हुईं या सिकुड़ गईं? (अप्रैल 2026)
– 518

➤ होकरसर झील किस नाम से जानी जाती है? (अप्रैल 2026)
– कश्मीर की आर्द्रभूमियों की रानी

➤ दिल्ली की 2026 की योजना में नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के लिए ईंधन नीति क्या है? (अप्रैल 2026)
– नो PUC-नो फ्यूल

➤ नियोजित EV चार्जिंग बिंदुओं की संख्या? (अप्रैल 2026)
– 32,000

➤ COP33 किस वर्ष होना निर्धारित है? (अप्रैल 2026)
– 2028

➤ पहला वैश्विक स्टॉकटेक किस COP में हुआ था? (अप्रैल 2026)
– COP28, दुबई (2023)

➤ IPCC की कौन-सी रिपोर्ट 2028 तक आगे बढ़ाई जा सकती है? (अप्रैल 2026)
– AR7

➤ वैश्विक भूजल निकासी में भारत का हिस्सा कितना है? (अप्रैल 2026)
– 25%

➤ 2023 में भूजल निकासी का स्तर क्या था? (अप्रैल 2026)
– 59.26%

➤ भारत के पहले उपग्रह-टैग किए गए गंगा नरम कवच कछुए को कहाँ छोड़ा गया? (मई 2026)
– काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

➤ सफेद पेट वाले बगुले की IUCN स्थिति क्या है? (मई 2026)
– अत्यधिक संकटग्रस्त

➤ कैराकल (स्याहगोश) कहाँ देखा गया? (जून 2026)
– कूनो राष्ट्रीय उद्यान

➤ किस द्वीप पर विशाल पावोना क्लावस प्रवाल क्षेत्र है? (जून 2026)
– कदमत द्वीप

➤ किस स्टार्टअप ने 3D-प्रिंटेड चट्टान विकसित की? (जून 2026)
– त्वष्टा

➤ किस राज्य में तैरते सौर की क्षमता सबसे अधिक है? (जून 2026)
– महाराष्ट्र

➤ राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य क्या है? (जून 2026)
– 2030 तक 100 मिलियन टन

➤ ओडिशा की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का विकास कौन-सी कंपनी कर रही है? (जून 2026)
– BCGCL

➤ COP31 कहाँ आयोजित होगा?
– अंताल्या, तुर्किये

➤ क्या भारत वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का हस्ताक्षरकर्ता है? (जून 2026)
– नहीं

➤ ETI 2026 में भारत का स्थान क्या है? (जून 2026)
– 70वीं

➤ भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? (जून 2026)
– 103

➤ भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन-सा है? (जून 2026)
– सुंदरबन आर्द्रभूमि

➤ ABS की मूल संधि कौन-सा प्रोटोकॉल है? (जून 2026)
– नागोया प्रोटोकॉल

➤ भारत में किस प्रजाति का ABS हिस्सा सबसे अधिक है? (जून 2026)
– रक्त चंदन

➤ जीवनी औषधि से किस जनजाति को लाभ मिला? (जून 2026)
– कानी जनजाति

➤ मिनामाता अभिसमय कहाँ अपनाया गया था? (जून 2026)
– कुमामोतो, जापान

➤ UNEP का मुख्यालय कहाँ है? (जून 2026)
– नैरोबी

➤ स्टॉकहोम अभिसमय कब लागू हुआ? (जून 2026)
– 17 मई 2004

➤ तमिलनाडु के बाद सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला दूसरा राज्य कौन-सा है? (जून 2026)
– उत्तर प्रदेश (14)

➤ CAFE मानदंडों का प्रशासन कौन करता है? (जुलाई 2026)
– ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

➤ CAFE-III की प्रस्तावित प्रारंभ तिथि क्या है? (जुलाई 2026)
– 1 अप्रैल 2027

➤ M1 वाहनों में चालक के अतिरिक्त कितने यात्री बैठ सकते हैं? (जुलाई 2026)
– अधिकतम आठ

➤ भारत ने किस वर्ष 20% मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया? (जुलाई 2026)
– 2025

➤ 2018 के बाद इथेनॉल पर GST कितना है? (जुलाई 2026)
– 5%

➤ E100 ढाँचे को किस मंत्रालय ने मंज़ूरी दी? (जुलाई 2026)
– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

➤ हिमालयी पैंगोलिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? (जुलाई 2026)
– मैनिस ऑरिटा

➤ मालवी ऊँट का नाम किस क्षेत्र पर रखा गया है? (जुलाई 2026)
– मालवा

➤ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? (जुलाई 2026)
– अत्यधिक संकटग्रस्त

➤ किस राज्य में GIB राज्य पक्षी है? (जुलाई 2026)
– राजस्थान

➤ EPI 2026 में भारत का स्थान क्या था? (जुलाई 2026)
– 176वाँ

➤ EPI 2026 में कौन-सा देश शीर्ष पर रहा? (जुलाई 2026)
– एस्टोनिया

➤ प्रस्तावित ESA का कुल क्षेत्रफल कितना है? (जुलाई 2026)
– 56,825.7 वर्ग किमी

➤ ESA किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए जाते हैं? (जुलाई 2026)
– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

➤ किस समिति की रिपोर्ट आधार है? (जुलाई 2026)
– कस्तूरीरंगन समिति

➤ भारत के पहले भूतापीय कुएँ कहाँ स्थित हैं? (जुलाई 2026)
– पुगा घाटी, लद्दाख

➤ पुगा परियोजना को कौन-सी एजेंसी क्रियान्वित करती है? (जुलाई 2026)
– ONGC एनर्जी सेंटर

➤ वैश्विक भूतापीय गठबंधन किस COP में शुरू किया गया था? (जुलाई 2026)
– COP21

➤ भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं? (जुलाई 2026)
– 58

➤ बाघ निगरानी में कौन-सी सॉफ्टवेयर-आधारित प्रणाली सहायक है? (जुलाई 2026)
– M-STrIPES

➤ 2022 में भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? (जुलाई 2026)
– 3,682

➤ BHS की घोषणा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? (जुलाई 2026)
– धारा 37, जैविक विविधता अधिनियम 2002

➤ कृषि योग्य (खेती वाले) चावल का जंगली पूर्वज कौन है? (जुलाई 2026)
– ओराइज़ा रूफ़िपोगन

➤ बोरजुली किस जिले में स्थित है? (जुलाई 2026)
– सोनितपुर

➤ कौन-सा निकाय भारतीय कार्बन बाजार का प्रशासन करता है? (जुलाई 2026)
– ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

➤ CCTS के लक्ष्य किस इकाई पर आधारित हैं? (जुलाई 2026)
– प्रति इकाई उत्पादन उत्सर्जन तीव्रता

➤ 2026 के संशोधन के अंतर्गत SEIAA का स्थान कौन-सा निकाय लेता है? (जुलाई 2026)
– EIA पर स्थायी प्राधिकरण

➤ SEIAA और SEAC का नया कार्यकाल क्या है? (जुलाई 2026)
– चार वर्ष

➤ EIA अधिसूचना 2006 किस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई है? (जुलाई 2026)
– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

➤ UNCCD COP17 कहाँ आयोजित हुआ? (अगस्त 2026)
– उलानबाटर, मंगोलिया

➤ मेघालय का राज्य पशु कौन-सा है? (अगस्त 2026)
– धुंधला तेंदुआ

➤ भारत में लेपिडोप्टेरा की कितनी प्रजातियाँ हैं? (अगस्त 2026)
– 13,703

➤ आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्वों के निकट खनन के लिए कितनी बफ़र दूरी लागू होती है? (अगस्त 2026)
– 10 किमी

➤ उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन-सा था? (अगस्त 2026)
– आसन संरक्षण रिज़र्व

➤ NMCG किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? (अगस्त 2026)
– जल शक्ति मंत्रालय

➤ सक्रिय बाढ़ मैदान में कितनी बार बाढ़ आती है? (अगस्त 2026)
– कम से कम 5 वर्ष में एक बार

➤ भारत का 101वाँ रामसर स्थल कौन-सा है? (अगस्त 2026)
– ग्लॉ झील

➤ ग्लॉ झील किस अभयारण्य में स्थित है? (अगस्त 2026)
– कमलांग वन्यजीव अभयारण्य

➤ भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण का हिस्सा कितना है? (सितंबर 2026)
– 25.17%

➤ PRAMAAN प्रमाणन का संचालन कौन-सा संस्थान करता है? (सितंबर 2026)
– भारतीय वन प्रबंधन संस्थान

➤ 2030 तक भारत का बॉन चैलेंज लक्ष्य क्या है? (सितंबर 2026)
– 26 मिलियन हेक्टेयर

➤ प्रस्तावित लाल प्रविष्टि कितने समय तक रहेगी? (सितंबर 2026)
– 15 महीने

➤ 2 एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर कितना जुर्माना है? (सितंबर 2026)
– ₹5,000

➤ जुर्माना कितने दिनों के भीतर चुकाना होगा? (सितंबर 2026)
– 30 दिन

➤ वर्तमान नीतियों के अंतर्गत 2100 तक कितनी तापमान वृद्धि की संभावना है? (सितंबर 2026)
– लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस

➤ वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा 2030 तक मीथेन में कितने अंश की कटौती चाहती है? (सितंबर 2026)
– 2020 के स्तर से 30%

➤ क्या भारत वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का हस्ताक्षरकर्ता है? (सितंबर 2026)
– नहीं

➤ WCCB की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की गई? (सितंबर 2026)
– धारा 38Y

➤ ओरांगउटान की कौन-सी प्रजाति सबसे अधिक संकटग्रस्त वानर (ग्रेट एप) है? (सितंबर 2026)
– तापनुली

➤ WCCB किस अभिसमय को लागू करने में सहायता करता है? (सितंबर 2026)
– CITES

➤ विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति रिपोर्ट कौन-सा नेटवर्क प्रकाशित करता है? (सितंबर 2026)
– ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क

➤ कौन-से शैवाल प्रवालों के साथ सहजीवी रूप में रहते हैं? (सितंबर 2026)
– ज़ूज़ैन्थेली

➤ अब तक की सबसे व्यापक वैश्विक विरंजन घटना कौन-सी रही? (सितंबर 2026)
– 2023-25

➤ अक्टूबर 2026 तक IBCA के कितने देश सदस्य हैं? (अक्टूबर 2026)
– 29

➤ ISO 50001:2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन-सा है? (अक्टूबर 2026)
– वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह, तूतीकोरिन

भूगोल

➤ विशाखापत्तनम के बाद भारत का कौन-सा प्रमुख बंदरगाह 18 मीटर ड्राफ्ट प्रदान करता है? (जनवरी 2026)
– कामराजर बंदरगाह

➤ गेटवे ऑफ गुवाहाटी तैरता टर्मिनल कहाँ स्थित है? (जनवरी 2026)
– गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर

➤ 1963 के किस समझौते के तहत शक्सगाम घाटी चीन को सौंपी गई? (जनवरी 2026)
– चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता

➤ डिएगो गार्सिया किस द्वीपसमूह का हिस्सा है? (जनवरी 2026)
– चागोस द्वीपसमूह

➤ यूनाइटेड किंगडम डिएगो गार्सिया को कितने वर्षों के लिए पट्टे पर रखेगा? (जनवरी 2026)
– 99 वर्ष

➤ किस अधिकरण ने मंजूरी को बरकरार रखा? (फरवरी 2026)
– राष्ट्रीय हरित अधिकरण

➤ ग्रेट निकोबार पर कौन-सा PVTG रहता है? (फरवरी 2026)
– शोम्पेन

➤ यह द्वीप किस जलडमरूमध्य की ओर स्थित है? (फरवरी 2026)
– मलक्का जलडमरूमध्य

➤ थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में है? (फरवरी 2026)
– पश्चिमी अंटार्कटिका

➤ विश्व ग्लेशियर दिवस कब है? (फरवरी 2026)
– 21 मार्च

➤ भारत के अंटार्कटिक स्टेशनों के नाम बताइए। (फरवरी 2026)
– भारती और मैत्री

➤ भारत की पहली मेगावाट-घंटा (MWh) स्तर की वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी कहाँ स्थापित है? (फरवरी 2026)
– NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा

➤ भारत में सुनामी चेतावनी के लिए कौन-सी एजेंसी नोडल है? (फरवरी 2026)
– INCOIS

➤ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? (फरवरी 2026)
– बैरन द्वीप

➤ केरल में स्वेल सर्ज के लिए कौन-सा स्थानीय नाम प्रयोग किया जाता है? (फरवरी 2026)
– कल्लक्कडल

➤ सावलकोट परियोजना किस नदी पर है? (फरवरी 2026)
– चिनाब

➤ तुलबुल नौवहन परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? (फरवरी 2026)
– वूलर बैराज

➤ आदम का पुल किस जलडमरूमध्य में है? (मार्च 2026)
– पाक जलडमरूमध्य

➤ ईरान और कतर द्वारा साझा किया जाने वाला क्षेत्र कौन-सा है? (मार्च 2026)
– साउथ पार्स-नॉर्थ फील्ड

➤ कौन-सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? (मार्च 2026)
– लिपुलेख दर्रा

➤ कौन-सी रिफाइनरी भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोरसायन परिसर है? (अप्रैल 2026)
– पचपदरा रिफाइनरी

➤ भोपाल की कौन-सी झील अपर लेक के साथ भोज आर्द्रभूमि रामसर स्थल का हिस्सा है? (अप्रैल 2026)

– लोअर लेक

➤ किशाऊ बाँध किस नदी पर प्रस्तावित है? (जून 2026)

– टोंस

➤ किशाऊ बाँध कितना ऊँचा है? (जून 2026)

– 236 मीटर

➤ किशाऊ की स्थापित जलविद्युत क्षमता कितनी है? (जून 2026)

– 660 मेगावाट

➤ जल घटक की लागत में केंद्र का हिस्सा कितना है? (जून 2026)

– 90%

➤ कीरथाई-II किस प्रकार की परियोजना है? (जून 2026)

– रन-ऑफ-द-रिवर

➤ अरब सागर के ऊपर भारत तक नमी कौन-सी जेट धारा लाती है? (जून 2026)

– सोमाली जेट

➤ IOD का कौन-सा चरण अल नीनो को संतुलित करता है? (जून 2026)

– धनात्मक IOD

➤ अल नीनो किस परिसंचरण को कमजोर करता है? (जून 2026)

– वॉकर परिसंचरण

➤ भूकंपीय डबलेट क्या है? (जून 2026)

– समान तीव्रता के दो भूकंप जो तेजी से एक के बाद एक आते हैं

➤ वेनेज़ुएला के नीचे कौन-सी प्लेट सीमा स्थित है? (जून 2026)

– कैरिबियन-दक्षिण अमेरिकी

➤ कैलिफ़ोर्निया में कौन-सा भ्रंश है? (जून 2026)

– सैन एंड्रियास

➤ कौन-सा राज्य सबसे पहले वाणिज्यिक रूप से मचा चाय का उत्पादन करने वाला बना? (जुलाई 2026)

– असम

➤ मध्य प्रदेश का 27वाँ अभयारण्य कौन-सा है? (जुलाई 2026)

– ओंकारेश्वर अभयारण्य

➤ कौन-सी संस्था जैविक विविधता अधिनियम के अंतर्गत भारत की 21वीं अभिहित भंडार (डेज़िग्नेटेड रिपॉज़िटरी) बनी? (जुलाई 2026)

– प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, मिज़ोरम विश्वविद्यालय

➤ पाइझेन भ्रंश किस नदी पर स्थित परियोजना के नीचे है? (जुलाई 2026)

– ब्रह्मपुत्र

➤ किन प्लेटों की टक्कर से पाइझेन भ्रंश बना? (जुलाई 2026)

– भारतीय और यूरेशियाई

➤ शाहजहाँपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? (जुलाई 2026)

– जलालाबाद

➤ मोल्दोवा की राजधानी क्या है? (जुलाई 2026)

– चिसिनाउ

➤ बांग्लादेश का कौन-सा बंदरगाह सुंदरबन के निकट है? (जुलाई 2026)

– मोंगला

➤ 'इस्लास माल्विनास' किस विवाद से जुड़ा है? (जुलाई 2026)

– फ़ॉकलैंड द्वीप

➤ जापान का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन-सा है? (जुलाई 2026)

– ओकिनोटोरी द्वीप

➤ अरल सागर को कौन-सी नदियाँ पोषित करती हैं? (जुलाई 2026)

– अमु दरिया और सिर दरिया

➤ तेलंगाना में गोदावरी पर कौन-सा बाघ अभयारण्य (टाइगर रिज़र्व) स्थित है? (जुलाई 2026)

– कवल टाइगर रिज़र्व

➤ भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन-सी है? (जुलाई 2026)

– मानसबल झील

➤ नेयिंग परियोजना की क्षमता कितनी है? (जुलाई 2026)

– 1,000 मेगावाट

➤ नर्मदा का उद्गम कहाँ है? (जुलाई 2026)

– अमरकंटक

➤ कौन-सी सुरंग भारत की सबसे लंबी भूमिगत जल-परिवहन सुरंग है? (जुलाई 2026)

– स्लीमनाबाद सुरंग

➤ कोलंबिया भूकंप की तीव्रता कितनी थी? (अगस्त 2026)

– 7.4

➤ ज़ास्कर हिमनद का अध्ययन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? (अगस्त 2026)

– द क्रायोस्फियर

➤ शिपकी ला किस जिले में स्थित है? (अगस्त 2026)

– किन्नौर

➤ कौन-सी नदी लूनी की एकमात्र दाहिने तट की सहायक नदी है? (अगस्त 2026)

– जोजरी

➤ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा किस नदी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया? (अगस्त 2026)

– ताम्रपर्णी

➤ नेपाल की बाढ़ के पीछे किस पर्वत-समूह में हिमनद ध्वस्त हुआ? (अगस्त 2026)

– लांगटांग लिरुंग

➤ भारत ने कितने बेली पुलों के लिए सहायता की पेशकश की? (अगस्त 2026)

– 42

➤ लद्दाख की कौन-सी रामसर झील का हिमनदीय जल मोड़कर पुनरुद्धार किया जा रहा है? (सितंबर 2026)

– त्सो कर

➤ बखिरा झील किस जिले में स्थित है? (सितंबर 2026)

– संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश

➤ पंढरपुर में किस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है? (सितंबर 2026)

– भीमा

➤ अलकनंदा बेसिन में कितने लटकते हिमनद पाए गए? (सितंबर 2026)

– 219

➤ उत्तराखंड की पहली वास्तविक-समय GLOF प्रणाली कहाँ शुरू होगी? (सितंबर 2026)

– वसुंधरा ताल, चमोली

➤ GLOF का पूर्ण रूप क्या है? (सितंबर 2026)

– हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड)

➤ 2026 में औपचारिक रूप से मृत्युदंड समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन-सा है? (अक्टूबर 2026)

– लेबनान

➤ लद्दाख का आठवाँ जिला कौन-सा है? (अक्टूबर 2026)

– सांकू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

➤ स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किस संगठन की प्रयोगशाला ने किया? (जनवरी 2026)

– DRDO की DRDL

➤ स्क्रैमजेट किस गति पर कुशलता से कार्य करता है? (जनवरी 2026)

– मैक 5 से ऊपर

➤ स्क्रैमजेट सामान्यतः कौन-सा ईंधन उपयोग करता है? (जनवरी 2026)

– हाइड्रोजन

➤ PSLV-C62 मिशन PSLV की कौन-सी उड़ान थी? (जनवरी 2026)

– 64वीं

➤ निजी अंतरिक्ष गतिविधि के लिए नोडल एजेंसी कौन-सी संस्था है? (जनवरी 2026)

– IN-SPACe

➤ निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल में कितने उपग्रह होंगे? (जनवरी 2026)

– 12

➤ PSLV के दूसरे चरण में कौन-सा इंजन उपयोग होता है? (जनवरी 2026)

– विकास इंजन

➤ वित्त वर्ष 2025 में घरेलू रक्षा उत्पादन कितना रहा? (जनवरी 2026)

– लगभग ₹1.51 लाख करोड़

➤ किन दो राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारे हैं? (जनवरी 2026)

– उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु

➤ iDEX कब शुरू की गई? (जनवरी 2026)

– अप्रैल 2018

➤ प्रलय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? (जनवरी 2026)

– 150 से 500 किमी

➤ भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के रूप में 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में कौन-सी मिसाइल प्रदर्शित की गई? (जनवरी 2026)

– LR-AShM

➤ भारत में C-295 विमान कहाँ असेंबल किया जा रहा है? (जनवरी 2026)

– वडोदरा

➤ सूर्यास्त्र के लिए अनुबंध भागीदार कौन है? (जनवरी 2026)

– NIBE लिमिटेड

➤ सैन्य क्वांटम मिशन नीति रूपरेखा किसने जारी की? (जनवरी 2026)

– चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

➤ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का अनुमानित बजट कितना है? (जनवरी 2026)

– ₹6,000 करोड़

➤ कौन-सी क्वांटम तकनीक सैद्धांतिक रूप से अहैकेबल कुंजियाँ प्रदान करती है? (जनवरी 2026)

– क्वांटम कुंजी वितरण

➤ उपयोगकर्ता आधार की कौन-सी सीमा सत्यापन संबंधी दायित्व लागू करती है? (फरवरी 2026)

– 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता

➤ 2026 में किन नियमों में संशोधन किया गया? (फरवरी 2026)

– IT नियम, 2021

➤ SFDR का पूर्ण रूप क्या है? (फरवरी 2026)

– ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट

➤ इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? (फरवरी 2026)

– एकीकृत परीक्षण रेंज, ओडिशा तट

➤ INS अंजदीप का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया? (फरवरी 2026)

– GRSE, कोलकाता

➤ धर्म गार्डियन किस देश के साथ है? (फरवरी 2026)

– जापान

➤ MILAN क्या है? (फरवरी 2026)

– द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास

➤ LIGO-इंडिया कहाँ बनाया जाएगा? (फरवरी 2026)

– हिंगोली, महाराष्ट्र

➤ NLOT कहाँ स्थापित किया जाएगा? (फरवरी 2026)

– हानले, लद्दाख

➤ कौन-सा मिशन मॉन्स मूटन पर उतरेगा? (फरवरी 2026)

– चंद्रयान-4

➤ मॉन्स मूटन किस बेसिन के किनारे पर स्थित है? (फरवरी 2026)

– दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन

➤ चंद्रयान-4 कब नियोजित है? (फरवरी 2026)

– 2027

➤ भारत जेनएआई की क्रियान्वयन संस्था फ़ाउंडेशन कौन-सा IIT चलाता है? (फरवरी 2026)

– आईआईटी बॉम्बे

➤ इंडिया AI स्टैक में कितनी परतें हैं? (फरवरी 2026)

– पाँच

➤ युवा AI फॉर ऑल कौन-सा लक्ष्य निर्धारित करता है? (फरवरी 2026)

– 1 करोड़ नागरिकों के लिए AI साक्षरता

➤ किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया? (फरवरी 2026)
– केरल

➤ अंगदान की शीर्ष संस्था कौन-सी है? (फरवरी 2026)
– NOTTO

➤ DME प्रौद्योगिकी किस संस्थान ने विकसित की? (मार्च 2026)
– CSIR-NCL

➤ DART मिशन का लक्ष्य क्या था? (मार्च 2026)
– डिमॉर्फोस

➤ साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है? (मार्च 2026)
– 1930

➤ डार्क ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है? (मार्च 2026)
– क्लेरियन-क्लिपर्टन क्षेत्र

➤ भारत की तीसरी SSBN कौन-सी है? (अप्रैल 2026)
– आईएनएस अरिधमान

➤ कौन-सा सिद्धांत भारत के लिए SSBN को महत्वपूर्ण बनाता है? (अप्रैल 2026)
– परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति (No First Use)

➤ महासागर (MAHASAGAR) का पूर्ण रूप क्या है? (अप्रैल 2026)
– क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति

➤ किस जहाज़ का नाम बदलकर IOS सागर किया गया? (अप्रैल 2026)
– INS सुनयना

➤ आर्टेमिस II के चालक दल को किस अंतरिक्ष यान ने ले जाया? (अप्रैल 2026)
– ओरियन

➤ आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या (2026)? (अप्रैल 2026)
– 64

➤ BioE3 का पूर्ण रूप क्या है? (अप्रैल 2026)
– अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी

➤ BioE3 बजट का कितना हिस्सा पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित है? (अप्रैल 2026)
– 10%

➤ PFBR कहाँ स्थित है? (अप्रैल 2026)
– कलपक्कम, तमिलनाडु

➤ PFBR भारत के परमाणु कार्यक्रम के किस चरण की शुरुआत करता है? (अप्रैल 2026)
– चरण II

➤ 2047 तक लक्षित परमाणु क्षमता कितनी है? (अप्रैल 2026)
– 100 गीगावाट

➤ वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात कितना रहा? (अप्रैल 2026)
– ₹38,424 करोड़

➤ रक्षा निर्यात में DPSU की हिस्सेदारी कितनी है? (अप्रैल 2026)
– 54.84%

➤ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का परिव्यय कितना है? (अप्रैल 2026)
– ₹6,003.65 करोड़

➤ NQM के अंतर्गत QKD नेटवर्क की लक्षित लंबाई कितनी है? (अप्रैल 2026)
– 2,000 किमी

➤ क्वांटम वैली कहाँ बनाई जा रही है? (अप्रैल 2026)
– अमरावती

➤ क्वांटम संचार हब का नेतृत्व कौन-सा संस्थान करता है? (अप्रैल 2026)
– IIT मद्रास

➤ 2022 का QKD लिंक उत्तर प्रदेश के किन शहरों के बीच था? (अप्रैल 2026)
– प्रयागराज और विंध्याचल

➤ अमेरिकी महाद्वीपों में कुष्ठ रोग से मुक्त सत्यापित होने वाला पहला देश कौन-सा बना? (अप्रैल 2026)
– चिली

➤ तारा (TARA) को DRDO की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया? (मई 2026)
– रिसर्च सेंटर इमारत

➤ कौन-सी मिसाइल सी ईगल का स्थान लेती है? (मई 2026)
– NASM-SR

➤ किन दो परिषदों ने मिशन सेहत लॉन्च किया? (मई 2026)
– ICMR और ICAR

➤ SMILE को किस रॉकेट ने प्रक्षेपित किया? (मई 2026)
– वेगा-C

➤ विक्रम के हॉप की ऊँचाई कितनी थी? (मई 2026)
– लगभग 50 सेमी

➤ सेना की स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली को क्या कहा जाता है? (मई 2026)
– आकाशतीर

➤ किस एक्सप्रेसवे पर ELF अभ्यास किया गया? (मई 2026)
– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (सुल्तानपुर)

➤ कौन-सा मिशन राष्ट्रीय वायु रक्षा कवच का लक्ष्य रखता है? (मई 2026)
– सुदर्शन चक्र मिशन

➤ ऑप्टोSAR उपग्रह दृष्टि किस कंपनी ने बनाया? (मई 2026)
– गैलेक्सआई

➤ कौन-सी एजेंसी निजी अंतरिक्ष गतिविधि को अधिकृत करती है? (मई 2026)
– IN-SPACe

➤ हंगोर श्रेणी किस चीनी डिजाइन पर आधारित है? (मई 2026)
– टाइप 039A (युआन)

➤ कुल कितनी हंगोर पनडुब्बियाँ हैं? (मई 2026)
– 8

➤ JANANI किस पोर्टल का उन्नत रूप है? (मई 2026)
– RCH पोर्टल

➤ मधुमेह जाँच ढाँचा किस आयु तक लागू होता है? (मई 2026)
– 18 वर्ष

➤ मई 2026 के बाद भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत कितनी परियोजनाएँ स्वीकृत हैं? (मई 2026)
– 12

➤ स्काईकास्ट पहली बार कहाँ स्थापित किया गया है? (मई 2026)
– IGI हवाई अड्डा, नई दिल्ली

➤ अगला स्काईकास्ट कहाँ नियोजित है? (मई 2026)
– जेवर हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश

➤ अगले CDS कौन होंगे? (मई 2026)
– लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि

➤ प्रगति 2026 कहाँ आयोजित हुआ? (मई 2026)
– उमरोई, मेघालय

➤ वर्तमान प्रकोप किस इबोला स्ट्रेन के कारण हुआ है? (मई 2026)
– बुंदीबुग्यो

➤ किस टाइगर रिजर्व में CDV से मौतें हुईं? (मई 2026)
– कान्हा

➤ UMMID का पूर्ण रूप बताइए। (मई 2026)
– वंशानुगत विकारों के प्रबंधन की अनूठी पद्धतियाँ (Unique Methods of Management of Inherited Disorders)

➤ PCOS का नया नाम क्या रखा गया है? (मई 2026)
– PMOS

➤ भारत का BMD कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? (जून 2026)
– 1999

➤ किन इंटरसेप्टरों ने चरण-II परीक्षण पूरे किए? (जून 2026)
– AD-1 और AD-2

➤ कौन-सी अग्नि मिसाइल ICBM है? (जून 2026)
– अग्नि-V

➤ SIPRI 2026 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? (जून 2026)
– लगभग 190

➤ सैन्य व्यय में भारत का स्थान क्या है? (जून 2026)
– 5वाँ

➤ हथियार निर्यात में कौन-सा देश अग्रणी है? (जून 2026)
– अमेरिका

➤ तीनों पोत किस शिपयार्ड ने बनाए? (जून 2026)
– GRSE, कोलकाता

➤ S-400 सौदे का मूल्य क्या है? (जून 2026)
– 5.43 अरब डॉलर

➤ INS अग्रे की श्रेणी क्या है? (जून 2026)
– अर्णाला श्रेणी

➤ शुक्र ऑर्बिटर मिशन का वर्ष? (जून 2026)
– 2028

➤ भारत द्वारा प्रक्षेपित विदेशी उपग्रह? (जून 2026)
– 399

➤ LUPEX के लिए चंद्र सहयोग भागीदार? (जून 2026)
– JAXA

➤ नई फ्लेक्स-फ्यूल कार किस मिश्रण सीमा पर चल सकती है? (जून 2026)
– E20 से E100

➤ FFV में कौन-सा घटक ईंधन इंजेक्शन को समायोजित करता है? (जून 2026)
– ECU

➤ किस एल्कोहल को डीज़ल के साथ मिश्रित किया जा सकता है? (जून 2026)
– आइसोब्यूटेनॉल

➤ नेत्र AEW&C को कौन-सा विमान ले जाता है? (जून 2026)
– एम्ब्रेयर EMB-145I

➤ ब्रह्मोस की गति कितनी है? (जून 2026)
– 2.8 मैक

➤ कौन-सी मिसाइल निर्भय की उत्तराधिकारी है? (जून 2026)
– LRLACM

➤ IMI शाकनाशी किस एंज़ाइम को लक्षित करते हैं? (जून 2026)
– ALS

➤ JWST कहाँ परिक्रमा करता है? (जून 2026)
– लैग्रेंज बिंदु 2

➤ खावड़ा BESS की क्षमता कितनी है? (जून 2026)
– 3.37 GWh

➤ NGHM का परिव्यय कितना है? (जून 2026)
– ₹19,744 करोड़

➤ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? (जून 2026)
– जींद, हरियाणा

➤ 2035 तक मूल्य श्रृंखला का कितना आकार लक्षित है? (जून 2026)
– 120 से 150 अरब डॉलर

➤ किस निकाय ने सेमीकंडक्टर रोडमैप जारी किया? (जून 2026)
– नीति आयोग

➤ SPECS कौन-सा प्रोत्साहन प्रदान करता है? (जून 2026)
– 25 प्रतिशत पूंजीगत व्यय

➤ भारत का 2035 का जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य क्या है? (जुलाई 2026)
– 691 अरब डॉलर

➤ जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष के लिए कितना कोष आकार प्रस्तावित है? (जुलाई 2026)
– ₹50,000 करोड़

➤ भारत में 2025 में कितनी साइबर घटनाएँ दर्ज हुईं? (जुलाई 2026)
– 2.9 मिलियन

➤ क्विशिंग का क्या अर्थ है? (जुलाई 2026)
– QR-कोड फिशिंग

➤ कुशा का परीक्षण कहाँ से किया गया? (जुलाई 2026)
– APJ अब्दुल कलाम द्वीप

➤ बहु-स्तरीय वायु रक्षा के लिए मिशन? (जुलाई 2026)
– मिशन सुदर्शन चक्र

➤ भारत की पहली GAGAN-आधारित लैंडिंग किस हवाई अड्डे पर संचालित की गई? (जुलाई 2026)
– उदयपुर

➤ कौन-सी एजेंसियाँ संयुक्त रूप से GAGAN को लागू करती हैं? (जुलाई 2026)
– ISRO और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

➤ आईएनएस महेंद्रगिरि को कहाँ कमीशन किया गया? (जुलाई 2026)
– विशाखापत्तनम

➤ आईएनएस मालवण की श्रेणी क्या है? (जुलाई 2026)
– माहे श्रेणी ASW-SWC

➤ आईएनएस मालवण का आदर्श वाक्य क्या है? (जुलाई 2026)
– साइलेंट क्लॉज़ (मौन पंजे)

➤ आईएनएस महेंद्रगिरि प्रोजेक्ट 17A का कौन-सा पोत है? (जुलाई 2026)
– छठा

➤ SOLVE का पूर्ण रूप क्या है? (जुलाई 2026)
– प्रयोगों के लिए उप-कक्षीय प्रक्षेपण यान (सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स)

➤ SOLVE परीक्षणों की ऊँचाई सीमा? (जुलाई 2026)
– 10-17 किमी

➤ गगनयान प्रणाली में पैराशूटों की संख्या? (जुलाई 2026)
– 10

➤ WAICO का मुख्यालय कहाँ है? (जुलाई 2026)
– शंघाई

➤ कौन-सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का नेतृत्व करती है? (जुलाई 2026)
– ITU

➤ IN-SPACe का मुख्यालय कहाँ है? (जुलाई 2026)
– अहमदाबाद

➤ ISRO के किस परीक्षण ने स्वायत्त रनवे लैंडिंग का प्रदर्शन किया? (जुलाई 2026)
– RLV-LEX

➤ आयुर्वेद WHO के किस वर्गीकरण में शामिल है? (जुलाई 2026)
– ICD-11

➤ 2023 में भारत का आयुर्वेद निर्यात मूल्य कितना है? (जुलाई 2026)
– 2.16 अरब डॉलर

➤ नाभिकीय हाइड्रोजन सुविधा में कौन-सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? (जुलाई 2026)
– कॉपर-क्लोरीन ताप-रासायनिक

➤ यह सुविधा कहाँ स्थित है? (जुलाई 2026)
– IGCAR, कलपक्कम

➤ भारत का पहला स्वीकृत डेंगू टीका कौन-सा है? (जुलाई 2026)
– क्यूडेंगा

➤ क्यूडेंगा की खुराकों के बीच कितना अंतर होता है? (जुलाई 2026)
– 3 माह

➤ ज़ायनिच किसने बनाई? (जुलाई 2026)
– वॉकहार्ट

➤ क्यूडेंगा टीका किसने विकसित किया? (जुलाई 2026)
– टाकेडा जीएमबीएच

➤ भारत में क्यूडेंगा को किस निकाय ने मंज़ूरी दी? (जुलाई 2026)
– सीडीएससीओ

➤ भारत में स्वीकृत पहला डेंगू टीका कौन-सा है? (जुलाई 2026)
– क्यूडेंगा (टाकेडा)

➤ अस्त्र मिसाइलों का आयात करने वाला पहला देश कौन-सा था? (जुलाई 2026)
– इंडोनेशिया

➤ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का मार्ग क्या है? (जुलाई 2026)
– जींद-सोनीपत

➤ किस प्रकार का फ्यूल सेल प्रयुक्त है? (जुलाई 2026)
– PEMFC

➤ बैटरी का प्रकार क्या है? (जुलाई 2026)
– लिथियम फेरो फॉस्फेट

➤ विक्रम-1 किस कंपनी ने बनाया? (जुलाई 2026)
– स्काईरूट एयरोस्पेस

➤ विक्रम-1 के पहले मिशन का नाम बताइए। (जुलाई 2026)
– आगमन

➤ SSO तक पेलोड? (जुलाई 2026)
– 260 किग्रा

➤ 2030 तक MMR के लिए SUMAN का लक्ष्य क्या है? (जुलाई 2026)
– 70 से कम

➤ AMB किस ढाँचे तक विस्तारित हुआ है? (जुलाई 2026)
– 7x7x7

➤ भारत आर्टेमिस समझौते का कौन-सा हस्ताक्षरकर्ता था? (अगस्त 2026)
– 27वाँ

➤ मून बेस कहाँ स्थापित किया जाना है? (अगस्त 2026)
– चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट

➤ जीसैट-1ए को कौन-सा रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? (अगस्त 2026)
– जीएसएलवी-एफ17

➤ जीसैट-1ए ने किस पूर्ववर्ती उपग्रह का स्थान लिया? (अगस्त 2026)
– जीसैट-1 (ईओएस-03)

➤ एवरेस्ट कौन-सा ईंधन और ऑक्सीकारक उपयोग करता है? (अगस्त 2026)
– मीथेन और तरल ऑक्सीजन

➤ इन-स्पेस पुनःप्रवेश दिशानिर्देशों में अधिकतम अपेक्षित हताहत जोखिम कितना है? (अगस्त 2026)
– 10,000 में 1 से कम

➤ भारत का पहला स्वदेशी एएसएफ टीका किस संस्थान ने विकसित किया? (अगस्त 2026)
– आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल

➤ श्रवाणी कितनी भाषाओं को कवर करता है? (अगस्त 2026)
– 65

➤ अग्नि-4 की मारक क्षमता कितनी है? (अगस्त 2026)
– 4,000 किमी तक

➤ छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में कितनी मदें हैं? (अगस्त 2026)
– 405

➤ निस्तार श्रेणी का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन-सा है? (सितंबर 2026)
– आईएनएस निपुण

➤ आईएनएस निपुण को कहाँ कमीशन किया गया? (सितंबर 2026)
– मुंबई नौसेना डॉकयार्ड

➤ आईएनएस निपुण किस कमान को मज़बूत करेगा? (सितंबर 2026)
– पश्चिमी नौसेना कमान

➤ कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की कौन-सी धारा कंप्यूटर-जनित कृतियों के लेखकत्व से संबंधित है? (सितंबर 2026)
– धारा 2(d)(vi)

➤ कॉपीराइट कार्यालय के हालिया निर्णय का विषय कौन-सी एआई प्रणाली थी? (सितंबर 2026)

– डेबस (DABUS)

➤ भारत में मौलिकता के लिए न्यूनतम रचनात्मकता की कसौटी किस मामले ने निर्धारित की? (सितंबर 2026)

– ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डी.बी. मोदक

➤ ऑस्ट्रेल बेसिन की पहचान किस संस्थान ने की? (सितंबर 2026)

– भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला

➤ चंद्रयान-1 के किस उपकरण ने आँकड़े उपलब्ध कराए? (सितंबर 2026)

– मून मिनरलॉजी मैपर (M3)

➤ बेसिन में कितने बेसाल्ट तालाब हैं? (सितंबर 2026)

– 248

➤ तृष्णा में कौन-सी दो एजेंसियाँ साझेदार हैं? (सितंबर 2026)

– इसरो और सीएनईएस

➤ सागर मंथन को किस शिपयार्ड ने लॉन्च किया? (सितंबर 2026)

– गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स

➤ सागर मंथन की अनुसंधान गहराई कितनी है? (सितंबर 2026)

– 6 किमी तक

➤ वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किस विभाग ने विकसित किया? (सितंबर 2026)

– दूरसंचार विभाग

➤ एफआरआई की तीन जोखिम श्रेणियाँ कौन-सी हैं? (सितंबर 2026)

– मध्यम, उच्च, अत्यंत उच्च

➤ एफआरआई जोखिम संकेत कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म साझा करता है? (सितंबर 2026)

– डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म

➤ राष्ट्रीय औषधि संग्रह (नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया) कौन-सा निकाय प्रकाशित करता है? (सितंबर 2026)

– भारतीय फार्माकोपिया आयोग

➤ एनएफआई 2026 में कितने औषधि मोनोग्राफ हैं? (सितंबर 2026)

– 653

➤ मटेरियोविजिलेंस किन उत्पादों को कवर करता है? (सितंबर 2026)

– चिकित्सा उपकरण

➤ 20 अस्पतालों वाला एएमआर अध्ययन किस निकाय ने किया? (सितंबर 2026)

– आईसीएमआर

➤ अध्ययन में किन जीवाणुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया? (सितंबर 2026)

– कार्बापेनेम-प्रतिरोधी ग्राम-ऋणात्मक जीवाणु

➤ भारत की वर्तमान एएमआर योजना का नाम क्या है? (सितंबर 2026)

– एनएपी-एएमआर 2.0

➤ एनएपी-एएमआर 2.0 की अवधि क्या है? (सितंबर 2026)

– 2025-2029

➤ भारत का आधिकारिक समय कौन-सी संस्था बनाए रखती है? (सितंबर 2026)

– सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

➤ यूटीसी के सापेक्ष आईएसटी क्या है? (सितंबर 2026)

– यूटीसी जमा 5 घंटे 30 मिनट

➤ समय प्रसारण में कौन-सी भारतीय उपग्रह प्रणाली सहायता करती है? (सितंबर 2026)

– नाविक

➤ आईएसटी का आधार कौन-सा देशांतर है? (सितंबर 2026)

– 82 अंश 30 मिनट पूर्व

संस्कृति एवं पर्यटन

➤ महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर पहली बार किस वर्ष आक्रमण किया? (जनवरी 2026)

– 1026 ई.

➤ 1947 के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण किसने आरंभ किया? (जनवरी 2026)

– सरदार वल्लभभाई पटेल

➤ वर्तमान सोमनाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली का है? (जनवरी 2026)

– मारु-गुर्जर

➤ कौन-सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है? (फरवरी 2026)

– 2026

➤ संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2029 का केंद्र बिंदु क्या है? (फरवरी 2026)

– क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा

➤ ओल चिकी लिपि किसने विकसित की? (फरवरी 2026)

– पंडित रघुनाथ मुर्मू

➤ संथाली को आठवीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? (फरवरी 2026)

– 2003

➤ बस्तर पंडुम कहाँ आयोजित होता है? (फरवरी 2026)

– छत्तीसगढ़

➤ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? (फरवरी 2026)

– 28 फरवरी

➤ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब पड़ता है? (फरवरी 2026)

– 23 अगस्त

➤ ओल चिकी की रचना किसने की? (फरवरी 2026)

– रघुनाथ मुर्मू

➤ किस संशोधन द्वारा संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया? (फरवरी 2026)

– 92वाँ संशोधन, 2003

➤ किस विभाग ने भारत जीआई की शुरुआत की? (फरवरी 2026)

– DPIIT

➤ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी (डॉकयार्ड) है? (फरवरी 2026)

– लोथल

➤ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन-सा है? (फरवरी 2026)

– सुतकागेन डोर

➤ सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में दुर्ग नहीं था? (फरवरी 2026)

– चन्हूदड़ो

➤ मिज़ोरम में कौन-सा उत्सव झूम की सफाई के अंत का प्रतीक है? (मार्च 2026)
– चपचार कुट

➤ विश्व जल दिवस 2026 का विषय क्या है? (मार्च 2026)
– जल और लैंगिकता

➤ 21 मार्च को वनों के लिए कौन-सा दिवस मनाया जाता है? (मार्च 2026)
– अंतरराष्ट्रीय वन दिवस

➤ पिपरहवा अवशेषों का स्थल किस जिले में स्थित है? (अप्रैल 2026)
– सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश

➤ 1898 में पिपरहवा अवशेषों की खोज किसने की? (अप्रैल 2026)
– विलियम क्लैक्सटन पेप्पे

➤ हाथीगुम्फा अभिलेख किन गुफाओं में है? (अप्रैल 2026)
– उदयगिरि-खंडगिरि (ओडिशा)

➤ कौन-सी गुफाएँ आजीविक संप्रदाय से जुड़ी हैं? (अप्रैल 2026)
– बराबर की गुफाएँ

➤ गुफा 5 में वराह की मूर्ति कहाँ मिलती है? (अप्रैल 2026)
– उदयगिरि गुफाएँ, विदिशा

➤ किस जिले की बाँसुरी को 2024 में जीआई टैग मिला? (मई 2026)
– पीलीभीत

➤ जीआई टैग में कौन-सा राज्य अग्रणी है? (मई 2026)
– तमिलनाडु (56)

➤ पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है? (मई 2026)
– आंध्र प्रदेश

➤ रू-सोम पुल कौन-सा समुदाय बनाता है? (मई 2026)
– लेप्चा

➤ किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया? (मई 2026)
– 1026

➤ हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? (जून 2026)
– 30 मई

➤ उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया? (जून 2026)
– जुगल किशोर शुक्ल

➤ शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन-सा है? (जून 2026)
– अशोक चक्र

➤ ज्ञान भारतम मिशन का परिव्यय कितना है? (जून 2026)
– ₹491.66 करोड़

➤ पांडुलिपि के लिए आयु का मानदंड क्या है? (जून 2026)
– कम से कम 75 वर्ष

➤ भारत की सबसे प्राचीन पांडुलिपियाँ कौन-सी हैं? (जून 2026)
– गिलगित पांडुलिपियाँ

➤ झारखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिले? (जून 2026)
– 11

➤ केसरिया कलाकंद किस नगर से जुड़ा है? (जून 2026)
– झुमरी तिलैया

➤ डोकरा की तकनीक? (जून 2026)
– लुप्त-मोम ढलाई (लॉस्ट-वैक्स कास्टिंग)

➤ राखीगढ़ी कहाँ है? (जून 2026)
– हरियाणा

➤ मृद्भांड भेंटों की पहले की सर्वाधिक संख्या? (जून 2026)
– 22

➤ उत्खनन करने वाली एजेंसी? (जून 2026)
– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

➤ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय क्या है? (जून 2026)
– स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग

➤ विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 किस भू-दृश्य पर केंद्रित है? (जून 2026)
– चारागाह भूमियाँ

➤ 1926 में नर्तकी की खोज करने वाली खुदाई का नेतृत्व किसने किया? (जून 2026)
– जॉन मार्शल

➤ पुरोहित-राजा की मूर्ति किस पदार्थ की है? (जून 2026)
– सेलखड़ी

➤ बूस्ट्रोफेडन लेखन क्या है? (जून 2026)
– दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ क्रमिक रूप से बदलती पंक्तियाँ

➤ राजस्थान के किस शिल्प को जीआई टैग मिला? (जुलाई 2026)
– जोधपुर मोजड़ी

➤ जोधपुर मोजड़ी कौन-सा समुदाय बनाता है? (जुलाई 2026)
– जिंगर

➤ जीआई रजिस्ट्री कहाँ स्थित है? (जुलाई 2026)
– चेन्नई

➤ स्पीति सीबकथॉर्न का स्थानीय नाम? (जुलाई 2026)
– छरमा

➤ सीबकथॉर्न की ऊँचाई सीमा? (जुलाई 2026)
– 2,500-4,500 मीटर

➤ हड़प्पा के पतन के अध्ययन के लिए किस झील की तलछट का अध्ययन किया गया? (जुलाई 2026)
– देवरिया ताल

➤ सबसे पूर्वी हड़प्पाई स्थल कौन-सा है? (जुलाई 2026)
– आलमगीरपुर

➤ संत रविदास का जन्मस्थान? (जुलाई 2026)
– वाराणसी

➤ आदि ग्रंथ में उनके पदों की संख्या? (जुलाई 2026)
– लगभग 41

➤ 650वें वर्ष के अभियान का नाम? (जुलाई 2026)
– समरस्य संकल्प अभियान

➤ प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? (अगस्त 2026)
– हरिषेण

➤ कौन-सा अभिलेख कुडवोलई प्रणाली का उल्लेख करता है? (अगस्त 2026)
– उत्तरमेरूर अभिलेख

➤ सबसे प्राचीन ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख कौन-सा है? (अगस्त 2026)
– सोहगौरा ताम्रपत्र

➤ विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? (अगस्त 2026)
– 12 अगस्त

➤ अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को पड़ता है? (अगस्त 2026)
– 29 जुलाई

➤ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? (अगस्त 2026)
– पिंगली वेंकैया

➤ गोपबंधु दास ने 1919 में कौन-सा समाचार पत्र शुरू किया? (अगस्त 2026)
– द समाज

➤ डोगरी को किस वर्ष आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया? (सितंबर 2026)
– 2003

➤ नामे डोगरा अक्खर किस लिपि से व्युत्पन्न है? (सितंबर 2026)
– टाकरी

➤ किस शासक के सुधारों से नामे डोगरा अक्खर लिपि का विकास हुआ? (सितंबर 2026)
– महाराजा रणबीर सिंह

➤ शेखावाटी की यूनेस्को संभावित सूची में कितने कस्बे शामिल हैं? (सितंबर 2026)
– 14

➤ राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को कौन-सा अधिनियम संरक्षण देता है? (सितंबर 2026)
– प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

➤ 1213 ईस्वी में रामप्पा मंदिर का निर्माण किसने कराया? (सितंबर 2026)
– रेचर्ला रुद्र

➤ 15 सितंबर को कौन-सा संयुक्त राष्ट्र दिवस पड़ता है? (अक्टूबर 2026)
– अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस

➤ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? (अक्टूबर 2026)
– 10 अक्टूबर

खेल, पुरस्कार एवं रिपोर्ट

➤ TIFF प्लैटफ़ॉर्म पुरस्कार 2026 किस भारतीय फ़िल्म ने जीता? (जनवरी 2026)
– आंग

➤ नए MoSPI लोगो की टैगलाइन क्या है? (जनवरी 2026)
– विकास के लिए आँकड़े

➤ कितने पद्म पुरस्कारों को मंज़ूरी दी गई? (जनवरी 2026)
– 131

➤ किस मामले में निर्णय दिया गया कि पद्म पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं? (जनवरी 2026)
– बालाजी राघवन बनाम भारत संघ

➤ सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन-सा है? (जनवरी 2026)
– अशोक चक्र

➤ प्रति वर्ष पद्म पुरस्कारों की अधिकतम संख्या? (जनवरी 2026)
– 120

➤ 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स कहाँ आयोजित हुए? (जनवरी 2026)
– टोक्यो, जापान (नवंबर 2025)।

➤ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन-सी संस्था प्रकाशित करती है? (जनवरी 2026)
– विश्व बैंक

➤ GEP में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर? (जनवरी 2026)
– 7.2 प्रतिशत

➤ UNCTAD के अनुसार 2025 में भारत में FDI प्रवाह? (जनवरी 2026)
– 47 अरब डॉलर

➤ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? (जनवरी 2026)
– ILO

➤ KIUG 2025 के शुभंकर कौन-से थे? (फरवरी 2026)
– दो ऊँट, खम्मा और घणी।

➤ ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 किसने जीता? (फरवरी 2026)
– रूबल नागी

➤ पुरस्कार राशि कितनी है? (फरवरी 2026)
– 10 लाख डॉलर

➤ किस मणिपुरी फिल्म ने बाफ्टा जीता? (फरवरी 2026)
– बूंग

➤ मृत्युदंड पर रिपोर्ट किसने जारी की? (फरवरी 2026)
– स्क्वायर सर्कल क्लिनिक

➤ दिसंबर 2025 में कितने व्यक्ति मृत्युदंड की प्रतीक्षा में थे? (फरवरी 2026)
– 574

➤ CPI 2025 में भारत की रैंक क्या थी? (फरवरी 2026)
– 91

➤ CPI 2025 में कौन-सा देश शीर्ष पर रहा? (फरवरी 2026)
– डेनमार्क

➤ एशिया पावर इंडेक्स कौन-सा संस्थान तैयार करता है? (फरवरी 2026)
– लोवी इंस्टीट्यूट

➤ राजाजी ने 1959 में किस पार्टी की स्थापना की? (फरवरी 2026)
– स्वतंत्र पार्टी

➤ राजाजी ने 1930 में दक्षिण में कौन-सी यात्रा का नेतृत्व किया? (फरवरी 2026)
– त्रिची से वेदारण्यम

➤ उन्हें भारत रत्न कब मिला? (फरवरी 2026)
– 1954

➤ महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? (मार्च 2026)
– भारत, दक्षिण अफ्रीका को हराकर।

➤ भारत ने कितने टी20 विश्व कप जीते हैं? (मार्च 2026)
– तीन, 2026 की जीत के बाद।

➤ 98वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार किस फ़िल्म ने जीता? (मार्च 2026)
– वन बैटल आफ्टर अनदर

➤ खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान वाला देश? (मार्च 2026)
– आइसलैंड

➤ पॉली उमरीगर अवार्ड 2024-25 किसे मिला? (मार्च 2026)
– शुभमन गिल।

➤ लॉरियस स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2026 किसने जीता? (मार्च 2026)
– आर्यना सबालेंका।

➤ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर? (मार्च 2026)
– मोरवीर

➤ 'फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी' किसने लिखी? (मार्च 2026)
– पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे

➤ 'एम. एस. स्वामीनाथन: द मैन हू फेड इंडिया' के लेखक कौन हैं? (मार्च 2026)
– प्रियम्बदा जयकुमार

➤ ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसने जीता? (मार्च 2026)
– आर. वैरामुथु

➤ सरस्वती सम्मान की नकद पुरस्कार राशि? (मार्च 2026)
– ₹15 लाख

➤ इब्राहिमपट्टी, बलिया में कौन-से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? (अप्रैल 2026)
– चंद्रशेखर

➤ प्रत्येक मुख्य ब्रेकथ्रू पुरस्कार की राशि? (अप्रैल 2026)
– 30 लाख डॉलर

➤ भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 में कौन-सा ब्रांड शुरू किया गया? (अप्रैल 2026)
– RISA

➤ सुधा मूर्ति की कौन-सी पुस्तक संसद के भित्तिचित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास बताती है? (अप्रैल 2026)
– टाइड्स ऑफ़ टाइम

➤ 'व्हेन ऑडिट मैटर्स' का संपादन किसने किया? (अप्रैल 2026)
– विनोद राय, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

➤ NCRB के अनुसार 2024 में साइबर अपराध कितने प्रतिशत बढ़ा? (मई 2026)
– 17.9 प्रतिशत

➤ किस कानून में चोट के वर्गीकरण में बदलाव से अपराध के आँकड़े घटे? (मई 2026)
– भारतीय न्याय संहिता, 2023

➤ 2024 में भारत की आत्महत्या दर प्रति लाख कितनी थी? (मई 2026)
– 12.2

➤ जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनीं? (मई 2026)
– साने ताकाइची

➤ 2026 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कीर स्टार्मर का उत्तराधिकारी कौन बना? (मई 2026)
– एंडी बर्नहम

➤ किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है? (मई 2026)
– गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार

➤ भारत के 94वें ग्रैंडमास्टर कौन थे? (मई 2026)
– मयंक चक्रवर्ती

➤ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेल अधिभोग सर्वाधिक था? (मई 2026)
– दिल्ली (194.6%)

➤ भारत में जेल सांख्यिकी कौन प्रकाशित करता है? (मई 2026)
– NCRB

➤ भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025 कौन-सा संस्करण है? (मई 2026)
– 27वाँ

➤ 2023 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य? (मई 2026)
– अरुणाचल प्रदेश (1085)

➤ आईएसएल 2025-26 किसने जीता? (मई 2026)
– ईस्ट बंगाल एफसी, पहली बार।

➤ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य ने जीते? (मई 2026)
– कर्नाटक

➤ कितनी पंचायतों का चयन किया गया? (मई 2026)
– 42

➤ नियामक के रूप में PARAKH का क्या अर्थ है? (मई 2026)
– NCERT के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक

➤ कितने स्कूलों में नामांकन शून्य है? (मई 2026)
– लगभग 7,993

➤ हाल ही में कौन-सा राज्य AB-PMJAY में शामिल हुआ? (जून 2026)
– पश्चिम बंगाल

➤ प्रति परिवार वार्षिक कवर कितना है? (जून 2026)
– ₹5 लाख

➤ कौन-सा प्राधिकरण PM-JAY को क्रियान्वित करता है? (जून 2026)
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

➤ NFHS-6 के लिए नोडल एजेंसी कौन-सा संस्थान है? (जून 2026)
– IIPS, मुंबई

➤ NFHS-6 में कुल प्रजनन दर कितनी है? (जून 2026)
– 2.0

➤ NFHS-6 में कितने जिले कवर किए गए? (जून 2026)
– 715

➤ NFHS-6 में बौनेपन का आँकड़ा? (जून 2026)
– 29.3 प्रतिशत (35.5 से)

➤ NFHS-6 के कवरेज से कौन-सा राज्य बाहर रखा गया? (जून 2026)
– मणिपुर

➤ PMSMA किस दिन निःशुल्क प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) प्रदान करता है? (जून 2026)
– प्रत्येक माह की 9 तारीख

➤ SRS 2022-24 के अनुसार भारत की MMR (मातृ मृत्यु अनुपात) क्या है? (जून 2026)
– 87

➤ कितने ABHA खाते मौजूद हैं? (जून 2026)
– 90 करोड़ से अधिक

➤ QS 2027 में भारतीय संस्थान कितने हैं? (जून 2026)
– 52

➤ सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान कौन-सा है? (जून 2026)
– IIT दिल्ली (118वाँ)

➤ वैश्विक प्रथम स्थान? (जून 2026)
– MIT

➤ टिम कुक के बाद एप्पल के CEO कौन बने? (जून 2026)
– जॉन टर्नस

➤ आईपीएल 2026 किसने जीता? (जून 2026)
– रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।

➤ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? (जून 2026)
– रणधीर सिंह

➤ शिक्षा व्यय के लिए NEP का लक्ष्य क्या है? (जून 2026)
– GDP का 6 प्रतिशत

➤ कितने DIET को उन्नत किया जाएगा? (जून 2026)
– 613

➤ NTF का गठन किस मामले में किया गया था? (जून 2026)
– अमित कुमार बनाम भारत संघ

➤ ITLOS के न्यायाधीशों की संख्या? (जून 2026)
– 21

➤ FATF के पहले भारतीय उपाध्यक्ष कौन हैं? (जून 2026)
– विवेक अग्रवाल

➤ ITLOS का मुख्यालय कहाँ है? (जून 2026)
– जर्मनी

➤ छठे एशियाई बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुए? (जून 2026)
– सान्या, चीन (2026)।

➤ 2025 के अंत तक कितने लोग विस्थापित थे? (जून 2026)
– 11.78 करोड़ (117.8 मिलियन)

➤ कौन-सा समूह सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी है? (जून 2026)
– रोहिंग्या

➤ UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? (जून 2026)
– जिनेवा

➤ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का उत्तराधिकारी कौन है? (जून 2026)
– लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ

➤ NDA की कितनी महिला अधिकारियों को कमीशन मिला? (जून 2026)
– 17

➤ NDA के किस पाठ्यक्रम में पहली महिलाएँ थीं? (जून 2026)
– 148वाँ

➤ CWG 2026 की मेज़बानी? (जुलाई 2026)
– ग्लासगो

➤ 2026 में खेलों की संख्या? (जुलाई 2026)
– 10

➤ 1930 में पहली बार किस रूप में आयोजित हुए? (जुलाई 2026)
– ब्रिटिश साम्राज्य खेल

➤ 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की जूरी के अध्यक्ष कौन थे? (जुलाई 2026)
– जयराज

➤ 2025 में भारत की अंतर्वाह FDI रैंक क्या थी? (जुलाई 2026)
– 11वीं

➤ विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट कौन-से दो संस्थान प्रकाशित करते हैं? (जुलाई 2026)
– WIPO और लुइस बिज़नेस स्कूल

➤ 2022 और 2026 में लगातार विश्व कपों में गोल्डन बूट किसने जीता? (जुलाई 2026)
– किलियन एम्बाप्पे

➤ फीफा विश्व कप 2026 किसने जीता? (जुलाई 2026)
– स्पेन, जिसने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया।

➤ 2026 के फीफा विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? (जुलाई 2026)
– 48 टीमें, जिसकी मेज़बानी कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका ने की।

➤ फील्ड्स मेडल कितने समय बाद दिया जाता है? (जुलाई 2026)
– चार वर्ष

➤ तीसरी महिला फील्ड्स मेडलिस्ट? (जुलाई 2026)
– हांग वांग

➤ फील्ड्स मेडल के लिए आयु सीमा? (जुलाई 2026)
– 40 वर्ष से कम

➤ 2023-24 में GDP के अनुपात में भारत का GERD कितना है? (जुलाई 2026)
– 0.84 प्रतिशत

➤ RDI कोष का आकार कितना है? (जुलाई 2026)
– ₹1 लाख करोड़

➤ समुद्र प्रदक्षिणा में प्रयुक्त पोत? (जुलाई 2026)
– IASV त्रिवेणी

➤ लगे दिन? (जुलाई 2026)
– 314

➤ तय की गई दूरी? (जुलाई 2026)
– लगभग 25,500 समुद्री मील

➤ 60वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? (जुलाई 2026)
– आर. वैरामुथु

➤ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए? (अगस्त 2026)
– 1952

➤ भारत का शांतिकाल का दूसरा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन-सा है? (अगस्त 2026)
– कीर्ति चक्र

➤ सनशाइन डबल क्या है? (अगस्त 2026)
– एक ही वर्ष में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जीतना।

➤ पीडब्ल्यूएल 2026 किसने जीती? (अगस्त 2026)
– हरियाणा थंडर्स।

➤ राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन-सी ट्रॉफी जीती? (अगस्त 2026)
– विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी।

➤ महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री कौन हैं? (अगस्त 2026)
– सुनेत्रा पवार

➤ विज्ञान रत्न 2025 मरणोपरांत किसे प्राप्त हुआ? (अगस्त 2026)
– जयंत विष्णु नार्लीकर

➤ 2026 में FIDE के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? (अगस्त 2026)
– विश्वनाथन आनंद

➤ स्क्वैश विश्व कप 2025 किसने जीता? (अगस्त 2026)
– भारत, अपना पहला खिताब, चेन्नई में।

➤ 2026 एफआईएच हॉकी विश्व कप (पुरुष) किसने जीता? (अगस्त 2026)
– जर्मनी।

➤ ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में किस पहल ने स्वर्ण पुरस्कार जीता? (सितंबर 2026)
– पंचायत उन्नति सूचकांक

➤ कौन-सा संस्थान V-Dem रिपोर्ट प्रकाशित करता है? (सितंबर 2026)
– वैरायटीज़ ऑफ़ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय

➤ V-Dem निर्वाचन लोकतंत्र सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? (सितंबर 2026)
– 106वीं

➤ V-Dem 2026 में भारत को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? (सितंबर 2026)
– निरंकुशता की ओर बढ़ता हुआ

➤ 78वें एमी में बॉब होप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता? (सितंबर 2026)
– माइकल जे. फ़ॉक्स

➤ 2026 विंबलडन पुरुष एकल किसने जीता? (सितंबर 2026)
– यानिक सिनर।

➤ 2026 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पुरुष रिकर्व स्वर्ण किसने जीता? (सितंबर 2026)
– धीरज बोम्मदेवरा।

➤ 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? (सितंबर 2026)
– अनंत नाग

➤ दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थीं? (सितंबर 2026)
– देविका रानी

➤ प्रत्येक तेनज़िंग नोर्गे पुरस्कार विजेता को कितनी नकद राशि मिलती है? (सितंबर 2026)
– ₹15 लाख

➤ थॉमस कप 2026 किसने जीता? (सितंबर 2026)
– चीन।

➤ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? (सितंबर 2026)
– 1957

➤ 2026 का पुरस्कार किस बांग्लादेशी ने जीता? (सितंबर 2026)
– रुना खान

➤ टॉमी कोह 1982 के किस अभिसमय से जुड़े हैं? (सितंबर 2026)
– संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय

➤ वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? (सितंबर 2026)
– 131वीं

➤ वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन-सी संस्था प्रकाशित करती है? (सितंबर 2026)
– विश्व आर्थिक मंच

➤ 2026 में भारत का कौन-सा उप-सूचकांक सर्वोच्च रैंक वाला है? (सितंबर 2026)
– राजनीतिक सशक्तीकरण

➤ फिडे विश्व कप 2025 किसने जीता? (सितंबर 2026)
– उज़्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव।

➤ अगस्त 2026 में नियुक्त नीति आयोग के CEO कौन हैं? (सितंबर 2026)
– अनुराग जैन

➤ 1995 से 2013 तक कतर के अमीर कौन थे? (अक्टूबर 2026)
– शेख हमद बिन खलीफा अल थानी

➤ 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? (अक्टूबर 2026)
– अहमदाबाद

➤ एशियाई खेल 2026 में व्यक्तिगत गोल्फ स्वर्ण किस भारतीय महिला ने जीता? (अक्टूबर 2026)
– प्रणवी उर्स।

➤ विद्या रामराज ने किसका 42 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा? (अक्टूबर 2026)
– महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में पी.टी. उषा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड।

➤ 20वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? (अक्टूबर 2026)
– आइची-नागोया, जापान (2026)।

➤ एशियाई खेल 2026 में भारत का स्थान और पदकों की संख्या क्या रही? (अक्टूबर 2026)
– चौथा स्थान, 21 स्वर्ण सहित कुल 85 पदक।

➤ 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को कौन-सा उज़्बेक सम्मान दिया गया? (अक्टूबर 2026)
– ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट फ्रेंडशिप

➤ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनीं? (अक्टूबर 2026)
– वर्षा अशोक अगलावे

➤ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के किस मूर्तिकार का दिसंबर 2025 में निधन हुआ? (अक्टूबर 2026)
– राम वी. सुतार

➤ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? (अक्टूबर 2026)
– न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई

उत्तर प्रदेश

➤ भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? (जनवरी 2026)
– गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

➤ उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 की नकद पुरस्कार राशि क्या थी? (जनवरी 2026)
– ₹11 लाख

➤ नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हैं? (जनवरी 2026)
– 98

➤ पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? (जनवरी 2026)
– एटा

➤ कच्छी भाषा में 'ढांड' का क्या अर्थ है? (जनवरी 2026)
– उथली आर्द्रभूमि

➤ पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? (जनवरी 2026)
– गोंडा

➤ कौन-सा शहर भारत का काँच नगर कहलाता है? (जनवरी 2026)
– फिरोजाबाद

➤ लखनऊ के राज भवन का नया नाम क्या है? (जनवरी 2026)
– जन भवन

➤ भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई? (जनवरी 2026)
– नमो घाट, वाराणसी

➤ सर्वेक्षण के अनुसार दुग्ध उत्पादन में कौन-सा राज्य प्रथम है? (फरवरी 2026)
– उत्तर प्रदेश।

➤ उत्तर प्रदेश का आर्थिक लक्ष्य क्या है? (फरवरी 2026)
– एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था।

➤ उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? (फरवरी 2026)
– वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को।

➤ 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? (फरवरी 2026)
– जीएसडीपी का 3 प्रतिशत।

➤ 2023 में किस राज्य में दहेज के सबसे अधिक मामले थे? (फरवरी 2026)
– उत्तर प्रदेश

➤ दहेज मृत्यु के लिए भारतीय न्याय संहिता की कौन-सी धारा है? (फरवरी 2026)
– धारा 80

➤ किस मामले ने 498-क में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगाई? (फरवरी 2026)
– अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य

➤ किस अधिकरण ने सुआव को नदी के रूप में बहाल करने का आदेश दिया? (फरवरी 2026)
– राष्ट्रीय हरित अधिकरण

➤ राप्ती का प्राचीन नाम क्या था? (फरवरी 2026)
– इरावती

➤ राप्ती किस नदी की सहायक नदी है? (फरवरी 2026)
– घाघरा

➤ नमो भारत आरआरटीएस का क्रियान्वयन कौन करता है? (फरवरी 2026)
– एनसीआरटीसी

➤ प्रणाली की अधिकतम गति कितनी है? (फरवरी 2026)
– 180 किमी/घंटा

➤ पहले गलियारे पर उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर है? (फरवरी 2026)
– मेरठ

➤ उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर दो प्रस्तावित उच्च गति रेल गलियारों पर स्थित है? (फरवरी 2026)
– वाराणसी

➤ विकसित किए जाने वाले 15 स्थलों में उत्तर प्रदेश के कौन-से विरासत स्थल शामिल हैं? (फरवरी 2026)
– सारनाथ और हस्तिनापुर

➤ बासमती जैविक प्रदर्शन फार्म कहाँ है? (मार्च 2026)
– पीलीभीत

➤ कालिंजर किला किस जिले में है? (मार्च 2026)
– बाँदा

➤ प्रति सांसद वार्षिक एमपीलैड्स पात्रता कितनी है? (मार्च 2026)
– ₹5 करोड़

➤ एमपीलैड्स का प्रबंधन करने वाला पोर्टल? (मार्च 2026)
– ई-साक्षी

➤ उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जापान सिटी कहाँ है? (मार्च 2026)
– जेवर हवाई अड्डे के निकट YEIDA सेक्टर 5A

➤ उत्तर प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना में श्रेणी I में कौन-से जिले हैं? (अप्रैल 2026)
– गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद

➤ गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? (अप्रैल 2026)
– 594 किमी

➤ नवयुग पालिका योजना का पाँच वर्षीय परिव्यय कितना है? (अप्रैल 2026)
– ₹2,916 करोड़

➤ उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक केंद्र में फैक्ट्री श्रमिकों के प्रदर्शन हुए? (अप्रैल 2026)
– नोएडा

➤ श्रम विवादों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन-सा संस्थागत उपाय किया? (अप्रैल 2026)
– विशेष औद्योगिक प्रकोष्ठ

➤ शेखा झील के बाद भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? (अप्रैल 2026)
– 99

➤ अब उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? (अप्रैल 2026)
– 12

➤ शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस शहर के निकट है? (अप्रैल 2026)
– अलीगढ़

➤ उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला रूफटॉप सोलर में अग्रणी है? (जून 2026)
– लखनऊ

➤ 50 और डॉप्लर रडार किस मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित हैं? (जून 2026)
– मिशन मौसम

➤ लखनऊ में आग कहाँ लगी? (जून 2026)
– अलीगंज

➤ कौन-सा अनुच्छेद अग्निशमन को नगरपालिका कार्य के रूप में सूचीबद्ध करता है? (जून 2026)
– अनुच्छेद 243W

➤ एनबीसी 2016 का स्थान लेने वाली संहिता? (जून 2026)
– एनबीसीएस 2026

➤ उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया? (जून 2026)
– लखनऊ

➤ भारत का 100वाँ रामसर स्थल कौन-सा है? (जून 2026)
– जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार

➤ सुरहा ताल किस जिले में है? (जून 2026)
– बलिया

➤ यह किस उड़ान पथ पर स्थित है? (जून 2026)
– मध्य एशियाई उड़ान पथ

➤ उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल? (जून 2026)
– 13

➤ किस राज्य में सबसे अधिक जन औषधि केंद्र हैं? (जुलाई 2026)
– उत्तर प्रदेश

➤ ऑपरेशन साइ-वज्र किसने शुरू किया? (जुलाई 2026)
– उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण

➤ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के अंतर्गत संशोधित निर्वाह भत्ता कितना है? (जुलाई 2026)
– दो वर्षों के लिए ₹20,000 प्रति माह

➤ कौशल सेतु क्या करता है? (जुलाई 2026)
– प्रशिक्षण भागीदारों का कागज रहित पंजीकरण और पैनल में शामिल किया जाना

➤ प्रोजेक्ट गंगा में GANGA का पूर्ण रूप क्या है? (जुलाई 2026)
– गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट

➤ रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कितने स्कूटर दिए जाएँगे? (जुलाई 2026)
– 50,000

➤ कौन-सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने की गारंटी देता है? (जुलाई 2026)
– अनुच्छेद 22(1)

➤ कौन-सा अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देश देता है? (जुलाई 2026)
– अनुच्छेद 39A

➤ अयोध्या बार द्वारा बचाव पक्ष के वकीलों पर लगाया गया जुर्माना? (जुलाई 2026)
– ₹5 लाख

➤ पहला सैन्य चिकित्सा विभाग कहाँ है? (जुलाई 2026)
– कमांड अस्पताल, लखनऊ

➤ यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? (जुलाई 2026)
– चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना)

➤ किस कमान का अस्पताल इसका संचालन करता है? (जुलाई 2026)
– मध्य कमान

➤ उत्तर प्रदेश में एके-203 शेर राइफल कहाँ बनती है? (अगस्त 2026)
– कोरवा, अमेठी

➤ परिछा बैराज कहाँ है? (अगस्त 2026)
– झाँसी, बेतवा नदी पर

➤ समुचित प्राधिकारी का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है? (अगस्त 2026)
– धारा 17

➤ यह मामला उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पन्न हुआ? (अगस्त 2026)
– बुलंदशहर

➤ सारनाथ को किन मानदंडों के अंतर्गत अंकित किया गया? (अगस्त 2026)
– मानदंड (iii) और (vi)

➤ सारनाथ के बाद भारत में कितनी विश्व धरोहर संपत्तियाँ हैं? (अगस्त 2026)
– 45

➤ विश्व धरोहर समिति का 48वाँ सत्र कहाँ आयोजित हुआ? (अगस्त 2026)
– बुसान, दक्षिण कोरिया

➤ सारनाथ में किस तीर्थंकर का मंदिर है? (अगस्त 2026)
– श्रेयांसनाथ

➤ वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटक यात्राओं में कौन-सा राज्य अग्रणी रहा? (सितंबर 2026)
– उत्तर प्रदेश

➤ रानी अवंती बाई किस रियासत की रानी थीं? (सितंबर 2026)
– रामगढ़

➤ 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को कहाँ पराजित किया? (सितंबर 2026)
– खेरी का युद्ध, मंडला के निकट

➤ उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई? (सितंबर 2026)
– 1858

➤ उत्तर प्रदेश के किसानों को धान का भुगतान कितने घंटे के भीतर किया जाता है? (अक्टूबर 2026)
– 48 घंटे

➤ UP AI मिशन को कौन-सा विभाग लागू करता है? (अक्टूबर 2026)
– सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

➤ लखनऊ AI सिटी के लिए कितने GPU प्रस्तावित हैं? (अक्टूबर 2026)
– 10,000

➤ भदोही के लिए कौन-सा नया नाम घोषित किया गया? (अक्टूबर 2026)
– संत रविदास नगर भदोही

➤ उत्तर प्रदेश की SAF नीति के लिए कौन-सी एजेंसी नोडल है? (अक्टूबर 2026)
– UPNEDA

राजव्यवस्था, शासन एवं न्यायपालिका

समसामयिक नोट्स

परिसीमन और दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ

संदर्भ: दक्षिणी राज्यों ने चिंता जताई है कि लोकसभा सीटों का केवल जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण, तथा वित्त आयोग द्वारा धन के वितरण का वर्तमान तरीका, उन राज्यों के विरुद्ध जाता है जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया। इस बहस ने परिसीमन की संवैधानिक व्यवस्था को फिर से केंद्र में ला दिया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- परिसीमन प्रत्येक राज्य में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाएँ निर्धारित करता है।
- यह कार्य एक उच्चाधिकार प्राप्त परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे सीमा आयोग भी कहा जाता है।
- परिसीमन आयोग अब तक चार बार गठित किए जा चुके हैं, 1952, 1963, 1973 और 2002 में।
- 2022 के जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश को 90 विधानसभा सीटों (जम्मू में 43 और कश्मीर में 47) और 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्गठित किया।
- आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है, उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होते हैं।
- अनुच्छेद 82 और 170 प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के पुनः समायोजन का उपबंध करते हैं, जो संसद द्वारा कानून से तय की गई रीति से होगा।
- अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के निर्धारण से संबंधित हैं।
- किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग का ऐसा आदेश जो स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध हो, संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन के योग्य है।
- मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग (1966) में न्यायिक हस्तक्षेप को केवल चुनावों में विलंब से बचने के लिए सीमित किया गया था, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति समाप्त नहीं की गई थी।

प्रगति प्लेटफ़ॉर्म की 50वीं बैठक पूरी

संदर्भ: प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 50वीं बैठक आयोजित हुई, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला प्रौद्योगिकी-संचालित समीक्षा मंच है। इसने रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रगति को 2015 में एक बहुउद्देशीय, बहु-माध्यम मंच के रूप में शुरू किया गया था, जो प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और समय पर निर्णय लाता है।
- समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इनमें टीम इंडिया की भावना से राज्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सीधा संवाद होता है।
- इस मंच पर पीएम गति शक्ति, परिवेश और पीएम रेफरेंस पोर्टल जैसे शासन उपकरण उपलब्ध हैं।
- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सैद बिज़नेस स्कूल के एक बाहरी अध्ययन ने इसे वैश्विक मानक और वास्तविक समय में परियोजना निगरानी के लिए सत्य का एकल स्रोत बताया।

रोमियो-जूलियट खंड और पॉक्सो अधिनियम

संदर्भ: एक न्यायालय ने किशोरों के बीच सहमति वाले संबंधों में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाया और केंद्र से 'रोमियो-जूलियट खंड' पर विचार करने को कहा, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाल संरक्षण के बीच संतुलन बनाए।

□ **मुख्य बिंदु**

- न्यायालय ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया जिनमें पीड़ित की आयु गलत बताई गई ताकि मामला पॉक्सो के कठोर प्रावधानों के अंतर्गत आ जाए।
- इसने ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया जिनमें परिवारों ने युवाओं के बीच संबंधों का विरोध करने के लिए कानून का उपयोग किया।
- रोमियो-जूलियट खंड का उद्देश्य वास्तव में सहमति वाले किशोर संबंधों को पॉक्सो के कठोर प्रयोग से छूट देना है, जहाँ साझेदारों के बीच आयु का अंतर बहुत कम हो।
- ऐसे संबंधों में सहमति की अनदेखी करने से किशोरों को गलत तरीके से कारावास हो सकता है।

लैंड स्टैक, पंखुड़ी और ईसीआईनेट की शुरुआत

संदर्भ: जनवरी 2026 में तीन डिजिटल शासन मंच शुरू किए गए: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अंतर्गत भूमि और संपत्ति अभिलेखों के लिए लैंड स्टैक, महिला एवं बाल विकास में सीएसआर साझेदारी के लिए पंखुड़ी पोर्टल, और IICDEM

2026 सम्मेलन में अनावरण किया गया निर्वाचन आयोग का ईसीआईनेट। ये ई-गवर्नेंस सुधारों के उदाहरण के रूप में महत्वपूर्ण हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- भूमि और संपत्ति अभिलेखों के लिए एक एकीकृत जीआईएस-आधारित डिजिटल मंच लैंड स्टैक को डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अंतर्गत शुरू किया गया।
- इसकी रूपरेखा सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड जैसे देशों की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है।
- लैंड स्टैक के साथ राजस्व शब्दों की एक शब्दावली (GoRT) भी शुरू की गई।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल शुरू किया, जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारियों को सुगम बनाने वाला एकल-खिड़की डिजिटल मंच है।
- पंखुड़ी व्यक्तियों, प्रवासी भारतीयों, गैर-सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट और सरकारी निकायों को जोड़ता है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य सेवा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) और बाल कल्याण शामिल हैं।
- भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM) 2026 में ईसीआईनेट डिजिटल मंच शुरू किया।
- ईसीआईनेट के एक प्रारंभिक संस्करण का 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया

संदर्भ: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और अब इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। यह कई मौजूदा निकायों के स्थान पर उच्च शिक्षा के लिए एक शीर्ष नियामक का प्रस्ताव करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यूजीसी वर्तमान में मानदंड बनाता भी है और अनुदान वितरित भी करता है, जिसे हितों का टकराव माना जाता है। यूजीसी के बजट का लगभग 65 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जाता है, जबकि अधिकांश छात्रों को नामांकित करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को लगभग 35 प्रतिशत मिलता है।
- यह विधेयक संघ सूची की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत बनाया गया है, जो उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण से संबंधित है।
- एक एकल आयोग, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, उच्च शिक्षा के लिए शीर्ष नियामक निकाय बनेगा।
- VBSA संस्थानों के वित्तपोषण को नियंत्रित नहीं करेगा।
- इसके अधीन तीन परिषदें कार्य करेंगी: विनियमन के लिए, गुणवत्ता और प्रत्यायन के लिए, तथा मानक निर्धारण के लिए।
- विधेयक यूजीसी अधिनियम 1956, एआईसीटीई अधिनियम 1987 और एनसीटीई अधिनियम 1993 को निरस्त करता है।
- नियामक परिषद उल्लंघन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों पर दंड लगा सकती है, और निर्णयों के विरुद्ध अपील केंद्र सरकार के पास की जाती है।
- विधि और चिकित्सा शिक्षा इसके दायरे से बाहर रहती हैं; काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव है।
- अमित कुमार बनाम भारत संघ में न्यायालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर निर्देश जारी करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया।
- संस्थानों को किसी भी छात्र की आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना पुलिस को तुरंत देनी होगी, भले ही यह छात्रावास या पीजी में हुई हो।
- रिक्त शिक्षक और प्रशासनिक पदों को 4 महीने के भीतर भरा जाना है, और लंबित छात्रवृत्तियों का 4 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है।
- भारत अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 0.68 प्रतिशत खर्च करता है।

16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2026-31)

संदर्भ: डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में रखी गई। यह 2026-27 से 2030-31 तक की पाँच वर्षीय पंचाट अवधि को कवर करती है और तय करती है कि कर राजस्व और अनुदान संघ और राज्यों के बीच कैसे बाँटे जाएँगे।

□ **मुख्य बिंदु**

- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण विभाज्य पूल (अनुच्छेद 270), सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे विवेकाधीन अनुदानों (अनुच्छेद 282) के माध्यम से होता है। क्षैतिज हस्तांतरण में जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय जैसे समानता कारकों को वन आच्छादन और राजकोषीय अनुशासन जैसे दक्षता कारकों के साथ तौला जाता है।
- आयोग की अध्यक्षता डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने की, जिसमें टी. रबी शंकर, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्य कांति घोष सदस्य थे।
- इसकी पंचाट अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलती है।
- विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) 41 प्रतिशत रखा गया है, जो 15वें आयोग के समान है।
- 14वें आयोग ने 42 प्रतिशत की सिफारिश की थी, जिसे बाद में 15वें आयोग ने घटा दिया।
- उपकर और अधिभार विभाज्य पूल से बाहर रहते हैं; संग्रह लागत सहित उनका हिस्सा 2021-22 में संघ के कर संग्रह के प्रति ₹100 पर ₹13.5 तक पहुँच गया।

- आय दूरी किसी राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और शीर्ष तीन बड़े राज्यों के औसत के बीच का अंतर है; गरीब राज्यों को बड़ा हिस्सा मिलता है।
- जनसंख्या की गणना 2011 की जनगणना के आधार पर की जाती है।
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन में अब 1971 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि का उपयोग किया जाता है, जिसने पहले उपयोग किए जाने वाले कुल प्रजनन दर में परिवर्तन का स्थान लिया है।
- वन मानदंड में अब किसी राज्य के कुल वन क्षेत्र में हिस्से और 2015 से 2023 के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि दोनों को गिना जाता है, तथा इसमें खुले वन भी शामिल हैं।
- कर या राजकोषीय प्रयास मानदंड की जगह जीडीपी में योगदान को लिया गया है, जिसकी गणना किसी राज्य की जीएसडीपी के वर्गमूल को सभी राज्यों की जीएसडीपी के वर्गमूलों के योग के सापेक्ष लेकर की जाती है।
- जीडीपी माप के लिए 2018-19 से 2023-24 की औसत सांकेतिक जीएसडीपी का उपयोग किया गया है, जिसमें महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़ दिया गया है।
- राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट अनुदान बंद कर दिए गए हैं।
- स्थानीय निकाय अनुदानों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹4.4 लाख करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹3.6 लाख करोड़ शामिल हैं; शहरी हिस्सा 36 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है।
- स्थानीय निकाय अनुदान 80 प्रतिशत मूल और 20 प्रतिशत प्रदर्शन-आधारित में बाँटे गए हैं; मूल अनुदान का आधा हिस्सा स्वच्छता, अपशिष्ट और जल प्रबंधन से जुड़ा है।
- राज्य आपदा राहत एवं प्रबंधन निधियों के लिए ₹2,04,401 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र-राज्य हिस्सेदारी पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य के लिए 75:25 है।
- लू और बिजली गिरने को राष्ट्रीय आपदा के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की गई है, और एनडीएमआईएस को उन्नत किया जाना है।
- निधियों की शर्तों में स्थानीय निकायों का उचित गठन, लेखा-परीक्षित खातों का प्रकाशन और राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन शामिल हैं।
- केंद्र को 2030-31 तक अपना राजकोषीय घाटा GDP के 3.5 प्रतिशत तक घटाना चाहिए और राज्यों को इसे GSDP के 3 प्रतिशत पर सीमित रखना चाहिए।
- सभी ऑफ-बजट उधारियाँ बंद होनी चाहिए, और बिजली क्षेत्र के सुधारों में बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का निजीकरण तथा DISCOM ऋण धारण करने के लिए विशेष प्रयोजन इकाइयाँ (SPV) शामिल हैं।
- सब्सिडी में बहिष्करण मानदंड और सूर्यास्त खंड (समय-सीमा संबंधी प्रावधान) होने चाहिए, और राज्यों के 308 निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमों की बंदी के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।
- वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हर पाँच वर्ष में किया जाता है।
- विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है, यद्यपि राज्यों ने 50 प्रतिशत की माँग की थी।
- GDP में योगदान का एक नया मानदंड, 10 प्रतिशत भारांश के साथ, कर और राजकोषीय प्रयास का स्थान लेता है।
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को अब 1971 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि से मापा जाता है, जिसने 15वें आयोग द्वारा प्रयुक्त कुल प्रजनन दर में परिवर्तन का स्थान लिया है।

□ विचारार्थ विषय

- संघ और राज्यों के बीच (ऊर्ध्वाधर) तथा राज्यों के बीच (क्षैतिज) शुद्ध कर आगमों का वितरण।
- अनुच्छेद 275 के अंतर्गत भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांत।
- पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधियों को बढ़ाने के उपाय।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा वित्तपोषण व्यवस्थाओं की समीक्षा।

□ अनुदान और लागत-साझाकरण

- 2026-31 के लिए कुल ₹9.47 लाख करोड़ के सहायता अनुदान की अनुशंसा की गई है।
- स्थानीय निकाय अनुदान ग्रामीण निकायों के लिए लगभग ₹4.35 लाख करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹3.56 लाख करोड़ हैं, जो 80 प्रतिशत मूल और 20 प्रतिशत प्रदर्शन-आधारित में विभाजित हैं।
- राज्यों के लिए लगभग ₹2.04 लाख करोड़ के आपदा प्रबंधन कोष की अनुशंसा की गई है।
- लागत-साझाकरण पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा शेष राज्यों के लिए 75:25 प्रस्तावित है।

16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकाय अनुदान

घटक	आवंटन
ग्रामीण स्थानीय निकाय	₹4.4 लाख करोड़
शहरी स्थानीय निकाय	₹3.6 लाख करोड़
मूल : प्रदर्शन विभाजन	80 : 20
स्वच्छता, अपशिष्ट, जल से जुड़ा मूल अनुदान	50 प्रतिशत
आपदा कोष (SDRF/SDMF)	₹2,04,401 करोड़

क्षैतिज हस्तांतरण के मानदंड और भारांश

मानदंड	भारांश

आय अंतर	42.5%
जनसंख्या (2011)	17.5%
क्षेत्रफल	10%
वन और पारिस्थितिकी	10%
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	10%
GDP में योगदान	10%

NDMA ने पहली आपदा पीड़ित पहचान SOP जारी की

संदर्भ: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा पीड़ित पहचान (DVI) और प्रबंधन पर देश की पहली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दस्तावेज़ पीड़ितों की पहचान को आपदा प्रतिक्रिया का मूल अंग मानता है और मानवीय, चिकित्सा-विधिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक प्रणालियों को जोड़ता है।

□ मुख्य बिंदु

- प्राथमिक पहचानकर्ता अंगुलियों के निशान, दंत अभिलेख और DNA हैं, जिन्हें अवशेषों की स्थिति के अनुसार द्वितीयक पहचानकर्ताओं का समर्थन मिलता है।
- पद्धतियों में शव-परीक्षण के बाद अंगुलि-छाप लेना, DNA विश्लेषण, फॉरेंसिक दंत-विज्ञान, आभासी शव-परीक्षण और फॉरेंसिक पुरातत्व शामिल हैं।
- दिशानिर्देश गरिमा, नैतिक आचरण, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और परिवारों को सहायता पर बल देते हैं।
- राष्ट्रीय दंत डेटा रजिस्ट्री (NDDR) प्रस्तावित है ताकि दंत अभिलेखों से जले या सड़े-गले शवों की पहचान की जा सके और DNA पर अत्यधिक निर्भरता घटाई जा सके।
- तैयारी न्यूनतम तत्परता मानकों, नियमित प्रशिक्षण, सुदृढ़ डेटा प्रणालियों और अंतर-एजेंसी सहयोग पर आधारित है।

□ DVI के चार चरण

- पहला चरण स्थल पर अवशेषों की व्यवस्थित पुनर्प्राप्ति, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण है।
- दूसरा चरण केंद्रीय रजिस्ट्री के माध्यम से मृत्यु-पूर्व दंत डेटा का संग्रह है।
- तीसरा चरण योग्य फॉरेंसिक दंत-विशेषज्ञों द्वारा मृत्यु-पश्चात दंत अभिलेखों की तैयारी है।
- चौथे चरण में विशेष सॉफ्टवेयर और विशेषज्ञ समीक्षा द्वारा दोनों डेटासेटों की तुलना की जाती है, जिसका अंत सकारात्मक पहचान, अपवर्जन या अनिर्णायक परिणाम में होता है।

PAC ने संकल्प योजना के कमजोर क्रियान्वयन को रेखांकित किया

संदर्भ: लोक लेखा समिति ने संकल्प के 'सुस्त' क्रियान्वयन की आलोचना की, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की विश्व बैंक-सहायता प्राप्त केंद्र प्रायोजित योजना है। निधियों का केवल एक अंश ही उपयोग किया गया और निगरानी कमजोर पाई गई।

□ मुख्य बिंदु

- SANKALP का पूर्ण रूप है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion), और इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसे मार्च 2023 तक चलना था और इसे मार्च 2024 तक बढ़ाया गया।
- कौशल भारत मिशन 2015 में शुरू किया गया था; PMKVY 4.0, PM-NAPS और जन शिक्षण संस्थान योजना को कौशल भारत कार्यक्रम में विलय कर दिया गया।
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना 1950 की है; पीएम विश्वकर्मा (2023) का 2027-28 तक ₹13,000 करोड़ का परिव्यय है।
- DDU-GKY 2014 में और RSETI 2009 में शुरू हुए।
- कुल परिव्यय ₹4,455 करोड़ है: विश्व बैंक ऋण ₹3,300 करोड़, राज्यों का लीवरेज ₹660 करोड़ और उद्योग का लीवरेज ₹495 करोड़।
- इसके तीन प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं: संस्थागत सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और वंचित समूहों का समावेशन।
- विश्व बैंक का संवितरण संवितरण-सम्बद्ध संकेतकों (DLI) से जुड़ा है, जिसमें IIM इंदौर स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी है।

अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मासिक धर्म स्वच्छता

संदर्भ: डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार (2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुँच अनुच्छेद 21 से उत्पन्न एक संवैधानिक अधिकार है। इसने इस विषय को सार्वजनिक स्वास्थ्य से हटाकर गरिमा, समानता और मौलिक अधिकारों से जोड़ा और देशभर के विद्यालयों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।

□ निर्णय

- मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार का भाग माना गया है।
- मासिक धर्म स्वच्छता के उपायों का अभाव लड़कियों को विद्यालय में समान भागीदारी से वंचित करता है, इसलिए समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 भी लागू होता है।
- सैनिटरी उत्पादों तक पहुँच का अभाव अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत शिक्षा के मौलिक अधिकार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावित करता है।

- न्यायालय ने कक्षा 6 से 12 तक की विद्यालय जाने वाली लड़कियों के लिए केंद्र की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया।

□ विद्यालयों को निर्देश

- प्रत्येक सरकारी और निजी विद्यालय, चाहे शहरी हो या ग्रामीण, में पानी, निजता और दिव्यांगजन के लिए सुगमता के साथ कार्यशील, लिंग-आधारित अलग-अलग शौचालय होने चाहिए।
- साबुन और पानी के साथ हाथ धोने की सुविधा हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।
- ASTM D-6954 के अनुरूप निःशुल्क ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन शौचालयों में वेंडिंग मशीनों या निर्धारित प्राधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- अतिरिक्त वर्दी, अंतःवस्त्र और निपटान थैलों से युक्त मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) कोने स्थापित किए जाने चाहिए।
- प्रत्येक शौचालय में ढका हुआ कूड़ादान होना चाहिए, और निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार होना चाहिए।
- पुरुष शिक्षकों और छात्रों का संवेदनशीलीकरण।

□ जागरूकता और निगरानी

- एनसीईआरटी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERT) को पाठ्यक्रम में मासिक धर्म, किशोरावस्था और पीसीओएस/पीसीओडी पर लैंगिक रूप से संवेदनशील सामग्री जोड़नी होगी, और दोनों लिंगों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- जिला शिक्षा अधिकारियों को वार्षिक निरीक्षण करना, छात्रों से गुमनाम प्रतिक्रिया एकत्र करना और शिक्षा का अधिकार नियमों के अंतर्गत अनुपालन नोटिस जारी करना होगा।
- अनुपालन में विफल रहने वाले निजी विद्यालयों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत मान्यता रद्द होने का जोखिम है।
- समग्र शिक्षा और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत MHM अवसंरचना के लिए निर्धारित निधि।

उच्च न्यायपालिका में विविधता लाने हेतु विधेयक

संदर्भ: फरवरी 2026 में राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने और सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें बनाने के लिए संविधान संशोधन हेतु एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया। यह हाल की उच्च न्यायालय नियुक्तियों में कम प्रतिनिधित्व और सर्वोच्च न्यायालय में भारी लंबित मामलों से प्रेरित है, और यह अनुच्छेद 124, 130 और 217 को छूता है।

□ मुख्य बिंदु

- जनवरी 2021 से जनवरी 2026 के बीच उच्च न्यायालयों की 593 नियुक्तियों में केवल 26 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जनजाति, 80 अन्य पिछड़ा वर्ग, 37 अल्पसंख्यक और 96 महिलाएँ थीं। जनवरी 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय में 90,000 से अधिक मामले लंबित थे।
- 229वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2009) ने चार क्षेत्रों में कैसेशन पीठों का सुझाव दिया था।
- अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय की नियुक्तियों को नियंत्रित करता है; अनुच्छेद 130 न्यायालय का स्थान दिल्ली में निर्धारित करता है।

□ विधेयक में क्या प्रस्तावित है

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
- कॉलेजियम की सिफारिशों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र हेतु 90 दिन की समय-सीमा।
- नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थायी क्षेत्रीय पीठें, जिनमें संवैधानिक मामले दिल्ली में ही रहेंगे।

क्या ED अनुसूचित-भिन्न अपराधों के लिए संपत्ति कुर्क कर सकता है?

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2025 के उस निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें ब्रिटेन-स्थित मंच के माध्यम से हवाला-समर्थित ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ी लगभग ₹20 करोड़ की प्रवर्तन निदेशालय की कुर्की को वैध ठहराया गया था। यह मामला इस बहस को फिर जीवित करता है कि क्या किसी अनुसूचित-भिन्न गतिविधि से हुई आय को PMLA, 2002 के अंतर्गत अपराध की आय माना जा सकता है।

□ मुख्य बिंदु

- ED ने 2015 में लगभग ₹20 करोड़ की संपत्तियों को रोकने वाला अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी अनुसूचित अपराध नहीं है, इसलिए ED ने अधिकारिता का दावा करने के लिए इसे जालसाजी जैसे किसी अनुसूचित अपराध से जोड़ा।
- धारा 3 अपराध को परिभाषित करती है और धारा 4 3 से 7 वर्ष के सश्रम कारावास का प्रावधान करती है, जो NDPS-संबंधित आय के लिए 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- धारा 5 अभिलिखित विश्वास करने के कारण पर 180 दिन तक अनंतिम कुर्की की अनुमति देती है; 30 दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से संपर्क करना आवश्यक है।
- न्यायनिर्णायक प्राधिकारी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
- अपीलें अपीलीय अधिकरण में जाती हैं और फिर 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में।
- अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, जिनमें धारा 45 के अंतर्गत दोहरी जमानत शर्तें हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने PMLA को स्वयं-पूर्ण कानून कहा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाओं को पोषणीय नहीं माना, और 'विषैले

वृक्ष का फल' के तर्क का प्रयोग करते हुए अपराध की आय की व्यापक व्याख्या की।

➤ अपील में तर्क दिया गया है कि किसी अन्य अपराध से मात्र संबंध सट्टेबाजी की आय को अपराध की आय में नहीं बदल सकता।

□ **पूर्व-निर्णय: विजय मदनलाल चौधरी (2022)**

➤ धन शोधन एक स्वतंत्र, सतत अपराध है जो अनुसूचित अपराध से स्वतंत्र है।

➤ अनुसूचित अपराध में दोषसिद्धि के बिना भी कुर्की की कार्यवाही हो सकती है।

➤ ED अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, इसलिए धारा 50 के अंतर्गत दिए गए बयान स्वीकार्य हैं।

➤ ECIR को अभियुक्त को FIR की तरह उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।

खेल शासन: बिंद्रा टास्क फोर्स, राष्ट्रीय खेल बोर्ड और ट्रिब्यूनल नियम

संदर्भ: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता वाले एक टास्क फोर्स ने खेल प्रशासकों की क्षमता निर्माण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जबकि सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल निकायों और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए नियम अधिसूचित किए हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह टास्क फोर्स खेलो भारत नीति 2025 के अंतर्गत गठित किया गया था और इसका उद्देश्य 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में स्थान दिलाना तथा 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी को समर्थन देना है।

➤ इसने पाया कि खेल प्रशासकों का कोई पेशेवर कैडर नहीं है, प्रशिक्षण खंडित और पुराना है, और खिलाड़ियों के लिए प्रशासन में आने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है।

➤ इसने खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय खेल शिक्षा एवं क्षमता निर्माण परिषद का प्रस्ताव रखा, जो प्रशासकों के प्रशिक्षण को विनियमित, मान्यता प्रदान और प्रमाणित करेगी।

➤ एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं विकास प्रकोष्ठ भारत-विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाएगा, प्रशासकों का रजिस्टर रखेगा और भारतीय खेल प्राधिकरण के डिजिटल मंच ई-खेल पाठशाला का प्रबंधन करेगा।

➤ पदोन्नति को मापने योग्य कौशल से जोड़ने के लिए पाँच स्तरों वाले क्षमता परिपक्वता मॉडल और एक विशिष्ट प्रशासक पहचान संख्या (UAID) की सिफारिश की गई।

➤ एक दोहरे करियर की योजना खिलाड़ियों को उनके खेल के वर्षों में नेतृत्व का अध्ययन करने और 'स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ मेरिट' प्रमाणपत्र अर्जित करने की सुविधा देगी।

➤ राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 भारतीय ओलंपिक संघ और क्षेत्रीय खेल महासंघों जैसे निकायों पर लागू होते हैं।

➤ प्रत्येक निकाय में एक साधारण सभा और एक कार्यकारी समिति होनी चाहिए, और कार्यकारी समिति में कम से कम चार पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

➤ चुनावों की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल में हमेशा कम से कम 20 सदस्य होंगे।

➤ न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और कारावास की सजा पाया व्यक्ति सदस्यता के लिए अयोग्य है।

➤ राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026 के अंतर्गत समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें खेल सचिव, खेलों में प्रशासनिक अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के दो प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं।

➤ राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देगा और शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों की निगरानी करेगा।

➤ बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र खोज-सह-चयन समिति के पैनल से नियुक्त करता है।

➤ राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण खेल विवादों के लिए एक विशेष निकाय है, जो त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करता है।

➤ एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल दाखिल करने, आभासी सुनवाई और डिजिटल अभिलेखों में सहायता करता है।

चार धाम मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की योजना

संदर्भ: उत्तराखंड के छोटा चार धाम मंदिरों की मंदिर समितियाँ, जिनका नेतृत्व बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति कर रही है, गैर-हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश से रोकने पर विचार कर रही हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कदम अनुच्छेद 19, 25 और 26 के विरुद्ध है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ अनुच्छेद 19(1)(d) पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता देता है, और धर्म-आधारित रोक सार्वजनिक हित के बजाय समुदाय के हित की पूर्ति करती है।

➤ अनुच्छेद 25 और 26 लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन हैं।

➤ अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण के अंतर्गत समिति को यह सिद्ध करना होगा कि गैर-हिंदुओं को प्रवेश देने से मंदिर के धार्मिक स्वरूप को क्षति पहुँचती है।

➤ 2018 के सबरीमाला निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को प्रवेश से रोकना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

➤ अनिवार्य धार्मिक प्रथा सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई।

➤ किसी भी प्रतिबंध को अनुच्छेद 19, 25 और 26 की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

- नियमों को धार्मिक पहचान के बजाय आचरण को विनियमित करना चाहिए।
- हितधारकों से परामर्श और न्यायिक समीक्षा आवश्यक हैं।

प्रहार: भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी रणनीति

संदर्भ: गृह मंत्रालय ने प्रहार जारी किया, जो आठ पृष्ठों का दस्तावेज़ है और भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रतिपादित राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति है। यह शून्य-सहिष्णुता के रुख और रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनर्प्राप्ति को जोड़ने वाले सात-स्तंभीय ढाँचे पर आधारित है।

□ **मुख्य बिंदु**

- रोकथाम बहु-एजेंसी केंद्र और खुफिया ब्यूरो में खुफिया पर संयुक्त कार्य बल के माध्यम से खुफिया-निर्देशित कार्रवाई पर निर्भर करती है।
- स्थानीय पुलिस प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करती है, जिसे राज्य और केंद्रीय बलों का समर्थन प्राप्त होता है, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नोडल आतंकवाद-रोधी बल है।
- क्षमताओं का समेकन बलों के आधुनिकीकरण पर बल देता है, जिसमें BPR&D और NSG द्वारा प्रशिक्षण शामिल है।
- मानवाधिकार और विधि के शासन का स्तंभ UAPA 1967, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, आयुध अधिनियम 1959 और PMLA 2002 जैसे कानूनों पर निर्भर है।
- अंतरराष्ट्रीय संरेखण में पारस्परिक विधिक सहायता संधियों, प्रत्यर्पण संधियों और संयुक्त कार्य समूहों का उपयोग किया जाता है।
- पुनर्प्राप्ति और समुत्थानशीलता में प्रभावित समुदायों के पुनर्वास के लिए चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, वकील और नागरिक समाज शामिल होते हैं।

□ **रूपरेखा**

- यह सीमा-पार आतंकवाद, अल-कायदा और ISIS जैसे वैश्विक जिहादी नेटवर्कों, तथा ड्रोन, डार्क वेब उपकरण, क्रिप्टो-वित्तपोषण, साइबर हमलों और CBRN सामग्रियों जैसे नए जोखिमों से उत्पन्न खतरों को स्वीकार करती है।
- यह आतंकवाद को किसी धर्म या पहचान से नहीं जोड़ती।
- यह शून्य-सहिष्णुता के राजनीतिक रुख पर आधारित है।
- सात स्तंभ हैं: खुफिया-आधारित रोकथाम, त्वरित और आनुपातिक प्रतिक्रिया, क्षमता समेकन, विधि का शासन और मानवाधिकार, उग्रवाद-मुक्ति (डी-रेडिकलाइजेशन) और सामुदायिक सहभागिता, अंतरराष्ट्रीय संरेखण, तथा पुनर्प्राप्ति और समुत्थानशीलता।

फ्रंटियर नगालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण समझौता

संदर्भ: भारत सरकार, नगालैंड सरकार और पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने फ्रंटियर नगालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण (FNTA) बनाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह नगालैंड के छह पूर्वी जिलों को शक्तियाँ हस्तांतरित करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- ENPO आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों की शीर्ष संस्था है: कोन्याक, संगतम, चांग, खियम्नियुंगन, यिमखिउंग, टिखिर, फोम और सुमी।
- FNTA में तुएनसांग, मोन, किफिरे, लोंगलेंग, नोकलाक और शमातोर जिले शामिल हैं।
- प्राधिकरण को 46 विषयों पर शक्तियाँ हस्तांतरित की गई हैं।
- अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक मिनी-सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
- यह व्यवस्था नगालैंड के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371(क), को प्रभावित नहीं करती।

भारत का मानसिक स्वास्थ्य बोझ और बजट की प्रतिक्रिया

संदर्भ: बच्चों में डिजिटल लत पर आर्थिक समीक्षा की चेतावनी के बाद, 1 फरवरी के केंद्रीय बजट में उत्तर भारत में दूसरे निमहांस (NIMHANS) और रांची तथा तेजपुर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन की घोषणा की गई। भारत का मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय बोझ की तुलना में अब भी कम है।

□ **बोझ**

- आत्महत्या, अवसाद और नशे की लत के वैश्विक मामलों में भारत का हिस्सा लगभग एक-तिहाई है।
- 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में आत्महत्या मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि 2012 से 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन डॉलर की हानि होगी।
- मानसिक विकारों से ग्रस्त 70 से 92 प्रतिशत लोगों को उचित देखभाल नहीं मिलती।
- भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर 0.75 मनोचिकित्सक हैं, जबकि WHO द्वारा अनुशंसित न्यूनतम संख्या 3 है।

□ **सरकार की प्रतिक्रिया**

- मानसिक स्वास्थ्य आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 1.73 लाख से अधिक केंद्रों का उन्नयन किया गया है।
- 20 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र और 47 स्नातकोत्तर विभाग स्थापित किए गए हैं।
- अक्टूबर 2022 में शुरू की गई टेली मानस (Tele MANAS) 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 53 प्रकोष्ठों के माध्यम से 14416 या 1-800-891-4416 पर 24 घंटे सहायता प्रदान करती है।

➤ मानसिक स्वास्थ्य बजट 2020-21 में ₹683 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में लगभग ₹1,898 करोड़ हो गया, जो अब भी स्वास्थ्य बजट के 2 प्रतिशत से कम है।

भारत में विकेंद्रीकरण और ग्रामीण रूपांतरण

संदर्भ: ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय बजट आवंटन 2016-17 से 2026-27 के बीच 211 प्रतिशत से अधिक बढ़कर ₹2.73 लाख करोड़ तक पहुँच गए हैं। इस वृद्धि ने इस पर ध्यान फिर केंद्रित किया है कि 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा सशक्त पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण परिवर्तन कैसे लाती हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया; पहली पंचायती राज संस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में स्थापित की गई। अशोक मेहता समिति (1977) ने जिला परिषद और मंडल पंचायत वाली द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की।

➤ 1992 के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने पंचायतों के लिए भाग IX और नगरपालिकाओं के लिए भाग IXक जोड़ा।

➤ ये त्रिस्तरीय संरचना (जहाँ जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहाँ द्विस्तरीय), पाँच वर्ष का कार्यकाल, महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण तथा राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग अनिवार्य करते हैं।

➤ ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ पंचायतों के लिए 29 और नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यों की सूची देती हैं।

➤ स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तांतरण 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग ₹2.36 लाख करोड़ से बढ़कर 16वें के अंतर्गत लगभग ₹4.35 लाख करोड़ हो गया है।

➤ PRI नेतृत्व में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है।

➤ पंचायतों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।

➤ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 प्रति ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष 125 दिन का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए

संदर्भ: सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ (2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए की संवैधानिक वैधता पर खंडित निर्णय दिया, जिसके अनुसार किसी लोक सेवक के विरुद्ध जाँच शुरू होने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ संबंधित उपायों में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 शामिल हैं। भारत ने 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की।

➤ धारा 17ए को भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ा गया था।

➤ न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने धारा को वैध ठहराया, लेकिन यह भी जोड़ा कि मंजूरी का निर्णय लोकपाल या संबंधित राज्य के लोकायुक्त द्वारा लिया जाना चाहिए।

➤ न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि यह धारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह लोक सेवकों के केवल एक वर्ग को संरक्षण देती है।

➤ इससे पहले, विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई (2014) में न्यायालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की जाँच से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता वाले कार्यकारी और वैधानिक प्रावधानों को रद्द कर दिया था।

➤ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में लोक सेवक की परिभाषा में सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा या वेतन में कार्यरत कोई भी व्यक्ति तथा कोई भी न्यायाधीश शामिल है।

➤ भ्रष्टाचार का अर्थ किसी सरकारी कार्य को करने या न करने के लिए वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई परितोषण स्वीकार करना या माँगना माना जाता है।

➤ आदतन अपराधी को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जो 10 वर्ष तक बढ़ सकता है, तथा जुर्माने का दंड मिलता है।

➤ निरीक्षक से नीचे के पद के पुलिस अधिकारी (डीएसपीई मामलों में), महानगर क्षेत्रों में सहायक आयुक्त से नीचे के या अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारी, आवश्यक मजिस्ट्रेट आदेश के बिना जाँच नहीं कर सकते।

➤ अन्य पारदर्शिता कानून सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 हैं।

➤ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को राज्य सतर्कता आयोग के अधीन लाने की सिफारिश की।

मुफ्त सौगात संस्कृति पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ: तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के बीच मुफ्त सौगात संस्कृति पर चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि अंधाधुंध नकद अंतरण राजकोषीय अनुशासन और श्रम की गरिमा को कमजोर कर सकते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु (2013) में न्यायालय ने रंगीन टीवी जैसी वस्तुओं के वितरण को नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप ठहराया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार या वादों को रिश्वतखोरी, यानी भ्रष्ट आचरण, मानती है।

- न्यायालय ने कहा कि सेवाओं का खर्च उठा सकने वालों और न उठा सकने वालों में भेद किए बिना प्रत्यक्ष नकद अंतरण काम के प्रति हतोत्साहित कर सकते हैं।
- उसने उल्लेख किया कि करदाताओं के धन से दी गई उदारता आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है और राज्यों से दीर्घकालिक विकास पर ध्यान देने का आग्रह किया।
- RBI मुफ्त सौगात को निःशुल्क प्रदान किया गया लोक कल्याणकारी उपाय परिभाषित करता है, जो शिक्षा जैसी योग्यता वस्तुओं से भिन्न है।
- कुल बिना शर्त नकद अंतरण, जिनका अधिकांश लक्ष्य महिलाएँ हैं, 2025-26 में ₹1.7 लाख करोड़ आँके गए।
- राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा 2021-22 में GDP के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 3.2 प्रतिशत हो गया।
- आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के घोषणापत्र संबंधी दिशानिर्देश दलों से ऐसे वादों से बचने को कहते हैं जो चुनाव की शुचिता को दूषित करते हैं।
- अनुच्छेद 38, 39 और 41 में निहित नीति निदेशक तत्वों को प्रायः कल्याणकारी अंतरणों के पक्ष में उद्धृत किया जाता है।

लैंगिक बजट का हिस्सा बढ़कर 9.37 प्रतिशत हुआ

संदर्भ: केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा बढ़कर 9.37 प्रतिशत हो गया है, जिसमें 53 मंत्रालयों या विभागों और पाँच केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी है। भारत ने 2004-05 से लैंगिक बजटिंग अपनाई है।

□ **मुख्य बिंदु**

- लैंगिक बजटिंग अलग बजट बनाने के बजाय सरकारी बजटों की लैंगिक दृष्टिकोण से जाँच करती है।
- भारत ने इसे औपचारिक रूप से 2004-05 में अपनाया, जिसके साथ मंत्रालयों और विभागों में लैंगिक बजट प्रकोष्ठ बनाए गए।
- विवरण का भाग क उन योजनाओं की सूची देता है जिनमें महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान है; भाग ख उन योजनाओं की सूची देता है जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए है।
- मिशन शक्ति (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की समर्थ उप-योजना लैंगिक बजटिंग का समर्थन करती है और पूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखती है।
- ओडिशा और कर्नाटक इसे अपनाने वाले राज्यों में शामिल हैं।

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव

संदर्भ: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फरवरी 2026 में 118 विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा होने तक कार्यवाही की अध्यक्षता न करने का निर्णय लिया, जिस पर चर्चा और मतदान 9 मार्च को होना है। इस घटना ने अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों तथा पहले के ऐसे प्रस्तावों की ओर ध्यान खींचा है, जिनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ।

□ **प्रक्रिया**

- नियम 200 के अनुसार महासचिव को कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है।
- नियम 200A के अनुसार प्रस्ताव विशिष्ट, स्पष्ट शब्दों में और तर्कों या मानहानिकारक कथनों से मुक्त होना चाहिए।
- यदि कम से कम 50 सदस्य समर्थन में खड़े हों तो अनुमति दी जाती है, और 10 दिनों के भीतर चर्चा होती है।
- नियम 203 सामान्य भाषणों को 15 मिनट तक सीमित करता है।
- प्रस्ताव पारित होने के लिए तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत आवश्यक है; अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, किंतु सांसद बना रहता है।

□ **पूर्व के प्रस्ताव**

- 1954: जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध, ऐसा पहला प्रस्ताव।
- 1966: हुकम सिंह के विरुद्ध।
- 1987: बलराम जाखड़ के विरुद्ध।
- इनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ।

वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम-II और सीमा प्रौद्योगिकी

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री ने फरवरी 2026 में असम के कछार से ₹6,839 करोड़ के वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम-II की शुरुआत की, जिसमें बुनियादी ढाँचे के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ सीमावर्ती गाँवों को शामिल किया गया है। उन्होंने ड्रोन और सुरंगों जैसे नए सीमा खतरों के विरुद्ध उन्नत प्रौद्योगिकी पर भी बल दिया।

□ **वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम-II**

- सीमावर्ती खंडों के चयनित गाँवों को चार क्षेत्रों में पूर्ण कवरेज मिलता है: सभी मौसमों में उपयोगी सड़कें, दूरसंचार, टेलीविज़न और विद्युतीकरण।
- विद्युतीकरण में ग्रिड आपूर्ति और नवीकरणीय समाधानों को मिलाया गया है।
- यह कार्यक्रम अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से मौजूदा केंद्रीय योजनाओं का अभिसरण करता है।
- आजीविका सहायता में पर्यटन, कौशल, सहकारिताएँ, कृषि, बागवानी और औषधीय पौधे शामिल हैं।
- गाँवों का चयन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता, सुरक्षा संवेदनशीलता और रणनीतिक प्रासंगिकता के आधार पर किया जाता है।
- वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम-I 2023 में उत्तरी सीमा के गाँवों के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

- VVP-II 2025 में स्वीकृत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो VVP-I के अंतर्गत आने वाले गाँवों के अतिरिक्त 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में स्थलीय सीमाओं के गाँवों के लिए है।

□ **सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी**

- BOLD-QIT जैसी पायलट परियोजनाओं के बाद, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के चरण II और III लगभग 1,955 किमी की संवेदनशील सीमाओं को कवर करेंगे।
- सीमा सुरक्षा बल (BSF) एक एकीकृत स्मार्ट सीमा निगरानी प्रणाली की योजना बना रहा है।
- पश्चिमी क्षेत्र में ड्रोन से मादक पदार्थों और हथियारों को गिराने की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

विमुक्त जनजातियों की जनगणना में अलग कॉलम की माँग

संदर्भ: विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ 2027 की जनगणना में अलग कॉलम और एक पृथक संवैधानिक अनुसूची चाहती हैं। उनका कहना है कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में खो जाती हैं और लक्षित कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं ले पातीं।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारत फरवरी 2027 में 1931 के बाद पहली बार जाति गणना करेगा।
- कई विमुक्त जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में समाहित कर दिया गया, जहाँ राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त समूह उन्हें पीछे छोड़ देते हैं।
- आरोप है कि 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरसन के बावजूद पुलिस अब भी उन्हें आदतन अपराधी मानती है।
- राज्य उचित विमुक्त जनजाति प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहे हैं, जिससे कल्याण योजनाओं तक पहुँच बाधित होती है।
- कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय जनसंख्या आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।

□ **सीड (SEED) योजना**

- विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
- यह ₹200 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- यह ₹2.5 लाख से कम आय वाले परिवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका सहायता प्रदान करती है।
- दिसंबर 2025 तक केवल ₹69.3 करोड़ ही व्यय किए गए थे।

शहरीकरण और बजट 2026-27 के शहरी उपाय

संदर्भ: केंद्रीय बजट 2026-27 ने नगर आर्थिक क्षेत्रों, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को सहायता तथा नगरपालिका बॉण्ड प्रोत्साहनों के माध्यम से शहरी विकास को प्राथमिकता दी। ये उपाय इस बहस के बीच आए हैं कि भारत शहरीकरण को कैसे परिभाषित और मापता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- जनगणना किसी स्थान को शहरी तब मानती है जब जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष कामगार गैर-कृषि कार्यों में हों और घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो; इसके अलावा वैधानिक नगर भी शहरी माने जाते हैं। उपग्रह-आधारित GHSL आँकड़ों ने संकेत दिया कि 2015 में भारत लगभग 63 प्रतिशत शहरी था, जो 2011 की जनगणना के आँकड़े का लगभग दोगुना है।
- नगर आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण विकास प्रेरकों के आसपास किया जाएगा, जिसमें पाँच वर्षों में प्रति क्षेत्र ₹5,000 करोड़ दिए जाएँगे।
- अवसंरचना में प्राथमिकता 0.5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों तथा मंदिर नगरों को दी जाती है।
- ₹1,000 करोड़ से अधिक के एकल नगरपालिका बॉण्ड निर्गम पर ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि AMRUT ₹200 करोड़ या उससे कम के निर्गमों का समर्थन जारी रखता है।
- 2026-27 में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ दिए जाते हैं।
- केरल जनगणना (2011) के अनुसार 47.7 प्रतिशत शहरी है, लेकिन DEGURBA पद्धति के अंतर्गत लगभग 80.8 प्रतिशत।

समाचारों में संसदीय और चुनावी अवधारणाएँ

संदर्भ: फरवरी 2026 में कई संवैधानिक और संसदीय मुद्दे सामने आए: NOTA पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, और वापस बुलाने के अधिकार (राइट टू रिकॉल) का एक प्रस्ताव। ये अवधारणाएँ परीक्षा में प्रायः पूछी जाती हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- NOTA को PUCL बनाम भारत संघ (2013) के निर्णय के बाद लागू किया गया, जिसमें निर्वाचन आयोग को इसे EVM पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसका पहली बार प्रयोग छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 2013 के विधानसभा चुनावों में हुआ।
- अनुच्छेद 87(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
- अभिभाषण पर चर्चा लोकसभा की नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत धन्यवाद प्रस्ताव पर होती है, और सदस्य चूकों पर खेद व्यक्त करने वाले संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि NOTA की शुरुआत के एक दशक से अधिक समय बाद भी दलों द्वारा उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के चयन पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है।
- इस अवधि में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की माँग करने वाला विपक्षी प्रस्ताव लाया गया।

- यदि NOTA को सबसे अधिक मत मिलें, तब भी अगले सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है।
- महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोग NOTA को काल्पनिक उम्मीदवार मानते हैं और उसके बहुमत पाने पर पुनर्निर्वाचन का आदेश देते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप-मेटा डेटा साझाकरण पर सवाल उठाए

संदर्भ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2021 की 'मानो या छोड़ो' निजता नीति को लेकर व्हाट्सऐप और मेटा की आलोचना की और कहा कि व्यावसायिक संचालन की आड़ में नागरिकों की निजता से समझौता नहीं किया जा सकता। यह मामला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के जुर्माने से उत्पन्न हुआ है।

□ मुख्य बिंदु

- CCI ने माना कि व्हाट्सऐप ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग किया। नवंबर 2024 में उसने ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया और विज्ञापन के लिए उपयोगकर्ता डेटा को मेटा की अन्य इकाइयों के साथ साझा करने पर पाँच वर्ष का प्रतिबंध लगाया।
- राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) ने दुरुपयोग के निष्कर्ष और जुर्माने को बरकरार रखा, किंतु पाँच वर्ष के प्रतिबंध को रद्द कर दिया, यह उल्लेख करते हुए कि निजता का नियमन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत होगा।

□ सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- कंपनियाँ नागरिकों की निजता के साथ 'खिलवाड़' नहीं कर सकतीं।
- 'मानो या छोड़ो' नीति के अंतर्गत दी गई सहमति भ्रामक हो सकती है, क्योंकि व्हाट्सऐप छोड़ना देश छोड़ने जैसा है।
- न्यायालय ने व्यवहारगत डेटा के आर्थिक मूल्य और इस प्रश्न को उठाया कि इससे किसे लाभ होता है।
- जब तक मेटा डेटा साझा न करने का वचन नहीं देता, तब तक अपील खारिज की जा सकती है या कठोर अंतरिम निर्देश दिए जा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक रूढ़िवादिता पुस्तिका पर पुनर्विचार कर रहा है

संदर्भ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय से उत्पन्न स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए, जिसमें कुछ कृत्यों को बलात्कार के प्रयास के बजाय मात्र 'तैयारी' कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने संबंधी 2023 की पुस्तिका से हटने का संकेत दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पुस्तिका को अत्यधिक अकादमिक बताया और व्यावहारिक न्यायिक प्रशिक्षण की माँग की।

□ वर्तमान मामला

- सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाई और फिर उसे निरस्त कर दिया।
- निचली अदालत को बलात्कार के प्रयास के आरोपों पर कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी होगी।
- न्यायाधीशों को यौन हमले के मामलों को संवेदनशीलता से संभालने का बैच-वार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

□ 2023 की पुस्तिका

- तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में अगस्त 2023 में जारी; यह 35 पृष्ठों की है।
- इसमें रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले शब्दों की सूची उनके पसंदीदा विकल्पों के साथ दी गई है, जैसे 'ईव टीज़िंग' के स्थान पर 'सड़क पर यौन उत्पीड़न' और 'हाउसवाइफ' के स्थान पर 'गृहिणी/होममेकर'।
- इसमें कहा गया है कि कपड़े, शराब का सेवन या प्रतिरोध का अभाव सहमति का संकेत नहीं है।
- इसमें पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता पर स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह (1996) और टू-फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने वाले स्टेट ऑफ झारखंड बनाम शैलेंद्र कुमार राय (2022) का उल्लेख है।

CEC नियुक्ति अधिनियम: मुख्य न्यायाधीश का अलग होना और बड़ी पीठ को संदर्भ

संदर्भ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने संभावित हितों के टकराव का हवाला देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले को मुख्य न्यायाधीश उत्तराधिकार पंक्ति से बाहर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। इस कदम से स्वयं को अलग करने के सिद्धांत और आवश्यकता के सिद्धांत पर चर्चा छिड़ गई है।

□ मुख्य बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी 2024 में स्वयं को अलग कर लिया था।
- दूसरे न्यायाधीश मामले (1993) ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता की परंपरा स्थापित की।

□ सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ

- पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को न केवल स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए।
- न्यायमूर्ति दत्ता ने प्रश्न उठाया कि क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका केवल सजावटी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री तीन चयनकर्ताओं में से दो होते हैं।

- दोनों न्यायाधीशों ने संविधान पीठ के मामलों के लंबे समय से लंबित रहने की ओर संकेत किया।

□ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना

- अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाने की अनुमति देता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होते हैं।
- आधार अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत सिद्ध कदाचार या अक्षमता हैं।
- प्रस्ताव के लिए लोकसभा के 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- पारित होने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है, जिसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश देते हैं।
- अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं।
- आज तक किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया गया है; मार्च 2026 में प्रस्तुत प्रस्तावों को अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने अस्वीकार कर दिया।

IVFRT योजना 2031 तक बढ़ाई गई

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आप्रवासन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को पाँच वर्ष, अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक, ₹1,800 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी। गृह मंत्रालय की यह परियोजना पहली बार 2010 में स्वीकृत हुई थी।

□ मुख्य बिंदु

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य आप्रवासन, वीज़ा और विदेशी पंजीकरण प्रणालियों को एकीकृत और आधुनिक बनाना है।
- इसके स्तंभ हैं उभरती प्रौद्योगिकी, आप्रवासन चौकियों, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (FRRO) और डेटा केंद्रों सहित मूल अवसंरचना, तथा सेवा अनुकूलन।
- लगभग 91% ई-वीज़ा 72 घंटों के भीतर संसाधित किए जाते हैं।
- आप्रवासन निकासी का समय 5 से 6 मिनट से घटकर 2.5 से 3 मिनट रह गया है।
- फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम ई-गेट के माध्यम से निकासी का समय लगभग 30 सेकंड कर देता है।

उच्चतम न्यायालय का निर्देश: कोविड टीके से हुई क्षति के लिए बिना-दोष मुआवज़ा

संदर्भ: रचना गंगू बनाम भारत संघ (2026) में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित या मृत लोगों के लिए बिना-दोष (no-fault) मुआवज़ा नीति बनाए। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य, शारीरिक अखंडता और गरिमा शामिल हैं। इसने वैज्ञानिक कार्य-कारण का निर्णय स्वयं करने से इनकार कर दिया।

□ मुख्य बिंदु

- बिना-दोष का अर्थ है कि दावेदार को केवल कार्य-कारण दिखाना होता है, चिकित्सा लापरवाही या टीके में दोष नहीं।
- मौजूदा AEFI (टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएँ) तंत्र पर्याप्त है; कोई नया चिकित्सा बोर्ड गठित करने का आदेश नहीं दिया गया।
- न्यायालय ने दीवानी अदालतों में जाने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लापरवाही सिद्ध करना वैज्ञानिक रूप से जटिल और बोझिल है।
- समान मुआवज़ा ढाँचे का अभाव अनुच्छेद 21 और 14 के अंतर्गत संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करता है।

उच्चतम न्यायालय का महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश

संदर्भ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन संबंधित निर्णय दिए, जिनमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना को पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया गया। जो पहले ही सेवा से मुक्त हो चुकी हैं, उन्हें पूर्ण पेंशन मिलेगी, और उन्हें 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी की हुई माना जाएगा। पेंशन का बकाया 1 जनवरी 2025 से देय है।

□ मुख्य बिंदु

- सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया (थल सेना) और भारत संघ बनाम एनी नागराजा (नौसेना) में 2020 के निर्णयों ने महिलाओं पर पुरुषों के समान स्थायी कमीशन के लिए विचार करना आवश्यक किया।
- 2020 के बाद, कई महिलाओं को चयन बोर्डों ने अस्वीकार कर दिया, जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर निर्भर थे।
- वे रिपोर्टें तब लिखी गई थीं जब महिलाओं को स्थायी कमीशन से वंचित रखा गया था, इसलिए मूल्यांकनकर्ताओं ने उन्हें लापरवाही से श्रेणीबद्ध किया।
- न्यायालय ने इसे मूल्यांकन में निहित प्रणालीगत पक्षपात माना।

उच्चतम न्यायालय ने दत्तक माताओं को भी सवेतन मातृत्व अवकाश दिया

संदर्भ: हमसानंदिनी नंदुरी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के उस प्रतिबंध को रद्द कर दिया, जो दत्तक माताओं के अवकाश को उन मामलों तक सीमित करता था जहाँ बच्चा तीन माह से कम आयु का हो। अब दत्तक माताएँ बच्चे की आयु की परवाह किए बिना 12 सप्ताह के सवेतन अवकाश की हकदार हैं। न्यायालय ने पितृत्व अवकाश के लिए भी कानूनी ढाँचे का आग्रह किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में मूल रूप से 12 सप्ताह का अवकाश था; 2017 के संशोधन ने जैविक माताओं के लिए अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया।
- अधिनियम की धारा 5(4), जो बाद में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4) बनी, ने दत्तक अवकाश को तीन माह से कम आयु के बच्चों तक सीमित किया था।
- आँकड़ों से पता चला कि गोद लिए गए बच्चों में 5% से कम तीन माह से कम आयु के होते हैं।
- न्यायालय ने कहा कि मातृत्व को जीव विज्ञान के संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता और गोद लेने को प्रजनन स्वायत्तता से जोड़ा।

□ **पितृत्व अवकाश**

- पुरुष केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है (दो से कम जीवित बच्चे होने पर)।
- पितृत्व अवकाश पर कोई व्यापक राष्ट्रीय कानून नहीं है; निजी क्षेत्र की नीतियाँ अलग-अलग हैं।

उच्चतम न्यायालय: धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। यह रोक संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद (पैराग्राफ) 3 से आती है और इसे स्पष्ट तथा पूर्ण बताया गया। न्यायालय ने एक पादरी से जुड़े उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा।

□ **न्यायालय ने क्या कहा**

- जाति प्रमाण-पत्र और कार्यकारी आदेश संवैधानिक योजना को अधिभावी (override) नहीं कर सकते; अनुसूचित जाति का दर्जा केवल अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से शासित होता है।
- 'अभिव्यक्त करना' (Profess) का अर्थ सार्वजनिक घोषणा और बाह्य आचरण है, केवल निजी आस्था नहीं।
- दर्जा समाप्त होने पर आरक्षण, कल्याणकारी अधिकार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत संरक्षण समाप्त हो जाता है।
- अनुसूचित जाति के धर्मांतरितों को लाभ देने वाला आंध्र प्रदेश का आदेश केवल गैर-वैधानिक रियायतों पर लागू होता है।
- पुनः धर्मांतरण के लिए मूल जाति का प्रमाण, वास्तविक पुनः धर्मांतरण और समुदाय द्वारा स्वीकृति आवश्यक है, जिसमें सबूत का भार दावेदार पर होता है।

□ **अनुसूचित जाति बनाम अनुसूचित जनजाति**

- अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म पर निर्भर करता है।
- अनुसूचित जनजाति का दर्जा जनजातीय पहचान की निरंतरता और समुदाय की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

कुकी और हमार समूहों के साथ असम शांति समझौता

संदर्भ: मार्च 2026 में असम सरकार ने तीन कुकी उग्रवादी समूहों और एक हमार समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह राज्य में जातीय उग्रवाद को समाप्त करता है। समझौते से गुवाहाटी में मुख्यालय वाली दो कल्याण विकास परिषदें बनेंगी और कैडरों के पुनर्वास का प्रावधान है। यह आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद-समझौते से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- दो परिषदें गठित की जाएँगी: हमार कल्याण विकास परिषद और कुकी कल्याण विकास परिषद, दोनों का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा।
- प्रत्येक में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी सदस्य, कार्यकारी सदस्य और सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे।
- कैडरों का पुनर्वास मौजूदा प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाएगा और मारे गए कैडरों के परिवारों को मुआवज़ा दिया जाएगा।
- बोडो, कार्बी और आदिवासी समूहों के 9,000 से अधिक कैडरों का पहले ही पुनर्वास किया जा चुका है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026

संदर्भ: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 राज्य सभा में CAPF अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों पर एक एकल कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया। इसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB शामिल हैं। विधेयक वरिष्ठ स्तरों पर IPS प्रतिनियुक्ति को बनाए रखता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- केंद्र ग्रुप A सामान्य ड्यूटी अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों पर नियम बना सकता है, जो परस्पर विरोधी कानूनों, न्यायालय के आदेशों या पूर्व नियमों पर प्रभावी होंगे।
- IPS प्रतिनियुक्ति: महानिरीक्षक स्तर पर 50%, अपर महानिदेशक स्तर पर कम से कम 67%, और विशेष महानिदेशक तथा महानिदेशक स्तर पर 100%।
- केंद्र अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में संशोधन कर सकता है; परिवर्तन तुरंत प्रभावी होते हैं, लेकिन उन्हें दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है, जो उन्हें संशोधित या रद्द कर सकते हैं।
- ग्रुप A GD अधिकारियों को पहले से दिए गए भत्ते नए आदेश जारी होने तक जारी रहेंगे।
- पाँचों बलों में सेवा नियमों का मानकीकरण करना।

- मुकदमेबाजी कम करने के लिए बिखरे हुए नियमों के स्थान पर एक कानून लाना।
- सुरक्षा अभियानों में केंद्र-राज्य समन्वय के लिए IPS प्रतिनियुक्ति को बनाए रखना।

क्या न्यायालय व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं: शरीयत अधिनियम याचिका

संदर्भ: विरासत में लैंगिक भेदभाव के आधार पर मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 के विरुद्ध एक याचिका ने उच्चतम न्यायालय को यह पूछने के लिए प्रेरित किया है कि क्या व्यक्तिगत कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के बाद यह अधिनियम एक सामान्य नागरिक कानून की तरह कार्य करता है। न्यायालय ने मौखिक रूप से संसद पर निर्णय छोड़ने का सुझाव दिया।

□ मुख्य बिंदु

- याचिका में मुस्लिम महिलाओं के लिए उत्तराखंड UCC के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के समान संपत्ति के बराबर अधिकार माँगे गए हैं। यह अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 पर आधारित है, और तर्क देती है कि विरासत एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक विषय (मुआमलात) है, पूजा (इबादत) नहीं।
- अनुच्छेद 25(2)(b) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है।
- उच्चतम न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अधिनियम को रद्द करने से कानूनी शून्यता उत्पन्न हो सकती है और संसद को समान नागरिक संहिता लानी चाहिए।

गिलोटिन और अनुदान की माँगें 2026-27

संदर्भ: लोक सभा ने गिलोटिन लागू करके बिना चर्चा के 2026-27 के लिए मंत्रालयों की अनुदान की माँगें पारित कीं, जो ₹53 लाख करोड़ से अधिक की हैं। लोक सभा ने आठ सांसदों का निलंबन भी रद्द किया और नए आचरण नियम जारी किए।

□ गिलोटिन

- समय समाप्त होने पर सभी शेष माँगों को एक साथ मतदान के लिए रखने हेतु अध्यक्ष द्वारा इसे लागू किया जाता है।
- अनुदान की माँगों पर केवल लोक सभा मतदान करती है; राज्य सभा को उन पर मतदान की शक्ति नहीं है।
- गिलोटिन के बाद विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकालने को अधिकृत करता है, और फिर वित्त विधेयक कर प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है।
- राज्य सभा विनियोग विधेयक पर केवल चर्चा कर सकती है और उसे लौटा सकती है।

□ सांसदों के लिए नए आचरण नियम

- संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान AI-निर्मित चित्रों और अपमानजनक चित्रों या नारों पर प्रतिबंध।
- आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियाँ, भाले, तलवारें, लाठियाँ और ईंट-पत्थर ले जाने पर निषेध।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति मिली

संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दे दी है, जो 2019 के अधिनियम में संशोधन करता है। सबसे चर्चित परिवर्तन लिंग की स्व-पहचान को हटाकर उसके स्थान पर चिकित्सकीय प्रमाणन लाना है। अधिकार समूह इसे नालसा (2014) की स्थिति से पीछे हटना मानते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- नालसा बनाम भारत संघ (2014) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी और अनिवार्य चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बिना स्व-पहचान के अधिकार को बरकरार रखा। 2019 के अधिनियम ने पहचान पत्रों, दस्तावेज़ों में तृतीय लिंग की प्रविष्टि और कल्याण बोर्डों के माध्यम से मान्यता को संस्थागत रूप दिया; 32,000 से अधिक पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा को किन्नर, हिजड़ा, अरावणी, जोगता और ख्वाजासरा (eunuch) जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों तथा निर्दिष्ट जन्मजात जैविक विभिन्नताओं वाले व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है।
- एक नई श्रेणी उन व्यक्तियों को शामिल करती है जिन्हें दबाव, शल्य-क्रिया या छल-छद्म द्वारा ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए विवश किया गया।
- स्व-अनुभूत लिंग पहचान की अनुमति देने वाला प्रावधान हटा दिया गया है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाला एक चिकित्सा बोर्ड आवेदकों का आकलन करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को सलाह देगा।
- संबंधित निकाय में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अब निदेशक स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी होने चाहिए।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) ने सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया, जबकि सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023) ने गैर-विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं दी।

□ नए दंड

- किसी वयस्क को ट्रांसजेंडर पहचान के लिए विवश करना: 10 वर्ष से आजीवन कारावास और ₹2 लाख का जुर्माना।
- किसी बच्चे को ट्रांसजेंडर पहचान के लिए विवश करना: आजीवन कारावास और ₹5 लाख का जुर्माना।

- किसी वयस्क से जबरन भीख मँगवाना या दासता कराना: 5 से 10 वर्ष का कारावास और ₹1 लाख का जुर्माना।
- किसी बच्चे से जबरन भीख मँगवाना या दासता कराना: 10 से 14 वर्ष का कारावास और ₹3 लाख का जुर्माना।

नक्सल-मुक्त भारत: घोषणा और राज्य

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में भारत को 'नक्सल-मुक्त' घोषित किया, यह उनके द्वारा माओवादी हिंसा समाप्त करने के लिए तय की गई 31 मार्च 2026 की समय-सीमा से एक दिन पहले हुआ। उन्होंने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है।

□ मुख्य बिंदु

- CPI (माओवादी) का पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमान ढाँचा लगभग पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है।
- चरम स्थिति में 12 राज्य रेड कॉरिडोर का हिस्सा थे।
- माओवादी हिंसा में लगभग 20,000 लोग मारे गए, जिनमें 5,000 सुरक्षाकर्मी शामिल थे।
- बस्तर में विकास के अंतर्गत हर गाँव में स्कूल, राशन दुकानें, आधार और राशन कार्ड तथा 5 किलो मुफ्त राशन शामिल थे।
- बेला ग्राम (भंडारा, विदर्भ) पंचायत नेतृत्व के माध्यम से महाराष्ट्र का पहला नेट-ज़ीरो गाँव बना (फरवरी 2026); इसने 2024 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार जीता था।

□ घोषणाएँ

- मध्य प्रदेश: बालाघाट में दो माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य को नक्सल-मुक्त घोषित किया (दिसंबर 2025)।
- बिहार: राज्य पुलिस के अनुसार फरवरी 2026 में नक्सल गतिविधि से मुक्त घोषित।
- तेलंगाना: 42 कैडरों के हथियार डालने के बाद अप्रैल 2026 में नक्सल-मुक्त घोषित।

भारत-म्यांमार सीमा: बाड़बंदी और मुक्त आवागमन व्यवस्था

संदर्भ: मिज़ोरम के रास्ते म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण देने के आरोप में सात विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने काफी हद तक बिना बाड़ वाली भारत-म्यांमार सीमा की ओर ध्यान खींचा है। 1,643 किमी लंबी सीमा में से केवल 43 किमी पर बाड़ लगी है।

□ मुख्य बिंदु

- राज्यवार सीमा की लंबाई: अरुणाचल प्रदेश 520 किमी, नगालैंड 215 किमी, मणिपुर 398 किमी, मिज़ोरम 510 किमी।
- सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्च 2024 में ₹31,000 करोड़ की लागत से बाड़बंदी परियोजना को मंजूरी दी।
- सड़क कार्य: 3,194.8 किमी स्वीकृत, 941.91 किमी के ठेके दिए गए, 11.5 किमी पूर्ण।
- बाड़बंदी में बायोमेट्रिक गेट शामिल हैं; मासिक रिपोर्टिंग के साथ एक संयुक्त ड्रोन-रोधी तंत्र मौजूद है।
- असम राइफल्स सीमा की रक्षा करती है; यह सेना के परिचालन नियंत्रण और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का पहला नोटिस

संदर्भ: दोनों सदनों के विपक्षी सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की माँग वाले नोटिस दिए, जिन पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध ऐसा नोटिस पहली बार दिया गया है। आरोपों में पक्षपातपूर्ण आचरण और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा बड़े पैमाने पर मताधिकार-हनन शामिल हैं।

□ मुख्य बिंदु

- नोटिस में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण का आरोप लगाया गया है।
- इसमें चुनावी अनियमितताओं की जाँच में बाधा डालने का आरोप है।
- इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, मतदाता सूचियों से वास्तविक मतदाताओं को हटाने का उल्लेख है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए प्रयुक्त कठोर प्रक्रिया के समान है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य चुनाव कर्मचारी चुनाव कार्य के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं।
- ऐसे अधिकारी ECI के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन में रहते हैं, और कर्तव्य में लापरवाही के लिए ECI उन्हें निलंबित या प्रतिस्थापित कर सकता है।

रक्षा बल विज़न 2047 जारी

संदर्भ: मार्च 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'रक्षा बल विज़न 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सैन्य बल का रोडमैप' जारी किया, जिसे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने तैयार किया है। यह तीनों सेनाओं को एक साथ शामिल करने वाला पहला दीर्घकालिक विज़न दस्तावेज़ है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय, चुस्त बल और आत्मनिर्भरता है।

□ मुख्य बिंदु

- लक्ष्य 2047 तक एक एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय और चुस्त बल बनाना है।
- बहु-क्षेत्रीय का अर्थ है भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में कार्य करना।

- यह तीनों सेनाओं को एक साथ शामिल करने वाला पहला दीर्घकालिक विज़न दस्तावेज़ है।
- यह विकसित भारत 2047 के अनुरूप आत्मनिर्भरता और आयात निर्भरता में कमी पर बल देता है।

सर्वोच्च न्यायालय का अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर परीक्षण पर निर्णय

संदर्भ: भारत संघ बनाम रोहित नाथन (2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल माता-पिता की आय अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की क्रीमी लेयर स्थिति तय नहीं कर सकती। उसने सिविल सेवा अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए मद्रास, दिल्ली और केरल उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध केंद्र की अपीलें खारिज कर दीं। 1993 के कार्यालय ज्ञापन को शासी नीति घोषित किया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- 1993 का कार्यालय ज्ञापन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद बनाई गई बाध्यकारी नीति है, जबकि 2004 का स्पष्टीकरण पत्र केवल व्याख्यात्मक है।
- क्रीमी लेयर का ढाँचा मुख्यतः स्थिति-आधारित है, जो माता-पिता के पद या स्थान पर निर्भर करता है।
- आय और संपत्ति परीक्षण (श्रेणी VI) केवल एक अवशिष्ट छलनी है; इसे लागू करते समय वेतन और कृषि आय को अलग रखा जाना चाहिए।
- सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की संतानों को केवल वेतन के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता, जब सरकारी सेवाओं के साथ पदों की समतुल्यता निर्धारित नहीं की गई हो।
- उनके साथ सरकारी कर्मचारियों की संतानों से भिन्न व्यवहार को वैमनस्यपूर्ण भेदभाव माना गया, जो अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है।

□ **निर्देश**

- अभ्यर्थियों के दावों पर 1993 के कार्यालय ज्ञापन की सही व्याख्या के अनुसार पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
- सरकार को निर्देश दिया गया कि पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अधिसंख्य पद सृजित करे।
- न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के इस सिद्धांत को दोहराया कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत वास्तविक समानता का एक पहलू है।

हरीश राणा मामला: कॉमन कॉज़ के अंतर्गत पहली निष्क्रिय इच्छामृत्यु

संदर्भ: हरीश राणा बनाम भारत संघ (2026) में उच्चतम न्यायालय ने कॉमन कॉज़ ढाँचे के अंतर्गत पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी। इसने 13 वर्षों से अधिक समय से लगातार वानस्पतिक अवस्था (persistent vegetative state) में रहे 32 वर्षीय व्यक्ति के जीवन-रक्षक उपचार को हटाने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि PEG ट्यूब के माध्यम से कृत्रिम पोषण चिकित्सा उपचार है।

□ **मुख्य बिंदु**

- PEG ट्यूब के माध्यम से नैदानिक रूप से सहायता प्राप्त पोषण और जलयोजन (CANH) चिकित्सा उपचार है, बुनियादी देखभाल नहीं, इसलिए इसे हटाया जा सकता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के इस मत को अस्वीकार कर दिया गया कि वेंटिलेटर सहायता का न होना जीवन-रक्षक सहायता का न होना है।
- सर्वोत्तम हित परीक्षण यह पूछता है कि क्या उपचार जारी रखने से चिकित्सकीय लाभ मिलता है, उससे कौन-से बोझ पड़ते हैं, और क्या रोगी को बिना चेतना, स्वायत्तता या मानवीय संपर्क के जीवित रखा जा रहा है।

□ **प्रक्रियात्मक निर्देश**

- उच्च न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी करेंगे, ताकि अस्पताल उन्हें चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की औपचारिक सूचना दे सकें।
- जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा बोर्डों के शीघ्र गठन के लिए चिकित्सकों के पैनल बनाए रखने होंगे।

25% कोटे पर RTE धारा 12(1)(c) का निर्णय

संदर्भ: दिनेश बिवाजी अष्टीकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (जनवरी 2026) में उच्चतम न्यायालय ने RTE अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में वंचित बच्चों के लिए 25% आरक्षण के खराब क्रियान्वयन को संबोधित किया। उसने राज्यों को बाध्यकारी नियम बनाने का निर्देश दिया।

□ **मुख्य बिंदु**

- धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों को प्रवेश स्तर की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।
- इन बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा मिलती है और विद्यालयों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
- यह अनुच्छेद 21A को क्रियान्वित करता है और अनुच्छेद 14 का समर्थन करता है।
- सीट आवंटित हो जाने के बाद विद्यालय प्रवेश से इनकार या उसमें विलंब नहीं कर सकते और राज्य की चयन प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं उठा सकते।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को निगरानी और शिकायत निवारण का कार्य सौंपा गया।
- 50 लाख से अधिक बच्चों को लाभ मिला है और प्रतिधारण दर 90% है।

CBI अभय, प्रॉक्सी सरपंच अभियान और सेवा तीर्थ

संदर्भ: 2026 के दौरान शासन से संबंधित कई संस्थागत शुरुआतें हुईं। नोटिसों के सत्यापन के लिए CBI की AI-संचालित प्रणाली अभय का

शुभारंभ अप्रैल 2026 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया, पंचायती राज मंत्रालय ने मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर निर्वाचित महिलाओं के रिश्तेदारों द्वारा प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के विरुद्ध अभियान शुरू किया, और प्रधानमंत्री ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) वाले परिसर का नाम सेवा तीर्थ घोषित किया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 28 मई 2026 को सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज (President's Police Colour) प्रदान किया गया; सिक्किम इसे प्राप्त करने वाला 15वाँ राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य है।

➤ UIDAI ने 8 जनवरी 2026 को आधार शुभंकर (मैस्कॉट) लॉन्च किया।

➤ भारतीय सेना ने मई 2026 में रसद और अनुरक्षण प्रबंधन एप्लिकेशन Q-FORCE लॉन्च किया।

□ **CBI अभय**

➤ CBI द्वारा जारी नोटिसों के सत्यापन के लिए AI-संचालित चैटबॉट-शैली की प्रणाली, जिसे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 20 अप्रैल 2026 को 22वें डी.पी. कोहली स्मृति व्याख्यान में लॉन्च किया।

□ **प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें**

➤ पंचायती राज मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 2026 को निर्वाचित महिलाओं के रिश्तेदारों द्वारा प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के विरुद्ध देशव्यापी सोशल मीडिया अभियान शुरू किया।

□ **सेवा तीर्थ**

➤ प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को PMO वाले नए परिसर का नाम घोषित किया और कर्तव्य भवन 1 व 2 के साथ उसका उद्घाटन किया।

FCRA संशोधन विधेयक और नियम, 2026

संदर्भ: विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 बहस के बीच लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जबकि विपक्ष को NGO पर अत्यधिक कार्यपालिका नियंत्रण की आशंका है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 व्यक्तियों, NGO और संघों द्वारा विदेशी धन की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है।

➤ इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी अंशदान राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या जनहित को हानि न पहुँचाए।

➤ सरकार का तर्क है कि विधेयक धन के दुरुपयोग को रोकेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और निगरानी को केंद्रीकृत करेगा।

➤ NGO को अधिसूचित अनुसूची में से चुने गए विशिष्ट अनुमोदित उद्देश्यों के लिए पंजीकरण कराना होगा, जिसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग शुल्क होगा।

➤ मौजूदा पंजीकृत संगठनों के पास यह बताने के लिए एक वर्ष है कि वे कौन-से उद्देश्य बनाए रखना चाहते हैं।

➤ पंजीकरण प्रमाणपत्रों में उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम होंगे जहाँ विदेशी-वित्तपोषित कार्य किया जा सकता है; अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

➤ पूजा स्थल, धार्मिक शिक्षा और लंगर जैसी धार्मिक गतिविधियाँ अनुमत रहती हैं, किंतु धर्मांतरण के प्रयास को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

➤ 'प्रमुख पदाधिकारी' शब्द में अब निदेशक, न्यासी, भागीदार, पदाधिकारी, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता, शासी निकाय के सदस्य और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है।

□ **प्रकटीकरण और उपयोग संबंधी मानदंड**

➤ विदेशी नागरिक प्रमुख पदाधिकारियों (भारतीय मूल के व्यक्तियों को छोड़कर) वाले संघ सामान्यतः पंजीकरण या पूर्व अनुमति के लिए अपात्र होंगे, जब तक केंद्र द्वारा छूट न दी जाए।

➤ NGO को गतिविधि रिपोर्ट, वेबसाइट, सोशल मीडिया खाते, प्रकाशन और, जहाँ धन दाता-सलाहित निधियों या मध्यस्थों के माध्यम से आता है, वहाँ अंतिम दाताओं का प्रकटीकरण करना होगा।

➤ कोई संघ उचित गतिविधि तभी दर्शाता है जब उसने पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम ₹10 लाख विदेशी अंशदान का उपयोग किया हो।

➤ पूर्व-अनुमति वाले मामलों में अगली किस्त तभी जारी की जाती है जब पिछली किस्त का 75% उपयोग हो जाए और क्षेत्रीय जाँच से उसका सत्यापन हो जाए।

संशोधित शमन (कंपाउंडिंग) जुर्माने

उल्लंघन	संशोधित जुर्माना
20% की वैधानिक सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय	₹1 लाख या अधिकता का 5%, जो भी अधिक हो
विदेशी अंशदान का सट्टात्मक निवेश	₹1 लाख या निवेशित राशि का 30%, जो भी अधिक हो, साथ ही प्रतिफल का 100% वसूला जाएगा
अनुमोदित उद्देश्यों या क्षेत्रों से परे धन का अन्यत्र उपयोग	₹1 लाख या दुरुपयोग की गई राशि का 30%, जो भी अधिक हो

NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया

संदर्भ: शिक्षा मंत्रालय ने UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत 'डी नोवो' श्रेणी में NCERT को उसकी छह घटक इकाइयों सहित डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया। इससे वह स्वयं पाठ्यक्रम तैयार कर सकेगा और उपाधियाँ प्रदान कर सकेगा।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ छह इकाइयाँ हैं: अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरु और शिलांग के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान तथा भोपाल का पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान।

- NCERT और उसके संस्थान बिना संबद्धता के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और डॉक्टरेट उपाधियाँ प्रदान कर सकते हैं।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का समर्थन करता है।
- इसे UGC के मानदंडों, अकादमिक क्रेडिट बैंक, NAAC/NBA प्रत्यायन तथा NIRF में भागीदारी का पालन करना होगा।
- NCERT द्वारा 2017 में शुरू किया गया दीक्षा (DIKSHA) 36 भाषाओं में QR-कोड युक्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराता है।

अनुच्छेद 142 के अंतर्गत राजमार्ग सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश

संदर्भ: नवंबर 2025 में दो बड़ी सड़क दुर्घटनाओं में 34 लोगों की मृत्यु के बाद उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और बाध्यकारी राजमार्ग सुरक्षा निर्देश जारी करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। उसने सुरक्षित सड़कों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य के सकारात्मक कर्तव्य का भाग माना।

□ **मुख्य बिंदु**

- निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर राजमार्गों पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है।
- कैमरों, सूचना पट्टों, आपातकालीन कॉल बॉक्स और GPS ट्रैकिंग वाली उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणालियों को ई-चालान से जोड़ा जाना है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेंस और रिकवरी क्रेन 75 किमी से अधिक के अंतराल पर नहीं, बल्कि उससे कम अंतराल पर तैनात की जानी चाहिए।
- अनधिकृत सड़क किनारे के ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किया जाना है।
- राज्यों को राजमार्ग के मध्य बिंदु से 40 मी (आवासीय) और 75 मी (व्यावसायिक) के भीतर संरचनाओं पर प्रतिबंध अधिसूचित करने होंगे।
- निर्देशों को 60 दिनों में लागू किया जाना है, जिसके लिए पुलिस और परिवहन विभागों की राजमार्ग निगरानी टीमें NHAI के साथ मिलकर कार्य करेंगी और दुर्घटना-संभावित स्थलों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी।

अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अधिसूचित

संदर्भ: अमरावती को अप्रैल 2026 में पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से आंध्र प्रदेश की स्थायी एकमात्र राजधानी के रूप में अधिसूचित किया गया। इससे 2014 के विभाजन से शुरू हुई अनिश्चितता समाप्त हो गई।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह कानून 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव रखता है, जब तेलंगाना के साथ 10 वर्ष की साझा राजधानी की अवधि समाप्त हुई थी।
- यह पहली बार है जब किसी नगर को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करने के लिए संसद में विशेष विधेयक लाया गया।
- यह विशाखापत्तनम (कार्यपालिका), अमरावती (विधायिका) और कुरनूल (न्यायपालिका) की पूर्व की तीन-राजधानी योजना को निरस्त करता है।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2026

संदर्भ: केंद्र ने PROG अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 अधिसूचित किए। नियम एक केंद्रीय नियामक और खेलों को ऑनलाइन मनी गेम, सामाजिक खेल या ई-स्पोर्ट्स के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया बनाते हैं, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध बना रहता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI) की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है।
- प्राधिकरण में छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता MeitY के अपर सचिव करते हैं, जिसमें गृह, सूचना एवं प्रसारण, वित्त, विधि कार्य तथा युवा कार्य एवं खेल के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- किसी खेल की श्रेणी एक निर्धारण (determination) के माध्यम से तय की जाती है, जो 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।
- निर्धारण प्राधिकरण की स्वयं की कार्रवाई से, खेल को ई-स्पोर्ट्स के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रदाता के आवेदन पर, या केंद्र सरकार की अधिसूचना पर शुरू हो सकता है।
- जिन कारकों की जाँच की जाती है उनमें शुल्क या दाँव का भुगतान, मौद्रिक जीत की अपेक्षा, राजस्व मॉडल और पुरस्कारों को भुनाने का तरीका शामिल हैं।
- पंजीकरण ई-स्पोर्ट्स और केंद्र द्वारा अधिसूचित श्रेणियों पर लागू होता है, और प्रमाण-पत्र अधिकतम 10 वर्ष तक वैध रहता है।
- राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत किसी ऑनलाइन मनी गेम को ई-स्पोर्ट्स के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता।
- बैंकों और भुगतान गेटवे को लेन-देन संसाधित करने से पहले खेल की नियामकीय स्थिति की जाँच करनी होगी।
- उपयोगकर्ता सुरक्षा उपायों में आयु सत्यापन, समय सीमा, अभिभावकीय नियंत्रण और परामर्श सहायता शामिल हैं।
- उपयोगकर्ता पहले प्रदाता से, फिर 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण से, और अंत में अपीलीय प्राधिकरण, यानी MeitY सचिव, से अपील कर सकते हैं।
- सामाजिक खेल या ई-स्पोर्ट्स प्रदान करने वाले प्लेटफ़ॉर्मों को डेटा भारत में संग्रहीत करना होगा।
- कार्यवाही डिजिटल होती है और शिकायत के 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी है।

खाप पंचायत के फरमानों पर राजस्थान उच्च न्यायालय

संदर्भ: राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि खाप पंचायतों और इसी प्रकार की जातीय परिषदों द्वारा जारी फरमान असंवैधानिक हैं और विधि के शासन को कमजोर करते हैं। उसने 'हुक्का-पानी बंद' जैसी सामाजिक बहिष्कार की प्रथाओं की आलोचना की।

□ **मुख्य बिंदु**

- न्यायालय ने ऐसी संस्थाओं को वैधानिक अधिकार के बिना समानांतर न्याय-निर्णय प्रणालियाँ कहा।
- उसने कहा कि इनके निर्देश अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं।
- उसने सामाजिक बहिष्कार को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना।
- उसने राज्य की निष्क्रियता से निपटने के लिए नीति, मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) और प्रशासनिक जवाबदेही का निर्देश दिया।
- याचिकाओं में सिरोही, बाड़मेर, नागौर, बालोतरा, जालोर और जोधपुर के मामले उजागर किए गए।

गृह मंत्रालय ने LWE प्रभावित जिलों का पुनर्वर्गीकरण किया

संदर्भ: अप्रैल 2026 में गृह मंत्रालय ने हिंसा में कमी आने पर वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों का वर्गीकरण संशोधित किया और पूर्व की 'सर्वाधिक प्रभावित' श्रेणी को हटा दिया। नई श्रेणियाँ हैं: LWE प्रभावित (2 जिले), चिंता के जिले (1) तथा विरासत और जोर वाले जिले (35)। LWE प्रभावित जिले 2005 में 200 से अधिक थे, जो 2026 में घटकर केवल 2 रह गए हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- LWE प्रभावित जिले छत्तीसगढ़ का बीजापुर और झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम हैं।
- छत्तीसगढ़ का कांकेर चिंताग्रस्त जिला है।
- LWE प्रभावित जिले 2005 में 200 से अधिक थे, जो 2026 में घटकर केवल 2 रह गए।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026

संदर्भ: संसद ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यह व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कई केंद्रीय अधिनियमों में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2025 का संस्करण अगस्त 2025 में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। सुधारों का दायरा बढ़ाने के लिए इसे मार्च 2026 में वापस ले लिया गया।
- यह 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन करता है।
- इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है और 67 में संशोधन किया गया है।
- 1,000 से अधिक अपराधों को युक्तिसंगत बनाया गया है; लगभग 805 को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जिनमें कारावास के स्थान पर दीवानी जुर्माना या चेतावनी रखी गई है।
- लगभग 125 अपराध अनावश्यक होने या भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा कवर होने के कारण हटा दिए गए हैं।
- आपराधिक जुर्माने (न्यायालय द्वारा लगाए गए) को दीवानी जुर्माने (प्रशासनिक रूप से लगाए गए) से अलग किया गया है।
- जन विश्वास अधिनियम, 2023 ने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन किया था।

दल-बदल विरोधी कानून और AAP राज्य सभा विलय विवाद

संदर्भ: आम आदमी पार्टी के दस राज्य सभा सांसदों में से सात भाजपा में चले गए, जिससे उच्च सदन में AAP की संख्या तीन रह गई। इस घटना ने दसवीं अनुसूची में विलय के अपवाद और अयोग्यता का निर्णय कौन करे, इस पर बहस को फिर से जगा दिया।

□ **मुख्य बिंदु**

- विवाद पैराग्राफ 4 से संबंधित है: संयोजी (conjunctive) पाठ के अनुसार मूल पार्टी का विलय और विधायक दल की दो-तिहाई सहमति, दोनों आवश्यक हैं। वियोजी (disjunctive) पाठ केवल विधायक दल की दो-तिहाई सहमति को ही मान्य विलय मानता है।
- दसवीं अनुसूची सदस्यों को अयोग्यता से संरक्षण देती है, यदि विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय के लिए सहमत हों।
- दस में से सात दो-तिहाई की सीमा से अधिक है, इसलिए इस कदम को विलय माना जा सकता है।
- राज्य सभा के सभापति इस मामले का निर्णय करते हैं और उनका निर्णय बाद में न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है।
- कानून पीठासीन अधिकारी के निर्णय पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता।
- कानून विलय को मान्यता देता है, विभाजन को नहीं, क्योंकि 2003 में 91वें संशोधन द्वारा विभाजन का अपवाद हटा दिया गया था।
- राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007) में उच्चतम न्यायालय संयोजी पाठ की ओर झुका।

- गोवा के मामले में कांग्रेस के 15 में से दस विधायक भाजपा में शामिल हुए; बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फरवरी 2022 में वियोजी दृष्टिकोण अपनाते हुए अध्यक्ष द्वारा इसकी स्वीकृति को बरकरार रखा।
- राज्य सभा सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, और इन सांसदों को चुनने वाले पंजाब के AAP विधायक AAP में ही बने हुए हैं।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का त्यागपत्र और न्यायाधीशों का महाभियोग

संदर्भ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने घर में नकदी विवाद से उत्पन्न महाभियोग कार्यवाही के दौरान 2026 में अनुच्छेद 217(1)(a) के अंतर्गत त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र से पद से हटाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई और न्यायिक जवाबदेही की कमियाँ उजागर हुईं।

□ **मुख्य बिंदु**

- बताया जाता है कि 2025 में आग लगने के बाद उनके आवास पर बिना हिसाब की नकदी मिली, जिससे आंतरिक जाँच और महाभियोग कार्यवाही शुरू हुई।
- जाँच समिति ने कार्यवाही बंद कर दी और अपनी रिपोर्ट लोकसभा को भेज दी।
- पदस्थ न्यायाधीश के पद छोड़ देने के बाद पद से हटाने की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।
- स्वीकृति के अधीन, सामान्य कानून के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही अब भी शुरू की जा सकती है।
- संविधान लागू होने के बाद से किसी भी न्यायाधीश पर सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं चलाया गया है।

पहलगाम के एक वर्ष बाद: आतंकवाद-रोधी रणनीति में बदलाव

संदर्भ: अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के एक वर्ष बाद जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा रणनीति खुफिया-आधारित और भू-भाग-केंद्रित अभियानों की ओर बदल गई है। भारत का व्यापक सिद्धांत अब बड़े हमलों को निरंतर, बहुआयामी जवाबी कार्रवाई का कारण मानता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- सिंधु जल संधि को स्थगित रखा गया है और जल को रणनीतिक साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर (2025) में पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए।
- घुसपैठ मार्गों के निकट लगभग 75 उच्च-ऊँचाई वाले पर्यटन स्थल खोले गए थे और हमले के बाद 50 से अधिक स्थान बंद कर दिए गए।
- 3,000-9,000 फुट की ऊँचाई पर स्थित अस्थायी संचालन अड्डे (टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस) पर्वत-श्रृंखलाओं और घुसपैठ मार्गों पर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- इन उपायों में पर्यटन कर्मियों के लिए आधार-लिंक्ड पहचान प्रणाली, चेहरा पहचान तकनीक और ड्रोन निगरानी गलियारे शामिल हैं।
- ऑपरेशन महादेव (2025) में पहलगाम हमले के अपराधियों को मार गिराया गया।
- ऑपरेशन अमृत भर्ती और रसद नेटवर्क को, ऑपरेशन त्रिशूल तटीय सुरक्षा को तथा ऑपरेशन वज्र आतंकी वित्तपोषण और स्लीपर सेल को लक्षित करता है।
- यह सिद्धांत चार आयामों पर आधारित है: सैन्य सटीक हमले, निरंतर आंतरिक अभियान, शून्य सहनशीलता और जल-कूटनीतिक दबाव।

पोषण अभियान: पोषण मिशन के आठ वर्ष

संदर्भ: पोषण अभियान, भारत का प्रमुख बहु-मंत्रालयी पोषण मिशन, 8 मार्च 2018 को शुरू होने के बाद से आठ वर्ष पूरे कर चुका है। यह विभागों के बीच अभिसरण और प्रौद्योगिकी-आधारित, जन-आंदोलन दृष्टिकोण के माध्यम से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के पोषण को लक्षित करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- पहले के प्रयास बिखरे हुए थे: ICDS (1975), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017) और राष्ट्रीय पोषण रणनीति (2017) ने आधार तैयार किया। मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, 2021-22) ने पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाओं और किशोरियों के लिए योजना का विलय किया।
- POSHAN का पूरा नाम प्रधानमंत्री की समग्र पोषण के लिए व्यापक योजना (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition) है।
- इसमें 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ और किशोरियाँ शामिल हैं।
- इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 2% की दर से बौनापन, कम वज़न और जन्म के समय कम वज़न तथा 3% प्रति वर्ष की दर से रक्ताल्पता (एनीमिया) कम करना है।
- यह आहार, स्वच्छता और भोजन कराने की पद्धतियों में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है तथा सेवा वितरण और निगरानी को सुदृढ़ करता है।
- पोषण ट्रैकर वह डिजिटल उपकरण है जिसका उपयोग पारदर्शिता और लाभों के लक्ष्यीकरण को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।
- यह नेटवर्क लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों और लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है।
- PM पोषण एक अलग योजना है: यह पुनर्गठित मध्याह्न भोजन योजना (2021) है, जो सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 1-8 के विद्यार्थियों तथा बालवाटिका के बच्चों को प्रतिदिन एक पका हुआ भोजन देती है।

➤ NFHS-5 (2019-21) ने दिखाया कि बच्चों में बौनापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गया, जबकि बच्चों में रक्ताल्पता 58.6% से बढ़कर 67.1% हो गई।

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 और लोक सभा का विस्तार

संदर्भ: संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026, जिसका उद्देश्य लोक सभा की संख्या बढ़ाना और महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को लागू करना था, लोक सभा में विफल हो गया क्योंकि उसे विशेष दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। संबंधित परिसीमन विधेयक और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक भी प्रभावित हुए।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ विधेयक में लोक सभा को अधिकतम 850 सदस्यों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव था, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और संघ राज्यक्षेत्रों से अधिकतम 35 सदस्य होते।

➤ वर्तमान में संविधान राज्यों से अधिकतम 530 और संघ राज्यक्षेत्रों से 20 सदस्यों की अनुमति देता है।

➤ इसने 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) की उस शर्त को हटा दिया कि महिला आरक्षण अधिनियम के बाद पहली जनगणना के बाद ही शुरू होगा।

➤ इसने संसद को कानून द्वारा यह तय करने का अधिकार दिया कि परिसीमन कब होगा और कौन-सी जनगणना प्रयुक्त होगी, जो साधारण बहुमत से किया जा सकता था।

➤ परिसीमन विधेयक, 2026 में परिसीमन आयोग के गठन के समय प्रकाशित नवीनतम जनगणना के उपयोग का प्रस्ताव था, जिसका अर्थ 2011 की जनगणना है।

➤ आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करते, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके नामित व्यक्ति तथा संबंधित राज्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य होते।

सत्तानकुलम हिरासत में मौतों पर फैसला

संदर्भ: मदुरै की एक निचली अदालत ने 2020 में पिता और पुत्र की सत्तानकुलम हिरासत में मौतों के मामले में, जिसकी जाँच CBI ने की थी, नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस फैसले ने निचली अदालतों की सजा देने की शक्तियों की सीमाओं को रेखांकित किया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ न्यायालय ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले के 'दुर्लभतम में दुर्लभ' सिद्धांत को लागू किया।

➤ संविधान पीठ द्वारा UoI बनाम वी. श्रीहरन (2015) में निर्धारित और किरण बनाम कर्नाटक राज्य (2025) में पुनः पुष्ट मत के अनुसार निचली अदालतें निश्चित अवधि की या छूट-रहित आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकतीं।

➤ इसलिए केवल साधारण आजीवन कारावास, जिसमें लगभग 14 वर्ष बाद छूट संभव है, या मृत्युदंड ही उपलब्ध था।

➤ मद्रास उच्च न्यायालय सजा की समीक्षा करेगा और उसे छूट-रहित निश्चित अवधि के आजीवन कारावास में बदल सकता है।

NSO का 80वाँ चक्र स्वास्थ्य सर्वेक्षण

संदर्भ: NSO के 80वें दौर के घरेलू उपभोग: स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसमें 1.39 लाख परिवार शामिल थे, से स्वास्थ्य बीमा कवरेज में तीव्र वृद्धि और सार्वजनिक सुविधाओं के अधिक उपयोग के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ का पता चलता है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 2017-18 से 2025 के बीच बीमार बताई गई जनसंख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 6.8 से बढ़कर 12.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 9.1 से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गया।

➤ सरकार-वित्तपोषित बीमा कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में 12.9 से बढ़कर 45.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.9 से बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गया।

➤ प्रति अस्पताल-भर्ती मामले में औसत (माध्यिका) स्वयं वहन किया गया व्यय ₹11,285 था, जबकि सार्वजनिक सुविधाओं में बाह्य रोगी देखभाल पर माध्यिका व्यय शून्य था।

➤ सार्वजनिक सुविधाओं में ग्रामीण बाह्य रोगी उपयोग 28 प्रतिशत (2014) से बढ़कर 35 प्रतिशत (2025) हो गया।

➤ संस्थागत प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों में 95.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 97.8 प्रतिशत तक पहुँच गए।

➤ संक्रामक रोगों में कमी आई, जबकि मधुमेह और हृदय-संवहनी रोगों में वृद्धि हुई।

□ **हस्तक्षेप**

➤ 1.84 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक देखभाल प्रदान करते हैं।

➤ निःशुल्क औषधि सेवा पहल, निःशुल्क निदान पहल और अमृत फार्मेसियाँ सुलभता (वहनीयता) में सुधार करती हैं।

➤ PM-JAY वित्तीय सुरक्षा देती है, और JSY, JSSK तथा PMSMA मातृ स्वास्थ्य को सहारा देते हैं।

UAPA जमानत और के.ए. नजीब निर्णय

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले पूर्व निर्णय पर प्रश्न उठाया और दोहराया कि UAPA में भी, जहाँ सुनवाई में देरी हो, जमानत नियम है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ UAPA की धारा 43D(5) उन मामलों में जमानत पर कठोर शर्तें लगाती है जहाँ प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। NIA बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (2019) में अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें

अदालतों को जमानत के चरण पर साक्ष्यों की विस्तार से जाँच न करने को कहा गया।

- भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021), तीन न्यायाधीशों की पीठ, में कहा गया कि यदि सुनवाई में देरी हो और कारावास लंबा खिंचे तो संवैधानिक न्यायालय धारा 43D(5) के बावजूद जमानत दे सकते हैं।
- 2026 में न्यायालय ने टिप्पणी की कि छोटी पीठें बड़ी पीठों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को कमजोर नहीं कर सकतीं।

उच्चतम न्यायालय ने एसिड हमला पीड़ितों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एसिड हमला पीड़ितों के अर्थ का विस्तार किया, ताकि उसमें वे व्यक्ति भी शामिल हों जिन्हें जबरन एसिड पिलाया गया और जिन्हें बिना दिखाई देने वाली विकृति के आंतरिक चोटें आईं।

□ **मुख्य बिंदु**

- याचिका एसिड हमला पीड़िता शाहीन मलिक ने दायर की थी।
- विस्तारित परिभाषा 2016 से, जब अधिनियम लागू हुआ, पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 एसिड हमले से गंभीर चोट पहुँचाने को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाती है, जिसमें 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का दंड है।
- BNSS की धारा 397 सभी अस्पतालों में निःशुल्क तत्काल उपचार अनिवार्य करती है, और धारा 396 पीड़ित प्रतिकर योजना का प्रावधान करती है।
- लक्ष्मी मामले (2015) ने काउंटर पर एसिड की बिक्री को विनियमित किया।

केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पोर्टल और समाधान दीदी

संदर्भ: नीति आयोग ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक समय निगरानी के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया, जबकि DARPG ने शिकायतों के लिए AI वॉयस चैटबॉट 'समाधान दीदी' शुरू किया।

□ **केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पोर्टल**

- इसके माध्यम से केंद्रीय प्रभारी अधिकारी (CPO) मोबाइल उपकरणों से वास्तविक समय में क्षेत्र-स्तरीय अवलोकन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- CPO वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सामान्यतः अपर सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के, जो केंद्र, राज्यों और जिलों को जोड़ते हैं तथा 300 से अधिक केंद्रीय योजनाओं की देखरेख करते हैं।
- पोर्टल जिलों, राज्य सरकारों और मंत्रालयों को सुझावों की तत्काल दृश्यता प्रदान करता है।

□ **समाधान दीदी**

- यह CPGRAMS से एकीकृत AI-सक्षम वॉयस चैटबॉट है, जिसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने लॉन्च किया।
- इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने भाषिणी के साथ मिलकर विकसित किया।
- नागरिक अपनी भाषा में बोलकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और चैटबॉट सही मंत्रालय और श्रेणी की पहचान करता है।

त्रिशंकु विधानसभा की स्थितियों में राज्यपाल का विवेकाधिकार

संदर्भ: 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद 234 सदस्यीय सदन में TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी, जबकि DMK घटकर 59 पर रह गई। राज्यपाल द्वारा TVK नेता विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में देरी से राज्यपाल के विवेकाधिकार और संवैधानिक परंपरा पर बहस फिर शुरू हो गई।

□ **मुख्य बिंदु**

- विधानसभा चुनाव में अपने दल की हार के बाद ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने रहने से इस प्रश्न पर बहस फिर तेज हो गई।
- हार के बाद त्यागपत्र देना संसदीय परंपरा है, किंतु औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले राज्यपाल केवल चुनावी हार के आधार पर मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता।
- चुनाव परिणामों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत चुनाव याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है, जिसमें धारा 100 आधारों की सूची देती है।

□ **अनुशंसित परंपराएँ**

- सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2007) ने दलों को आमंत्रित करने के लिए वरीयता क्रम सुझाया।
- पहली वरीयता चुनाव-पूर्व गठबंधन या स्पष्ट बहुमत वाले दल को, फिर अन्य के समर्थन वाले सबसे बड़े एकल दल को, फिर चुनाव-पश्चात गठबंधन को जिसके घटक सरकार में शामिल हों, और फिर बाहरी समर्थन वाले चुनाव-पश्चात गठबंधन को दी जाती है।
- राज्यपाल को उस नेता की पहचान करनी चाहिए जिसके पास विश्वास प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना हो और उचित समय के भीतर सदन में शक्ति परीक्षण के लिए कहना चाहिए।
- बहुमत के प्रश्नों का निपटारा निजी आकलन या हस्ताक्षरों की माँग के बजाय सदन के पटल पर किया जाना चाहिए।
- तमिलनाडु में राज्यपाल ने TVK को आमंत्रित करने से पहले आरंभ में 118 हस्ताक्षर माँगे, जिसे पर्यवेक्षकों ने असामान्य कहा; बहुमत का आँकड़ा 118 था।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): चरण, फॉर्म 6 और निर्वाचन आयोग के कदम

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को बरकरार रखा। चरण II में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों से लगभग 5.18 करोड़ नाम कम हुए थे, और चरण III 30 मई 2026 को शुरू हुआ।

□ **मुख्य बिंदु**

- SIR मतदाता सूचियों की दस्तावेज सत्यापन सहित घर-घर गणना है। इसका उद्देश्य दोहरे, मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं को हटाना तथा सभी पात्र नागरिकों को शामिल करना है।
- फॉर्म 6 निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत पहली बार नामांकन के लिए या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर निवास बदलने के लिए आवेदन है।
- यह आवश्यकता बिहार SIR के दौरान शुरू हुई और अब देशभर में सभी नए पंजीकरणों पर लागू कर दी गई है।
- पिछले SIR में शामिल न किए गए मौजूदा मतदाताओं को भी सूची में बने रहने के लिए अपने माता-पिता के SIR विवरण देने होंगे।
- एक जाँच रिपोर्ट के अनुसार निर्वाचन आयुक्त संधू और जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति जताई।
- जिन मतदाताओं को अमैप्ड या तार्किक विसंगतियों वाला चिह्नित किया गया है, उन्हें सामान्यतः निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है; बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।
- फॉर्म 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा SIR के बाद हटा दी जाएगी, जिससे फॉर्म निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत पूर्ववत हो जाएगा।
- एक वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें IIT या IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ होगा, यह समीक्षा करेगी कि ECINet निर्वाचन कानूनों का अनुपालन करता है या नहीं।
- कार्यसूचियाँ पहले से वितरित की जाएँगी, कार्यवृत्त दर्ज किए जाएँगे और अधिकारियों की समिति द्वारा नए IT मॉड्यूल पर चर्चा की जाएगी।
- SIR में छूटे व्यक्ति सतत अद्यतन के माध्यम से शामिल किए जाने की माँग कर सकते हैं, और राज्यों को विशेष नामांकन अभियान चलाने होंगे।

□ **SIR चरण II**

- सूचियों में लगभग 10.2% की कमी आई और अब उनमें 45.81 करोड़ नाम हैं।
- पश्चिम बंगाल में मतदाता लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गए, जिनमें 63 लाख से अधिक नाम हटाए गए और लगभग 60 लाख न्याय-निर्णयाधीन हैं।
- उत्तर प्रदेश में लगभग 2.05 करोड़ नाम हटाए गए और अंतिम सूची में 13.39 करोड़ मतदाता हैं।

□ **SIR चरण III**

- चरण III 30 मई 2026 से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा और लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा।
- 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी घर-घर सत्यापन करेंगे, जिनकी सहायता लगभग 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट करेंगे।
- इस चरण के साथ SIR हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे देश को कवर कर लेता है।
- गणना के दौरान दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएँगे, और आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं।

मतदान से मतगणना तक EVM की यात्रा

संदर्भ: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान EVM से छेड़छाड़ के आरोपों के कारण निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना के बीच मशीनों से जुड़े सुरक्षा उपायों को दोहराया, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इसकी नियमावली, 2023 में निर्धारित हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- मतदान से पहले EVM को जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्यतः जिलाधिकारी, के अधीन सुरक्षित गोदामों में रखा जाता है।
- यादृच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) एक डिजिटल प्रक्रिया है, जो मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में EVM और VVPAT को निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को आवंटित करती है।
- मतदान के बाद मशीनों को मतदान अधिकारियों और प्रत्याशियों के एजेंटों के सामने सील किया जाता है और सुरक्षा के साथ स्ट्रॉन्गरूम वापस ले जाया जाता है।
- स्ट्रॉन्गरूम में प्रवेश का एक ही द्वार होता है जिसमें दोहरी ताला प्रणाली होती है; एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास और दूसरी सहायक RO के पास रहती है।
- सशस्त्र पुलिस की कम से कम एक प्लाटून चौबीसों घंटे स्ट्रॉन्गरूम की रखवाली करती है, साथ में प्रवेश रजिस्टर और वीडियोग्राफी रखी जाती है।
- प्रयुक्त EVM को आरक्षित मशीनों से अलग रखा जाता है, और मतगणना के दिन उन्हें प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के अंतर्गत मतगणना केंद्रों पर ले जाया जाता है।

राजद्रोह कानून: धारा 124A और BNS की धारा 152

संदर्भ: मई 2026 में उच्चतम न्यायालय ने कामरान बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में लंबित राजद्रोह मुकदमों को अभियुक्त की सहमति से आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिससे एस.जी. वोम्बटकेरे मामले में 2022 के उसके

स्थगन आदेश के बावजूद बहस फिर शुरू हो गई। IPC की धारा 124A, जो सरकार के प्रति असंतोष को दंडित करती थी, का स्थान BNS की धारा 152 ने ले लिया है, इसलिए निर्णय-विधि और नया प्रावधान दोनों परीक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- IPC की धारा 124A सरकार के प्रति असंतोष को तीन वर्ष से आजीवन कारावास तक के दंड से दंडित करती थी।
- केदारनाथ सिंह (1962) में राजद्रोह को वैध ठहराया गया, लेकिन उसे हिंसा के लिए उकसावे या लोक व्यवस्था भंग करने तक सीमित किया गया।
- बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) में कहा गया कि केवल नारेबाजी राजद्रोह नहीं है।
- एस.जी. वोम्बटकेरे (2022) में धारा 124A के अंतर्गत नई FIR पर रोक लगाई गई।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और NEET-UG 2026 का रद्द होना

संदर्भ: मई 2026 में NEET-UG 2026 के रद्द होने से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की क्षमता, पारदर्शिता और संकट प्रबंधन को लेकर चिंताएँ फिर उभरीं। NTA शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई और जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है; यह NEET-UG, JEE Main, CUET और UGC-NET आयोजित करती है। राधाकृष्णन समिति (2024) ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर बढ़ने की वकालत की थी।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसकी स्थापना 2017 में हुई, इसने 2018 में कार्य करना शुरू किया, और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। यह NEET-UG, JEE Main, CUET, UGC-NET, CMAT, GPAT और AISSEE आयोजित करती है।
- इसकी स्थापना 2017 में हुई, इसने 2018 में कार्य करना शुरू किया, और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है।
- यह NEET-UG, JEE Main, CUET, UGC-NET, CMAT, GPAT और AISSEE आयोजित करती है।
- राधाकृष्णन समिति (2024) ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर चरणबद्ध बदलाव की वकालत की।
- प्रश्नपत्रों के एन्क्रिप्टेड प्रसारण और स्थानीय मुद्रण वाला कंप्यूटर-सहायता प्राप्त पेन-एंड-पेपर मॉडल प्रस्तावित किया गया।
- NTA के पास 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए एक साथ NEET आयोजित करने हेतु CBT अवसंरचना का अभाव है, इसलिए हाइब्रिड संक्रमण को व्यावहारिक माना जाता है।

वृद्धजन कल्याण: जीवन ऐप, शतायु और पेंशन अध्ययन

संदर्भ: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किए, जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि 2012 के बाद से वृद्धावस्था पेंशन का मूल्य घट गया है।

□ **जीवन और शतायु**

- जीवन (JEEVAN) का पूर्ण रूप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क है; यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप है जो योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वृद्धाश्रमों का विवरण देता है।
- शतायु (SHATAYU) का पूर्ण रूप सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी है; यह एक डैशबोर्ड है जिसमें प्रशिक्षित वृद्धजन-देखभालकर्ताओं का जिला और राज्य स्तरीय डेटाबेस है।

□ **NSAP प्रभाव मूल्यांकन**

- ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, मासिक पेंशन में केंद्र का योगदान 2012 से स्थिर रहा है।
- ₹200 से ₹500 के निश्चित अंतरण ने अपने वास्तविक मूल्य का लगभग 45 प्रतिशत खो दिया।
- ₹200 की पेंशन आज ₹353-382 होनी चाहिए, क्योंकि CPI 2012 में 100 से बढ़कर 2024 में 191 हो गया।
- इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (नेशनल फ्लोर पेंशन), मुद्रास्फीति सूचकांकन और NFBS सहायता को ₹20,000 से बढ़ाकर लगभग ₹40,000 करने की सिफारिश की गई है।

NEET-UG पुनः परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर प्रतिबंध

संदर्भ: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 की पुनः परीक्षा से पहले भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया। यह पेपर लीक के आरोपों और टेलीग्राम चैनलों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण मूल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद हुआ।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह केंद्र सरकार को ऑनलाइन सूचना या सेवाओं को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है। आधारों में संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और संज्ञेय अपराधों के लिए उकसावे को रोकना शामिल हैं।
- मूल NEET-UG 2026 को कथित पेपर लीक और कदाचार के कारण रद्द कर दिया गया था।

- Re-NEET 2026 जैसे नामों वाले चैनलों ने पुनः परीक्षा का पेपर बेचने का दावा किया; NTA ने कहा कि सुरक्षित श्रृंखला के बाहर कोई पेपर नहीं था।
- MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के अंतर्गत अवरोधन आदेश जारी किया।
- टेलीग्राम को यह भी निर्देश दिया गया कि वह 30 जून 2026 तक भारत में पुराने संदेशों के लिए संदेश संपादन की सुविधा बंद कर दे।

NeSDA 2025 और दिव्यांगजन अधिकारों पर COSP19

संदर्भ: माह के शासन और अधिकार संबंधी दो घटनाक्रम थे: ई-गवर्नेंस मूल्यांकन के लिए NeSDA 2025 पोर्टल का शुभारंभ और न्यूयॉर्क में दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकार राज्यों का 19वाँ सम्मेलन।

□ **NeSDA 2025**

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन एक द्विवार्षिक रूपरेखा है, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) संचालित करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण के ऑनलाइन सेवा सूचकांक पर आधारित है।
- यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों में ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच और परिपक्वता का आकलन करता है, जिसमें G2C और G2B सेवाएँ शामिल हैं।

□ **COSP19 और UNCRPD**

- COSP19 ने UNCRPD की 20वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2006 में अपनाया था और जो 2008 में लागू हुआ।
- यह अभिसमय 193 पक्षकारों (192 राज्य और यूरोपीय संघ) वाली विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है; भारत ने अक्टूबर 2007 में इसका अनुसमर्थन किया।
- भारत ने इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से लागू किया, जिसने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी।
- दिव्यांगजन अधिकार समिति इस अभिसमय की निगरानी करती है, और एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल व्यक्तिगत शिकायत तंत्र प्रदान करता है।

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक कोटा पर बहस

संदर्भ: न्यायमूर्ति वी. मोहना के बार से सीधे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली केवल दूसरी महिला बनने से उच्च न्यायपालिका में लैंगिक कोटा की माँग फिर उठी है। संवैधानिक न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम है।

□ **मुख्य बिंदु**

- कनाडा, जर्मनी और बेल्जियम के संवैधानिक न्यायालयों में लगभग 50% महिला न्यायाधीश हैं।
- बेल्जियम अपने संवैधानिक न्यायालय में प्रत्येक लिंग के कम से कम एक-तिहाई न्यायाधीशों की अनिवार्यता रखता है।
- सुझाए गए सुधारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लिखित नीति, वस्तुनिष्ठ नियुक्ति मानदंड, मार्गदर्शन (मेंटरशिप) और लैंगिक रूप से संवेदनशील अवसंरचना शामिल हैं।

□ **वर्तमान स्थिति**

- इंदु मल्होत्रा 2018 में बार से सीधे पदोन्नत की गई पहली महिला थीं।
- 1950 से अब तक उच्चतम न्यायालय में केवल 12 महिलाओं की नियुक्ति हुई है।
- उच्चतम न्यायालय के 37 न्यायाधीशों में से केवल 2 महिलाएँ हैं, यानी लगभग 5.4%।
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में लगभग 15% महिलाएँ हैं।

उच्चतम न्यायालय का मानव-तस्करी विरोधी ढाँचा और पीड़ित संरक्षण योजना

संदर्भ: गैर-सरकारी संगठन प्रज्वला की 2004 की जनहित याचिका से उत्पन्न मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 और 142 का प्रयोग करते हुए मानव-तस्करी को संवैधानिक गरिमा पर सीधा प्रहार कहा और सहमति, पुनर्वास तथा पीड़ित संरक्षण पर निर्देश जारी किए। इसने एक पीड़ित संरक्षण योजना तैयार की जो तब तक लागू रहेगी जब तक संसद समर्पित कानून नहीं बनाती।

□ **मुख्य बिंदु**

- पालेर्मो प्रोटोकॉल के अनुसार तस्करी के तीन तत्व हैं: कृत्य, साधन और शोषण। अनुच्छेद 23(1) तस्करी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है।
- न्यायालय ने तस्करी को संवैधानिक गरिमा पर सीधा प्रहार कहा और एक समान राष्ट्रीय पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल का आदेश दिया।
- स्वैच्छिक वयस्क यौन कार्य को तस्करी से अलग करने के लिए सहमति केंद्रीय कसौटी है; जहाँ बल, दबाव या छल सिद्ध हो, वहाँ सहमति अप्रासंगिक हो जाती है।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धाराओं 15 और 16 के अंतर्गत छापे तस्करों को लक्षित करें, पीड़ितों को नहीं।
- पुनर्वास का अधिकार अनुच्छेद 21 से, गरिमा के साथ जीने के अधिकार के भाग के रूप में, प्रवाहित होता है।
- बचाए गए पीड़ितों को गिरफ्तार, प्रताड़ित या ऐसे तरीकों से फोटो खींचा नहीं जाना चाहिए जिनसे पहचान उजागर हो, और बच्चों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, दिव्यांगजनों तथा मानसिक रोगियों के प्रति विशेष सावधानी बरती जाए।

- संरक्षण गृह जेल जैसे नहीं होने चाहिए; प्रत्येक उत्तरजीवी को एक केस वर्कर और व्यक्तिगत देखभाल योजना मिलती है।
- मानव-तस्करी विरोधी इकाइयों का प्रमुख DSP या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी होना चाहिए और उन्हें पुलिस थाने के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।
- BNS की धारा 143 तस्करी को परिभाषित करती है।
- NCRB की क्राइम इन इंडिया 2024 में 6,018 तस्करी पीड़ित दर्ज हैं, जिनमें 2,297 बच्चे शामिल हैं।

□ संसद को निर्देश

- न्यायालय ने सरकार द्वारा वादा किए गए संगठित अपराध अन्वेषण अभिकरण के गठन से इनकार कर दिया।
- संसद से कहा गया कि वह अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं 7, 8 और 20 में संशोधन करे, गृहों में अनिवार्य निश्चित निरोध पर पुनर्विचार करे और एक स्वतंत्र मानव-तस्करी विरोधी कानून बनाए।

उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता कहा

संदर्भ: शीश राम एवं अन्य बनाम सुरजीत मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावों में प्रतिकर तय करते समय गृहिणियों के कार्य को औपचारिक मान्यता दी जानी चाहिए और उसका मौद्रिक मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता कहा।

□ मुख्य बिंदु

- न्यायालय ने गृहिणी की मृत्यु पर खोई गई घरेलू देखभाल सेवाओं के लिए ₹30,000 प्रति माह का न्यूनतम काल्पनिक मूल्य निर्धारित किया।
- अवैतनिक देखभाल कार्य को सामाजिक न्याय की संवैधानिक परिकल्पना का भाग माना गया।
- यह निर्णय अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत श्रम की गरिमा और वास्तविक समानता को बनाए रखता है।

ऊपरी यमुना जल पर हरियाणा-राजस्थान समझौता

संदर्भ: हरियाणा और राजस्थान ने लगभग 32 वर्ष बाद 1994 के ऊपरी यमुना जल बँटवारा समझौते को क्रियान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान का हिस्सा यमुना जल परियोजना के लिए एक समर्पित भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाएगा।

□ मुख्य बिंदु

- पाइपलाइन नई नहर के बजाय पश्चिमी यमुना नहर से शुरू होगी।
- यमुना जल परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹34,102 करोड़ है।
- एमओए पर हस्ताक्षर केंद्रीय गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में किए गए।
- 1994 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 12 मई 1994 को हस्ताक्षर हुए थे और यह दिल्ली की पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है; इसके परिणामस्वरूप जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (1995) का गठन हुआ।

ऊपरी यमुना के उपयोग योग्य जल में हिस्सेदारी

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	हिस्सेदारी
हरियाणा	47.82%
उत्तर प्रदेश	33.65%
राजस्थान	9.34%
दिल्ली	6.04%
हिमाचल प्रदेश	3.15%

कावेरी और अन्य अंतर-राज्यीय जल मामले

संदर्भ: न्यायिक निर्णयों ने भारत में अंतर-राज्यीय नदी विवादों के निपटारे को आकार दिया है, कावेरी पंचाट से लेकर मुल्लापेरियार बाँध तक। ये मामले स्पष्ट करते हैं कि जब किसी विवाद पर अधिकरण पहले से विचार कर रहा हो तो उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय कर सकता है और क्या नहीं।

□ मुख्य बिंदु

- तमिलनाडु राज्य बनाम कर्नाटक राज्य (2018) में उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण के आवंटन में संशोधन किया, जिससे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच विवाद समाप्त हुआ, और कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड के गठन का निर्देश दिया।
- उड़ीसा राज्य बनाम भारत सरकार मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि केंद्र निर्धारित अवधि के भीतर अधिकरण का गठन करने में विफल रहता है तो क्षेत्राधिकार का वर्जन लागू नहीं होता।
- मुल्लापेरियार मामले में न्यायालय ने कहा कि बाँध सुरक्षा के प्रश्न ISRWD अधिनियम के अंतर्गत कड़ाई से जल विवाद नहीं हैं; यह बाँध केरल में पेरियार नदी पर है, किंतु तमिलनाडु द्वारा संचालित है।
- आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कर्नाटक मामले में न्यायालय ने कहा कि वह अधिकरण के समक्ष लंबित किसी प्राथमिक जल विवाद पर निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन अधिकरण के पंचाटों की व्याख्या कर सकता है।
- न्यायालय राज्यों के बीच विवादों के लिए अनुच्छेद 131 और अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाओं के लिए अनुच्छेद 136 का उपयोग करता है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति

संदर्भ: केंद्र ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. पी. नवलेकर करेंगे। यह प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2025 को जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा के बाद

गठित हुई है और अवैध आप्रवासन से जुड़े जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करेगी।

□ **अधिदेश**

➤ समिति में जनगणना आयुक्त और तीन अन्य सदस्य शामिल हैं।

➤ यह क्षेत्रों और समुदायों में जनसांख्यिकीय बदलावों और उनके कारणों का अध्ययन करेगी, जिनमें अवैध आप्रवासन, प्रजनन क्षमता में भिन्नता, आर्थिक प्रवासन और प्रशासनिक विफलताएँ शामिल हैं।

➤ विशेष ध्यान के क्षेत्र सीमावर्ती जिले, जनजातीय क्षेत्र, शहरी केंद्र और औद्योगिक गलियारे हैं।

➤ यह अवैध आप्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए स्थायी, कानूनी और समयबद्ध तंत्र की अनुशंसा करेगी।

➤ यह सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण, पहचान और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों की सतत निगरानी के लिए संस्थाओं का सुझाव देगी।

➤ यह केंद्र-राज्य समन्वय के लिए नीतिगत ढाँचा प्रस्तावित करेगी।

□ **कानूनी पृष्ठभूमि**

➤ नागरिकता अधिनियम, 1955 वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले या निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने वाले विदेशी को अवैध प्रवासी मानता है।

➤ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को छूट देता है।

➤ आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 अवैध प्रवेश पर अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास, ₹5 लाख के जुर्माने या दोनों का दंड देता है।

➤ भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय या उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है।

➤ मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ (2021) में न्यायालय ने रोहिंग्या के निर्वासन की अनुमति केवल विधिसम्मत प्रक्रिया के बाद ही दी।

➤ NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 विदेशियों को भी शामिल करता है और चकमा शरणार्थियों को विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना बलपूर्वक बेदखल करने पर रोक लगाई।

ट्रॉमा केयर, PM राहत और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित राजमार्ग

संदर्भ: सेवलाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने ट्रॉमा केयर को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का भाग माना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा को प्रवर्तनीय अधिकार घोषित किया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की PM राहत योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद-रहित आपातकालीन उपचार प्रदान करती है।

□ **उच्चतम न्यायालय के निर्देश**

➤ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आपातकालीन नंबरों 100, 101, 102, 108, 1033 और 1091 को तीन महीने के भीतर एकल नंबर 112 में विलय करना होगा।

➤ राज्यों को PM राहत योजना को क्रियाशील करना होगा, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को स्वर्णिम घंटे (गोल्डन आवर) में नकद-रहित उपचार देती है।

➤ तीन महीने के भीतर गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा।

➤ ट्रॉमा रजिस्ट्री और बहुभाषी जागरूकता अभियानों के साथ एक समान ट्रॉमा-केयर ढाँचे का निर्देश दिया गया।

➤ घातक राजमार्ग दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान मामले में न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित, चलने योग्य और खतरा-मुक्त सड़कें एक प्रवर्तनीय अधिकार हैं।

➤ भारत में प्रति वर्ष लगभग 4.67 लाख आकस्मिक मौतें दर्ज होती हैं, और विधि आयोग की 201वीं रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में लगभग आधी मौतें समय पर देखभाल मिलने से टाली जा सकती हैं।

□ **PM राहत योजना**

➤ प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक का नकद-रहित उपचार दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों के लिए कवर किया जाता है।

➤ जानलेवा न होने वाली चोटों के लिए 24 घंटे तक और जानलेवा चोटों के लिए 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार दिया जाता है।

➤ अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है; बीमित वाहनों के मामलों का वित्तपोषण सामान्य बीमा कंपनियाँ करती हैं, और बिना बीमा या हिट-एंड-रन मामलों का वित्तपोषण भारत सरकार करती है।

➤ दावों का निपटारा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 10 दिनों के भीतर किया जाना है।

➤ पीड़ित या गुड सेमेरिटन (राह-वीर) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के अंतर्गत 112 पर कॉल करके निकटतम अस्पताल तक पहुँच सकते हैं।

तुंगभद्रा विवाद और अंतर-राज्यीय जल कानून

संदर्भ: केंद्र ने तुंगभद्रा नदी पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल-बँटवारे के मतभेदों को सुलझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकरण ने अंतर-राज्यीय नदी विवादों के लिए संवैधानिक तंत्र को फिर चर्चा में ला दिया है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ तुंगभद्रा, जिसे प्राचीन काल में पंपा कहा जाता था, कर्नाटक में शिवमोग्गा (शिमोगा) में तुंगा और भद्रा के संगम से बनती है; दोनों पश्चिमी घाट से निकलती हैं। यह कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमा का भाग

बनाती है और आंध्र प्रदेश में संगमेश्वरम पर कृष्णा से दाएँ तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है।

- कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना, जो तुंगभद्रा बाँध के ऊपरी भाग में है, का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विरोध करते हैं, क्योंकि जल रोकने से निचले क्षेत्र की नहर आपूर्ति प्रभावित होती है।
- तेलंगाना का कहना है कि गाद जमाव और संरचनात्मक अवरोधों के कारण वह राजोलीबंडा डायवर्जन योजना (RDS) के अंतर्गत अपने आवंटित हिस्से का जल नहीं ले पाता, जो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक अंतर-राज्यीय परियोजना है।
- तेलंगाना ने RDS की कमी की पूर्ति के लिए तुम्मिला लिफ्ट सिंचाई योजना और मल्लम्मकुंटा जलाशय के विस्तार की रूपरेखा बनाई है।
- तुंगभद्रा बोर्ड कृष्णा जल विवाद अधिकरण के आदेश के अनुरूप राज्यों को जल आपूर्ति का विनियमन करता है।
- जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन अंतर-राज्यीय नदियों का विनियमन और विकास संघ सूची की शक्ति है।
- अनुच्छेद 262 संसद को कानून द्वारा अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने और उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित करने की अनुमति देता है।
- अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 तदर्थ अधिकरणों का प्रावधान करता है; इसके 2002 के संशोधन ने अधिकरण गठित करने के लिए एक वर्ष और पंचाट देने के लिए तीन वर्ष की समय-सीमा तय की।
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 अंतर-राज्यीय बेसिनों के एकीकृत विकास के लिए संघ द्वारा बनाए गए बोर्डों की अनुमति देता है, किंतु आज तक कोई भी गठित नहीं हुआ है।
- ISRWD (संशोधन) विधेयक, 2019 कई पीठों वाले एकल स्थायी अधिकरण और एक विवाद समाधान समिति का प्रस्ताव करता है।
- अनुच्छेद 263 अंतर-राज्यीय परिषद को वार्ता के माध्यम से तनाव कम करने में सहायता करने की अनुमति देता है।
- वरदा इसकी बाएँ तट की सहायक नदी और वेदवती दाएँ तट की सहायक नदी है; यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी इसके तट पर स्थित है।

धर्मांतरित जनजातीय लोगों को ST सूची से हटाने पर बहस

संदर्भ: इस पर नई बहस उठी है कि ईसाई या इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा जारी रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ जनजातीय समूह सूची से हटाने की माँग कर रहे हैं। यह झारखंड के आदिवासियों की उस माँग के साथ मेल खाती है जिसमें जनगणना में सरना को पृथक धर्म के रूप में मान्यता देने की बात है।

□ **मुख्य बिंदु**

- सूची से हटाने (डीलिस्टिंग) का अर्थ यह माँग है कि धर्मांतरित जनजातीय लोग अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित संवैधानिक लाभ खो दें।
- समर्थकों का तर्क है कि धर्मांतरण से ST दर्जे का सामाजिक-सांस्कृतिक आधार बदल जाता है।
- विरोधियों का कहना है कि जनजातीय पहचान जातीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है, धार्मिक नहीं।
- अनुच्छेद 342 में कोई धार्मिक अर्हता नहीं है, इसलिए सूची से हटाने के लिए संभवतः विधायी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक होगा और उसे न्यायिक जाँच का सामना करना पड़ेगा।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास विषय पर नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। यह पहली बार था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

□ **मुख्य बिंदु**

- 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक उपस्थित हुए।
- चार स्तंभ निर्धारित किए गए: बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल; उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास; स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण; सबके लिए समानता और गरिमा।
- राज्यों से आग्रह किया गया कि वे परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप दीर्घकालिक विकास दृष्टि अपनाएँ।
- ध्यान के क्षेत्रों में एक जिला एक उत्पाद पर आधारित निर्यात रणनीतियाँ, कौशल विकास, सीखने के परिणाम, वृद्धजन देखभाल, लखपति दीदी जैसी महिला-नेतृत्व वाली वृद्धि, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती शामिल थे।

न्यायालयों में AI के उपयोग पर मसौदा विनियम

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए विनियम, 2026 का मसौदा जारी किया है। इनमें प्रशासनिक और अनुसंधान सहायता के लिए AI की अनुमति है, परंतु न्यायनिर्णयन और न्यायिक निर्णय-प्रक्रिया में इसका उपयोग वर्जित है। मसौदे का उद्देश्य निर्णयों की जवाबदेही मानव न्यायाधीशों के पास ही रखना है।

□ **मुख्य बिंदु**

- न्यायालयों में प्रशासनिक और अनुसंधान कार्य के लिए AI का उपयोग किया जा सकता है।
- न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यों और न्यायिक निर्णय-प्रक्रिया में AI निषिद्ध है।

➤ मसौदा न्यायपालिका में AI के उत्तरदायी उपयोग के लिए औपचारिक रूपरेखा प्रदान करता है।

पंचायत सुधारों के 12 वर्ष रिपोर्ट

संदर्भ: पंचायती राज मंत्रालय ने बिल्डिंग विकसित भारत फ्रॉम ग्राउंड अप: 12 इयर्स ऑफ पंचायत रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह क्षमता निर्माण, डिजिटल शासन तथा जनजातीय क्षेत्रों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तीकरण में प्रगति को दर्ज करती है।

□ मुख्य बिंदु

➤ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 2.70 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाओं के 4.10 करोड़ से अधिक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

➤ वित्त वर्ष 2022-23 और 2025-26 के बीच 33.55 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया।

➤ स्वामित्व योजना ने ड्रोन सर्वेक्षण और 1.92 लाख गाँवों में लगभग 3.18 करोड़ संपत्ति कार्ड संभव बनाए।

➤ मेरी पंचायत ऐप ने एक करोड़ डाउनलोड का आँकड़ा पार किया।

➤ ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ ई-ग्रामस्वराज मंच के माध्यम से 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में संस्थागत की गई हैं।

□ पेसा, महिलाएँ और युवा

➤ पेसा, 1996 के लिए मंत्रालय ने पेसा-GPDP पोर्टल, एक उत्कृष्टता केंद्र और भारत का पहला पेसा रैंकिंग ढाँचा शुरू किया।

➤ 744 आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान की गई और निर्भय रहो अभियान शुरू किया गया।

➤ मॉडल युवा ग्राम सभा ने 29,000 से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा।

पासपोर्ट, आधार और नागरिकता का प्रमाण

संदर्भ: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट मुख्यतः एक यात्रा दस्तावेज है और नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, जिससे यह ध्यान आकर्षित हुआ है कि भारत में नागरिकता कैसे सिद्ध की जाती है।

□ मुख्य बिंदु

➤ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित में गैर-नागरिकों को पासपोर्ट जारी कर सकती है।

➤ भारत में ऐसा कोई एकल सार्वभौमिक दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता का निर्णायक प्रमाण हो।

➤ आधार एक पहचान दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं।

➤ मतदाता सूची में प्रविष्टि से नागरिकता की धारणा बनती है, परंतु वह निर्णायक नहीं है, जैसा कि लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (1995) में कहा गया।

➤ नागरिकता प्रमाणपत्र मुख्यतः उन लोगों को जारी किया जाता है जो पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम और पुत्र-प्राथमिकता: उच्चतम न्यायालय

संदर्भ: महाराष्ट्र के एक चिकित्सक के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि पुत्र को वरीयता और गुप्त लिंग चयन अब भी बने हुए हैं। निर्णय इस बात पर बल देता है कि वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त होने तक यह कानून आवश्यक बना रहेगा।

□ मुख्य बिंदु

➤ भारत का बाल लिंगानुपात 945 (1991) से घटकर 927 (2001) और 919 (2011) रह गया।

➤ जन्म के समय लिंगानुपात सुधरकर लगभग 929 (NFHS-5) हो गया है, किंतु राज्यों में प्रगति असमान है।

➤ अधिनियम का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 में निहित है।

➤ यह लिंग निर्धारण और गर्भधारण-पूर्व लिंग चयन पर रोक लगाता है; 2003 के संशोधन ने इसका दायरा गर्भधारण-पूर्व तकनीकों तक बढ़ा दिया।

➤ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों की अनुमति केवल आनुवंशिक, गुणसूत्र संबंधी और जन्मजात विकृतियों के लिए, अभिलेख रखने के साथ, दी जाती है।

➤ गर्भवती महिला की लिखित सहमति अनिवार्य है।

➤ अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और परामर्श केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य है।

➤ केंद्रीय और राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड तथा समुचित प्राधिकारी इस कानून को लागू करते हैं।

➤ लिंग चयन संबंधी विज्ञापन प्रतिबंधित हैं और अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती तथा अशमनीय हैं।

पैदल चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षित, बाधारहित और चिह्नित फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मनियार इलियाज और शेख रियाज बनाम पी. अय्यप्पन मामले में यह निर्णय एक पाँच वर्षीय बच्चे की मृत्यु से जुड़े मोटर दुर्घटना दावे से उत्पन्न हुआ, जिसे पैदल यात्री अवसंरचना के अभाव में सड़क पर चलने के लिए विवश होना पड़ा था।

□ मुख्य बिंदु

➤ यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) (आवागमन की स्वतंत्रता) को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने से उत्पन्न होता है।

➤ पैदल यात्रियों के अधिकारों को मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता प्राप्त है।

- नगर विकास प्राधिकरणों, नगरपालिका निकायों और यहाँ तक कि पंचायतों को भी सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराने और उनका रखरखाव करने होंगे।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस अधिकार को लागू करने के लिए विधिक ढाँचे पर विचार करे।
- फुटपाथों के अभाव या उन पर अतिक्रमण से हानि उठाने वाले नागरिक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उपायों से स्वतंत्र रूप से संवैधानिक उपचार और प्रतिकर माँग सकते हैं।

ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की भारत से तुलना

संदर्भ: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने जून 2026 में इस्तीफा दे दिया, जिससे वे एक दशक में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री बन गए। इससे ब्रिटेन और भारत की वेस्टमिंस्टर-शैली की प्रणालियों की तुलना होने लगी। दोनों में नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तविक कार्यपालिका और द्विसदनीय संसद है, किंतु ब्रिटेन संसदीय संप्रभुता पर आधारित है, जबकि भारत संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित है।

□ समानताएँ

- दोनों वेस्टमिंस्टर मॉडल का पालन करते हैं, जिसमें कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है।
- दोनों में नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष (सम्राट या राष्ट्रपति) और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तविक कार्यपालिका होती है।
- दोनों में द्विसदनीय संसद है।
- दोनों में मंत्रिपरिषद निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

□ भिन्नताएँ

- ब्रिटेन संसदीय संप्रभुता पर आधारित है, जबकि भारत संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित है।
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और परंपराओं, कानूनों तथा न्यायिक निर्णयों पर आधारित है; भारत का संविधान लिखित है।
- ब्रिटेन का प्रधानमंत्री परंपरागत रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, जबकि भारत में कोई मंत्री संसद सदस्य हुए बिना छह माह तक पद पर रह सकता है।
- ब्रिटेन में दल-बदल विरोधी कानून नहीं है, जबकि भारत में है।
- ब्रिटेन के न्यायालय संवैधानिक आधार पर संसद के अधिनियमों को रद्द नहीं कर सकते; भारतीय न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन की तुलना

आधार	यूनाइटेड किंगडम	भारत
संवैधानिक सिद्धांत	संसदीय संप्रभुता	संवैधानिक सर्वोच्चता
संविधान	अलिखित	लिखित
दल-बदल विरोधी कानून	नहीं है	विद्यमान है
कानूनों की न्यायिक समीक्षा	संवैधानिक आधार पर नहीं	न्यायालय कानूनों को रद्द कर सकते हैं

भूल जाने का अधिकार: दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

संदर्भ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भूल जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का हिस्सा है और जहाँ निरंतर पहुँच से अनुपातहीन हानि होती है, वहाँ नाम-आधारित खोजों को सूचीबद्ध होने से हटाने (डी-इंडेक्सिंग) का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बाद ऐसे एक निर्णय के विरुद्ध याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिससे यह प्रश्न उठा है कि क्या आरोपी के आरोपमुक्त होने के बाद पुरानी समाचार रिपोर्टें हटाई जा सकती हैं।

□ मुख्य बिंदु

- भूल जाने का अधिकार (RTBF) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार में निहित है, जिसे पुट्टस्वामी (2017) में मान्यता दी गई। भारत में RTBF संहिताबद्ध नहीं है; निकटतम प्रावधान डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में मिटाने का अधिकार है।
- यूरोपीय संघ का GDPR मिटाने का एक विकसित अधिकार देता है, किंतु यह निरपेक्ष नहीं है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी दायित्वों तथा लोकहित के आगे सीमित हो जाता है।
- नवंबर 2025: पटियाला हाउस कोर्ट ने गूगल को एक बरी हुए बैंकर से संबंधित लिंक हटाने का आदेश दिया।
- मार्च 2025: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त होने के बाद एक याचिकाकर्ता का नाम कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।
- फरवरी 2025: राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि किशोरों को भूल जाने का निरपेक्ष अधिकार है।
- जुलाई 2024: सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें इंडियन कानून से एक निर्णय हटाने को कहा गया था, और निर्णयों को सार्वजनिक अभिलेख बताया।

□ अधिकार और उसकी सीमाएँ

- लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का एक पहलू माना।
- यह अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचनात्मक निजता से उत्पन्न होता है।
- इंटरनेट पर स्थायी स्मृति बरी होने, आरोपमुक्त होने या समझौते के बाद भी प्रतिष्ठा, रोज़गार और गरिमा को क्षति पहुँचा सकती है।
- यह अधिकार इतिहास मिटाने का अधिकार नहीं है; न्यायिक अभिलेख बने रहते हैं और केवल नाम-आधारित खोज-योग्यता को सीमित किया जा सकता है।
- डी-इंडेक्सिंग अभिलेख को मिटाए बिना किसी व्यक्ति के नाम को खोज-कुंजी के रूप में हटा देती है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर

लागू होना है; यह बरी या आरोपमुक्त होने पर समाप्त मामलों के लिए उपयुक्त है।

- महिलाओं, बच्चों या लोक विश्वास के उल्लंघन से जुड़े मामलों में डी-इंडेक्सिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- मास्किंग में न्यायालय के अभिलेखों में नामों और पहचान-चिह्नों को XYZ जैसे तटस्थ नामों से बदल दिया जाता है।

विदेशी विश्वविद्यालय परिसर: बेंगलुरु में लिवरपूल

संदर्भ: विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं की मेजबानी के भारत के प्रयास तब आगे बढ़े जब शिक्षा मंत्रालय ने जून 2026 में कर्नाटक के बेंगलुरु में परिसर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिवरपूल (यूके) को अनुमोदन पत्र सौंपा। जुलाई 2026 में NIFTEM-कुंडली ने भी शैक्षणिक सहयोग के लिए न्यूज़ीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। भारत में विदेशी परिसर शिक्षा-नीति का एक बार-बार चर्चा में आने वाला विषय है।

□ **मुख्य बिंदु**

- शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में परिसर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिवरपूल (यूके) को अनुमोदन पत्र सौंपा।
- NIFTEM-कुंडली ने 2 जुलाई 2026 को शैक्षणिक सहयोग के लिए न्यूज़ीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए।

BNSS की धारा 356 के अंतर्गत अनुपस्थिति में सुनवाई (ट्रायल इन एब्सेंशिया)

संदर्भ: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 356 न्यायालयों को कुछ फरार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने और निर्णय सुनाने की अनुमति देती है। यह मुद्दा तब फिर से चर्चा में आया जब जम्मू की विशेष NIA न्यायालय ने पहलगाम हमले की जाँच में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- लगातार दो गिरफ्तारी वारंट कम से कम 30 दिन के अंतर पर जारी किए जाने चाहिए।
- अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए 30 दिन देते हुए एक स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- नोटिस को अभियुक्त के अंतिम ज्ञात निवास पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए, और किसी रिश्तेदार या मित्र को मुकदमे की सूचना दी जानी चाहिए।
- आरोप तय होने के 90 दिन बाद तक मुकदमा शुरू नहीं हो सकता।
- BNSS की धारा 84 फरार व्यक्तियों को उद्घोषित अपराधी घोषित करने की उद्घोषणा से संबंधित है।
- यूनाइटेड किंगडम सीमित मामलों में अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देता है, विशेष रूप से जहाँ अभियुक्त स्वेच्छा से अनुपस्थित रहता है।
- अमेरिका में सामान्यतः अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक होती है, परंतु यदि कार्यवाही शुरू होने के बाद अभियुक्त फरार हो जाए तो सुनवाई जारी रखी जा सकती है।
- फ्रांस और इटली इसे सुरक्षा उपायों के साथ अनुमति देते हैं, जैसे अभियुक्त के उपस्थित होने पर पुनर्विचारण या अपील।

CCI विनियमों पर अधीनस्थ विधान समिति की रिपोर्ट

संदर्भ: राज्य सभा की अधीनस्थ विधान समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चार 2024 के विनियमों और दिशानिर्देशों की समीक्षा की। रिपोर्ट में प्रतिस्पर्धा ढाँचे की समय-समय पर समीक्षा और दंड में बेहतर पारदर्शिता का आह्वान किया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रत्येक सदन की अपनी अधीनस्थ विधान समिति होती है, जिसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते; यह जाँच करती है कि प्रत्यायोजित नियम-निर्माण शक्तियों का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं। CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है; इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं और यह स्वतः संज्ञान ले सकता है।
- बड़ी कंपनियों द्वारा ढाँचे के दुरुपयोग से MSME और स्टार्ट-अप की रक्षा के लिए लक्षित पैरोकारी (एडवोकेसी) की सलाह दी गई है।
- बार-बार उल्लंघन करने वालों को मौद्रिक दंड दिशानिर्देशों के अंतर्गत सख्ती से दंडित किया जाना चाहिए, ताकि जुर्माने को व्यवसाय की लागत न माना जाए।
- CCI को दंड की विस्तृत गणितीय गणना देनी चाहिए; वह वसूली योग्य दंड का लगभग 98 प्रतिशत वसूल कर लेता है।
- क्षेत्रीय नियामकों के साथ संरचित समन्वय की सिफारिश की गई है, उदाहरण के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) के माध्यम से।
- CCI के आदेशों के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में की जाती है।

PM-AJAY को 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव

संदर्भ: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) को 2026-27 से 2030-31 तक बढ़े हुए परिव्यय के साथ जारी रखने का प्रस्ताव किया है। यह योजना 2021-22 में तीन पुरानी योजनाओं का विलय करके बनाई गई थी।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका पूरा वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाता है, हालांकि राज्य अपनी निधि भी जोड़ सकते हैं।

- इसमें PMAGY (आदर्श ग्राम घटक), SCA to SCSP (सहायता अनुदान घटक) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (छात्रावास घटक) का विलय किया गया।
- कोई गाँव आदर्श ग्राम के रूप में तब योग्य होता है जब उसकी 40 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की हो और जनसंख्या कम से कम 500 हो; प्रत्येक को ₹20 लाख तथा प्रशासन के लिए ₹1 लाख अतिरिक्त मिलते हैं।
- आदर्श ग्राम का लक्ष्य 10 क्षेत्रों में 50 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को संतृप्त करना है।
- अनुदान का कम से कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आय-सृजन योजनाओं में जाना चाहिए, और कौशल कार्यक्रमों में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को भाग लेना चाहिए।
- PM-AJAY पोर्टल और AJAY मोबाइल ऐप (मई 2026) जियो-टैगिंग, डैशबोर्ड और चरण-आधारित निधि प्रवाह उपलब्ध कराते हैं।

PM-विद्यालक्ष्मी का 1,425 संस्थानों तक विस्तार

संदर्भ: PM-विद्यालक्ष्मी अब 1,425 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों को कवर करती है, जो शुरुआत में 860 थे। यह योजना एकल डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बिना गिरवी (कोलैटरल) और बिना गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करती है।

□ मुख्य बिंदु

- इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी और मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर 2024 को इसे मंजूरी दी।
- यह ₹3,600 करोड़ के परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 2024-25 से 2030-31 तक के लिए है और जिससे लगभग 7 लाख नए विद्यार्थियों को ब्याज सहायता (सब्वेंशन) मिलने की आशा है।
- कवरेज में NIRF के शीर्ष 100 संस्थान, NIRF के शीर्ष 200 में आने वाले राज्य सरकार के संस्थान और सभी केंद्र सरकार के संस्थान शामिल हैं।
- ₹8 लाख प्रतिवर्ष तक आय वाले परिवारों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सहायता लागू है, जो प्रतिवर्ष ₹1 लाख तक सीमित है।
- केनरा बैंक नोडल बैंक है और NCGTC गारंटी निधि का प्रबंधन करता है।
- विद्यार्थी एक ही पोर्टल पर सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन पत्र (CELAF) का उपयोग करते हैं और अधिकतम तीन बैंकों में आवेदन कर सकते हैं।
- यह PM-USP CSIS का पूरक है, जो ₹4.5 लाख तक की पारिवारिक आय के लिए पूर्ण ब्याज सब्सिडी देती है, तथा शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना का भी पूरक है।

UDISE+ 2025-26, PGI 2.0 और AISHE

संदर्भ: शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ रिपोर्ट 2025-26 और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI) 2.0 जारी किया। UDISE+ विद्यालयों का कच्चा आँकड़ा देता है, जबकि PGI उसी के आधार पर राज्यों और जिलों की ग्रेडिंग करता है।

□ मुख्य बिंदु

- PGI की शुरुआत 2017 में हुई थी और NEP 2020 के अनुरूप इसे PGI 2.0 के रूप में नया रूप दिया गया; इसमें रैंक के स्थान पर ग्रेड बैंड का उपयोग होता है। PGI-S में 1000 अंक और छह क्षेत्रों में 70 संकेतक हैं; PGI-D में 600 अंक और 11 क्षेत्रों में 70 संकेतक हैं।
- UDISE+ 2025-26 में 14.67 लाख विद्यालय, 24.72 करोड़ विद्यार्थी और 1.03 करोड़ शिक्षक शामिल हैं।
- माध्यमिक स्तर का GER 68.5 प्रतिशत से बढ़कर 71.7 प्रतिशत हो गया; माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट 8.2 प्रतिशत से घटकर 7.0 प्रतिशत रह गया।
- आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों में छात्र-शिक्षक अनुपात क्रमशः 10, 12, 17 और 21 है, जो NEP के 30:1 के मानक से बेहतर है।
- 69.9 प्रतिशत विद्यालयों में कंप्यूटर और 67.4 प्रतिशत में इंटरनेट है; नामांकन में बालिकाओं की हिस्सेदारी 48.4 प्रतिशत है।
- एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या घटकर 1,00,843 रह गई।
- कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश उत्कर्ष, उत्तम-1 या उत्तम-2 तक नहीं पहुँचा; चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता रहा, जो उत्तम-3 में अकेला है।
- दिल्ली, केरल, पंजाब तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को प्रचेष्टा-1 में रखा गया।
- सर्वाधिक और सबसे कम अंक पाने वाले राज्यों के बीच का अंतर 2017-18 के 51 प्रतिशत से घटकर 31.4 प्रतिशत रह गया।

□ UDISE+ 2025-26

- इसमें लगभग 14.67 लाख विद्यालय और 24 करोड़ से अधिक विद्यार्थी शामिल हैं।
- शिक्षकों की संख्या 1.02 करोड़ से अधिक रही; माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट घटकर 7.0 प्रतिशत रह गया।
- माध्यमिक GER 68.5 से बढ़कर 71.7 प्रतिशत हो गया; 95 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली है।

□ AISHE

- उच्च शिक्षा में GER 23.7 (2014-15) से बढ़कर 30.0 (2023-24) हो गया।
- 2023-24 में महिला GER 31.2 रहा और STEM नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत है।
- AISHE के आँकड़े स्वैच्छिक और स्वयं-प्रदत्त होते हैं।

□ **PGI 2.0**

➤ PGI-S राज्यों की ग्रेडिंग छह क्षेत्रों में 70 संकेतकों पर 1,000 अंकों में करता है; PGI-D जिलों की ग्रेडिंग 600 अंकों में करता है।

PGI ग्रेड बैंड

ग्रेड	अंक सीमा
उत्कर्ष	941-1000
उत्तम-1 से 3	761-940
प्रचेष्टा-1 से 3	581-760
आकांक्षी-1 से 3	401-580

असम में नागरिकता निर्धारण पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ: सबित्री डे उर्फ स्वस्ति डे बनाम भारत संघ (2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने 27 व्यक्तियों को विदेशी घोषित करने वाले विदेशी अधिकरण और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया। इसने मामलों को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया और आग्रह किया कि नागरिकता का निर्धारण निष्पक्ष, विधिसम्मत और युक्तियुक्त प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ न्यायालय ने पाया कि अधिकरणों ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार नहीं किया था।

➤ नागरिकता संबंधी कार्यवाहियों के गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे हिरासत, निर्वासन और राज्यविहीनता, इसलिए विधि की उचित प्रक्रिया आवश्यक है।

➤ प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का सार्थक अवसर मिलना चाहिए।

➤ अवैध प्रवासियों की पहचान करने में राज्य का हित प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से ऊपर नहीं हो सकता।

उल्लास के अंतर्गत उत्तराखंड पूर्ण साक्षर

संदर्भ: उत्तराखंड NEP 2020 और उल्लास (ULLAS: Understanding Lifelong Learning for All in Society) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश तब पूर्ण साक्षर कहलाता है जब उसकी साक्षरता दर 95 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 2024 में साक्षरता को नए सिरे से परिभाषित किया गया: समझ के साथ पढ़ना, लिखना और गणना करना, साथ ही डिजिटल और वित्तीय साक्षरता।

➤ उल्लास शिक्षा मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 2022 में शुरू हुई और 2022-27 की अवधि के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों हेतु चल रही है।

➤ इसका लक्ष्य हाइब्रिड माध्यम से 5 करोड़ शिक्षार्थी हैं, यानी प्रतिवर्ष 1 करोड़।

➤ शिक्षण सामग्री 27 भाषाओं में उपलब्ध है और वितरण के लिए उल्लास ऐप तथा DIKSHA का उपयोग होता है।

➤ FLNAT मूल्यांकन प्रमाणपत्र NIOS और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाते हैं।

➤ 2 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी FLNAT में सम्मिलित हो चुके हैं; 3.2 करोड़ शिक्षार्थी और 47.7 लाख स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 और EPFO 3.0

संदर्भ: श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 अधिसूचित की, जिसने 1952 की योजना का स्थान लिया। अलग से, सरकार EPFO 3.0 पर कार्य कर रही है, जिसमें गिग, स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना भी शामिल है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ EPFO की स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत की गई है और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह EPF (1952), कर्मचारी पेंशन योजना (1995) और EDLI (1976) का संचालन करता है।

➤ नियोक्ता और कर्मचारी का 12 प्रतिशत अंशदान अपरिवर्तित है।

➤ अनिवार्य कवरेज के लिए ₹15,000 मासिक वेतन सीमा जारी है।

➤ ब्याज दर प्रतिवर्ष केंद्र द्वारा EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अनुशंसा पर अधिसूचित की जाती है; वर्तमान में यह 8.25 प्रतिशत है।

➤ मौजूदा UAN, शेष राशि और खाते बिना किसी व्यवधान के जारी रहते हैं।

➤ EPFO 2.0 ने 123 क्षेत्रीय डेटाबेस को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में मिला दिया।

➤ EPFO 3.0 में कोर बैंकिंग समाधान के एकीकरण, लचीली और पोर्टेबल सेवानिवृत्ति बचत तथा व्यापक पेंशन कवरेज की योजना है।

□ **EPF योजना 2026**

➤ नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करते हैं, अथवा अधिसूचित प्रतिष्ठानों के लिए 10 प्रतिशत।

➤ मौजूदा सदस्य स्वतः नई योजना में चले जाते हैं।

➤ आंशिक निकासी के नियमों को तीन श्रेणियों में सरल किया गया है: बीमारी, शिक्षा और विवाह, तथा आवास।

➤ किसी बड़े संकट में सरकार तीन महीने तक के लिए अंशदान घटा या स्थगित कर सकती है।

➤ नामांकन ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है।

- विश्वास 2026 और एम्नेस्टी 2026 विवादों के निपटारे और छूटों के नियमितीकरण के लिए छह महीने की अवधि वाली खिड़कियाँ हैं।
- EPS 2026 और EDLI योजना 2026 भी अधिसूचित की गईं।

केंद्र ने UAPA के अंतर्गत 23 और आतंकवादी नामित किए

संदर्भ: गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित समूहों, मुख्यतः जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, के 23 सक्रिय सदस्यों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आतंकवादी नामित किया। इससे नामित व्यक्तिगत आतंकवादियों की कुल संख्या 80 हो गई है।

□ मुख्य बिंदु

- इन 23 में से 17 पाकिस्तानी नागरिक हैं और 6 भारतीय नागरिक हैं जो पाकिस्तान और PoJK से सक्रिय हैं।
- उनकी भूमिकाओं में भर्ती, घुसपैठ, प्रशिक्षण, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति, साइबर अभियान और जम्मू-कश्मीर में हमलों की योजना बनाना शामिल है।
- 2019 के UAPA संशोधन ने केवल संगठनों ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों को भी धारा 35 और चौथी अनुसूची के अंतर्गत आतंकवादी नामित करने की अनुमति दी।
- 2024 तक, इस चरण से पहले 57 व्यक्तियों को नामित किया जा चुका था।

ग्राम सभा में कम भागीदारी पर अध्ययन और महिला-नेतृत्व वाली पंचायतें

संदर्भ: पंचायती राज मंत्रालय के लिए NIRD&PR द्वारा तैयार किए गए एक राष्ट्रीय अध्ययन में यह जाँच की गई कि नागरिक ग्राम सभा की बैठकों में कम संख्या में क्यों आते हैं और भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाए गए। भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता 2026 के दौरान मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण की पहलें भी प्रस्तुत कीं।

□ मुख्य बिंदु

- ग्राम सभा में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा तैयार की गई थी।
- 2025 में शुरू किए गए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- UNFPA के सहयोग से 744 ग्राम पंचायतों को आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक है।
- रिपोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) और शिकायत ट्रैकिंग की सिफारिश की गई है, ताकि ग्राम सभा के निर्णयों के दृश्यमान परिणाम सामने आएं।
- इसमें राष्ट्रीय ग्राम सभा जागरूकता, प्रक्रियात्मक साक्षरता और लामबंदी मिशन का प्रस्ताव किया गया है।
- उद्धृत सर्वोत्तम प्रथाओं में पंजाब में घर-घर निमंत्रण पत्र, तमिलनाडु में दिव्यांगजनों के लिए विशेष ग्राम सभाएँ और बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क का उपयोग शामिल हैं।

ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल और सामाजिक अंकेक्षण

संदर्भ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की अनुपालन और जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच है। इस शुभारंभ से जमीनी स्तर की जवाबदेही के एक साधन के रूप में सामाजिक अंकेक्षण का विचार चर्चा में आ गया है।

□ मुख्य बिंदु

- इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। यह हस्तचालित, कागज-आधारित लेखा परीक्षा की जगह AI-सक्षम, डेटा-आधारित लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली लाता है।
- मानचित्र दृश्य (मैप व्यू) लेखा परीक्षा कवरेज, टीमों की तैनाती और पैरा निपटान की स्थिति दिखाता है तथा उन लेखा परीक्षा इकाइयों को चिह्नित करता है जिनकी पहले कभी लेखा परीक्षा नहीं हुई।
- यह लेखा परीक्षा अभिलेखों, रिपोर्टों और अनुपालन प्रतिक्रियाओं का केंद्रीय भंडार रखता है तथा अनुमोदनों की वास्तविक समय में निगरानी करता है।
- सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें समुदाय और सरकार मिलकर किसी क्षेत्र में पहले से किए गए कार्यों और व्यय की जाँच करते हैं।
- विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 के अनुसार सभी कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कम से कम हर छह महीने में एक बार किया जाना आवश्यक है।
- चिंताओं में सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों की स्वतंत्रता का अभाव, निष्कर्षों पर कमजोर अनुवर्ती कार्रवाई और स्थानीय कार्यवाही पर अभिजात वर्ग का कब्जा शामिल हैं।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2024

संदर्भ: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें 99.1 प्रतिशत जन्म पंजीकरण और 99.4 प्रतिशत मृत्यु पंजीकरण दर्शाया गया है। वर्ष 2000 में जन्मों का पंजीकरण 56 प्रतिशत और मृत्यु का 48 प्रतिशत था।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक द्वारा किया जाता है। यह जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म का सतत, अनिवार्य और सार्वभौमिक पंजीकरण प्रदान करती है।
- 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत जन्म पंजीकरण तथा 21 ने 100 प्रतिशत मृत्यु पंजीकरण प्राप्त किया।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण के बीच का पारंपरिक अंतर लगभग समाप्त हो गया है।
- राज्यों के बीच गुणवत्ता, समयबद्धता (21 दिन की निर्धारित अवधि) और जन्म के समय लिंगानुपात में अंतर बना हुआ है।
- RBD अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत, विदेश में जन्मे ऐसे बच्चे का, जिसके माता-पिता भारत में बसने के लिए लौटते हैं, आगमन के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण किया जा सकता है।

भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 100 करोड़ के पार

संदर्भ: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में एक अरब का आँकड़ा पार कर लिया है। कवरेज 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 68.4 प्रतिशत हो गया, जिसमें 101 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- कवरेज 2015 में लगभग 25 करोड़ लोगों (19 प्रतिशत) से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ से अधिक (68.4 प्रतिशत) हो गया।
- भारत में 50 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं और उन्हें नियोक्ता-समर्थित सुरक्षा कवच प्राप्त नहीं है।
- JAM, आधार, ई-श्रम और DBT जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने इस विस्तार को बड़े पैमाने पर पहुँचाने में सहायता की।
- संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों और ILO अभिसमयों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा को एक मूल मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म और CBFC की न्यायिक समीक्षा

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने CBFC द्वारा प्रमाणित एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज़ को 27 जुलाई 2026 को पुरी रथ यात्रा के बाद तक स्थगित कर दिया। इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय ने धार्मिक मान्यताओं को विकृत करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर फिल्म पर रोक लगा दी थी।

□ **मुख्य बिंदु**

- रिलीज़ 17 जुलाई 2026 को होनी तय थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया; निर्माताओं के रिलीज़ टालने पर सहमत होने के बाद उसने अपील का निपटारा कर दिया, तथा सेंसरशिप के व्यापक मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं दिया।
- CBFC का प्रमाणपत्र न्यायिक समीक्षा में बाधक नहीं है, परंतु न्यायालय संयम से कार्य करते हैं और केवल सशक्त प्रथम दृष्टया मामले तथा अपूरणीय क्षति की स्थिति में ही हस्तक्षेप करते हैं।
- एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989): लोक-व्यवस्था बिगड़ने की धमकियों मात्र के आधार पर अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता।
- भारत संघ बनाम के.एम. शंकरप्पा (2000): CBFC वैधानिक विशेषज्ञ निकाय है और विधि द्वारा उपबंधित स्थिति को छोड़कर कार्यपालिका का हस्तक्षेप अनुमेय नहीं है।
- फिल्म प्रमाणन सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 द्वारा शासित है, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(a) को अनुच्छेद 19(2) के साथ संतुलित किया जाता है।

राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम लागू किए गए

संदर्भ: भारतीय खिलाड़ियों में डोपिंग के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 15 जुलाई 2026 से लागू किया गया। ये कानून खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2005 को प्रभावी बनाते हैं, जिसकी भारत ने 2007 में पुष्टि की थी।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह खेलों में डोपिंग-रोधी राष्ट्रीय बोर्ड को एक सलाहकारी और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में स्थापित करता है।
- NADA का सांविधिक निकाय के रूप में पुनर्गठन किया गया है, जिसे परीक्षण, जाँच और प्रवर्तन की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें प्रवेश, तलाशी और जब्ती शामिल हैं।
- राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अनुशासनात्मक पैनल मामलों की सुनवाई करता है और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अपील पैनल घरेलू अपीलों की सुनवाई करता है।
- अधिनियम में डोपिंग-रोधी नियम उल्लंघनों की 11 श्रेणियाँ सूचीबद्ध हैं और चिकित्सीय उपयोग छूट (Therapeutic Use Exemptions) की अनुमति दी गई है।
- राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को प्रमुख परीक्षण सुविधा के रूप में मान्यता दी गई है।
- एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की अपराधियों की सूची में 162 नामों के साथ भारत शीर्ष पर रहा।
- अत्यधिक उच्च डोपिंग जोखिम के कारण भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को श्रेणी A में रखा गया।

□ **2025 के संशोधन के अंतर्गत परिवर्तन**

- धारा 2A और एक अनुसूची विश्व डोपिंग-रोधी संहिता के अनुच्छेद 2 को प्रत्यक्ष विधिक बल प्रदान करती हैं, और केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को अद्यतन कर सकती है।
- 2025 का संशोधन अपील पैनल के गठन की शक्ति राष्ट्रीय बोर्ड से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है।
- खेल पंचाट न्यायालय (Court of Arbitration for Sport) में अपील कर सकने वालों में WADA, IOC, IPC और अंतरराष्ट्रीय महासंघ शामिल हैं।
- NADA के महानिदेशक और कर्मचारियों को महासंघों और खेल निकायों से परिचालन स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
- दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय सम्मान संशोधन अधिनियम, 2026 और वंदे मातरम पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया। यह 1971 के अधिनियम की धारा 3 द्वारा राष्ट्रगान को दी गई सुरक्षा को राष्ट्रीय गीत तक विस्तारित करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और यह पहली बार 7 नवंबर 1875 को बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ, तथा बाद में उपन्यास आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया और 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया।
- यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 में संशोधन करता है।
- वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या इसे गा रही किसी सभा में विघ्न डालना अब अपराध है।
- दंड तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों है; बार-बार दोषसिद्धि होने पर कम से कम एक वर्ष का अनिवार्य न्यूनतम दंड है।
- यह कानून सभी पर इस गीत को गाने का कोई सामान्य दायित्व नहीं डालता।
- 1971 का अधिनियम राष्ट्रगान की रक्षा करता है, परंतु वर्तमान में वंदे मातरम की नहीं।
- चिंताएँ अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक दंडों के दायरे से संबंधित हैं।
- इसका पहली बार राजनीतिक नारे के रूप में उपयोग 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था।
- 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे जन गण मन के समान सम्मान दिया जाना चाहिए।
- गृह मंत्रालय (MHA) के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब आधिकारिक छह-पद वाला संस्करण बजाया जाए तो श्रोताओं को खड़ा होना चाहिए, और जब दोनों बजाए जाएँ तो इसे राष्ट्रगान से पहले प्रस्तुत किया जाता है।
- संविधान में राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है; अनुच्छेद 51A(a) राष्ट्रगान के सम्मान का उल्लेख करता है।
- 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक समारोहों में केवल पहले दो पदों का उपयोग किया जाएगा।

□ **संवैधानिक प्रावधान**

- अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने तथा उसका आचरण करने के अधिकार की रक्षा करता है।
- अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों के अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने के अधिकार की रक्षा करता है।
- अनुच्छेद 51A(a) संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मूल कर्तव्य बनाता है, परंतु राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं करता।

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और BNSS की धारा 163

संदर्भ: नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों ने विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और BNSS, 2023 की धारा 163 (CrPC की धारा 144 की उत्तराधिकारी) के अंतर्गत निषेधात्मक आदेशों के उपयोग पर बहस को फिर से जीवित कर दिया। न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि यह अधिकार संरक्षित है, परंतु इसे युक्तियुक्त रूप से विनियमित किया जा सकता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(b) से उत्पन्न होता है और इसे अनुच्छेद 19(2) तथा 19(3) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- संविधान हर विरोध प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति की माँग नहीं करता, परंतु समय, स्थान और तरीके को विनियमित करने के लिए पुलिस की अनुमति और निर्धारित स्थल सामान्य व्यवहार हैं।
- BNSS की धारा 163 आपात स्थितियों के लिए एक असाधारण निवारक शक्ति है, असीमित शक्ति नहीं।
- हिम्मत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त (1973): राज्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को विनियमित कर सकता है, परंतु नागरिकों को एकत्र होने से मनमाने ढंग से नहीं रोक सकता।
- बाबूलाल पाराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961): CrPC की धारा 144 को वैध ठहराया गया, परंतु इसका उपयोग केवल आपात स्थिति और लोक व्यवस्था के लिए विशिष्ट खतरे में ही किया जा सकता है।
- मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018): जंतर मंतर के पास प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध अनुपातहीन था।

➤ अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020), शाहीन बाग मामला: सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता; विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर होने चाहिए।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन अधिनियम, 2026

संदर्भ: मानसून सत्र में संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को स्वीकृति दे दी और यह 31 जुलाई 2026 को लागू होगा। यह 2024 के अधिनियम को कठोर बनाता है, जिसके अंतर्गत बार-बार पेपर लीक की घटनाओं के बावजूद दो वर्षों में कोई दोषसिद्धि नहीं हुई थी; इसमें समर्पित न्यायालय, निश्चित समय-सीमाएँ और कठोर दंड हैं।

□ मुख्य बिंदु

➤ 2015 से लगभग 148 पेपर लीक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें NEET-UG 2026 और 2024 की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है और उसके स्वीकृत पदों में से लगभग 41 प्रतिशत रिक्त हैं।

➤ प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक (SFT) न्यायालय के रूप में नामित करना होगा; लंबित मामले उसमें स्थानांतरित किए जाएँगे।

➤ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SFT न्यायालयों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने होंगे, जिसकी आवश्यकता 2024 के अधिनियम में नहीं थी।

➤ जाँच 2 माह के भीतर और सुनवाई आरोप-पत्र दाखिल होने के 3 माह के भीतर पूरी करनी होगी, जिसमें प्रतिदिन सुनवाई होगी।

➤ केंद्र सरकार एक विशेष कार्य बल (STF) का गठन कर सकती है; गठन के बाद केवल STF ही मामले की जाँच करेगा।

➤ विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष होगी, 30 दिनों के भीतर (90 दिनों तक बढ़ाई जा सकने वाली) दायर करनी होगी और उसका निपटारा 3 माह के भीतर किया जाना है।

➤ कदाचार की परिभाषा व्यापक है, जिसमें प्रश्न पत्रों या उत्तर कुंजियों का लीक होना तथा OMR शीट या कंप्यूटर प्रणालियों से छेड़छाड़ शामिल हैं।

➤ संबंधित सुधार कदमों में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाला कार्य बल और राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशें शामिल हैं।

□ बढ़ाए गए दंड

➤ व्यक्तिगत अपराधी: 5-10 वर्ष का कारावास और ₹50 लाख तक का जुर्माना (पहले 3-5 वर्ष और ₹10 लाख)।

➤ सेवा प्रदाता: ₹5 करोड़ तक का जुर्माना और 8 वर्ष के लिए प्रतिबंध (पहले ₹1 करोड़ और 4 वर्ष)।

➤ सेवा प्रदाताओं का प्रबंधन: 5-10 वर्ष और ₹5 करोड़ का जुर्माना (पहले 3-10 वर्ष और ₹1 करोड़)।

➤ संगठित अपराध: 7-10 वर्ष और न्यूनतम ₹10 करोड़ का जुर्माना (पहले 5-10 वर्ष और न्यूनतम ₹1 करोड़)।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर और अत्याचार नियम सुधार

संदर्भ: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आय-आधारित क्रीमी लेयर का विरोध करता है। अलग से, एक सरकारी कार्यबल ने राहत और अन्वेषण से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों में बदलाव की सिफारिश की।

□ मुख्य बिंदु

➤ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यबल का गठन दिसंबर 2025 में किया गया था।

➤ इसने राहत राशि बढ़ाने की सिफारिश की, जो वर्तमान में ₹85,000 से ₹8.25 लाख है और 2016 में निर्धारित की गई थी।

➤ इसने पीड़ितों के लिए परामर्श, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास प्रकोष्ठ, तथा प्राथमिकी और आरोप-पत्र 24 घंटे के भीतर अधिकारियों को भेजने का सुझाव दिया।

➤ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने अलग से प्रस्ताव दिया कि मुकदमे के दौरान बेदखल किए गए आदिवासियों को आजीविका के लिए विवादित भूमि का उपयोग करने की अनुमति जिलाधिकारी दे सकें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विद्यालय में हिजाब की याचिका खारिज की

संदर्भ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्कूल की वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति माँगी थी। न्यायालय ने कहा कि सिर पर दुपट्टा या स्कार्फ आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्ध नहीं हुआ है और विद्यालय वर्दी निर्धारित कर सकते हैं।

□ मुख्य बिंदु

➤ आवश्यक धार्मिक प्रथा की कसौटी की उत्पत्ति शिरूर मठ वाद (1954) में हुई, जो 7 न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था।

➤ रेशम बनाम कर्नाटक राज्य (2022): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिजाब आवश्यक प्रथा नहीं है।

➤ आइशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य (2022): सर्वोच्च न्यायालय ने खंडित निर्णय दिया (न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया) और मामले को वृहत्तर पीठ को सौंप दिया।

- आमना बिंत बशीर बनाम CBSE (2016): केरल उच्च न्यायालय ने सिर पर दुपट्टा या स्कार्फ को आवश्यक माना और अतिरिक्त जाँच के साथ परीक्षाओं में उसकी अनुमति दी।
- मई 2026 में कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसने फरवरी 2022 के प्रतिबंध को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर दिया।

□ न्यायालय का तर्क

- कोई विद्यालय अपना ड्रेस कोड स्वयं निर्धारित कर सकता है, यदि वह एकसमान, सद्भावपूर्ण और भेदभाव-रहित हो।
- पूर्व में प्रवर्तन न होने से कोई निहित अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
- अनिवार्य धार्मिक प्रथा का दावा प्रामाणिक साक्ष्य के बिना मात्र एक कथन था।
- छात्रा यह नहीं दिखा सकी कि अनुच्छेद 25 ने उसे समान नीति के विरुद्ध कोई प्रवर्तनीय अधिकार दिया था।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या को भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 38 न्यायाधीशों तक बढ़ाया गया, पहले मई 2026 में जारी अध्यादेश द्वारा और फिर उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 द्वारा, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और संविधान पीठों को अधिक नियमित रूप से बैठने देना है।

□ मुख्य बिंदु

- नई स्वीकृत संख्या CJI सहित 38 न्यायाधीश है।
- यह अधिनियम 16 मई 2026 से प्रभावी माना गया है और यह उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 का स्थान लेता है।
- न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम द्वारा निर्धारित होती है।
- पूर्व की संख्याएँ: 1950 में 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34।
- जनवरी 2026 में उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले 92,101 थे।

□ न्यायिक बकाया (लंबित मामले)

- कुल लंबित मामले 5.5 करोड़ से अधिक हैं, जिनमें लगभग 4.914 करोड़ जिला अदालतों में और 64.2 लाख उच्च न्यायालयों में हैं।
- भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 15 से 22 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने 50 की सिफारिश की है।
- उच्च न्यायालयों के 1,114 पदों में से लगभग 350 रिक्त हैं।
- जेल के लगभग 75 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं।
- सुधार के रूप में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सुझाव दिया गया है।

गोरखालैंड: स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए समिति

संदर्भ: केंद्र ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों और निकटवर्ती क्षेत्रों में गोरखालैंड की माँग के स्थायी राजनीतिक समाधान हेतु समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वार्ताकार पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की।

□ माँग का विकास

- 1980 का दशक: गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पृथक राज्य का आंदोलन तेज हुआ।
- 1988: त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद का गठन किया गया।
- 2007: गोरखा पर्वतीय परिषद को छठी अनुसूची में शामिल करने वाले विधेयक समाप्त हो गए।
- 2011: त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन की स्थापना की गई।
- 2017: 100 दिन के आंदोलन ने राज्य के दर्जे की माँग को पुनर्जीवित कर दिया।
- 2025: पंकज कुमार सिंह को वार्ताकार नियुक्त किया गया।

□ संभावित समाधान

- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पृथक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश।
- अधिक विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों वाला सुदृढ़ GTA।
- भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची जैसी व्यवस्था।
- सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है, इसलिए सुरक्षा और सामरिक हितों में संतुलन बनाना आवश्यक है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026

संदर्भ: जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन गया। यह एक आधिकारिक या न्यायिक आदेश की आवश्यकता जोड़कर विलंबित पंजीकरण को और कठोर बनाता है।

□ मुख्य बिंदु

- यह अधिनियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में संशोधन करता है।
- 1 से 2 वर्ष के विलंब के लिए सत्यापन और शुल्क भुगतान के बाद जिला मजिस्ट्रेट या उप-खंड मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है।
- 2 वर्ष से अधिक के विलंब के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है।

- चिंताओं में न्यायालयों पर बढ़ा कार्यभार, दूरदराज के क्षेत्रों में कठिन पहुँच, वास्तविक नागरिकों के बहिष्कृत होने का जोखिम और दो वर्ष की सीमा के लिए स्पष्ट औचित्य का अभाव शामिल हैं।

2026 के संशोधन के अंतर्गत विलंबित पंजीकरण

विलंब	आवश्यक प्राधिकारी
1 से 2 वर्ष	DM या SDM
2 वर्ष से अधिक	प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

दिशा 2.0: प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय तक पहुँच

संदर्भ: दिशा 2.0 (समग्र न्याय पहुँच हेतु नवोन्मेषी समाधान का निर्माण) न्याय विभाग की पाँच वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो डिजिटल और AI उपकरणों के माध्यम से विधिक सहायता, जागरूकता और निःशुल्क (प्रो बोनो) सेवाओं द्वारा न्याय तक पहुँच का विस्तार करती है। इसका परिव्यय ₹255 करोड़ है, जिसका पूरा वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता से किया जाता है।

□ योजना का विवरण

- यह 2021 से 2026 की पूर्ववर्ती दिशा योजना पर आधारित है, जिसने मई 2026 तक 2.37 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुँच बनाई।
- यह विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलेगी।

□ चार घटक

- टेली-लॉ 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों और न्याय सहायकों के माध्यम से, AI तथा बहुभाषी पहुँच की सहायता से, मुकदमे से पूर्व निःशुल्क परामर्श देता है।
- न्याय बंधु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क (प्रो बोनो) विधिक सहायता प्रदान करता है और विधि महाविद्यालयों में प्रो बोनो क्लबों को बढ़ावा देता है।
- विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज, विधि विश्वविद्यालयों और मीडिया के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- विधि-संजीवनी एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है, जिसमें डैशबोर्ड है और जो AI-संचालित बहुभाषी न्याय सेतु चैटबॉट से एकीकृत है।

न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग

संदर्भ: न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है और यह न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करता है। यह न्यायाधिकरण सदस्यों के चयन और पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करता है, जो स्वतंत्रता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की दीर्घकालिक चिंताओं का उत्तर है।

□ मुख्य बिंदु

- एस.पी. संपत कुमार (1987) और एल. चंद्र कुमार (1997) में कहा गया कि न्यायाधिकरणों के निर्णय उच्च न्यायालय की समीक्षा के लिए खुले रहते हैं क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचे का अंग है। रोजर मैथ्यू (2019) में एक स्वतंत्र वैधानिक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) की अनुशंसा की गई।
- NTC सदस्यों का चयन करता है, न्यायाधिकरणों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, शिकायतों का पर्यवेक्षण करता है और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड का रखरखाव करता है; इसके लेखों की लेखापरीक्षा CAG द्वारा की जाती है।
- इसमें 5 सदस्य हैं: एक अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति), दो न्यायिक सदस्य और कम से कम 25 वर्ष के अनुभव वाले दो तकनीकी सदस्य।
- सदस्य 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
- न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं; न्यायाधिकरणों के सदस्य 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं।
- एक खोज-सह-चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए एक अभ्यर्थी और एक प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी की अनुशंसा करती है, और केंद्र को 3 महीने के भीतर नियुक्ति करनी होगी।
- हितों के टकराव या पद के दुरुपयोग के आधार पर हटाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जाँच आवश्यक है।
- मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2025) में 2021 के अधिनियम के कुछ भागों को शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन के कारण निरस्त कर दिया गया और एक स्वतंत्र NTC का निर्देश दिया गया।
- रिक्तियों, विलंब तथा अनियमित योग्यताओं और कार्यकालों ने न्यायाधिकरणों को कमजोर कर दिया था।

पुलिस हिरासत और FIR तक पहुँच पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों ने आपराधिक प्रक्रिया को स्पष्ट किया। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम सुडा सुरेश वीरा वेंकट नागा राजू में न्यायालय ने BNSS की धारा 187(2) का यह अर्थ लगाया कि पुलिस हिरासत किश्तों में दी जा सकती है, और उसने गाजियाबाद पुलिस को एक पत्रकार को FIR और CCTV फुटेज की प्रति देने का निर्देश दिया।

□ BNSS के अंतर्गत पुलिस हिरासत

- BNSS की धारा 187(2) अनुमेय निरोध के पहले 40 या 60 दिनों के भीतर कुल मिलाकर अधिकतम 15 दिन तक पुलिस हिरासत किश्तों में देने की अनुमति देती है।
- पहले हिरासत केवल एक 15 दिन की अवधि तक सीमित थी।

- BNSS की धारा 38 अधिवक्ता तक पहुँच देती है, परंतु पूछताछ के दौरान अधिवक्ता की निरंतर उपस्थिति नहीं।

□ FIR तक पहुँच

- BNSS की धारा 173(2) FIR की प्रति सूचनादाता या पीड़ित को निःशुल्क देती है, परंतु अभियुक्त का उल्लेख नहीं करती।
- BNSS की धारा 230 आरोप-पत्र के न्यायालय पहुँचने के बाद अभियुक्त को FIR की प्रतियाँ देती है।
- यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ (2016) में FIR को 24 घंटे के भीतर अपलोड करने की अपेक्षा की गई, जो असाधारण मामलों में 48 से 72 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है।
- यौन अपराधों, POCSO और आतंकवाद से संबंधित FIR को प्रकाशित होने से रोका जा सकता है।
- अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी, विधिक परामर्शदाता और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की गारंटी देता है।

बीसीआई-नालसार नामांकन विवाद और बीसीआई की शक्तियाँ

संदर्भ: दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने राज्य बार काउंसिलों को नालसार के 2026 के स्नातकों का नामांकन रोकने का निर्देश दिया, फिर उस निर्देश को वापस ले लिया। इस घटना ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बीसीआई की शक्तियों पर प्रश्न खड़े किए।

□ मुख्य बिंदु

- अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नामांकन आवेदन पर व्यक्तिगत रूप से विचार करना आवश्यक है। शांतिपूर्ण विरोध या राय व्यक्त करना कोई वैधानिक अयोग्यता नहीं है।
- इंडियन काउंसिल ऑफ़ लीगल एड एंड एडवाइस बनाम बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (1995) में उच्चतम न्यायालय ने 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के नामांकन पर रोक लगाने वाले बीसीआई के नियम को रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि बीसीआई अपनी धारा 49 की नियम-निर्माण शक्ति का उपयोग अतिरिक्त अयोग्यताएँ बनाने के लिए नहीं कर सकती।
- नामांकन मुख्यतः धारा 24 से 26 के तहत राज्य बार काउंसिलों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारतीय न्यायपालिका का डिजिटल रूपांतरण और ई-कोर्ट्स

संदर्भ: 2007 में शुरू की गई ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत की कागज-आधारित न्यायपालिका को डिजिटल प्रणाली में बदल रही है, जिसके चरण III (2023-27) में AI उपकरणों का परीक्षण (पायलट) किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सिक्किम को देश की पहली कागज-रहित (पेपरलेस) राज्य न्यायपालिका घोषित किया।

□ ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना

- इसे उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ न्याय विभाग चलाता है और उच्च न्यायालयों के माध्यम से लागू किया जाता है।
- चरण I (2007-2015) में बुनियादी कम्प्यूटरीकरण, LAN और केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम शामिल थे; चरण II (2015-2023) में ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड और वर्चुअल कोर्ट आए; चरण III (2023-2027) का लक्ष्य संपूर्ण डिजिटल रूपांतरण, कागज-रहित अदालतें, ई-सेवा केंद्र और AI का उपयोग है।
- ई-फाइलिंग से भुगतान, ई-हस्ताक्षर, ई-वकालतनामा और मामले की ट्रैकिंग के साथ ऑनलाइन दाखिल करना संभव होता है।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड अदालतों में लंबित और निपटाए गए मामलों पर एक सार्वजनिक डैशबोर्ड है।
- 11 उच्च न्यायालयों में लाइवस्ट्रीमिंग है और 31 वर्चुअल कोर्ट यातायात चालान निपटाते हैं; न्याय श्रुति से वर्चुअल गवाही संभव होती है।
- अदालती अभिलेखों के 753 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
- अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस, अदालतों, जेलों, अभियोजन और फोरेंसिक को जोड़ती है; संबंधित उपकरणों में CCTNS, ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-प्रिजन और NAFIS शामिल हैं।
- NSTEP GPS-सक्षम है और समन की वास्तविक समय में तामील सुनिश्चित करता है।

□ चरण III के अंतर्गत AI उपकरण

- LegRAA विधिक शोध और विश्लेषण में सहायता करता है।
- ASR-SHRUTI आवाज को पाठ में बदलता है और PANINI अनुवाद करता है।
- eSCR निर्णयों का 18 भाषाओं में अनुवाद करता है।
- IIT मद्रास का एक उपकरण याचिकाओं की त्रुटियों का पता लगाता है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026

संदर्भ: केंद्र ने ISI अधिनियम, 1959 का स्थान लेने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। यह ISI को सोसाइटी से वैधानिक निगमित निकाय बनाता है और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का उसका दर्जा बनाए रखता है, परंतु कुछ प्रावधानों पर संकाय सदस्यों और सांसदों ने आपत्ति जताई है।

□ मुख्य बिंदु

- भारत के राष्ट्रपति विज़िटर होते हैं, जिन्हें संस्थान की समीक्षा करने, जाँच का आदेश देने और बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

- 11 सदस्यीय शासी मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) प्रमुख कार्यकारी निकाय है और शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक तथा वित्तीय मामलों में अंतिम निर्णयकर्ता है।
- बोर्ड में एक अध्यक्ष, केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि, 4 प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञ (कम से कम एक महिला) और ISI के 4 प्रतिनिधि होते हैं।
- अध्यक्ष को केंद्र की अनुशंसा पर विज़िटर द्वारा नामित किया जाता है।
- निदेशक की अध्यक्षता वाली अकादमिक परिषद प्रमुख शैक्षणिक निकाय है।
- निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे बोर्ड विज़िटर की पूर्व स्वीकृति से नियुक्त करता है, और उसे हटाने के लिए भी विज़िटर की स्वीकृति आवश्यक है।
- नए केंद्रों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए कॉर्पस फंड अनिवार्य किया गया है।
- शासन का आधुनिकीकरण करना और ISI को सांख्यिकीय विज्ञान में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र बनाना।
- सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान में अंतर-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- आरक्षण के प्रयोजन से ISI को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान माना जाएगा।

भूमिका ट्रस्ट वाद: न्यायिक सेवा के लिए बार प्रैक्टिस

संदर्भ: भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2026) में 2:1 के बहुमत वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए पूर्व विधि प्रैक्टिस की अनिवार्यता को बनाए रखा, परंतु इसे तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह ने बहुमत बनाया, जबकि न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने असहमति जताई।

□ अनिवार्यता का विकास

- 1993, द्वितीय AIJA वाद: न्यायालय ने बार में तीन वर्ष की प्रैक्टिस निर्धारित की।
- 2002, तृतीय AIJA वाद: शेट्टी आयोग की सलाह पर इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।
- 2025: सर्वोच्च न्यायालय ने तीन वर्ष की अनिवार्यता बहाल कर दी।
- 2026: न्यायालय ने इसे घटाकर एक वर्ष कर दिया और पर्यवेक्षित क्लर्कशिप को अनुभव के एक रूप में स्वीकार किया।

□ निर्धारित ढाँचा

- संक्रमणकालीन अवधि (मई 2025 से मार्च 2027): सभी विधि स्नातक परीक्षा में बैठ सकते हैं; चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी होते हैं, जिन्हें JMFC के कुल पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत दिया जाता है।
- प्रशिक्षण दो वर्ष का होता है: पहला वर्ष राज्य न्यायिक अकादमी में, दूसरा वर्ष पर्यवेक्षित विधि लिपिक के रूप में (6 महीने प्रधान जिला न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अधीन और 6 महीने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन)।
- 1 अप्रैल 2027 से अभ्यर्थियों को कम से कम 10 वर्ष की वरिष्ठता वाले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित एक वर्ष की सक्रिय बार प्रैक्टिस आवश्यक होगी।
- यह ढाँचा 5 वर्ष तक चलेगा, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर इसकी समीक्षा करेगा।
- न्यायमूर्ति चंद्रन ने असहमति जताई और मूल तीन वर्ष की बार प्रैक्टिस को वरीयता दी।

मानसून सत्र 2026 में संसद की उत्पादकता

संदर्भ: अगस्त में हुए मानसून सत्र 2026 के दौरान लोकसभा ने दो दशकों से अधिक समय में अपने सबसे निम्न उत्पादकता स्तरों में से एक दर्ज किया; 2004 के बाद केवल दो सत्रों का कामकाज इससे बुरा रहा। पीआरएस के आँकड़ों के अनुसार उत्पादकता लोकसभा के लिए 15 प्रतिशत और राज्यसभा के लिए 33 प्रतिशत रही, जबकि सरकारी आँकड़ों के अनुसार 19 और 39 प्रतिशत रही।

□ मुख्य बिंदु

- लोकसभा की उत्पादकता निर्धारित समय का 15 प्रतिशत और राज्यसभा की 33 प्रतिशत रही।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार यह लोकसभा के लिए 19 प्रतिशत और राज्यसभा के लिए 39 प्रतिशत रही।
- पीआरएस उत्पादकता की गणना वास्तविक बैठक घंटों को निर्धारित घंटों से भाग देकर 100 से गुणा करके करता है, इसलिए यह 100 प्रतिशत से अधिक भी हो सकती है।
- ऐतिहासिक निम्न स्तर: शीतकालीन सत्र 2010 (लोकसभा 5 प्रतिशत, राज्यसभा 2 प्रतिशत), शीतकालीन सत्र 2013 (लोकसभा 8, राज्यसभा 19) और शीतकालीन सत्र 2016 (लोकसभा 15, राज्यसभा 18)।
- सर्वाधिक उत्पादकता बजट सत्र 2024 में रही: लोकसभा 148 प्रतिशत और राज्यसभा 137 प्रतिशत।

मिशन समृद्ध गाँव और नशा मुक्त युवा अभियान

संदर्भ: दो ग्रामीण और युवा पहलें शुरू की गईं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन समृद्ध गाँव को पायलट आधार पर शुरू किया, और प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया।

□ मिशन समृद्ध गाँव

- पायलट क्षेत्र मध्य प्रदेश में बुदनी ब्लॉक (सीहोर) और खातेगाँव ब्लॉक (देवास) हैं।
- योजनाओं के अभिसरण के साथ परिवार, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर योजनाएँ तैयार की जाएँगी।
- यह महिला किसानों की पहचान करता है और संकटजनित प्रवासन को कम करने का लक्ष्य रखता है।

□ **नशा मुक्त युवा अभियान**

- इसकी 100 सप्ताह की कार्य योजना है, जिसमें प्रत्येक रविवार खेल, कला, संस्कृति, योग और नशा-विरोधी जागरूकता का कार्यक्रम होता है।
- यह काशी पायलट परियोजना से विकसित हुआ है और काशी घोषणा-पत्र के तहत 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है।
- काशी घोषणा-पत्र 20 जुलाई 2025 को वाराणसी में अपनाया गया था और यह 5 वर्ष की रूपरेखा देता है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) 1969 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी; इसका आदर्श वाक्य है 'स्वयं से पहले आप'।

लाइवस्ट्रीम की गई न्यायालयी कार्यवाही: हर्षिता ग्रोवर आदेश

संदर्भ: हर्षिता ग्रोवर बनाम भारत संघ (2026) में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम निर्देश जारी किए, जिनमें पूर्व अनुमति के बिना लाइवस्ट्रीम की गई न्यायालयी कार्यवाही के निष्कर्षण, प्रसार और मुद्रीकरण पर रोक लगाई गई। न्यायालय ने आधिकारिक न्यायालय अभिलेखागारों के माध्यम से पहुँच के लिए एक प्रोटोकॉल का भी प्रस्ताव रखा।

□ **मुख्य बिंदु**

- खुली कार्यवाही की लाइवस्ट्रीमिंग जारी रखें, जबकि संकीर्ण रूप से परिभाषित संवेदनशील श्रेणियों को इससे बाहर रखें।
- मानक उपयोग-शर्तों के साथ एक प्रमाणित आधिकारिक खुला अभिलेखागार बनाएँ।
- जानबूझकर की गई मिथ्या प्रस्तुति को मौजूदा कानून के तहत दंडित करें, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 129 के तहत न्यायालय की अवमानना।
- छेड़छाड़ रोकने के लिए डिजिटल वॉटरमार्क, टाइमस्टैंप और प्रमाणित स्रोत-लिंक का उपयोग करें।
- प्रोटोकॉल बनाने में न्यायपालिका, बार, पत्रकारों, प्लेटफ़ॉर्म और नागरिक समाज को शामिल करें।

विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंज़ूरी

संदर्भ: विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण से मंज़ूरी देने से इनकार करने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई। यह मामला अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए मंज़ूरी की व्यवस्था को रेखांकित करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- विदेश मंत्रालय राजनीतिक मंज़ूरी देता है, जिसकी प्रक्रिया 2016 से ई-पॉलिटिकल क्लीयरेंस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है।
- मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों को सामान्यतः विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंज़ूरी, एफसीआरए मंज़ूरी और आर्थिक कार्य विभाग से आर्थिक मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।
- विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंज़ूरी अन्य मंज़ूरियों की पूर्व शर्त है।
- केंद्रीय मंत्रियों को विदेश मंत्रालय की मंज़ूरी के साथ प्रधानमंत्री की स्वीकृति भी चाहिए।
- लोकसभा सांसदों को अध्यक्ष की मंज़ूरी और राज्यसभा सांसदों को सभापति की मंज़ूरी चाहिए।
- पहले की अस्वीकृतियों में अरविंद केजरीवाल की 2022 की सिंगापुर यात्रा तथा तरुण गोगोई की अमेरिका और इज़राइल यात्राएँ शामिल थीं।

संसद के अधिनियम द्वारा केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया

संदर्भ: राष्ट्रपति ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को स्वीकृति दे दी, जो अब केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 है। यह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की स्वीकृति और 2024 में राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद किया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- अनुच्छेद 3 संसद को नया राज्य बनाने, किसी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने, घटाने या बदलने तथा किसी राज्य का नाम बदलने की अनुमति देता है।
- केरल विधानसभा ने 2024 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और जून 2024 में उसे केंद्र को भेजा।
- गृह मंत्रालय इसकी जाँच करता है और रेलवे, खुफिया ब्यूरो (IB), डाक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, महापंजीयक तथा जहाँ प्रासंगिक हो वहाँ विदेश मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करता है।
- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।
- राष्ट्रपति को विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार जानने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर भेजना होता है, किंतु वे उन विचारों से बाध्य नहीं होते।
- विधेयक संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
- नाम परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन आवश्यक नहीं है।
- केरल के स्थान पर केरलम रखने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फाँसी को मृत्युदंड के तरीके के रूप में बरकरार रखा

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फाँसी को वैज्ञानिक रूप से अविश्वसनीय और अनुच्छेद

21 के अंतर्गत गरिमामय मृत्यु का उल्लंघन बताया गया था। न्यायालय ने कहा कि इस चुनौती में दीना बनाम भारत संघ (1983) के बाध्यकारी पूर्व-निर्णय को हिलाने के लिए कोई नया साक्ष्य नहीं था।

□ **मुख्य बिंदु**

- विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट (1967) में एक निश्चित, मानवीय, त्वरित और शालीन तरीके की अपेक्षा की गई थी, परंतु फाँसी को बदलने की अनुशंसा नहीं की गई।
- 187वीं रिपोर्ट (2003) ने विकल्प के रूप में घातक इंजेक्शन की अनुशंसा की।
- न्यायालय ने मौजूदा पूर्व-निर्णय पर और इस बात पर भरोसा किया कि संसद ने BNSS लागू करते समय फाँसी को बनाए रखा।
- स्टेयर डिसाइसिस का अर्थ है तय किए गए विषयों पर कायम रहना।

□ **न्यायिक पूर्व-निर्णय**

- राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979) ने मृत्युदंड को अपवादस्वरूप मामलों तक सीमित किया।
- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मृत्युदंड को बरकरार रखा और दुर्लभतम से दुर्लभ सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- दीना बनाम भारत संघ (1983) ने CrPC की धारा 354(5) के अंतर्गत फाँसी को त्वरित, सरल और शालीन मानते हुए बरकरार रखा।
- ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) ने कहा कि अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 को लिव-इन साझेदारों तक विस्तारित किया

संदर्भ: डॉ. लोकेश बी.एच. बनाम कर्नाटक राज्य (2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नियों के प्रति क्रूरता के विरुद्ध दंडात्मक संरक्षण विवाह की प्रकृति वाले लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं पर भी लागू होता है। न्यायालय ने दो शर्तों पर बल दिया: वास्तविक सहवास और विवाह करने का आशय।

□ **मुख्य बिंदु**

- डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्माल (2010) में ऐसे संबंध की तुलना सामान्य विधि विवाह से की गई, जिसमें वैधानिक आयु, स्वैच्छिक सहवास और पति-पत्नी के रूप में सार्वजनिक प्रस्तुति आवश्यक है। इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा (2013) में लंबे समय तक सहवास, साझा घर, साझा वित्त और दंपति के रूप में सार्वजनिक छवि जैसे गैर-विस्तृत कारक गिनाए गए।
- संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है, जो अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 है।
- यह अपराध पति या उसके संबंधियों द्वारा की गई क्रूरता को 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित करता है।
- क्रूरता में ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण शामिल है जिससे महिला के आत्महत्या करने या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने की संभावना हो, तथा संपत्ति की अवैध माँगों के लिए दबाव डालने हेतु उत्पीड़न भी शामिल है।
- विवाह की प्रकृति वाले संबंध की अवधारणा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) से आई है।
- 2026 के निर्णय ने इंद्रा सरमा के कारकों की पुनः पुष्टि की और आपराधिक दायित्व के लिए विवाह के आशय को पूर्व शर्त के रूप में जोड़ा।

लिव-इन संबंध विधिशास्त्र का विकास

वाद	सिद्धांत
डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्माल (2010)	सामान्य विधि विवाह की कसौटी
इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा (2013)	घरेलू संबंध के दृष्टांतात्मक कारक
डॉ. लोकेश बी.एच. बनाम कर्नाटक राज्य (2026)	दंडात्मक क्रूरता प्रावधान के लिए सहवास के साथ विवाह का आशय

अनुच्छेद 124(3) और प्रतिष्ठित विधिवेत्ता की नियुक्ति

संदर्भ: सितंबर 2026 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ ने प्रश्न उठाया कि अनुच्छेद 124(3), जो किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति देता है, 76 वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त क्यों रहा है। उन्होंने कॉलेजियम की कैरियर न्यायाधीशों को प्राथमिकता और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियम 49 की ओर संकेत किया। यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है।

□ **मुख्य बिंदु**

- कॉलेजियम में केवल कैरियर न्यायाधीश होते हैं, जो विद्वत्ता की तुलना में न्यायालयी अनुभव को प्राथमिकता देते हैं।
- बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया का नियम 49 उन अधिवक्ताओं को, जो विधि शिक्षण जैसी पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकरी करते हैं, अपना लाइसेंस सौंपने के लिए बाध्य करता है।
- विद्वानों की सीधी नियुक्ति से वरिष्ठता और मुख्य न्यायाधीश की उत्तराधिकार पंक्ति जटिल हो सकती है।
- जर्मनी, दक्षिण अफ़्रीका, स्पेन, इटली, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे देश विधि के शिक्षाविदों को संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्त करते हैं।
- पेटेंट कानून पर नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ वाद में प्रो. शमनाद बशीर की भूमिका को शैक्षणिक प्रभाव के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है।

अनुच्छेद 142 और जेन ज़ी प्रदर्शन मामलों को रद्द करना

संदर्भ: अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के बाद हुए देशव्यापी प्रदर्शनों से जुड़े जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले रद्द कर दिए। इस आदेश ने पूर्ण न्याय के लिए न्यायालय की शक्ति की सीमाओं की परीक्षा ली है।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश (1962): अनुच्छेद 142 संविधान या मौलिक अधिकारों को अधिभावी नहीं कर सकता।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998): यह शक्ति पूर्ण और अनुपूरक है, परंतु मूल कानून का स्थान नहीं ले सकती।
- शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023): न्यायालय विवाह के अपूरणीय भंग होने पर उसे विघटित कर सकता है।
- हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024): अनुच्छेद 142 उन व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता जो न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।

ईवीएम टोटलाइज़र और उच्चतम न्यायालय का नोटिस

संदर्भ: सितंबर 2026 में उच्चतम न्यायालय ने 2014 की उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए, जिसमें मतदान केंद्रों के मतों को मिलाने की माँग की गई है, ईवीएम मतगणना के लिए टोटलाइज़र लागू करने पर केंद्र की राय माँगी। बीईएल और ईसीआईएल द्वारा विकसित टोटलाइज़र लगभग 14 मतदान केंद्रों के मतों को जोड़ता है ताकि बूथ-वार मतदान का स्वरूप उजागर न हो। वर्तमान चुनाव कानूनों में इसके लिए कोई स्पष्ट ढाँचा नहीं है।

□ **मुख्य बिंदु**

- बीईएल बेंगलुरु और ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा विकसित टोटलाइज़र मतगणना से पहले लगभग 14 मतदान केंद्रों के मतों को जोड़ता है।
- यह 14 ईवीएम की कंट्रोल यूनिटों से जुड़ता है और बूथ-वार मत उजागर किए बिना उम्मीदवार-वार समेकित परिणाम देता है।
- चिंताओं में पारदर्शिता में कमी शामिल है, क्योंकि परिणामों का फ़ॉर्म 17C से मिलान नहीं किया जा सकता, और खराबियों का पता लगाने में कठिनाई।
- वर्तमान चुनाव कानून टोटलाइज़र के लिए कोई स्पष्ट ढाँचा प्रदान नहीं करते।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में संशोधन

संदर्भ: सितंबर 2026 में उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2026 में संशोधन किया, जिसके नए प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। यह परिवर्तन 5,11,196 ई-कॉमर्स शिकायतों के बाद किया गया, जो 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को प्राप्त शिकायतों का लगभग 29 प्रतिशत थीं। यह भ्रामक खोज परिणामों, डार्क पैटर्न और मूल्य संबंधी दावों को लक्षित करता है, तथा मूल देश का विवरण देना अनिवार्य करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की अभिसरण प्रक्रिया से जुड़ना होगा।
- NCH को 2025 में 17,71,622 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5,11,196, यानी लगभग 29%, ई-कॉमर्स से संबंधित थीं।
- प्लेटफ़ॉर्म खोज परिणामों में भ्रामक ढंग से हेरफेर नहीं कर सकते और प्रायोजित सूचियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना होगा।
- मूल्य में कमी की घोषणा करते समय घटा हुआ मूल्य और पहले का मूल्य, दोनों दिखाए जाने चाहिए।
- इकाइयों को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के दिशानिर्देश, 2023 का पालन करना, वार्षिक स्व-लेखापरीक्षा करना और अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा।
- आयातित उत्पादों पर आयातक का विवरण और मूल देश अंकित होना चाहिए।

काम का अधिकार और वीबी-जी राम जी अधिनियम

संदर्भ: मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ ने ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों के तहत न्यूनतम मज़दूरी पर एक याचिका खारिज कर दी और नई याचिका दायर करने को कहा, साथ ही यह पूछा कि क्या काम के अधिकार को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के समकक्ष होना चाहिए।

□ **मुख्य बिंदु**

- मनरेगा माँग-आधारित आधार पर ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों तक का गारंटीशुदा मज़दूरी रोज़गार प्रदान करता था।
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), या वीबी-जी राम जी, अधिनियम, 2025 अब उस ढाँचे का स्थान लेता है।
- नए अधिनियम को लेकर चिंताओं में माँग-आधारित अधिकार के संभावित कमजोर होने और राज्यों पर अधिक राजकोषीय बोझ शामिल हैं।
- अनुच्छेद 41, जो काम के अधिकार पर एक नीति निदेशक तत्व है, न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं है।

केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के नए फ़िल्म प्रमाणन दिशानिर्देश

संदर्भ: सितंबर 2026 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B(2) के अंतर्गत CBFC के लिए नए फ़िल्म प्रमाणन दिशानिर्देश अधिसूचित किए, जिन्होंने 1991 की अधिसूचना का

स्थान लिया। इनमें नशीले पदार्थ दिखाने वाले दृश्यों के लिए नशा-विरोधी चेतावनी अनिवार्य की गई है और सिनेमैटोग्राफ नियम, 2024 से आयु-आधारित चिह्नों U/A 7+, 13+ और 16+ को औपचारिक रूप से अपनाया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- नशीले पदार्थों के सेवन, उपयोग या तस्करी दिखाने वाले दृश्यों में नशा-विरोधी चेतावनी अनिवार्य रूप से देनी होगी; पहले के दिशानिर्देश केवल नशे की लत के महिमामंडन पर रोक लगाते थे।
- दिशानिर्देश सिनेमैटोग्राफ नियम, 2024 के आयु-आधारित चिह्नों को औपचारिक रूप से अपनाते हैं: U/A 7+, U/A 13+ और U/A 16+।
- अन्य श्रेणियाँ बनी रहती हैं: पारिवारिक दर्शकों के लिए U, वयस्कों के लिए A और विशिष्ट दर्शकों के लिए S।
- फ़िल्मों के शीर्षक उत्तेजक, अश्लील या आपत्तिजनक नहीं होने चाहिए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2025 के निष्कर्ष

संदर्भ: सितंबर 2026 में चर्चा में रही केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2025 भ्रष्टाचार के मामलों में अन्वेषण, अभियोजन और अंतिम न्याय-निर्णयन के बीच बड़े अंतर की ओर इशारा करती है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सीबीआई के 7,229 मामले विचारण के लिए लंबित, सीबीआई के 1,088 रिक्त पद और सीबीआई की दोषसिद्धि दर 71.71 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो 2024 में 69.14 प्रतिशत थी।

□ **मुख्य बिंदु**

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सीबीआई के 7,229 मामले विचारण के लिए लंबित हैं, जिनमें से 2,856 में 10 वर्ष से अधिक और 409 में 20 वर्ष से अधिक की देरी हुई है।
- उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 14,083 अपीलें, पुनरीक्षण और रिट याचिकाएँ लंबित हैं।
- सीबीआई में 7,300 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 1,088 पद रिक्त हैं।
- 201 मामले अभियोजन मंज़ूरी की प्रतीक्षा में हैं, और 172 अधिकारियों से संबंधित 72 संदर्भ धारा 17A के तहत अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं।
- सीबीआई की दोषसिद्धि दर 2024 के 69.14% से बढ़कर 71.71% हो गई।

गिरफ़्तारी के आधार और पुनः गिरफ़्तारी पर उच्चतम न्यायालय

संदर्भ: जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य (2026) में उच्चतम न्यायालय ने मनमानी गिरफ़्तारी के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को मज़बूत किया और ऐसे व्यक्ति की पुनः गिरफ़्तारी पर कड़े दिशानिर्देश दिए जिसे गिरफ़्तारी के आधार न बताए जाने के कारण पहले रिहा किया गया था।

□ **मुख्य बिंदु**

- अपीलकर्ता को मई 2026 में पॉक्सो अधिनियम, 2012 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत गिरफ़्तार किया गया था। उसे 24 घंटे से अधिक समय बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन था, और उसे गिरफ़्तारी के लिखित आधार नहीं दिए गए, जो अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन था।
- पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023): गिरफ़्तारी के लिखित आधार सामान्य प्रक्रिया के रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए; राम किशोर अरोड़ा (2023) ने इसे भविष्यलक्षी बना दिया।
- प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2024): अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन गिरफ़्तारी और रिमांड को दूषित कर देता है, और बाद का आरोप-पत्र इसे ठीक नहीं कर सकता।
- विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025): आधार सार्थक रूप से बताए जाने चाहिए, अन्यथा अनुच्छेद 21 और 22(1) का उल्लंघन होता है।
- मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025): सभी अपराधों के लिए लिखित आधार उस भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे गिरफ़्तार व्यक्ति समझता हो।
- मजिस्ट्रेट ने गिरफ़्तारी को अवैध घोषित कर रिहाई का आदेश दिया, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एजेंसी को पुनः गिरफ़्तारी की माँग करने की अनुमति दे दी।

ग्राम सभा की सहमति और वन मंज़ूरी विवाद

संदर्भ: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय को बताया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वन मंज़ूरी के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब विद्युत मंत्रालय और एनएचपीसी ने ग्राम सभा की सहमति को अवसंरचना परियोजनाओं में बाधा बताया।

□ **मुख्य बिंदु**

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वनवासी समुदायों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था। यह अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि और संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
- यह ग्राम सभा को वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का प्राथमिक प्राधिकारी बनाता है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

□ **न्यायिक पहलू**

- ओडिशा खनन निगम बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (नियमगिरि वाद, 2013) में उच्चतम न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के तहत

धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक अधिकारों का निर्णय करने में ग्राम सभा की भूमिका को मान्यता दी।

➤ निर्णय में कहा गया कि विकास परियोजनाएँ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकतीं।

जनगणना 2027: जाति गणना के साथ भारत की पहली डिजिटल जनगणना

संदर्भ: भारत की 16वीं जनगणना, जनगणना 2027, देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है और 1931 के बाद देशभर में सभी समुदायों की जाति की गणना करने वाली पहली जनगणना है। शुभंकर प्रगति (महिला) और विकास (पुरुष) का अनावरण किया गया, और सी-डैक द्वारा विकसित चार डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट-लॉन्च किया गया।

□ मुख्य बिंदु

➤ भारत की पहली समकालिक जनगणना 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के अधीन की गई थी। जनगणना संघ सूची का विषय है, जो जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित है और 1971 से दो चरणों में कराई जाती है।

➤ जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 व्यक्तिगत अभिलेखों को निरीक्षण और साक्ष्य के रूप में उपयोग से संरक्षण देती है।

□ चरण और दायरा

➤ मकान सूचीकरण चरण, जो पहला चरण है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आयोजित होगा।

➤ जनसंख्या गणना, जो दूसरा चरण है, फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है।

➤ स्वतंत्र भारत में पहली बार देशभर में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ही नहीं, बल्कि सभी समुदायों की जातियों की गणना की जाएगी।

➤ यह 2011 के बाद की पहली जनगणना है, क्योंकि 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई थी।

➤ जनसंख्या गणना चरण में 2011 के 29 प्रश्नों की तुलना में 40 प्रश्न हैं; माता-पिता का विवरण, राष्ट्रीयता और स्थायी पते से संबंधित नए प्रश्न राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्षेत्रों से मिलते-जुलते हैं और निजता तथा एनआरसी से जुड़ाव संबंधी चिंताएँ उठाते हैं।

□ डिजिटल उपकरण

➤ मकान सूचीकरण ब्लॉक निर्माता (HLBC) वेब एप्लिकेशन मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करता है।

➤ HLO मोबाइल एप्लिकेशन गणनाकारों के लिए एक ऑफ़लाइन ऐप है, जो एंड्रॉइड और आईओएस पर चलता है तथा 16 क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता करता है।

➤ स्व-गणना (SE) पोर्टल पहली बार ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा देता है और सत्यापन के लिए एक SE आईडी तैयार करता है।

➤ जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल उप-जिला, जिला और राज्य स्तर पर संचालन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है।

➤ सेवा के रूप में जनगणना (CaaS) मंत्रालयों को साक्ष्य-आधारित नीति नियोजन के लिए एक स्वच्छ, मशीन-पठनीय और खोजने योग्य डेटाबेस उपलब्ध कराएगी।

➤ दोनों शुभंकर गणनाकारों को दर्शाते हैं और महिलाओं तथा पुरुषों की समान भागीदारी के प्रतीक हैं।

नाबालिगों के सोशल मीडिया खाते और संविदात्मक क्षमता

संदर्भ: मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से जवाब माँगा, जिसमें नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया के स्वतंत्र उपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की माँग की गई है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ फ़ायरवॉल आवश्यक हैं।

□ मुख्य बिंदु

➤ भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है।

➤ प्लेटफ़ॉर्म प्रायः बच्चों को, कभी-कभी 13 वर्ष की आयु से ही, सेवा की शर्तें स्वीकार कर खाता खोलने की अनुमति दे देते हैं।

➤ प्लेटफ़ॉर्मों द्वारा प्रयुक्त 13 वर्ष की सीमा मुख्यतः विदेशी मानकों पर आधारित है, यह भारत की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

➤ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 10A इलेक्ट्रॉनिक संविदाओं को मान्यता देती है, किंतु जो व्यक्ति अन्यथा अक्षम हैं उन्हें संविदा की क्षमता प्रदान नहीं करती।

➤ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 बच्चों के डेटा के प्रसंस्करण के लिए सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करता है, किंतु नाबालिगों के खाता बनाने पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाता।

➤ सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 आयु सत्यापन या अभिभावकीय प्रमाणीकरण को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते।

निर्वाचन आयोग (ECI) के समक्ष TMC के नाम और चुनाव चिह्न का विवाद

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह ममता बनर्जी और प्रतिद्वंद्वी नेता ऋतब्रत बनर्जी के बीच नेतृत्व विवाद का निपटारा अभिवचन पूर्ण होने के तीन महीने के भीतर करे, तथा पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया।

□ **मुख्य बिंदु**

- अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में फूट के कारण नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनावों से पहले पार्टी के नाम और फूल-घास चुनाव चिह्न पर प्रतिद्वंद्वी दावे सामने आए।
- निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के अंतर्गत ECI ने नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज़ कर दिया और गुटों को वैकल्पिक नाम व चिह्न दिए।
- ECI सांगठनिक समर्थन तथा निर्वाचित सांसदों और विधायकों में संख्या-बल की जाँच करता है; बहुमत ही एकमात्र कसौटी नहीं है।
- 1997 के संशोधन के बाद, पराजित गुट को सामान्यतः एक अलग दल के रूप में पंजीकरण कराना पड़ता है।
- पहले के मामलों में शिवसेना का चुनाव चिह्न फ्रीज़ किया जाना, NCP का नाम और घड़ी चिह्न अजीत पवार गुट को मिलना, तथा अन्नाद्रमुक (AIADMK) का दो पत्तियों वाला विवाद शामिल हैं।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और चंदा

संदर्भ: एक मीडिया जाँच में पाया गया कि गुजरात स्थित छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 2023-24 में लगभग ₹1,700 करोड़ का चंदा मिला, जो भाजपा को छोड़कर पाँच राष्ट्रीय दलों को मिले ₹1,480 करोड़ से अधिक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A निर्वाचन आयोग के पास दलों के पंजीकरण का प्रावधान करती है।
- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वार्षिक ₹20,000 से अधिक देने वाले दाताओं का खुलासा करना होता है और ₹2,000 से अधिक का चंदा बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त करना होता है।
- 2,800 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल लगभग 750 ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा।
- निर्वाचन आयोग सामान्यतः दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल वेलफेयर (2002) ने पंजीकरण रद्द करने को धोखाधड़ी जैसे मामलों तक सीमित कर दिया।
- विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट ने निर्वाचन आयोग को पंजीकरण रद्द करने की शक्तियाँ देने की सिफारिश की।

मणिपुर की 1951 को आधार वर्ष मानकर एनआरसी की माँग

संदर्भ: मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार की मंज़ूरी के अधीन, 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन करने का प्रस्ताव दिया है। यह माँग 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार से आमद, 2023 से जारी जातीय संघर्ष और आगामी जनगणना तथा परिसीमन को लेकर चिंताओं से प्रेरित है।

□ **मुख्य बिंदु**

- राज्य के अनुसार सीमावर्ती जिलों में 24,475 अवैध प्रवासियों का पता चला, जिनमें से 14,992 को राजनयिक माध्यमों से वापस म्यांमार भेजा गया।
- एनआरसी भारतीय नागरिकों का रजिस्टर है; नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2003 के तहत केंद्र राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आँकड़ों का उपयोग करके इसका आदेश दे सकता है।
- बाहरी लोगों के लिए मणिपुर की पारंपरिक परमिट प्रणाली 18 नवंबर 1950 को समाप्त कर दी गई थी, जिसका हवाला समर्थक 1951 को चुनने के लिए देते हैं।
- 1980 का एक समझौता-ज्ञापन, नवंबर 1994 का एक समझौता और मणिपुर जन संरक्षण विधेयक, 2018 भी 1951 को आधार वर्ष मानते हैं।
- मणिपुर ने 2022 में इनर लाइन परमिट ढाँचे के लिए 1961 को आधार वर्ष अपनाया, जो आधार वर्ष की विवादित प्रकृति को दर्शाता है।

मातृत्व अवकाश और कार्य-भूमिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय

संदर्भ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला सामान्यतः अपने पूर्व पद पर लौटने की हकदार है और उसे ज़िम्मेदारियों, प्रबंधकीय अधिकार या करियर संभावनाओं में नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता।

□ **मुख्य बिंदु**

- याचिकाकर्ता राखी बिष्ट, जो हैशीकॉर्प में लेखा प्रबंधक थीं, को जुलाई 2024 में लौटने पर एक अलग ट्रेज़री भूमिका में भेज दिया गया था।
- यदि पूर्व पद वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो वेतन, ग्रेड, प्रस्थिति और अधिकार में सारतः समतुल्य पद दिया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने ₹10 लाख मुआवज़ा तथा ₹1.5 लाख कानूनी खर्च प्रदान किया।
- इसने मातृत्व संरक्षण को अनुच्छेद 14, 15, 21 और 42 से जोड़ा।

मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन दस्तावेज 2026-29 और नशा मुक्त भारत

संदर्भ: जून 2026 में नई दिल्ली में हुई 10वीं शीर्ष-स्तरीय NCORD बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन दस्तावेज (2026-2029) और NCB वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रोडमैप का उद्देश्य नेटवर्क-केंद्रित रणनीति और मापनीय समय-सीमाओं के साथ 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाना है।

□ **विजन दस्तावेज 2026-2029**

- लक्ष्य हैं माँग में कमी, आपूर्ति में कमी और पुनर्वास, जिनका सिद्धांत है पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो।
- ध्यान वाहकों से हटकर नेटवर्क को ध्वस्त करने पर केंद्रित हो गया है, जिसके साथ 100 प्रमुख अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कार्टेलों को तोड़ने का अभियान है।
- प्रवर्तन, खुफिया और अभियान: नेटवर्क-लक्षित प्रवर्तन, मार्च 2029 तक सभी प्रमुख समुद्री बंदरगाहों पर कंटेनर स्कैनर और मार्च 2027 तक हवाई अड्डों पर AI/ML आधारित यात्री प्रोफाइलिंग।
- पूर्ववर्ती रसायनों और सिंथेटिक मादक पदार्थों का नियंत्रण: पूर्ववर्ती रसायनों के विपथन को रोकने और गुप्त प्रयोगशालाओं को ध्वस्त करने के लिए राष्ट्रीय ढाँचा।
- माँग में कमी और पुनर्वास: नशा मुक्त भारत अभियान द्वारा 50 करोड़ नागरिकों तक पहुँचना और मार्च 2029 तक 10 लाख विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता फैलाना।
- क्षमता निर्माण और समन्वय: राज्य मादक पदार्थ-निरोधक कार्य बलों के लिए नई शत-प्रतिशत केंद्र-वित्तपोषित योजना।
- NCB एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है; मानस 24x7 हेल्पलाइन 1933 संचालित करता है।

□ **NCB वार्षिक रिपोर्ट 2025**

- इसमें 1.48 लाख से अधिक मामले और 1,200 टन से अधिक मादक पदार्थों की जब्ती दर्ज है।
- म्यांमार ने अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर अवैध अफीम का प्रमुख स्रोत बनने का स्थान ले लिया है।

□ **उपलब्धियाँ (2019 से जुलाई 2026)**

- 93,33,987 किलोग्राम मादक और मनोदैहिक पदार्थ जब्त किए गए, जिनका मूल्य ₹1,53,212 करोड़ है।
- ₹3,992 करोड़ मूल्य की अवैध संपत्तियाँ जब्त या कुर्क की गईं और 128 गुप्त प्रयोगशालाएँ ध्वस्त की गईं।
- भारतपोल 195 देशों के साथ इंटरपोल से सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है।
- मानस हेल्पलाइन (1933) ने 3.33 लाख से अधिक नागरिकों से संपर्क किया है।

लद्दाख: पर्वतीय परिषदें और प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K)

संदर्भ: 2026 में पाँच नए जिले बनाए जाने के बाद लद्दाख प्रशासन सभी सात जिलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें बनाने की योजना बना रहा है, जबकि छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की माँगें जारी हैं। अलग से, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ वार्ता के बाद केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 371(K), का प्रस्ताव किया है।

□ **पर्वतीय परिषदें**

- अब तक केवल लेह और कारगिल में पर्वतीय परिषदें थीं।
- परिषदों का प्रस्ताव लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1997 की धारा 3(1) के अंतर्गत किया गया है, जिसे 1 जून 1995 से लागू माना जाता है।
- क्रियान्वयन से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अधिनियम में संशोधन आवश्यक हैं।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बना।
- लद्दाख की पर्वतीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, जिनके कार्य मुख्यतः प्रशासनिक और विकासात्मक हैं तथा वे केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधीन कार्य करती हैं।
- छठी अनुसूची की परिषदें अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत संवैधानिक निकाय हैं, जिन्हें विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।

□ **प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K)**

- अनुच्छेद 371 और 371A-371J भाग XXI में हैं, जो विशिष्ट राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है।
- प्रस्तावित प्रावधान एक विशिष्ट (sui generis) ढाँचा है, जो केंद्र शासित प्रदेश स्तर के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय का प्रावधान करता है।
- इसमें भूमि, संस्कृति और भाषा, वन, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर विधायी शक्तियों का प्रस्ताव है, जिनमें अनुच्छेद 240 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित विषय भी शामिल हैं।
- कार्यकारी, वित्तीय, नियोजन, पुलिस और कानून-व्यवस्था की शक्तियों पर अभी भी वार्ता चल रही है।
- यह प्रस्ताव राज्य का दर्जा या छठी अनुसूची का दर्जा देने की माँगों को सीधे संबोधित नहीं करता।

□ **नौतोड़ नियमितीकरण नियम, 2026**

- ये नियम पात्र बंजर भूमि पर भूमिधारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं।
- इनका उद्देश्य हजारों भूमिधारकों को प्रभावित करने वाली एक लंबे समय से लंबित भूमि समस्या का समाधान करना और संस्थागत ऋण तक पहुँच सक्षम बनाना है।

शुद्धिकरण अनुष्ठान और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता

संदर्भ: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करने के दो दिन बाद वहाँ आयोजित एक शुद्धिकरण अनुष्ठान ने कानूनी बहस को फिर से जगा दिया है। प्रश्न यह है कि क्या किसी दलित व्यक्ति के उपयोग के बाद किसी स्थान को शुद्ध करना अस्पृश्यता की श्रेणी में आता है। न्यायालयों ने कहा है कि इसका उत्तर इस

पर निर्भर करता है कि कार्य जाति-आधारित शुचिता और अपवित्रता की धारणाओं पर आधारित है या नहीं।

□ **मुख्य बिंदु**

- सूर्य नारायण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य (1988): राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा में प्रवेश से पहले दलित भक्तों के शुद्धिकरण पर रोक लगा दी, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन था।
- हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का हर अपमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(r) को आकर्षित नहीं करता; अपमान का संबंध पीड़ित की जातिगत पहचान से होना चाहिए।
- सुकन्या शांता बनाम भारत संघ (2024): उच्चतम न्यायालय ने अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था तथा शुचिता और अपवित्रता की धारणाओं से जोड़ा, और कहा कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व, स्पर्श या उपस्थिति पर कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता।
- गुंजन उर्फ़ गिरिजा कुमारी बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2026): उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध के लिए स्थान सार्वजनिक दृष्टि के भीतर होना चाहिए।

□ **कानूनी परीक्षण**

- मुख्य परीक्षण आचरण और जाति-आधारित शुचिता तथा अपवित्रता की धारणाओं के बीच संबंध है।
- अस्पृश्यता अधिक स्पष्ट रूप से तब सिद्ध होती है जब किसी व्यक्ति के स्पर्श या उपस्थिति को जाति के कारण अपवित्र माना जाता है।
- यह तब भी सिद्ध होती है जब किसी दलित व्यक्ति पर ऐसी जाति-विशिष्ट निर्योग्यता या शर्त लगाई जाती है जो दूसरों पर नहीं लगाई जाती।
- मात्र अपमान स्वतः अस्पृश्यता नहीं है; जाति या अस्पृश्यता से संबंध होना आवश्यक है।

हिंदी दिवस और मुंशी-अयंगर फ़ॉर्मूला

संदर्भ: हिंदी दिवस, जो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, संघ की राजभाषा पर मुंशी-अयंगर फ़ॉर्मूले को 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने का स्मरण कराता है, जो के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अयंगर से जुड़ा है। इसने देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा बनाया, जबकि अंग्रेज़ी 15 वर्ष तक जारी रही। ये प्रावधान भाग XVII के अनुच्छेद 343-351 में हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह फ़ॉर्मूला के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अयंगर से जुड़ा है।
- देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है, तथा आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी 15 वर्ष तक जारी रही।
- अन्य भारतीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची के माध्यम से मान्यता दी गई है, तथा आधिकारिक प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है।
- ये प्रावधान भाग XVII के अंतर्गत अनुच्छेद 343-351 में हैं।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 ने 1965 में 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी अंग्रेज़ी को हिंदी के साथ जारी रखने की अनुमति दी।
- आर.वी. धुलेकर ने हिंदी या हिंदुस्तानी का समर्थन किया, जबकि नेहरू और मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ी को तत्काल हटाने की कठिनाई की ओर संकेत किया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

समसामयिक नोट्स

2026 के लिए UNSC सदस्य और IMO परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन

संदर्भ: पाँच नए अस्थायी सदस्यों ने 1 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना दो वर्ष का कार्यकाल शुरू किया, जबकि भारत नवंबर 2025 में श्रेणी ख में 2026-27 के लिए IMO परिषद में पुनः निर्वाचित हुआ। बहरीन, कोलंबिया, डीआर कांगो, लातविया और लाइबेरिया ने अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लिया। श्रेणी ख में समुद्री व्यापार में सबसे अधिक हित रखने वाले 10 राष्ट्र आते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- भारत 28 नवंबर 2025 को श्रेणी ख में 2026-27 के लिए IMO परिषद में पुनः निर्वाचित हुआ।
- श्रेणी ख में अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक हित रखने वाले 10 राष्ट्र आते हैं।

□ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- बहरीन, कोलंबिया, डीआर कांगो, लातविया और लाइबेरिया ने 1 जनवरी 2026 को दो वर्ष का अस्थायी कार्यकाल शुरू किया।
- उन्होंने अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लिया।
- 2026 के अंत तक जारी रहने वाले सदस्य: डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की वापसी

संदर्भ: जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वित्तीय बोझ, संप्रभुता और 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण का हवाला देते हुए 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में भागीदारी और वित्तपोषण समाप्त कर दिया गया। सूची में UNFCCC, IPCC, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, IRENA, WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शामिल हैं, और पेरिस समझौते से दूसरी बार औपचारिक निकासी की घोषणा की गई। यह वैश्विक शासन और जलवायु सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है।

□ मुख्य बिंदु

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी 2026 में दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से अपनी औपचारिक निकासी की घोषणा की, और वापसी में UNFCCC, IPCC, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, IRENA और IUCN शामिल हैं।
- प्रभावित स्वास्थ्य और लैंगिक निकायों में WHO (और गावी), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और यूएन वीमेन शामिल हैं।
- प्रभावित शांति और विकास निकायों में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, शांति निर्माण आयोग और कोष, UNCTAD, UNRWA और UNESCO शामिल हैं, जिनसे अमेरिका पहले 1984 और 2017 में हट चुका था।
- USAID, जो अब भंग हो चुकी है, का 2024 में बजट 44.2 अरब डॉलर था, जो उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा दर्ज की गई कुल मानवीय सहायता का लगभग 42 प्रतिशत था।

अमेरिका और नाटो के बीच ग्रीनलैंड विवाद

संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीनलैंड से जुड़ी अपनी टैरिफ धमकी वापस ले ली और कहा कि उसने और नाटो ने भविष्य की व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा विकसित की है, जिससे उस विवाद में कमी आई जिसने अटलांटिक-पार गठबंधन में तनाव पैदा कर दिया था।

□ मुख्य बिंदु

- ग्रीनलैंड GIUK गैप (ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूनाइटेड किंगडम) के केंद्र में स्थित है, जो उत्तरी अटलांटिक में पनडुब्बियों पर नज़र रखने के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है।
- यहाँ पिटुफिक स्पेस बेस है, जो अमेरिकी पूर्व-चेतावनी रडार नेटवर्क से जुड़ा है, और प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े अप्रयुक्त दुर्लभ मृदा भंडार हैं, जिनमें क्वानेफ्येल्ड (जहाँ यूरेनियम भी है) और दक्षिण ग्रीनलैंड में क्रिंगलर्ने शामिल हैं।
- डेनमार्क ने संकेत दिया कि वह नाटो का अनुच्छेद 5 लागू कर सकता है, और उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है।
- फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके और डेनमार्क के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया कि क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं से समझौता नहीं किया जा सकता।

तृतीय पथ सिद्धांत और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026

संदर्भ: विश्व आर्थिक मंच 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने मध्यम शक्तियों के लिए 'तृतीय पथ' (कार्नी सिद्धांत) की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 ने भू-आर्थिक टकराव को सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम बताया।

□ **मुख्य बिंदु**

- तृतीय पथ मूल्य-आधारित यथार्थवाद, आधिपत्यवादी शक्तियों के विरुद्ध मध्यम शक्तियों के बीच सहयोग, और परिवर्तनशील ज्यामिति पर आधारित है, जिसका अर्थ है अलग-अलग मुद्दों के लिए अलग-अलग गठबंधन।
- मध्यम शक्तियों में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील शामिल हैं।
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 भू-आर्थिक टकराव, राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष, चरम मौसमी घटनाओं और सामाजिक ध्रुवीकरण को निकट अवधि के शीर्ष जोखिमों के रूप में चिह्नित करती है।
- 2036 तक के 10-वर्षीय परिदृश्य के लिए प्रमुख जोखिम चरम मौसम, जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन हैं।
- भारत के लिए मुख्य जोखिम साइबर असुरक्षा, संपत्ति और आय असमानता, तथा अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा हैं।

दिल्ली में उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक जारी

संदर्भ: उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक (RNI), जो देशों को उनकी शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर रैंक देता है कि वे अपने लोगों, पृथ्वी और वैश्विक समुदाय के प्रति कितनी उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- RNI को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और IIM मुंबई के साथ मिलकर विकसित किया है।
- यह 58 संकेतकों के आधार पर 154 देशों का मूल्यांकन करता है, जिन्हें 13 उप-विषयों और 7 विषयों में समूहीकृत किया गया है, और ये मिलकर 3 मुख्य आयाम बनाते हैं।
- सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क रहे; शीर्ष 10 में यूरोपीय देशों का दबदबा रहा।
- भारत वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर रहा और सिंगापुर के अलावा सर्वोच्च स्थान पाने वाला प्रमुख एशियाई देश था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका 66वें और चीन 68वें स्थान पर रहे, जो आर्थिक या सैन्य शक्ति और उत्तरदायित्व के बीच अंतर को दर्शाता है।

भारत का मुक्त व्यापार समझौता नेटवर्क

संदर्भ: न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न होने के साथ, भारत के पास अब चीन को छोड़कर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के सभी देशों के साथ व्यापार समझौते हैं। यह व्यापार में विविधता लाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए आक्रामक द्विपक्षीय प्रयास का हिस्सा है।

□ **मुख्य बिंदु**

- RCEP में आसियान के सदस्य और उनके FTA साझेदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं।
- दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत-ओमान CEPA, ओमान को भारत के 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर शुल्क हटाता है और 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।
- ओमान समझौता भारतीय पेशेवरों को लंबे समय तक रहने की अनुमति देता है और प्रमुख सेवा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति देता है।
- भारत-यूके CETA पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए और यह भारत के 99 प्रतिशत निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।
- घरेलू किसानों की रक्षा के लिए डेयरी को यूरोपीय संघ और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए समझौतों से बाहर रखा गया।

भारत के हालिया व्यापार समझौते

समझौता	स्थिति / तिथि
भारत-यूएई CEPA	2022 से लागू
भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA	दिसंबर 2022 से प्रभावी
भारत-EFTA TEPA	मार्च 2024 में हस्ताक्षर
भारत-यूके CETA	जुलाई 2025 में हस्ताक्षर
भारत-ओमान CEPA	दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर
भारत-न्यूज़ीलैंड FTA	दिसंबर 2025 में वार्ता संपन्न
भारत-यूरोपीय संघ FTA	जनवरी 2026 में संपन्न

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न

संदर्भ: भारत और यूरोपीय संघ ने भारत में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के समापन की घोषणा की, जिसे 'सभी समझौतों की जननी' कहा गया। यूरोपीय संघ भारत का 22वाँ FTA साझेदार बन गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारत और यूरोपीय संघ क्रमशः चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो मिलकर वैश्विक GDP का 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा हैं। 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार ₹11.5 लाख करोड़ था, जिसमें निर्यात ₹6.4 लाख करोड़ और आयात ₹5.1 लाख करोड़ था।
- वार्ता 2007 में शुरू हुई, 2013 में स्थगित हुई और 2022 में फिर शुरू हुई।
- पाठों की विधिक समीक्षा और अनुवाद होगा, फिर लागू होने से पहले उन्हें यूरोपीय परिषद की मंजूरी और यूरोपीय संसद की सहमति, तथा भारत द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- भारत को 97 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर यूरोपीय बाज़ारों में तरजीही पहुँच मिलती है, जो व्यापार मूल्य के 99.5 प्रतिशत को कवर करती है।

- 70.4 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर, जो भारत के 90.7 प्रतिशत निर्यात को कवर करती हैं, शुल्क तुरंत हटा दिए जाएँगे, जिससे वस्त्र, चमड़ा और जूते-चप्पल को लाभ होगा।
- भारत अपनी 92.1 प्रतिशत टैरिफ लाइनें प्रदान करता है, जो यूरोपीय संघ के 97.5 प्रतिशत निर्यात को कवर करती हैं, और इनमें से 49.6 प्रतिशत लाइनों पर शुल्क तुरंत समाप्त होगा।
- यूरोपीय संघ ने 144 सेवा उप-क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबद्धताएँ की हैं, जिनमें IT/ITES और व्यावसायिक सेवाएँ शामिल हैं।
- एक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर भी हस्ताक्षर हुए, जो जापान और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया में यूरोपीय संघ की तीसरी ऐसी साझेदारी है।
- यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र भारतीय निर्यातकों पर अनुपालन लागत के रूप में प्रति वर्ष ₹17,000 से ₹34,000 करोड़ का बोझ डाल सकता है।
- यूरोपीय संघ ने भारत को GDPR के तहत 'डेटा सुरक्षित' का दर्जा नहीं दिया है, जिससे भारतीय डिजिटल कंपनियों की अनुपालन लागत बढ़ती है।
- यूरोपीय संघ की परिषद और आयोग के अध्यक्ष भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे।
- यूरोपीय संघ 27 सदस्यों का एक अनूठा आर्थिक और राजनीतिक संघ है, जो एकल बाज़ार के रूप में कार्य करता है।
- इसकी शुरुआत 1951 में छह देशों के साथ हुई: बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड।
- यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ दिया।
- 1999 में शुरू की गई यूरो, यूरोपीय संघ के 21 देशों की आधिकारिक मुद्रा है।
- यूरोपीय आयोग की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है।

भारत-विश्व बैंक देश साझेदारी ढाँचा 2026-31

संदर्भ: जनवरी 2026 में भारत और विश्व बैंक ने 2026-2031 के लिए नए देश साझेदारी ढाँचे (NCPF) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को 8-10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है। यह निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले रोज़गार सृजन, ग्रामीण समृद्धि, शहरी परिवर्तन, लोगों में निवेश, और जलवायु लचीलेपन के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित है।

□ मुख्य बिंदु

- यह ढाँचा कौशल सुधार, लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के लिए बाधाएँ कम करने और युवाओं तथा महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने के माध्यम से निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले रोज़गार सृजन पर केंद्रित है।
- रणनीतिक लक्ष्य एक है कृषि से परे आय के अवसर पैदा करके ग्रामीण समृद्धि और लचीलेपन को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य दो है शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना, क्योंकि भारत की शहरी जनसंख्या 2050 तक 80 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- लक्ष्य तीन है लोगों में निवेश करना, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल पर ध्यान दिया गया है।
- लक्ष्य चार है ऊर्जा सुरक्षा, मूल अवसंरचना और जलवायु लचीलेपन को मज़बूत करना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी शामिल हैं।

यूएई, जर्मनी और वाइमर त्रिकोण के साथ भारत की भागीदारी

संदर्भ: यूएई के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर की भारत यात्राओं तथा वाइमर त्रिकोण में भारत की पहली भागीदारी से व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा में सहयोग का विस्तार हुआ।

□ मुख्य बिंदु

- जर्मनी और भारत ने रक्षा औद्योगिक रोडमैप पर संयुक्त आशय घोषणा तथा विदेश और सुरक्षा नीति पर 'ट्रैक 1.5' संवाद पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-मुक्त पारगमन और अर्धचालक तथा महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौतों की घोषणा की।
- भारत और यूएई 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से भी अधिक, 200 अरब डॉलर से ऊपर ले जाने पर सहमत हुए।
- वे SHANTI अधिनियम, 2025 के बाद छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और परमाणु सुरक्षा में साझेदारी की संभावनाएँ तलाशेंगे।
- एक डिजिटल या डेटा दूतावास स्थापित किया जाएगा और इंडियाएआई मिशन के तहत सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर पर सहयोग पर सहमति बनी।
- ADNOC गैस ने HPCL को 0.5 MTPA LNG की आपूर्ति के लिए 10 वर्ष के बिक्री और क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 2022 में हस्ताक्षरित भारत-यूएई CEPA ने 2024-25 में व्यापार को लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने में मदद की, और यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
- इस यात्रा ने सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष (2025) और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष (2026) को चिह्नित किया।
- द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 50 अरब डॉलर को पार कर गया, और 2024 तक के आँकड़ों के अनुसार जर्मनी भारत में FDI का नौवाँ सबसे बड़ा स्रोत था।
- वाइमर त्रिकोण फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय समूह है, जिसका गठन 1991 में जर्मनी के वाइमर में हुआ था।
- वाइमर त्रिकोण यूरोपीय एकीकरण, राजनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है।

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र शुरू

संदर्भ: यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), शुरू किया, जिससे 2023 से

चला संक्रमणकालीन चरण समाप्त हुआ और कार्बन-गहन वस्तुओं के आयात पर कार्बन शुल्क लगाया गया। इसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना है और यह सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, लोहा और इस्पात, हाइड्रोजन तथा बिजली को कवर करता है, इसलिए भारतीय इस्पात, एल्युमीनियम और सीमेंट निर्यात को अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- CBAM कम सख्त जलवायु नीतियों वाले देशों से आयात पर कर लगाता है; यह 2023 से संक्रमणकालीन चरण में चल रहा था।
- इसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना है, जिसमें कंपनियाँ उत्पादन को कमजोर जलवायु नियमों वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं।
- कवर किए गए क्षेत्र सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, लोहा और इस्पात, हाइड्रोजन तथा बिजली हैं।
- यूरोपीय संघ को भारत के इस्पात, एल्युमीनियम और सीमेंट निर्यात को अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है।

वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले: ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व

संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' के तहत काराकास और आसपास के क्षेत्रों पर हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में व्यापक आलोचना हुई और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी आधिपत्य पर बहस फिर से शुरू हो गई।

□ **मुख्य बिंदु**

- मुनरो सिद्धांत की घोषणा 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने की थी और यह गैर-उपनिवेशीकरण, यूरोपीय अहस्तक्षेप तथा यूरोप में अमेरिकी अहस्तक्षेप पर आधारित था। 'डोनरो सिद्धांत', जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है और जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 से जुड़ा है, अमेरिकी महाद्वीपों में अमेरिकी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का एक अनौपचारिक नाम है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गहरी चिंता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पूर्ण सम्मान पर बल दिया, तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस दावे को खारिज कर दिया कि मानवाधिकार उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए यह छापा आवश्यक था।
- रूस, चीन, कोलंबिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, चिली, पनामा और क्यूबा ने इस कार्रवाई की आलोचना की, जबकि अर्जेंटीना, पैराग्वे और इज़राइल ने इसकी सराहना की।
- भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की, संप्रभुता और अहस्तक्षेप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और शांतिपूर्ण संवाद तथा कूटनीति का आह्वान किया।
- अमेरिका द्वारा बताए गए कारण मादक पदार्थ तस्करी, नार्को-आतंकवाद और संगठित अपराध थे, तथा यह दावा था कि 2024 के विवादित चुनाव के बाद वेनेज़ुएला के नेता वैध नहीं थे।
- वेनेज़ुएला के पास दुनिया के लगभग 17 प्रतिशत कच्चे तेल के भंडार हैं, जो किसी भी देश के भंडारों में सबसे बड़े हैं, और ये ज़्यादातर ओरिनोको बेल्ट में हैं।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) राज्यों को बल प्रयोग से बचने के लिए बाध्य करता है, आत्मरक्षा जैसे मामलों को छोड़कर।
- अहस्तक्षेप और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित गुजराल सिद्धांत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक आदर्श के रूप में उद्धृत किया जाता है।

वैश्विक न्यूनतम कर पर OECD साइड-बाय-साइड पैकेज

संदर्भ: जनवरी 2026 में आधार क्षरण और लाभ अंतरण पर OECD/G20 समावेशी ढाँचे ने वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्थाओं के कार्य में समन्वय के लिए एक 'साइड-बाय-साइड' पैकेज पर सहमति जताई। वैश्विक न्यूनतम कर GloBE मॉडल नियमों पर आधारित है और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रत्येक क्षेत्राधिकार में न्यूनतम स्तर का कर दिलवाता है, जिससे लाभ अंतरण हतोत्साहित होता है। पैकेज में सरलीकरण उपाय और सेफ हार्बर शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- वैश्विक न्यूनतम कर वैश्विक आधार क्षरण-रोधी (GloBE) मॉडल नियमों पर आधारित है।
- यह बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों से प्रत्येक उस क्षेत्राधिकार में, जहाँ वे कार्य करते हैं, आय पर न्यूनतम स्तर का कर दिलवाता है, जिससे लाभ अंतरण और कॉर्पोरेट कर दरें घटाने की होड़ हतोत्साहित होती है।
- BEPS बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उस कर योजना को कहते हैं जो राष्ट्रीय कर नियमों के बीच की कमियों का फायदा उठाकर लाभ को कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करती है, जैसे कटौती योग्य ब्याज या रॉयल्टी भुगतान के माध्यम से।

□ **पैकेज के पाँच घटक**

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कर प्राधिकरणों के लिए अनुपालन का बोझ कम करने हेतु सरलीकरण उपाय।
- कर प्रोत्साहनों के वैश्विक व्यवहार को समान बनाने के लिए सार-आधारित कर प्रोत्साहन सेफ हार्बर।
- उन पात्र बहुराष्ट्रीय समूहों के लिए सेफ हार्बर, जिनकी मूल इकाइयाँ न्यूनतम कर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पात्र क्षेत्राधिकारों में हैं।
- समावेशी ढाँचे के सभी सदस्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य-आधारित समीक्षा प्रक्रिया।
- पात्र घरेलू न्यूनतम टॉप-अप करों की मज़बूत सुरक्षा, विशेषकर विकासशील देशों के कर आधार के लिए।

AI इम्पैक्ट समिट 2026 और नई दिल्ली घोषणा

संदर्भ: नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट ने AI पर स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी नई दिल्ली घोषणा प्रस्तुत की, जिसे 88 देशों और संगठनों ने अपनाया। भारत वहाँ अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में भी शामिल हुआ।

□ मुख्य बिंदु

- स्विट्ज़रलैंड 2027 के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जिनेवा में करेगा।
- बनाए गए मंचों में ग्लोबल AI इम्पैक्ट कॉमन्स, ट्रस्टेड AI कॉमन्स और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान के लिए AI नेटवर्क शामिल हैं।
- कुल प्रतिबद्धताएँ 250 अरब डॉलर की हैं, जिनमें डीप-टेक अनुसंधान के लिए 20 अरब डॉलर शामिल हैं।
- सर्वम AI ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से प्रशिक्षित बहु-अरब पैरामीटर वाले LLM लॉन्च किए।
- रिलायंस ने सात वर्षों में AI अवसंरचना के लिए ₹10 लाख करोड़ की घोषणा की।
- नई दिल्ली फ्रंटियर AI इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई।
- सर्वम AI ने दो LLM लॉन्च किए, ज्ञानी.ai ने वाचना टेक्स्ट-टू-स्पीच लॉन्च किया, और भारतजेन ने पैरम2 17B जारी किया, जो एक मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स मॉडल है।
- शिखर सम्मेलन में भारत जीआई (Bharat GI) का भी अनावरण किया गया।
- यह ब्लेचली पार्क (2023), सियोल (2024) और पेरिस (2025) के शिखर सम्मेलनों की कड़ी में आया।
- शिखर सम्मेलन सात चक्रों और तीन सूत्रों पर आधारित था।
- भारत का M.A.N.A.V. ढाँचा: नैतिक और आचारगत प्रणाली (Moral and ethical system), जवाबदेह शासन (Accountable governance), राष्ट्रीय संप्रभुता (National sovereignty), सुलभ और समावेशी AI (Accessible and inclusive AI), वैध और विधिसम्मत प्रणालियाँ (Valid and legitimate systems)।
- AI इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय से निर्देशित है।
- सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशानिर्देश संशोधन नियम, 2026 कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री को विनियमित करते हैं।

□ शिखर सम्मेलनों की परंपरा

- 2023 ब्लेचली पार्क (ब्रिटेन), 2024 सियोल, 2025 पेरिस, 2026 नई दिल्ली।
- पैक्स सिलिका ने दिसंबर 2025 में अपना उद्घाटन शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

BNP की जीत और भारत-बांग्लादेश संबंध

संदर्भ: तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद फरवरी 2026 में हुए बांग्लादेश के चुनावों में निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और हसीना भारत में हैं। यह परिणाम भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि BNP काल (2001-2006) के संबंध उग्रवादी समूहों को लेकर तनावपूर्ण रहे थे, जबकि हसीना के काल में आतंकवाद-रोधी सहयोग मजबूत रहा।

□ मुख्य बिंदु

- BNP की स्थापना 1978 में जनरल ज़िया-उर-रहमान ने की थी।
- 2001-2006 के BNP-जमात गठबंधन के दौरान उग्रवादी समूहों को लेकर भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे।
- हसीना के काल (2008-2024) में आतंकवाद-रोधी सहयोग मजबूत रहा।
- अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और हसीना भारत में हैं।
- प्रारंभिक संकेत सतर्क आशावाद की ओर इशारा करते हैं।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने IEEPA शुल्कों पर अंकुश लगाया

संदर्भ: फरवरी 2026 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने 6-3 के निर्णय में अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA), 1977 के अंतर्गत राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि व्यापक शुल्क राष्ट्रपति के अधिकार से परे थे, क्योंकि शुल्क लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है। IEEPA का उपयोग मुख्यतः प्रतिबंधों और परिसंपत्तियाँ फ्रीज़ करने (एसेट फ्रीज़) के लिए होता है और इसमें शुल्कों का उल्लेख नहीं है।

□ मुख्य बिंदु

- न्यायालय ने कहा कि व्यापक शुल्क राष्ट्रपति के अधिकार से परे थे, क्योंकि शुल्क लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है।
- IEEPA का उपयोग मुख्यतः प्रतिबंधों और परिसंपत्तियाँ फ्रीज़ करने के लिए होता है और इसमें शुल्कों का उल्लेख नहीं है।
- ट्रंप व्यापक शुल्कों के लिए इसका उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे।

आर्कटिक सेंट्री और समाचारों में संघर्ष क्षेत्र

संदर्भ: फरवरी 2026 में नाटो ने आर्कटिक सेंट्री शुरू किया, जो आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ज्वाइंट फोर्स कमांड नॉरफ़ॉक के नेतृत्व में एक मिशन है, जबकि कई संघर्ष स्थल समाचारों में रहे। इनमें गाजा-मिस्र सीमा पर आंशिक रूप से पुनः खुला राफा क्रॉसिंग, चागोस (जिसे ब्रिटेन ने 2025 में मॉरीशस को लौटाने पर सहमति दी, और डिएगो गार्सिया

को 99 वर्ष के पट्टे पर अपने पास रखा), और सूडान के दारफुर में अल-फाशिर शामिल थे।

□ **मुख्य बिंदु**

- नाटो का आर्कटिक सेंट्री मिशन, जिसका नेतृत्व ज्वाइंट फोर्स कमांड नॉरफ़ॉक कर रहा है, आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने निर्देशों से विकिरण संरक्षण के ALARA सिद्धांत को हटा दिया।
- गाजा-मिस्र सीमा पर राफा क्रॉसिंग आंशिक रूप से पुनः खुल गया; अन्य दो क्रॉसिंग एरेज़ और केरेम शालोम हैं।
- ब्रिटेन ने 2025 में चागोस को मॉरीशस को लौटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि डिएगो गार्सिया को 99 वर्ष के पट्टे पर अपने पास रखा।
- सूडान के दारफुर क्षेत्र में अल-फाशिर में एक अर्धसैनिक समूह द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान नरसंहार के कथित संकेत सामने आए।

इज़राइल-अमेरिका के ईरान पर हमले और भारत का रुख

संदर्भ: जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में हुई अप्रत्यक्ष अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता विफल होने के बाद इज़राइल ने तेहरान पर दिन के उजाले में हमला किया, जिसमें अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल हुआ। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमला किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- ईरान ने अल उदैद (कतर), अल-सलेम (कुवैत), अल-धफ़रा (संयुक्त अरब अमीरात) और बहरीन में अमेरिकी पाँचवें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया।
- मोदी की इज़राइल यात्रा के दो दिन से भी कम समय बाद भारत ने संयम बरतने का आग्रह किया।
- ईरान में लगभग 10,000 भारतीय, इज़राइल में 41,000 से अधिक और खाड़ी में 80 से 90 लाख भारतीय हैं।
- भारत के ऊर्जा आयात का लगभग 60 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आता है।

गाज़ा के लिए शांति बोर्ड

संदर्भ: फरवरी 2026 में भारत ने वाशिंगटन DC में शांति बोर्ड की उद्घाटन बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। यह बोर्ड गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिका की 20-सूत्री योजना का प्रमुख हिस्सा है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) का समर्थन प्राप्त है। इसे सार्वभौमिक बहुपक्षवाद से 'मिनीलेटरल', नेता-केंद्रित संस्थाओं की ओर बदलाव के रूप में देखा जाता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- इस बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) का समर्थन प्राप्त है।
- इसके साथ-साथ गाज़ा के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति (NCAG) और अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- इसे सार्वभौमिक बहुपक्षवाद से 'मिनीलेटरल', नेता-केंद्रित संस्थाओं की ओर बदलाव के रूप में देखा जाता है।
- समर्थकों का तर्क है कि यह आम सहमति-आधारित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की तुलना में अधिक परिणाम-उन्मुख हो सकता है और इसमें निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति

संदर्भ: अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई, जिससे पाँच दशकों की बाध्यकारी परमाणु सीमाओं का अंत हुआ। 2010 में हस्ताक्षरित और 2011 से लागू इस संधि ने तैनात परमाणु हथियारों की संख्या 1,550 और प्रक्षेपण वाहनों की संख्या 800 तक सीमित की थी तथा 18 वार्षिक निरीक्षणों का प्रावधान किया था, और 2021 में इसे पाँच वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। इसके समाप्त होने से दोनों शक्तियों के बीच अंतिम शस्त्र-नियंत्रण संधि भी समाप्त हो गई।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2010 में ओबामा और मेदवेदेव द्वारा हस्ताक्षरित तथा 2011 से लागू। इसने परमाणु हथियारों की संख्या 1,550 और प्रक्षेपण वाहनों की संख्या 800 तक सीमित की तथा 18 वार्षिक निरीक्षणों का प्रावधान किया।
- 2021 में पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई गई।

□ **पूर्ववर्ती संधियाँ**

- SALT वार्ताएँ 1969 में शुरू हुईं और ABM संधि पर 1972 में हस्ताक्षर हुए; अमेरिका 2002 में इससे बाहर हो गया।
- START I (1991 में हस्ताक्षरित, 1994 में लागू) ने परमाणु हथियारों को 6,000 तक सीमित किया।
- SORT (2002) ने 2012 तक तैनात परमाणु हथियारों को घटाकर 1,700-2,200 कर दिया।
- अमेरिका के पास लगभग 5,277 और रूस के पास लगभग 5,449 परमाणु हथियार हैं।

प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा ने अगस्त 2024 की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ किया। वायु सेनाओं के बीच एक सामरिक मामलों का कार्य समूह और एक Su-30 फोरम स्थापित किया गया, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का पाँचवाँ संस्करण आयोजित हुआ, और मलेशिया ने पाम तेल के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी

भूमिका की पुनः पुष्टि की तथा सौर एवं हाइड्रोजन में निवेश का वादा किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- वायु सेनाओं के बीच एक सामरिक मामलों का कार्य समूह और एक Su-30 फोरम स्थापित किया गया।
- अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का पाँचवाँ संस्करण आयोजित किया गया।
- मलेशिया ने पाम तेल के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका की पुनः पुष्टि की और मलेशियाई कंपनियाँ सौर एवं हाइड्रोजन में निवेश करेंगी।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढाँचा और भारत-GCC FTA

संदर्भ: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी 2025 में शुरू किए गए द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक सोपान के रूप में अंतरिम व्यापार समझौते के ढाँचे पर सहमति व्यक्त की; भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के पारस्परिक शुल्क 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गए। इसके अतिरिक्त, भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) मुक्त व्यापार समझौते के लिए कार्य-शर्तें (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तय की गईं।

□ **मुख्य बिंदु**

- आर्थिक सहयोग पर एक ढाँचा समझौते (फ्रेमवर्क एग्रीमेंट) पर 2004 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। 2024-25 में GCC के साथ भारत का व्यापार 178.56 अरब डॉलर था, जो उसके वैश्विक व्यापार का लगभग 15.42 प्रतिशत है।
- GCC के छह सदस्य संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत हैं; इसका मुख्यालय रियाद में है।
- GCC की स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी और यहाँ लगभग एक करोड़ भारतीय रहते हैं।

□ **ढाँचे की शर्तें**

- रूसी तेल के आयात पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क अमेरिका द्वारा वापस ले लिया गया है।
- अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक के शुल्क लगाए थे।
- भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क घटाएगा या समाप्त करेगा तथा वृक्षीय मेवे (ट्री नट्स), फल, सोयाबीन तेल और वाइन एवं स्पिरिट जैसी वस्तुओं पर शुल्क कम करेगा।
- भारत पाँच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर की वस्तुएँ खरीदने की योजना बना रहा है, जिनमें ऊर्जा, विमान, कीमती धातुएँ और कोकिंग कोयला शामिल हैं।
- अमेरिका जेनेरिक दवाओं तथा रत्नों एवं हीरों पर शुल्क हटाएगा, विमान-संबंधी शुल्कों में ढील देगा और ऑटो पार्ट्स के लिए तरजीही कोटा देगा।
- GPU सहित उन्नत प्रौद्योगिकी में व्यापार का विस्तार होगा।
- वित्त वर्ष 2025 में भारत-अमेरिका व्यापार 132.2 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, और अमेरिका से कुल FDI प्रवाह 70.65 अरब डॉलर (2000-2025) है।

□ **पारस्परिक व्यापार पर समझौते**

- ART पर GATT के अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत हस्ताक्षर नहीं किए जाते और उनकी सूचना WTO को नहीं दी जाती।
- अनुच्छेद XXIV के अनुसार मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को लगभग समस्त व्यापार को शामिल करना होता है तथा सीमा शुल्क संघों को साझा बाह्य शुल्क अपनाना होता है।
- चिंताओं में पारदर्शिता में कमी और WTO विवाद निपटान का अभाव शामिल हैं।

भारत-इज़राइल विशेष रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2026 की दो दिवसीय इज़राइल राजकीय यात्रा ने संबंधों को शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचा दिया, जिसमें 17 समझौतों सहित 27 परिणाम शामिल थे। इनमें महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ, एक साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, इज़राइल में UPI, पाँच वर्षों में 50,000 तक भारतीय कामगार और मुक्त व्यापार समझौते में प्रगति शामिल थे। पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 से हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में शुरू हुए। मोदी की 2017 की यात्रा ने रणनीतिक साझेदारी का सृजन किया।
- AI, क्वांटम, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल करने वाली एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारी।
- दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल AI, साइबर सुरक्षा, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष को शामिल करती है।
- पाँच वर्षों में 50,000 तक भारतीय कामगारों के कोटे पर सहमति बनी।
- भारत में साइबर सुरक्षा में एक भारत-इज़राइल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- इज़राइल में UPI को सक्षम करने का समझौता और मुक्त व्यापार समझौते में प्रगति।
- कृषि में 100 उत्कृष्टता केंद्रों का लक्ष्य और उत्कृष्टता गाँवों (विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस) की शुरुआत।
- IMEC और I2U2 पर सहयोग।
- रक्षा को छोड़कर द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2022-23 में 10.77 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुँचा।

भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक साझेदारी

संदर्भ: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत की यात्रा की, एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लिया और मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ

द्विपक्षीय शिखर बैठक की। साझेदारी को सामरिक साझेदारी से बढ़ाकर विशेष वैश्विक सामरिक साझेदारी बनाया गया, जिसके रक्षा-औद्योगिक, परमाणु, महत्वपूर्ण खनिज और नवाचार संबंधी परिणाम रहे।

□ **मुख्य बिंदु**

- संबंध 1947 में शुरू हुए, 1998 में सामरिक साझेदारी बने, और होराइज़न 2047 रोडमैप 2023 में अपनाया गया। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है; अभ्यासों में वरुण, फ्रिंजेक्स, ला पेरूज़ और ओरियन शामिल हैं।
- यह 2017 के बाद मैक्रों की चौथी यात्रा थी और मुंबई की पहली आधिकारिक यात्रा थी।
- एक नया वार्षिक विदेश मंत्रियों का व्यापक संवाद होराइज़न 2047 रोडमैप की प्रगति पर नज़र रखेगा।
- H125 हेलीकॉप्टर अंतिम असेंबली लाइन, जो टाटा-एयरबस परियोजना है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सुविधा है।
- LEAP और M-88 इंजनों के लिए MRO केंद्र प्रस्तावित हैं, और BEL तथा सफ्रान हैमर स्मार्ट गोला-बारूद के लिए संयुक्त उद्यम बनाएँगे।
- 1992 के दोहरे कराधान परिहार अभिसमय में संशोधन किया गया ताकि BEPS बहुपक्षीय लिखत के प्रावधान शामिल किए जा सकें और सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र खंड हटाया जा सके।
- महत्वपूर्ण खनिजों पर एक संयुक्त आशय घोषणा है, और लघु तथा उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों, हाई-स्पीड रेल और हाइड्रोजन ट्रेनों पर सहयोग पर सहमति बनी।
- दोनों नेताओं ने कर्नाटक के वेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर अंतिम असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का शुभारंभ गेटवे ऑफ इंडिया पर किया गया।
- ISRO और CNES तृष्णा तापीय अवरक्त उपग्रह पर कार्य जारी रखे हुए हैं।
- 2026 के भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।
- दोनों देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन की सह-अध्यक्षता करते हैं।
- 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 12.67 अरब यूरो था; फ्रांस में UPI शुरू किया गया है।

भारत-ब्राज़ील दुर्लभ मृदा समझौता और व्यापार लक्ष्य

संदर्भ: राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और ब्राज़ील ने डिजिटल और व्यापार समझौतों के साथ दुर्लभ मृदा तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और 2030 तक अपना व्यापार लक्ष्य बढ़ाकर 30 अरब डॉलर कर दिया।

□ **मुख्य बिंदु**

- राजनयिक संबंध 1948 से हैं और 2006 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई; ब्राज़ील वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का सह-संस्थापक है।
- चीन के प्रसंस्करण संबंधी प्रभुत्व पर निर्भरता कम करने के लिए दुर्लभ मृदा तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों पर एक रणनीतिक समझौता।
- ब्राज़ील के भंडारों का केवल 30 प्रतिशत ही अन्वेषित है।
- इस्पात, खनन और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर समझौते।
- AI, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), ब्लॉकचेन और सुपरकंप्यूटिंग पर एक संयुक्त घोषणा।
- 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 25 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 15.21 अरब डॉलर हो गया।
- भविष्य के लिए डिजिटल साझेदारी पर एक संयुक्त घोषणा अपनाई गई।
- 2030 तक व्यापार लक्ष्य 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 30 अरब डॉलर किया गया।
- ब्राज़ील ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए व्यावसायिक वीज़ा की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ा दी।

वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार

संदर्भ: विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जो भू-राजनीतिक, लॉजिस्टिक, हरित और संस्थागत दबावों का सामना कर रही है। WTO की विवाद निपटान प्रणाली और वार्ता कार्य ठप बने हुए हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- WTO का अपीलीय निकाय काफी हद तक निष्क्रिय है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति रोक रखी है।
- 2001 में शुरू हुआ दोहा विकास एजेंडा 25 वर्ष बाद भी अधूरा है।
- आम सहमति का नियम किसी भी एक सदस्य को निर्णय रोकने की अनुमति देता है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ तर्क देती हैं कि चीन और भारत जैसी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विशेष और विभेदक व्यवहार नहीं मिलना चाहिए।
- यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे उपायों को विकासशील देश हरित व्यापार बाधाओं के रूप में देखते हैं।

समुद्री मंच और महत्वपूर्ण खनिज पहलें

संदर्भ: भारत ने हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS) की अध्यक्षता संभाली और संयुक्त टास्क फोर्स-154 की कमान ग्रहण की। इसी बीच, अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए FORGE और प्रोजेक्ट वॉल्ट की घोषणा की।

□ **समुद्री मंच**

➤ IONS की स्थापना 2008 में भारतीय नौसेना की पहल पर हुई थी और इसके 25 सदस्य देश हैं।

➤ भारत ने संयुक्त समुद्री बलों (CMF) के अंतर्गत एक प्रशिक्षण टास्क फोर्स, संयुक्त टास्क फोर्स-154 की पहली बार कमान संभाली।

➤ संयुक्त समुद्री बल (CMF) 47 देशों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है, जो नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखती है।

□ **महत्वपूर्ण खनिज**

➤ FORGE (फोरम ऑन रिसोर्स, जियोस्ट्रैटेजिक एँगेजमेंट) को वाशिंगटन डी.सी. में उद्घाटन महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत सहित 50 से अधिक देशों के साथ शुरू किया गया।

➤ FORGE, खनिज सुरक्षा साझेदारी (मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप) का उत्तराधिकारी है।

➤ प्रोजेक्ट वॉल्ट अमेरिकी सामरिक महत्वपूर्ण खनिज भंडार का निर्माण एक स्वतंत्र सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में करता है, जो महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों को खरीदेगा और भंडारित करेगा।

सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संदर्भ: सेशेल्स के राष्ट्रपति ने फरवरी 2026 में भारत की यात्रा की; सेशेल्स कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बनेगा और भारत ने 175 मिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की। सेशेल्स आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल होने पर भी सहमत हुआ। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेशेल्स SAGAR और विज़न महासागर (MAHASAGAR) के केंद्र में है तथा भारत की असम्प्शन द्वीप निगरानी योजनाओं का स्थल है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ सेशेल्स कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बनेगा, जिसमें भारत, श्रीलंका, मॉरीशस, मालदीव और बांग्लादेश शामिल हैं।

➤ वह आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने तथा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने पर सहमत हुआ।

➤ भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और एक जलमापन (हाइड्रोग्राफिक) इकाई के निर्माण में सहायता करेगा, और उसने 175 मिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की।

➤ सेशेल्स SAGAR और विज़न महासागर के केंद्र में है तथा भारत की असम्प्शन द्वीप निगरानी योजनाओं का स्थल है।

अमेरिका-इज़राइल-ईरान संघर्ष: खामेनेई मारे गए, खाड़ी की ऊर्जा पर प्रहार

संदर्भ: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, 86, अमेरिकी और इज़राइली बलों के हमले में मारे गए; उनके पुत्र मोज्तबा खामेनेई को बाद में उत्तराधिकारी चुना गया। युद्ध खाड़ी के ऊर्जा स्थलों और हिंद महासागर तक फैल गया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ विशेषज्ञ सभा (असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स) द्वारा मोज्तबा खामेनेई को चुने जाने से पहले तीन सदस्यों की एक अंतरिम नेतृत्व परिषद ने कार्यभार संभाला।

➤ इज़राइल ने साउथ पार्स पर हमला किया; इसके बाद ईरान ने कतर के रास लफ़ान औद्योगिक नगर पर प्रहार किया।

➤ अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर बमबारी की।

➤ ईरान ने लगभग 4,000 किमी दूर डिएगो गार्सिया पर दो खोर्रमशहर-4 मिसाइलें दागीं; जवाब में एक SM-3 इंटरसेप्टर का उपयोग किया गया।

➤ एक अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के EEZ के निकट ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को टारपीडो से नष्ट कर दिया, जिसमें कम से कम 80 नाविक मारे गए; यह पोत मिलन-2026 और अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा से लौटा था।

ईरान की सत्ता संरचना और वेलायत-ए-फकीह

संदर्भ: मार्च 2026 में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मृत्यु के बाद, ध्यान ईरान की उस राजनीतिक व्यवस्था की ओर गया जो खुमैनी के वेलायत-ए-फकीह, अर्थात विधिवेत्ता के शासन, के सिद्धांत पर आधारित है। 1979 के संविधान ने सर्वोच्च नेता का पद सृजित किया, जिसे राजनीतिक और धार्मिक मामलों पर अधिकार प्राप्त है, और विशेषज्ञ सभा सर्वोच्च नेता का चयन करती है। 1979 की क्रांति के बाद गठित IRGC एक प्रमुख शक्ति केंद्र है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 1979 के संविधान ने सर्वोच्च नेता का पद सृजित किया, जिसे राजनीतिक और धार्मिक मामलों पर अधिकार प्राप्त है।

➤ 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद, संशोधनों द्वारा प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और उसके कार्य राष्ट्रपति तथा मजलिस के अध्यक्ष को दे दिए गए।

➤ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का गठन 1979 की क्रांति के बाद हुआ था और वह हमास तथा हिज़बुल्लाह का समर्थन करता है।

➤ विशेषज्ञ सभा सर्वोच्च नेता का चयन करती है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा

संदर्भ: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत की यात्रा की, जो 2018 में जस्टिन ट्रूडो के बाद किसी कनाडाई प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस यात्रा का उद्देश्य हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर 2023 के विवाद के बाद विश्वास का पुनर्निर्माण करना था, और इसने यूरेनियम सहित ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत और कनाडा के बीच 2018 से रणनीतिक साझेदारी है। कनाडा में 18 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो उसकी जनसंख्या का लगभग 5% हैं।

➤ 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 8.66 अरब डॉलर था।

➤ भारत औषधियाँ, इस्पात, समुद्री खाद्य, परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करता है तथा दालें, उर्वरक, कोयला, कच्चा तेल और कीमती पत्थर आयात करता है।

□ **यूरेनियम का संदर्भ**

➤ भारत के अयस्क की गुणवत्ता (ग्रेड) 0.02% से 0.45% तक है, जबकि वैश्विक औसत 1 से 2% है, और कुछ कनाडाई खदानों में यह 15% तक पहुँचती है।

➤ भारत की यूरेनियम आवश्यकताओं का 70% से अधिक आयात किया जाता है।

➤ 2025 में वार्षिक आवश्यकता लगभग 1,884 टन थी और परमाणु विस्तार के बाद इसके लगभग 5,400 टन होने का अनुमान है।

➤ यूरेनियम उत्पादन झारखंड और आंध्र प्रदेश में केंद्रित है।

डिजिटलीकरण और सततता में भारत-फिनलैंड सामरिक साझेदारी

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलीकरण और सततता में सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचाया। यह साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G, स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम कंप्यूटिंग, रक्षा, अंतरिक्ष, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल करती है। पूर्व सहयोग में नोकिया, चिनाब रेल पुल का डिज़ाइन और नुमालीगढ़ बाँस-से-जैव-एथेनॉल रिफाइनरी शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 6G दूरसंचार।

➤ स्वच्छ ऊर्जा और क्वांटम कंप्यूटिंग।

➤ रक्षा, अंतरिक्ष, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और महत्वपूर्ण खनिज।

➤ पूर्व सहयोग में नोकिया, चिनाब रेल पुल का डिज़ाइन और असम में नुमालीगढ़ बाँस-से-जैव-एथेनॉल रिफाइनरी शामिल हैं।

प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत: पड़ोसियों को ईंधन और सहायता

संदर्भ: मार्च 2026 में पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ईंधन व्यवधान के बीच भारत ने बांग्लादेश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल, श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम और काबुल को 2.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी तथा म्यांमार के साथ 2021 के दलहन समझौता ज्ञापन (MoU) को पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये कदम पड़ोसी पहले (Neighbourhood First) नीति और महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत की प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता की भूमिका को दर्शाते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत ने 2023 से संचालित भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की; बांग्लादेश 2015 से नुमालीगढ़ से डीजल खरीद रहा है।

➤ भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम भेजा, जो पड़ोसी पहले नीति और महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण को दर्शाता है।

➤ MAHASAGAR का पूर्ण रूप है: Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति)।

➤ एक हवाई हमले में 2,000 बिस्तरों वाले नशामुक्ति अस्पताल को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने काबुल को 2.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी।

➤ उड़द (2.5 लाख टन) और अरहर (1 लाख टन) पर म्यांमार के साथ 2021 का समझौता ज्ञापन 2025-26 से आगे पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तथा 2026-27 के लिए 1 लाख टन अतिरिक्त अरहर की अनुमति दी गई।

बालेन्द्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

संदर्भ: 35 वर्षीय बालेन्द्र शाह को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, जिससे पिछले सितंबर के जेन ज़ी (Gen Z) प्रदर्शनों के बाद का संक्रमण काल समाप्त हुआ, जिन प्रदर्शनों ने के.पी. शर्मा ओली सरकार को गिरा दिया था।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ प्रदर्शनों में स्वच्छ शासन और भ्रष्टाचार की समाप्ति की माँग की गई थी।

➤ पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार ने इस दौरान नेपाल का शासन चलाया।

➤ शाह को नेपाल के हाल के इतिहास का सबसे युवा प्रधानमंत्री बताया गया है।

भारत के विरुद्ध अमेरिकी धारा 301 जाँचें

संदर्भ: अमेरिका ने भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हुए धारा 301(b) के अंतर्गत जाँचें शुरू कीं, जिनमें एक अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता पर और दूसरी 60 देशों में बलात श्रम सुरक्षा उपायों पर है। यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा IEEPA शुल्कों को रद्द किए जाने के बाद की गई है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 USTR को अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं की जाँच करने और जवाबी शुल्क लगाने की अनुमति देती है।

- USTR ने सौर मॉड्यूल, पेट्रोरसायन, इस्पात, वस्त्र, स्वास्थ्य-सेवा उत्पाद, निर्माण सामग्री और ऑटोमोबाइल की पहचान की।
- अमेरिका 2025 में भारत के साथ अपना घाटा 58 अरब डॉलर आँकता है, जबकि भारतीय आँकड़े 42.2 अरब डॉलर दर्शाते हैं।
- 2024-25 में भारत-अमेरिका व्यापार 131.84 अरब डॉलर तक पहुँच गया।
- न्यायालय के निर्णय के बाद, व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के अंतर्गत 150 दिनों के लिए अस्थायी 10% शुल्क लगाया गया।

याउंडे में WTO की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (MC14) बिना सहमति के समाप्त

संदर्भ: कैमरून के याउंडे में WTO का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया, मुख्यतः इसलिए कि अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर शुल्क पर पाँच वर्ष की रोक (मोरेटोरियम) चाहता था, जबकि अन्य देशों ने केवल परंपरागत दो वर्ष का विस्तार स्वीकार किया। भारत ने विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते (IFD) को भी रोक दिया।

□ ई-कॉमर्स पर रोक (मोरेटोरियम)

- इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर सीमा शुल्क की रोक 1998 से चली आ रही है और वह प्रभावी रूप से समाप्त हो चुकी है।
- भारत ने शुरू से ही इस रोक को बढ़ाने का विरोध किया है।
- विकासशील देशों का तर्क है कि भौतिक वस्तुओं के डिजिटल डाउनलोड बन जाने से उन्हें राजस्व की हानि होती है।

□ क्या सहमति बनी

- दूरस्थ-जल मछली पकड़ने वाले बेड़ों के लिए मत्स्य सब्सिडी पर वार्ताएँ जारी हैं, जिनकी सिफारिशों का लक्ष्य MC15 रखा गया है।
- छोटी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण तथा SPS और TBT समझौतों के अंतर्गत विशेष एवं विभेदक व्यवहार पर निर्णय अपनाए गए।
- WTO सुधार कार्य योजना और LDC पैकेज को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

□ IFD समझौता

- 166 सदस्यों में से 129 ने इसे अपनाने का समर्थन किया, लेकिन अकेले भारत ने इसे WTO में शामिल करने से रोक दिया।
- भारत का तर्क है कि बहुपक्षीय के बजाय कुछ देशों के बीच के (प्लूरिलेटरल) समझौते WTO को दो-स्तरीय बना देते हैं और कृषि सब्सिडी तथा सार्वजनिक भंडारण से ध्यान भटकाते हैं।
- 129 समर्थकों में से लगभग 98 चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का भी हिस्सा हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का दास व्यापार प्रस्ताव और अरब लीग के नए प्रमुख

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घाना द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव में अटलांटिक पार दास व्यापार में अफ्रीकियों की दासता को 'मानवता के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराध' के रूप में मान्यता दी। अलग से, मिस्र के नबील फहमी को अरब लीग का महासचिव नियुक्त करने की मंजूरी दी गई।

□ संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव

- यह राज्यों से माफी माँगने और क्षतिपूर्ति कोष में योगदान देने पर विचार करने का आग्रह करता है, जिसमें कोई राशि निर्दिष्ट नहीं है।
- यह लूटी गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी का आह्वान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते।

□ अरब लीग

- मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फहमी 1 जुलाई 2026 को पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार संभालेंगे।
- वे अहमद अबुल घेत का स्थान लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है।

BRICS 2026: भारत की अध्यक्षता, अध्यक्ष का सार-कथन और सदस्यता

संदर्भ: भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका विषय है: लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर उप-विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त वक्तव्य के बजाय अध्यक्ष के सार-कथन के साथ समाप्त हुई, जिससे ईरान पर अमेरिका-इज़राइल युद्ध को लेकर मतभेद उजागर हुए।

□ मुख्य बिंदु

- संयुक्त वक्तव्य के लिए सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक होती है; अध्यक्ष का सार-कथन केवल मेज़बान द्वारा जारी किया जाता है।
- BRICS के 11 सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया।
- ईरान पर हमला हो रहा है, जबकि सऊदी अरब और UAE अमेरिकी अड्डों की मेज़बानी करते हैं और ईरानी मिसाइलों से प्रभावित हुए।
- BRICS 2026 का विषय है: लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability)।
- BRICS+ का 2023 में विस्तार हुआ, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इथियोपिया और ईरान शामिल किए गए; इंडोनेशिया जनवरी 2025 में शामिल हुआ।
- नए सदस्यों में केवल मिस्र और ईरान ने ही दिसंबर 2025 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) प्रस्तावों के आह्वान में भाग लिया।

➤ प्रमुख भूमिका अध्यक्षता के साथ प्रतिवर्ष बदलती रहती है; कोई स्थायी सचिवालय या कोष-प्रबंधन निकाय नहीं है।

UAE का OPEC और OPEC+ से बाहर निकलना

संदर्भ: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1 मई से प्रभावी रूप से OPEC और व्यापक OPEC+ गठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया, जिससे लगभग छह दशकों की सदस्यता समाप्त हो गई। यह कदम अमेरिका-ईरान संघर्ष से तेल बाज़ार में उत्पन्न व्यवधान के बीच उठाया गया और इसमें सुरक्षा तथा आर्थिक, दोनों उद्देश्य परिलक्षित होते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ OPEC की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा की गई थी।

➤ UAE 1967 में इसमें शामिल हुआ, आरंभ में अबू धाबी के माध्यम से।

➤ OPEC+ का गठन 2016 में OPEC और रूस, मेक्सिको तथा कज़ाखस्तान जैसे 10 प्रमुख गैर-OPEC उत्पादकों द्वारा किया गया।

➤ OPEC+ विश्व के लगभग 40% कच्चे तेल का उत्पादन करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किए जाने वाले लगभग 60% पेट्रोलियम का योगदान देता है।

➤ बाहर निकलने से पहले UAE सहित OPEC के 12 सदस्य थे।

अमेरिका-ईरान दो सप्ताह का युद्धविराम और भारत पर प्रभाव

संदर्भ: राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी समय-सीमा से कुछ समय पहले अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की, और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शीघ्र ही सहमति जताई। इस्लामाबाद में बाद की वार्ता विफल हो गई और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी, जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य और भारत की ऊर्जा सुरक्षा चिंता के केंद्र में आ गए।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ युद्धविराम से ईरान की ऊर्जा अवसंरचना और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रति खतरे कम हुए।

➤ इस्लामाबाद वार्ता 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच पहला उच्च-स्तरीय राजनीतिक संपर्क थी।

➤ वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के नियंत्रण और जमी हुई संपत्तियों को लेकर टूट गई।

➤ ईरान ने 60% संवर्धित यूरेनियम के 440 किलोग्राम से अधिक भंडार को छोड़ने से इनकार कर दिया और सात देशों में रखे 27 अरब डॉलर के जमे हुए राजस्व को जारी करने की माँग की।

➤ ईरान की 10-सूत्री योजना को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित किया गया: प्रतिबंधों से राहत, संवर्धन के अधिकार और जलडमरूमध्य का नियंत्रण।

ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा

संदर्भ: ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जो 42 वर्षों में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की पहली यात्रा थी। यह प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई 2024 की ऑस्ट्रिया यात्रा के बाद हुई और इसने उन्नत भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी की पुनः पुष्टि की।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ एक आशय-पत्र (Letter of Intent) द्वारा आतंकवाद-रोध पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई और साइबर सुरक्षा संवाद शुरू किया गया।

➤ सैन्य मामलों में सहयोग पर आशय-पत्र रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है।

➤ भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र और ऑस्ट्रिया के सशस्त्र बल अंतरराष्ट्रीय केंद्र (AUTINT) के बीच साझेदारी का स्वागत किया गया।

➤ एक फास्ट-ट्रैक तंत्र दोनों देशों के निवेशकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा।

➤ सड़क अवसंरचना सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया, और पंप भंडारण तथा हरित हाइड्रोजन को प्राथमिकता वाले क्षेत्र घोषित किया गया।

➤ द्विपक्षीय अंतरिक्ष उद्योग संगोष्ठी 2026 के शरद ऋतु में वियना में आयोजित की जाएगी।

➤ एक संयुक्त आशय-पत्र दोहरे व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यताओं की मान्यता को शामिल करता है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत यात्रा

संदर्भ: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने नई दिल्ली की यात्रा की और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता की, जिससे भारत-दक्षिण कोरिया विशेष सामरिक साझेदारी आगे बढ़ी। समझौतों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, समुद्री मामले और संस्कृति शामिल थे, जिन्हें 'चिप्स से जहाज़ तक, प्रतिभा से प्रौद्योगिकी तक' के रूप में संक्षेपित किया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए और 2015 में विशेष सामरिक साझेदारी में उन्नत किए गए।

➤ भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण कोरिया की नई दक्षिणी नीति (New Southern Policy), दोनों हिंद-प्रशांत को प्राथमिकता देती हैं।

➤ के9 वज्र-टी तोप, जो दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी से भारत में निर्मित है, रक्षा सह-उत्पादन का एक प्रमुख उदाहरण है।

➤ सहयोग का विस्तार AI, पोत निर्माण और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) में हो रहा है।

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 2010 से लागू है और 15 वर्षों में व्यापार लगभग 90% बढ़ा है।
- अयोध्या में रानी सुरीरत्ना स्मारक ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है।

श्रीलंका में OCI छठी पीढ़ी तक विस्तारित

संदर्भ: श्रीलंका की दो-दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने घोषणा की कि श्रीलंका में भारतीय प्रवासियों के लिए OCI की पात्रता चौथी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी गई है। गृह मंत्रालय (MHA) ने ई-वीज़ा प्रवेश के लिए 14 और समुद्री बंदरगाहों को भी अधिसूचित किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- पात्रता श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज़ों पर आधारित होगी।
- चक्रवात दित्वा के लिए भारत के 45 करोड़ डॉलर के सहायता पैकेज को रेखांकित किया गया।
- OCI योजना 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधनों के माध्यम से शुरू हुई थी और यह दोहरी नागरिकता नहीं है।
- OCI धारकों को आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा मिलता है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, वे संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते और कृषि भूमि नहीं खरीद सकते।
- 14 नए ई-वीज़ा समुद्री बंदरगाहों में गुजरात के सात (अलंग, बेदी बंदर, भावनगर, पोरबंदर, हजीरा, पीपावाव, मांडवी), तमिलनाडु के तीन, आंध्र प्रदेश के दो और ओडिशा के दो (पारादीप, धामरा) शामिल हैं।
- भारत में 114 आप्रवासन जाँच चौकियाँ हैं, और ई-वीज़ा चीन, पाकिस्तान, यमन और ईरान को छोड़कर 207 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
- ई-वीज़ा की वैधता 1 महीने से 5 वर्ष तक होती है।

ट्रंप-शी बीजिंग शिखर सम्मेलन 2026

संदर्भ: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन की यात्रा की, जो उनके दूसरे कार्यकाल की पहली चीन यात्रा और 2017 के बाद किसी पदासीन अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। शिखर सम्मेलन पश्चिम एशिया संकट की छाया में रहा और इससे कोई बड़ी सफलता नहीं, बल्कि कुछ अस्थायी कदम ही निकले।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह ट्रंप और शी के बीच सातवीं प्रत्यक्ष (व्यक्तिगत) बैठक थी।
- ट्रंप एक दर्जन से अधिक अमेरिकी CEO के साथ यात्रा पर गए।
- दोनों पक्ष होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खुला रखने और ऊर्जा के मुक्त प्रवाह का समर्थन करने की आवश्यकता पर सहमत हुए।
- वे एक व्यापार बोर्ड और एक निवेश बोर्ड की स्थापना पर सहमत हुए, जो गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश की अनुमति देगा।
- अमेरिका ने 10 चीनी कंपनियों को एनवीडिया H200 चिप्स खरीदने की मंजूरी दी।
- दोनों पक्षों ने AI सुरक्षा संवाद पर चर्चा की।

□ **टकराव के बिंदु**

- ताइवान सबसे तीखा विवाद-बिंदु था, और दिसंबर 2025 में घोषित 11 अरब डॉलर का अमेरिकी हथियार सौदा बीजिंग को खटकता है।
- अमेरिका चीन के दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) प्रतिबंधों पर आपत्ति करता है, जबकि चीन अमेरिकी अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) निर्यात नियंत्रणों पर आपत्ति करता है।
- अमेरिका-चीन के बीच कोई भी रियायती शुल्क (टैरिफ) समझौता अमेरिका-भारत व्यापार समझौता वार्ता के लिए आधार-रेखा तय कर सकता है।

नीदरलैंड में मोदी: चोल ताम्रपत्र लौटाए गए

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने 16-17 मई 2026 को नीदरलैंड की राजकीय यात्रा की, जो चार देशों के यूरोपीय दौरे का पहला चरण था। संबंधों को सामरिक साझेदारी में उन्नत किया गया और नीदरलैंड ने 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र लौटाए।

□ **मुख्य बिंदु**

- इस दौरे में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल थे, और यह भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने तथा नई भारत-EU सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी के बाद हुआ।
- मोदी ने हेग में डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ वार्ता की; यह 2017 के बाद उनकी दूसरी यात्रा थी।
- सत्रह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें जल, कृषि और स्वास्थ्य पर WAH ढाँचा शामिल है।
- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML की अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) निर्माण परियोजना प्रमुख समझौता थी; ASML का EUV लिथोग्राफी मशीनों पर लगभग एकाधिकार है।
- नीदरलैंड वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuel Alliance) में शामिल हुआ, नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना हुई और भारत-नीदरलैंड हरित हाइड्रोजन रोडमैप शुरू किया गया।

□ **चोल ताम्रपत्र**

- ये पट्टिकाएँ, जिन्हें अनैमंगलम या लीडेन पट्टिकाएँ भी कहा जाता है, राजराज चोल प्रथम (985-1014 ई.) के शासनकाल की हैं।
- इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी पट्टिकाएँ हैं, इनका वजन लगभग 30 किग्रा है और इन पर भूमि अनुदान, शासन तथा कराधान से संबंधित संस्कृत और तमिल लेख अंकित हैं।
- इन्हें 1712 में फ्लोरेंशियस कैम्पर नीदरलैंड ले गए थे, जब नागपट्टिनम पर डच नियंत्रण था।
- इनकी वापसी 14 वर्षों के राजनयिक प्रयासों का परिणाम थी।

प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा और 5 अरब डॉलर का निवेश

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2026 में अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान के साथ वार्ता की, जिसके दौरान यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप दिया गया, तथा 8 एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर, वाडिनार जहाज-मरम्मत क्लस्टर और भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों में यूएई की बड़ी भूमिका पर सहमति बनी।

□ मुख्य बिंदु

- रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप दिया गया।
- कोचीन शिपयार्ड और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड ने वाडिनार में जहाज-मरम्मत क्लस्टर पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- सी-डैक (C-DAC) और G42 8 एक्साफ्लॉप का सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करेंगे।
- मैत्री (MAITRI) ढाँचे के अंतर्गत वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को चालू किया गया।
- निवेश में ADIA और NIIF द्वारा 1 अरब डॉलर तक, एमिरेट्स एनबीडी द्वारा आरबीएल बैंक में 3 अरब डॉलर, और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा सम्मान कैपिटल में 1 अरब डॉलर शामिल हैं।

□ ऊर्जा

- यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता और सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता है, जो एलपीजी की लगभग 40 प्रतिशत आवश्यकता पूरी करता है।
- भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों में यूएई की भागीदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी; एसपीआर स्थल विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर हैं।
- आईओसीएल (IOCL) और एडनॉक (ADNOC) ने दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति समझौते पर सहमति जताई।

प्रोजेक्ट फ्रीडम और होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट

संदर्भ: मई 2026 में अमेरिका ने ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की, लेकिन व्यापारिक जहाजों और दो अमेरिकी विध्वंसकों पर हमले के बाद एक दिन में ही इसे निलंबित कर दिया। ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता में प्रगति का हवाला दिया। यह जलडमरूमध्य विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल का मार्ग है, इसलिए यह संकट ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।

□ मुख्य बिंदु

- विश्व का लगभग 20 प्रतिशत तेल होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- ट्रंप ने निलंबन का कारण ईरान के साथ वार्ता में प्रगति को बताया।
- ईरान ने असममित साधनों के रूप में ड्रोन और बारूदी सुरंगों का उपयोग किया है।
- अमेरिका ने इससे पहले 1987-88 में काफिला अनुरक्षण के साथ ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाया था।

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और SAI शिखर सम्मेलन

संदर्भ: भारत ने अपनी 2026 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत मंडपम में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, हालाँकि ईरान-यूएई तनाव के कारण संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हो सका। 5वाँ ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ।

□ विदेश मंत्रियों की बैठक

- 28 फरवरी 2026 को खाड़ी संघर्ष शुरू होने के बाद से यह भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ी बहुपक्षीय बैठक थी।
- भारत ने द्वि-राज्य समाधान को दोहराया और गाजा में स्थायी युद्धविराम का आह्वान किया।
- भारत ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवागमन का आग्रह किया।
- उसने एकपक्षीय दंडात्मक उपायों को अंतरराष्ट्रीय कानून के असंगत बताया।

□ 5वाँ ब्रिक्स SAI प्रमुखों का शिखर सम्मेलन

- यह बेंगलुरु में आयोजित हुआ और इसका आयोजन CAG के. संजय मूर्ति ने किया।
- विषय था: शहरी गतिशीलता पर केंद्रित जीवन सुगमता।
- सदस्यों ने बेंगलुरु घोषणा-पत्र और ब्रिक्स SAI कार्य योजना 2027-28 को अपनाया।

भारत-इटली विशेष सामरिक साझेदारी

संदर्भ: अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत-इटली संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचाया, जिसका आधार संयुक्त सामरिक कार्य योजना 2025-29 है।

□ मुख्य बिंदु

- द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 2029 तक 20 अरब यूरो है, जो वर्तमान 14.25 अरब यूरो से अधिक है।
- टाटा मोटर्स द्वारा इवेको ग्रुप का 3.8 अरब यूरो में अधिग्रहण इटली में सबसे बड़ा भारतीय निवेश है।

- इटली ने दिल्ली में 50 करोड़ यूरो की वित्तपोषण सुविधा के साथ SIMEST कार्यालय खोला, और SACE ने SME के लिए 20 करोड़ यूरो जोड़े।
- एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप हेलीकॉप्टर, नौसैनिक प्लेटफ़ॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और MRO में सह-विकास, सह-उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करता है।
- एक भारत-इटली नवाचार केंद्र का प्रस्ताव किया गया, साथ ही AI, क्वांटम, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग पर सहमति बनी।

□ **IMEC और संपर्क**

- इटली ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का समर्थन किया और स्वयं को इसका पश्चिमी आधार मानता है।
- पहली IMEC मंत्रिस्तरीय बैठक 2026 में आयोजित की जानी है।
- जेनोआ से जुड़ने वाली स्पार्कल-एयरटेल ब्लू-रमन समुद्र के भीतर बिछी केबल सक्रिय हो गई है; ब्लू इटली, ग्रीस और इज़राइल को जोड़ती है, जबकि रमन इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान और भारत को जोड़ती है।

भारत-वियतनाम उन्नत व्यापक सामरिक साझेदारी

संदर्भ: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को उन्नत व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचाया। 2030 तक 25 अरब डॉलर का नया व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- तो लाम वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं और राष्ट्रपति बनने के एक माह के भीतर उन्होंने यात्रा की।
- व्यापार लक्ष्य 2030 तक 25 अरब डॉलर है, जबकि वर्तमान में यह 16.4 अरब डॉलर है।
- तेरह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें डिजिटल भुगतान और QR-आधारित सीमा-पार लेन-देन पर RBI और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है।
- रेडियोधर्मी और दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) खनिजों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, AI, 6G, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर सहमति बनी।
- भारतीय अंगूर और अनार तथा वियतनामी दुरियान और पोमेलो के लिए बाज़ार पहुँच का विस्तार किया जाएगा।

भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ: साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडेस ने मई 2026 में नई दिल्ली की यात्रा की और संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। साइप्रस वर्तमान में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। दोनों पक्षों ने पाँच वर्षों में द्विपक्षीय निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की, जिसमें साइप्रस ने पहलगाम हमले की निंदा की और यूरोपीय संघ के भीतर 'फ्रेंड्स ऑफ IMEC' समूह का गठन किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस को भारत और यूरोप के बीच निवेश का प्रवेशद्वार बताया, और दोनों ने पाँच वर्षों में द्विपक्षीय निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
- एक समझौता ज्ञापन साइप्रस रक्षा एवं अंतरिक्ष उद्योग क्लस्टर को SIDM से जोड़ता है, और साइबर सुरक्षा संवाद स्थापित किया जाएगा।
- आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया; साइप्रस ने पहलगाम हमले की निंदा की।
- साइप्रस ने यूरोपीय संघ के भीतर 'फ्रेंड्स ऑफ IMEC' समूह का गठन किया है।
- दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही शुरू होंगी।

रूस-चीन संबंध और पुतिन की बीजिंग यात्रा

संदर्भ: रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मई 2026 में ट्रंप के कुछ दिनों बाद बीजिंग की यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ और 40 से अधिक समझौते हुए। शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना एकपक्षीय और आधिपत्यवादी प्रतिकूल प्रवृत्तियों के विरुद्ध चेतावनी दी, और दोनों नेताओं ने बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन किया। चीन रूस के व्यापार का लगभग 32 प्रतिशत है, और यह गहराती साझेदारी भारत के रणनीतिक अवसर को सीमित करती है।

□ **मुख्य बिंदु**

- शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना एकपक्षीय और आधिपत्यवादी प्रतिकूल प्रवृत्तियों के विरुद्ध चेतावनी दी, और दोनों नेताओं ने बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन किया।
- चीन रूस के व्यापार का लगभग 32 प्रतिशत है, अर्थात 2025 में 700 अरब डॉलर में से लगभग 228 अरब डॉलर।
- व्यापार का निपटान अब अधिकाधिक युआन और रूबल में हो रहा है।

लिपुलेख दर्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा विवाद

संदर्भ: मई 2026 में भारत ने जून से अगस्त 2026 तक लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिस पर नेपाल की नई सरकार ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया। लिपुलेख भारत-नेपाल-चीन त्रि-संगम पर स्थित है। नेपाल सुगौली संधि (1816) का हवाला देकर लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी पर दावा करता है, जबकि भारत इस दावे को अनुचित बताता है और द्विपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता देता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- लिपुलेख भारत-नेपाल-चीन त्रि-संगम पर स्थित है, और भारत 1954 से इसका उपयोग यात्रा के लिए करता आ रहा है।

- नेपाल सुगौली संधि (1816) का हवाला देकर महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी पर दावा करता है और उसने 2020 में एक नया मानचित्र प्रकाशित किया।
- भारत इस दावे को अनुचित बताता है और द्विपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता देता है।
- चीन ने 2025 में लिपुलेख के रास्ते व्यापार फिर से शुरू किया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव चुनाव 2026

संदर्भ: मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनौपचारिक संवादों के दौरान अगले महासचिव के लिए चार उम्मीदवारों ने स्वयं को प्रस्तुत किया: मिशेल बैचेलेट, रेबेका ग्रिनस्पैन, मैकी सॉल और राफेल ग्रोसी। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है, जहाँ P5 के पास प्रभावी वीटो है, और यह पद क्षेत्रों के बीच बारी-बारी से दिया जाता है, जिसमें अगली बारी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की है।

□ प्रक्रिया

- महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है, जहाँ P5 के पास प्रभावी वीटो है।
- 1981 से पदधारकों ने स्वयं को दो कार्यकाल तक सीमित रखा है।
- यह पद क्षेत्रों के बीच बारी-बारी से दिया जाता है, और वर्तमान बारी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की है।

□ उम्मीदवार

- मिशेल बैचेलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख हैं।
- रेबेका ग्रिनस्पैन अंकटाड (UNCTAD) की प्रमुख हैं।
- मैकी सॉल सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति हैं।
- राफेल ग्रोसी IAEA के प्रमुख हैं।

स्ट्रोक पर विश्व स्वास्थ्य सभा का संकल्प

संदर्भ: मई 2026 में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने स्ट्रोक पर अपना पहला संकल्प पारित किया, जिसमें इसे एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में मान्यता दी गई। 'स्ट्रोक के बोझ को कम करना' शीर्षक वाला यह संकल्प फरवरी 2026 में WHO कार्यकारी बोर्ड में चिली, मिस्र, जॉर्जिया, फिलिस्तीन, पैराग्वे और ट्यूनीशिया द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह स्ट्रोक रजिस्ट्री, स्ट्रोक इकाइयों, पुनर्वास और टेलीमेडिसिन का आह्वान करता है, तथा WHO को तकनीकी मार्गदर्शन विकसित करने का अधिदेश देता है।

□ मुख्य बिंदु

- संकल्प का शीर्षक है 'स्ट्रोक के बोझ को कम करना: रोकथाम, तीव्र देखभाल, पुनर्वास और स्वास्थ्य-प्रणाली की तत्परता को सुदृढ़ करना'।
- इसे फरवरी 2026 में WHO कार्यकारी बोर्ड के 158वें सत्र में चिली, मिस्र, जॉर्जिया, फिलिस्तीन, पैराग्वे और ट्यूनीशिया द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- यह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और डिस्लिपिडेमिया (रक्त में वसा का असंतुलन) के जनसंख्या-स्तरीय नियंत्रण पर बल देता है, और स्ट्रोक-सक्षम सुविधाओं को परिभाषित करता है।
- यह राष्ट्रीय स्ट्रोक रजिस्ट्री, स्ट्रोक इकाइयों, पुनर्वास और टेलीमेडिसिन का आह्वान करता है।
- WHO को सदस्य देशों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन विकसित करने का अधिदेश दिया गया है।
- भारत में स्ट्रोक के लगभग 7 में से 1 रोगी की आयु 45 वर्ष से कम होती है और केवल 5 में से 1 रोगी समय पर अस्पताल पहुँचता है।

स्वीडन, नॉर्वे में मोदी और भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने 17-18 मई को स्वीडन और 18-19 मई 2026 को नॉर्वे की यात्रा की। स्वीडन के साथ संबंध सामरिक साझेदारी और नॉर्वे के साथ हरित सामरिक साझेदारी में बदले, जबकि उन्होंने ओस्लो में तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

□ स्वीडन

- यह आठ वर्षों में उनकी पहली यात्रा थी; पिछली यात्रा अप्रैल 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए हुई थी।
- संबंधों को सामरिक साझेदारी में उन्नत किया गया और 2026-2030 के लिए संयुक्त कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।
- 2025 में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब डॉलर था, और 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियाँ भारत में कार्यरत हैं।

□ नॉर्वे

- यह 1983 में इंदिरा गांधी के बाद 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्वतंत्र द्विपक्षीय यात्रा थी।
- हरित सामरिक साझेदारी चार स्तंभों पर आधारित है: स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु सहनीयता, नीली अर्थव्यवस्था और हरित नौवहन।
- समझौता ज्ञापनों में ISRO और नॉर्वे अंतरिक्ष एजेंसी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल स्वास्थ्य और AI अनुसंधान शामिल थे।
- नॉर्वे ने घोषणा की कि वह हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative) में शामिल होगा।
- भारत के आर्कटिक स्टेशन हिमाद्रि ने 2008 से अब तक 400 से अधिक वैज्ञानिकों की मेज़बानी की है।
- मोदी को राजा हेराल्ड पंचम से रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ।

□ तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

- इसमें नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेताओं ने भाग लिया।

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसे देश हैं जो नॉर्डिक समूह के साथ शिखर-स्तर पर संवाद करते हैं।
- पहले के शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित हुए थे।

हिंद महासागर संवाद और IORA

संदर्भ: हिंद महासागर संवाद, एक ट्रैक 1.5 सम्मेलन, का सह-आयोजन IORA और भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने किया तथा इसका आयोजन ICWA ने मई 2026 में दिल्ली में किया, जिसमें पश्चिम एशिया का युद्ध चिंताओं पर हावी रहा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसका गठन 1997 में हुआ, के 23 सदस्य देश और 12 संवाद साझेदार हैं, और भारत 2025-2027 के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहा है। IORA भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

□ मुख्य बिंदु

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का गठन 1997 में हुआ था और इसके 23 सदस्य देश तथा 12 संवाद साझेदार हैं। भारत 2025-2027 के लिए IORA की अध्यक्षता कर रहा है।
- पाकिस्तान को कभी सदस्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि भारत को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) का दर्जा देने से उसका इनकार चार्टर के संप्रभु समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- IORA भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण और हिंद-प्रशांत रणनीति का समर्थन करता है।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, मत्स्य पालन, आपदा जोखिम प्रबंधन, पर्यटन, शैक्षणिक सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तीकरण शामिल हैं।

IMEC, CPEC 2.0 और चर्चित क्षेत्र

संदर्भ: पश्चिम एशियाई संघर्ष ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के तर्क को मजबूत किया है, साथ ही उसे जटिल भी बनाया है, और चीन तथा पाकिस्तान CPEC 2.0 को तेज़ करने पर सहमत हुए; लिपुलेख और पद्मा बैराज जैसे सीमा बिंदु भी चर्चा में रहे।

□ IMEC

- IMEC की घोषणा भारत की अध्यक्षता में 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी; हस्ताक्षरकर्ता भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ हैं।
- इसमें भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ने वाला पूर्वी गलियारा और खाड़ी से यूरोप तक उत्तरी गलियारा है।
- अनुमान है कि यह परिवहन समय में 40 प्रतिशत और रसद लागत में 30 प्रतिशत की कमी करेगा।
- जोखिमों में ईरान संघर्ष, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट व्यवधान और इज़राइल-अरब संबंधों में तनाव शामिल हैं।

□ CPEC

- CPEC चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की प्रमुख परियोजना है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई, और यह ग्वादर बंदरगाह को शिनजियांग के काशगर से जोड़ती है।
- ग्वादर बंदरगाह का औपचारिक उद्घाटन 2016 में हुआ था।
- भारत CPEC का विरोध करता है क्योंकि यह पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरता है।

□ चर्चित क्षेत्र

- बांग्लादेश ने राजबाड़ी जिले में पद्मा बैराज को मंजूरी दी, जबकि 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है।
- उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत-चीन सीमा व्यापार छह वर्षों बाद फिर से शुरू होगा।
- भारत-चीन व्यापार के अन्य दर्रे हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला और सिक्किम में नाथू ला हैं।

एवियन में 52वाँ G7 शिखर सम्मेलन और भारत की साझेदारी भूमिका

संदर्भ: 52वाँ G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस की अध्यक्षता में एवियन-ले-बैंस में आयोजित हुआ, जिसका विषय था: नई साझेदारियाँ गढ़ना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण। भारतीय प्रधानमंत्री विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने दाता-प्राप्तकर्ता मॉडल के बजाय एकजुटता पर आधारित साझेदारियों की वकालत की।

□ शिखर सम्मेलन के परिणाम

- नेताओं ने विकास वित्त और ऋण प्रबंधन में सुधार का आह्वान किया, जिसमें IMF-विश्व बैंक के 3-स्तंभीय दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना शामिल है।
- उन्होंने डीआरसी (DRC) और युगांडा में बुंदीबुग्यो इबोला प्रकोप के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया।
- उन्होंने कैंसर अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिसमें फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु दर घटाना और बाल कैंसर डेटा तक पहुँच में सुधार करना शामिल है।
- G7 ने अमेरिका-ईरान परमाणु समझौते का स्वागत किया और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत का समर्थन किया।
- समुद्री मादक पदार्थ तस्करी और संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाहों से निपटने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क की घोषणा की गई।

□ शिखर सम्मेलन में भारत

- भारत ने कहा कि विश्व संसाधनों की नहीं बल्कि विश्वास की कमी का सामना कर रहा है, जिसे व्यापार और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग ने और बढ़ा दिया है।
- भारत के दृष्टिकोण को वसुधैव कुटुंबकम और मानवता-प्रथम सोच पर आधारित बताया गया।

- प्रधानमंत्री मोदी आउटरीच सत्र और कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल हुए।
- उन्होंने भारत-अफ्रीका सहयोग को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।
- भारत ने बाधित व्यापार मार्गों पर चिंता व्यक्त की, सुरक्षित समुद्री मार्गों और नाविकों की सुरक्षा का आह्वान किया, तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया।

कृषि पर ब्रिक्स इंदौर घोषणा-पत्र

संदर्भ: भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत इंदौर में 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ने सर्वसम्मति से ब्रिक्स इंदौर घोषणा-पत्र अपनाया; यह पहली ऐसी बैठक थी जिसमें सदस्यों के साथ साझेदार देश भी शामिल हुए। अलग से, संयुक्त यूनेस्को नामांकनों पर चर्चा के लिए दूसरा ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह वाराणसी में मिला।

□ मुख्य बिंदु

- जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC शब्द गढ़ा, और पहला BRIC शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 के फोर्टालेज़ा शिखर सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की अधिकृत पूंजी के साथ की गई, साथ ही 100 अरब डॉलर की आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement) भी बनाई गई।
- साझेदार देश बेलारूस, बोलीविया, कज़ाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम हैं।
- ब्रिक्स का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।

□ इंदौर घोषणा-पत्र

- यह चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित करता है: खाद्य सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और प्रौद्योगिकी।
- खाद्य सुरक्षा में किसान-केंद्रित शासन, आय की सुदृढ़ता और पोषण पर बल दिया गया है।
- व्यापार में स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाएँ और समन्वय, जलवायु में पुनर्योजी और जलवायु-सहिष्णु खेती, तथा प्रौद्योगिकी में खाद्य प्रणालियों में नवाचार शामिल हैं।
- विषय था: लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण।
- बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर एक वैश्विक मंच मुख्यतः वर्चुअल रूप से कार्य करेगा, जिसका समन्वय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण करेगा।
- सदस्यों ने प्रस्तावित ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज का समर्थन किया और बीज, आनुवंशिक संसाधन तथा कृषि आदानों के नेटवर्क ब्रिक्स एग्रिन (BRICS AGRIN) की शुरुआत की।
- कृषि-पारिस्थितिकी और पुनर्योजी कृषि पर उत्कृष्टता केंद्रों के ब्रिक्स नेटवर्क का समन्वय प्रारंभ में ICAR-IIFSR, मोदीपुरम करेगा।
- डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क का समन्वय प्रारंभ में IIT दिल्ली करेगा।

□ संस्कृति कार्य समूह

- ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी में हुई और उसमें भारत-चीन प्रस्ताव सहित संयुक्त नामांकनों पर विचार किया गया।
- साझा विरासत में इंडोनेशिया के साथ रामायण परंपराएँ और चीन के साथ बौद्ध ग्रंथ शामिल हैं।

गाज़ा पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक जाँच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इज़राइल ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया, जिससे नरसंहार का आशय स्थापित होता है। इस आयोग की अध्यक्षता भारत के न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर कर रहे हैं।

□ मुख्य बिंदु

- अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्र और इज़राइल पर आयोग की स्थापना मई 2021 में UNHRC के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर 2023 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए।
- संयुक्त राष्ट्र आयोग दंड नहीं लगा सकता, लेकिन उसके निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य बन सकते हैं।

□ कानून में नरसंहार

- 1948 के नरसंहार अभिसमय का अनुच्छेद II नरसंहार को किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के आशय से किए गए कृत्यों के रूप में परिभाषित करता है।
- पाँच कृत्य सूचीबद्ध हैं, जिनमें हत्या करना, गंभीर क्षति पहुँचाना, समूह को नष्ट करने के लिए जीवन की परिस्थितियाँ थोपना, जन्म को रोकना और बच्चों को जबरन स्थानांतरित करना शामिल हैं।
- यही परिभाषा रोम संविधि के अनुच्छेद 6 में भी दी गई है।
- आशय सिद्ध करना मुख्य बाधा है।

तीस्ता परियोजना पर चीन-बांग्लादेश वार्ता

संदर्भ: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को जून 2026 की अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनरुद्धार परियोजना के लिए चीन से आश्वासन मिला। इस कदम से भारत के लिए रणनीतिक चिंताएँ बढ़ती हैं।

□ मुख्य बिंदु

- बांग्लादेश जल विकास बोर्ड और पावरचाइना (POWERCHINA) ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन का विस्तार किया।
- तीस्ता में शीतकालीन प्रवाह दिसंबर से फरवरी के बीच तेज़ी से घट जाता है, जब धान और सब्जियों की बुवाई होती है।
- तीस्ता का उद्गम सिक्किम में 5,100 मीटर की ऊँचाई पर स्थित चोलामू (त्सो ल्हामो) झील से होता है; पश्चिम बंगाल में गजोलडोबा बैराज एक प्रमुख भारतीय संरचना है।

- 2010 का एक अंतरिम जल-बँटवारा समझौता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की आपत्तियों के कारण 2011 में विफल हो गया।
- नीलफामारी और रंगपुर के निकट स्थित परियोजना क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी गलियारे के समीप है।

नई दिल्ली में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

संदर्भ: 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई 2026 को नई दिल्ली में जयशंकर, रुबियो, मोतेगी और पेनी वोंग की उपस्थिति में आयोजित हुई। इसमें संपर्क, समुद्री निगरानी, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर पहलों की घोषणा हुई, परंतु संयुक्त वक्तव्य में अगले नेताओं के शिखर सम्मेलन के मेज़बान या तिथि का उल्लेख नहीं था।

□ मुख्य बिंदु

- क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी शुरुआत 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद राहत कार्यों के समन्वय के रूप में हुई थी। शिंजो आबे ने 2007 में इसे औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया और 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया।
- क्वाड ने 2026 तक फिजी सहित प्रशांत द्वीप मंच के सभी देशों को समुद्र के भीतर बिछी केबलों से जोड़ने और क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के अंतर्गत फिजी में बंदरगाह अवसंरचना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
- हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग (IPMSC) पहल, जो आरंभ में हिंद महासागर पर केंद्रित है, सदस्यों की संयुक्त निगरानी क्षमताओं का उपयोग करके वास्तविक समय में सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगी।
- हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर एक क्वाड पहल प्रौद्योगिकी, नीति, बाज़ार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों में सहयोग के क्षेत्र चिह्नित करेगी।
- क्वाड महत्वपूर्ण खनिज पहल ढाँचा खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में निवेश के समन्वय का 20 अरब डॉलर का प्रयास है।
- भारत विलिंगटन घोषणा-पत्र के अंतर्गत तटरक्षक-नेतृत्व वाले क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की मेज़बानी करेगा, जिसके पहले मिशन का संचालन पलाऊ से गुआम तक हुआ था।
- सदस्यों ने अगली पीढ़ी के संचार मानकों, विशेष रूप से 6G, पर सहयोग की घोषणा की।
- बैठक के इतर एक अलग भारत-अमेरिका सामरिक महत्वपूर्ण खनिज सहयोग ढाँचे पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसके छह नेता-स्तरीय कार्य समूह हैं: जलवायु, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, साइबर, स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी, अवसंरचना और अंतरिक्ष।
- क्वाड का कोई स्थायी सचिवालय, संधि-दायित्व या समर्पित कोष नहीं है।

□ नेताओं के शिखर सम्मेलन को लेकर अनिश्चितता

- छठा क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में विल्मिंगटन, डेलावेयर में आयोजित हुआ था।
- भारत में होने वाला शिखर सम्मेलन 2024 से विलंबित है, और संयुक्त वक्तव्य में मेज़बान या तिथि का उल्लेख नहीं किया गया।

पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने वाला अमेरिका-ईरान ज्ञापन

संदर्भ: अमेरिका और ईरान ने 14 खंडों वाले एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, अमेरिका ने वर्साय के महल में और ईरान ने तेहरान में, जिससे 40 दिनों का युद्ध और 60 से अधिक दिनों की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त हुई। यह अंतिम समझौते पर वार्ता के लिए 60 दिनों की अवधि खोलता है।

□ मुख्य बिंदु

- लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्धविराम, और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता।
- ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटा ली गई है और होर्मुज़ के निकट शेष विमानवाहक पोत समूह वहाँ से हटेंगे।
- ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों के लिए बिना शर्त पारगमन मार्ग की गारंटी देता है; ईरान और ओमान मिलकर इसके भावी प्रशासन को परिभाषित करेंगे।
- ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कोष और अंतिम समझौते में पूर्ण प्रतिबंध राहत।
- 100 अरब डॉलर से अधिक की जमी हुई ईरानी संपत्तियाँ मुक्त की जाएँगी, जिनमें से 12 अरब डॉलर कतर और यूएई के बैंकों के माध्यम से पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

□ परमाणु और संस्थागत शर्तें

- ईरान ने दोहराया कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और 60 दिनों तक परमाणु यथास्थिति बनाए रखेगा।
- ईरान अपने 60% संवर्धित यूरेनियम भंडार को बनाए रखेगा; दोनों पक्ष IAEA की निगरानी में संवर्धित सामग्री को डाउनब्लेंड करने पर सहमत हुए।
- 60 दिनों की अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है, एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा और अंतिम समझौते का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा किया जाना है।

□ होर्मुज़ नौवहन शुल्क

- UNCLOS के अनुच्छेद 37 से 44 अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्यों को नियंत्रित करते हैं और ऐसे पारगमन मार्ग की गारंटी देते हैं जिसे बाधित या निलंबित नहीं किया जा सकता।
- कोर्फू चैनल मामले (यूके बनाम अल्बानिया, 1949) में यह निर्णय दिया गया कि शांति काल में जहाज़ों को अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से गुज़रने का अधिकार प्राप्त है।

➤ ईरान ने प्रति-पारगमन टोल हटा दिया, लेकिन नौवहन शुल्क और पर्यावरण संरक्षण शुल्क जारी रखा है, जिससे कानूनी प्रश्न उठते हैं।

पीओके में विरोध प्रदर्शन और आरक्षित सीटों का विवाद

संदर्भ: स्थानीय चुनावों से एक महीने पहले पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 15 लोग मारे गए। तात्कालिक कारण पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय था जिसमें 53 सदस्यीय पीओके विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों को बरकरार रखा गया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जो व्यापारियों, पेशेवरों और कार्यकर्ताओं का गठबंधन है।

➤ अशांति की शुरुआत 2023 में बिजली के बिलों, गेहूँ सब्सिडी की कमी और नौकरशाही के वर्चस्व को लेकर हुई थी।

➤ 53 सीटों में से 33 पर स्थानीय मतदाता सीधे चुनाव करते हैं; 12 शरणार्थी सीटें हैं जिनके लिए मतदान पीओके के बाहर होता है, जबकि 5 महिलाओं के लिए, 1 उलेमा के लिए, 1 प्रवासी कश्मीरियों के लिए और 1 तकनीकी विशेषज्ञों के लिए हैं।

➤ भारत ने पुलिस की बर्बरता की निंदा की है और जवाबदेही की माँग की है।

□ **भारत की समान स्थिति**

➤ भारत जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें रखता है, लेकिन वे रिक्त रहती हैं, जबकि पाकिस्तान संगत सीटों को भरता है।

प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स की राजकीय यात्रा

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स की राजकीय यात्रा ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया और राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने को चिह्नित किया। इसने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण को भी मज़बूत किया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत ने 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की: 125 मिलियन डॉलर रुपया ऋण सीमा (लाइन ऑफ क्रेडिट) के रूप में और 50 मिलियन डॉलर अनुदान के रूप में।

➤ समझौता ज्ञापनों में UPI, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, एक्ज़िम बैंक सहयोग, नौवहन, अंतरिक्ष, प्रत्यर्पण संधि और ऋण सीमा शामिल थे।

➤ भारत ने तीव्र आक्रमण पोत पीएस लेस्पवार सेशेल्स तटरक्षक बल को उपहार में दिया और पीएस ज़ोरोस्टर की मरम्मत एवं नवीनीकरण पर सहमति जताई।

➤ मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और उन्हें 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न' सम्मान प्राप्त हुआ।

➤ सेशेल्स ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल होने का निर्णय लिया।

➤ 29 जून 2026 को सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में असम रेजिमेंट की 32 कर्मियों की एक टुकड़ी ने भाग लिया।

भारत-ओमान CEPA लागू हुआ

संदर्भ: भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 1 जून 2026 को लागू हुआ। यह भारतीय निर्यातकों को व्यापक शुल्क-मुक्त पहुँच देता है और खाड़ी, हिंद महासागर तथा पूर्वी अफ्रीका का प्रवेश द्वार खोलता है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 8.94 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.18 अरब डॉलर हो गया।

➤ CEPA से पहले MFN के अंतर्गत केवल 15.33% भारतीय निर्यात ओमान में शुल्क-मुक्त प्रवेश करते थे।

➤ ओमान अब अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच देता है, जो मूल्य के आधार पर भारत के 99.38% निर्यात को कवर करती हैं।

➤ ओमान ने लेखांकन, इंजीनियरिंग, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परामर्श के क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के लिए बाध्यकारी बाज़ार पहुँच प्रतिबद्धताएँ कीं।

➤ यह समझौता कंपनी-अंतर्गत स्थानांतरित कर्मियों के कोटे को बढ़ाता है और आयुष तथा पारंपरिक चिकित्सा के प्रावधान शामिल करता है।

➤ भारत 77.79 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क उदारीकरण प्रदान करता है, जो ओमान से 94.81 प्रतिशत आयात को कवर करती हैं, जबकि डेयरी, तिलहन और अनाज को संरक्षित रखा गया है।

➤ ओमान भारतीय कंपनियों को प्रमुख सेवाओं में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति भी देता है।

□ **रणनीतिक अवस्थिति**

➤ सोहार होर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट एक औद्योगिक केंद्र है।

➤ दुक़्म अरब सागर पर स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जहाँ भारत को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र तक पहुँच प्राप्त है।

➤ सलालाह खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक प्रमुख पारपोतन (ट्रांसशिपमेंट) केंद्र है।

भारत-फ्रांस नीस शिखर सम्मेलन और नवाचार रोडमैप 2030

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से फ्रांस की अपनी सातवीं आधिकारिक यात्रा की, और एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के रास्ते में नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता की। फरवरी 2026 में संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद यह

पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन था, और 14 जून 2026 को भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030 को अपनाया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- एक उच्च-स्तरीय तंत्र का लक्ष्य पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 16 अरब डॉलर से दोगुना कर 32 अरब डॉलर करना होगा।
- फ्रांस यूरोपीय संघ में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ 2025-26 में 15.81 अरब डॉलर का व्यापार हुआ।
- भारत-फ्रांस आर्थिक सुरक्षा संवाद की शुरुआत की जाएगी।
- कानपुर में वैमानिकी कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- दोनों देश उन्नत रक्षा प्लेटफ़ॉर्मों का सह-डिज़ाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन करने पर सहमत हुए।
- ISRO और CNES मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता में सहयोग को गहरा करेंगे।
- भारत का शांति (SHANTI) अधिनियम लघु और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों में सहयोग की गुंजाइश खोलता है।
- फ्रांस ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त हवाई अड्डा पारगमन को लागू किया।

□ **नवाचार रोडमैप 2030**

- यह 2026 के भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष, होराइज़न 2047 रोडमैप, विकसित भारत 2047 और फ्रांस 2030 के अनुरूप है।
- विश्वसनीय एआई पर स्तंभ I में एआई शासन, ऑनलाइन बाल सुरक्षा और भारत के DEPA को फ्रांस के विश्वसनीय डेटा स्थलों से जोड़ने वाला सुरक्षित डेटा साझाकरण शामिल है।
- शैक्षणिक गतिशीलता पर स्तंभ II 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों की मेजबानी के फ्रांस के लक्ष्य का समर्थन करता है और 2018 के योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता ढाँचे का विस्तार करता है।
- प्रौद्योगिकीय संप्रभुता पर स्तंभ III में इनोएक्सचेंज ब्रिज स्टार्टअप गलियारा, भारत-फ्रांस नवाचार नेटवर्क (IFIN) डिजिटल उपकरण, और MSDE के साथ कानपुर में वैमानिकी प्रशिक्षण परिसर शामिल हैं।
- वैश्विक स्वास्थ्य पर स्तंभ IV में सहमति-आधारित स्वास्थ्य डेटा साझाकरण के लिए ICMR और फ्रांस के हेल्थ डेटा हब का एक पायलट शामिल है।
- नीस और पेरिस के हवाई अड्डों पर UPI का विस्तार किया जाएगा।

भारत-स्लोवाकिया व्यापक साझेदारी

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी की ब्रातिस्लावा यात्रा, जो 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया। रक्षा, प्रौद्योगिकी, श्रम गतिशीलता और आतंकवाद-रोधी क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

□ **मुख्य बिंदु**

- चेकोस्लोवाकिया के शांतिपूर्ण विघटन के बाद 1993 में भारत के स्लोवाकिया के साथ औपचारिक संबंध शुरू हुए। स्लोवाकिया यूरोपीय संघ (EU) और नाटो (NATO) का सदस्य है।
- रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र का उद्देश्य उपकरणों का संयुक्त विकास और उत्पादन है।
- प्राथमिकता वाले व्यापार क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक समझौता ज्ञापन और एक स्लोवाक विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर इंडिया चेयर स्थापित करने पर सहमति बनी।
- श्रम प्रवासन पर एक समझौता ज्ञापन श्रमिकों की संरचित आवाजाही का प्रावधान करता है।
- 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 1.28 अरब यूरो तक पहुँच गया।

महत्वपूर्ण खनिज: भारत-अमेरिका ढाँचा, भारत-यूके वेधशाला

संदर्भ: भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ढाँचे पर हस्ताक्षर किए, और भारत-यूके महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला की औपचारिक शुरुआत की।

□ **भारत-अमेरिका ढाँचा**

- यह ढाँचा पैक्स सिलिका और फोर्ज (FORGE) जैसी पूर्ववर्ती अमेरिका-नेतृत्व वाली पहलों पर आधारित है।
- इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए वित्तपोषण, पुनर्चक्रण और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण शामिल है।
- दुर्लभ मृदा तत्व 17 तत्व हैं: स्कैंडियम, यिट्रियम और 15 लैंथेनाइड।
- चीन के पास 49 प्रतिशत भंडार हैं, वह 69 प्रतिशत दुर्लभ मृदा का उत्पादन करता है और 90 प्रतिशत प्रसंस्करण एवं परिशोधन को नियंत्रित करता है।
- चीन गैलियम परिशोधन के 99 प्रतिशत और वैश्विक लिथियम परिशोधन के 58 प्रतिशत पर भी नियंत्रण रखता है।

□ **भारत-यूके वेधशाला**

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला (GSCO) की घोषणा 2025 की भारत-यूके प्रधानमंत्रियों की वार्ता के दौरान की गई थी और मार्च 2026 में एक अनुसंधान सहयोग समझौते द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया।
- यह TEXMiN (TTRP, DST), IIT (ISM) धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल है।
- यह वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी करेगी और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का समर्थन करेगी।

म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा

संदर्भ: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की, जिसके मुख्य विषय संपर्क, व्यापार और सुरक्षा सहयोग थे। दोनों पक्षों ने कालादान बहु-मॉडल परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई, रुपया-क्यात निपटान तंत्र सहित व्यापार को सुगम बनाने पर सहमति जताई, और म्यांमार ने आश्वासन दिया कि उसकी भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा।

□ **मुख्य बिंदु**

- उन्होंने यात्रा की शुरुआत बोधगया से की, जहाँ उन्होंने महाबोधि मंदिर, महाबोधि ध्यान केंद्र और सुजाता मंदिर में प्रार्थना की।
- दोनों पक्षों ने मिज़ोरम को सित्तवे बंदरगाह से जोड़ने वाली कालादान बहु-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को पूरा करने के महत्व की पुनः पुष्टि की।
- वे रुपया-क्यात निपटान तंत्र सहित व्यापार को सुगम बनाने पर सहमत हुए।
- म्यांमार ने आश्वासन दिया कि उसकी भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा।
- म्यांमार के विद्यार्थियों के लिए मेकांग गंगा ICCR छात्रवृत्तियाँ 2026 से 36 से बढ़कर 100 हो जाएँगी।
- रुपया-क्यात निपटान तंत्र 2024 में क्रियाशील किया गया था।
- भारत-म्यांमार सीमा 1,643 किमी लंबी है, और परियोजनाओं में भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कालादान बहु-मॉडल परियोजना शामिल हैं।

वैश्विक शांति सूचकांक 2026 और मानवाधिकार गठबंधन

संदर्भ: जून 2026 में, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत 163 देशों में 127वें स्थान पर रहा, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने UDHR की 80वीं वर्षगांठ से पहले मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की। आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा और रूस सबसे निचले स्थान पर रहा।

□ **वैश्विक शांति सूचकांक 2026**

- यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष पहले स्थान पर रहा, उसके बाद न्यूज़ीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड रहे।
- रूस सबसे निचले स्थान पर रहा, उससे ठीक पहले सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यूक्रेन और इज़राइल रहे।
- यह सामाजिक सुरक्षा, जारी संघर्ष और सैन्यीकरण के 23 संकेतकों का उपयोग करता है।

□ **मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन**

- इसे OHCHR ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) की 10 दिसंबर 2028 को होने वाली 80वीं वर्षगांठ तक चलने वाले दीर्घकालिक प्रयास के रूप में शुरू किया।
- इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं: कल्पना, संवाद और कार्रवाई।
- UDHR को 1948 में अपनाया गया था।

16वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन

संदर्भ: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आईं, जो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत की पहली यात्रा थी। शिखर सम्मेलन ने विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ किया, आर्थिक सुरक्षा पर एक संयुक्त घोषणा संपन्न की तथा रक्षा, AI, ऊर्जा और गतिशीलता में सहयोग की घोषणा की।

□ **मुख्य बिंदु**

- संबंध 1952 में स्थापित हुए और 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी में उन्नत किए गए। वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर था, जबकि 2035 तक जापानी निवेश का लक्ष्य 67 अरब डॉलर है।
- आर्थिक सुरक्षा पर एक संयुक्त घोषणा में अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), महत्वपूर्ण खनिज, ICT और AI, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधियाँ शामिल हैं।
- AI साझेदारी को रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया; इंडियाAI मिशन को जापान की GENIAC पहल से जोड़ा गया है।
- पहली भारत-जापान रक्षा सह-विकास परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न (UNICORN) से संबंधित है।
- नेक्स्ट जेनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप को क्रियाशील किया गया; इसमें रेलवे, ऑटोमोबाइल, विमानन, जहाज़ निर्माण, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।
- सहकारी बायोगैस फॉर ग्रोथ पहल 1,000 बायोगैस और उर्वरक संयंत्र बनाएगी, और ओडिशा में एक स्वच्छ अमोनिया परियोजना को सहायता मिलेगी।
- नेक्स्ट जेनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप का लक्ष्य E10 शिंकानसेन रेलगाड़ियों का उपयोग करते हुए मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल के प्राथमिकता वाले खंड पर 2027 में वाणिज्यिक संचालन शुरू करना है।
- जापान ने अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की घोषणा की।
- भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय और जापान के METI के बीच ऊर्जा सुदृढ़ता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए।

- भूविज्ञान और खनिज अन्वेषण, बैटरियों, तथा औषधियों और चिकित्सा उपकरणों पर सहयोग ज्ञापनों (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत-जापान सहकारी बायोगैस फॉर ग्रोथ पहल का लक्ष्य डेयरी सहकारी नेटवर्क का उपयोग करते हुए 1,000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करना है।
- रक्षा सहभागिता में ACSA, 2+2 संवाद तथा अभ्यास जिमेक्स (JIMEX), मालाबार और धर्म गार्जियन शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने पाँच वर्षों में 5 लाख द्विपक्षीय आदान-प्रदान का लक्ष्य रखा है, जिनमें जापान जाने वाले 50,000 कुशल भारतीय कामगार शामिल हैं।

59वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक, ARF और EAS

संदर्भ: मनीला में आसियान के नेतृत्व वाली मंत्रिस्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित हुई, जहाँ फिलीपींस 2026 में 'नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टुगेदर' विषय के अंतर्गत आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। इनमें 59वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक, 33वाँ आसियान क्षेत्रीय मंच और 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल थीं।

□ **मुख्य बिंदु**

- आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी, इसके तिमोर-लेस्ते सहित 11 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ARF की स्थापना 1994 में हुई थी और इसके 27 प्रतिभागी हैं; भारत 1996 से इसका सदस्य है।
- मंत्रियों ने आसियान समुदाय विज़न 2045 के क्रियान्वयन का पहला वर्ष पूरा होने का उल्लेख किया।
- मैत्री और सहयोग संधि के अंतर्गत उच्च संविदाकारी पक्षों के साथ आसियान के जुड़ाव के लिए दिशानिर्देश अपनाए गए; लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन ने TAC को स्वीकार किया (उसमें शामिल हुए)।
- तुर्किये आसियान का 12वाँ संवाद साझेदार बना; जर्मनी और कतर क्षेत्रीय संवाद साझेदार बने।
- उन्होंने वर्ष के भीतर चीन के साथ दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लक्ष्य की पुनः पुष्टि की और म्यांमार पर पाँच-सूत्रीय सहमति का समर्थन किया।
- 33वें ARF ने मनीला कार्य योजना 2026-2036 अपनाई।
- EAS की शुरुआत 2005 में हुई थी और इसमें 19 प्रतिभागी हैं; भारत शुरुआत से ही इसका सदस्य है।
- 2026 आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष है; भारत कोच्चि में 7वें EAS समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन और लोथल में EAS समुद्री विरासत महोत्सव की मेज़बानी करेगा।

अमेरिका-इज़राइल-लेबनान त्रिपक्षीय रूपरेखा

संदर्भ: जुलाई 2026 में अमेरिका, इज़राइल और लेबनान ने इज़राइल तथा लेबनान के बीच शत्रुता समाप्त करने और हिज़बुल्लाह को चरणबद्ध रूप से निःशस्त्र करने के लिए एक त्रिपक्षीय रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए, हालाँकि हिज़बुल्लाह ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया है। हिज़बुल्लाह द्वारा हथियार छोड़ने की पुष्टि होने पर लेबनानी सेना पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लेगी, इज़राइली सेनाएँ क्रमशः पीछे हटेंगी, और अमेरिका-समर्थित सैन्य समन्वय समूह इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

□ **मुख्य बिंदु**

- हिज़बुल्लाह द्वारा हथियार और सैन्य अवसंरचना छोड़ने की पुष्टि होने पर लेबनानी सेना पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लेगी।
- इज़राइल रक्षा बल दक्षिणी लेबनान के अधिकृत क्षेत्रों से क्रमशः पीछे हटेंगे।
- अमेरिका-समर्थित सैन्य समन्वय समूह इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा।
- अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 100 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता और लेबनानी सशस्त्र बलों के लिए 30 मिलियन डॉलर से अधिक देने का वचन दिया।
- अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अंतर्गत 30 वर्षीय असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल के बिना 20 प्रतिशत तक संवर्धन की अनुमति देता है।

अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में चाबहार बंदरगाह

संदर्भ: ईरान में भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंध-छूट 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गई और अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच इसके नवीनीकरण के कोई संकेत नहीं हैं। संघर्ष के दौरान बंदरगाह पर अमेरिकी हमले से भारत में चिंता बढ़ी, परंतु विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, जिसका संचालन भारत करता है, को कोई क्षति नहीं पहुँची।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारत और ईरान ने 2003 में पहली बार इस बंदरगाह को विकसित करने पर सहमति जताई। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने तेहरान की यात्रा की और 50 करोड़ डॉलर देने का वचन दिया।
- चाबहार दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है और इसके दो टर्मिनल हैं, शहीद कलंतरी और शहीद बेहेश्ती; भारत शहीद बेहेश्ती का विकास करता है।
- यह भारत को पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
- पाकिस्तान का चीन-वित्तपोषित ग्वादर बंदरगाह, जो नवंबर 2016 में खुला, चाबहार से लगभग 140 किमी पूर्व में स्थित है।

- चाबहार अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का दक्षिणी केंद्र (नोड) है, जो ईरान के माध्यम से रूस और भारत को जोड़ने वाला 7,200 किमी लंबा नेटवर्क है।
- चाबहार को पिछले वित्तीय वर्ष में ₹400 करोड़ मिले थे, परंतु केंद्रीय बजट 2026-27 में कुछ नहीं मिला।
- अमेरिका 2018 में JCPOA से बाहर हो गया और प्रतिबंध पुनः लगा दिए, परंतु भारत को छूट मिली।

अवसर के महासागर के रूप में हिंद महासागर

संदर्भ: सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पारस्परिक सम्मान, विश्वास और साझा समुद्री उत्तरदायित्व पर आधारित हिंद महासागर को 'अवसर का महासागर' बनाने के भारत के दृष्टिकोण का वर्णन किया।

□ हिंद महासागर क्यों महत्वपूर्ण है

- भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार मात्रा के अनुसार और लगभग 70 प्रतिशत मूल्य के अनुसार समुद्र के रास्ते होता है।
- भारत की तटरेखा लगभग 11,099 किमी है और EEZ 23 लाख वर्ग किमी से अधिक है, जो 13 तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 लाख से अधिक मछुआरों का भरण-पोषण करता है।
- इस क्षेत्र में तीन मुख्य अवरोध-बिंदु (चोकपॉइंट) हैं: मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज़ जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब।
- भारत अपनी लगभग 85 प्रतिशत कच्चे तेल की और 51 प्रतिशत गैस की आवश्यकता का आयात करता है।
- बंगाल की खाड़ी में वैश्विक चक्रवातों का केवल 5 प्रतिशत आता है, फिर भी वहाँ चक्रवातों से होने वाली 80 प्रतिशत से अधिक मौतें दर्ज की जाती हैं।

□ भारत का दृष्टिकोण

- सागर (SAGAR) का विस्तार महासागर (MAHASAGAR: क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) के रूप में किया गया है।
- सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहायता करता है।
- भारत IORA, IPOI, बिम्सटेक (BIMSTEC), कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, IONS और क्वाड के माध्यम से जुड़ता है।
- ऑपरेशन सागर बंधु ने चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका को राहत पहुँचाई।

एक्ट ईस्ट नीति और आसियान केंद्रीयता

संदर्भ: जुलाई 2026 में क्वाड ने आसियान केंद्रीयता और हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक (AOIP) को 'अटूट समर्थन' दिया, जो एक ऐसी अवधारणा है जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति का आधार है। 2014 में 1991 की लुक ईस्ट नीति के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित एक्ट ईस्ट वाणिज्य, संस्कृति, संपर्क और क्षमता निर्माण पर आधारित है। 2019 में अपनाया गया AOIP हिंद और प्रशांत महासागरों को एक परस्पर जुड़े हुए स्थान के रूप में देखता है।

□ एक्ट ईस्ट नीति

- इसे 2014 में 1991 की लुक ईस्ट नीति के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया था।
- यह चार 'C' पर आधारित है: वाणिज्य (Commerce), संस्कृति (Culture), संपर्क (Connectivity) और क्षमता निर्माण (Capacity Building)।
- यह पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करती है।
- संपर्क परियोजनाओं में भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, जिसका लगभग 30 प्रतिशत भाग अधूरा है, और कालादान बहु-मॉडल परियोजना शामिल हैं।
- 2025-26 में भारत-आसियान व्यापार 128 अरब डॉलर था, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 45 अरब डॉलर का घाटा है।

□ आसियान केंद्रीयता और AOIP

- आसियान केंद्रीयता को सर्वप्रथम 2008 के आसियान चार्टर में संहिताबद्ध किया गया था और यह आसियान को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा ARF जैसे क्षेत्रीय मंचों के केंद्र में रखती है।
- हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक (AOIP) 2019 में अपनाया गया था और यह हिंद तथा प्रशांत महासागरों को एक परस्पर जुड़े हुए स्थान के रूप में देखता है।
- AOIP के चार प्राथमिकता वाले स्तंभ हैं: समुद्री सहयोग, संपर्क, संयुक्त राष्ट्र SDGs 2030 और आर्थिक सहयोग।

ऑपरेशन अमिस्ताद और भारत-वेनेज़ुएला संबंध

संदर्भ: जुलाई 2026 में भारत ने भूकंप-पीड़ित वेनेज़ुएला की सहायता के लिए मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया; स्पेनिश में 'अमिस्ताद' का अर्थ मित्रता है। भारतीय वायु सेना के दो C-17 विमान एक फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री ले गए। यह मैत्री, दोस्त, करुणा, सद्भाव और ब्रह्मा जैसे भारत के पूर्व HADR अभियानों में एक और कड़ी है, और मई 2026 में वेनेज़ुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया।

□ मुख्य बिंदु

- भारतीय वायु सेना के दो C-17 विमान एक फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री ले गए।
- भारत के पूर्व HADR अभियानों में मैत्री (नेपाल), दोस्त (तुर्किये और सीरिया), करुणा (म्यांमार), सद्भाव (म्यांमार, लाओस और वियतनाम) तथा ब्रह्मा (म्यांमार) शामिल हैं।

□ **भारत-वेनेज़ुएला संबंध**

➤ वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-वेनेज़ुएला व्यापार 678.94 मिलियन डॉलर था, जिसमें भारतीय निर्यात 210 मिलियन डॉलर का था।

➤ मई 2026 में वेनेज़ुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया।

नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन

संदर्भ: नाटो के 32 सदस्य देश 2025 के हेग शिखर सम्मेलन के बाद की प्रगति की समीक्षा के लिए तुर्किये के अंकारा में मिले। नेताओं ने अनुच्छेद 5 के अंतर्गत सामूहिक रक्षा की पुनः पुष्टि की और 2035 तक GDP का 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने की प्रतिबद्धता का समर्थन किया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ नाटो की स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि के माध्यम से हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। फिनलैंड (2023) और स्वीडन (2024) नवीनतम सदस्य हैं।

➤ सदस्यों ने वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

➤ हेग रक्षा प्रतिबद्धता 2035 तक GDP का न्यूनतम 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने की सीमा तय करती है, जो पहले की 2 प्रतिशत की प्रतिज्ञा से अधिक है।

➤ नेताओं ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अटूट समर्थन की घोषणा की।

➤ उन्होंने उच्च क्षमता वाले, यूरोप-व्यापी रक्षा औद्योगिक आधार का संकल्प लिया।

पैक्स सिलिका और हिंद-प्रशांत महासागर पहल

संदर्भ: भारत फरवरी 2026 में अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल हुआ और वाशिंगटन, डी.सी. में दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में 34 अन्य देशों के साथ AI अवसर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। अलग से, स्पेन भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल हुआ।

□ **पैक्स सिलिका**

➤ पैक्स सिलिका को अमेरिका ने 2025 में AI, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक गैर-बाध्यकारी रणनीतिक गठबंधन के रूप में शुरू किया था।

➤ यह किसी एक राष्ट्र, मुख्यतः चीन, पर दबावकारी निर्भरता को कम करने का प्रयास करता है।

➤ सदस्यों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, संयुक्त निवेश की संभावनाएँ तलाशना और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की रक्षा करना है।

➤ भारत फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इस पहल में शामिल हुआ।

➤ पैक्स सिलिका का उद्देश्य अर्धचालक और AI अवसंरचना, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, तथा कंप्यूटिंग और डेटा लॉजिस्टिक्स को कवर करने वाली एक सुरक्षित, नवाचार-आधारित प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।

➤ वर्तमान सदस्यों में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और इज़राइल शामिल हैं।

➤ भारत ने 2026 में भारत-जर्मनी अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी आशय घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए।

□ **हिंद-प्रशांत महासागर पहल**

➤ IPOI एक गैर-संधि-आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है जो मुक्त और स्वतंत्र हिंद-प्रशांत तथा नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है।

➤ भारत ने इसे 2019 में शुरू किया था, और इसे बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था।

➤ यह 2015 के भारत के सागर (SAGAR: क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण पर आधारित है।

➤ इसके सात स्तंभ हैं, जिनमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, क्षमता निर्माण एवं संसाधन साझाकरण, तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन शामिल हैं।

➤ यह AIIPOIP, हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक (AOIP) और हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचे (IPEF) के साथ अभिसरण में कार्य करती है।

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा की, जिससे भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया गया। समझौते अंतरिक्ष, खनिज, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, इस्पात और दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित थे तथा उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों की दो बैटरियाँ आपूर्ति करेगा और अस्त्र मिसाइल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; इंडोनेशिया अपने Su-30 बेड़े के लिए अस्त्र Mk 1 दृश्य सीमा से परे (बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज) वायु-से-वायु मिसाइलें आयात करने का समझौता करने वाला पहला देश है।

➤ सेल (SAIL) और पीटी क्रकटाउ स्टील ने स्टेनलेस-स्टील स्लैब के लिए संयुक्त उद्यम पर सहमति जताई।

➤ आईआईएम बैंगलोर पूर्वी जावा के मलंग स्थित सिंघासरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा।

➤ प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुर्णा प्राप्त हुआ।

➤ योग्यकार्ता स्थित प्रम्बानन मंदिर, जो 9वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर-समूह है, के लिए एक संयुक्त संरक्षण परियोजना शुरू की गई।

- भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट स्थित सबांग बंदरगाह के एकीकृत विकास में रुचि व्यक्त की।
- ONDC की तर्ज़ पर बना इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क (ION) शुरू किया गया तथा RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच QR भुगतान संपर्क पर सहमति बनी।
- रबींद्रनाथ टैगोर की 1927 की यात्रा के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2026-27 को टैगोर-देवांतरा वर्ष घोषित किया गया।
- भारत ने मुआरा जांबी के एक संग्रहालय को नालंदा ताम्रपत्र (लगभग 860 ई.) की प्रतिकृति उपहार में दी।

भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ

संदर्भ: भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता जुलाई 2026 में लागू हुआ। यह 1996 की भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश संधि का स्थान लेता है, जिसे भारत ने 2017 में समाप्त कर दिया था, और यह भारत के 2015 के मॉडल BIT पाठ का अनुसरण करता है। यह दोनों देशों के निवेशकों की रक्षा करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और कल्याण के लिए विनियमन के सरकारों के अधिकार को सुरक्षित रखता है और निवेशक-राज्य अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की अनुमति देता है।

□ मुख्य बिंदु

- भारत ने 2015 में 1993 के मॉडल का स्थान लेते हुए एक नए मॉडल BIT पाठ को मंज़ूरी दी। बजट 2025-26 में BIT ढाँचे की समीक्षा की घोषणा की गई।
- यह दोनों देशों के निवेशकों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्र में किए गए निवेशों की रक्षा करता है।
- युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या नागरिक अशांति के कारण हानि उठाने वाले निवेशकों को मुआवज़े के संबंध में भेदभाव-रहित व्यवहार मिलता है।
- सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण के लिए विनियमन का अधिकार बनाए रखती हैं।
- विवादों का समाधान निवेशक-राज्य अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सकता है।
- संधियों के विधि पर वियना अभिसमय, 1969 के अंतर्गत संधि और समझौते में कोई सारभूत कानूनी अंतर नहीं है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन और यूरेनियम समझौता

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। 2014 के असैन्य परमाणु समझौते को क्रियाशील बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया, जिससे भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के निर्यात का मार्ग खुल गया।

□ मुख्य बिंदु

- परमाणु प्रशासनिक व्यवस्था 12 वर्ष के अंतराल को समाप्त करती है और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम की अनुमति देती है।
- दोनों पक्ष ECTA को आधार बनाते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता में तेज़ी लाएँगे।
- साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर PACTS साझेदारी शुरू की गई तथा कनाडा के साथ त्रिपक्षीय ACIT। ढाँचे पर हस्ताक्षर किए गए।
- CSIR और आईपी ऑस्ट्रेलिया के बीच TKDL पहुँच समझौता पारंपरिक ज्ञान को जैव-चोरी से बचाता है।
- गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय में रूफटॉप सौर प्रशिक्षण अकादमी 2,000 महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करेगी।
- ऑस्ट्रेलिया तमिलनाडु की तीन प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाएगा: नंदी की मूर्ति, भद्रकाली सहित कांस्य त्रिशूल और छह मुख वाले स्कंद की मूर्ति।
- रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर एक नई संयुक्त घोषणा और समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप अपनाए गए।

□ भारत की यूरेनियम स्थिति

- भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट-विद्युत (GWe) परमाणु क्षमता प्राप्त करना है और उसने इस क्षेत्र को अधिक निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है।
- 47 निक्षेपों में लगभग 4.3 लाख टन यूरेनियम ऑक्साइड के भंडार हैं; यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा, तुरामडीह और तुम्मालपल्ले में खनन करता है।
- PHWR प्राकृतिक यूरेनियम पर चलते हैं, जबकि तारापुर और कुडनकुलम के हल्के जल रिएक्टर पूरी तरह आयातित संवर्धित यूरेनियम का उपयोग करते हैं।
- भारत कनाडा और कज़ाखस्तान से भी आपूर्ति में विविधता ला रहा है।

भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी और 2030 तक का रोडमैप

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड की यात्रा की, जो 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचाया और 2030 तक के रोडमैप का समर्थन किया।

□ मुख्य बिंदु

- रोडमैप के छह स्तंभ हैं: राजनीतिक और कूटनीतिक जुड़ाव; रक्षा और सुरक्षा; व्यापार और आर्थिक सहयोग; लोग, संस्कृति और खेल; शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन; तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग।

- एक वार्षिक समुद्री सुरक्षा वार्ता स्थापित की गई और IPOI के समुद्री सुरक्षा स्तंभ के अंतर्गत सहयोग का उल्लेख किया गया।
- आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह और भारत-न्यूज़ीलैंड साइबर वार्ता की स्थापना की गई।
- NDMA और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (न्यूज़ीलैंड) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) तैयारी और प्रतिक्रिया को कवर करता है।
- खेल पर संयुक्त कार्य योजना और अंटार्कटिक अनुसंधान में सहयोग पर सहमति बनी।
- 2025 में CTF-150 सहयोग में न्यूज़ीलैंड कमान में था और भारत उप-कमान में था।
- लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 7 अरब न्यूज़ीलैंड डॉलर करना है।
- पारस्परिक नौसैनिक ईंधन भरने और रखरखाव के लिए पारस्परिक रसद सहायता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए।
- न्यूज़ीलैंड IPOI के समुद्री सुरक्षा स्तंभ और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हुआ।

भारत-ब्रिटेन CETA लागू हुआ

संदर्भ: भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) हस्ताक्षर के एक वर्ष बाद 15 जुलाई 2026 को दोहरे अंशदान सम्मेलन के साथ प्रभावी हो गया। यह किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापक व्यापार समझौता है।

□ मुख्य बिंदु

- इस समझौते में डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, MSME, श्रम, पर्यावरण और लैंगिक विषयों सहित 30 अध्याय शामिल हैं।
- भारत लगभग 90 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क घटाता है: व्यापार मूल्य का 30.3 प्रतिशत तुरंत, 47 प्रतिशत चरणबद्ध रूप से और 12.1 प्रतिशत कोटा के माध्यम से।
- ब्रिटेन भारतीय निर्यात के 99 प्रतिशत पर शुल्क समाप्त करता है।
- ब्रिटिश कारों पर शुल्क 110 प्रतिशत तक से घटकर पहले वर्ष में 30 प्रतिशत और पाँचवें वर्ष तक 10 प्रतिशत हो जाएगा, जिसमें 20,000 वाहनों का प्रारंभिक कोटा है।
- ब्रिटिश मादक पेयों पर शुल्क 150 प्रतिशत से घटकर 75 प्रतिशत और फिर दसवें वर्ष तक 40 प्रतिशत हो जाएगा।
- भारत के किसी FTA में पहली बार, ब्रिटिश निर्यातक वस्तुओं की उत्पत्ति की स्व-घोषणा कर सकते हैं।

मनीला में क्वाड विदेश मंत्री और बिम्सटेक NSA बैठक

संदर्भ: क्वाड के विदेश मंत्री मई 2026 में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक के बाद मनीला में आसियान बैठकों के इतर मिले। अलग से, बिम्सटेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों ने NSA अजीत डोभाल की मेज़बानी में नई दिल्ली में बैठक की।

□ क्वाड की मुख्य बातें

- पहले की दिल्ली बैठक में हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग (जिसमें फिजी में बंदरगाह अवसंरचना शामिल है) और हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पहल की घोषणा की गई थी।
- क्वाड महत्वपूर्ण खनिज पहल के अंतर्गत सहयोग जारी है।
- मंत्रियों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत तथा आसियान की केंद्रीयता और हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक के समर्थन की पुनः पुष्टि की।
- इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन इस वर्ष दिल्ली में आयोजित होगा।

□ 5वीं बिम्सटेक NSA बैठक

- सदस्यों ने आतंकवाद और संगठित अपराध पर संयुक्त कार्रवाई का संकल्प लिया।
- मानवीय सहायता और आपदा राहत के समुद्री घटक के लिए दिशानिर्देश अपनाए गए।
- समुद्र में समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आचरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का समर्थन किया गया।
- बिम्सटेक अगले वर्ष अपनी 30वीं वर्षगांठ के निकट पहुँच रहा है।

मादक पदार्थ तस्करी पर ब्रिक्स गुवाहाटी घोषणा

संदर्भ: ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ-रोधी एजेंसियों के प्रमुखों ने भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत गुवाहाटी में दो दिन बैठक की और गुवाहाटी घोषणा अपनाई। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सिंडिकेटों के विरुद्ध नेटवर्क-केंद्रित रणनीति का प्रस्ताव रखा।

□ मुख्य बिंदु

- भारत ने शून्य सहनशीलता और सीमा-पार वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने का आग्रह किया।
- भारत ने संपूर्ण आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने, व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा उपचार और पुनर्वास को मज़बूत करने के लिए तीन वर्षीय मादक पदार्थ-रोधी रोडमैप (2026-29) की रूपरेखा रखी।
- प्रस्तावों में ब्रिक्स वर्चुअल कार्यशाला समूह, सीमा-पार प्रशिक्षण और वास्तविक समय खुफिया नेटवर्क शामिल हैं।
- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त ब्रिक्स में अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया भी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय मादक पदार्थ हेल्पलाइन (1933) MANAS को 18 जुलाई 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ शुरू किया गया था।

➤ यह गुमनाम रिपोर्टिंग की अनुमति देती है और 14446 नशामुक्ति हेल्पलाइन से जुड़ी है।

विश्व संक्षेप में: कंबोडिया में UPI, ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया प्रतिबंध और अन्य

संदर्भ: पिछले वर्ष के भारत से संबंधित विदेशी घटनाक्रम प्रस्तुत किए गए। NIPL ने जून 2026 में ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी कर कंबोडिया में UPI शुरू किया, जिससे UPI स्वीकार करने वाले देशों की संख्या नौ हो गई, और ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। बांग्लादेश ने अप्रैल 2026 में अपने पहले परमाणु संयंत्र में यूरेनियम ईंधन भरना शुरू किया, इसलिए 'पहले' से जुड़े तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने की संभावना रखते हैं।

□ **भुगतान और संस्कृति**

➤ NIPL ने ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी कर कंबोडिया में UPI शुरू किया (जून 2026); UPI अब भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और कतर सहित नौ देशों में स्वीकार किया जाता है।

➤ स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा, जो अमेरिका में पहली है, का 11 अप्रैल 2026 को सिएटल में अनावरण किया गया।

➤ डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा (बस्ट) का 26 नवंबर 2025 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अनावरण किया गया।

□ **ऊर्जा और नीति**

➤ बांग्लादेश ने अप्रैल 2026 में अपने पहले परमाणु संयंत्र में यूरेनियम ईंधन भरना शुरू किया, और वह 33वाँ परमाणु ऊर्जा संपन्न देश बनने जा रहा है।

➤ चीन ने जनवरी 2026 में जियांगसू में विश्व का सबसे बड़ा संपीडित-वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र (2.4 GWh) संचालित करना शुरू किया।

➤ ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना, जो 10 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

अगस्त 2026 में भारत की द्विपक्षीय गतिविधियाँ

संदर्भ: अगस्त 2026 में भारत ने जापान के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता व्यवस्था-पत्र (Memorandum of Arrangement) पर हस्ताक्षर किए, मॉस्को में रूस के साथ 27वीं IRIGC-TEC आयोजित की, ई-वीज़ा प्रवेश के लिए 11 बंदरगाह जोड़े (कुल 88) और तालिबान के साथ जुड़ाव की समीक्षा की, जिसके नियुक्त राजनयिक औपचारिक मान्यता के बिना भारत में अफ़ग़ान मिशनों में कार्यरत हैं। ये घटनाक्रम भारत की द्विपक्षीय कूटनीति और 2030 तक भारत-रूस 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य की दृष्टि से परीक्षा-प्रासंगिक हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता व्यवस्था-पत्र पर हस्ताक्षर किए; वीर गार्जियन 26 में भारत में किसी अभ्यास में जापानी लड़ाकू विमानों की पहली भागीदारी की योजना है।

➤ जयशंकर ने मॉस्को में 27वीं IRIGC-TEC में भाग लिया; भारत-रूस व्यापार लक्ष्य 2030 तक 100 अरब डॉलर है और वित्त वर्ष 2025-26 में व्यापार 59.86 अरब डॉलर था।

➤ केंद्र ने ई-वीज़ा प्रवेश के लिए 11 बंदरगाह जोड़े, जिससे कुल संख्या 88 हो गई; पाकिस्तानी नागरिक इससे बाहर हैं।

➤ ई-वीज़ा सुविधा 2014 में शुरू हुई थी और अब 172 देशों को सेवा प्रदान करती है।

➤ काबुल के पतन के पाँच वर्ष बाद, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में अफ़ग़ान मिशनों में तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिक कार्यरत हैं, लेकिन भारत ने औपचारिक मान्यता नहीं दी है।

➤ अमेरिकी सीनेट ने रूसी तेल या गैस के शीर्ष खरीदारों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया।

➤ अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम व्यापार को लेकर ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के अंतर्गत भारत स्थित चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए।

➤ नाउरू ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाओरो रख लिया।

➤ WHO ने 42 दिन की निगरानी अवधि के बाद युगांडा को इबोला मुक्त घोषित किया।

भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठकें

संदर्भ: भारत ने अपनी अध्यक्षता के विषय 'बिल्डिंग फॉर रेज़िलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' के अंतर्गत 2026 में ब्रिक्स की कई मंत्रिस्तरीय बैठकों की मेज़बानी की, जिनमें नई दिल्ली में 12वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक और चेन्नई में 14वीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक शामिल हैं, जिसमें चेन्नई घोषणा अपनाई गई। ब्रिक्स विश्व की लगभग 49.5 प्रतिशत जनसंख्या और वैश्विक GDP के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

□ **बैठकें**

➤ नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की।

➤ इसकी प्राथमिकताएँ टिकाऊ जीवनशैली, वनीकरण और आपदा सहनशीलता, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा जलवायु अनुकूलन थीं।

➤ ब्रिक्स विश्व की लगभग 49.5 प्रतिशत जनसंख्या, वैश्विक GDP के 40 प्रतिशत और व्यापार के 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

➤ चेन्नई में 14वीं ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक में चेन्नई घोषणा अपनाई गई।

➤ 11वाँ ब्रिक्स+ विधि मंच आर्थिक सहनशीलता के लिए विधि के शासन पर केंद्रित था।

□ **संयुक्त राष्ट्र महासचिव**

➤ UNSC ने अगले महासचिव के लिए अनौपचारिक मतदान (स्ट्रॉ पोल) आयोजित किया, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा।

➤ माना जा रहा है कि रेबेका ग्रिनस्पैन, कैरोलिन बर्केट और राफेल ग्रोसी का प्रदर्शन अच्छा रहा, जो किसी लैटिन अमेरिकी उम्मीदवार के पक्ष में है।

भारत-उज़्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने उज़्बेकिस्तान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा की, जहाँ संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। इसके बाद वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 26वें SCO शिखर सम्मेलन के लिए बिश्केक गए।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह यात्रा 2012 में बनाई गई भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का हिस्सा है। भारत के हितों में INSTC संपर्क, कज़ाख यूरेनियम और प्रस्तावित TAPI पाइपलाइन शामिल हैं।

➤ उज़्बेकिस्तान से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति व्यवस्था भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम को सहारा देती है।

➤ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर (2025) है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 अरब डॉलर है।

➤ उज़्बेकिस्तान ने भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिन तक के प्रवास हेतु वीज़ा समाप्त कर दिया है और वहाँ UPI भुगतान उपयोग योग्य होने वाले हैं।

➤ तेरमेज़ में फ़ायाज़ टेपा और कारा टेपा के बौद्ध स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

➤ 100 लाल बहादुर शास्त्री हिंदी छात्रवृत्तियों और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में ICCR संस्कृत पीठ की घोषणा की गई।

➤ भारत ने अरल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर के अनुदान की घोषणा की।

➤ दुस्तलिक संयुक्त अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।

भारत-चीन 25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता

संदर्भ: NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की वार्ता की, जिसमें सीमा परिसीमन और सीमा प्रबंधन पर आठ-सूत्रीय सहमति बनी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को अपने आधिकारिक मानचित्र पर भी अंकित किया।

□ **SR वार्ता के परिणाम**

➤ SR वार्ता अक्टूबर 2003 में शुरू हुई थी।

➤ सीमा परिसीमन पर विशेषज्ञ समूह और WMCC के अंतर्गत सीमा प्रबंधन पर कार्य समूह अपने कार्य-निर्देश (Terms of Reference) को अंतिम रूप देंगे।

➤ पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में दो नई हॉटलाइन स्थापित की जाएँगी।

➤ तीन सीमा व्यापार केंद्र फिर से खोले गए और कैलाश-मानसरोवर यात्रा के जत्थों की संख्या बढ़ाई गई।

➤ 26वाँ SR दौर 2027 में भारत में आयोजित होगा।

□ **अरुणाचल के नाम**

➤ भारत ने सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को मानक भारतीय नामों से चिह्नित किया।

➤ चीन की सूचियाँ: 2017 में 6 नाम, 2021 में 15 और 2023 में 11, जो अप्रैल 2026 तक छह खेपों में कुल 112 हैं।

➤ भारत नाम बदलने को काल्पनिक बताकर अस्वीकार करता है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

संदर्भ: सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने मक्का (मक्कह) संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें किसी भी एक हस्ताक्षरकर्ता पर हमले को तीनों पर हमला माना गया है। यह सितंबर 2025 के सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर आधारित है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ पूरा पाठ सार्वजनिक नहीं है; केवल एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

➤ इसके चार स्तंभ हैं: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 की तर्ज़ पर सामूहिक निवारण खंड, संयुक्त प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करना और रक्षा-औद्योगिक एकीकरण।

➤ इसमें कोई एकीकृत कमान, स्थायी संयुक्त बल, साझा बजट या परमाणु-साझाकरण खंड नहीं है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा

संदर्भ: होर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण भारत को मई से जुलाई 2026 के बीच अपने LNG और LPG स्रोतों में फेरबदल करना पड़ा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता बढ़ी। कतर की LNG आपूर्ति 91 प्रतिशत से अधिक घटी क्योंकि उसकी जगह अमेरिका, नाइजीरिया और ओमान ने ली, और भारत की 67 प्रतिशत LPG अब अमेरिका से आती है, जो पहले लगभग 10 प्रतिशत थी। यह घटना ऊर्जा-सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है।

□ **LNG**

➤ कतर की जगह अमेरिका, नाइजीरिया और ओमान के आने से मई-जुलाई 2026 में भारत का LNG आयात बढ़ा।

➤ कतर की आपूर्ति 91 प्रतिशत से अधिक घटी; UAE की आपूर्ति 34.4 प्रतिशत घटी।

➤ भारत अपनी लगभग आधी गैस ज़रूरतों के लिए LNG पर निर्भर है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से लगभग 60 प्रतिशत होर्मुज़ से होकर आता है।

□ **LPG**

- भारत की 67 प्रतिशत LPG अब अमेरिका से आती है, जो पहले लगभग 10 प्रतिशत थी।
- फरवरी से जून 2026 के बीच पश्चिम एशियाई LPG आयात लगभग 85 प्रतिशत घटा।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक है और 2026 के लिए 22 लाख टन का दीर्घकालिक समझौता रखता है।
- विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और अंगोला से आपूर्ति में विविधता लाने का सुझाव देते हैं।

18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और नई दिल्ली घोषणा

संदर्भ: ब्रिक्स ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अपने 18वें शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। ईरान-यूएई मतभेदों के बीच मई में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य जारी करने में विफल रहने के बाद, मेज़बान और अध्यक्ष के रूप में भारत ने मतभेदों को पाटा।

□ **मुख्य बिंदु**

- घोषणा में एकतरफा दंडात्मक उपायों की निंदा की गई और एकतरफा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का विरोध किया गया।
- इसमें अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई और ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्य समूह को मान्यता दी गई।
- इसमें ब्रिक्स की साझा मुद्रा का कोई उल्लेख नहीं किया गया और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान को बढ़ावा दिया गया।
- गिफ्ट सिटी में भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स रिस्क लैब को आगे बढ़ाया जाएगा।
- इसमें पश्चिम एशिया को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई, गाज़ा युद्धविराम का समर्थन किया गया और 1967 की सीमाओं के साथ द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया गया।

□ **भारतीय पहलें**

- पायलट परियोजनाओं के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए एक ब्रिक्स भंडार (रिपॉजिटरी) का प्रस्ताव रखा गया।
- मानसिक कल्याण पर ब्रिक्स प्रशिक्षण केंद्र नेटवर्क और उत्कृष्टता केंद्रों का समन्वय निम्हांस (NIMHANS), बेंगलुरु द्वारा किया जाएगा।
- MSME को सहयोग देने के लिए भारत के ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र का स्वागत किया गया।
- वृद्धि और विकास पर एक नए ब्रिक्स कार्य बल तथा ब्रिक्स-NDB ज्ञान पोर्टल की घोषणा की गई।

26वाँ SCO शिखर सम्मेलन और बिश्केक घोषणा

संदर्भ: शंघाई सहयोग संगठन ने अपना 26वाँ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित किया, जो इस समूह के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, और नेताओं ने बिश्केक घोषणा अपनाई। इसमें दोहरे मानदंडों के बिना आतंकवाद की निंदा की गई, पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की गई, ईरान पर हमलों की निंदा की गई, तथा अफ़ग़ानिस्तान में समावेशी सरकार और वैश्विक शासन में सुधार का आह्वान किया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसमें सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की गई और कहा गया कि दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं, तथा संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का आग्रह किया गया।
- सदस्यों ने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के उपयोग का मुकाबला करने तथा सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध पर समन्वय करने पर सहमति जताई।
- इसमें पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की गई, ईरान पर हमलों की निंदा की गई और सदस्यों के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार का समर्थन किया गया।
- इसमें फ़िलिस्तीन प्रश्न के न्यायसंगत समाधान और वैश्विक शासन में सुधार का आह्वान किया गया।
- इसमें वैश्विक मिसाइल रक्षा के असीमित निर्माण की ओर संकेत किया गया और सदस्य देशों में अनधिकृत उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की आलोचना की गई।
- इसमें अफ़ग़ानिस्तान से समावेशी सरकार बनाने का आह्वान किया गया और यूक्रेन युद्ध में रूस की भूमिका पर चुप्पी रखी गई।

अमेरिका का रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम, 2026

संदर्भ: अमेरिका ने लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम 2026 पारित किया, जो राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति देता है। विधेयक पर हस्ताक्षर होकर यह कानून बन चुका है और यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस उसके लगभग आधे कच्चे तेल की आपूर्ति करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- शुल्क की शक्ति रूसी तेल और गैस के पाँच सबसे बड़े खरीदारों पर लागू होती है, जिसे मूल प्रस्ताव के 500% से घटाया गया है।
- अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि लक्षित देशों की पहचान करेंगे और दरों की सिफारिश करेंगे।
- लक्षित देशों को आमतौर पर आयात घटाने या वार्ता करने के लिए 180 दिन मिलेंगे।
- भारत ने अगस्त 2026 में प्रतिदिन लगभग 20.8 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल आयात किया, जो उसके तेल आयात का लगभग 45% है।
- भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 88% से अधिक आयात करता है।

पाकिस्तान-चीन सीमा समझौता और शक्सगाम घाटी

संदर्भ: सितंबर 2026 में पाकिस्तान और चीन ने भारत द्वारा दावा किए जाने वाले एक हिमालयी क्षेत्र में सीमा को औपचारिक रूप दिया, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग पर हस्ताक्षर किए, और भारत ने इस कदम को कानूनी आधार से रहित बताकर अस्वीकार कर दिया। इसमें शक्सगाम घाटी शामिल है, जो उत्तरी काराकोरम में लगभग 5,180 वर्ग किमी का क्षेत्र है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था, जबकि भारत इसे लद्दाख का हिस्सा बताता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह व्यवस्था शक्सगाम घाटी को कवर करती है, जो लगभग 5,180 वर्ग किमी का क्षेत्र है।
- इस घाटी को ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है; यह उत्तरी काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में स्थित है।
- पाकिस्तान ने 1963 में यह क्षेत्र चीन को सौंप दिया, जबकि भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है।
- भारत का मानना है कि यह पूर्ववर्ती रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था और पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्ज़ा किया और फिर इसे सौंप दिया।
- विशेषज्ञ LAC पर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं देखते।
- चाइना सदर्न एयरलाइंस ने छह वर्ष के निलंबन के बाद 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली उड़ानें फिर शुरू कीं।

पीएनएस हुनैन की भारतीय युद्धपोत से टक्कर

संदर्भ: पाकिस्तान नौसेना के जहाज़ हुनैन, जो यारमुक-श्रेणी का कार्वेट है, ने उत्तरी अरब सागर में एक भारतीय नौसेना युद्धपोत के पास असुरक्षित तेज़ गति से पहुँच बनाई, जिससे मामूली टक्कर हुई। भारत ने इसे अस्वीकार्य और 1991 के द्विपक्षीय समझौते के अनुच्छेद 10 का उल्लंघन बताया।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह घटना ओमान की खाड़ी से लगभग 120 समुद्री मील दूर हुई।
- नियमित निगरानी कर रहे भारतीय जहाज़ को कोई क्षति नहीं हुई, जबकि पीएनएस हुनैन क्षतिग्रस्त हुआ।
- यह जून 2011 के बाद ऐसी दूसरी घटना थी, जब अदन की खाड़ी में पीएनएस बाबर आईएनएस गोदावरी से रगड़ खाते हुए निकला था।
- 1991 का समझौता सैन्य अभ्यासों की अग्रिम सूचना से संबंधित है।
- विश्लेषक इस कृत्य को दक्षिण चीन सागर में चीन की ऐसी ही ग्रे-ज़ोन रणनीति बताते हैं।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री की यात्रा और भारत-बेल्जियम रक्षा संबंध

संदर्भ: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की यात्रा के दौरान, जो दो दशकों में किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, भारत और बेल्जियम ने रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने, व्यापार, अर्धचालक, फिनटेक और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग गहरा करने पर सहमति जताई।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 13.01 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 के बीच भारत में बेल्जियम का FDI प्रवाह लगभग 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, संयुक्त अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग को कवर करने वाले संरचित रक्षा सहयोग के लिए आशय पत्र का आदान-प्रदान किया।
- लगभग 15 बेल्जियम रक्षा कंपनियों ने भारतीय उद्योग के साथ संपर्क किया।

□ **रक्षा औद्योगिक परियोजनाएँ**

- लाशोसे और टेम्बो क्लासिक इंजीनियरिंग 5 करोड़ यूरो की परियोजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ राउंड की वार्षिक क्षमता वाली गोला-बारूद लाइन स्थापित करेंगी।
- एक्ज़ेल बेल्जियम और लार्सन एंड टुब्रो बारूदी सुरंग-रोधी पोतों के लिए स्वायत्त प्रणालियों पर सहयोग करेंगी, शुरू में 12 पोतों के लिए और संभावित रूप से 59 के लिए।
- अन्य क्षेत्रों में 70 मिमी रॉकेट, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, अर्जुन टैंकों के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणालियाँ और ज़ोरावर हल्का टैंक शामिल हैं।

ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दी

संदर्भ: ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के अंतर्गत मूल्य राहत के लिए एक योग्यता मानदंड के रूप में मान्यता दी, जिससे भारतीय निर्यातकों पर कर का बोझ कम होगा।

□ **मुख्य बिंदु**

- राहत इस पर निर्भर करती है कि वस्तुओं पर कितना प्रभावी कार्बन मूल्य लागू था।
- दायित्वधारी व्यक्तियों को फिर भी साक्ष्य और सत्यापन की आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी।
- भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार साझेदारी जुलाई 2026 में लागू हुई।

➤ द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2025-26 में 25.1 अरब डॉलर था और सेवा व्यापार 2024 में 35.4 अरब डॉलर।

भारत की विदेशी सैन्य और सामरिक उपस्थिति

संदर्भ: हिंद महासागर क्षेत्र और पड़ोस में भारत की निगरानी, नौसैनिक पहुँच और प्रशिक्षण सुविधाओं का नेटवर्क सितंबर 2026 में चर्चा में रहा, जो समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सामरिक पहुँच को सहारा देता है। प्रमुख उदाहरण हैं मेडागास्कर तटीय निगरानी रडार स्टेशन (2007), मालदीव का तटीय रडार नेटवर्क, भूटान के हा में IMTRAT (1962) और सिंगापुर में आरएसएस सिंगापुरा-चांगी नौसैनिक अड्डे तक भारतीय नौसेना की पहुँच।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 2007 में स्थापित मेडागास्कर तटीय निगरानी रडार स्टेशन भारत की पहली विदेशी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुविधा है।

➤ मालदीव में 10 तटीय रडार स्टेशन हैं जो भारत के नेटवर्क से जुड़े हैं और जिनका नियंत्रण विलिमाले से होता है।

➤ पश्चिमी भूटान के हा में 1962 में स्थापित IMTRAT विदेश में भारत का सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण मिशन है।

➤ भारतीय नौसेना के जहाज़ मलक्का जलडमरूमध्य के पूर्वी छोर पर डॉकिंग और ईंधन भरने के लिए आरएसएस सिंगापुरा-चांगी नौसैनिक अड्डे का उपयोग कर सकते हैं।

भारत की चुनिंदा विदेशी सुविधाएँ

सुविधा	स्थान
असम्प्शन द्वीप तटीय निगरानी	सेशेल्स
तटीय निगरानी रडार स्टेशन	उत्तरी मेडागास्कर
अगालेगा द्वीप रडार और हवाई पट्टी	उत्तरी मॉरीशस
दुक़्म नौसैनिक पहुँच	ओमान
कांकेसंतुरै बंदरगाह	उत्तरी श्रीलंका
सुर्खेत हवाई अड्डा (वायुसेना अड्डा प्रशिक्षण)	पश्चिमी नेपाल
IMTRAT	हा, भूटान
चांगी नौसैनिक अड्डे तक पहुँच	सिंगापुर

राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा और रक्षा समझौता ज्ञापन

संदर्भ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2026 में श्रीलंका का दौरा किया, जो लगभग 40 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली यात्रा थी, और तीन रक्षा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। ये श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L70 तोपों के उन्नयन, NCC सहयोग और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग से संबंधित हैं। भारत ने चक्रवात दित्वा के बाद ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत 45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज का वादा किया था।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ ये समझौता ज्ञापन श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L70 तोपों के उन्नयन, NCC सहयोग और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग से संबंधित हैं।

➤ भारत ने 2025 के अंत में चक्रवात दित्वा के बाद ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत 45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज का पहले वादा किया था।

➤ भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित तीन बेली पुलों का कुरुनेगला और बट्टिकलोआ जिलों में वर्चुअल उद्घाटन किया गया।

संयुक्त राष्ट्र ने इक्कल अर्थ मानचित्र प्रस्ताव अपनाया

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टोगो के नेतृत्व वाला 'मानचित्र सुधारें' प्रस्ताव अपनाया, जो मर्केटर प्रक्षेपण से इक्कल अर्थ प्रक्षेपण की ओर बदलाव करता है। भारत ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के नए विश्व मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के चित्रण पर आपत्ति जताई।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ इस प्रस्ताव का भारत सहित 164 देशों ने समर्थन किया, अमेरिका ने विरोध किया और छह देश अनुपस्थित रहे।

➤ मर्केटर प्रक्षेपण, जिसे 1569 में गेरार्डस मर्केटर ने प्रस्तुत किया, भूमध्य रेखा से दूर के क्षेत्रों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है; ग्रीनलैंड अफ्रीका जैसा दिखता है, जबकि वह उससे बहुत छोटा है।

➤ नया संयुक्त राष्ट्र मानचित्र अरुणाचल की उत्तरी सीमा को भारतीय रेखा और दक्षिणी सीमा को चीनी रेखा के रूप में दर्शाता है।

➤ यह अक्साई चिन को लद्दाख से अलग दिखाता है, जो भारत के इस रुख के विरुद्ध है कि यह लद्दाख का हिस्सा है।

सिंधु जल संधि पर हेग न्यायालय का निर्णय

संदर्भ: हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1960 की सिंधु जल संधि पूरी तरह लागू है और भारत को इसका पालन करते रहना होगा। भारत ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि उसने संधि पर पहले के एक पंचाट को अस्वीकार किया था, और कहा कि न्यायालय का गठन अवैध है तथा उसके निर्णय अमान्य और निरर्थक हैं।

□ **संधि**

➤ यह संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी।

➤ रावी, ब्यास और सतलुज मुख्य रूप से भारत को आवंटित हैं; सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को।

➤ भारत पश्चिमी नदियों पर घरेलू उपयोग, सिंचाई और रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत के अधिकार रखता है।

➤ विवाद निपटान तंत्र हैं: स्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय।

- भारत ने 2023 में संशोधन और 2024 में समीक्षा एवं संशोधन की माँग की।

□ **निर्णय**

- भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद घोषणा की कि संधि को स्थगित रखा जाएगा।
- न्यायालय ने कहा कि संधि में एकतरफा निलंबन का कोई तंत्र नहीं है और स्थगन से इसे निलंबित नहीं किया जा सकता।
- इसने चिनाब पर रातले परियोजना में बाँध की दीवार की कंक्रीट भराई और बिजली इनटेक पर भारत के काम पर अंतरिम सीमाएँ लगाईं।
- ये सीमाएँ तटस्थ विशेषज्ञ के अंतिम निर्णय के 90 दिन बाद तक लागू रहेंगी, जो जुलाई 2027 के आसपास अपेक्षित है।
- भारत न्यायालय के निर्णयों को अमान्य और निरर्थक कहता है और उसने इसकी कार्यवाही में भाग नहीं लिया है।
- बताया जाता है कि पंचाट अधिकतम पौंडेज (जल संचयन) से संबंधित है।

सम्मेलन, शिखर सम्मेलन और बैठकें 2025-26: वर्षवार सूची

संदर्भ: 2025-26 के दौरान भारत और विदेश में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन, शिखर सम्मेलन और मंत्रिस्तरीय बैठकें स्थान तथा टिप्पणियों या विषयों के साथ एक ही सूची में वर्षवार प्रस्तुत हैं।

2025 के सम्मेलन और शिखर सम्मेलन

आयोजन	स्थान	टिप्पणियाँ
राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2025 (11-12 नवंबर)	नई दिल्ली	राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय व्यापार सम्मेलन 2025 (12 नवंबर)	नई दिल्ली	FICCI के साथ संस्कृति मंत्रालय और DPIIT द्वारा आयोजित
13वाँ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (13-16 नवंबर)	गंगटोक, सिक्किम	पर्यटन मंत्रालय और सिक्किम सरकार
10वाँ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव (15 नवंबर-5 दिसंबर)	कुरुक्षेत्र, हरियाणा	मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उद्घाटित
विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन (17-28 नवंबर)	बाकू, अज़रबैजान	सार्वभौमिक, सार्थक और किफायती संपर्कता
भारत अंतरिक्ष कॉन्क्लेव (18-19 नवंबर)	नई दिल्ली	भारतीय अंतरिक्ष संघ द्वारा आयोजित
छठी अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस (24-26 नवंबर)	नई दिल्ली	स्मार्ट कृषि-खाद्य प्रणालियाँ
सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन (28-29 नवंबर)	भारत मंडपम, दिल्ली	जल शक्ति मंत्रालय
आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (28-30 नवंबर)	देहरादून	उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
अर्थ समिट 2025 (5-6 दिसंबर)	गांधीनगर, गुजरात	अमित शाह द्वारा उद्घाटित

2026 के सम्मेलन और शिखर सम्मेलन

आयोजन	स्थान	टिप्पणियाँ
चौथा 1 बिलियन फॉलोअर्स शिखर सम्मेलन (9-11 जनवरी)	दुबई	भलाई के लिए सामग्री
दूसरा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (11-12 जनवरी)	राजकोट	प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित
उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन (12-13 जनवरी)	लखनऊ	उत्तर प्रदेश सरकार के साथ IndiaAI और MeitY
ग्रीन AI पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (24-25 जनवरी)	दुबई	पर्यावरणीय स्थिरता के लिए AI का उपयोग
दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन (24-25 जनवरी)	नई दिल्ली	संस्कृति मंत्रालय के साथ अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन (3-5 फरवरी)	दुबई	भविष्य की सरकारों को आकार देना
छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन (5-6 फरवरी)	मुंबई	कृषि आगत विनिर्माण केंद्र
तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन (15-17 फरवरी)	दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर	मन-शरीर के स्वास्थ्य के लिए साक्ष्य-आधारित आयुष
इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट (16-20 फरवरी)	भारत मंडपम, दिल्ली	सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय
बायोएशिया 2026, 23वाँ संस्करण (17-18 फरवरी)	हाइटेक्स, हैदराबाद	टेकबायो अनलीश्ड
एआई4एग्री 2026 शिखर सम्मेलन (22-23 फरवरी)	जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई	महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित
पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन (24 फरवरी)	नई दिल्ली	संकल्प फाउंडेशन के साथ अमेरिका-भारत साझेदारी मंच
25वाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (25-27 फरवरी)	ताज पैलेस, नई दिल्ली	सतत विकास के लिए दृष्टि, स्वर और मूल्य
राष्ट्रीय आरोग्य मेला (25-28 फरवरी)	शेगाँव, महाराष्ट्र	आयुष मंत्रालय
अन्वेष-2026 (26-28 फरवरी)	सोनीपत, हरियाणा	निफ्टेम-के
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (2-5 मार्च)	बार्सिलोना	ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल
अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन (7-9 मार्च)	नई दिल्ली	मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की ओर अग्रसर
9वाँ अंतरराष्ट्रीय संताल सम्मेलन (7 मार्च)	दार्जिलिंग	राष्ट्रपति मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति
रणनीतिक संचार सम्मेलन (7 मार्च)	लखनऊ	भारतीय सेना की मध्य कमान, पहली बार
जियोडकॉन-26 (11-13 मार्च)	आईएनएसए, नई दिल्ली	भूगणित (जियोडेसी) पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन,

		आईआईटी कानपुर
प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 11वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन (16 मार्च)	भारत मंडपम	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
साहित्योत्सव (30 मार्च-4 अप्रैल)	नई दिल्ली	भारतीय साहित्य: संस्कृतियों का पालना
विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस (14-16 अप्रैल)	वियना	अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल
छठा सुजल ग्राम संवाद (22 अप्रैल)	-	जल शक्ति; सी. आर. पाटिल की वर्चुअल अध्यक्षता में
11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक (26 मई)	नई दिल्ली	एस. जयशंकर द्वारा आयोजित
काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव (6-7 जून)	ललितपुर, नेपाल	सीमाओं से परे: दक्षिण एशियाई साहित्य
11वीं अंतरराष्ट्रीय पुलिस प्रदर्शनी (24-25 जून)	भारत मंडपम	नेक्सजेन एग्जिबिशन्स
प्लास्टिक पुनर्चक्रण पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन (2-5 जुलाई)	भारत मंडपम	जीसीपीआरएस
17वीं टॉय बिज अंतरराष्ट्रीय बी2बी प्रदर्शनी (4-7 जुलाई)	भारत मंडपम	टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया
डब्ल्यूएसआईएस फोरम 2026 (6-10 जुलाई)	जिनेवा	-
एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद, पहला सत्र (6-7 जुलाई)	जिनेवा	-
13वीं एआईटीआईजीए संयुक्त समिति (6-10 जुलाई)	वाणिज्य भवन, दिल्ली	आसियान-भारत वस्तु व्यापार
नाटो शिखर सम्मेलन (7-8 जुलाई)	अंकारा, तुर्किये	-
तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक (11-12 जुलाई)	नागपुर	नितिन गडकरी की अध्यक्षता में
विधिक शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन (11 जुलाई)	बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली	-
नेक्स्टजेन प्रशासनिक और ई-गवर्नेंस सुधार (13-14 जुलाई)	शिलांग	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), मेघालय सरकार के साथ
भारत टेक्स 2026 (14-17 जुलाई)	भारत मंडपम	भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन
भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC), तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक (15 जुलाई)	ब्रसेल्स	-
भारत-बेल्जियम सामरिक संवाद, पहला (15 जुलाई)	ब्रसेल्स	-
सौश्रुतम 2026 (15-17 जुलाई)	नई दिल्ली	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) द्वारा आयोजित
उत्तरदायी कारोबारी आचरण पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन (15-16 जुलाई)	नई दिल्ली	ईएसजी-आधारित रूपांतरण
पाँचवीं बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक (16 जुलाई)	नई दिल्ली	-
बाँध सुरक्षा पर 12वीं राष्ट्रीय समिति (17 जुलाई)	डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	-
आठवीं ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की बैठक (20-21 जुलाई)	वर्चुअल	आपराधिक न्याय-निर्णयन में सर्वोत्तम प्रथाएँ
16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक (22-24 जुलाई)	चंडीगढ़	-
दूसरा भारत हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन (23 जुलाई)	नई दिल्ली	फिक्की; वैश्विक हाइड्रोजन केंद्र के रूप में भारत
33वाँ आसियान क्षेत्रीय मंच (23 जुलाई)	मनीला	-
ब्रिक्स सांख्यिकी कार्यालय प्रमुखों की बैठक (3-4 अगस्त)	लखनऊ	सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI)
दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन (6 अगस्त)	नई दिल्ली	-
16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक (7 अगस्त)	जयपुर	-
11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक (7-8 अगस्त)	भोपाल	-
ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक (17-21 अगस्त)	पुणे	लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और रूपांतरण
12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक (21 अगस्त)	पुणे	ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में
ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक (22 अगस्त)	विशाखापत्तनम	युवा कार्यक्रम विभाग
ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक (23 अगस्त)	विशाखापत्तनम	-
जी20 नवाचार मंत्रियों की बैठक (1-2 सितंबर)	चैपल हिल, अमेरिका	अमेरिकी वाणिज्य विभाग और ओएसटीपी द्वारा आयोजित
सातवाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (8-11 सितंबर)	मुंबई	एजेंटिक एआई, टोकनीकरण, क्वांटम
27वाँ विश्व ज्ञान मंच (8-10 सितंबर)	सियोल	को-इंटेलिजेंस ऑर्डर
ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (9-10 सितंबर)	मुंबई	-
वैश्विक शुष्क भूमि कांग्रेस (10-12 सितंबर)	नई दिल्ली	शुष्क भूमि कृषि के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग
69वाँ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (13-19 सितंबर)	केप टाउन	हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल
जी20 ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक (14-16 सितंबर)	ह्यूस्टन, अमेरिका	-

विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (15-18 सितंबर)	गांधीनगर	लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन
पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा बिम्सटेक सम्मेलन (16-17 सितंबर)	गोवा	आयुष मंत्रालय; AIIA गोवा नोडल संस्थान
छठा राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह (17-23 सितंबर)	-	दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना
17वाँ कथकली महोत्सव (18-20 सितंबर)	चेन्नई	कथा रस संगम
पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर सम्मेलन (19-20 सितंबर)	विज्ञान भवन, दिल्ली	प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित
भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह (22-26 सितंबर)	भारत मंडपम	जलवायु-सहिष्णु जल प्रबंधन
11वीं एआईआईबी वार्षिक बैठक (28-29 सितंबर)	दोहा, कतर	कल का बुनियादी ढाँचा: प्रभाव और नवाचार
पाँचवाँ कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन (3-5 अक्टूबर)	नई दिल्ली	अस्थिरता के युग में सहनशीलता
153वीं आईपीयू सभा (5-9 अक्टूबर)	अरुशा, तंजानिया	हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल
10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस (7-10 अक्टूबर)	यशोभूमि, नई दिल्ली	सीमाओं से परे विस्तार
आठवाँ विंडरजी इंडिया (7-9 अक्टूबर)	चेन्नई	प्रह्लाद जोशी द्वारा उद्घाटन
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (11-13 अक्टूबर)	बर्लिन	संकट से सहनशीलता तक
पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक (13 अक्टूबर)	नई दिल्ली	अमित शाह की अध्यक्षता में
25वीं एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद (19-20 अक्टूबर)	दुशांबे, ताजिकिस्तान	राजनाथ सिंह के नेतृत्व में
14वाँ इंडिया केम 2026 (22-24 अक्टूबर)	मुंबई	एडवांटेज भारत: उभरता वैश्विक रसायन केंद्र
इंडिया माइनिंग वीक (15-17 नवंबर)	यशोभूमि	-

2027 में सम्मेलन और शिखर सम्मेलन

आयोजन	स्थान	टिप्पणियाँ
इंडिया एनर्जी वीक 2027 (28-31 जनवरी 2027)	कोलकाता	नवाचार को खोलना। ऊर्जा को सुरक्षित करना। कल को आकार देना

सैन्य अभ्यास 2025-26: संपूर्ण वर्षवार सूची

संदर्भ: 2025-26 के दौरान भारतीय सेनाओं के सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास साझेदार देश, स्थान और तिथियों के साथ वर्षवार एक स्थान पर प्रस्तुत हैं, क्योंकि अभ्यासों के नाम और साझेदार प्रायः पूछे जाते हैं। 29वें मालाबार अभ्यास में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका गुआम के आसपास एक साथ आए, और अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत-इंडोनेशिया का विशेष बल अभ्यास है। ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका को दी गई राहत थी।

□ मुख्य बिंदु

- 29वें मालाबार अभ्यास में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ आए, जो उत्तरी प्रशांत में गुआम के आसपास आयोजित हुआ।
- ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दित्वा से भीषण बाढ़ आने के बाद श्रीलंका को दी गई भारत की मानवीय सहायता थी।
- अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत-इंडोनेशिया का विशेष बल अभ्यास है; गरुड़ भारत-फ्रांस का वायु अभ्यास है।
- अभ्यास अजेय वॉरियर भारत-ब्रिटेन का थल सेना अभ्यास है; हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ है।
- दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका से जुड़ा त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है।
- किर्गिस्तान के साथ खंजर असम के मिसामारी में आयोजित हुआ; अमेरिका के साथ वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल अभ्यास है।
- अभ्यास साइक्लोन-IV भारत-मिस्र का विशेष बल अभ्यास है, जो मिस्र के अंशास में आयोजित हुआ।
- वायु शक्ति जैसलमेर के पोखरण में भारतीय वायुसेना का मारक क्षमता प्रदर्शन है।
- CINBAX-II भारत-कंबोडिया का अभ्यास है, जो कंपोंग स्पू प्रांत में आयोजित हुआ।
- पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का बहुराष्ट्रीय वायु-युद्ध अभ्यास है, जो RAAF डार्विन, टिंडल और एम्बरले में होता है।
- मैत्री भारत-थाईलैंड का थल सेना अभ्यास है; उदार शक्ति IAF और रॉयल मलेशियाई वायुसेना का अभ्यास है।
- सुदर्शन शक्ति-V IGI हवाई अड्डे पर अपहरण-रोधी मॉक ड्रिल थी; साइ-वज्र उत्तर प्रदेश पुलिस का साइबर अभ्यास था।
- SIMBEX सिंगापुर-भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जो विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ (33वाँ संस्करण)।
- ऑस्ट्राहिंद भारत-ऑस्ट्रेलिया का है; माउंटेन गार्जियन भारत-यूएई का है; काज़िंद भारत-कज़ाखस्तान का है।
- SAREX राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास है, जो ओडिशा के पारादीप तट के पास आयोजित हुआ।
- श्रीलंका के साथ SLINEX-26 और मलेशिया के साथ समुद्र लक्ष्मण नौसैनिक अभ्यास हैं।
- आईएनएस त्रिशूल वरुण के 24वें संस्करण के लिए फ्रांस के तूलों गया; यह अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था और 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया।
- IAF 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर में तरंग शक्ति-26 की मेज़बानी करेगी; पहला संस्करण 2024 में 11 देशों के साथ हुआ था।

- आठ देश तरंग शक्ति-26 में अपने विमान आदि संसाधन उड़ा रहे हैं और 32 देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं।
- जोधपुर में वीर गार्जियन 2026 IAF-JASDF अभ्यास का दूसरा संस्करण था; पहला संस्करण 2023 में ह्याकुरी वायु सेना अड्डे पर हुआ था।
- युद्ध अभ्यास 2004 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है; 22वाँ संस्करण उत्तराखंड के औली और राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ।

2025 के अभ्यास

अभ्यास	साझेदार	स्थान	तिथियाँ
मालाबार-2025 (29वाँ)	भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका	गुआम, उत्तरी प्रशांत	10-18 नवंबर
मित्र शक्ति-2025 (11वाँ)	भारत-श्रीलंका	बेलगावी, कर्नाटक	10-23 नवंबर
विनबैक्स-2025 (6ठा)	भारत-वियतनाम	हनोई, वियतनाम	11-27 नवंबर
गरुड़-25 (8वाँ)	भारत-फ्रांस	मों-दे-मार्सां, फ्रांस	16-27 नवंबर
अजेय वॉरियर-25 (8वाँ)	भारत-ब्रिटेन	महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान	17-30 नवंबर
सूर्य किरण-2025 (19वाँ)	भारत-नेपाल	पिथौरागढ़, उत्तराखंड	25 नवंबर-8 दिसंबर
ऑपरेशन सागर बंधु	भारत से श्रीलंका	श्रीलंका (चक्रवात दित्वा राहत)	28 नवंबर
एकुवेरिन-2025 (14वाँ)	भारत-मालदीव	तिरुवनंतपुरम, केरल	2-15 दिसंबर
गरुड़ शक्ति-2025 (10वाँ)	भारत-इंडोनेशिया	विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय, बकलोह, हिमाचल प्रदेश	3-12 दिसंबर
हरिमाऊ शक्ति-2025 (5वाँ)	भारत-मलेशिया	महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान	5-18 दिसंबर
डेज़र्ट साइक्लोन-II	भारत-यूएई	अबू धाबी, यूएई	18-30 दिसंबर

2026 के अभ्यास

अभ्यास	साझेदार	स्थान	तिथियाँ
ICG-JCG संयुक्त अभ्यास	भारतीय तटरक्षक बल-जापान तटरक्षक बल	मुंबई	15-17 जनवरी
दोस्ती (17वाँ)	भारत, मालदीव, श्रीलंका	मालदीव	16-19 जनवरी
खंजर (13वाँ)	भारत-किर्गिस्तान	मिसामारी, असम	4-17 फरवरी
वज्र प्रहार (6ठा)	भारत-अमेरिका	विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय, बकलोह	24 फरवरी-16 मार्च
लामितिये (11वाँ)	भारत-सेशेल्स	सेशेल्स रक्षा अकादमी	9-20 मार्च
साइक्लोन-IV	भारत-मिस्र	अंशास, मिस्र	9-17 अप्रैल
DIVEX (4था)	भारतीय नौसेना-श्रीलंका नौसेना	कोलंबो	21-28 अप्रैल
CINBAX-II	भारत-कंबोडिया	कंपोंग स्पू, कंबोडिया	4-17 मई
साइ-वज्र	उत्तर प्रदेश पुलिस	-	7-13 जुलाई
टाइगर लाइटनिंग	अमेरिका-बांग्लादेश	बांग्लादेश	19-31 जुलाई
पिच ब्लैक	बहुराष्ट्रीय वायु-युद्ध	डार्विन, टिंडल, एम्बरले (ऑस्ट्रेलिया)	20 जुलाई-7 अगस्त
सदर्न रेडिनेस 26-2	बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण	कोच्चि	20-23 जुलाई
भारत-अमेरिका नौसेना EOD अभ्यास (8वाँ)	भारतीय नौसेना-अमेरिकी नौसेना	दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि	10-14 अगस्त
मैत्री (15वाँ)	भारत-थाईलैंड	सुरत थानी, थाईलैंड	18-31 अगस्त
समुद्र लक्ष्मण (4था)	भारतीय नौसेना-रॉयल मलेशियाई नौसेना	लुमुत, मलेशिया	9-12 सितंबर
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव टेबल टॉप अभ्यास	CSC के सदस्य	पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम	9-11 सितंबर
SLINEX-26 (13वाँ)	भारत-श्रीलंका	विशाखापत्तनम के तट के पास	17-21 सितंबर
काज़िंद	भारत-कज़ाखस्तान	ओस्केमेन, कज़ाखस्तान	28 सितंबर-11 अक्टूबर
माउंटेन गार्जियन	भारत-यूएई	चौबटिया, उत्तराखंड	5-18 अक्टूबर
SAREX-2026	राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास	पारादीप, ओडिशा के तट के पास	8 अक्टूबर
ऑस्ट्राहिंद (5वाँ)	भारत-ऑस्ट्रेलिया	तिरुवनंतपुरम	19 अक्टूबर-1 नवंबर
SIMBEX-2026 (33वाँ)	भारत-सिंगापुर	विशाखापत्तनम	21-26 अक्टूबर
वायु शक्ति 2026-27	भारतीय वायुसेना	पोखरण रेंज, जैसलमेर	फरवरी
उदार शक्ति	IAF-रॉयल मलेशियाई वायुसेना	सुबांग, मलेशिया	अगस्त
सुदर्शन शक्ति-V	अपहरण-रोधी और आतंक-रोधी मॉक ड्रिल	IGI हवाई अड्डा, नई दिल्ली	अगस्त

अन्य उल्लेखनीय अभ्यास (सेवावार)

अभ्यास	सेवा
युद्ध अभ्यास	थल सेना
कोप इंडिया	वायुसेना
टाइगर ट्रायम्फ	त्रि-सेवा
सी डिफेंडर्स	तटरक्षक बल

अर्थव्यवस्था

समसामयिक नोट्स

RB-IOS 2026: जुलाई से एकीकृत लोकपाल योजना

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2026 जारी की है, जो RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए एक संशोधित शिकायत निवारण तंत्र है। यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसका उद्देश्य बैंक और NBFC जैसी RBI-विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए एक कम लागत वाला, त्वरित और गैर-प्रतिकूल वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराना है।
- RBI अधिकारियों को RBI लोकपाल और उप लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है, सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए।
- RBI शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए एक केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित करेगा।
- लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले विवाद के मूल्य पर कोई सीमा नहीं है।
- लोकपाल ₹30 लाख तक का मुआवज़ा प्रदान कर सकता है।
- विनियमित संस्था के किसी कार्य या चूक से उत्पन्न सेवा में कमी के लिए शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
- कोई भी पक्ष निर्णय के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।
- प्रत्येक विनियमित संस्था को अपने प्रधान कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी नामित करना होगा।

RBI ने PSL मानदंड संशोधित किए; बैंकों की NPA कई दशकों के निचले स्तर पर

संदर्भ: RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण - लक्ष्य और वर्गीकरण) निर्देश, 2025 जारी किए। अलग से, बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर इसकी रिपोर्ट में भारतीय बैंकों की सकल NPA कई दशकों के निचले स्तर पर दिखी।

□ **PSL निर्देश, 2025**

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का उद्देश्य कमजोर वर्गों और अल्पविकसित क्षेत्रों को ऋण की आसान उपलब्धता प्रदान करना है।
- बैंकों को अब बाहरी लेखा परीक्षकों से प्रमाणन प्राप्त करना होगा ताकि एक ही अंतर्निहित ऋण को मूल बैंक और NBFC या सहकारी संस्था जैसे किसी मध्यस्थ, दोनों द्वारा PSL के रूप में दावा न किया जाए।
- लघु वित्त बैंकों के लिए PSL लक्ष्य को समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) के 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सहकारी समितियों को आगे ऋण देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को दिए गए बैंक ऋणों को अब औपचारिक रूप से PSL के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बैंक सह-ऋण के माध्यम से PSL लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, और कृषि तथा MSME को निर्यात ऋण PSL में गिना जाता है।

□ **NPA की स्थिति**

- सकल NPA अनुपात 2025 के अंत तक घटकर 2.1 प्रतिशत हो गया, और निवल NPA अनुपात मार्च 2025 तक घटकर 0.5 प्रतिशत हो गया।
- सकल NPA अनुपात 2018 में 11.18 प्रतिशत के शिखर पर था।
- कोई ऋण तब NPA बन जाता है जब ब्याज या मूलधन देय तिथि के बाद 90 दिनों तक अवैतनिक रहता है।
- निवल NPA सकल NPA में से प्रावधानों को घटाने के बराबर होता है।
- NPA के विरुद्ध प्रमुख उपकरणों में IBC 2016, SARFAESI अधिनियम 2002, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ, ऋण वसूली अधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए इंद्रधनुष योजना शामिल हैं।

किफायती आवास पर नीति आयोग का ढाँचा

संदर्भ: जनवरी 2026 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें किफायती आवास की लचीली परिभाषा और उसे बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें दी गई हैं। यह किफायती आवास को महानगरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र और ₹60 लाख तक की इकाई, तथा अन्यत्र 90 वर्ग मीटर और ₹45 लाख तक की इकाई के रूप में परिभाषित करती है। यह आवासीय भूमि का 10 प्रतिशत आरक्षित करने, पारगमन-उन्मुख ज़ोनिंग और किराये के आवास की नीतियों की अनुशंसा करती है।

□ **मुख्य बिंदु**

- ज़ोनिंग: मास्टर प्लान में कुल आवासीय भूमि का कम से कम 10 प्रतिशत किफायती आवास के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जैसा कि वियना और दक्षिण कोरिया में है।
- पारगमन-उन्मुख विकास: मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के निकट के क्षेत्रों को मिश्रित उपयोग के लिए ज़ोन किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यालय, वाणिज्यिक स्थान और किफायती आवास सम्मिलित हों।

- आरक्षण: 10,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र या 5,000 वर्ग मीटर के भूखंडों वाली परियोजनाओं में EWS/LIG आवास के लिए 10-15 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र आरक्षित होना चाहिए।
- किराये का आवास: राज्यों को PMAY-U 2.0 के किफायती किराया आवास घटक के अनुरूप, PPP के माध्यम से समर्पित किराया आवास भंडार नीतियाँ अपनानी चाहिए।

□ **परिभाषा**

- महानगरों में, 60 वर्ग मीटर तक कारपेट क्षेत्र और ₹60 लाख तक मूल्य वाली इकाई किफायती मानी जाती है।
- गैर-महानगरीय क्षेत्रों में, 90 वर्ग मीटर तक कारपेट क्षेत्र और ₹45 लाख तक मूल्य वाली इकाई किफायती मानी जाती है।
- PMAY-शहरी 2.0 (2024) किफायती आवास को समान कारपेट क्षेत्र और ₹45 लाख से अधिक न होने वाले मूल्य से परिभाषित करती है।

कोकिंग कोयला महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज घोषित

संदर्भ: कोकिंग कोयले को MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग D में जोड़ा गया है, जिसमें महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज सूचीबद्ध हैं। यह कदम खनिज सुरक्षा और इस्पात क्षेत्र में इसकी भूमिका को मान्यता देता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह केंद्र को खदानों को विनियमित करने और खनिज संसाधनों के विकास का अधिकार देता है। यह जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) का प्रावधान करता है।
- इस्पात क्षेत्र की कोकिंग कोयले की लगभग 95 प्रतिशत आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी होती है, जिससे विदेशी मुद्रा का भारी बहिर्गमन होता है।
- इस निर्णय से अनुमोदन में तेज़ी आने, कारोबार सुगमता में सुधार होने तथा गहरे स्थित भंडारों सहित अन्वेषण और खनन में तीव्रता आने की अपेक्षा है।
- कोकिंग कोयला ब्लास्ट फर्नेस इस्पात निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है और इसका उपयोग सीमेंट, रसायन तथा पेट्रोरसायन में भी होता है।
- अनुमानित भंडार 37.37 अरब टन हैं, जो मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हैं।
- 2023 के संशोधनों ने 12 परमाणु खनिजों की सूची में से 6 खनिजों को हटा दिया, केंद्र को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनिज रियायतों की विशेष रूप से नीलामी करने की अनुमति दी, और गहरे स्थित तथा महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत की।
- संबंधित पहलों में मिशन कोकिंग कोल, वाणिज्यिक कोयला खनन में 100 प्रतिशत FDI और 39 प्रथम-मील संपर्क परियोजनाएँ शामिल हैं।

त्रि-वर्षीय PPP परियोजना पाइपलाइन

संदर्भ: आर्थिक कार्य विभाग ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹12.2 लाख करोड़ के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के अनुरूप, अवसंरचना विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की तीन वर्षीय पाइपलाइन तैयार की।

□ **मुख्य बिंदु**

- इस पाइपलाइन में केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 852 परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनकी संयुक्त परियोजना लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है।
- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर BE 2025-26 में ₹11.2 लाख करोड़ हो गया।
- आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने 2014-15 से 4 दिसंबर 2025 के बीच ₹5.6 लाख करोड़ मूल्य की 129 परियोजनाओं की अनुशंसा की।
- विश्व बैंक की PPI रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत अवसंरचना में निजी भागीदारी में लगातार शीर्ष पाँच देशों में रहा है और दक्षिण एशिया में ऐसे निवेश का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत का है।
- AMRUT 2.0 के अंतर्गत, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 10 प्रतिशत परियोजनाएँ PPP के माध्यम से होनी चाहिए।
- वाढवन गहरे जल का बंदरगाह PPP के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।
- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय के 40 प्रतिशत तक को कवर कर सकता है।
- सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय का 80 प्रतिशत तक और पाँच वर्षों के लिए परिचालन व्यय का 50 प्रतिशत तक मिल सकता है।
- भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष को 2022 में लेन-देन सलाहकारों के वित्तपोषण के लिए अधिसूचित किया गया था।
- प्रस्तावित अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।

PPP निवेश मॉडल

मॉडल	विशेषता
BOT	निजी भागीदार निर्माण करता है, संचालन करता है और सरकार को हस्तांतरित करता है
LOT	मौजूदा परिसंपत्ति निजी क्षेत्र को पट्टे पर दी जाती है, संचालित की जाती है और वापस हस्तांतरित की जाती है
BOOT	निर्माण करना, स्वामित्व रखना, संचालन करना और निवेश की वसूली के बाद हस्तांतरित करना
EPC	सरकार ठेकेदार को डिज़ाइन, खरीद और निर्माण के लिए भुगतान करती है

HAM	40% का भुगतान सरकार द्वारा, 60% का डेवलपर द्वारा

निर्यात तैयारी सूचकांक 2024

संदर्भ: जनवरी 2026 में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024 का चौथा संस्करण जारी किया, जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तत्परता का आकलन करता है। यह सूचकांक, जो पहली बार 2020 में प्रकाशित हुआ था, 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के वस्तु निर्यात और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य का समर्थन करता है। राज्यों को आकांक्षी, चुनौती देने वाले या अग्रणी के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- EPI का पहला संस्करण 2020 में प्रकाशित हुआ था, और यह सूचकांक 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के वस्तु निर्यात और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- राज्यों को दो समूहों में बाँटा गया है, बड़े राज्य तथा छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और उन्हें आकांक्षी, चुनौती देने वाले या अग्रणी के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।
- बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं।
- छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, नगालैंड, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और गोवा हैं।
- उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना को नीतिगत शक्ति के रूप में उद्धृत किया गया है, जबकि NABL प्रयोगशालाओं के व्यापक नेटवर्क के अभाव के कारण वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने की उसकी क्षमता सीमित है।
- निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा 2025 में MSME, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने के लिए की गई थी।
- देशभर में निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- जिले निर्यात केंद्र के रूप में पहल 2019 में शुरू की गई थी।
- केंद्रीय बजट 2026-27 ने कूरियर निर्यात पर प्रति खेप ₹10 लाख की मूल्य सीमा को हटा दिया।

EPI के स्तंभ और भारांश

स्तंभ	भारांश
निर्यात अवसंरचना	20%
व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र	40%
नीति और शासन	20%
निर्यात प्रदर्शन	20%

निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत ऋण-संबद्ध उप-योजनाएँ

संदर्भ: जनवरी 2026 में निर्यातकों के लिए ऋण की पहुँच आसान बनाने हेतु निर्यात संवर्धन मिशन के निर्यात प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत दो पायलट ऋण-संबद्ध उप-योजनाएँ शुरू की गईं। ब्याज सहायता उप-योजना पोत-लदान से पूर्व और पश्चात के रुपया निर्यात ऋण पर 2.75 प्रतिशत की आधार ब्याज सब्सिडी देती है, जबकि CGTMSE के साथ संचालित संपार्श्विक सहायता उप-योजना सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 85 प्रतिशत तक का गारंटी कवर प्रदान करती है।

□ **ब्याज सहायता उप-योजना**

- भारतीय रुपये में पोत-लदान से पूर्व और पश्चात के निर्यात ऋण पर 2.75 प्रतिशत की आधार ब्याज सब्सिडी देती है।
- अधिसूचित कम प्रतिनिधित्व वाले या उभरते बाज़ारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिकतम वार्षिक सहायता ₹50 लाख।
- पात्र टैरिफ लाइनें वे हैं जो HS 6-अंक स्तर पर सकारात्मक सूची में हैं, जो भारत की लगभग 75 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को कवर करती हैं।

□ **संपार्श्विक सहायता उप-योजना**

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के साथ मिलकर क्रियान्वित।
- सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 85 प्रतिशत तक और मध्यम निर्यातकों के लिए 65 प्रतिशत तक का गारंटी कवर।
- प्रति निर्यातक प्रति वित्त वर्ष बकाया गारंटीकृत ऋण की ₹10 करोड़ की सीमा।

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025

संदर्भ: बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर 2025) पर जारी की गई, जो मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक चले एकीकृत नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है और 2024-25 के पशुधन उत्पादन के आँकड़े देती है। दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा, जो 3.58% अधिक है, और भारत विश्व में प्रथम है; अंडे 149.11 अरब तक पहुँचे, जिसमें भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह पशुधन संबंधी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।

□ **पशुधन की अर्थव्यवस्था**

- 2014-15 से 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्यों पर पशुधन GVA में लगभग 195% की वृद्धि हुई।
- 2023-24 में यह कृषि GVA का 31% और राष्ट्रीय GVA का 5.5% था।
- 2024-25 में पशुधन उत्पादों का निर्यात ₹66,249 करोड़ रहा, जिसमें गोजातीय मांस और खाने योग्य ऑफल जैसी मांस वस्तुएँ अग्रणी रहीं।

□ **2024-25 में उत्पादन**

- दूध: 247.87 मिलियन टन, 3.58% की वृद्धि; भारत विश्व में पहले स्थान पर है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 319 से बढ़कर 485 ग्राम/दिन हो गई। शीर्ष पाँच राज्य 54.09% उत्पादन देते हैं।
- अंडे: 149.11 अरब, 4.44% की वृद्धि; भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 62 से बढ़कर 106 अंडे प्रति वर्ष हो गई; वाणिज्यिक कुक्कुट पालन 84.49% देता है।
- मांस: 10.50 मिलियन टन, 2.46% की वृद्धि; भारत विश्व में चौथे स्थान पर है; कुक्कुट मांस लगभग आधा है।
- ऊन: 34.57 मिलियन किग्रा, 2.63% की वृद्धि।

शीर्ष उत्पादक राज्य (हिस्सेदारी)

उत्पाद	अग्रणी राज्य
दूध	उत्तर प्रदेश 15.66%, राजस्थान 14.82%, मध्य प्रदेश 9.12%, गुजरात 7.78%, महाराष्ट्र 6.71%
अंडे	आंध्र प्रदेश 18.37%, तमिलनाडु 15.63%, तेलंगाना 12.98%, पश्चिम बंगाल 10.72%, कर्नाटक 6.67%
मांस	पश्चिम बंगाल 12.46%, उत्तर प्रदेश 12.20%, महाराष्ट्र 11.57%, आंध्र प्रदेश 10.84%, तेलंगाना 10.49%
ऊन	राजस्थान 47.85%, जम्मू और कश्मीर 22.88%, गुजरात 6.22%, महाराष्ट्र 4.75%, हिमाचल प्रदेश 4.30%

भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना

संदर्भ: जनवरी 2026 में भारत लगभग 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया; यह सबसे बड़ा चावल निर्यातक भी है, जिसने 2024-25 में 20.1 मिलियन मीट्रिक टन का निर्यात किया। चावल 8 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उगाया जाता है और इसके लिए 100-150 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है, तथा राज्यवार उत्पादन में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल अग्रणी हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- चावल 8 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और समुद्र तल से लगभग 2,500 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जाता है। इसके लिए 100-150 सेमी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा दिन में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और रात में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
- 2024-25 में भारत ने 20.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया।
- भारतीय चावल के प्रमुख गंतव्यों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, बेनिन और UAE शामिल हैं।
- 2024-25 में राज्यवार उत्पादन हिस्सेदारी: उत्तर प्रदेश 13.8 प्रतिशत, तेलंगाना 11.6 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल 10.6 प्रतिशत, पंजाब 9.5 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ 7 प्रतिशत।
- सरकार ने दो नई सिंथेटिक (संश्लिष्ट) गोवंश नस्लों, कर्ण फ्राइज़ और वृंदावनी, को पंजीकृत किया, जो अधिक दूध उपज देती हैं।
- मान्यता प्राप्त देशी नस्लों में मेदिनी (झारखंड), रोहिलखंडी (उत्तर प्रदेश) और मेलघाटी (महाराष्ट्र) शामिल हैं।
- यह अपारगम्य अधोमृदा में सबसे अच्छी तरह उगता है, जिसका pH 5.5 से 6.5 के बीच हो, और इसे अपने वृद्धि काल के लगभग तीन-चौथाई समय तक खड़े पानी की आवश्यकता होती है।
- अमन शीतकालीन चावल है, जिसे जून-जुलाई में बोया जाता है और नवंबर-दिसंबर में काटा जाता है।
- औस शरदकालीन चावल है, जिसे मई-जून में बोया जाता है और सितंबर-अक्टूबर में काटा जाता है।
- बोरो ग्रीष्मकालीन चावल है, जो नवंबर से मई के बीच उगाया जाता है, प्रायः उन क्षेत्रों में जो सर्दियों में गीले रहते हैं।

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा 5.0 और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 5.0

संदर्भ: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा के पाँचवें दौर और पाँचवें राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के परिणाम घोषित किए, जिसमें रैंकिंग में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भाग लिया। गुजरात श्रेणी A में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता रहा। स्टार्टअप इंडिया ने जनवरी 2026 में दस वर्ष पूरे किए, इसलिए रैंकिंग की श्रेणियाँ और शीर्ष राज्य परीक्षा के संभावित तथ्य हैं।

□ **स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के तथ्य**

- स्टार्टअप इंडिया ने 16 जनवरी 2026 को दस वर्ष पूरे किए; 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है (2022 में घोषित)।
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 2 लाख से अधिक स्टार्टअप और लगभग 125 यूनिकॉर्न हैं।

□ **SRF 5.0 के परिणाम**

- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी A: गुजरात।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी B: अरुणाचल प्रदेश और गोवा।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी A: कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी B: हिमाचल प्रदेश।
- श्रेणी B में अग्रणी (लीडर): मणिपुर, मेघालय और नगालैंड।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 5.0 में 20 पुरस्कार श्रेणियाँ थीं, जिनमें टियर-II/III शहर और डीप-टेक शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का एफडीआई प्रवाह

संदर्भ: सरकारी आँकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का एफडीआई प्रवाह 71.28 अरब डॉलर से 14% बढ़कर 81.04 अरब डॉलर (अनंतिम) हो गया, जिसमें सेवा क्षेत्र अग्रणी रहा और महाराष्ट्र शीर्ष गंतव्य रहा। सेवा क्षेत्र 19% के साथ इक्विटी का शीर्ष प्राप्तकर्ता था, और महाराष्ट्र को इक्विटी प्रवाह का 39% मिला। एफडीआई तालिका में शीर्ष पर रहने वाले क्षेत्र और राज्य परीक्षा के सामान्य प्रश्न हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रवाह 36.05 अरब डॉलर (2013-14) से बढ़कर 2024-25 में 81.04 अरब डॉलर (अनंतिम) हो गया, जो 71.28 अरब डॉलर से 14% अधिक है।
- सेवा क्षेत्र इक्विटी का शीर्ष प्राप्तकर्ता (19%) रहा, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (16%) तथा व्यापार (8%)।
- सेवा क्षेत्र का एफडीआई 40.77% बढ़कर 9.35 अरब डॉलर हुआ; विनिर्माण एफडीआई 18% बढ़कर 19.04 अरब डॉलर हुआ।
- महाराष्ट्र के पास इक्विटी प्रवाह का 39% रहा, उसके बाद कर्नाटक (13%) और दिल्ली (12%)।
- स्रोत देश: सिंगापुर 30%, मॉरीशस 17%, अमेरिका 11%।
- 2014-25 के ग्यारह वर्षों में 748.78 अरब डॉलर आया, जो पिछले ग्यारह वर्षों (308.38 अरब डॉलर) की तुलना में 143% अधिक है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: APY, NPS वात्सल्य, PM स्वनिधि

संदर्भ: जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया, PFRDA ने NPS वात्सल्य 2025 के लिए दिशानिर्देश जारी किए, और PM स्वनिधि का विस्तार रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा के साथ किया गया। APY 18 से 40 वर्ष के गैर-करदाताओं को 60 वर्ष की आयु से ₹1,000 से ₹5,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देती है, और इसके 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। ये प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं।

□ **अटल पेंशन योजना (APY)**

- 2015 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत PFRDA द्वारा प्रशासित।
- 18 से 40 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारकों के लिए खुली है जो आयकरदाता नहीं हैं।
- 60 वर्ष की आयु से ₹1,000 से ₹5,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देती है।
- अभिदाता की मृत्यु पर पति/पत्नी को पेंशन मिलती है, और दोनों के बाद नामित व्यक्ति को संचित कोष मिलता है।
- अंशदान पर धारा 80CCD(1) के अंतर्गत कर लाभ मिलता है।
- सरकारी सह-अंशदान केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध था जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच जुड़े थे।
- 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं।

□ **NPS वात्सल्य योजना, 2025**

- PFRDA ने दिशानिर्देश जारी किए; नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।
- इसका उद्देश्य बच्चों में कम उम्र से बचत की आदत विकसित करना और उनकी भविष्य की पेंशन के लिए दीर्घकालिक अनुशासित निवेश को बढ़ावा देना है।

□ **PM स्वनिधि**

- कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए शुरू की गई।
- ऋण की किस्तें ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 हैं, तथा कार्यशील पूंजी ऋण पर 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- डिजिटल लेन-देन पर ₹1,600 तक का कैशबैक दिया जाता है।
- जिन विक्रेताओं ने दूसरी किस्त चुका दी है, या तीसरी किस्त ली है, वे अब ₹30,000 की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड के पात्र हैं।
- ऋण गारंटी का प्रबंधन CGTMSE द्वारा किया जाता है।

अनाज भंडारण और PACS का विस्तार

संदर्भ: सरकार ने अनाज भंडारण को मज़बूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष के ऋण लक्ष्य को दोगुना करने की प्रक्रिया तेज़ की, साथ ही पाँच वर्षों में सभी पंचायतों को बहुउद्देशीय PACS या डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

□ **अनाज भंडारण**

- तीसरे अग्रिम अनुमानों 2024-25 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 353.96 मिलियन टन रहा।
- 1 जुलाई 2025 को FCI और राज्य एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल के अनाज की भंडारण क्षमता 917.83 लाख टन थी।
- कृषि अवसंरचना कोष 2020 में शुरू किया गया था।
- शांता कुमार समिति (2014) ने परक्राम्य गोदाम रसीदों की सिफारिश की थी।

□ **PACS**

- एकल-राज्य PACS राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आते हैं; बहु-राज्य PACS संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत।
- स्वीकृत PACS: 79,630; नव-पंजीकृत: 32,802; डिजिटल किए गए: 61,478।
- राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 सदस्यता और महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिकाओं का विस्तार करती है।

आधार वर्ष 2022-23 के साथ भारत की नई GDP श्रृंखला

संदर्भ: MoSPI ने 27 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला जारी की, जिसमें आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया। इसमें नए डेटा स्रोतों और दोहरे अपस्फीतिकरण का उपयोग किया गया है, जिससे वास्तविक वृद्धि अनुमान बढ़ते हैं लेकिन नाममात्र GDP घटती है।

□ मुख्य बिंदु

- निजी कॉरपोरेट GVA का आवंटन कंपनी की मुख्य गतिविधि के बजाय गतिविधि-वार राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है।
- घरेलू क्षेत्र के अनुमान एक्सट्रापोलेशन के बजाय ASUSE और PLFS का वार्षिक उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।
- क्षेत्रीय उत्पादन, कॉरपोरेट मूल्य वर्धन और सक्रिय कंपनियों की पहचान के लिए GST डेटा का उपयोग किया जाता है।
- बैंकों का मापन RBI के STRBI डेटा से और NBFC का कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के डेटा से किया जाता है।
- दोहरा अपस्फीतिकरण एकल अपस्फीतिक पद्धति के स्थान पर आगतों और निर्गतों पर अलग-अलग मूल्य समायोजन लागू करता है।
- आपूर्ति एवं उपयोग तालिकाओं को राष्ट्रीय लेखों में एकीकृत किया गया है।

□ प्रभाव

- दूसरे अग्रिम अनुमानों में वित्त वर्ष 26 की वास्तविक GDP वृद्धि 7.6 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि पुरानी श्रृंखला में यह 7.4 प्रतिशत थी।
- वित्त वर्ष 26 की नॉमिनल GDP ₹345.47 लाख करोड़ है, जो पहले से लगभग 3.3 प्रतिशत कम है; वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 25 को प्रत्येक में लगभग 3.8 प्रतिशत नीचे संशोधित किया गया।
- वित्त वर्ष 26 का राजकोषीय घाटा GDP के 4.36 प्रतिशत से बढ़कर 4.51 प्रतिशत हो गया, और वित्त वर्ष 27 में ऋण-GDP अनुपात 55.6 प्रतिशत के बजाय 57.5 प्रतिशत है।
- ₹90.98 प्रति डॉलर की दर पर 2025-26 में GDP लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर है।
- भारत अपने अगले आधार वर्ष संशोधन में SNA 2025 को अपनाने की योजना बना रहा है; पिछली श्रृंखला तैयार करने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

आधार वर्ष 2024 के साथ नई CPI श्रृंखला

संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2012 के आधार को प्रतिस्थापित करते हुए आधार वर्ष 2024 के साथ नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला जारी की। जनवरी 2026 की पहली रीडिंग में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत रही।

□ मुख्य बिंदु

- CPI लास्पेयर्स सूचकांक सूत्र का उपयोग करता है और संयुक्त CPI को हेडलाइन मुद्रास्फीति के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। RBI CPI (संयुक्त) के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत रखता है, जिसमें ±2 प्रतिशत (2 प्रतिशत ऊपर-नीचे) का दायरा है।
- जनवरी 2026 के लिए अखिल भारतीय वार्षिक मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत रही, जिसमें ग्रामीण 2.73 प्रतिशत और शहरी 2.77 प्रतिशत रही।
- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 2.13 प्रतिशत और आवास मुद्रास्फीति 2.05 प्रतिशत रही।
- नई टोकरी में 358 मदें हैं, जिनमें वस्तुएँ 259 से बढ़कर 308 और सेवाएँ 40 से बढ़कर 50 हो गई हैं।
- भारांश घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 से लिए गए हैं, और आँकड़े CAPI के माध्यम से टैबलेट का उपयोग करके एकत्र किए जाते हैं।
- ग्रामीण किराये को पहली बार आवास सूचकांक में शामिल किया गया है, जबकि सरकारी और नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आवास को बाहर रखा गया है।
- ई-कॉमर्स की कीमतें 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 12 बड़े शहरों के लिए शामिल की गई हैं, और हवाई किराये तथा OTT सदस्यताओं के लिए ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
- टोकरी में ऑनलाइन मीडिया और स्ट्रीमिंग सेवाएँ तथा CNG/PNG ईंधन भी जोड़े गए हैं, और प्रथम स्तर पर 12 प्रभागों वाला COICOP 2018 अपनाया गया है।
- एक संयोजन गुणक की गणना 2025 को अधिव्यापन वर्ष मानकर की जाती है, जब 2012 और 2024 दोनों श्रृंखलाएँ उपलब्ध हैं।
- MoSPI की योजना हर 3 से 5 वर्ष में आधार वर्ष को संशोधित करने की है।

CPI 2024 बनाम CPI 2012

विशेषता	CPI 2024	CPI 2012
आधार वर्ष	2024	2012
टोकरी में मदें	358	मूल्य संग्रह के लिए 299 मदें
भारांश स्रोत	HCES 2023-24	CES 2011-12
वर्गीकरण	COICOP 2018 (12 प्रभाग)	COICOP 1999 (6 समूह)
आँकड़ा संग्रह	टैबलेट पर CAPI	कागज़ी अनुसूचियाँ
खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश	36.75%	45.86%

केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ने ऑरेंज (रचनात्मक) अर्थव्यवस्था के लिए उपाय प्रस्तावित किए, जिनमें 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब

तथा पूर्वी भारत में एक नया राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान शामिल हैं। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द 2013 में इवान डूके मार्केज़ और फेलिपे बुइट्रागो ने गढ़ा था, और 2023-24 में रचनात्मक निर्यात 11 अरब डॉलर से अधिक रहा।

□ **मुख्य बिंदु**

- ऑरेंज इकोनॉमी शब्द इवान डूके मार्केज़ और फेलिपे बुइट्रागो ने 2013 में अपनी पुस्तक में गढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था।
- भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के साथ मिलकर 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएँगी।
- AVGC क्षेत्र को 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है।
- पूर्वी भारत में एक नया राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान बनेगा; भारत में सात NID हैं।
- 2023-24 में रचनात्मक निर्यात 20 प्रतिशत बढ़कर 11 अरब डॉलर से अधिक हो गया।
- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने पाइरेसी-रोधी प्रावधान लागू किए।

केंद्रीय बजट 2026-27: राजकोषीय आँकड़े और तीन कर्तव्य

संदर्भ: केंद्रीय बजट 2026-27, जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, तीन कर्तव्यों के इर्द-गिर्द बनाया गया है: विकास को बनाए रखना, आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण, तथा सबका साथ, सबका विकास के अंतर्गत समावेशी विकास। इसमें GDP के 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है।

□ **बजट अनुमान**

- गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹36.5 लाख करोड़ और कुल व्यय ₹53.5 लाख करोड़ हैं।
- केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹28.7 लाख करोड़ हैं।
- सकल बाज़ार उधारी ₹17.2 लाख करोड़ और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाज़ार उधारी ₹11.7 लाख करोड़ है।
- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है।
- ऋण-GDP अनुपात BE 2026-27 में 55.6 प्रतिशत है, जबकि RE 2025-26 में 56.1 प्रतिशत था, और वित्त वर्ष 31 तक 50 प्रतिशत (±1 प्रतिशत) का लक्ष्य है।

□ **संरचना**

- भाग क में अर्थव्यवस्था का अवलोकन, व्यय ढाँचा, नई योजनाएँ और राजकोषीय अनुमान शामिल हैं।
- भाग ख में कर प्रस्ताव हैं।
- पहला कर्तव्य छह विकास क्षेत्रों को कवर करता है: 7 रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण, पुराने औद्योगिक समूह (क्लस्टर), चैंपियन MSME, अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा और सिटी इकोनॉमिक रीजन।

गिग श्रमिक और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटरों ने 10 मिनट की डिलीवरी समय-सीमा को छोड़ने पर सहमति जताई, जिससे गिग श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित हुआ। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की पहली कानूनी परिभाषा दी और एग्रीगेटरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना अनिवार्य किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने गिग श्रमिकों की संख्या कार्यबल के 2 प्रतिशत से अधिक आँकी।

□ **मुख्य बिंदु**

- राजस्थान ने 2023 में और कर्नाटक ने 2025 में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग श्रमिक विधेयक पारित किया। स्पेन के 2021 के राइडर कानून ने खाद्य डिलीवरी कूरियर को कर्मचारी माना।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की पहली कानूनी परिभाषा दी।
- एग्रीगेटरों को वार्षिक कारोबार का 1 से 2 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना होगा, जो ऐसे श्रमिकों को किए गए भुगतान के 5 प्रतिशत तक सीमित है।
- गिग श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं और उन्हें एक सार्वभौमिक खाता संख्या मिलती है, जिससे लाभ विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर पोर्टेबल हो जाते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने गिग श्रमिकों की संख्या कार्यबल के 2 प्रतिशत से अधिक आँकी, और लगभग 40 प्रतिशत प्रति माह ₹15,000 से कम कमाते हैं।
- यह संख्या वित्त वर्ष 21 में 77 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 120 लाख हो गई, और नीति आयोग का अनुमान है कि 2029-30 तक यह 2.35 करोड़ हो जाएगी।
- केंद्रीय बजट 2025-26 ने लगभग 1 करोड़ गिग श्रमिकों के लिए PM-JAY के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर की घोषणा की।
- यूरोपीय संघ का प्लेटफ़ॉर्म कार्य निर्देश 2024 में अपनाया गया था।
- ILO ने 2025 में प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में सम्मानजनक कार्य के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर औपचारिक चर्चा शुरू की।

दुर्लभ मृदा गलियारे और रसायन पार्क

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ने दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के लिए चार राज्यों (ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) में समर्पित गलियारों तथा ₹600 करोड़ की सहायता वाले तीन नए रसायन पार्कों की घोषणा की। दोनों का उद्देश्य आयात निर्भरता कम करना है, क्योंकि भारत ने 2022-25 के दौरान चीन से REPM का मूल्य के हिसाब से 60 से 80 प्रतिशत आयात किया।

□ **दुर्लभ मृदा गलियारे**

➤ खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गलियारे विकसित किए जाएँगे।

➤ भारत ने 2022-25 के दौरान चीन से REPM का मूल्य के हिसाब से 60 से 80 प्रतिशत आयात किया।

➤ ₹7,280 करोड़ की REPM विनिर्माण योजना का लक्ष्य 6,000 MTPA क्षमता है।

➤ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन तथा 2023 और 2025 के MMDR संशोधन अधिनियम इस क्षेत्र को सहायता देते हैं।

□ **रसायन पार्क**

➤ तीन नए रसायन पार्कों को ₹600 करोड़ की सहायता प्राप्त है।

➤ रसायन उद्योग GDP में 7 प्रतिशत का योगदान देता है और भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति

संदर्भ: फरवरी 2026 में दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख घरों में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित हैं। MNRE की यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो 2024 में शुरू हुई, 2027 तक एक करोड़ घरों को लक्षित करती है और प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का उद्देश्य रखती है। सब्सिडी की सीमा ₹78,000 है और 3 kW तक बिना गारंटी के लगभग 7 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह MNRE की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 2024 में शुरू हुई।

➤ इसका उद्देश्य प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

➤ सब्सिडी 1-2 kW के लिए ₹30,000 से 60,000 और 2-3 kW के लिए ₹60,000 से 78,000 है, तथा 3 kW से ऊपर ₹78,000 पर सीमित है।

➤ 3 kW तक बिना गारंटी के लगभग 7 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध हैं।

➤ प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर गाँव बनाया जाएगा।

बजट 2026-27 के अंतर्गत चैंपियन MSME

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ने चैंपियन MSME बनाने के लिए इक्विटी, तरलता और पेशेवर सहायता का त्रि-आयामी दृष्टिकोण निर्धारित किया। CPSE की खरीद के लिए TReDS का उपयोग अनिवार्य होगा, जिसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGTMSE गारंटी और GeM-TReDS एकीकरण का समर्थन प्राप्त है, तथा कॉरपोरेट मित्र अनुपालन में सहायता करेंगे। MSME का GDP में 31.1 प्रतिशत और निर्यात में 48.58 प्रतिशत योगदान है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ CPSE की खरीद के लिए TReDS का उपयोग अनिवार्य होगा, साथ ही इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGTMSE गारंटी, GeM-TReDS एकीकरण और प्राप्य राशियों के लिए परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियाँ होंगी।

➤ कॉरपोरेट मित्र MSME को अनुपालन में सहायता करेंगे।

➤ TReDS को RBI ने 2018 में बनाया था; केवल MSME ही विक्रेता हो सकते हैं।

➤ MSME का GDP में 31.1 प्रतिशत और निर्यात में 48.58 प्रतिशत योगदान है।

बजट 2026-27: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का भाग ख आयकर अधिनियम, 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करता है और सरलीकरण, राहत तथा सीमा शुल्क संबंधी कई उपायों का प्रस्ताव करता है। प्रत्यक्ष कर परिवर्तनों में विदेशी टूर पैकेज तथा शिक्षा और चिकित्सा के लिए LRS प्रेषण पर TCS का घटकर 2 प्रतिशत होना शामिल है, जबकि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित शुल्क-योग्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20 से घटकर 10 प्रतिशत हो गया है।

□ **प्रत्यक्ष कर**

➤ आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

➤ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा किसी प्राकृतिक व्यक्ति को दिया गया ब्याज कर से मुक्त है।

➤ विदेशी टूर पैकेज पर, तथा LRS के अंतर्गत शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण पर TCS घटकर 2 प्रतिशत हो गया है।

➤ रिटर्न संशोधित करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है; ITR 1 और 2 दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई ही रहेगी तथा गैर-लेखापरीक्षा (नॉन-ऑडिट) व्यावसायिक मामलों को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा।

➤ छोटे करदाताओं के लिए छह माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना।

➤ आईटी सेवाओं की एक एकल श्रेणी होगी जिसमें 15.5 प्रतिशत का सेफ हार्बर मार्जिन और ₹2,000 करोड़ की सीमा होगी; भारतीय डेटा केंद्रों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक कर अवकाश मिलेगा।

➤ वायदा (फ्यूचर्स) पर STT बढ़कर 0.05 प्रतिशत और विकल्प (ऑप्शंस) प्रीमियम पर 0.15 प्रतिशत हो गया है।

➤ APA को 2 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है, जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।

➤ उदारीकृत प्रेषण योजना (लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम) निवासी व्यक्तियों को प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 डॉलर तक विदेश भेजने की अनुमति देती है और इसे 2004 में शुरू किया गया था।

□ **अप्रत्यक्ष कर**

➤ व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित शुल्क-योग्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20 से घटकर 10 प्रतिशत हो गया है।

- 17 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (BCD) से छूट दी गई है, और आयात राहत के लिए सात और दुर्लभ बीमारियाँ जोड़ी गई हैं।
- परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के आयात पर शुल्क छूट 2035 तक बढ़ाई गई।
- महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं के लिए BCD छूट।
- सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम) दो वर्ष में लागू होगी और कूरियर निर्यात पर ₹10 लाख की सीमा हटा दी गई है।

बजट 2026-27: विनिर्माण, MSME और अवसंरचना संबंधी उपाय

संदर्भ: केंद्रीय बजट 2026-27 ने द्वि-स्तरीय विनिर्माण रणनीति प्रस्तावित की, जिसमें प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों में क्षमताओं का निर्माण करते हुए श्रम-प्रधान उद्योगों को बनाए रखा जाएगा, साथ ही MSME और अवसंरचना के नए उपाय भी हैं, जिनमें CCUS के लिए ₹20,000 करोड़ का परिव्यय शामिल है।

□ विनिर्माण

- जैविक और बायोसिमिलर औषधियों का पारितंत्र बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति (₹10,000 करोड़), तथा फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, उपकरण, सामग्री और संपूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0।
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय ₹22,919 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया।
- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे, तथा तीन रसायन पार्क।
- 200 पुराने औद्योगिक समूहों (क्लस्टरों) को पुनर्जीवित करने की योजना, निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण योजना और ₹10,000 करोड़ से अधिक की कंटेनर विनिर्माण योजना।
- राष्ट्रीय फाइबर योजना, समर्थ 2.0 और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल सहित एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम।

□ MSME और वित्त

- ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड और आत्मनिर्भर भारत कोष में ₹2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि।
- MSME से CPSE की खरीद के लिए TReDS अनिवार्य, तथा इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGTMSE गारंटी।
- विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति और PFC तथा REC का पुनर्गठन।
- ₹1,000 करोड़ से अधिक के नगरपालिका बॉन्ड निर्गम पर ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन।

□ अवसंरचना और ऊर्जा

- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय लगभग 9 प्रतिशत बढ़कर ₹12.2 लाख करोड़ हो गया; डनकुनी से सूरत तक नया समर्पित माल गलियारा।
- पाँच वर्षों में बीस नए राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसकी शुरुआत ओडिशा में NW-5 से होगी।
- जलमार्गों और तटीय नौवहन की हिस्सेदारी 2047 तक 6 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के लिए तटीय कार्गो संवर्धन योजना।
- कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के लिए पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़।
- सात उच्च गति रेल गलियारे, तथा पाँच वर्षों में प्रति सिटी इकोनॉमिक रीजन ₹5,000 करोड़।

बजट 2026-27: सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और पर्यटन संबंधी घोषणाएँ

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ने अपने दूसरे और तीसरे कर्तव्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, किसानों, दिव्यांगजनों और पूर्वोदय राज्यों के इर्द-गिर्द समूहित किया। घोषणाओं में पाँच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, पूर्वी भारत में राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, पंद्रह पुरातात्विक स्थलों का विकास, तथा काजू, कोको और नारियल के लिए समर्पित कार्यक्रम शामिल हैं।

□ स्वास्थ्य और शिक्षा

- निजी भागीदारी वाले पाँच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र और पाँच वर्षों में 100,000 संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर।
- तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और जामनगर में उन्नत WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र।
- उत्तर भारत में NIMHANS-2 और प्रत्येक जिला अस्पताल में आपातकालीन एवं ट्रॉमा देखभाल केंद्र।
- पूर्वी भारत में एक नया राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, पाँच विश्वविद्यालय नगर (यूनिवर्सिटी टाउनशिप) और प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास।
- राष्ट्रीय वृहत सौर दूरबीन (नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप) और हिमालयन चंद्र दूरबीन सहित चार दूरबीन एवं तारामंडल सुविधाओं का उन्नयन।

□ पर्यटन, संस्कृति और खेल

- लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित पंद्रह पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड (नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड) और 20 प्रतिष्ठित स्थलों पर 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित करने की एक पायलट परियोजना।
- NCHMCT राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी) बनेगा।
- एक दशक लंबे खेल रूपांतरण के लिए खेलो इंडिया मिशन।

- अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा के लिए बौद्ध सर्किट योजना।

□ **किसान और समावेशन**

- 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास; मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,827 सरोवर बनाए जा चुके हैं।
- काजू, कोको, नारियल, अखरोट, बादाम और भारतीय चंदन के लिए समर्पित कार्यक्रम।
- भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) एआई उपकरण, प्रत्येक जिले में शी-मार्ट (SHE-Mart) आउटलेट, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना।
- दुर्गापुर में एक नोड के साथ पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा और पूर्वोदय राज्यों के लिए 4,000 ई-बसें।

बायोफार्मा शक्ति मिशन

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ने भारत को वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति की रणनीति) की घोषणा की, जिसका परिव्यय पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ है। इसमें तीन नए NIPER, सात मौजूदा NIPER का उन्नयन, 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल परीक्षण स्थल और अधिक सशक्त CDSCO शामिल हैं, जो BioE3 नीति का पूरक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- जैविक औषधियाँ जीवित स्रोतों से बनी दवाएँ हैं, और बायोसिमिलर उनकी अत्यंत समान प्रतिलिपियाँ हैं। भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर (2014) से बढ़कर 165.7 अरब डॉलर (2024) हो गई, और 2030 के लिए 300 अरब डॉलर का लक्ष्य है; यह GDP में 4.25 प्रतिशत का योगदान देती है।
- परिव्यय पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ है।
- तीन नए NIPER स्थापित किए जाएँगे और सात मौजूदा NIPER का उन्नयन किया जाएगा।
- 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल परीक्षण स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा।
- वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए CDSCO को एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग मिलेगा।
- तीन नए NIPER और सात मौजूदा NIPER का उन्नयन।
- 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल परीक्षण स्थल।
- जटिल जैविक औषधियों के तेज़ मूल्यांकन के लिए सुदृढ़ CDSCO।
- यह BioE3 नीति और PRIP योजना का पूरक है।
- BIRAC द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन को विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित किया जाता है।
- भारत ग्रीनफील्ड फार्मा में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत FDI और ब्राउनफील्ड में 74 प्रतिशत तक FDI की अनुमति देता है।
- जैविक औषधियाँ जीवित कोशिकाओं से बनी दवाएँ हैं।
- बायोसिमिलर अत्यंत समान तथा समान रूप से सुरक्षित और प्रभावी संस्करण हैं।

भारत में कारोबार सुगमता सुधार

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ने कारोबार सुगमता को विकास के एक स्तंभ के रूप में पुनः दोहराया। 2019 में जारी डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DB 2020) में भारत की विश्व बैंक की अंतिम रैंकिंग 63वीं थी, जो पाँच वर्षों में 79 स्थानों का सुधार था। सुधारों में विनियामक अनुपालन बोझ पहल, 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने वाला जन विश्वास अधिनियम 2023, SPICe+ और ULIP शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारत 2019 में जारी डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DB 2020) में 63वें स्थान पर रहा, जो पाँच वर्षों में 79 स्थानों का सुधार था।
- 2020-21 और 2025-26 के बीच कारोबार पंजीकरण में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2020 की विनियामक अनुपालन बोझ पहल से लगभग 47,000 अनुपालनों को कम करने में मदद मिली।
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 ने 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया।
- सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 ने तीन बीमा कानूनों में संशोधन किया।
- SPICe+ DIN, PAN, TAN और GSTIN जैसी 10 सेवाओं को एकीकृत करता है, और ULIP 35 से अधिक प्रणालियों को एकीकृत करता है।

महिला श्रम बल भागीदारी और लखपति दीदी

संदर्भ: 2050 तक महिला श्रम बल भागीदारी को लगभग 55 प्रतिशत तक बढ़ाना विकास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार ने समय से पहले 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया और मार्च 2029 तक 6 करोड़ का नया लक्ष्य निर्धारित किया।

□ **महिला भागीदारी**

- WEF वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 129वें से गिरकर 131वें स्थान पर आ गया और आर्थिक भागीदारी में निचले पाँच देशों में रहा।
- महिलाएँ STEM स्नातकों में 43 प्रतिशत हैं, लेकिन STEM कार्यबल में लगभग 27 प्रतिशत हैं।
- महिलाएँ अवैतनिक कार्य पर प्रतिदिन 363 मिनट व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष 123 मिनट।
- श्रम संहिताएँ 26 सप्ताह तक के सवेतन मातृत्व अवकाश और क्रेच को बढ़ावा देने का प्रावधान करती हैं।

□ **लखपति दीदी**

- इसे 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा DAY-NRLM के अंतर्गत शुरू किया गया था।
- एक लखपति दीदी की वार्षिक घरेलू आय ₹1 लाख से अधिक होती है, जिसमें चार मौसमों या चक्रों में कम से कम ₹10,000 मासिक शामिल है।
- मार्च 2027 के लिए निर्धारित 3 करोड़ का लक्ष्य एक वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया।
- सहायता में ₹20,000-30,000 का आवर्ती कोष और प्रति SHG ₹2.5 लाख तक का सामुदायिक निवेश कोष शामिल है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0

संदर्भ: फरवरी 2026 में वित्त मंत्री ने नीति आयोग द्वारा विकसित परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 पर आधारित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) 2.0 शुरू की, जिसमें वित्त वर्ष 26 से वित्त वर्ष 30 तक ₹16.72 लाख करोड़ का मुद्रीकरण लक्ष्य है। NMP 1.0 (2021) ने अपने ₹6 लाख करोड़ के लक्ष्य का 89 प्रतिशत प्राप्त किया था। NMP 2.0 में 12 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें राजमार्गों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है।

□ **मुख्य बिंदु**

- NMP 1.0 (2021) का लक्ष्य वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 के बीच ₹6 लाख करोड़ था और उसने 89 प्रतिशत प्राप्त किया।
- NMP 2.0 में 12 क्षेत्र शामिल हैं, और ₹5.8 लाख करोड़ के निजी निवेश सहित इसकी क्षमता NMP 1.0 की 2.6 गुना है।
- राजमार्गों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत, बिजली की 17 प्रतिशत, तथा रेलवे और बंदरगाहों की 16-16 प्रतिशत है।
- यह प्रमुख परिसंपत्तियों पर केंद्रित है और DBFOT-प्रकार के PPP मॉडलों पर विचार करती है; गैर-प्रमुख परिसंपत्तियाँ केवल वहीं शामिल की गई हैं जहाँ आगे विकास की योजना है, और भूमि की विशुद्ध व्यावसायिक बिक्री को शामिल नहीं किया गया है।
- मंत्रिमंडल सचिव के अधीन परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों का कोर समूह प्रगति की निगरानी करता है।
- आय समेकित निधि, PSU या बंदरगाह प्राधिकरणों, राज्य समेकित निधियों (खान और कोयला रॉयल्टी) तथा प्रत्यक्ष निजी निवेश में जाती है।
- विजय केलकर समिति (2012) ने सबसे पहले परिसंपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव दिया था; राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम गैर-प्रमुख CPSE परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है।

NMP 2.0 में क्षेत्रवार हिस्सेदारी

क्षेत्र	लक्ष्य में हिस्सेदारी
राजमार्ग	26%
बिजली	17%
रेलवे	16%
बंदरगाह	16%
कोयला	13%

वस्त्र, पूंजीगत वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ने पाँच भागों वाले एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, पूंजीगत वस्तुओं के लिए CIE योजना और MeitY के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के लिए ₹40,000 करोड़ के बढ़े हुए परिव्यय की घोषणा की। यह परिधान, जूता-चप्पल और चमड़ा निर्यातकों के लिए निर्यात दायित्व अवधि को भी 6 से बढ़ाकर 12 माह करता है। इनका लक्ष्य विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता है।

□ **वस्त्र**

- एकीकृत कार्यक्रम के पाँच भाग हैं: राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0।
- महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल खादी और हथकरघा को सहायता देती है।
- परिधान, जूता-चप्पल और चमड़ा निर्यातकों के लिए निर्यात दायित्व अवधि 6 से बढ़कर 12 माह हो गई।

□ **पूंजीगत वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक्स**

- MeitY के अंतर्गत ECMS का परिव्यय बढ़कर ₹40,000 करोड़ हो गया।
- पूंजीगत वस्तुएँ विनिर्माण उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत का योगदान देती हैं।
- भारत वाशिंगटन समझौते का स्थायी सदस्य बना।
- राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का लक्ष्य 2025 तक विनिर्माण में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का था।

सीएजी की राज्य वित्त रिपोर्ट 2023-24

संदर्भ: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने प्रकाशन राज्य वित्त 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया, जो सभी 28 राज्यों का समेकित विश्लेषण है और जिसमें 2014-15 से 2023-24 तक का दस वर्षीय रुझान शामिल है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने भी बिना शर्त नकद हस्तांतरण के प्रति आगाह किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- राज्यों का स्वयं का कर राजस्व सबसे बड़ा घटक है, जिसका दशक भर में राजस्व प्राप्तियों में लगभग 47 प्रतिशत योगदान रहा।
- केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी का योगदान 28 प्रतिशत, सहायता अनुदान का 17 प्रतिशत और गैर-कर राजस्व का 8 प्रतिशत रहा।
- केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 में 21.34 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 29.77 प्रतिशत हो गई।

- 2023-24 में 16 राज्यों में राजस्व अधिशेष था, जबकि 12 राज्यों में राजस्व घाटा था।
- 2023-24 में 18 राज्यों का राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित GSDP के 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।
- वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे प्रतिबद्ध व्यय ने 2023-24 में राजस्व व्यय का 51.76 प्रतिशत हिस्सा लिया।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास के लिए एमएसपी सहायता हेतु ₹1,718.56 करोड़ को मंजूरी दी

संदर्भ: मार्च 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2023-24 सत्र के एमएसपी संचालन के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) को ₹1,718.56 करोड़ के वित्तपोषण को मंजूरी दी। 2023-24 के लिए एमएसपी मध्यम रेशे वाली कपास के लिए ₹6,620 प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास के लिए ₹7,020 था। एमएसपी का निर्धारण CACP की सिफारिशों पर किया जाता है, और 1970 में वस्त्र मंत्रालय के अधीन स्थापित CCI नोडल एजेंसी है।

□ मुख्य बिंदु

- 2023-24 के लिए एमएसपी: मध्यम रेशे वाली कपास के लिए ₹6,620 प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास के लिए ₹7,020।
- एमएसपी का निर्धारण CACP की सिफारिशों पर किया जाता है; CCI नोडल एजेंसी है।
- CCI की स्थापना 1970 में हुई थी, यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है।
- 2023-24 में क्षेत्रफल 114.47 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 325.22 लाख गाँठ (बेल) था।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026

संदर्भ: हेरिटेज फाउंडेशन ने मार्च 2026 में 32वाँ वार्षिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत 52.5 अंक के साथ 132वें स्थान पर है और 'अधिकांशतः अस्वतंत्र' श्रेणी में है। वाशिंगटन स्थित इस फाउंडेशन ने इसे 1995 से चार नीतिगत क्षेत्रों के 12 संकेतकों का उपयोग करके प्रकाशित किया है। सिंगापुर 84.4 अंक के साथ शीर्ष पर है और उत्तर कोरिया सबसे अंत में है, इसलिए प्रकाशक, श्रेणियाँ और शीर्ष देश महत्वपूर्ण हैं।

□ मुख्य बिंदु

- वाशिंगटन स्थित हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 1995 से प्रकाशित; चार नीतिगत क्षेत्रों में समूहित 12 संकेतक। 2026 का संस्करण मार्च 2026 में जारी; 176 देशों की रैंकिंग (184 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल)।
- सिंगापुर 84.4 अंक के साथ शीर्ष पर; उत्तर कोरिया 3.1 अंक के साथ सबसे अंत में (176वाँ), एक 'दमित' अर्थव्यवस्था।
- भारत 52.5 अंक के साथ 132वें स्थान पर है, अधिकांशतः अस्वतंत्र श्रेणी में।
- पड़ोसी देश: पाकिस्तान 152वाँ, चीन 154वाँ, मालदीव 158वाँ, म्यांमार 164वाँ (सभी दमित); श्रीलंका 144वाँ, बांग्लादेश 120वाँ, नेपाल 129वाँ।

□ श्रेणियाँ

- स्वतंत्र (80+): केवल चार देश - सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
- अधिकांशतः स्वतंत्र (70-79.9): 27 अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे लक्ज़मबर्ग 6वाँ, डेनमार्क 7वाँ, नॉर्वे 8वाँ, न्यूज़ीलैंड 12वाँ, अमेरिका 22वाँ, यूएई 23वाँ, जर्मनी 24वाँ, यूके 29वाँ, जापान 30वाँ।
- मध्यम स्वतंत्र (60-69.9): 58 अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इज़राइल, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली।
- अधिकांशतः अस्वतंत्र (50-59.9): 57 अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे भारत, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रूस।
- दमित (50 से कम)।

शीर्ष पाँच

रैंक	देश	अंक
1	सिंगापुर	84.4
2	स्विट्ज़रलैंड	83.7
3	आयरलैंड	83.3
4	ऑस्ट्रेलिया	80.1
5	ताइवान	79.8

एनएमडीसी का लौह अयस्क रिकॉर्ड और एनआईआईएफ का दूसरा कोष

संदर्भ: मार्च 2026 में NMDC एक वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) में 5 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी बनी, जबकि NIIF ने अपने दूसरे निजी बाज़ार कोष के लिए 75 करोड़ डॉलर जुटाए। NMDC इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है जिसका निगमन 1958 में हुआ था, और NIIF, जिसकी स्थापना 2015 में श्रेणी II के वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में हुई थी, में सरकार की 49% हिस्सेदारी है।

□ एनएमडीसी (NMDC)

- 1958 में निगमित; इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक।
- यह मध्य प्रदेश के पन्ना में भारत की एकमात्र यंत्रीकृत हीरा खदान का संचालन करता है।

□ एनआईआईएफ (NIIF)

- 2015 में श्रेणी II के वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित; सरकार की हिस्सेदारी 49% है।

- शासी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
- इसके पहले निजी बाज़ार कोष ने 2019 में लगभग 60 करोड़ डॉलर जुटाए थे।

नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026

संदर्भ: मार्च 2026 में नीति आयोग ने राज्यों के वित्त का आकलन करने वाला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया; राज्यों का सामान्य सरकारी ऋण में लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। पहले संस्करण में 18 प्रमुख राज्य शामिल थे, और इस संस्करण में 10 पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य जोड़े गए हैं, जिनकी रैंकिंग अलग से की गई है। सूचकांक व्यय की गुणवत्ता, राजकोषीय विवेकशीलता और ऋण धारणीयता जैसे उप-सूचकांकों का उपयोग करता है।

□ मुख्य बिंदु

- उप-सूचकांक: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेकशीलता, ऋण सूचकांक और ऋण धारणीयता।
- पहले संस्करण में 18 प्रमुख राज्य शामिल थे; इस संस्करण में 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य जोड़े गए हैं, जिनकी रैंकिंग अलग से की गई है।
- राज्यों को उपलब्धिकर्ता (अचीवर्स), अग्रणी (फ्रंट रनर), प्रदर्शनकर्ता (परफॉर्मर) और आकांक्षी (एस्पिरेशनल) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत चावल का पोषक-संवर्धन (फोर्टिफिकेशन) निलंबित

संदर्भ: मार्च 2026 में सरकार ने आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन में यह पाए जाने के बाद कि पोषक-संवर्धित चावल लंबे समय तक भंडारण के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्व खो देता है, पीएमजीकेएवाई और संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत चावल के पोषक-संवर्धन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। चावल दो से तीन वर्ष तक भंडारण में रहता है, जिसका वार्षिक आवंटन 372 LMT है। खाद्यान्न पात्रता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), ICDS और मध्याह्न भोजन का संचालन प्रभावित नहीं होगा।

□ मुख्य बिंदु

- चावल दो से तीन वर्ष तक भंडारण में रहता है।
- वार्षिक आवंटन 372 LMT है, जबकि केंद्रीय पूल में उपलब्धता 674 LMT अनुमानित है।
- खाद्यान्न पात्रता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), ICDS और मध्याह्न भोजन का संचालन प्रभावित नहीं होगा।

प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश और एलपीजी की कमी

संदर्भ: पश्चिम एशिया संघर्ष से आपूर्ति की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश जारी किया, क्योंकि एलपीजी की कमी ने भारत की भंडारण क्षमता की खामियों को उजागर कर दिया।

□ प्राथमिकता ढाँचा

- प्राथमिकता 1: घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन और पाइपलाइन आवश्यकताओं को पिछले छह माह के औसत का 100%।
- प्राथमिकता 2: उर्वरक संयंत्रों को 70%।
- प्राथमिकता 3: चाय उद्योगों और ग्रिड से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को 80%।
- प्राथमिकता 4: सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution) संस्थाओं को औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 80% देना होगा।

□ एलपीजी की कमजोरियाँ

- भारत के एलपीजी आयात का लगभग 90% होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- आयात से लगभग 60% माँग पूरी होती है; खपत लगभग 30 लाख टन प्रति माह है, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- भारत में 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 10 करोड़ 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जोड़े गए हैं।
- मंगलुरु और विशाखापत्तनम में भूमिगत गुफाएँ (कैवर्न) हैं, जिनकी कुल क्षमता 1.4 लाख टन है, जो दो दिन की खपत से भी कम है।

भव्य (BHAVYA): 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क

संदर्भ: मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों और निजी भागीदारों के सहयोग से 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए ₹33,660 करोड़ के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी। प्लग-एंड-प्ले पार्कों में भूमि, उपयोगिताएँ और अनुमोदन पहले से विकसित होते हैं। यह योजना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक स्मार्ट सिटी पर आधारित है, जिसमें NICDC 13 राज्यों में 20 परियोजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है।

□ मुख्य बिंदु

- यह राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक स्मार्ट सिटी पर आधारित है।
- DPIIT के अधीन NICDC 13 राज्यों में 20 परियोजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है।
- प्लग-एंड-प्ले पार्कों में भूमि, उपयोगिताएँ और अनुमोदन पहले से विकसित होते हैं।

राहत (RELIEF) योजना, लघु जलविद्युत योजना और पीएम ई-ड्राइव में संशोधन

संदर्भ: मार्च 2026 में सरकार ने खाड़ी देशों और पड़ोसी देशों को निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए ₹497 करोड़ की राहत (RELIEF) निर्यात

योजना (निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप - Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) शुरू की, मंत्रिमंडल ने ₹2,584.60 करोड़ के परिव्यय वाली लघु जलविद्युत विकास योजना को मंजूरी दी, और पीएम ई-ड्राइव के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। राहत (RELIEF) निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत संचालित होती है और ECGC से जुड़ा जोखिम कवर प्रदान करती है।

□ **निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत राहत (RELIEF)**

- निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप (Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) खाड़ी देशों और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, ईरान तथा यमन जैसे पड़ोसी देशों को निर्यात को कवर करता है।
- घटक 1 (₹56 करोड़) 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के लिए ECGC कवर के ऊपर 100% जोखिम कवर देता है।
- घटक 2 (₹159 करोड़) 16 मार्च से 15 जून 2026 के लिए हानि के 95% तक ECGC कवर को प्रोत्साहित करता है।
- घटक 3 (₹282 करोड़) MSME निर्यातकों को ₹50 लाख की सीमा तक 50% प्रतिपूर्ति देता है।

□ **लघु जलविद्युत और पीएम ई-ड्राइव**

- 2026-27 से 2030-31 के लिए लघु जलविद्युत योजना: लगभग 1,500 मेगावाट के लिए ₹2,584.60 करोड़ का परिव्यय।
- पीएम ई-ड्राइव: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी 31 जुलाई 2026 तक के पंजीकरण पर, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 31 मार्च 2028 तक।
- मूल्य सीमा: इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए ₹1.5 लाख और इलेक्ट्रिक तिपहिया के लिए ₹2.5 लाख; कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़।

आईएमएफ के आउटलुक में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

संदर्भ: आईएमएफ का नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक) 2026 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 4.15 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित करता है, जो जापान और यूके से पीछे है, और भारत को छठे स्थान पर रखता है। आईएमएफ को उम्मीद है कि भारत 2027 में चौथा स्थान पुनः प्राप्त कर लेगा।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारत का 2026 का GDP 4.15 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है, जो 2025 के 3.92 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
- जापान का अनुमान 4.38 ट्रिलियन डॉलर और यूके का 4.27 ट्रिलियन डॉलर है।
- भारत ने 2022 में यूके को पीछे छोड़कर पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया।
- 2025 में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुँच गया है।
- भारत के जर्मनी को पीछे छोड़ने से पहले ही जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया।
- आईएमएफ को उम्मीद है कि भारत 2027 में चौथा स्थान फिर से प्राप्त करेगा और 2031 तक तीसरा स्थान प्राप्त कर लेगा।

आयकर अधिनियम, 2025 लागू हुआ

संदर्भ: आयकर अधिनियम, 2025 ने 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लिया, जिसकी भाषा और संरचना अधिक सरल है। इसमें 536 धाराएँ, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियाँ हैं, और यह निर्धारण वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की अवधारणाओं के स्थान पर एकल 'कर वर्ष' लाता है। CBDT ने आयकर नियम, 2026 अधिसूचित किए, और फॉर्म 130 फॉर्म 16 का स्थान लेता है; ये प्रमुख परीक्षा तथ्य हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- निर्धारण वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की अवधारणा के स्थान पर एकल 'कर वर्ष'।
- नए अधिनियम में 536 धाराएँ, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियाँ हैं।
- CBDT द्वारा आयकर नियम, 2026 अधिसूचित; फॉर्म 130 TDS प्रमाणपत्र के रूप में फॉर्म 16 का स्थान लेता है।
- TDS और TCS के प्रावधान धारा 392, 393 और 394 में समेकित किए गए।
- नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक प्रभावी रूप से शून्य कर; मानक कटौती ₹75,000।
- 2025-26 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹7.99 लाख करोड़ रहा।

आरबीआई के मसौदा मानदंड: डिजिटल धोखाधड़ी, बीसी, फंसे हुए ऋण

संदर्भ: आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम पर एक चर्चा पत्र जारी किया, बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) ढाँचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा, और 1 अप्रैल 2027 से वैश्विक मानकों के अनुरूप फंसे हुए ऋणों के वर्गीकरण के नियमों में संशोधन किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 2025 में ₹22,931 करोड़ मूल्य की लगभग 28 लाख साइबर धोखाधड़ियाँ दर्ज की गईं।
- अधिकांश अधिकृत पुश-भुगतान धोखाधड़ी (ऑथराइज़्ड पुश-पेमेंट फ्रॉड) हैं, जिनमें पीड़ित छल के प्रभाव में स्वयं भुगतान शुरू करते हैं, जिससे यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी तात्कालिक प्रणालियों पर वसूली सीमित हो जाती है।
- आरबीआई ने प्रस्ताव दिया कि नए खोले गए खातों में यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएँ डिफ़ॉल्ट रूप से निष्क्रिय की जा सकती हैं।
- बैंकों से अधिक स्पष्ट धोखाधड़ी अलर्ट और तेज़ रिपोर्टिंग माध्यम उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जा सकती है।

➤ फंसे हुए ऋणों के वर्गीकरण, परिभाषा और वसूली के संशोधित नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।

□ **बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)**

➤ बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देते हैं और वित्तीय समावेशन में सहायता करते हैं; जून 2025 तक इनकी संख्या 16 लाख से अधिक थी।

➤ मसौदा मानदंड विभेदित बीसी आउटलेट, कड़ा शासन और औपचारिक पारिश्रमिक मानक लागू करते हैं, जो अंतिम रूप दिए जाने के बाद 1 जुलाई से लागू होंगे।

➤ बैंकों को बीसी आउटलेट पर शिकायत निवारण और लोकपाल (ओम्बड्समैन) का विवरण प्रदर्शित करना होगा।

ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 और नवीकरणीय क्षमता

संदर्भ: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 जारी की, जो आयात निर्भरता के जारी रहने के साथ नवीकरणीय क्षमता में तीव्र वृद्धि दर्शाती है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन क्षमता में अपनी अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि भी दर्ज की।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित संभाव्य क्षमता 47 लाख मेगावाट से अधिक है, जिसमें मार्च 2025 तक सौर लगभग 71% और पवन लगभग 25% है।

➤ स्थापित नवीकरणीय क्षमता मार्च 2016 में 90,134 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में 2,29,346 मेगावाट हो गई, जो 10.93% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) है।

➤ प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वित्त वर्ष 16 में 15,296 मेगाजूल से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 18,096 मेगाजूल हो गई।

➤ पारेषण और वितरण हानियाँ वित्त वर्ष 16 में 22% से घटकर वित्त वर्ष 25 में लगभग 17% रह गईं।

➤ नवीकरणीय क्षेत्र को ऋण 2021 में ₹1,688 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹10,325 करोड़ हो गया।

➤ भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना है।

➤ 31 मार्च 2026 तक गैर-जीवाश्म क्षमता 283.46 गीगावाट थी, जिसमें 274.68 गीगावाट नवीकरणीय और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है।

➤ नवीकरणीय ऊर्जा में 150.26 गीगावाट सौर, 56.09 गीगावाट पवन, 11.75 गीगावाट जैव-ऊर्जा, 5.17 गीगावाट लघु जलविद्युत और 51.41 गीगावाट वृहत जलविद्युत शामिल थे।

➤ स्थापित नवीकरणीय क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।

➤ वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट की पवन क्षमता वृद्धि अब तक की सर्वाधिक थी, जो मुख्यतः गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र से हुई।

टाटा धोलेरा फैब एसईजेड और सेमीकंडक्टर एसईजेड

संदर्भ: गुजरात के धोलेरा में टाटा की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र अप्रैल 2026 में अधिसूचित किया गया, और इसे देश की पहली वाणिज्यिक चिप फैब बताया गया है। मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को फरवरी 2024 में मंज़ूरी दी थी, जिसमें ₹91,000 करोड़ का प्रस्तावित निवेश है। धोलेरा और सूरत की इकाइयों के एसईजेड के साथ यह अधिसूचना भारत के सेमीकंडक्टर प्रयासों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ धोलेरा में क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड: एकीकृत कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब तथा एटीएमपी इकाई।

➤ सूरत में सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड: ओसैट (आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्ट) सुविधा।

□ **धोलेरा फैब एसईजेड**

➤ डेवलपर: टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड; स्थान: धोलेरा, गुजरात।

➤ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को फैब परियोजना को मंज़ूरी दी; एसईजेड 9 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया।

➤ क्षेत्रफल 66.166 हेक्टेयर; नियोजित क्षमता 50,000 वेफर स्टार्ट प्रति माह।

➤ प्रस्तावित निवेश ₹91,000 करोड़; लगभग 21,000 रोज़गार अपेक्षित।

➤ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा आईटी/आईटीईएस को सहयोग देता है; एक एआई-सक्षम फैब्रिकेशन सुविधा।

2025 में नियामकीय ढील के बाद अधिसूचित एसईजेड

इकाई	अधिसूचित	क्षेत्रफल	निवेश	रोज़गार	गतिविधि
माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया, साणंद	23 जून 2025	37.64 हेक्टेयर	₹13,000 करोड़	20,786	असेंबली, परीक्षण, मार्किंग, पैकेजिंग
हुब्बल्ली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर, धारवाड़	23 जून 2025	11.549 हेक्टेयर	₹100 करोड़	4,360	इलेक्ट्रॉनिक घटक
सीजी सेमी, साणंद	23 सितंबर 2025	11.541 हेक्टेयर	₹2,150 करोड़	1,911	ओसैट
कायन्स सेमीकॉन, साणंद	26 सितंबर 2025	18.44 हेक्टेयर	₹681 करोड़	2,020	ओसैट
टाटा सेमीकंडक्टर, धोलेरा	9 अप्रैल 2026	66.166 हेक्टेयर	₹91,000 करोड़	21,000	एआई-सक्षम फैब

दस वर्ष का स्टार्टअप इंडिया: मान्यता, फंड ऑफ फंड्स 2.0 और डीप-टेक मानदंड

संदर्भ: स्टार्टअप इंडिया ने 16 जनवरी 2026 को दस वर्ष पूरे किए, जिसे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार ने डीप-टेक स्टार्टअप के लिए मानदंडों में ढील दी, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 अधिसूचित किया और वित्त वर्ष 2025-26 में एक वर्ष में अब तक की सर्वाधिक स्टार्टअप मान्यता दर्ज की।

□ स्टार्टअप इंडिया ढाँचा

- स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, और इस तिथि को 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया।
- कोई इकाई निगमन से 10 वर्ष तक स्टार्टअप मानी जाती है, यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार ₹200 करोड़ से अधिक नहीं हुआ है।
- स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS 1.0, 2016 में शुरू) का प्रबंधन SIDBI द्वारा ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ किया जाता है; FFS 2.0 को अब उद्यम और विकास पूंजी जुटाने के लिए अधिसूचित किया गया है।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना में अवधारणा प्रमाण, प्रोटोटाइप और बाज़ार प्रवेश के लिए ₹945 करोड़ हैं।
- अन्य स्तंभों में स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना, स्टार्टअप इंडिया हब, MAARG मार्गदर्शन पोर्टल, इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल और राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग ढाँचा शामिल हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अकेले NIDHI ने 1,30,000 से अधिक रोज़गार सृजित किए हैं।

□ डीप-टेक स्टार्टअप

- DSIR ने डीप-टेक स्टार्टअप के लिए तीन वर्ष के निरंतर संचालन की आवश्यकता को हटाने हेतु अपने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम को संशोधित किया।
- डीप-टेक स्टार्टअप को पंजीकरण से 10 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष तक मान्यता दी जाती है।
- उनकी कारोबार सीमा बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दी गई है।
- अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना सामरिक प्रौद्योगिकियों और एक डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स को समर्थन देती है।

□ वित्त वर्ष 2025-26 का रिकॉर्ड

- वित्त वर्ष 2025-26 में 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई, जो 36,400 से 51.6% अधिक है, और प्रत्यक्ष रोज़गार 36.1% बढ़कर 3,66,870 से 4,99,400 हो गया।
- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 2.23 लाख से अधिक हैं और उन्होंने 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित किए हैं; लगभग 48% में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात केंद्र के रूप में अग्रणी हैं।
- GeM पर स्टार्टअप को दिए गए ऑर्डर ₹14,103 करोड़ से अधिक से बढ़कर ₹19,190 करोड़ से अधिक हो गए।

पीएमजीएसवाई-III का विस्तार और नई मंत्रिमंडलीय अवसंरचना मंजूरियाँ

संदर्भ: अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमजीएसवाई-III को ₹83,977 करोड़ के बढ़े हुए परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया, ₹12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ भारत समुद्री बीमा पूल को मंजूरी दी, और अरुणाचल प्रदेश में दो जलविद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। वर्ष 2019 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई-III मुख्य मार्गों (थ्रू रूट्स) और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों पर केंद्रित है, और बीमा पूल का उद्देश्य विदेशी अंडरराइटरों पर निर्भरता घटाना है।

□ मुख्य बिंदु

- वर्ष 2019 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई-III बाज़ारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों तक मुख्य मार्गों (थ्रू रूट्स) और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।
- इसका परिव्यय ₹80,250 करोड़ से संशोधित कर ₹83,977 करोड़ किया गया है।
- भारत समुद्री बीमा पूल को ₹12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी प्राप्त है और इसका उद्देश्य विदेशी अंडरराइटरों पर निर्भरता घटाना है।
- यह समुद्री भारत विज़न 2030 के अंतर्गत आता है।
- CCEA ने अरुणाचल प्रदेश में कमला (₹26,069.5 करोड़) और कलाई-II (₹14,105.83 करोड़) जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ₹40,176 करोड़ को मंजूरी दी।
- अरुणाचल प्रदेश को प्रत्येक परियोजना से 12% निःशुल्क बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए अतिरिक्त 1% प्राप्त होगा।

SRS बुलेटिन 2024: जन्म, मृत्यु और शिशु मृत्यु दरें

संदर्भ: भारत के महारजिस्ट्रार ने मई 2026 में नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2024 (खंड 59-I) और मातृ मृत्यु पर 2022-24 का विशेष बुलेटिन जारी किया। 2024 में भारत की जन्म दर घटकर 18.3 और मृत्यु दर 6.4 रही, जबकि शिशु मृत्यु दर 24 थी। बिहार में जन्म दर सर्वाधिक और केरल में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम रही, जो इसे जनांकिकी का एक प्रमुख प्रश्न बनाती है।

□ जन्म दर

- भारत की जन्म दर 1971 में 36.9 से घटकर 2024 में 18.3 हो गई (2014 में 21.0)।
- 2024 में ग्रामीण 20.2 और शहरी 14.7।
- सर्वाधिक: बिहार (26.8); न्यूनतम: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (9.9)।

□ **मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि**

- मृत्यु दर: 1971 में 14.9 से 2024 में 6.4; ग्रामीण 6.8, शहरी 5.6; पुरुष 7.1, महिला 5.6।
- सर्वाधिक मृत्यु दर: छत्तीसगढ़ (8.4); न्यूनतम: चंडीगढ़ (3.9)।
- प्राकृतिक वृद्धि दर 11.9 (ग्रामीण 13.5, शहरी 9.0); बिहार में सर्वाधिक 20.8, केरल में न्यूनतम 3.9।

□ **शिशु और मातृ मृत्यु**

- IMR: 1971 में 129, 2014 में 39 और 2024 में 24 (एक दशक में लगभग 38% की कमी)।
- ग्रामीण IMR 27, शहरी 17; सर्वाधिक छत्तीसगढ़ (36); न्यूनतम मणिपुर (2)।
- बुलेटिन में 8,839 नमूना इकाइयाँ शामिल थीं (4,960 ग्रामीण, 3,879 शहरी)।

आरबीआई द्वारा स्वर्ण वापसी 2025-26

संदर्भ: मई 2026 में सामने आया कि आरबीआई ने 2025-26 में लगातार तीसरे वर्ष 168.06 टन सोना भारत लाया, जिससे अब उसका 77 प्रतिशत सोना देश में रखा है, जबकि मार्च 2023 में यह 38 प्रतिशत था। कुल भंडार 880.52 मीट्रिक टन है। कारणों में रूस के भंडारों के जब्त किए जाने के बाद भू-राजनीतिक जोखिम, सुरक्षा, नियंत्रण और भंडारण लागत में बचत शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- वापसी 2023-24 में 107.21 मीट्रिक टन और 2024-25 में 103.68 मीट्रिक टन थी।
- कुल स्वर्ण भंडार 880.52 मीट्रिक टन है, जिसका मूल्य लगभग 122 अरब डॉलर है; मार्च 2023 में घरेलू हिस्सेदारी 38 प्रतिशत थी।
- ऊँची कीमतों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 16.7 प्रतिशत हो गई।
- कारणों में रूस के भंडारों के जब्त किए जाने के बाद भू-राजनीतिक जोखिम, सुरक्षा, नियंत्रण और भंडारण लागत में बचत शामिल हैं।
- स्वर्ण मानक 1973 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के साथ समाप्त हो गया।

ईसीएलजीएस 5.0 ऋण गारंटी योजना

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया की स्थिति से उत्पन्न तरलता संकट को कम करने के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के पाँचवें संस्करण को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य ₹2.55 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण देना है।

□ **मुख्य बिंदु**

- गारंटी राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से दी जाती है।
- कुल राशि में से ₹5,000 करोड़ विमानन क्षेत्र के लिए निर्धारित है।
- पात्र उधारकर्ता MSME, कार्यशील पूंजी सीमा वाले गैर-MSME और 31 मार्च 2026 तक मानक खाते वाली अनुसूचित यात्री विमानन कंपनियाँ हैं।
- MSME को अतिरिक्त ऋण पर 100 प्रतिशत गारंटी कवर मिलता है, जबकि गैर-MSME और विमानन कंपनियों को 90 प्रतिशत तक मिलता है।
- अतिरिक्त ऋण वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही की चरम कार्यशील पूंजी का 20 प्रतिशत तक है, जो प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ तक सीमित है।
- विमानन कंपनियाँ प्रति उधारकर्ता ₹1,500 करोड़ की सीमा के अधीन 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
- ऋण की अवधि पाँच वर्ष है जिसमें एक वर्ष की मोहलत (मोरेटोरियम) शामिल है, और विमानन कंपनियों के लिए सात वर्ष है जिसमें दो वर्ष की मोहलत शामिल है।
- यह योजना 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत ऋणों पर लागू होती है।

खरीफ MSP 2026-27: 14 फसलें अधिसूचित

संदर्भ: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, जिसमें तिलहन, दलहन और नकदी फसलों की ओर झुकाव रहा।

□ **मुख्य बिंदु**

- CCEA ने प्रधानमंत्री के अधीन 13 मई 2026 को नए MSP को मंजूरी दी।
- सबसे अधिक पूर्ण वृद्धि: सूरजमुखी बीज (₹622), कपास (₹557), रामतिल (₹515) और तिल (₹500) प्रति क्विंटल।
- बजट 2018-19 से MSP नियम: अखिल भारतीय भारित औसत लागत (A2+FL) का कम से कम 1.5 गुना।
- 2026-27 में लागत के ऊपर सर्वाधिक अनुमानित मार्जिन: मूंग (61%), इसके बाद बाजरा और मक्का (प्रत्येक 56%)।
- सभी खरीफ फसलों में तिल का MSP सबसे अधिक है, इसके बाद रामतिल का।
- खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन 28-29 मई 2026 को NASC परिसर, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
- 22 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।
- खेत बचाओ अभियान 1 से 30 जून 2026 तक चला।

चयनित खरीफ फसलों का MSP, 2026-27 (₹ प्रति क्विंटल)

फसल	MSP
धान (सामान्य)	2,441
धान (ग्रेड A)	2,461
ज्वार (संकर)	4,023
ज्वार (मालदंडी)	4,073

बाजरा	2,900
रागी	5,205
मक्का	2,410
तुअर/अरहर	8,450
मूंग	8,780
मूंगफली	7,517
कपास (मध्यम रेशा)	8,267
कपास (लंबा रेशा)	8,667
रामतिल	10,052
तिल	10,346

गन्ना एफआरपी 2026-27 और चीनी निर्यात प्रतिबंध

संदर्भ: मई 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) ₹365 प्रति क्विंटल तय किया, जो 2025-26 की तुलना में 2.81 प्रतिशत अधिक है, जबकि विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। FRP का निर्धारण CCEA द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर किया जाता है और चीनी मिलों को यह गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत कानूनन देना होता है।

□ **एफआरपी (FRP)**

- FRP 2025-26 की तुलना में 2.81 प्रतिशत अधिक है।
- इसका निर्धारण CCEA द्वारा CACP की सिफारिश पर किया जाता है और चीनी मिलों को यह गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर कानूनन देना होता है।
- यह गन्ने से चीनी की प्राप्ति (रिकवरी) से जुड़ा है।

□ **निर्यात प्रतिबंध**

- यूरोपीय संघ और अमेरिका को तरजीही कोटे को छोड़कर, कच्ची, सफेद और परिष्कृत चीनी का निर्यात सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है।
- 2025-26 में उत्पादन लगभग 275 लाख टन अनुमानित है और समापन भंडार लगभग 45 लाख टन है, जो 2016-17 के बाद सबसे कम है।
- फरवरी 2026 तक किसानों का गन्ना बकाया लगभग ₹16,087 करोड़ तक पहुँच गया।

तृतीय अग्रिम अनुमान 2025-26: खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर

संदर्भ: कृषि मंत्रालय ने 2025-26 के तृतीय अग्रिम अनुमान जारी किए, जिनमें भारत का खाद्यान्न उत्पादन 376.563 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा, जबकि 2024-25 में यह 357.732 मिलियन टन था, यानी लगभग 5.3% की वृद्धि। चावल 154.024 मिलियन टन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर रहा, तथा मूंगफली और गन्ना भी रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित हैं। फसलवार उत्पादन के आँकड़े परीक्षा की मानक सामग्री हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- खाद्यान्न: 376.563 मिलियन टन, जबकि 2024-25 में 357.732 मिलियन टन था; लगभग 18.8 मिलियन टन (5.3%) की वृद्धि।
- चावल: रिकॉर्ड 154.024 मिलियन टन (पिछला 150.184)।
- गेहूँ: 120.657 मिलियन टन (पिछला 117.945)।
- मूंगफली (13.074 मिलियन टन) और गन्ना (500.063 मिलियन टन) रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित हैं।
- कुल तिलहन 43.059 मिलियन टन; सोयाबीन 12.596 मिलियन टन; कपास 29.024 मिलियन गाँठ (प्रत्येक 170 किग्रा); जूट 9.176 मिलियन गाँठ (प्रत्येक 180 किग्रा)।
- दलहन: तुअर 3.592 मिलियन टन, चना 12.514 मिलियन टन, मसूर 1.762 मिलियन टन।

□ **2024-25 के अंतिम अनुमान**

- कुल खाद्यान्न 3,577.32 लाख टन (रिकॉर्ड); चावल 1,501.84 और गेहूँ 1,179.45 लाख टन, दोनों रिकॉर्ड।
- कुल दलहन 256.83 लाख टन; श्री अन्न 185.92 लाख टन; मक्का 434.09 लाख टन।
- तिलहन 429.89 लाख टन, जिसमें सोयाबीन और मूंगफली रिकॉर्ड स्तर पर हैं।

अग्रणी उत्पादक राज्य, 2025-26 (तृतीय अग्रिम अनुमान)

फसल	पहला	दूसरा	तीसरा
चावल	उत्तर प्रदेश (198.05 लाख टन)	तेलंगाना (185.29)	पश्चिम बंगाल (171.36)
गेहूँ	उत्तर प्रदेश (358.77)	मध्य प्रदेश (264.43)	पंजाब (170.79)
मक्का	मध्य प्रदेश (100.49)	कर्नाटक (65.51)	महाराष्ट्र (56.97)
दलहन	मध्य प्रदेश (53.48)	महाराष्ट्र (50.79)	राजस्थान (44.73)
तिलहन	राजस्थान (105.96)	गुजरात (89.35)	मध्य प्रदेश (82.40)
गन्ना	उत्तर प्रदेश (2,296.99)	महाराष्ट्र (1,316.49)	कर्नाटक (572.88)
कपास (लाख गाँठ)	महाराष्ट्र (77.55)	गुजरात (67.93)	तेलंगाना (55.54)
जूट (लाख गाँठ)	पश्चिम बंगाल (75.93)	बिहार (7.59)	असम (6.93)

थूथुकुडी मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड

संदर्भ: मई 2026 में भारत-कोरिया समुद्री ढाँचे VOYAGES के अंतर्गत तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके पक्षकार एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, एनशिप-टीएन

(NSHIP-TN) और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं। यह राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के अंतर्गत थूथुकुडी जहाज निर्माण क्लस्टर का मुख्य आधार बनेगा, जिसकी अपेक्षित वार्षिक क्षमता 2.5 मिलियन सकल टन भार (ग्रॉस टनेज) होगी।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसके पक्षकार एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, एनशिप-टीएन (NSHIP-TN) और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं।
- VOYAGES का पूर्ण रूप है Shared Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale (दक्षता और पैमाने के साथ यार्ड-सहायित विकास के संचालन के लिए साझा दृष्टि)।
- यह थूथुकुडी जहाज निर्माण क्लस्टर का मुख्य आधार बनेगा, जिसे राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के अंतर्गत सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त है।
- वार्षिक क्षमता 2.5 मिलियन सकल टन भार (ग्रॉस टनेज) होने की अपेक्षा है।

दक्षिण तट रेलवे जोन अधिसूचित

संदर्भ: मई 2026 में रेल मंत्रालय ने भारत के 18वें रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे को अधिसूचित किया, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है; यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धता की पूर्ति है। इसमें मुख्यतः दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल मंडल तथा पूर्व तट रेलवे के वाल्टेयर मंडल से अलग कर बनाया गया नया विशाखापत्तनम मंडल शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसमें मुख्यतः दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल मंडल तथा पूर्व तट रेलवे के वाल्टेयर मंडल से अलग कर बनाया गया नया विशाखापत्तनम मंडल शामिल हैं।
- इससे माल ढुलाई तथा विशाखापत्तनम, गंगावरम और कृष्णपट्टनम जैसे बंदरगाहों से संपर्क में सुधार की अपेक्षा है।

पुडुचेरी एसईजेड, एनपीएस सुनिश्चित भुगतान पैनल और केरल की गरीबी संबंधी उपलब्धि

संदर्भ: तीन संक्षिप्त आर्थिक समाचार चर्चा में रहे: मई 2026 में पुडुचेरी में दो नए एसईजेड अधिसूचित हुए, जनवरी 2026 में पीएफआरडीए ने डॉ. एम. एस. साहू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति बनाई जो एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान का ढाँचा तैयार करेगी, और 1 नवंबर 2025 को केरल को 'अत्यंत गरीबी-मुक्त' घोषित किया गया, जो ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ये परीक्षा के लिए विशिष्ट एक-पंक्ति के तथ्य हैं।

□ **पुडुचेरी में दो एसईजेड**

- अनुमोदन बोर्ड की 137वीं बैठक (27 फरवरी 2026) के बाद 27 मई 2026 को अधिसूचित।
- औलगरेट नगरपालिका (₹725 करोड़), औलगरेट तालुक के थट्टनचावडी गाँव में।
- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (₹1,250 करोड़), विल्लियनूर तालुक के करसूर गाँव में।

□ **एम. एस. साहू समिति**

- पीएफआरडीए ने 13 जनवरी 2026 को एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान का ढाँचा तैयार करने के लिए 15 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की।
- अध्यक्षता डॉ. एम. एस. साहू, आईबीबीआई के पूर्व अध्यक्ष।

□ **केरल**

- 1 नवंबर 2025 (केरल पिरवि) को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विशेष विधानसभा सत्र में केरल को 'अत्यंत गरीबी-मुक्त' घोषित किया; ऐसा करने वाला पहला राज्य।

भगोड़े आर्थिक अपराधी: ईडी के आँकड़े

संदर्भ: प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और विजय माल्या सहित 21 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और लगभग ₹2,178.34 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ जब्त की गई हैं, जैसा कि मई 2026 में बताया गया। अब तक 54 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकता है और भारत या विदेश में स्थित संपत्तियों की जब्ती का आदेश दे सकता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- अब तक 54 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।
- विशेष न्यायालय में आवेदन किया जाता है, जो किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित कर सकता है और भारत या विदेश में स्थित संपत्तियों की जब्ती का आदेश दे सकता है।
- आर्थिक अपराधों के लिए प्रयुक्त अन्य कानूनों में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002, बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 और कंपनी अधिनियम 2013 शामिल हैं।

वाडिनार जहाज मरम्मत सुविधा और कपास उत्पादकता मिशन

संदर्भ: मई 2026 में मंत्रिमंडल ने गुजरात के वाडिनार में जहाज मरम्मत सुविधा और 2026-27 से 2030-31 के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। ₹1,570 करोड़ की वाडिनार सुविधा का विकास दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा, क्योंकि भारत में 230 मीटर से बड़े जहाजों की मरम्मत की क्षमता नहीं है। ₹5,659.22 करोड़ का कपास मिशन 498 लाख गाँठ का लक्ष्य रखता है और लगभग 32 लाख किसानों को लाभ पहुँचाएगा।

□ **वाडिनार जहाज मरम्मत सुविधा**

➤ इसे दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ₹1,570 करोड़ की लागत से संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा।

➤ यह ब्राउनफील्ड परियोजना है, जिसमें 650 मीटर की जेटी और दो बड़ी तैरती शुष्क गोदियाँ (ड्राई डॉक) हैं, जो 300 मीटर तक के जहाजों की मरम्मत कर सकते हैं।

➤ भारत में 230 मीटर से बड़े जहाजों की मरम्मत की क्षमता नहीं है।

□ **कपास उत्पादकता मिशन**

➤ परिव्यय ₹5,659.22 करोड़ है, जिसे कृषि और वस्त्र मंत्रालय संचालित करेंगे।

➤ यह प्रारंभ में 14 राज्यों के 140 जिलों को कवर करता है और 2031 तक रेशा (लिंट) उत्पादकता को 440 से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करके 498 लाख गाँठ का लक्ष्य रखता है।

➤ यह खेत से रेशा, कारखाना, फैशन और विदेश (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) की 5F दृष्टि के अनुरूप है और लगभग 32 लाख किसानों को लाभ पहुँचाता है।

सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना

संदर्भ: मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना को मंजूरी दी, जो 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य में सहायक है। सिनगैस उत्पादन के लिए कोयला लिंकेज की अवधि 30 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। गैसीकरण कोयले को सिनगैस में बदलता है, जो ईंधन और रसायनों के लिए कच्चा माल है, और यह योजना 2021 के राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन पर आधारित है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी ढाँचे के अंतर्गत सिनगैस उत्पादन के लिए कोयला लिंकेज की अवधि 30 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

➤ भारत के पास लगभग 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट है, और ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक है।

➤ गैसीकरण कोयले को सिनगैस में बदलता है, जो ईंधन और रसायनों के लिए कच्चा माल है।

➤ LNG, यूरिया और मेथनॉल जैसे प्रतिस्थापन योग्य उत्पादों के आयात पर वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹2.77 लाख करोड़ खर्च हुए।

➤ यह 2021 के राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन पर आधारित है।

समुद्री खाद्य निर्यात के लिए यूरोपीय संघ की सूची में भारत बरकरार

संदर्भ: मई 2026 में यूरोपीय संघ ने सितंबर 2026 के बाद भी जलकृषि उत्पादों का निर्यात जारी रखने की अनुमति वाले देशों की अपनी संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल किया, जिससे अक्टूबर 2024 के विनियमन में हुई चूक को पलट दिया गया। एमपीईडीए (MPEDA) और निर्यात निरीक्षण परिषद ने राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम और कटाई-पश्चात परीक्षण के माध्यम से इस परिणाम को सुनिश्चित करने में सहायता की। भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 2024-25 में ₹62,408 करोड़ रहा, जिसमें जमे हुए झींगे अग्रणी रहे।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ एमपीईडीए (MPEDA) और निर्यात निरीक्षण परिषद ने राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम और कटाई-पश्चात परीक्षण के माध्यम से इस परिणाम को सुनिश्चित करने में सहायता की।

➤ भारत का मछली उत्पादन दस वर्षों में दोगुना होकर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत है।

➤ समुद्री खाद्य निर्यात 2024-25 में ₹62,408 करोड़ रहा, जिसमें जमे हुए झींगे अग्रणी रहे।

➤ मत्स्य पालन का कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 7.43 प्रतिशत योगदान है।

सेबी का PaRRVA और आरबीआई की Q-SAFE समिति

संदर्भ: मई 2026 में सेबी ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी (PaRRVA) को चालू किया, जबकि आरबीआई ने क्वांटम-सुरक्षित वित्त पर एक विशेषज्ञ समिति, Q-SAFE समिति, का गठन किया। PaRRVA निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों के पिछले प्रदर्शन के दावों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करती है, ताकि फिनफ्लुएंसरों द्वारा भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगे। आठ सदस्यीय Q-SAFE समिति, जिसके अध्यक्ष आईआईटी मद्रास के प्रो. अनिल प्रभाकर हैं, क्षेत्र की क्रिप्टोग्राफिक सूची (इन्वेंट्री) का आकलन करेगी।

□ **पैरवा (PaRRVA)**

➤ यह निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों के पिछले प्रदर्शन के दावों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करती है।

➤ पायलट परियोजना दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी और नियमित संचालन मई 2026 में शुरू हो रहा है।

➤ केयर रेटिंग्स (CARE Ratings) को PaRRVA के रूप में मान्यता दी गई है और एनएसई (NSE) PaRRVA डेटा सेंटर के रूप में कार्य करता है।

➤ इसका उद्देश्य विशेषकर अविनियमित फिनफ्लुएंसरों द्वारा किए जाने वाले भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाना है।

□ **Q-SAFE समिति**

➤ Q-SAFE का पूर्ण रूप है Quantum Secure and Adaptive Financial Ecosystem (क्वांटम-सुरक्षित और अनुकूली वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र)।

➤ आठ सदस्यीय समिति के अध्यक्ष आईआईटी मद्रास के प्रो. अनिल प्रभाकर हैं।

➤ यह क्रिप्टोग्राफी बिल ऑफ मटेरियल्स के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की क्रिप्टोग्राफिक सूची का आकलन करेगी और छह महीने में रिपोर्ट देगी।

2025-26 के लिए GDP के अनंतिम अनुमान

संदर्भ: MoSPI ने जून 2026 में 2025-26 के लिए GDP के अनंतिम अनुमान जारी किए, जिनमें नए 2022-23 आधार पर वास्तविक GDP वृद्धि 7.7% रही, तथा जनवरी-मार्च तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई। वास्तविक GDP ₹323.12 लाख करोड़ रही, जबकि 2024-25 में यह ₹299.89 लाख करोड़ थी। 2011-12 आधार का स्थान लेने वाली नई GDP श्रृंखला फरवरी 2026 में जारी की गई थी।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 5 जून 2026 को जारी।

➤ वास्तविक GDP ₹323.12 लाख करोड़, जबकि 2024-25 में ₹299.89 लाख करोड़ (7.7%)।

➤ जनवरी-मार्च 2026 तिमाही: वास्तविक GDP ₹81.36 लाख करोड़, 7.8% की वृद्धि, जबकि एक वर्ष पहले 6.9%; मौजूदा मूल्य पर GDP में 10.3% की वृद्धि; वास्तविक GVA में 8.2% की वृद्धि।

➤ नई GDP श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी की गई, जिसने 2011-12 आधार का स्थान लिया।

RBI और वित्त मंत्रालय के उपाय संक्षेप में

संदर्भ: वित्तीय क्षेत्र के कई उपायों की घोषणा की गई, जिनमें FCNR(B) जमाओं के विरुद्ध बैंक ऋण, REIT और InvIT को ऋण, CSR के लिए ZCZP लिखत, ATF के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष और संशोधित TReDS ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ RBI ने बैंकों को FCNR(B) जमाओं के विरुद्ध ऋण देने की अनुमति दी है, जिन्हें NRI और OCI 1 से 5 वर्ष के लिए रख सकते हैं और जिनका मूलधन तथा ब्याज पूरी तरह स्वदेश भेजने योग्य होता है।

➤ RBI ने बैंकों को REIT और InvIT को सीधे ऋण देने की अनुमति दी।

➤ कंपनियाँ सामाजिक शेयर बाजार के NPO के जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लिखतों के माध्यम से अपने CSR दायित्व पूरे कर सकती हैं, जो वार्षिक CSR व्यय के 10 प्रतिशत तक सीमित है।

➤ मंत्रिमंडल ने विमानन कंपनियों के लिए 36 महीने हेतु ₹10,000 करोड़ तक के कोष वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी; ATF विमानन कंपनियों की लागत का लगभग 40 प्रतिशत है।

➤ ऋण गारंटी योजना CGSMFI-2.0 छोटे NBFC-MFI के लिए चूक का 80 प्रतिशत, मध्यम के लिए 75 प्रतिशत और बड़े के लिए 70 प्रतिशत कवर करती है।

➤ सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत के पहले ब्लू बॉन्ड जारी करेगा; सेशेल्स ने 2018 में पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया था।

अल नीनो जोखिम के बीच खरीफ की तैयारी

संदर्भ: दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी, सामान्य से लगभग 43% कम वर्षा और अल नीनो के जोखिम के बीच केंद्र ने खरीफ की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। जोखिम वाले जिलों की पहचान की गई है और निगरानी ढाँचा स्थापित किया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ ICAR और ICAR-CRIDA ने सभी जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएँ तैयार कीं।

➤ प्रभावित जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवरेज बढ़ाया जाएगा।

➤ राज्य किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की गति बढ़ाएँगे।

➤ राष्ट्रीय स्तर पर एक अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और एक फसल मौसम निगरानी समूह का गठन किया गया है।

□ **जिलों की पहचान**

➤ लगभग 315 जिले कमजोर मानसून की स्थिति से संभावित रूप से प्रभावित हैं।

➤ 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं, जहाँ सिंचाई कवरेज 25% से कम है।

➤ 76 जिले मध्यम प्राथमिकता वाले हैं, जहाँ कवरेज 25 से 50% है, और 128 निम्न प्राथमिकता वाले हैं।

➤ अधिकांश जिले 12 राज्यों में हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक शामिल हैं।

असम-नगालैंड तेल और गैस अन्वेषण समझौता ज्ञापन

संदर्भ: केंद्र, असम और नगालैंड ने अपने विवादित सीमा क्षेत्र में तीन दशकों से रुके तेल और गैस अन्वेषण को फिर शुरू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन सीमा विवाद का समाधान नहीं करता।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ विवादित क्षेत्र पट्टी 1,000 वर्ग किमी से अधिक में फैली है।

➤ इसमें 50:50 संसाधन-साझाकरण सूत्र निर्धारित किया गया है।

➤ नगालैंड छह चिह्नित क्षेत्रों से आगे पूरे राज्य में अन्वेषण की अनुमति देगा।

➤ यह 31 वर्ष बाद नगालैंड की तेल उत्पादन में वापसी को दर्शाता है।

□ **संभावना**

➤ असम के पास भारत के कच्चे तेल भंडार का लगभग 22% और प्राकृतिक गैस भंडार का 15% है।

➤ पूर्वोत्तर का उत्पादन केवल 1,000 से 1,500 बैरल प्रति दिन है और यह दस गुना बढ़ सकता है।

आधार वर्ष 2022-23 के साथ नई IIP और WPI श्रृंखला

संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष संशोधित कर 2022-23 कर दिया, और वाणिज्य मंत्रालय ने उसी आधार पर उत्पादक मूल्य सूचकांकों के साथ नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला जारी की। MoSPI ने जिला घरेलू उत्पाद अनुमानों के लिए दिशानिर्देश भी अंतिम रूप दिए।

□ **संशोधित IIP**

- आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया है, जो IIP के आधार का दसवाँ संशोधन है; पहले IIP में 1937 का आधार वर्ष लिया गया था।
- खनन, विनिर्माण और बिजली के साथ अब गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन को भी शामिल किया गया है।
- वस्तुओं की टोकरी 839 से बढ़कर 1,042 उत्पादों (463 मद समूह) की हो गई है।
- खनन में अब गौण और दुर्लभ मृदा खनिज शामिल हैं; बिजली सूचकांक में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय उत्पादन को अलग-अलग दिखाया गया है।
- भार: विनिर्माण 76.062 प्रतिशत, खनन 11.053 प्रतिशत, बिजली और गैस 10.865 प्रतिशत, जल और अपशिष्ट 2.020 प्रतिशत।

□ **WPI और PPI**

- WPI का आधार 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया है, और इसे DPIIT के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है।
- नई WPI टोकरी में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और विद्युत तथा विनिर्मित उत्पादों में कुल 957 मदें हैं, जिनमें विनिर्मित उत्पादों का भार सबसे अधिक है।
- नए सूचकांकों में आउटपुट PPI, एक परीक्षण इनपुट PPI और बैंकिंग, बीमा, रेलवे तथा दूरसंचार जैसे सात क्षेत्रों के लिए सेवा PPI शामिल हैं।
- WPI और आउटपुट PPI मई 2026 से मासिक जारी होंगे और इनकी पिछली श्रृंखला अप्रैल 2023 से उपलब्ध है; WPI को चरणबद्ध रूप से हटाने से पहले दोनों पाँच वर्ष तक साथ-साथ चलेंगे।

□ **जिला घरेलू उत्पाद**

- जिला घरेलू उत्पाद अनुमानों के दिशानिर्देश आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित हैं।
- वर्तमान में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे अनुमान तैयार करते हैं।

एआरसी और बैंक ऋण बिक्री पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) और उधारकर्ताओं के बीच कथित सांठगांठ पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऋण के रूप में दिया गया सार्वजनिक धन बिना वसूली के नहीं छोड़ा जा सकता। उसने बैंकों द्वारा ऋण भारी छूट पर ARC को बेचने की प्रथा की आलोचना की, जिससे उधारकर्ता बकाये का केवल एक अंश चुकाकर निपटारा कर लेते हैं। ARC, SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत संस्थाएँ हैं जो बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) अधिग्रहित करती हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- ARC बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और प्रबंधन करती हैं; यह अवधारणा नरसिम्हम समिति II (1998) से आई थी। SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 3 में ARC के आरबीआई में पंजीकरण का प्रावधान है; 2026 में 27 ARC पंजीकृत हैं।
- 2002 में निगमित ARCIL भारत की पहली ARC थी।
- ARC को परिसंपत्तियों का समाधान 5 वर्ष के भीतर करना होता है, जिसे बोर्ड अधिकतम 8 वर्ष तक बढ़ा सकता है।
- NARCL की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी, जिसमें केनरा बैंक प्रायोजक बैंक है।
- आरबीआई (ARC) निर्देश, 2025 के अंतर्गत न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि (Net Owned Fund) ₹300 करोड़ और पूंजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का 15 प्रतिशत है।
- ARC को जारी सुरक्षा रसीदों (Security Receipts) का कम से कम 15 प्रतिशत धारित करना होता है।

□ **न्यायालय की टिप्पणियाँ**

- न्यायालय ने उस अति-चतुर युक्ति की आलोचना की जिसमें बैंक ऋण भारी छूट पर ARC को बेच देते हैं और उधारकर्ता बकाये का केवल एक छोटा हिस्सा चुकाकर निपटारा कर लेते हैं।
- उसने कहा कि जहाँ सार्वजनिक धन शामिल हो, वहाँ ARC को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढाँचे पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।
- उसने कहा कि बैंक लापरवाही से ऋण माफ करने के बहाने के रूप में वाणिज्यिक विवेक का उपयोग नहीं कर सकते।

कृषि-खाद्य योजनाएँ: SARTHAK-PDS, बीज भंडार, स्मार्ट वेयरहाउसिंग

संदर्भ: जून 2026 में खाद्य और कृषि संबंधी उपायों की घोषणा की गई, जिनमें SARTHAK-PDS, राष्ट्रीय बीज भंडार, सामुदायिक बीज बैंक मानक और स्मार्ट वेयरहाउसिंग प्रणाली शामिल हैं। SARTHAK-PDS राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन और FPS डीलर मार्जिन योजना को SMART PDS में मिला देता है; यह मार्च 2031 तक चलेगा और लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों के लिए इसका परिव्यय ₹25,530 करोड़ है।

□ **मुख्य बिंदु**

- स्मार्ट वेयरहाउसिंग प्रणाली 215 CWC गोदामों में AI और IoT का उपयोग करती है, और FCI 150 और गोदाम जोड़ेगा।

- 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार कृषि उन्नति योजना में NFSNM के अंतर्गत एक हस्तक्षेप है, जो SATHI पोर्टल का उपयोग करता है।
- BIS ने सामुदायिक बीज बैंकों के लिए स्वैच्छिक मानक IS 20201:2026 जारी किया।
- मिशन सेनेहजोरी का लक्ष्य असम मूगा रेशम मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है; मूगा भारत का पहला GI-टैग प्राप्त रेशम (2007) है और असम विश्व उत्पादन का 90 प्रतिशत देता है।
- त्रिपुरा के लिए मिशन क्लीन पाइनएप्पल शुरू किया गया, जिसका राज्य फल अब अनानास है।

□ **SARTHAK-PDS**

- यह राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन और FPS डीलर मार्जिन की योजना को SMART PDS में मिला देता है।
- यह 31 मार्च 2031 तक चलेगा, इसका परिव्यय ₹25,530 करोड़ है और यह लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों को कवर करता है।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मिलता है।

कोयला एक्सचेंज नियम 2026

संदर्भ: सरकार ने कोयले के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाने हेतु कोयला एक्सचेंज नियम 2026 जारी किए। ये MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 के अनुरूप हैं, जिसने खनिज एक्सचेंज की अवधारणा प्रस्तुत की।

□ **मुख्य बिंदु**

- कोयला एक्सचेंजों का पंजीकरण और विनियमन करने वाले प्राधिकरण के रूप में कोयला नियंत्रक संगठन को दिसंबर 2025 में नामित किया गया।
- पंजीकरण 25 वर्ष के लिए दिए जाएँगे।
- कोयला एक्सचेंज कई क्रेताओं और विक्रेताओं को मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा देता है, जिससे एक-से-अनेक बिक्री के बजाय अनेक-से-अनेक व्यापार की ओर बदलाव होता है।
- इससे मूल्य खोज में सुधार और वाणिज्यिक तथा कैप्टिव खनिकों के लिए क्रेताओं का विस्तार होने की अपेक्षा है।

डिजिटल धोखाधड़ी के लिए RBI का क्षतिपूर्ति ढाँचा

संदर्भ: RBI ने डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए संशोधित नियम जारी किए, जिससे ग्राहक की देयता सीमित करने वाले 2017 के ढाँचे का विस्तार हुआ है। ये नियम 1 जनवरी 2027 से एक वर्ष के लिए पायलट के रूप में लागू होंगे।

□ **मुख्य बिंदु**

- वित्त वर्ष 2025-26 में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले आधे से अधिक घटकर 10,114 रह गए, लेकिन राशि 46% बढ़कर ₹48,021 करोड़ हो गई।
- नई अवधारणा कपटपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की है, जो धोखाधड़ी से प्राप्त क्रेडेंशियल या दबाव में ग्राहक की स्वीकृति के माध्यम से किए जाते हैं।
- ₹50,000 तक की हानि पर पीड़ितों को हानि का 85% या ₹25,000, जो भी कम हो, जीवन में एक बार मिलता है।
- डिजिटल अरेस्ट के मामले और धोखाधड़ी से प्राप्त OTP इसमें शामिल हैं।
- शिकायत पाँच कैलेंडर दिनों के भीतर दर्ज करानी होगी।
- बैंकों को घरेलू शिकायतों का समाधान 45 दिनों में और सीमा-पार शिकायतों का 60 दिनों में करना होगा।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम 2026 और संहिता का एक दशक

संदर्भ: संसद ने अप्रैल 2026 में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित किया, जिसमें 12 संशोधन थे (11 प्रवर समिति से और एक सरकार की ओर से), और संहिता के दस वर्ष पूरे होने पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने बाद में इस अधिनियम को अधिसूचित किया। यह कानून समाधान को तेज करता है और न्यायालय के बाहर की प्रक्रिया, समूह दिवालियापन तथा सीमा-पार दिवालियापन के ढाँचे जोड़ता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- आईबीसी (IBC) 2016 में टी. के. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली दिवाला कानून सुधार समिति की सिफारिशों पर अधिनियमित की गई थी, और इससे पहले इसमें छह बार संशोधन किया जा चुका था। बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) वित्त वर्ष 18 में 11.5 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 26 में 2.3 प्रतिशत रह गईं।
- चूक सिद्ध होने पर NCLT को चूक के 14 दिनों के भीतर आवेदन स्वीकार करना होगा और वह अन्य आधारों पर उसे अस्वीकार नहीं कर सकता।
- लेनदार-प्रारंभित दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIIRP), एक मिश्रित न्यायालय-बाह्य तंत्र है, जिसके लिए कम से कम 51% वित्तीय लेनदारों की सहमति आवश्यक है।
- सक्षमकारी ढाँचे कॉर्पोरेट समूह की संस्थाओं के समन्वित समाधान और सीमा-पार दिवालियापन (विदेशी कार्यवाहियों की मान्यता और न्यायालयों के सहयोग) को कवर करते हैं।
- परिसमापन लचीला है, जिसमें व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की बिक्री और गारंटरों की परिसंपत्तियों को शामिल करना सम्मिलित है; इसे 180

दिनों में पूरा होना चाहिए, जिसे अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

- लेनदार परिसमापन की निगरानी कर सकते हैं और परिसमापक को बदल सकते हैं, और किसी कॉर्पोरेट देनदार का समाधान पेशेवर उसका परिसमापक नहीं बन सकता।
- NCLAT अपीलों के लिए तीन माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- पूर्व-निर्मित (प्री-पैकेज्ड) दिवाला के लिए मतदान सीमा घटाकर 51% कर दी गई है, और MSME के लिए PPIRP मार्ग 120 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिए; स्वच्छ-पट्टिका (क्लीन-स्लेट) सिद्धांत को सुदृढ़ किया गया है।
- लेनदारों ने ₹4 लाख करोड़ से अधिक की वसूली की है, और समाधान किए गए मामलों से अनुमानित परिसमापन मूल्य का औसतन 170 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

पर्यटन रिपोर्ट और सरकारी योजनाएँ

संदर्भ: पर्यटन मंत्रालय और नीति आयोग ने विनियमन को सरल बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिए अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर (2026) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह विश्व आर्थिक मंच (WEF) के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत के 39वें स्थान और होटल स्वीकृति की लंबी समय-सीमा की ओर संकेत करती है तथा स्वदेश दर्शन, प्रसाद, सास्की (SASCI) और क्रूज भारत मिशन जैसी योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

□ मुख्य बिंदु

- स्वदेश दर्शन 2014 में शुरू हुआ और विषयगत, सतत गंतव्यों के लिए SD 2.0 2022 में शुरू हुआ।
- प्रसाद (PRASHAD, 2014) तीर्थ स्थलों का उन्नयन करता है, जिसके अंतर्गत ₹1,168 करोड़ की 54 परियोजनाएँ हैं।
- सास्की (SASCI, 2024-25) 40 प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए ₹3,295.76 करोड़ प्रदान करती है।
- क्रूज भारत मिशन (2024-29) में 51 नए क्रूज सर्किट की योजना है।
- बजट 2026-27 में राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की घोषणा की गई।

□ पर्यटन की स्थिति

- WEF यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (2024) में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा।
- यह 231.6 अरब डॉलर के साथ 8वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है, जिसका 2023-24 में GDP में 5.22 प्रतिशत योगदान रहा।
- भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन और 3 ट्रिलियन डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था है।
- भारत का वीज़ा ओपननेस इंडेक्स स्कोर 38.14 है, जो वैश्विक औसत 40 से कम है।
- भारत में एक होटल परियोजना में 36 से 48 महीने लगते हैं, जबकि आसियान प्रतिस्पर्धियों में 12 से 18 महीने लगते हैं।

पीएसी ने पीएमकेवीवाई में कमियों को उजागर किया

संदर्भ: संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने जून 2026 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के प्रदर्शन पर चिंता जताई और कमजोर नियुक्ति (प्लेसमेंट), आँकड़ों की कमियों तथा वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया। PMKVY, जिसे 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया और जिसे NSDC लागू करता है, प्रमुख अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण योजना है और परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाने वाला विषय है।

□ मुख्य बिंदु

- PMKVY को 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया था और इसे NSDC लागू करता है। योजना भौतिक लक्ष्यों और निधियों का 75 प्रतिशत NSDC के लिए तथा 25 प्रतिशत राज्य कौशल विकास मिशनों के लिए निर्धारित करती है।
- NSDC की स्थापना 2008 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के रूप में की गई थी, जिसमें 49 प्रतिशत सरकारी और 51 प्रतिशत निजी शेयरधारिता है।

भारत का मध्यम वर्ग और घरेलू ऋण

संदर्भ: बढ़ती आय और शहरीकरण के साथ भारत का मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, हालाँकि घरेलू ऋण और आय असमानता चिंता के बढ़ते विषय हैं। मार्च 2026 तक घरेलू ऋण GDP के 45.5 प्रतिशत तक पहुँच गया, जबकि विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि 2036 तक मध्यम वर्ग और संपन्न उपभोक्ता कुल खर्च का 93 प्रतिशत होंगे। यह मुद्दा PMMY और एकीकृत पेंशन योजना जैसी योजनाओं से जुड़ा है।

□ मुख्य बिंदु

- विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि 2036 तक मध्यम वर्ग और संपन्न उपभोक्ता कुल खर्च का 93 प्रतिशत होंगे, जो 2026 में 80 प्रतिशत है।
- निजी अंतिम उपभोग में 7 प्रतिशत की वृद्धि और GDP में 61.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 12 के बाद सबसे अधिक है।
- भारत की प्रति व्यक्ति GNI लगभग 2,600 डॉलर है, जबकि उच्च-मध्यम आय की सीमा लगभग 4,500 डॉलर है।
- मार्च 2026 तक घरेलू ऋण GDP के 45.5 प्रतिशत तक पहुँच गया।
- विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 65 प्रतिशत है।
- बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के अंतर्गत शून्य-कर सीमा बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई (वेतनभोगियों के लिए ₹12.75 लाख)।
- एकीकृत पेंशन योजना 2025 से प्रभावी है।
- PMMY ने मार्च 2026 तक 57 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए हैं, जिनकी कुल राशि ₹40.07 लाख करोड़ है।

➤ 2019 में शुरू किए गए स्वामीह (SWAMIH) कोष ने 146 परियोजनाओं में 58,000 से अधिक आवास पूरे किए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23

संदर्भ: स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 की रूपरेखा के अंतर्गत तैयार 2022-23 के नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान दर्शाते हैं कि कुल स्वास्थ्य व्यय GDP का 3.37%, अर्थात ₹8,81,359 करोड़ है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय कुल व्यय का 43.72% (GDP का 1.48%) था, जबकि परिवारों का स्वयं का जेब से व्यय 43.41% था। इन हिस्सेदारियों और GDP प्रतिशतों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

□ मुख्य बिंदु

➤ कुल स्वास्थ्य व्यय: ₹8,81,359 करोड़; प्रति व्यक्ति ₹6,373।

➤ चालू स्वास्थ्य व्यय ₹7,66,814 करोड़ (87%); पूंजीगत व्यय ₹1,14,545 करोड़ (13%)।

➤ सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹3,85,332 करोड़: कुल का 43.72% और GDP का 1.48%; प्रति व्यक्ति ₹2,786।

➤ परिवारों का जेब से व्यय ₹3,82,629 करोड़ (43.41%); प्रति व्यक्ति ₹2,767।

➤ निजी स्वास्थ्य बीमा ₹81,012 करोड़ (9.19%)।

➤ देखभाल के स्तर के अनुसार: प्राथमिक लगभग 46%, द्वितीयक 34%, तृतीयक 15%, शासन 4%; सरकारी चालू व्यय का 51% प्राथमिक देखभाल पर खर्च होता है।

➤ औषधियाँ चालू स्वास्थ्य व्यय का 29.6% हैं; पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा 3.5%।

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

संदर्भ: हाल के महीनों में रुपया 96.96 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुँच गया। इस गिरावट ने इस बहस को फिर शुरू कर दिया है कि RBI को मुद्रा की रक्षा करनी चाहिए या उसे अपना स्तर स्वयं खोजने देना चाहिए। दबाव का कारण बढ़ता व्यापार घाटा, कच्चे तेल और सोने का भारी आयात बिल तथा इक्विटी से विदेशी निवेशकों की निकासी है, जिससे प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर प्रणाली परीक्षा का एक प्रमुख विषय बन गई है।

□ विनिमय दर प्रणाली

➤ 1993 से भारत में बाजार-निर्धारित विनिमय दर प्रणाली है, जो व्यवहार में प्रबंधित अस्थायी दर है।

➤ दर विदेशी मुद्रा की माँग और आपूर्ति, पूंजी प्रवाह, व्यापार संतुलन, मुद्रास्फीति और ब्याज दर अंतर तथा निवेशक विश्वास पर निर्भर करती है।

□ दबाव के कारण

➤ भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 90% आयात करता है; 2025-26 में कच्चे तेल का आयात बिल लगभग 144 अरब डॉलर था।

➤ 2025-26 में सोने का आयात 71.98 अरब डॉलर रहा, जो 24% की वृद्धि है।

➤ वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 860.09 अरब डॉलर (4.2% की वृद्धि) रहा, जबकि आयात 979.4 अरब डॉलर (लगभग 6.5% की वृद्धि) रहा।

➤ व्यापार घाटा 94.7 अरब डॉलर से बढ़कर 119.3 अरब डॉलर हो गया।

➤ विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से धन निकाला, और मजबूत डॉलर ने दबाव को और बढ़ाया।

□ आगे की राह

➤ RBI का संतुलित हस्तक्षेप सहायक है, लेकिन संरचनात्मक कदम अधिक महत्वपूर्ण हैं।

➤ भारत को तेल पर कम निर्भरता, सोने के पुनर्चक्रण, सुदृढ़ निर्यात क्षमता और स्थिर दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता है।

लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और जहाज पुनर्चक्रण

संदर्भ: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ नाविकों और समुद्री हितधारकों के लिए चार डिजिटल पहलें शुरू कीं। अंकटाड (UNCTAD) के आँकड़े भी भारत को 2025 में विश्व का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र दर्शाते हैं।

□ लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और डिजिटल पहलें

➤ सागर आंकलन ढाँचे के अंतर्गत निर्मित LPPI जहाज की वापसी अवधि (टर्नअराउंड), बर्थ निष्क्रिय समय और कंटेनर ठहराव समय जैसे संकेतकों का उपयोग करके शुष्क थोक, तरल थोक और कंटेनर खंडों का मानक-मूल्यांकन करता है।

➤ शुष्क थोक में पारादीप पत्तन प्राधिकरण शीर्ष पर रहा, तरल थोक में सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स अग्रणी रहा और कंटेनर कार्गो में मुंद्रा पोर्ट अग्रणी रहा, जिसमें जेएनपीए (JNPA) दूसरे स्थान पर रहा।

➤ ई-नाविक (e-Navik) प्लेटफ़ॉर्म समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 के अनुरूप 24x7 समुद्री शिकायत निवारण प्रणाली है।

➤ एकीकृत जहाज पुनर्चक्रण पोर्टल हांगकांग अभिसमय (HKC) के अनुरूप भारतीय यार्डों में पुनर्चक्रित जहाजों के लिए कबाड़ मूल्य का 40 प्रतिशत क्रेडिट नोट प्रदान करता है, जिसे नए भारतीय जहाज निर्माण के विरुद्ध भुनाया जा सकता है।

➤ ई-समुद्र (e-Samudra) पर एक डिजिटल जहाज पंजीकरण मॉड्यूल और एक चिकित्सा व्यवसायी मॉड्यूल भी शुरू किए गए।

➤ विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में भारत की रैंक 44वें से सुधरकर 22वें स्थान पर पहुँच गई।

□ क्षेत्र की स्थिति और जहाज पुनर्चक्रण

➤ वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी 2024 में 30.1 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 35.4 प्रतिशत हो गई, जो 2.99 मिलियन सकल टन

(लगभग 60% की वृद्धि) तक पहुँची; इसका लगभग 98 प्रतिशत अलंग-सोसिया में होता है।

- इससे समय से पहले ही जहाज पुनर्चक्रण में अग्रणी रहने का मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लक्ष्य पूरा हो गया; MIV 2030 का लक्ष्य वैश्विक जहाज निर्माण में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करना भी है।
- जहाज पुनर्चक्रण पर हांगकांग अभिसमय 26 जून 2025 को लागू हुआ।
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना का परिव्यय ₹24,736 करोड़ है और समुद्री विकास कोष की कोष राशि ₹25,000 करोड़ है।
- जहाज निर्माण विकास योजना का परिव्यय ₹19,989 करोड़ है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है।
- भारत की तटरेखा 11,099 किमी है और यहाँ 12 प्रमुख बंदरगाह तथा 200 से अधिक लघु बंदरगाह हैं, जो व्यापार की मात्रा का 95 प्रतिशत संभालते हैं।

विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जी-सेक सुधार

संदर्भ: वित्त मंत्रालय ने जून 2026 में सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। उपायों में ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर कर छूट तथा पूर्ण सुलभ मार्ग (FAR) के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विस्तार शामिल है, जो विदेशी निवेशकों के लिए एक खुली पहुँच वाला माध्यम है। यह जी-सेक, ट्रेजरी बिल और राज्य विकास ऋण (SDL) को दोहराने का उपयुक्त अवसर है।

□ मुख्य बिंदु

- जी-सेक (G-Secs) आरबीआई की नीलामी के माध्यम से ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म पर जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की अवधि के होते हैं और शून्य-कूपन होते हैं।
- उपायों में ब्याज आय, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर छूट तथा पूर्ण सुलभ मार्ग (FAR) के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विस्तार शामिल हैं।
- FAR विदेशी निवेशकों के लिए सामान्य मार्ग (General Route) के प्रतिबंधों के बिना चुनिंदा जी-सेक खरीदने का खुली पहुँच वाला माध्यम है।
- सूचीबद्ध भारतीय इक्विटी में व्यक्तिगत भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों (PROI) की समग्र सीमा 10 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है।
- 2010 में शुरू किए गए नकद प्रबंधन बिलों की परिपक्वता अवधि 91 दिन से कम होती है।
- राज्य केवल दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करते हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।

विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026

संदर्भ: विश्व आर्थिक मंच ने एक्सेंचर के साथ मिलकर जून में अपना ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 जारी किया, जिसमें भारत को 54.9 अंक के साथ 70वाँ स्थान मिला, जो दो स्थान का सुधार है। सूचकांक वर्तमान प्रदर्शन और तैयारी के 44 संकेतकों का उपयोग करते हुए 120 देशों को शामिल करता है। 2025 में वैश्विक ऊर्जा निवेश रिकॉर्ड 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया। प्रकाशक, कवरेज और भारत की रैंक परीक्षा के संभावित तथ्य हैं।

□ मुख्य बिंदु

- 18 जून 2026 को जारी; वर्तमान प्रदर्शन और तैयारी के 44 संकेतकों का उपयोग करते हुए 120 देशों को शामिल करता है।
- 2025 में वैश्विक ऊर्जा निवेश रिकॉर्ड 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- भारत 54.9 अंक के साथ 70वें स्थान पर रहा, दो स्थान का सुधार।

शीर्ष पाँच

रैंक	देश	अंक
1	स्वीडन	75.3
2	फिनलैंड	74.1
3	डेनमार्क	72.6
4	एस्टोनिया	70.9
5	नॉर्वे	70.5

विश्व बैंक, हुरुन यूनिकॉर्न और मत्स्य पालन रिपोर्टें

संदर्भ: जून 2026 में जारी वैश्विक रिपोर्टों ने भारत की अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप को संदर्भ में रखा, जिनमें विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स और FAO की SOFIA रिपोर्ट शामिल हैं। विश्व बैंक ने भारत के लिए 1.5 अरब डॉलर के विकास नीति वित्तपोषण पैकेज को भी मंजूरी दी, और भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ हुरुन सूचकांक में चौथे स्थान पर खिसक गया।

□ मुख्य बिंदु

- विश्व बैंक ने भारत के लिए 1.5 अरब डॉलर के विकास नीति वित्तपोषण पैकेज को मंजूरी दी।
- ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स 2026 का अनुमान है कि विश्व वृद्धि 2025 के 2.9 प्रतिशत से घटकर 2026 में 2.5 प्रतिशत रह जाएगी; दक्षिण एशिया 6.3 प्रतिशत के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है।
- भारत में 61 यूनिकॉर्न हैं और वह हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में चौथे स्थान पर खिसक गया; बेंगलुरु में 25 और मुंबई में 13 हैं।
- FAO की SOFIA 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व जलीय उत्पादन 23.5 करोड़ टन रहा, जिसमें जलकृषि का हिस्सा 53 प्रतिशत है।

➤ भारत ने वैश्विक जलीय पशु उत्पादन का 9 प्रतिशत उत्पादित किया, चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा, और अंतर्देशीय प्राकृतिक मत्स्य पालन में पहले स्थान पर है।

सीएजी राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25

संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट जारी की, जो 2015-16 से 2024-25 तक सभी 28 राज्यों की राजकोषीय स्थिति की दस वर्षीय तुलना है। इसमें व्यापक राजकोषीय घाटे और राज्यों की देनदारियों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 2024-25 में सभी 28 राज्यों में राजकोषीय घाटा रहा, और 18 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित GSDP के 3% की सीमा का उल्लंघन किया।

➤ मेघालय में सबसे अधिक घाटा GSDP का 8.69% रहा, उसके बाद नगालैंड 6.14% और सिक्किम 5.59% रहे।

➤ कुल बकाया सार्वजनिक ऋण ₹75.52 लाख करोड़ (GSDP का 23.27%) रहा, जबकि 31 मार्च 2025 तक कुल बकाया देनदारियाँ ₹90.51 लाख करोड़ (GSDP का 27.89%) तक पहुँच गईं।

➤ राज्यों का कुल व्यय 2015-16 में ₹22.18 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹51.20 लाख करोड़ हो गया, यानी 131 प्रतिशत की वृद्धि।

➤ राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.41 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 16.59 प्रतिशत था।

➤ तेरह राज्यों में राजस्व अधिशेष था, जबकि 15 राज्यों में राजस्व घाटा था।

□ **व्यय और राजस्व का स्वरूप**

➤ प्रतिबद्ध व्यय, सब्सिडी और अनुदान मिलकर राजस्व व्यय के 61 प्रतिशत से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार रहे।

➤ एक दशक में सब्सिडी पर व्यय तीन गुना से अधिक हो गया; कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब ने प्रत्येक ने अपने कुल व्यय का 13.5 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी पर खर्च किया।

➤ राज्यों का अपना कर राजस्व दोगुने से अधिक होकर ₹8.4 लाख करोड़ से ₹20.31 लाख करोड़ हो गया, जिसमें राज्य GST का योगदान 43 प्रतिशत से अधिक रहा।

➤ संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में राज्यों की हस्तांतरण हिस्सेदारी 2015-16 के 27.73 प्रतिशत से बढ़कर 31.76 प्रतिशत हो गई, फिर भी राज्य हस्तांतरण और सहायता अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

ISP और संशोधित कोर उद्योग सूचकांक जारी

संदर्भ: MoSPI ने सेवा उत्पादन सूचकांक शुरू किया, जो औपचारिक सेवा क्षेत्र का भारत का पहला मासिक संकेतक है, जबकि कोर उद्योग सूचकांक को आधार वर्ष 2022-23 पर संशोधित किया गया। संशोधित सूचकांक कोर उद्योग श्रृंखला को संशोधित GDP, मुद्रास्फीति और IIP श्रृंखलाओं के अनुरूप बनाता है।

□ **सेवा उत्पादन सूचकांक**

➤ पहला परीक्षण ISP अप्रैल 2026 के लिए 14 जुलाई को जारी किया गया, जिसका आधार वर्ष 2024-25 है।

➤ यह 19 उप-क्षेत्रों को कवर करता है, जो सेवा क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत है, और IIP का सेवा-क्षेत्र समकक्ष है।

➤ यह मुख्यतः GST-पंजीकृत उद्यमों पर आधारित है और लोक प्रशासन, रक्षा तथा अनौपचारिक गतिविधियों को शामिल नहीं करता।

➤ यह स्थिर भार वाले लास्पेयर्स मात्रा सूचकांक का उपयोग करता है।

□ **संशोधित कोर उद्योग सूचकांक**

➤ आधार वर्ष 2022-23 वाली नई श्रृंखला 2011-12 की श्रृंखला का स्थान लेती है और इसे DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

➤ लौह अयस्क को नौवें कोर उद्योग के रूप में जोड़ा गया है; पहले के आठ उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट, बिजली और उर्वरक थे।

➤ IIP में कोर उद्योगों का संयुक्त भार 32.88 प्रतिशत है, जो पहले 40.27 प्रतिशत था।

➤ इस्पात को अब IIP की तरह सकल उत्पादन आधार पर मापा जाता है, और दोहरी गणना से बचने के लिए कोयले में केवल कच्चा कोयला शामिल है।

LokOS, SHE-LEAPS और लखपति दीदी लक्ष्य

संदर्भ: SHG महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म SHE-LEAPS को जुलाई 2026 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शुरू किया गया, और लखपति दीदी लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाएँ कर दिया गया। SHE-LEAPS को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने विकसित किया है और यह LokOS के अंतर्गत चलता है, जो स्वयं सहायता समूहों तथा उनकी बचत, ऋण और आजीविका संबंधी आँकड़ों को डिजिटल बनाता है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ SHE-LEAPS का पूर्ण रूप है: सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर-लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन फ़ॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी।

➤ इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने विकसित किया है और यह LokOS प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत चलता है।

➤ यह कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में उद्यम निर्माण और प्रदर्शन की निगरानी में सहायता करता है।

➤ लखपति दीदी से SHG महिलाएँ ₹1 लाख से अधिक की स्थायी वार्षिक पारिवारिक आय अर्जित कर पाती हैं।

- LokOS स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों को डिजिटल बनाता है, जिसमें बचत, ऋण, पुनर्भुगतान और आजीविका संबंधी आँकड़े शामिल हैं।
- यह प्रतिवर्ष लगभग ₹2 लाख करोड़ मूल्य के लेन-देन दर्ज करता है।
- SHE-LEAPS कृषि और गैर-कृषि उद्यमों के लिए उद्यम निर्माण, व्यवसाय प्रबंधन और आय की निगरानी में सहायता करता है।
- लखपति दीदी लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाएँ कर दिया गया है, और पाँच वर्षों में ₹10 लाख करोड़ जारी करने की योजना है।
- सहायता ढाँचे में 6,611 मास्टर प्रशिक्षक, 4.09 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और 3.87 करोड़ संभावित लखपति दीदियाँ शामिल हैं।

MSMED (संशोधन) अधिनियम 2026

संदर्भ: संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित किया, जो 2006 के अधिनियम में संशोधन करता है। यह MSME के वर्गीकरण, पंजीकरण और भुगतान विवाद समाधान में परिवर्तन करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- निश्चित निवेश सीमाएँ हटा दी गई हैं; MSME का वर्गीकरण संयंत्र, मशीनरी या उपकरण में निवेश तथा टर्नओवर के आधार पर किया जा सकता है।
- ज्ञापन दाखिल करना सभी MSME के लिए निःशुल्क और स्वैच्छिक हो जाता है, जो केंद्र द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होगा; राज्य अपने प्लेटफ़ॉर्म अधिसूचित कर सकते हैं।
- एक ऑनलाइन मध्यस्थता या माध्यस्थम तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जिसमें मध्यस्थता के लिए 90 दिन, माध्यस्थम को भेजने के लिए 30 दिन और पंचाट के लिए 90 दिन मिलते हैं।
- मध्यस्थता से हुए समझौतों और माध्यस्थम पंचाटों की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है।
- TReDS के माध्यम से चालानों का निपटान सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए अनिवार्य हो जाता है।
- पंजीकरण दाखिल न करने जैसे अपराधों के लिए दोषसिद्धि-आधारित जुर्मानों के स्थान पर प्रथम बार चेतावनी सहित श्रेणीबद्ध दंड लागू होंगे।

NIIF के लिए अतिरिक्त ₹30,000 करोड़

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF) में ₹30,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश को मंज़ूरी दी, जिससे सरकार की कुल प्रतिबद्धता दोगुनी होकर ₹60,000 करोड़ हो गई। यह धन मुख्य रूप से NIIF अवसंरचना कोष II को सहायता देता है, जो प्रमुख अवसंरचना कोष का उत्तराधिकारी है और परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल तथा शहरी अवसंरचना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश करेगा।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह धन मुख्य रूप से NIIF अवसंरचना कोष II को सहायता देता है, जो प्रमुख अवसंरचना कोष का उत्तराधिकारी है।
- यह परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल तथा शहरी अवसंरचना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश करेगा।
- यह नई कोष रणनीतियों तथा उत्तराधिकारी द्विपक्षीय और रणनीतिक कोषों को भी सहायता देता है।

PMKSY के दस वर्ष पूरे

संदर्भ: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ने जुलाई 2026 में सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता को आगे बढ़ाने के दस वर्ष पूरे किए। इसे 1 जुलाई 2015 को 'हर खेत को पानी' के ध्येय के साथ शुरू किया गया था। यह कृषि, जल शक्ति और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' नामक सूक्ष्म सिंचाई घटक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह कृषि, जल शक्ति और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजना है। अधिकांश राज्यों के लिए वित्तपोषण 60:40 है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय है।
- राष्ट्रीय संचालन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं।
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई के लिए लघु और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तथा अन्य को 45 प्रतिशत सहायता देता है।

□ **उपलब्धियाँ**

- 24.61 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित या पुनःस्थापित की गई है।
- लगभग 11.092 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत है, जिससे 27 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।
- एक हेक्टेयर के खेत द्वार तक पाइप नेटवर्क के लिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM) 2025-26 में स्वीकृत किया गया।
- उत्तर प्रदेश की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, जो 1978 में शुरू हुई थी, 2016 में PMKSY के अंतर्गत लाई गई और इससे लगभग 29 लाख किसानों को लाभ होता है।
- हिमाचल प्रदेश का रेणुकाजी बाँध और उत्तराखंड की लखवाड़ परियोजना को 90 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण मिलता है।

SDG राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा प्रगति रिपोर्ट 2026

संदर्भ: MoSPI ने जुलाई में SDG राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF) प्रगति रिपोर्ट 2026 जारी की, जो सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के प्रदर्शन को ट्रैक करती है। रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी घटकर 14.96 प्रतिशत, सामाजिक

सुरक्षा कवरेज बढ़कर 65.3 प्रतिशत और नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के 25.97 प्रतिशत तक पहुँचने जैसे लाभ दिखाए गए हैं। ऐसी संकेतक-आधारित रिपोर्टें परीक्षा में नियमित रूप से पूछी जाती हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- बहुआयामी गरीबी घटकर 14.96 प्रतिशत (2019-21) रह गई।
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2016 में 22.0 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 65.3 प्रतिशत हो गया।
- स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2025-26 में 25.97 प्रतिशत तक पहुँच गई।
- मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप 2025 में 49,429 हो गए और बेरोज़गारी 2017-18 के 6.1 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण 2015-16 में 18 प्रतिशत से सुधरकर 2025-26 में 82.2 प्रतिशत हो गया।
- आर्द्रभूमि क्षेत्र में रामसर स्थलों के क्षेत्र की हिस्सेदारी 4.15 प्रतिशत (2016) से बढ़कर 8.66 प्रतिशत (2026) हो गई।

चयनित सतत विकास लक्ष्य (SDG) संकेतक

लक्ष्य	संकेतक
SDG 6	99.62% ग्रामीण आबादी को उन्नत पेयजल उपलब्ध
SDG 7	स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा 25.97%
SDG 8	बेरोज़गारी 3.1% (2025)
SDG 11	नगरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण 82.2%
SDG 16	हत्या दर 1.98 प्रति लाख (2024)

SOFI 2026: खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट

संदर्भ: FAO, IFAD, UNICEF, WFP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार SOFI 2026 रिपोर्ट का विषय स्वस्थ आहार की ऊँची लागत को समझना और उसका समाधान करना है। यह दर्शाती है कि भूख लगातार तीसरे वर्ष घट रही है, किंतु प्रगति नाज़ुक बनी हुई है।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2025 में विश्व के 7.8 प्रतिशत लोगों, यानी लगभग 64.5 करोड़ लोगों, ने भूख का सामना किया, जो 2024 में 8.1 प्रतिशत और 2022 में 8.6 प्रतिशत था।
- लगभग 25.8 प्रतिशत, यानी 2.1 अरब लोग, मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त थे।
- अफ़्रीका में लगभग 30.9 करोड़ भूखे लोग हैं, जबकि एशिया में 29.2 करोड़।
- वयस्क मोटापा 2012 में 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 16.2 प्रतिशत हो गया।
- उपभोक्ता जो भुगतान करते हैं, उसका 70-75 प्रतिशत खेत से बाहर की गतिविधियों (फ़ार्मगेट के बाद) का होता है।

नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक

संदर्भ: नीति आयोग ने जुलाई 2026 में निवेश अनुकूलता सूचकांक रिपोर्ट जारी की, जिसकी घोषणा राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। यह 8 स्तंभों के अंतर्गत 84 संकेतकों पर 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है तथा उन्हें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी, उभरते और आकांक्षी श्रेणियों में बाँटता है; इसमें गुजरात 56.6 अंकों के साथ सबसे ऊपर रहा।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह 8 स्तंभों में समूहित 84 संकेतकों पर 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता (अंक 50 से अधिक): गुजरात (56.6), महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा।
- अग्रणी (45-50): दिल्ली, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित अन्य।
- उभरते प्रदर्शनकर्ता (40-44.9): बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब सहित अन्य।
- आकांक्षी राज्यों के अंक 40 से कम हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हैं।
- समकक्ष समूह के शीर्ष: बड़े राज्यों में गुजरात, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड, तथा केंद्रशासित प्रदेशों और नगर-राज्यों में गोवा।

प्लेटफ़ॉर्म कार्य पर ILO अभिसमय 193

संदर्भ: जिनेवा में अपने 114वें सत्र में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में गरिमामय कार्य पर ILO अभिसमय संख्या 193 को अपनाया, जो गिग कार्य के लिए बाध्यकारी मानक तय करने वाली पहली वैश्विक संधि है। भारत मतदान से अनुपस्थित रहा।

□ **मुख्य बिंदु**

- ILO की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के तहत हुई थी और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बनी। इसके 187 सदस्य हैं और इसने 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
- यह दो सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के 12 महीने बाद लागू होता है।
- यह औपचारिक और अनौपचारिक, ऑनलाइन और स्थान-आधारित प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को कवर करता है।
- सरकारों को श्रमिकों का सही वर्गीकरण और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा, तथा कर्मचारी माने जाने वालों को न्यूनतम वेतन देना होगा।
- यह संगठन की स्वतंत्रता, गैर-भेदभाव और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है, और श्रमिकों को बिना दंड के खतरनाक कार्यों से इनकार करने का अधिकार देता है।

- श्रमिक निष्क्रियकरण जैसे स्वचालित निर्णयों की मानवीय समीक्षा की माँग कर सकते हैं।
- यह एल्गोरिदम पारदर्शिता की अपेक्षा करता है; भारत अभिसमय पर मतदान से अनुपस्थित रहा।
- भारत ने आठ मूल अभिसमयों में से छह का अनुसमर्थन किया है, जिनमें संख्या 87 और संख्या 98 शामिल नहीं हैं।

भारत WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते में शामिल

संदर्भ: भारत जुलाई 2026 में WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते में औपचारिक रूप से शामिल हो गया, जो पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य वाला पहला बहुपक्षीय WTO समझौता है। जिनेवा में 2022 में 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया यह समझौता सितंबर 2025 में लागू हुआ और अवैध, असूचित तथा अनियमित मत्स्यन और अतिदोहित भंडारों के लिए सब्सिडी पर रोक लगाता है। भारत चरण II की वार्ताओं के लिए भी अपना पक्ष ज़ोर देकर रख रहा है।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसे जिनेवा में 2022 में 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था और यह सितंबर 2025 में लागू हुआ।
- यह अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन, अतिदोहित भंडारों तथा अनियमित उच्च समुद्रों में मत्स्यन के लिए सब्सिडी पर रोक लगाता है।
- जलकृषि और अंतर्देशीय मत्स्य पालन इसके दायरे से बाहर हैं, जिससे भारत के झींगा निर्यात की रक्षा होती है।
- विकासशील और अल्पविकसित सदस्यों को दो वर्ष की शांति धारा मिलती है।
- एक स्वैच्छिक WTO मत्स्य कोष विकासशील सदस्यों को अनुपालन में सहायता करता है।

□ **चरण II में भारत की स्थिति**

- भारत विकासशील देशों के लिए 25 वर्ष की संक्रमण अवधि चाहता है।
- वह दूरस्थ जल में संचालित औद्योगिक बेड़ों पर सख़्त नियम और छोटे मछुआरों के लिए स्थायी छूट चाहता है।

भारत दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता

संदर्भ: BIMCO-ICS नाविक कार्यबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत अब 3,11,936 पेशेवरों के साथ, जो वैश्विक कार्यबल का 12.16 प्रतिशत है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता है। सरकार ने इस हिस्सेदारी को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मिशन 20% शुरू किया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- केवल फिलीपींस भारत से आगे है; 2015 में भारत 5.2 प्रतिशत के साथ पाँचवें स्थान पर था।
- भारत 1,40,718 अधिकारी उपलब्ध कराता है, जो विश्व के अधिकारियों का 13.41 प्रतिशत है।
- वैश्विक आपूर्ति 25.7 लाख नाविकों की है, जबकि माँग 25.5 लाख की है।
- हाल के कानूनों में व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 2025, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 और तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 शामिल हैं।

□ **नाविक सुरक्षा उपाय**

- अमेरिका-ईरान संघर्ष में एक भारतीय नाविक की मृत्यु के बाद, एक वास्तविक-समय डैशबोर्ड फ़ारस की खाड़ी, होर्मुज़ जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में हर जहाज़ पर मौजूद प्रत्येक भारतीय को ट्रैक करेगा।
- eNavik पोर्टल में दुर्घटना रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और शिकायत निवारण के मॉड्यूल हैं।
- मारे गए या घायल प्रत्येक नाविक के परिवार के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

मसालों के लिए कोडेक्स मानक और मिशन गोल्डन स्पाइस

संदर्भ: भारत ने एक उपलब्धि हासिल की जब कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग ने बड़ी इलायची, धनिया और वेनिला के लिए मानक अपनाए। अलग से, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) ने लाकाडोंग हल्दी के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया।

□ **कोडेक्स मानक**

- ये मानक जिनेवा में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र में अपनाए गए।
- इन्हें मसाला और पाक जड़ी-बूटी संबंधी कोडेक्स समिति के 8वें सत्र में अंतिम रूप दिया गया, जिसकी स्थापना 2013 में भारत की पहल पर हुई थी और जिसका सचिवालय मसाला बोर्ड, कोच्चि है।
- कोडेक्स की स्थापना 1963 में FAO और WHO ने की थी और इसके 189 सदस्य हैं।
- सिक्किम भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है।

□ **मिशन गोल्डन स्पाइस**

- इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को खोलने की अपनी पहल के अंतर्गत ₹175.45 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया।
- लाकाडोंग हल्दी मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों की GI-टैग प्राप्त किस्म है, जिसमें कर्क्यूमिन की मात्रा 7 से 10 प्रतिशत होती है।
- लक्ष्य: क्षेत्रफल को लगभग 2,500 से बढ़ाकर 7,500 हेक्टेयर करना और वित्त वर्ष 2028-29 तक ₹100 करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना।

मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंज़ूरी

संदर्भ: मंत्रिमंडल ने मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना (MPMS) को मंज़ूरी दी, जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना की

उत्तराधिकारी है; वह योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय ब्रांडों को मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ने में मदद करना है।

□ **मुख्य बिंदु**

- पाँच वर्षों के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक, बजट ₹62,500 करोड़ है।
- भारत में बने फ़ोनों की पात्र बिक्री पर 2.25 से 5 प्रतिशत का प्रोत्साहन।
- घटकों की अधिक घरेलू सोर्सिंग के लिए 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- डिज़ाइन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करने वाले भारतीय ब्रांडों के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत।
- लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।
- योजना से लगभग ₹39,00,000 करोड़ के संचयी उत्पादन की उम्मीद है।

□ **क्षेत्र की प्रगति**

- भारत मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है और देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत फ़ोन यहीं बनाता है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में मोबाइल फ़ोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गए।
- PLI-LSEM से ₹20,600 करोड़ से अधिक का निवेश आया और ₹6.53 लाख करोड़ का निर्यात संभव हुआ।
- पूर्ववर्ती PLI से ₹11.62 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन भी हुआ।

यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति 2026

संदर्भ: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों में निवेश आकर्षित करने और आयात निर्भरता घटाने के लिए नई निवेश नीति 2012 में संशोधन करते हुए यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंज़ूरी दी।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसका लक्ष्य 10 मिलियन टन क्षमता वाले 8-9 नए गैस-आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित करना है।
- स्थायी लागतें चार वर्ष बाद भारतीय रुपये में बदल जाती हैं, जिससे विदेशी मुद्रा जोखिम सीमित होता है।
- NIP-2012 की तुलना में प्रति संयंत्र ₹250 करोड़ से अधिक की बचत की उम्मीद है।

□ **यूरिया क्षेत्र**

- उत्पादन 2014-15 के 225 LMT से बढ़कर 2024-25 में 306.67 LMT हो गया, जबकि 2023-24 में रिकॉर्ड 314.07 LMT रहा।
- यूरिया ₹266.50 प्रति 45 किलो बोरी की दर पर बेचा जाता है।
- संबंधित उपायों में नीम-लेपित यूरिया, पीएम-प्रणाम और इफको का नैनो यूरिया शामिल हैं।
- भारत में 33 संचालित यूरिया इकाइयाँ हैं; अप्रैल-जनवरी 2025-26 में उत्पादन 251.26 LMT और आयात 89.30 LMT रहा, जिससे भारत वैश्विक मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

रासायनिक पार्कों के लिए भव्य-रसायन योजना

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में तीन समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (BHAVYA-Rasayan) योजना को मंज़ूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल परिव्यय ₹3,030 करोड़ है, जिसमें केंद्र प्रति पार्क ₹1,000 करोड़ तक देगा, बशर्ते राज्य कम से कम ₹500 करोड़ दे। प्रत्येक पार्क के लिए कम से कम 2,000 एकड़ भूमि आवश्यक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- ₹3,000 करोड़ साझा अवसंरचना और बुनियादी उपयोगिताओं के लिए तथा ₹30 करोड़ प्रशासन के लिए हैं।
- केंद्र प्रति पार्क ₹1,000 करोड़ तक देता है, बशर्ते राज्य कम से कम ₹500 करोड़ दे।
- योजना पाँच वर्षों के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक, चलेगी।
- प्रत्येक पार्क के लिए प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना के साथ न्यूनतम 2,000 एकड़ सन्निहित क्षेत्र आवश्यक है।

विश्व बैंक आय वर्गीकरण वित्त वर्ष 2027

संदर्भ: विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 का देशों का आय वर्गीकरण जारी किया, जो एटलस पद्धति से प्रति व्यक्ति GNI के आधार पर हर 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है। इसमें चार समूहों में 218 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, और भारत निम्न-मध्यम आय वर्ग में बना हुआ है।

□ **मुख्य बिंदु**

- सीमाएँ: निम्न आय 1,175 अमेरिकी डॉलर या उससे कम; निम्न-मध्यम 1,176-4,635 अमेरिकी डॉलर; उच्च-मध्यम 4,636-14,375 अमेरिकी डॉलर; उच्च आय 14,375 अमेरिकी डॉलर से अधिक।
- टोगो निम्न आय से निम्न-मध्यम आय वर्ग में पहुँच गया।
- जॉर्डन, माइक्रोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और वियतनाम निम्न-मध्यम से उच्च-मध्यम आय वर्ग में पहुँच गए।
- कोई भी अर्थव्यवस्था निचले वर्ग में नहीं गई।
- निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी 1987 में लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 2026 में 11 प्रतिशत रह गई।

संशोधित उड़ान (Modified UDAN) को 2026-36 के लिए मंजूरी

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान को दस वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36) के लिए

₹28,840 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी, जिसका पूरा वित्तपोषण केंद्र करेगा। यह परिव्यय वित्तपोषण में छह गुना वृद्धि है।

□ **मुख्य बिंदु**

- उड़ान (UDAN) को अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसने 95 हवाई अड्डों के 669 मार्गों को संचालित किया है और 1.66 करोड़ से अधिक यात्रियों को ढोया है।
- कुल परिव्यय ₹28,840 करोड़ है।
- असेवित हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे विकसित किए जाएँगे।
- लगभग 441 केवल-RCS हवाई क्षेत्रों को तीन वर्ष के लिए संचालन और रखरखाव सहायता दी जाएगी।
- पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएँगे।
- क्षेत्रीय मार्गों पर विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ₹10,043 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग) दी जाएगी।
- एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान जैसे स्वदेशी विमानों को बढ़ावा दिया जाता है।
- यह योजना हवाई अड्डों के पुनर्विकास से आगे बढ़कर संचालन और रखरखाव को भी सहायता देती है।
- भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 159 हो गई।

संसदीय समिति की PDS आधुनिकीकरण रिपोर्ट

संदर्भ: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का आधुनिकीकरण - तकनीकी डेटा आधार को सुदृढ़ करना' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इसमें डिजिटलीकरण से हुए लाभों की समीक्षा की गई है और डेटा तथा कवरेज की कमियों को रेखांकित किया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- लक्षित PDS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित होती है और ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तथा शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक, अर्थात जनगणना 2011 के आधार पर 81.35 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है। प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है; अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम मिलता है, जो PMGKAY के तहत निःशुल्क है।
- केंद्र FCI के माध्यम से खरीद और आवंटन करता है, जबकि राज्य लाभार्थियों की पहचान करते हैं और उचित मूल्य की दुकानें चलाते हैं।

सहकारिता मंत्रालय के पाँच वर्ष

संदर्भ: जुलाई 2026 में सहकारिता मंत्रालय के पाँच वर्ष पूरे होने पर सहकारी क्षेत्र के लिए नई डिजिटल और अवसंरचना पहलें शुरू की गईं। इनमें शहरी सहकारी बैंकों के लिए सहकार CBS, सहकार सहयोगी AI प्लेटफ़ॉर्म, 50,000 PACS का e-PACS में रूपांतरण और 47 अनाज भंडारण गोदामों की आधारशिला शामिल हैं, जो सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाती हैं।

□ **नई पहलें**

- NUCFDC की ओर से सहकार CBS, जो शहरी सहकारी बैंकों के लिए केंद्रीकृत कोर बैंकिंग समाधान है, और सहकार सहयोगी, जो एक संवादात्मक AI प्लेटफ़ॉर्म है।
- 50,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का e-PACS में रूपांतरण।
- 47 अनाज भंडारण गोदामों की आधारशिला और NDDB द्वारा दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल।

□ **व्यापक क्षेत्रीय सुधार**

- PACS अब कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र और ईंधन आउटलेट सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर सकती हैं।
- श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य 2028-29 तक सहकारी दूध खरीद में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना है।
- भारत टैक्सी भारत का पहला समुदाय-स्वामित्व वाला डिजिटल गतिशीलता प्लेटफ़ॉर्म है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति में परिवर्तन

संदर्भ: पिछले वर्ष के दौरान कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) को उच्च श्रेणी का दर्जा मिला। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (असम) दिसंबर 2025 में 27वाँ नवरत्न CPSE बना, रक्षा PSU यंत्र इंडिया लिमिटेड को फरवरी 2026 में मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा दिया गया, और इस्पात मंत्रालय के अधीन अनुसूची A के CPSE मेकॉन लिमिटेड को जुलाई 2026 में मिनीरत्न श्रेणी-I मिला। CPSE की श्रेणियाँ परीक्षा के आम विषय हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (असम) 2 दिसंबर 2025 को 27वाँ नवरत्न CPSE बना।
- रक्षा PSU यंत्र इंडिया लिमिटेड को 2 फरवरी 2026 को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा दिया गया।
- इस्पात मंत्रालय के अधीन अनुसूची A के CPSE मेकॉन लिमिटेड को 1 जुलाई 2026 को मिनीरत्न श्रेणी-I मिला।

CPSE का दर्जा

इकाई	दर्जा	तिथि
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नवरत्न (27वाँ)	2 दिसंबर 2025
यंत्र इंडिया लि.	मिनीरत्न-I	2 फरवरी 2026
मेकॉन लि.	मिनीरत्न-I	1 जुलाई 2026

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (सेमीकॉन 2.0) अधिसूचित

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अर्धचालक डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की योजना सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी और सरकार ने इसे अधिसूचित किया, जिसका परिव्यय ₹1,27,500 करोड़ है। यह 2021 के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम पर आधारित है, छह स्तंभों पर टिका है और इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता तथा प्रौद्योगिकी नेतृत्व को मजबूत करना है।

□ **मुख्य बिंदु**

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मूल्यांकन का कार्य करता है।
- राजकोषीय परिव्यय ₹1,27,500 करोड़ है।
- आवेदन शुरुआती तीन वर्षों के लिए खुले रहते हैं और परियोजना सहायता छह वर्ष तक चलती है।
- राज्य सरकारें केंद्र से प्रतिपूर्ति माँगने के बजाय भूमि और उपयोगिताएँ उपलब्ध कराती हैं।
- योजना छह स्तंभों के माध्यम से कार्य करती है, जो 10 श्रेणियों को कवर करते हैं।

□ **सेमीकॉन 1.0 की प्रगति**

- 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई।
- बारह विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें ओडिशा में एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब और नौ पैकेजिंग इकाइयाँ शामिल हैं।
- चौबीस डिजाइन परियोजनाओं को सहायता दी गई है और 105 स्टार्टअप को EDA उपकरणों की सुविधा प्राप्त है।
- भारत अपनी अर्धचालक आवश्यकताओं का 90 से 95 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है।

PMJDY के 12 वर्ष पूरे

संदर्भ: प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू हुई थी, ने अगस्त 2026 में बारह वर्ष पूरे किए। खाते बढ़कर 59.09 करोड़ हो गए, जिनमें से लगभग 55.7% महिलाओं के हैं, और जमा राशि ₹3,16,514 करोड़ तक पहुँच गई। लाभों में रुपे डेबिट कार्ड, ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा शामिल हैं।

□ **प्रगति**

- खाते लगभग चार गुना बढ़कर 14.72 करोड़ (2015) से 19 अगस्त 2026 तक 59.09 करोड़ हो गए; 77.8% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- महिलाओं के पास 32.92 करोड़ खाते हैं, यानी लगभग 55.7%।
- जमा राशि लगभग बीस गुना बढ़कर ₹3,16,514 करोड़ हो गई; औसत शेष ₹5,356 प्रति खाता।
- वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 (2021) से बढ़कर 67 (मार्च 2025) हो गया।
- गिनीज रिकॉर्ड: अगस्त 2014 में एक सप्ताह में 1,80,96,130 खाते खोले गए।

□ **लाभ**

- रुपे डेबिट कार्ड; 41.29 करोड़ कार्ड जारी किए गए।
- 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
- प्रति परिवार एक पात्र खाते के लिए ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट।

UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट

संदर्भ: कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन कर कुछ UPI और रुपे डेबिट-कार्ड लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की अनुमति दी। अधिनियम स्वयं कोई MDR नहीं लगाता।

□ **मुख्य बिंदु**

- MDR एक शुल्क है जिसे व्यापारी चुकाते हैं, उपभोक्ता नहीं।
- सरकार का कहना है कि UPI उपभोक्ताओं और व्यक्ति-से-व्यक्ति अंतरण के लिए निःशुल्क रहेगा।
- कोई भी MDR केवल एक सीमा से ऊपर के व्यापारी लेन-देन पर और नाममात्र की दर से लागू होगा।
- 2025-26 में व्यक्ति-से-व्यापारी UPI लेन-देन में केवल लगभग 4 प्रतिशत ₹2,000 से अधिक के थे, फिर भी वे मूल्य का लगभग दो-तिहाई थे।
- सरकार ने 2021-22 से 2024-25 तक प्रोत्साहन के रूप में ₹8,730 करोड़ वितरित किए; एक स्थायी समिति ने कहा कि यह उद्योग की लागत का केवल 11 प्रतिशत कवर करता है।

आईआईएचटी सूत्र 2026: हथकरघा प्रौद्योगिकी सम्मेलन

संदर्भ: भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, आईआईएचटी सूत्र 2026, अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया और इसका आयोजन विकास आयुक्त (हथकरघा) ने किया। भारत में छह केंद्रीय आईआईएचटी और पाँच राज्य आईआईएचटी हैं, और सम्मेलन का विषय 'भारतीय हथकरघा क्षेत्र का भविष्य बुनना' था, जो हथकरघा संबंधी प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- 12 अगस्त 2026 को डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उद्घाटित; आयोजन विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा।

- विषय: 'आईआईएचटी: भारतीय हथकरघा क्षेत्र का भविष्य बुनना - शिक्षित करें। नवाचार करें। रूपांतरित करें।'
- भारत में छह केंद्रीय आईआईएचटी और पाँच राज्य आईआईएचटी हैं, जिनके पास लगभग सात दशकों का अनुभव है।
- हथकरघा क्षेत्र लगभग 35 लाख बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को सहारा देता है, जिनमें 72% से अधिक महिलाएँ हैं।
- हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में लगभग ₹3.25 ट्रिलियन रहा।

उद्योग और सहकारिता के लिए योजनाएँ और अधिनियम

संदर्भ: कई आर्थिक उपायों की घोषणा की गई: इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना प्रस्तावित की गई, और दो संशोधन अधिनियमों ने MSME तथा सहकारी कानूनों में बदलाव किए।

□ योजनाएँ

- MeitY ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत ₹7,877 करोड़ मूल्य की 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी; कुल स्वीकृतियाँ ₹69,548 करोड़ तक पहुँच गई हैं।
- कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना का परिव्यय पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ है और इसका लक्ष्य लगभग 7.5 लाख TEU की वार्षिक क्षमता है।
- दूरसंचार विभाग (DoT) और मध्य प्रदेश ने ग्वालियर में भारत के पहले दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

□ अधिनियम

- MSME विकास (संशोधन) अधिनियम, 2026 भुगतान संबंधी बाधाओं को कम करने और विवाद समाधान को समयबद्ध बनाने के लिए 2006 के अधिनियम में संशोधन करता है।
- आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, MSME का GDP में योगदान 31.1 प्रतिशत और निर्यात में 48.58 प्रतिशत है; उद्यम पोर्टल पर 9.16 करोड़ MSME पंजीकृत हैं।
- NCDC (संशोधन) अधिनियम, 2026 1962 के अधिनियम में संशोधन करता है, NCDC के अधिदेश का विस्तार करता है और औद्योगिक वस्तुओं पर लगी केवल-ग्रामीण की सीमा को हटाता है।
- NCDC अब सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को वित्त पोषित कर सकता है और केंद्र की मंजूरी से राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं में अंश पूंजी ले सकता है।

कौशल, AI और विकास पर रिपोर्टें

संदर्भ: नीति आयोग की रिपोर्ट विकसित भारत और विश्व के लिए कौशल की पुनर्कल्पना (Reimagining Skilling for Viksit Bharat and the World) तथा विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2026, दोनों ने अगस्त में यह जाँचा कि कौशल और प्रौद्योगिकी रोजगार को कैसे आकार देते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर 3.2 प्रतिशत के मुकाबले स्नातकों में लगभग 13 प्रतिशत बेरोजगारी को रेखांकित करती है, जबकि विश्व बैंक की रिपोर्ट, जिसका विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा (The Promise of Artificial Intelligence) है, विकासशील देशों के लिए अपनाएँ, अनुकूलित करें और आगे बढ़ें (Adopt, Adapt and Advance) चरणों का प्रस्ताव करती है।

□ विकसित भारत के लिए कौशल की पुनर्कल्पना

- स्नातकों में बेरोजगारी लगभग 13 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय दर 3.2 प्रतिशत है; स्नातक महिलाओं में यह 20.4 प्रतिशत है।
- आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियों में कार्यरत हैं।
- 15 से 29 वर्ष आयु के लगभग 8.7 करोड़ लोग NEET श्रेणी में आते हैं।
- एक कुशल स्नातक लगभग ₹29,000 प्रति माह कमाता है, जबकि अकुशल स्नातक ₹22,000 कमाता है।

□ विश्व विकास रिपोर्ट 2026

- इसका विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा (The Promise of Artificial Intelligence) है।
- यह विकासशील देशों के लिए तीन चरणों का प्रस्ताव करती है: अपनाएँ (Adopt), अनुकूलित करें (Adapt) और आगे बढ़ें (Advance)।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 4.5 प्रतिशत नौकरियों को जेनरेटिव AI से स्वचालन का जोखिम है, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 14.2 प्रतिशत है।

खान और खनिज संशोधन अधिनियम, 2026 और धारा 9D

संदर्भ: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यह खनन कराधान में एकरूपता लाने के लिए खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों के उपकरों को सीमित करता है।

□ मुख्य बिंदु

- जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा और इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1989) के निर्णय को पलट दिया। 2024 के निर्णय ने बकाये का 1 अप्रैल 2026 से 12 वर्षों में किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी।
- नई धारा 9D राज्यों को खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर कोई कर, उपकर या शुल्क लगाने से रोकती है, सिवाय केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार।
- संशोधन से पहले जो उपकर अदा या वसूल नहीं किए गए, वे अमान्य हैं, परंतु जो राशि पहले ही वसूली जा चुकी है, वह वापस नहीं की जाएगी।

- धारा 13 में संशोधन कर केंद्र को शर्तें निर्धारित करने वाले नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
- रेत, बजरी, मिट्टी और ग्रेनाइट जैसे लगभग 50 गौण खनिज राज्यों के नियंत्रण में बने रहते हैं।
- झारखंड और तमिलनाडु ने खनिज-युक्त भूमि कर लागू किए।
- राज्य खनन पर लगभग 14 प्रकार के शुल्क लगाते हैं और खनन राजस्व का लगभग 90 प्रतिशत प्राप्त करते हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने ₹10,12,529 करोड़ मूल्य के खनिजों का आयात किया।

गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 के लिए ₹23,731 करोड़ के परिव्यय वाली गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य संपीडित बायोगैस को भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है।

□ मुख्य बिंदु

- इसका लक्ष्य घरेलू CBG उत्पादन में लगभग दस गुना वृद्धि करना है।
- पहले चार मंत्रालयों में फैले संपूर्ण CBG पारिस्थितिकी तंत्र को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत समेकित किया गया है।
- गोबरधन को 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शुरू किया गया था।
- भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग 50 प्रतिशत ज़रूरतें आयात से पूरी करता है, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से LNG आयात का लगभग 55 से 60 प्रतिशत गुज़रता है।
- SATAT को 2018 में CBG पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए शुरू किया गया था।
- बायोमास संग्रहण मशीनरी योजना का परिव्यय ₹564.75 करोड़ है।
- पाइपलाइन अवसंरचना विकास योजना का परिव्यय वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए ₹994.5 करोड़ है।
- बाज़ार विकास सहायता योजना CBG संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद के लिए ₹1,500 प्रति टन प्रदान करती है।

ग्रामोद्यम, मखाना निर्यात और अन्य आर्थिक पहलें

संदर्भ: 2026 के दौरान कृषि-व्यवसाय और उद्यम संबंधी पहलें शुरू की गईं। नाबार्ड ने जुलाई 2026 में अपने 45वें स्थापना दिवस पर NSDC के साथ ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के रूप में ग्रामोद्यम शुरू किया, और APEDA ने अगस्त 2026 में बिहार से ऑस्ट्रेलिया के लिए GI-टैग प्राप्त मिथिला मखाना के 18 टन की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप की सुविधा प्रदान की। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सितंबर 2026 में इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद की भी स्थापना की गई।

□ ग्रामीण एवं कृषि

- नाबार्ड ने 12 जुलाई 2026 (45वें स्थापना दिवस) को ग्रामोद्यम शुरू किया, जो NSDC और औद्योगिक विकास संस्थान के साथ एक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम है।
- APEDA ने 18 अगस्त 2026 को बिहार से ऑस्ट्रेलिया के लिए GI-टैग प्राप्त मिथिला मखाना के 18 टन की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप की सुविधा प्रदान की।
- ICAR और FCI ने 30 सितंबर 2026 को वैकल्पिक धूम्रीकरण अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसे ICAR-CIPHET लुधियाना द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा (चरण I ₹3.28 करोड़, दो वर्ष)।

□ उद्योग

- इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद की स्थापना 23 सितंबर 2026 को इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत की गई, जिसकी अध्यक्षता इस्पात सचिव करेंगे।
- मिधानी (MIDHANI) GE एयरोस्पेस से S400 धात्विक पदार्थ प्रयोगशाला अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी।
- डाक विभाग और TRAI ने 10 जुलाई 2026 को डाक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के लिए एक वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- पर्यटन मंत्रालय ने 30 जुलाई 2026 को 'इनक्रेडिबल इंडिया बाई इंडिगो' अभियान के लिए इंडिगो के साथ दो वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- NSO ने 8 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक सांख्यिकी अनुसंधान के लिए पहले इंडिया फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय सेना ने रक्षा कर्मियों के लिए भारत चावल शुरू किया और भंडारण सहायता के लिए FCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (12 अक्टूबर 2026)।

बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 2026

संदर्भ: बैंकर्स बही साक्ष्य विधेयक, 2026 को अगस्त 2026 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लेता है। यह इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड में संग्रहीत बैंक अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो डिजिटल प्रतियों के रूप में तब स्वीकार्य हैं जब वे सच्ची प्रतियाँ हों और उनमें छेड़छाड़ न हुई हो। केंद्र अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को किसी भी वित्तीय क्षेत्र की इकाई तक बढ़ा सकता है।

□ मुख्य बिंदु

- बैंकर्स बही में अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में रखे गए अभिलेख भी शामिल हैं, चाहे वे ऑनसाइट, ऑफसाइट, वर्चुअल या क्लाउड स्थानों पर संग्रहीत हों।
- डिजिटल प्रति तभी स्वीकार्य है जब वह सही प्रति हो और उसमें कोई अनधिकृत परिवर्तन या छेड़छाड़ न हुई हो।

- बैंक अधिकारियों को बाध्य करने के लिए विशेष कारण अब परिभाषित हैं: संदिग्ध सटीकता, अभिलेख-संधारण में बाधा या निरीक्षण आदेश की अवहेलना।
- केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को किसी भी वित्तीय क्षेत्र की संस्था पर लागू कर सकती है।

बैंकिंग कवरेज, CBDC DBT और ई-श्रम

संदर्भ: भारत ने अगस्त 2026 में लगभग सार्वभौमिक बैंकिंग पहुँच की सूचना दी, दो केंद्रशासित प्रदेशों में CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी अंतरण शुरू किया और ई-श्रम पोर्टल के पाँच वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। लगभग 99.92 प्रतिशत आबाद गाँवों में 5 किमी के भीतर बैंकिंग आउटलेट है, जबकि चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया टोकन के माध्यम से PMGKAY सब्सिडी देने वाले पहले प्रदेश बने।

□ **बैंकिंग कवरेज**

- 99.92 प्रतिशत आबाद गाँवों (6,01,328 में से 6,00,868) में 5 किमी के भीतर बैंकिंग आउटलेट है।
- जुलाई 2026 तक 1.81 लाख से अधिक बैंक शाखाएँ, 17.36 लाख बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और 1.65 लाख IPPB केंद्र हैं।
- RBI कई प्रकार के बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना कहीं भी शाखाएँ खोलने की अनुमति देता है, जिसमें नई शाखाओं का 25 प्रतिशत बैंकिंग-वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में होना आवश्यक है।

□ **CBDC DBT**

- चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया टोकन के माध्यम से PMGKAY खाद्य सब्सिडी देने वाले पहले प्रदेश बने।
- इससे पहले गुजरात और पुडुचेरी में पायलट परियोजनाएँ चलाई गई थीं।
- लाभार्थी QR या कूपन कोड के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर अनाज प्राप्त करते हैं और दालें भी चुन सकते हैं।

□ **ई-श्रम**

- इसे 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया और NIC ने विकसित किया।
- यह 12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) जारी करता है; 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक, जो करदाता या EPFO/ESIC सदस्य नहीं हैं, निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं।

भारत में आय गतिशीलता, 2014-2025

संदर्भ: 2014 से 2025 तक वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पर सीएमआईई घरेलू पैनल आँकड़ों का उपयोग करने वाले एक अध्ययन में क्रमिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के साथ बढ़ती अधोगामी गतिशीलता पाई गई। अधोगामी गतिशीलता का सामना करने वाले परिवारों का हिस्सा 2015 में 14% से बढ़कर 2025 में 26.8% हो गया, जबकि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता 14.1% से बढ़कर 23.5% हुई। ग्रामीण तनाव सबसे तीव्र था।

□ **मुख्य बिंदु**

- अधोगामी गतिशीलता का सामना करने वालों का हिस्सा 14% (2015) से बढ़कर 26.8% (2025) हो गया।
- कोई बदलाव न होने वाले परिवार 70% से अधिक से घटकर 50% से नीचे आ गए।
- ऊर्ध्वगामी गतिशीलता 14.1% से बढ़कर 23.5% हुई, परंतु अधिक धीमी गति से।
- ग्रामीण तनाव सबसे तीव्र है: लगभग 29% ग्रामीण परिवार 2014 की तुलना में बदतर स्थिति में थे।

□ **पद्धति**

- 2014-2025 के लिए संतुलित घरेलू पैनल के वास्तविक प्रति व्यक्ति आय आँकड़े।
- परिवारों को 2014 की आय रैंक के आधार पर शीर्ष 10%, अगले 40% और निचले 50% में समूहित किया गया; गतिशीलता का अर्थ समूहों के बीच जाना है।

भूमि-सीमावर्ती देशों के लिए FDI ढाँचा (प्रेस नोट 3)

संदर्भ: अगस्त 2026 तक, भूमि-सीमावर्ती देशों से स्वामित्व संबंध रखने वाले निवेशकों के लिए संशोधित ढाँचे के तहत ₹4,895.65 करोड़ से अधिक मूल्य के 29 FDI निवेश दर्ज किए गए। यह ढाँचा 2026 के प्रेस नोट 2 के माध्यम से लागू किया गया था।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2020 में भारत ने भूमि-सीमावर्ती देशों या उनके स्वामित्व वाली संस्थाओं से निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य किया था। 2026 का प्रेस नोट 2 और FEM (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में संशोधन मई 2026 में अधिसूचित किए गए।
- चयनित विनिर्माण क्षेत्रों में अनुमति: पूंजीगत वस्तुएँ, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत वस्तुएँ, इलेक्ट्रॉनिक घटक तथा पॉलीसिलिकॉन और इंगट-वेफर जैसे सौर इनपुट।
- सेमीकंडक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्र प्रतिबंधित बने रहेंगे।
- ऐसे देशों से 10% तक लाभकारी स्वामित्व की अनुमति स्वचालित मार्ग से है।
- बहुलांश स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय निवासियों या संस्थाओं के पास ही रहना चाहिए।
- प्रस्तावों का निपटान 60 दिनों के भीतर किया जाएगा; कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों की समिति पात्र क्षेत्रों की समीक्षा करती है।
- भूमि-सीमावर्ती देश से 10 प्रतिशत तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व वाला निवेशक स्वचालित मार्ग का उपयोग कर सकता है।

➤ जहाँ ऐसे देश की कंपनी के पास नियंत्रक हिस्सेदारी है, वहाँ अनुमोदन आवश्यक है।

➤ चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान स्थित संस्थाओं से FDI के लिए अब भी अनुमोदन आवश्यक है, जबकि चयनित क्षेत्रों के लिए 60 दिन की समय-सीमा स्वीकृत की गई है।

व्यावसायिक सेवाओं के विनियमन पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ: नीति आयोग ने अगस्त 2026 में अपनी सेवा विषयगत श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट 'इंडियाज़ सर्विसेज़ सेक्टर: इनसाइट्स ऑन रेगुलेटरी रेजीम इन प्रोफेशनल सर्विसेज़' जारी की। इसे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने जारी किया और इसका उद्देश्य नियामकीय स्पष्टता, पेशेवर गतिशीलता तथा योग्यताओं की मान्यता है।

□ **रिपोर्ट**

➤ 10 अगस्त 2026 को उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी द्वारा जारी: 'इंडियाज़ सर्विसेज़ सेक्टर: इनसाइट्स ऑन रेगुलेटरी रेजीम इन प्रोफेशनल सर्विसेज़'।

➤ इसका उद्देश्य बेहतर नियामकीय स्पष्टता, पेशेवर गतिशीलता, योग्यताओं की मान्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता है।

➤ चेतावनी देती है कि सर्वोत्तम पद्धतियों का अर्थ विदेशी कानूनों की यांत्रिक नकल नहीं होना चाहिए।

□ **चार-आयामी रणनीति**

➤ सतत व्यावसायिक विकास और आजीवन सीखना।

➤ सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना: स्पष्ट पात्रता नियम, समय-सीमाएँ, समीक्षा तंत्र और परामर्श।

➤ अनुसंधान, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, विधिक विश्लेषण और परामर्श में मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ना।

➤ एआई, स्वचालन, ईएसजी रिपोर्टिंग, कार्बन लेखांकन और सतत वित्त में कौशल निर्माण।

समुद्र मंथन: राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ₹84,084 करोड़ के परिव्यय वाली राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंज़ूरी दी। यह गहरे जल में अन्वेषण के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु जोखिम-साझाकरण दृष्टिकोण अपनाती है।

□ **आवश्यकता**

➤ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और उसका आयात बिल लगभग 144 अरब डॉलर है।

➤ भविष्य की संभावना गहरे जल के बेसिनों में है: कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, महानदी और अंडमान, जिनमें 5,600 MMTOE से अधिक भंडार हैं।

➤ गहरे जल का एक अन्वेषण कूप बनाने में लगभग 125 से 150 मिलियन डॉलर का खर्च आता है।

➤ मौजूदा क्षेत्रों का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 6 से 7 प्रतिशत घटता है।

□ **अपेक्षित परिणाम**

➤ भंडार 600 MMTOE से अधिक बढ़ेंगे, यानी 1.6 अरब टन तेल समतुल्य से बढ़कर 2.2 अरब टन तेल समतुल्य हो जाएँगे।

➤ वार्षिक उत्पादन लगभग 62 MMTOE से बढ़कर 80 MMTOE हो जाएगा।

➤ कच्चे तेल का आयात प्रतिवर्ष लगभग ₹1 लाख करोड़ घट सकता है।

₹10 और ₹20 के लिए पॉलीमर बैंकनोट

संदर्भ: सरकार ने अगस्त 2026 में ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग में पॉलीमर बैंकनोट लाने के RBI के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। ये नोट द्विअक्षीय अभिविन्यस्त पॉलीप्रोपाइलीन आधार से बने हैं और कागज़ी नोटों से 2.5 से 4 गुना अधिक चलते हैं, हालाँकि इन्हें बनाने में 30 से 60 प्रतिशत अधिक लागत आती है। RBI ने पहली बार 2009 में पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव रखा था, और यह कदम UPI की वृद्धि के बावजूद मुद्रा की बढ़ती माँग के बीच उठाया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ RBI ने पहली बार 2009 में पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव रखा था; कोच्चि, मैसूरु, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला के लिए 2012 की पायलट योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

➤ पॉलीमर नोट कागज़ी नोटों से 2.5 से 4 गुना अधिक चलते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में 30 से 60 प्रतिशत अधिक लागत आती है।

➤ RBI के लिए TERI के एक अध्ययन में कागज़ी मुद्रा की तुलना में कुल जीवनचक्र कार्बन पदचिह्न कम पाया गया।

➤ भारत ने मुद्रा की छपाई पर 2023-24 में ₹5,101 करोड़, 2024-25 में ₹6,373 करोड़ और 2025-26 में ₹4,875 करोड़ खर्च किए।

□ **नकद बनाम डिजिटल**

➤ UPI प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ से अधिक लेन-देन संभालता है और खुदरा डिजिटल भुगतानों का 85 प्रतिशत इसी से होता है।

➤ 2025-26 में प्रचलन में मुद्रा ₹41 लाख करोड़ से अधिक हो गई, जबकि एक दशक पहले यह ₹16 से 17 लाख करोड़ थी।

➤ RBI इसे मुद्रा माँग की पहेली कहता है।

EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की गई

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दी। इस सीमा में अंतिम बार 2014 में संशोधन हुआ था, जब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ इस परिवर्तन से सरकार पर वार्षिक व्यय का अनुमान लगभग ₹11,339 करोड़ है, जबकि मौजूदा बजटीय सहायता लगभग ₹10,250 करोड़ है।

- ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह के बीच कमाने वाले श्रमिकों को अनिवार्य कवरेज मिलेगा।
- उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
- एक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी की औसत आय अब लगभग ₹23,000 प्रति माह है।

FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर

संदर्भ: FAO खाद्य मूल्य सूचकांक अगस्त 2026 में बढ़कर 133.3 अंक हो गया, जो नवंबर 2022 के बाद सर्वाधिक है, हालांकि यह मार्च 2022 के रिकॉर्ड शिखर से लगभग 17% नीचे है। अनाज, वनस्पति तेल, चीनी, मांस और डेयरी के मूल्य सूचकांक सभी बढ़े, जिसका कारण यूरोप में गर्मी और सूखा, गंभीर अल नीनो का खतरा तथा यूक्रेन और ईरान युद्धों से उत्पन्न व्यवधान रहे।

□ मुख्य बिंदु

- अगस्त में अनाज, वनस्पति तेल, चीनी, मांस और डेयरी के मूल्य सूचकांक सभी बढ़े।
- यूरोप में गर्मी और सूखे, गंभीर अल नीनो के खतरे तथा यूक्रेन और ईरान युद्धों से उत्पन्न व्यवधान ने अनाज की कीमतों को तीन वर्ष के उच्चतम स्तर पर और चीनी को एक वर्ष के शिखर पर पहुँचा दिया।
- FAO ने 2026 के वैश्विक अनाज उत्पादन अनुमान को 34 लाख मीट्रिक टन घटाकर 2.980 अरब टन कर दिया, जो 2025 से 2% कम है।
- यह 2018 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है, हालांकि उत्पादन फिर भी रिकॉर्ड में दूसरा सबसे बड़ा होगा।

FCNR(B) स्वैप विंडो और रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार

संदर्भ: FCNR(B) जमाओं के लिए RBI की रियायती स्वैप विंडो ने सितंबर 2026 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को रिकॉर्ड 785.706 अरब डॉलर तक पहुँचाने में मदद की। FCNR(B) खाते निश्चित अवधि की विदेशी मुद्रा जमाएँ हैं जिन्हें NRI और OCI भारत में खोल सकते हैं, और ये जमाकर्ताओं को विनिमय दर जोखिम से बचाते हैं। भारी अंतर्वाह से अधिशेष रुपया तरलता भी बनी, जिसे RBI ने VRRR नीलामियों के माध्यम से अवशोषित किया।

□ मुख्य बिंदु

- ये निश्चित अवधि की बैंक जमाएँ हैं जिन्हें NRI और OCI भारत में खोल सकते हैं। इन्हें अमेरिकी डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कनाडाई डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं में रखा जाता है।
- जमाकर्ता विनिमय दर जोखिम से सुरक्षित रहते हैं।
- जब तक जमाकर्ता अनिवासी है, तब तक ब्याज भारतीय आयकर से मुक्त है।
- इन जमाओं के भारी अंतर्वाह से अधिशेष रुपया तरलता भी बनी, जिसे RBI ने VRRR नीलामियों के माध्यम से अवशोषित किया।

GeM के सार्वजनिक खरीद के 10 वर्ष पूरे

संदर्भ: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सितंबर 2026 में सरकारी खरीद के एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में 10 वर्ष पूरे किए, जो विक्रेता पंजीकरण से लेकर भुगतान तक के जीवनचक्र को कवर करता है। खरीदार प्रत्यक्ष खरीद, तुलना, इलेक्ट्रॉनिक बोली और रिवर्स नीलामी का उपयोग कर सकते हैं, जबकि AI और ML उपकरण कार्टेलीकरण तथा ऑर्डर विभाजन का पता लगाते हैं और समावेशन पहलें महिला तथा स्टार्टअप विक्रेताओं को समर्थन देती हैं।

□ मुख्य बिंदु

- खरीदार प्रत्यक्ष खरीद, तुलना, इलेक्ट्रॉनिक बोली और रिवर्स नीलामी का उपयोग कर सकते हैं।
- AI और ML उपकरण संदिग्ध कार्टेलीकरण, मिलीभगत और ऑर्डर विभाजन का पता लगाते हैं।
- समावेशन पहलों में स्वयत (SWAYATT), स्टार्टअप रनवे 2.0, वुमनिया (Womaniya) और सरस कलेक्शन शामिल हैं।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ GeM सहाय स्वामित्व वाले (प्रोपराइटरशिप) विक्रेताओं को बिना जमानत के कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है।
- CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ पायलट आधार पर 50 GeM सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
- GeM ने वुमनिया पहल के लिए UN वुमन के साथ तथा 2025 में IN-SPACe और ड्रोन फेडरेशन इंडिया के साथ साझेदारी की।

JCR ने भारत की संप्रभु रेटिंग को A- में उन्नत किया

संदर्भ: जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (JCR) ने सितंबर 2026 में भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर स्थिर परिदृश्य के साथ A- कर दिया, जिससे यह भारत पर प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों में सबसे सकारात्मक रेटिंग बन गई। JCR ने लगभग 7% की सतत वृद्धि, GST, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और मजबूत बैंक तुलन-पत्रों का उल्लेख किया, साथ ही सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे के ऊँचे स्तर को रेखांकित किया।

□ मुख्य बिंदु

- JCR ने लगभग 7% की सतत वृद्धि, GST, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और मजबूत बैंक तुलन-पत्रों का उल्लेख किया।
- इसने सामान्य सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे के ऊँचे स्तर को संरचनात्मक बाधाओं के रूप में रेखांकित किया।
- इसने राज्य सरकारों के उच्च ऋण का उल्लेख किया और यह देखेगी कि क्या सार्वजनिक पूंजीगत व्यय निजी निवेश को आकर्षित करता है।

UPI के दस वर्ष पूरे

संदर्भ: एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI), जिसे 2016 में RBI की निगरानी में NPCI ने शुरू किया था, ने सितंबर 2026 में एक दशक पूरा किया और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का प्रमुख स्तंभ बन गया। वार्षिक लेनदेन वित्त वर्ष 2016-17 में 1.78 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गए, और UPI ने डिजिटल भुगतानों का 84% संभाला तथा यह 11 देशों में संचालित है।

□ **मुख्य बिंदु**

- वार्षिक UPI लेनदेन वित्त वर्ष 2016-17 में 1.78 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गए।
- इसी अवधि में लेनदेन मूल्य ₹0.07 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹314 लाख करोड़ हो गया।
- मासिक लेनदेन मात्रा मई 2026 में पहली बार 2,300 करोड़ को पार कर गई।
- UPI प्रतिदिन लगभग 66 करोड़ लेनदेन संभालता है और वित्त वर्ष 2025-26 में डिजिटल भुगतान लेनदेन का 84% इसके माध्यम से हुआ।
- UPI 11 देशों में संचालित है: UAE, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरीशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव।

अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI की VRRR नीलामियाँ

संदर्भ: RBI ने सितंबर 2026 में ओवरनाइट परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से लगभग ₹2.9 लाख करोड़ अवशोषित किए, क्योंकि अधिशेष तरलता ₹9.85 लाख करोड़ से अधिक हो गई थी। यह अधिशेष FCNR(B) जमाओं के भारी संग्रहण और उसके बाद RBI के साथ डॉलर-रुपया स्वैप से आया। VRRR के तहत बैंक अपनी अधिशेष निधि RBI के पास नीलामी द्वारा तय दर पर रखते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह अधिशेष FCNR(B) जमाओं के भारी संग्रहण और उसके बाद RBI के साथ डॉलर-रुपया स्वैप से आया।
- VRRR के तहत बैंक अपनी अधिशेष निधि RBI के पास निश्चित दर के बजाय नीलामी द्वारा तय दर पर रखते हैं।
- अतिरिक्त तरलता ओवरनाइट दरों को RBI के वांछित स्तर से नीचे धकेल सकती है और मौद्रिक नीति के संचरण को कमजोर कर सकती है।

अरबपति सूचियाँ 2026: फॉर्च्यून, फोर्ब्स और हुरुन

संदर्भ: हुरुन, फोर्ब्स और फॉर्च्यून इंडिया की 2026 की अरबपति रैंकिंग में रिलायंस और अदाणी के प्रमुखों को भारतीय सूचियों में शीर्ष पर रखा गया। भारत ने हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में 57 अरबपति जोड़े, जिससे कुल संख्या 308 हो गई, जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, और मुंबई 95 के साथ अग्रणी है।

□ **हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 (मार्च)**

- भारत ने 57 अरबपति जोड़े, जिससे कुल संख्या 308 हो गई; अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा अरबपति केंद्र।
- संयुक्त संपत्ति 10% बढ़कर लगभग ₹112.6 ट्रिलियन हुई; औसत ₹36,570 करोड़, जो चीन के औसत से अधिक है।
- मुंबई 95 अरबपतियों के साथ शीर्ष केंद्र है, जिसमें 15 की वृद्धि हुई (न्यूयॉर्क में 14 की वृद्धि हुई)।
- शेन्ज़ेन 132 के साथ एशिया की अरबपति राजधानी है।
- मुकेश अंबानी इस सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

□ **फोर्ब्स 2026**

- विश्व के सबसे अमीर: एलन मस्क (839 अरब डॉलर), उसके बाद लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, जेफ बेज़ोस, मार्क ज़करबर्ग।
- भारत के 100 सबसे अमीर (30 सितंबर 2026): गौतम अदाणी और परिवार प्रथम (112.7 अरब डॉलर), मुकेश अंबानी द्वितीय (86.3 अरब डॉलर), फिर सावित्री जिंदल, लक्ष्मी मित्तल, सुनील मित्तल।

□ **फॉर्च्यून इंडिया शीर्ष 100**

- मुकेश अंबानी प्रथम (₹8.68 लाख करोड़), गौतम अदाणी द्वितीय, सावित्री देवी जिंदल बढ़कर तीसरे स्थान पर, मिस्त्री परिवार चौथे, सुनील मित्तल पाँचवें।

फोर्ब्स की विश्व शीर्ष 100 में भारतीय

विश्व रैंक	नाम	कुल संपत्ति
21	मुकेश अंबानी	99.7 अरब डॉलर
31	गौतम अदाणी	63.8 अरब डॉलर
51	सावित्री जिंदल और परिवार	39.1 अरब डॉलर
70	लक्ष्मी मित्तल	31 अरब डॉलर
71	शिव नादर	30.9 अरब डॉलर
95	साइरस पूनावाला	27 अरब डॉलर
100	दिलीप संघवी	25.6 अरब डॉलर

कांडला में भारत का पहला ग्रीन (ई-)मेथनॉल संयंत्र

संदर्भ: सितंबर 2026 में गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण में देश के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी गई, जो बंदरगाह और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की संयुक्त पहल है। ₹2,300 करोड़ की यह परियोजना एशिया-यूरोप गलियारे के जलयानों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैविक CO_2 से प्रतिदिन 150 टन ई-मेथनॉल का उत्पादन करेगी, जो ग्रीन पोर्ट्स और भारत के 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को समर्थन देगी।

□ **मुख्य बिंदु**

- परियोजना की लागत ₹2,300 करोड़ है और इसे दो चरणों में बनाया जाएगा।

- कुल क्षमता प्रतिदिन 150 टन ई-मेथनॉल होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैविक CO2 से बनाया जाएगा।
- यह ईंधन एशिया-यूरोप व्यापार गलियारे के जलयानों की सेवा करेगा।
- ग्रीन मेथनॉल की लागत लगभग 750 अमेरिकी डॉलर प्रति टन रहने की उम्मीद है, जबकि वैश्विक दर लगभग 1,300 अमेरिकी डॉलर है।
- यह भारत के 2070 के नेट ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप है।
- मेक्सिको का मूल निवासी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विश्व की 100 सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक है और इसने कच्छ के बन्नी घास के मैदानों को संकट में डाल दिया है।
- यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन मेथनॉल का उत्पादन करेगा और खोई तथा कपास के डंठल का भी उपयोग कर सकता है।
- ग्रीन मेथनॉल किसी जहाज़ के CO2 उत्सर्जन को 95 प्रतिशत तक और NOx को 80 प्रतिशत तक घटा सकता है।
- यह पश्चिमी तट के बंदरगाहों को ग्रीन पोर्ट बनाने की योजना का हिस्सा है।

□ भारत की पहली एलएनजी ट्रेन

- भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बाद एलएनजी-डीज़ल दोहरे ईंधन वाली ट्रेन शुरू की।
- साबरमती डिपो में 1,400 अश्वशक्ति की दो ड्राइविंग पावर कारों को परिवर्तित किया गया, जिनमें से प्रत्येक में 2,200 लीटर का एलएनजी टैंक है।
- एक कार पूरे एलएनजी भार पर लगभग 444 किमी चल सकती है, और एलएनजी लगभग 40% डीज़ल उपयोग की जगह ले सकती है।

क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध FIU-IND की कार्रवाई

संदर्भ: वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने सितंबर 2026 में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन नोटिस जारी किए। 2004 में स्थापित FIU-IND वित्तीय खुफिया सूचना और रिपोर्टों को प्राप्त करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें साझा करने वाली भारत की केंद्रीय एजेंसी है और वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करती है।

□ मुख्य बिंदु

- इसकी स्थापना 2004 में वित्तीय खुफिया सूचना को प्राप्त करने, उसका विश्लेषण करने और उसे साझा करने वाली भारत की केंद्रीय एजेंसी के रूप में हुई थी। यह सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करती है।
- यह नकद लेनदेन रिपोर्ट, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट, सीमा-पार वायर अंतरण रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टें प्राप्त करती है।
- इसके कर्मचारी CBDT, CBIC, RBI, SEBI और खुफिया एजेंसियों से लिए जाते हैं।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 3.0

संदर्भ: भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए, जो 2026-2031 के लिए ₹565.50 करोड़ के परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहले के चरणों में भूमि अभिलेखों का लगभग पूर्ण कंप्यूटरीकरण हो जाने के बाद, यह चरण मानचित्रों, स्वामित्व विवरण, संपत्ति पंजीकरण और न्यायालयीन मामलों को एकीकृत करने वाले GIS-सक्षम लैंड स्टैक की ओर बढ़ता है।

□ मुख्य बिंदु

- यह पहले के उन चरणों पर आधारित है जिनमें भूमि अभिलेखों का लगभग पूर्ण कंप्यूटरीकरण हुआ।
- यह मानचित्रों, स्वामित्व विवरण, संपत्ति पंजीकरण और न्यायालयीन मामलों को एकीकृत करने वाले GIS-सक्षम लैंड स्टैक पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह API आधारित सुरक्षित एकीकरण को बढ़ावा देता है ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में कम जाना पड़े।
- प्रगति की निगरानी उन्नत DILRMP-MIS डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

डिजिटल गिग श्रमिक शिकायत प्रणाली, मोबाइल फूड लैब और मृदा कार्बन भुगतान

संदर्भ: तीन संक्षिप्त समाचार चर्चा में रहे: कर्नाटक गिग श्रमिकों के लिए सरकार-समर्थित डिजिटल शिकायत प्रणाली वाला पहला राज्य बना, एनएबीएल ने अगस्त 2026 में मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए पहली प्रत्यायन योजना शुरू की, और सत्यापित मृदा कार्बन क्रेडिट से जुड़े पहले भुगतान सितंबर 2026 में पंजाब और हरियाणा के किसानों तक पहुँचे।

□ कर्नाटक के गिग श्रमिक

- गिग वर्कर्स के लिए सरकार समर्थित डिजिटल शिकायत प्रणाली वाला पहला राज्य, जो कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित है।
- शिकायतें एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाती हैं।

□ NABL की मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाएँ

- 10 अगस्त 2026 को NABL ने नई दिल्ली में 'गुणवत्ता समन्वय' कार्यक्रम में अपने एकीकृत मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए पहली प्रत्यायन योजना शुरू की।

□ पहला मृदा कार्बन भुगतान

- पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए सत्यापित मृदा कार्बन क्रेडिट से जुड़े भुगतान शुरू हुए; 14 सितंबर 2026 को PAU लुधियाना में

DBT के माध्यम से 2,550 किसानों को ₹2.9 करोड़ से अधिक की घोषणा की गई।

- ग्रो इंडिगो (2019, ICAR के मार्गदर्शन में) के आदि कार्यक्रम ने धान की सीधी बुवाई, कम जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा दिया।

तैरती सौर ऊर्जा के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना

संदर्भ: हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का उद्देश्य 5,000 मेगावाट के लक्ष्य और ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ तैरती सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसमें ग्रिड को सहारा देने के लिए साथ-साथ ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था होगी।

□ मुख्य बिंदु

- तैरती सौर परियोजना में जलाशयों और झीलों के ऊपर तैरते प्लेटफ़ॉर्मों पर पैनल लगाए जाते हैं, जिन्हें तल या किनारों से बाँधा जाता है।
- यह भूमि का उपयोग किए बिना बिजली उत्पन्न करती है, इसलिए इसे भूमि-तटस्थ नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है।

भारत का पहला ब्लू बॉन्ड और सागरमाला फाइनेंस

संदर्भ: सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹600 करोड़ का भारत का पहला ब्लू बॉन्ड निर्गम वापस ले लिया, क्योंकि निवेशक उसकी पेशकश से अधिक कूपन चाहते थे। वह 10 वर्षीय बॉन्डों का मूल्य 8% से कम रखना चाहता था, लेकिन बोलियाँ 7.69% से 8.44% के बीच रहीं।

□ मुख्य बिंदु

- ब्लू बॉन्ड की आय चिह्नित जल और महासागर परियोजनाओं, जैसे स्वच्छ जल, नौवहन, सतत मत्स्यपालन और बंदरगाह परियोजनाओं में ही लगनी चाहिए।
- ब्लूवाशिंग से बचने के लिए जारीकर्ताओं को प्रकटीकरण ढाँचे और प्रभाव रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है।
- वडोदरा नगर निगम ब्लू बॉन्ड के माध्यम से लगभग ₹200 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है।
- 2015 में शुरू किए गए सागरमाला कार्यक्रम में लगभग 845 परियोजनाएँ हैं, जिनका अनुमानित निवेश ₹6.06 लाख करोड़ है।
- SEBI ने ब्लू बॉन्ड को सतत वित्त लिखत के रूप में मान्यता दी है।

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025

संदर्भ: नीति आयोग और WRI इंडिया ने सितंबर 2026 में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसमें 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-मोबिलिटी के लिए राज्य स्तरीय नीति और परिणामों का आकलन किया गया है। सूचकांक परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग अवसंरचना और EV अनुसंधान को शामिल करने वाले 16 संकेतकों का उपयोग करता है। दिल्ली 84 अंक के साथ शीर्ष पर रही, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक रहे।

□ मुख्य बिंदु

- सूचकांक 16 संकेतकों का उपयोग करता है: परिवहन विद्युतीकरण प्रगति (50%), चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी (30%) तथा EV अनुसंधान और नवाचार (20%)।
- अंक 10 से 84 तक हैं और माध्यिका 40 है।
- दिल्ली 84 के साथ शीर्ष पर रही, उसके बाद महाराष्ट्र (78), कर्नाटक (73), चंडीगढ़ (71) और गोवा (65) रहे।
- मध्य प्रदेश 23वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुँच गया।
- उत्तर प्रदेश 50-64 अंक पाने वाले आठ अग्रणी बड़े राज्यों में शामिल है।
- कर्नाटक ने चार्जिंग अवसंरचना में 97 के साथ सर्वाधिक अंक पाए, और दिल्ली ने अनुसंधान तथा नवाचार में 94 के साथ सर्वाधिक अंक पाए।

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

संदर्भ: भारत ने यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के साथ समझौतों के बाद न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए; अनुसमर्थन के बाद यह 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसे भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला एफटीए बताया गया है और इसका उद्देश्य चार से पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर ₹35,000 करोड़ करना है।

□ मुख्य बिंदु

- भारत और न्यूज़ीलैंड ने 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित किए; 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत के पास अब नौ एफटीए हैं, जो लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं।
- न्यूज़ीलैंड भारतीय निर्यात के 100% को शुल्क-मुक्त पहुँच देता है; पहले शुल्क 10% तक थे।
- भारत को न्यूज़ीलैंड के निर्यात का लगभग 95% शुल्क-मुक्त या काफी घटे हुए शुल्कों पर प्रवेश करेगा।
- लाभान्वित क्षेत्रों में परिधान, कालीन, जूते-चप्पल, ऑटो कलपुर्जे, मशीनरी, रत्न और आभूषण, चीनी मिट्टी के उत्पाद (सेरामिक्स) और हस्तशिल्प शामिल हैं।
- भारत ने डेयरी, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, चीनी, कृत्रिम शहद और चुनिंदा तेल एवं वसा जैसी संवेदनशील वस्तुओं को बाहर रखा।
- न्यूज़ीलैंड ने स्टार्टअप, विनिर्माण और अवसंरचना में 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुगम बनाने का वचन दिया, और प्रतिबद्धताएँ कम पड़ने पर पुनर्संतुलन खंड का प्रावधान है।
- उत्पादकता साझेदारियाँ कीवीफल, सेब और मधुमक्खी पालन (शहद) पर केंद्रित होंगी।
- कनाडा और चिली के साथ वार्ताएँ एक साथ जारी हैं।

□ **गतिशीलता संबंधी प्रावधान**

- भारतीय छात्रों की संख्या पर कोई संख्यात्मक सीमा नहीं है, और वे सप्ताह में कम से कम 20 घंटे काम कर सकते हैं; अध्ययन के बाद कार्य के अधिकार STEM स्नातकों के लिए 3 वर्ष तक और डॉक्टरेट शोधार्थियों के लिए 4 वर्ष तक हैं।
- एक अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा (टेम्परारी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा) एक समय में 5,000 भारतीय पेशेवरों को 3 वर्ष के प्रवास के लिए अनुमति देता है।
- प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीयों के लिए 12 माह तक का वर्किंग हॉलिडे वीज़ा प्रदान किया जाता है।

भारतीय रेलवे में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का प्रवेश

संदर्भ: वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति ने माल गलियारों के साथ छह रेल लाइनों को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत बनाने की मंजूरी दी, जो भारतीय रेलवे द्वारा HAM का पहला उपयोग है।

□ **मुख्य बिंदु**

- छह लाइनों में से चार ओडिशा में हैं तथा एक-एक तेलंगाना और झारखंड में हैं।
- कुल बोली परियोजना लागत ₹15,976 करोड़ है और 17-19 वर्ष की रियायत अवधि में पूंजीगत लागत ₹40,866 करोड़ है।
- प्रमुख वस्तुओं में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोक, सीमेंट और खाद्यान्न शामिल हैं।
- लगभग ₹1.80 लाख करोड़ मूल्य की 49 अन्य परियोजनाएँ PPP पाइपलाइन में हैं।
- HAM सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक रूप है, जिसका उपयोग राजमार्ग क्षेत्र में पहले से हो रहा है।

वैश्विक बॉन्ड बिकवाली और बढ़ती प्रतिफल दरें

संदर्भ: दुनिया भर के निवेशक सरकारी बॉन्ड बेच रहे हैं, जिससे प्रतिफल (यील्ड) बढ़ रहा है। 30 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी का प्रतिफल लगभग 25 वर्षों में सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया और जापान की 10 वर्षीय प्रतिफल दर 3% को छू गई, जो कथित तौर पर 1996 के बाद पहली बार है।

□ **मुख्य बिंदु**

- जर्मनी और ब्रिटेन की 10 वर्षीय प्रतिफल दरें कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गईं।
- बॉन्ड प्रतिफल निवेशक को मिलने वाला प्रतिलाभ है; जब बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं, तो प्रतिफल बढ़ता है।
- सरकारी बॉन्ड को अमेरिका में ट्रेजरी, ब्रिटेन में गिल्ट्स और भारत में G-Sec कहा जाता है।
- अगस्त 2026 में अमेरिका का संघीय ऋण 40 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर था, जो GDP का लगभग 126% है, जबकि भारत का सामान्य सरकारी ऋण GDP का 80-84% है।

□ **कारण**

- अमेरिका के उच्च उधार का अर्थ है अधिक बॉन्ड निर्गम, और निवेशक जोखिम के लिए अधिक क्षतिपूर्ति की माँग करते हैं।
- पश्चिम एशिया संघर्ष ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मुद्रास्फीति को ऊँचा बनाए रखा है।
- केंद्रीय बैंकों द्वारा दरें बढ़ाने की अपेक्षा में, बॉन्डधारक अभी बेच देते हैं ताकि बाद में अधिक भुगतान वाले बॉन्ड खरीद सकें।

वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 2026

संदर्भ: वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक का 40वाँ संस्करण सितंबर 2026 में जारी किया गया, जिसमें गिफ्ट सिटी भारत के शीर्ष रैंक वाले केंद्र के रूप में उभरा। इसे लंदन की ज़ेन पार्टनर्स द्वारा चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (शेन्ज़ेन) के साथ वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है, और न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग तथा सिंगापुर शीर्ष चार स्थानों पर हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- लंदन की ज़ेड/येन (Z/Yen) पार्टनर्स द्वारा चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (शेन्ज़ेन) के साथ प्रकाशित; वर्ष में दो बार, मार्च और सितंबर में जारी। पहला संस्करण 2007 में आया; 40वाँ संस्करण 16 सितंबर 2026 को जारी हुआ।
- गिफ्ट सिटी, मुंबई और नई दिल्ली मुख्य सूचकांक में शामिल हैं; गिफ्ट सिटी सबसे ऊँची रैंक पर है।
- गिफ्ट सिटी और मुंबई को 'अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ' तथा नई दिल्ली को 'अंतरराष्ट्रीय विविधीकृत' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- गिफ्ट सिटी में भारत का पहला संचालित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) है; आईएफएससीए की स्थापना 27 अप्रैल 2020 को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत की गई थी।
- 139 केंद्रों का अध्ययन किया गया: मुख्य सूचकांक में 117 और 22 सहयोगी केंद्र।
- 144 साधनात्मक कारकों के साथ वित्तीय पेशेवरों के आकलन (6,147 उत्तरदाताओं के 39,531 आकलन) का उपयोग करता है।
- प्रतिस्पर्धात्मकता के पाँच क्षेत्र: व्यावसायिक वातावरण, मानव पूंजी, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र का विकास, प्रतिष्ठा।

□ **वैश्विक रैंकिंग**

- न्यूयॉर्क पहले, लंदन दूसरे, हांगकांग तीसरे, सिंगापुर चौथे स्थान पर।
- शंघाई 5वें, टोक्यो 6ठे स्थान पर पहुँचे, सियोल 7वें, शेन्ज़ेन 8वें स्थान पर।

जीएफसीआई में भारतीय केंद्र

केंद्र	जीएफसीआई 39 रैंक	जीएफसीआई 40 रैंक	रेटिंग	परिवर्तन

गिफ्ट सिटी	46	37	722	9 ऊपर
मुंबई	52	49	710	3 ऊपर
नई दिल्ली	54	56	703	2 नीचे

57वीं GST परिषद बैठक

संदर्भ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं GST परिषद की बैठक अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली में हुई, जिसमें पंजीकरण, धनवापसी और क्रेडिट मिलान से जुड़े प्रक्रियात्मक सुधारों पर विचार किया गया। निर्णयों में सरल GST REG-01 आवेदन, पंजीकरण विवरणों में अधिकांश संशोधनों की स्वतः स्वीकृति और नियम 4B के अंतर्गत छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सरल पंजीकरण शामिल थे।

□ मुख्य बिंदु

- 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित।
- सरल GST REG-01 आवेदन, स्पष्ट दस्तावेज दिशानिर्देश और अधिक सुविधाजनक पोर्टल।
- पंजीकरण विवरणों में संशोधनों की स्वतः स्वीकृति, प्रमुख व्यावसायिक स्थान को छोड़कर।
- नियम 4B के अंतर्गत छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सरल पंजीकरण।
- GSTR-1, 1A, 2B और 3B में देयता और ITC का बेहतर मिलान।
- इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही में अतिरिक्त शेष की स्वचालित धनवापसी; कमी ज्ञापन की समय-सीमा 15 से घटाकर 10 दिन।
- 1 नवंबर 2026 को या उसके बाद प्राप्त इनपुट सेवाओं पर ITC उलटे शुल्क ढाँचे की धनवापसी के लिए गिना जाएगा; पूंजीगत वस्तुओं के लिए 1 अप्रैल 2027 से।
- कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए ₹10,000 की न्यूनतम कर राशि।

ADB वित्तपोषण: चेन्नई जल, ग्रीन अमोनिया और विकास अनुमान

संदर्भ: एशियाई विकास बैंक ने 2026 के दौरान भारत से जुड़े कई ऋणों और अनुमानों की घोषणा की। उसने जुलाई 2026 में ग्रेटर चेन्नई में जल और स्वच्छता के लिए 23 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, जिससे 45 लाख लोगों को लाभ होगा, और अक्टूबर 2026 में ACCEL के अंतर्गत AM ग्रीन अमोनिया (इंडिया) के साथ वित्तपोषण समझौता किया। ADO अप्रैल 2026 ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.9% लगाया।

□ चेन्नई जल और स्वच्छता

- 3 जुलाई 2026 को ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र के लिए 23 करोड़ डॉलर का ऋण मंजूर किया गया, जिससे 45 लाख लोगों को लाभ होगा।
- योजना में 170 से अधिक किमी जल और सीवर पाइप, 7 जल पंपिंग स्टेशन और 38 सीवर पंपिंग स्टेशन शामिल हैं।
- चेन्नई व्यापक रिंग-मेन समाधान वाला पहला भारतीय शहर होगा।

□ ग्रीन अमोनिया

- ADB और जापान ने अक्टूबर 2026 में AM ग्रीन अमोनिया (इंडिया) के साथ विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय-आधारित अमोनिया संयंत्रों में से एक के लिए वित्तपोषण समझौता किया।
- यह ACCEL (दीर्घकालिक सुदृढ़ता के लिए ऊर्जा सुरक्षा निर्माण की कार्रवाई) के अंतर्गत पहला निवेश है, जिसमें JICA समर्थित लीडिंग एशियाज प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड 2 से 10 करोड़ डॉलर का ऋण शामिल है।

□ परिदृश्य

- ADO अप्रैल 2026 ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.9% लगाया, जो पिछले वर्ष के 7.6% से कम है।
- IMF और विश्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2026 को बैंकॉक ब्लूप्रिंट जारी किया, जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी के विरुद्ध एक रूपरेखा है।
- विश्व बैंक ने 2 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के लिए नई पाँच वर्षीय देश साझेदारी रूपरेखा शुरू की, जो 7% के मध्यम अवधि के वृद्धि लक्ष्य का समर्थन करती है।

IDBI बैंक की फेयरफैक्स से जुड़े खरीदार को रणनीतिक बिक्री

संदर्भ: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2026 में IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के स्वामित्व वाली एक कनाडाई इकाई को लगभग ₹52,878 करोड़ में मंजूरी दी। सरकार 30.48% और LIC 30.24% बेच रही है। IDBI 2004 में बैंक बना और 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक वर्गीकृत किया गया।

□ मुख्य बिंदु

- IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को विकास वित्त संस्था के रूप में हुई थी और यह 1 अक्टूबर 2004 को बैंक बना। LIC द्वारा 51% इक्विटी लेने के बाद RBI ने इसे 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया।
- 14 अक्टूबर 2026 को मंजूरी; खरीदार 1095230 कनाडा इंक. है।
- सरकार 30.48% और LIC 30.24% बेच रही है; बोली मूल्य ₹81 प्रति शेयर, जबकि बेंचमार्क ₹75.99 था।
- बिक्री के बाद सरकार के पास लगभग 15% और LIC के पास लगभग 19% रहेगा।
- पूर्णता नियामकीय अनुमोदनों पर निर्भर है।

NSAP जारी रहेगा और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया। अगस्त 1995 में शुरू हुए इस कार्यक्रम की उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए, जैसे IGNOAPS का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना हुआ।

□ मुख्य बिंदु

- पाँच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय; NSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था।
- कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया।
- IGNOAPS का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना होगा; IGNWPS का नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना होगा; दिव्यांगता योजना का नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगा।
- दिव्यांगता पेंशन: 79 वर्ष तक की आयु के लिए ₹375 प्रति माह और 80 वर्ष तथा उससे अधिक के लिए ₹625; पात्रता सीमा 80% से घटाकर जन्म से 40% बेंचमार्क दिव्यांगता कर दी गई।
- 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थी।

NSAP के घटकों का नाम परिवर्तन

पहले	नया
NSAP	प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
IGNOAPS	प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
IGNWPS	प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
IGNDPS	प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना

RBI मौद्रिक नीति अक्टूबर 2026: रेपो दर बढ़ाकर 5.50%

संदर्भ: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की 63वीं बैठक अक्टूबर 2026 में हुई और उसने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.25% से 5.50% कर दिया। उसने 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% और CPI मुद्रास्फीति 5.2% रहने का अनुमान लगाया। रेपो दर, अनुमान और 2-6% की सीमा के साथ 4% का मुद्रास्फीति लक्ष्य परीक्षा के मुख्य विषय हैं।

□ मुख्य बिंदु

- बैठक 5-7 अक्टूबर 2026 को हुई; रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.50% हुई।
- 2026-27 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% और CPI मुद्रास्फीति 5.2%; कोर मुद्रास्फीति 4.4%।
- अगस्त में CPI मुद्रास्फीति 4.8% थी; सितंबर में मुद्रास्फीति 5.54% दर्ज हुई, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति 7.74% थी (CPI आधार 2024=100)।
- अप्रैल 2026 से मार्च 2031 के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 4%, 2-6% की सहनशीलता सीमा के साथ।
- अगली MPC बैठक 24 दिसंबर 2026 को है।

1 अक्टूबर 2026 से नीतिगत दरें

दर	स्तर
नीतिगत रेपो दर	5.50%
स्थायी जमा सुविधा	5.25%
सीमांत स्थायी सुविधा	5.75%
बैंक दर	5.75%

आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2026

संदर्भ: आईएमएफ ने अक्टूबर 2026 का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 'रेज़िलिएंस अंडर स्ट्रेन, अर्जेंट चॉइसेज़' शीर्षक से जारी किया, जिसमें मध्यम वैश्विक वृद्धि का अनुमान है और भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। भारत की वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7.0% अनुमानित है, जो अप्रैल की तुलना में 0.5 अंक बढ़ाई गई है, जबकि 2026 में वैश्विक वृद्धि 3.1% रहने का अनुमान है। अनुमान और रिपोर्ट के शीर्षक परीक्षा की नियमित सामग्री हैं।

□ मुख्य बिंदु

- वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 और वित्त वर्ष 2027-28 में प्रत्येक में 7.0% अनुमानित, दोनों अप्रैल की तुलना में 0.5 अंक बढ़ाए गए।
- कैलेंडर वर्ष के अनुमान: 2026 के लिए 7.4% और 2027 के लिए 7.0%।
- जीडीपी की गणना 2022-23 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय लेखा पर की गई है।

□ वैश्विक परिदृश्य

- 2025 में वैश्विक वृद्धि 3.5% थी; 2026 में 3.1% और 2027 में 3.4% अनुमानित।
- 2026 का पूर्वानुमान अप्रैल से अपरिवर्तित; 2027 का 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ाया गया।
- 2028-31 के लिए मध्यम अवधि की वृद्धि लगभग 3.2%, जो 2000-19 के औसत 3.7% से कम है।
- वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2026 में बढ़कर 4.7% और 2027 में घटकर 4.1% रहने की संभावना है, जिसका कारण ऊर्जा और खाद्य कीमतें हैं।

वृद्धि अनुमान (%)

अर्थव्यवस्था	2025	2026	2027

विश्व	3.5	3.1	3.4
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	2.0	2.1	1.8
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.3	2.3	2.3
फ्रांस	0.9	0.4	0.7
चीन	5.0	4.5	4.0
भारत (वित्तीय वर्ष)	7.8	7.0	7.0
रूस	1.0	0.9	0.9

पारादीप मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित; ITLA को मंजूरी

संदर्भ: सितंबर और अक्टूबर 2026 में बंदरगाह वर्गीकरण और लॉजिस्टिक्स शासन में परिवर्तन हुए। केंद्र ने सितंबर 2026 में पारादीप बंदरगाह (ओडिशा) को मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया, जो दीनदयाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंद्रा के साथ पूर्वी तट पर एकमात्र मेगा पोर्ट है। मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2026 में एकीकृत योजना के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) को मंजूरी दी।

□ मेगा पोर्ट

- 25 सितंबर 2026 को केंद्र ने पारादीप बंदरगाह (ओडिशा) को मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया; यह पूर्वी तट का एकमात्र मेगा पोर्ट है।
- दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (न्हावा शेवा) और मुंद्रा को भी मेगा पोर्ट घोषित किया गया।
- पारादीप, दीनदयाल और JNPA प्रमुख बंदरगाह हैं; मुंद्रा एक गैर-प्रमुख बंदरगाह है।

□ ITLA

- 6 अक्टूबर 2026 को मंत्रिमंडल ने एक विशेष प्रयोजन वाहन, एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण, को मंजूरी दी।
- यह एकीकृत योजना, अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और डेटा विश्लेषण की शीर्ष संस्था होगी।

□ नवी मुंबई हवाई अड्डा

- 2 जुलाई 2026 को औषधि नियम 1945 के अंतर्गत दवाओं के आयात के लिए प्रवेश बंदरगाह (Port of Entry) के रूप में अधिसूचित किया गया, जिससे अधिसूचित बंदरगाहों की संख्या 42 हो गई।

पीजीआई-डी 2024-25: जिला विद्यालय प्रदर्शन

संदर्भ: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी) 2024-25 जारी किया, जिसमें 782 जिलों का आकलन किया गया और अधिकांश ने अपने अंकों में सुधार दिखाया। 653 जिलों ने अंकों में सुधार किया, हालाँकि कोई भी जिला सर्वोच्च उत्कर्ष ग्रेड तक नहीं पहुँचा। सूचकांक 600 अंकों और छह श्रेणियों के 70 संकेतकों का उपयोग करता है तथा समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की निगरानी में सहायक है।

□ मुख्य बिंदु

- शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी; 6 श्रेणियों में 600 अंक और 70 संकेतक। समग्र शिक्षा के अंतर्गत नियोजन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की निगरानी में सहायक।
- 653 जिलों ने अंकों में सुधार किया; 251 ने अपना ग्रेड सुधारा; 508 उसी ग्रेड में बने रहे; 20 एक ग्रेड नीचे गए।
- कोई भी जिला उत्कर्ष (90% से अधिक) या उत्तम-1 (81-90%) तक नहीं पहुँचा।
- उत्तम-2 जिले 1 से बढ़कर 16 हुए; उत्तम-3 40 से 75; प्रचेष्टा-1 281 से 332।
- शीर्ष जिला: दीव (469, उत्तम-2); इसके बाद कोल्हापुर 463, बरनाला 461, मुक्तसर 456, नवांशहर 453, एर्नाकुलम 438।
- केरल के सभी 14 जिले उत्तम-2 या उत्तम-3 में आए।
- सबसे कम अंक पाने वाले जिले मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के थे, जैसे दक्षिण-पश्चिम गारो हिल्स (173), पश्चिम खासी हिल्स (176), लोंगडिंग (182), लॉन्गतलाई (210)।

ग्रेड के अनुसार जिले

ग्रेड	अंक सीमा	2023-24	2024-25
उत्कर्ष	90% से अधिक	0	0
उत्तम-1	81-90%	0	0
उत्तम-2	71-80%	1	16
उत्तम-3	61-70%	40	75
प्रचेष्टा-1	51-60%	281	332
प्रचेष्टा-2	41-50%	355	313
प्रचेष्टा-3	31-40%	110	43
आकांक्षा-1	21-30%	1	3

बैंकिंग अपडेट: RBI डेटा सेंटर, फिनो SFB और बैंक ऑफ बड़ौदा NPS

संदर्भ: दिसंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में कई घटनाक्रम हुए। RBI ने फरवरी 2026 में भुवनेश्वर में दूसरा उच्च-सुरक्षा डेटा सेंटर स्थापित किया और दिसंबर 2025 में फिनो पेमेंट्स बैंक को लघु वित्त बैंक बनने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। बैंक ऑफ बड़ौदा अक्टूबर 2026 में SBI के बाद पेंशन निधि कारोबार में प्रवेश करने वाला दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना।

□ RBI और विनियमन

- RBI ने फरवरी 2026 में भुवनेश्वर (ओडिशा) में दूसरा उच्च-सुरक्षा डेटा सेंटर स्थापित किया; उसका प्राथमिक डेटा सेंटर खारघर, नवी मुंबई में है।

➤ RBI ने दिसंबर 2025 में फिनो पेमेंट्स बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी दी।

□ **बैंक**

➤ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जनवरी 2026 में सौर ऊर्जा चालित मोबाइल ATM वैन वाला पहला RRB बना।

➤ बैंक ऑफ बड़ौदा SBI के बाद पेंशन निधि कारोबार में प्रवेश करने वाला दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना (1 अक्टूबर 2026)।

➤ NABARD की सहायक कंपनी NABKISAN फाइनेंस ने 1 अक्टूबर 2026 को NSE पर जल, स्वच्छता और साफ-सफाई को समर्पित भारत का पहला सामाजिक बॉन्ड सूचीबद्ध किया।

➤ NHAI ने दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार-आधारित सुरक्षा अलर्ट प्रणाली के लिए रिलायंस जियो के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

महिला रोज़गार और उद्यम के आँकड़े

संदर्भ: 2026 में जारी सरकारी आँकड़े महिला श्रम बल भागीदारी में 2017-18 के 23.3% से 2025 में 40.0% तक तीव्र वृद्धि और एमएसएमई तथा स्टार्टअप में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी दर्शाते हैं। लगभग 3.69 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई महिला-स्वामित्व वाले हैं (लगभग 38%), और 1.07 लाख से अधिक स्टार्टअप में कोई महिला निदेशक या भागीदार है।

□ **रोज़गार**

➤ महिला श्रम बल भागीदारी दर (15+, सामान्य स्थिति) 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 2025 में 40.0% हुई; कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 22.0% से 38.8% हुआ।

➤ 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की लगभग 20 करोड़ महिलाएँ नियोजित थीं।

□ **उद्यमिता**

➤ लगभग 3.69 करोड़ महिला-स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई, लगभग 38% हिस्सेदारी (उद्यम और उद्यम असिस्ट: 9,89,02,198 पंजीकरणों में से 3,71,97,598, यानी 37.61%)।

➤ 31 मार्च 2026 तक 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (लगभग 48%) में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार थी।

□ **कौशल आधारित क्षेत्र**

➤ मोबाइल फोन निर्माण में महिलाएँ प्रत्यक्ष कार्यबल का लगभग 70% हैं।

➤ भारत के लगभग 15% पायलट महिलाएँ हैं।

➤ एसटीईएम अनुसंधान में महिलाओं की हिस्सेदारी 13% (2000-01) से बढ़कर 18.6% (2020-21) और 29% (2023-24) हो गई।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2026

संदर्भ: यूएनडीपी और ओपीएचआई ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2026 का अद्यतन जारी किया, जिसमें 2010 में सूचकांक शुरू होने के बाद पहली बार वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी बढ़ती दिखी। यह 108 देशों को शामिल करता है और 1.2 अरब लोगों को गंभीर रूप से गरीब पाता है। सूचकांक तीन आयामों और दस संकेतकों का उपयोग करता है, और 33.3% या उससे अधिक अभाव स्कोर पर व्यक्ति को गरीब माना जाता है, इसलिए संरचना और प्रकाशक महत्वपूर्ण हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ तीन आयाम, दस संकेतक: स्वास्थ्य (2 संकेतक), शिक्षा (2), जीवन स्तर (6)। प्रत्येक आयाम का भार 1/3 है; यदि अभाव स्कोर 33.3% या उससे अधिक है तो व्यक्ति गरीब माना जाता है।

➤ 2019-21 के सर्वेक्षण पर आधारित: एमपीआई 0.069, गरीबी की व्यापकता 16.4%, तीव्रता 42.0%; 4.2% अत्यंत गरीब, 18.7% संवेदनशील।

➤ एमपीआई 0.283 (2005-06) से घटकर 0.069 हुआ; गरीबी की व्यापकता 55.1% से घटकर 16.4% हुई।

➤ 2024 की जनसंख्या के आधार पर अनुमानित 23.78 करोड़ गरीब, जो शामिल देशों में सबसे अधिक संख्या है।

➤ मान 0 से 1 तक होता है; अधिक मान का अर्थ अधिक गरीबी है।

□ **वैश्विक निष्कर्ष**

➤ 108 देशों को शामिल करता है; 6.3 अरब लोगों में से 1.2 अरब (18.9%) गंभीर रूप से बहुआयामी गरीब हैं।

➤ गरीबों की संख्या 2010 के बाद पहली बार बढ़ी है; 13 देशों के नए सर्वेक्षण जोड़े गए।

➤ 53.4 करोड़ लोग (गरीबों का 44.6%) अत्यंत गरीबी का सामना करते हैं; 95.2 करोड़ संवेदनशील हैं।

➤ 61.7 करोड़ गरीब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं (51.5%); लगभग हर तीन में से एक बच्चा गरीब है, जबकि वयस्कों में सात में से एक।

➤ गरीबों का 83.3% (99.8 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है; व्यापकता ग्रामीण 28.7% बनाम शहरी 7.0%।

➤ सब-सहारा अफ्रीका: सबसे अधिक व्यापकता (51.4%) और 61.6 करोड़ गरीब; दक्षिण एशिया में लगभग 39.3 करोड़ (19.9%)।

➤ लगभग 65.1% गरीब (77.9 करोड़) मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।

➤ 33 देशों ने अपना एमपीआई आधा किया, जिनमें भारत भी शामिल है; चीन ने सबसे तेज़ी से, चार वर्षों (2010-14) में इसे आधा किया।

➤ 21 देशों में आधी से अधिक जनसंख्या गरीब है; इनमें से 18 सब-सहारा अफ्रीका में हैं।

सर्वाधिक एमपीआई वाले देश

देश	एमपीआई	व्यापकता
चाड	0.517	84.2%
नाइजर	0.470	79.9%
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	0.461	80.4%
बुरुंडी	0.409	75.1%
मेडागास्कर	0.386	68.4%

पर्यावरण

समसामयिक नोट्स

BBNJ उच्च सागर संधि लागू हुई

संदर्भ: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समझौता (BBNJ), जिसे उच्च सागर संधि के नाम से जाना जाता है, जनवरी 2026 में लागू हुआ। यह उच्च सागर और अंतरराष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र को कवर करने वाली विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे 2023 में UNCLOS के अंतर्गत तीसरे क्रियान्वयन समझौते के रूप में अपनाया गया था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, किंतु अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जल, यानी 'उच्च सागर', और अंतरराष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र को कवर करने वाली विधिक रूप से बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र संधि है।
- उच्च सागर महासागर की सतह के दो-तिहाई से अधिक भाग में फैले हैं।
- इसे 2023 में अपनाया गया था और यह भाग XI पर 1994 के समझौते तथा 1995 के संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौते के बाद UNCLOS के अंतर्गत तीसरा क्रियान्वयन समझौता है।
- अब तक 83 देश इसका अनुसमर्थन कर चुके हैं; भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, किंतु अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है।

□ **चार मुख्य क्षेत्र**

- समुद्री आनुवंशिक संसाधन, जिनमें लाभों का उचित और न्यायसंगत बँटवारा शामिल है।
- क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण, जिनमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।
- क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

□ **संस्थाएँ**

- एक पक्षकार सम्मेलन (COP), एक सूचना-आदान-प्रदान तंत्र (क्लियरिंग-हाउस) और एक सचिवालय, साथ ही एक वित्तपोषण तंत्र।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

संदर्भ: पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए, जिन्होंने 2016 के नियमों का स्थान लिया। ये 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित ये नियम चक्रीय अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं तथा इनमें स्रोत पर चार श्रेणियों में कचरे का पृथक्करण अनिवार्य है, और थोक अपशिष्ट उत्पादकों को अपने कचरे के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित।
- कचरे को स्रोत पर ही चार श्रेणियों में पृथक् किया जाना चाहिए।
- सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और आवासीय सोसाइटियों सहित थोक अपशिष्ट उत्पादकों को पर्यावरण-अनुकूल संग्रह और निपटान सुनिश्चित करना होगा; गीले कचरे का प्रसंस्करण परिसर में ही किया जाना चाहिए अथवा वह विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व (EBWGR) प्रमाणपत्र के अंतर्गत आना चाहिए।
- एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के पंजीकरण, अनुमोदन और लेखा-परीक्षा की निगरानी करेगा।
- सीमेंट संयंत्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों को कचरा-व्युत्पन्न ईंधन (Refuse Derived Fuel) का उपयोग करना अनिवार्य है।
- लैंडफिलों की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा की जाएगी और उनका उपयोग केवल उस कचरे के लिए होगा जिसका न पुनर्चक्रण हो सकता है और न ही जिसे ऊर्जा में बदला जा सकता है; पुराने कचरा स्थलों का जैव-खनन और जैव-उपचार किया जाएगा।
- पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों के स्थानीय निकाय पर्यटकों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूल सकते हैं और अपशिष्ट-प्रबंधन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की संख्या सीमित कर सकते हैं।
- नियमों का पालन न करने पर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होती है।

विस्तारित कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के लक्ष्य

संदर्भ: जनवरी 2026 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए, जिनसे भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के अंतर्गत क्षेत्रों का दायरा बढ़ा है। चार नए क्षेत्र जोड़े गए हैं: पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ, पेट्रोरसायन, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमीनियम। 208 औद्योगिक इकाइयों को अनुपालन वर्ष 2025-26 से GHG उत्सर्जन तीव्रता में कटौती करनी होगी, जो भारत के NDC और 2070 के नेट ज़ीरो लक्ष्यों में सहायक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- चार नए क्षेत्र जोड़े गए हैं: पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ, पेट्रोरसायन, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमीनियम।

- पहले के क्षेत्र थे: एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी एवं कागज़, और क्लोर-क्षार।
- 208 औद्योगिक इकाइयों को अनुपालन वर्ष 2025-26 से GHG उत्सर्जन तीव्रता में कटौती करनी होगी।
- GHG उत्सर्जन तीव्रता प्रति इकाई उत्पाद के लिए उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा है।
- लक्ष्य 2023-24 के आधार स्तर की तुलना में 2026-27 तक उत्सर्जन तीव्रता में 3 से 7 प्रतिशत की कटौती है।
- लक्ष्य पूरा न करने वाली इकाइयों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र खरीदने होंगे; अन्यथा औसत CCC व्यापार मूल्य के दोगुने के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगती है।
- यह 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कटौती और 2070 तक नेट ज़ीरो के भारत के NDC लक्ष्यों में सहायक है।
- पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम, 2026 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अंतर्गत निधि को नियंत्रित करते हैं।
- वायु, जल और पर्यावरण अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए दंड इस निधि में जाते हैं; 75 प्रतिशत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जाता है और 25 प्रतिशत केंद्र के पास रहता है।

हिमालय में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)

संदर्भ: आईआईटी रुड़की के एक अध्ययन में जनवरी 2026 में पाया गया कि हिमालय-काराकोरम क्षेत्र में हिमनद झीलों की संख्या, क्षेत्रफल और जल-आयतन बढ़ रहे हैं, जबकि बढ़ते हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) जोखिम का पर्याप्त आकलन नहीं हुआ है। GLOF तब होता है जब किसी हिमनद झील का जल अचानक छूट जाता है, जैसा कि 2023 में दक्षिण ल्होनक झील की घटना में हुआ, जिसने सिक्किम में तीस्ता-III बाँध को नष्ट कर दिया।

□ मुख्य बिंदु

- GLOF तब होता है जब किसी हिमनद झील का जल अचानक छूट जाता है। निर्माण के आधार पर झीलों के प्रकार हैं: हिमोढ़-बाधित, हिम-बाधित, अपरदन-निर्मित और अन्य।
- उदाहरण हैं: सिक्किम में तीस्ता-III बाँध को नष्ट करने वाला 2023 का दक्षिण ल्होनक झील GLOF, उत्तराखंड में 2013 की चोराबाड़ी झील की घटना और 2021 की चमोली घटना।
- कारणों में वैश्विक तापन, हिमनद उछाल, अस्थिर हिमोढ़ों का टूटना, झीलों में हिमस्खलन या भूस्खलन, भूकंप और मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं।

□ अध्ययन के निष्कर्ष

- एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 31,000 हिमनद झीलें फैल रही हैं।
- पूर्वी हिमालय में हिमनद झीलों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
- उच्च पर्वतीय एशिया में हिमनद झीलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 प्रतिशत बढ़ा है।
- विश्व स्तर पर 1990 से हिमनद झीलों की संख्या, क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 53, 51 और 48 प्रतिशत बढ़े हैं।

□ शमन

- राष्ट्रीय GLOF जोखिम शमन परियोजना में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल हैं।
- केंद्रीय जल आयोग 900 से अधिक हिमनद झीलों की निगरानी करता है।
- आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में 493 उच्च जोखिम वाले स्थलों की पहचान की।
- पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, झीलों से साइफन या पंपिंग द्वारा जल निकासी, कृत्रिम अतिप्रवाह मार्ग और 2020 के NDMA दिशा-निर्देश मुख्य उपाय हैं।

CCUS और हरित अमोनिया: भारत का विकार्बनीकरण अभियान

संदर्भ: केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के लिए पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए। SIGHT योजना के अंतर्गत SECI की हरित अमोनिया नीलामियाँ भी वैश्विक रुचि आकर्षित कर रही हैं।

□ CCUS

- CCUS स्रोत पर CO2 को कैप्चर करता है, उसका उपयोग हरित यूरिया, मेथनॉल या कंक्रीट जैसे उत्पादों में करता है, या उसे गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में संग्रहित करता है।
- नीति आयोग का ढाँचा प्रतिवर्ष 75 करोड़ टन CO2 के कैप्चर, उपयोग और भंडारण का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसके लिए 100-150 अरब डॉलर के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है।
- भंडारण विकल्पों में उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति, उन्नत कोयला-स्तर मीथेन पुनर्प्राप्ति, खारे जलभृत और बेसाल्ट शामिल हैं।
- प्रत्यक्ष वायु कैप्चर (डायरेक्ट एयर कैप्चर) की लागत अनुमानतः 400-800 डॉलर प्रति टन है।
- दिसंबर 2025 में शुरू किया गया रोडमैप विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरियों और रसायनों को लक्षित करता है।
- CCUS इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे कठिन-से-कम-होने वाले उत्सर्जन क्षेत्रों का विकार्बनीकरण करता है और कोयला गैसीकरण से ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन को संभव बनाता है।
- कार्बन कैप्चर और उपयोग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी बॉम्बे में है।

□ **वैश्विक संदर्भ**

➤ यूरोपीय संघ का CBAM 2026 में एक निर्णायक चरण में प्रवेश करता है और यूरोपीय संघ का नेट-ज़ीरो उद्योग अधिनियम 2030 तक प्रतिवर्ष 5 करोड़ टन CO2 भंडारण क्षमता अनिवार्य करता है।

➤ नॉर्वे का नॉर्दर्न लाइट्स विश्व की पहली ओपन-एक्सेस (मुक्त-पहुँच) CO2 परिवहन और भंडारण अवसंरचना है।

□ **हरित अमोनिया**

➤ यह नाइट्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हरित हाइड्रोजन से बनाई जाती है।

➤ ग्रे अमोनिया प्रति टन लगभग 2 टन CO2 उत्सर्जित करती है।

➤ अमोनिया लगभग शून्य से 33 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर द्रवित हो जाती है, जिससे यह हाइड्रोजन का सुविधाजनक वाहक बनती है।

➤ SIGHT मोड 2A ने SECI द्वारा संचालित नीलामी मॉडल प्रस्तुत किया।

पूर्वोत्तर भारत में वनाग्नि और ऑपरेशन वालोंग

संदर्भ: अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी और नगालैंड-मणिपुर सीमा पर स्थित ज़ुकोउ घाटी में एक सप्ताह से अधिक समय तक बड़ी वनाग्नि जलती रही। अरुणाचल में 2026 के आरंभ में एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक आग की घटनाएँ दर्ज की गईं।

□ **प्रतिक्रिया**

➤ ऑपरेशन वालोंग के अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों और बांबी बकेट की सहायता से 9,500 फीट से ऊपर 1.4 लाख लीटर से अधिक पानी गिराया।

➤ FSI MODIS और VIIRS आँकड़ों का उपयोग करके 1.6 लाख से अधिक पंजीकृत वन अधिकारियों को लगभग वास्तविक समय में अलर्ट भेजता है।

➤ राष्ट्रीय अग्नि खतरा रेटिंग प्रणाली विकासाधीन है।

□ **कारण और नीति**

➤ मानसून-पूर्व वर्षा की गंभीर कमी, सूखा बाँस और चीड़ की पत्तियाँ, तथा तेज़ हवाएँ।

➤ अनियंत्रित झूम खेती और मानवीय लापरवाही।

➤ वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना, 2018 तथा वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, 2017, जिसका वित्तपोषण पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में होता है।

संक्षेप में पर्यावरण: मछुआरा बिल्ली, बीकॉरिडोर और अन्य

संदर्भ: फरवरी 2026 में पर्यावरण से जुड़े कई समाचार चर्चा में रहे: पहले वैज्ञानिक आकलन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मछुआरा बिल्ली (IUCN में सुभेद्य) का गढ़ पाया गया, NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे फूलदार पौधों के बीकॉरिडोर की घोषणा की, और संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के अंतर्गत पहले कार्बन क्रेडिट को मंज़ूरी दी। कांगो बेसिन के पीटलैंड और मेघालय में रैट-होल खनन भी समाचारों में रहे।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ पहले वैज्ञानिक आकलन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मछुआरा बिल्ली का गढ़ पाया गया, जो IUCN में सुभेद्य है, WPA 1972 की अनुसूची । में है और पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है।

➤ NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे फूलदार पौधों के बीकॉरिडोर की घोषणा की।

➤ संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया के साथ म्यांमार की एक परियोजना के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 तंत्र के अंतर्गत पहले कार्बन क्रेडिट को मंज़ूरी दी।

➤ अनुच्छेद 6.2 लेखांकन मार्गदर्शन को और अनुच्छेद 6.8 गैर-बाज़ार सहयोग को कवर करता है।

➤ मेघालय में अवैध रैट-होल खनन 20 से अधिक लोगों की जान ले चुका है; NGT ने 2014 में इस पर प्रतिबंध लगाया था।

➤ पीटलैंड का जल-निकासी और उनमें लगने वाली आग वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 5 प्रतिशत का योगदान करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने नदी प्रदूषण मामला बंद किया

संदर्भ: फरवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषित नदियों पर 2021 की अपनी स्वतः संज्ञान कार्यवाही बंद कर दी और निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंप दी। न्यायालय ने कहा कि NGT जैसे विशिष्ट अधिकरण सतत निगरानी के लिए अधिक उपयुक्त हैं, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की पुनः पुष्टि की। CPCB ने 271 नदियों पर 296 प्रदूषित खंडों की पहचान की है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB) की स्थापना की। NGT अधिनियम, 2010 त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है।

➤ न्यायालय ने कहा कि NGT जैसे विशिष्ट अधिकरण सतत निगरानी के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

➤ इसने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की पुनः पुष्टि की।

➤ CPCB ने 271 नदियों पर 296 प्रदूषित खंडों की पहचान की, और आकलित नदियों में से 43 प्रतिशत प्रदूषित थीं।

➤ 2,116 स्थानों में से 1,312 ने 3.0 mg/L की BOD सीमा को पूरा किया।

➤ 2024-25 तक नमामि गंगे की केवल 69 प्रतिशत निधि का उपयोग हुआ।

➤ गंगा कार्य योजना 1986 में और नमामि गंगे 2014 में शुरू हुई।

2031-2035 के लिए भारत के अद्यतन NDC

संदर्भ: मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के अंतर्गत 2031-2035 के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंज़ूरी दी। नए लक्ष्य हैं: 2035 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों से, 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कटौती, और 3.5 से 4 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक। 2070 तक नेट ज़ीरो दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2035 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों से; फरवरी 2026 तक 52.57% प्राप्त हो चुका है।
- 2035 तक 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी; 2005 से 2020 के बीच 36% पहले ही प्राप्त हो चुकी है।
- 3.5 से 4 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना; 2025 तक 2.29 अरब टन बनाया जा चुका है।
- 2070 तक नेट ज़ीरो दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है।
- पहले के लक्ष्य थे: 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म क्षमता, 45% तीव्रता कटौती और 2.5 से 3 अरब टन का सिंक।

पर्यावरणीय संस्थाएँ: आवरण, भवसागर, NH हरित आवरण सूचकांक

संदर्भ: मार्च 2026 में पर्यावरणीय संस्थाओं से जुड़े तीन अद्यतन: भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने 'आवरण' को बंद कर दिया, जो जनवरी 2024 से सेंटिनल-2 और सेंटिनल-1 आँकड़ों का उपयोग करने वाली वनोन्मूलन चेतावनी प्रणाली थी; CMLRE, कोच्चि के भवसागर रेफरल केंद्र को 3,500 से अधिक नमूनों के साथ गहरे समुद्र के जीव-जंतुओं का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया; और NHAI ने NRSC-ISRO के साथ पहला राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (NH-GCI 2025-26) जारी किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारतीय वन सर्वेक्षण के अंतर्गत जनवरी 2024 से संचालित 'आवरण' गूगल अर्थ इंजन पर सेंटिनल-2 और सेंटिनल-1 का उपयोग करता था; FSI ने इसे बंद कर दिया है।
- CMLRE, कोच्चि के भवसागर रेफरल केंद्र को 3,500 से अधिक नमूनों के साथ गहरे समुद्र के जीव-जंतुओं का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया।
- NHAI ने NRSC-ISRO के साथ जुलाई-दिसंबर 2024 के लिए 24 राज्यों में लगभग 30,000 किमी को कवर करने वाला NH-GCI 2025-26 जारी किया।

प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट और CMS COP15

संदर्भ: मार्च 2026 में 'विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति' रिपोर्ट के एक अंतरिम अद्यतन में बिगड़ते रुझान सामने आए, जिसमें CMS-सूचीबद्ध 49% प्रजातियाँ घट रही हैं, जो पहले 44% थीं। प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय, जिसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है, का 15वाँ COP ब्राज़ील के कैम्पो ग्रांदे में आयोजित हुआ। यह संधि UNEP के अंतर्गत 1979 में अपनाई गई थी, और भारत ने 2020 में COP13 की मेज़बानी की थी।

□ **मुख्य बिंदु**

- UNEP के अंतर्गत 1979 में अपनाई गई संधि, जिसके 133 पक्षकार हैं और जिसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। परिशिष्ट I में उन संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें कठोर संरक्षण की आवश्यकता है।
- भारत ने 2020 में COP13 की मेज़बानी की और तीन वर्षों तक अध्यक्षता की।

□ **रिपोर्ट के निष्कर्ष**

- CMS-सूचीबद्ध 49% प्रजातियाँ घट रही हैं, जो पहले 44% थीं।
- 24% संकटग्रस्त हैं, जो पहले 22% थीं; 26 प्रजातियाँ अधिक संकटग्रस्त श्रेणियों में चली गईं।
- साइगा मृग और मंक सील में कुछ सुधार देखा गया।

भारत की नागोया प्रोटोकॉल रिपोर्ट और सातवीं CBD राष्ट्रीय रिपोर्ट

संदर्भ: मार्च 2026 में भारत ने नागोया प्रोटोकॉल पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट और जैव विविधता अभिसमय (CBD) को अपनी सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR-7) प्रस्तुत की। नागोया रिपोर्ट 2017-2025 की अवधि को कवर करती है, जिसमें 12,830 ABS अनुमोदन जारी किए गए और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ₹216 करोड़ से अधिक जुटाए गए। NR-7 में NBSAP 2024-2030 के अंतर्गत 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों से संबद्ध 142 संकेतकों का उपयोग किया गया है।

□ **नागोया प्रोटोकॉल रिपोर्ट (2017-2025)**

- 12,830 ABS अनुमोदन जारी किए गए।
- 3,556 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (IRCC), जो वैश्विक IRCC के 60% से अधिक हैं।
- ₹216 करोड़ से अधिक जुटाए गए और लगभग ₹140 करोड़ समुदायों में वितरित किए गए।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के माध्यम से NBA, राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा कार्यान्वित।

□ **NR-7 की प्रमुख बातें**

- वन और वृक्ष आवरण 25.17% है; रामसर स्थल 26 से बढ़कर 98 हो गए।
- 58 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 574 वन्यजीव अभयारण्य।
- बाघ 3,682; हाथी 22,446; गैंडे 4,014; एशियाई शेर 891; डॉल्फ़िन 6,327।

➤ NBSAP 2024-2030 के अंतर्गत 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों से संबद्ध 142 संकेतकों का उपयोग करती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चंबल में रेत खनन पर स्वतः संज्ञान लिया

संदर्भ: मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को खतरे में डालने वाले अवैध रेत खनन की रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया। यह अभयारण्य चंबल नदी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है, जिसका लगभग 600 किमी अधिसूचित है, और यह भारत का एकमात्र तीन-राज्यीय नदीय संरक्षित क्षेत्र है। यह घड़ियाल, मगर, लाल मुकुट वाले छत कछुए, चिकनी खाल वाले ऊदबिलाव और गंगा नदी डॉल्फ़िन की रक्षा करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह चंबल नदी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है, जिसका लगभग 600 किमी अधिसूचित है। यह भारत का एकमात्र तीन-राज्यीय नदीय संरक्षित क्षेत्र है।

➤ प्रमुख प्रजातियाँ: घड़ियाल, मगर, लाल मुकुट वाला छत कछुआ, चिकनी खाल वाला ऊदबिलाव और गंगा नदी डॉल्फ़िन।

सुखना आर्द्रभूमि: चंडीगढ़ का पहला रामसर स्थल

संदर्भ: चंडीगढ़ की सुखना झील को 2026 में रामसर सूची में जोड़ा गया है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला आर्द्रभूमि स्थल बन गई है। यह शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौसमी सुखना चो धारा पर बाँध बनाकर 1958 में निर्मित एक मानव-निर्मित झील है और प्रवासी जलपक्षियों का प्रमुख शीतकालीन पड़ाव है। जलग्रहण क्षेत्र से गाद जमना इसके लिए मुख्य दीर्घकालिक खतरा है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ सुखना शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौसमी सुखना चो धारा पर बाँध बनाकर निर्मित एक मानव-निर्मित झील है।

➤ यह झील 1958 में ली कॉर्बूज़िए से जुड़ी चंडीगढ़ शहर की योजना के भाग के रूप में बनाई गई थी।

➤ यह प्रवासी जलपक्षियों का प्रमुख शीतकालीन पड़ाव तथा एक महत्वपूर्ण मनोरंजन स्थल और वर्षा-पोषित जलाशय है।

➤ जलग्रहण क्षेत्र से गाद जमना इसके लिए मुख्य दीर्घकालिक खतरा है, इसलिए चेक-डैम और जलग्रहण क्षेत्र का उपचार इसके प्रबंधन के केंद्र में हैं।

जम्मू-कश्मीर की लुप्त होती झीलों पर CAG रिपोर्ट

संदर्भ: मार्च 2022 तक झील संरक्षण पर CAG की एक रिपोर्ट में पाया गया कि जम्मू-कश्मीर की 697 झीलों में से 518 लुप्त हो गई हैं या सिकुड़ गई हैं। रामसर स्थल होकरसर झील पर 2,500 कनाल से अधिक अतिक्रमण है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ होकरसर, 'कश्मीर की आर्द्रभूमियों की रानी', श्रीनगर के निकट झेलम बेसिन में स्थित है। यह कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है और मुख्यतः दूधगंगा नदी से जल प्राप्त करता है।

➤ 1967 के आधार वर्ष की तुलना में झीलों का कुल क्षेत्रफल 2,851.26 हेक्टेयर घट गया।

➤ संदर्भ वर्ष कश्मीर संभाग के लिए 2014 और जम्मू संभाग के लिए 2020 थे।

➤ झीलों का नियंत्रण वन, राजस्व, कृषि, आवास एवं शहरी विकास, और पर्यटन विभागों के बीच बँटा हुआ है।

➤ संरक्षण कार्यक्रम केवल डल, वुलर, होकरसर, मानसबल, सुरिनसर और मानसर के लिए हैं, जिन्हें 2017-22 में जम्मू-कश्मीर के पूंजी बजट का लगभग 1% प्राप्त हुआ।

➤ सिकुड़ती झीलें सितंबर 2014 की बाढ़ जैसी बाढ़ों को और गंभीर बना देती हैं।

दिल्ली वायु प्रदूषण शमन योजना, 2026

संदर्भ: अप्रैल 2026 में दिल्ली सरकार ने अपनी वायु प्रदूषण शमन योजना, 2026 प्रस्तुत की, जिसमें परिवहन, धूल, निर्माण और कचरे को शामिल करने वाला बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है, क्योंकि औसत PM2.5 स्तर लगातार 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक रहते हैं। प्रमुख उपायों में 'नो PUC-नो फ्यूल' नीति, नवंबर 2026 से केवल BS-VI, CNG या विद्युत वाहनों का प्रवेश, 32,000 EV चार्जिंग बिंदु और 2026-27 में 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ औसत PM2.5 स्तर लगातार 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक रहते हैं। वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण में 18-24% योगदान देता है, और शहर में लगभग 88 लाख वाहन हैं।

➤ 'नो PUC-नो फ्यूल' नीति के अंतर्गत कैमरा-आधारित निगरानी का उपयोग करके नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को ईंधन देने से मना किया जाएगा।

➤ नवंबर 2026 से केवल BS-VI, CNG या विद्युत वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।

➤ नई EV नीति, 2026 के साथ चार वर्षों में 32,000 EV चार्जिंग बिंदु लगाने की योजना है।

➤ AI-आधारित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट पोर्टल 2.0 वास्तविक समय में निगरानी करेगा।

➤ एक ग्रीन वॉर रूम, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र तथा वार्ड-स्तरीय वायु रक्षक दल स्थापित किए जाएँगे।

➤ 2026-27 में 70 लाख पेड़, झाड़ियाँ और बाँस लगाने का लक्ष्य है।

भारत COP33 की मेज़बानी से पीछे हटा

संदर्भ: भारत ने 2028 में COP33 की मेज़बानी का प्रयास न करने का निर्णय लिया, यद्यपि उसने दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 के दौरान इसकी मेज़बानी की पेशकश की थी। 2028 का सम्मेलन वैश्विक समीक्षा (ग्लोबल स्टॉकटेक) वाले वर्ष में पड़ता है, जिससे भारत पर अधिक जलवायु महत्वाकांक्षा के लिए दबाव पड़ता।

□ **मुख्य बिंदु**

- COP के मेज़बान से पेरिस समझौते के क्रियान्वयन का पैरोकार बनने की अपेक्षा की जाती है, जो भारत के आलोचनात्मक रुख से टकराता है।
- दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक 2028 में होना है; पहला 2023 में COP28 में हुआ था।
- IPCC की सातवीं आकलन रिपोर्ट (AR7), जो 2029 में आनी है, को स्टॉकटेक को आधार देने के लिए 2028 तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
- भारत और चीन ने विकासशील देशों की सीमित समीक्षा क्षमता का हवाला देते हुए AR7 के शीघ्र प्रकाशन का विरोध किया।
- पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी और COP29 के बाद घटे विश्वास ने सर्वसम्मति को और कठिन बना दिया।
- तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक होने के नाते भारत को अधिक अंतरराष्ट्रीय जाँच-परख का सामना करना पड़ता।

भूजल प्रबंधन पर लोक लेखा समिति (PAC) की 41वीं रिपोर्ट

संदर्भ: अप्रैल 2026 में संसद की लोक लेखा समिति ने भूजल प्रबंधन पर अपनी 41वीं रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक भूजल निकासी में भारत का हिस्सा 25% है, जिससे वह सबसे बड़ा निकासीकर्ता है। भूजल 80% पेयजल आवश्यकताओं और 64% सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा प्रतिवर्ष लगभग 245 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में निकासी पुनर्भरण के 100% से अधिक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- भूजल 80% पेयजल आवश्यकताओं और 64% सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- प्रतिवर्ष लगभग 245 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है।
- दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में निकासी पुनर्भरण के 100% से अधिक है।
- 267 जिलों में निकासी का स्तर 64% से 385% के बीच है।
- निकासी का स्तर 2004 में 58% से बढ़कर 2017 में 63% हो गया, फिर 2023 में घटकर 59.26% रह गया।

चर्चा में प्रजातियाँ: बिल्ली, कछुआ, बगुला, व्हेल

संदर्भ: मई 2026 में संरक्षण संबंधी समाचारों में कई प्रजातियाँ चर्चा में रहीं। भारत के पहले उपग्रह-टैग किए गए गंगा नरम कवच कछुए को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रह्मपुत्र में छोड़ा गया, जबकि रस्टी-स्पॉटेड कैट (निकट संकटग्रस्त, अनुसूची I), अत्यधिक संकटग्रस्त सफेद पेट वाला बगुला और स्पर्म व्हेल (सुभेद्य, CITES परिशिष्ट I) भी चर्चा में रहीं। IUCN स्थिति, आवास और विधिक संरक्षण परीक्षा की दृष्टि से सामान्य पहलू हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- रस्टी-स्पॉटेड कैट का वजन 1 से 1.6 किग्रा होता है, इसकी लगभग 80 प्रतिशत आबादी भारत में है, और यह IUCN सूची में निकट संकटग्रस्त तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I में है।
- भारत के पहले उपग्रह-टैग किए गए गंगा नरम कवच कछुए को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रह्मपुत्र में छोड़ा गया; यह संकटग्रस्त है और नदी का सफाईकर्मी जीव है।
- सफेद पेट वाला बगुला अत्यधिक संकटग्रस्त है, इसके 250 से कम वयस्क जीव हैं, और यह अरुणाचल प्रदेश, भूटान तथा उत्तरी म्यांमार में पाया जाता है।
- स्पर्म व्हेल सबसे बड़े दंतयुक्त शिकारी हैं, जो IUCN सूची में सुभेद्य और CITES परिशिष्ट I में हैं; 8,000 से अधिक कोडा के एक अध्ययन से संयोजनात्मक संचार का संकेत मिलता है।

चर्चा में प्रजातियाँ और समुद्री संरक्षण

संदर्भ: जून 2026 में वन्यजीव और समुद्री क्षेत्र के उल्लेखनीय घटनाक्रमों में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कैराकल (स्याहगोश) का दिखना, काजीरंगा में एल्बिनो हॉग डियर, ग्रेट निकोबार में प्रवाल स्थानांतरण और लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के पास पावोना क्लावस प्रवाल का विशाल क्षेत्र शामिल रहे। ZSI ने गैलाथिया खाड़ी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह से प्रभावित प्रवालों को स्थानांतरित करने के लिए चार नए स्थल चिह्नित किए, और तमिलनाडु भारत की पहली 3D-प्रिंटेड कृत्रिम भित्ति (आर्टिफिशियल रीफ) स्थापित करेगा।

□ **प्रजातियाँ**

- भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल (स्याहगोश) मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई; यह IUCN में कम चिंताजनक और अनुसूची I में है।
- काजीरंगा में एक एल्बिनो हॉग डियर देखा गया; हॉग डियर संकटग्रस्त और अनुसूची I में है।
- सुमात्रा के बाटांग टोरू का स्थानिक तापनुली ओरांगउटान अत्यधिक संकटग्रस्त है; 2025 के चक्रवात में इसकी लगभग 7 प्रतिशत आबादी मारी गई।

□ **समुद्री**

- ZSI ने गैलाथिया खाड़ी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह से प्रभावित प्रवालों और विशाल क्लैम को स्थानांतरित करने के लिए चार नए स्थल चिह्नित किए।
- लक्षद्वीप के कदमत द्वीप पर लगभग 4,250 वर्ग मीटर का विशाल पावोना क्लावस प्रवाल क्षेत्र पाया गया।
- तमिलनाडु PMMSY के अंतर्गत भारत की पहली 3D-प्रिंटेड कृत्रिम भित्ति (आर्टिफिशियल रीफ) स्थापित करेगा, जिसे त्वष्टा ने ICAR-CMFRI के साथ मिलकर विकसित किया है।

फ्लोटिंग सोलर पीवी क्षमता आकलन रिपोर्ट समाचार

संदर्भ: जून 2026 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने फ्लोटिंग सोलर पीवी क्षमता आकलन रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की फ्लोटिंग सौर क्षमता 102.18 GWp आँकी गई, और प्रधानमंत्री ने ओडिशा में भारत की पहली वाणिज्यिक-स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना का संचालन राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के अंतर्गत भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो BHEL और कोल इंडिया का संयुक्त उद्यम है।

□ **तैरता सौर**

- भारत में फ्लोटिंग सोलर की अनुमानित क्षमता 102.18 GWp है।
- कुल आकलित सौर क्षमता बढ़कर 3,445 GWp हो गई है, और स्थापित सौर क्षमता 2014 में 2.8 GW से बढ़कर 2026 में 155 GW हो गई।
- महाराष्ट्र 16.28 GW के साथ अग्रणी है, उसके बाद मध्य प्रदेश (14.89 GW) और कर्नाटक (13.69 GW) हैं।

□ **कोयले से अमोनियम नाइट्रेट**

- भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो BHEL और कोल इंडिया का संयुक्त उद्यम है, प्रतिदिन 2,000 टन का उत्पादन करेगा।
- राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है।
- ₹8,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना (2024) गैसीकरण परियोजनाओं को सहायता देती है।
- भारत के पास विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार है, जो 400 अरब टन से अधिक है।

बॉन SB64 जलवायु लक्ष्य और मीथेन पर कार्रवाई का आह्वान

संदर्भ: जून 2026 में बॉन जलवायु सम्मेलन (SB64) ने अंताल्या, तुर्किये में 9 से 20 नवंबर 2026 को प्रस्तावित COP31 से पहले 2035 के नए लक्ष्य निर्धारित किए, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मीथेन पर वैश्विक कार्रवाई का आह्वान शुरू किया। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को भी अंतिम रूप दिया, जो भारत का पहला सक्रिय द्विपक्षीय कार्बन व्यापार ढाँचा है।

□ **मुख्य बिंदु**

- भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को अंतिम रूप दिया, जो भारत का पहला सक्रिय द्विपक्षीय कार्बन व्यापार ढाँचा है।
- इसके अंतर्गत दिल्ली मेट्रो कार्बन क्रेडिट हस्तांतरण के लिए पात्र होगी।
- WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत 70वें स्थान पर है, जो दो स्थान की वृद्धि है।

□ **SB64 के लक्ष्य**

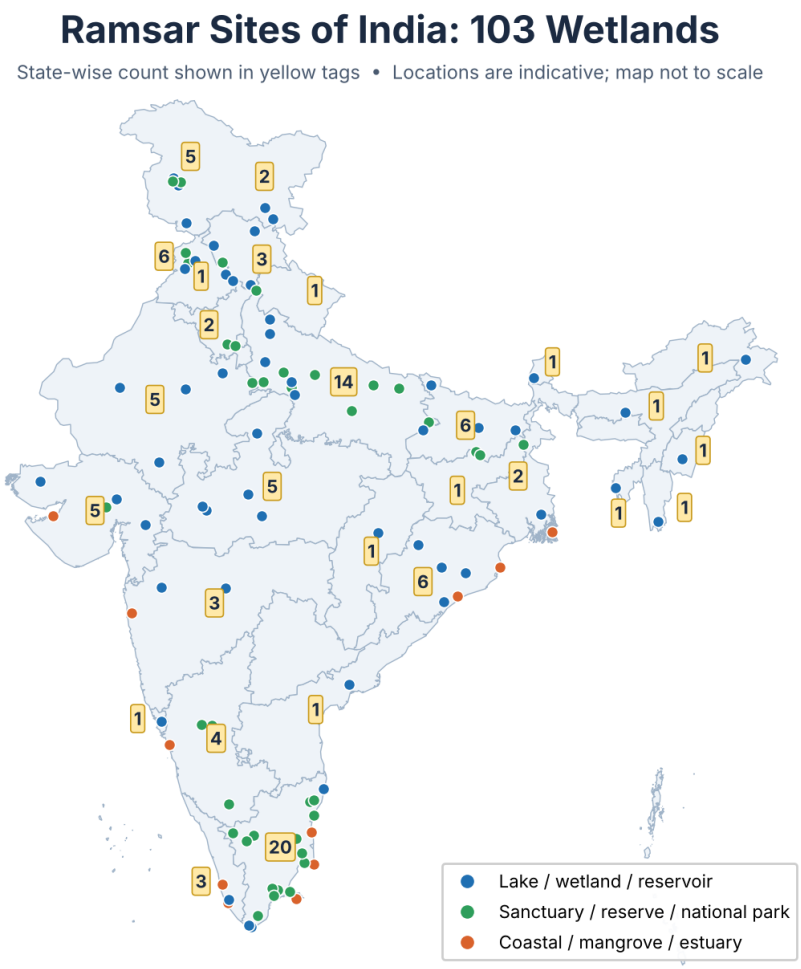
- COP31 अंताल्या, तुर्किये में 9 से 20 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित है।
- 2035 तक अंतिम ऊर्जा माँग में बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर 35 प्रतिशत होनी चाहिए।
- वैश्विक अपशिष्ट की वृद्धि को आधा किया जाना चाहिए तथा भवन क्षेत्र की ऊर्जा गहनता में कम से कम 25 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए।

□ **मीथेन**

- 2021 में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा शुरू की गई वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का लक्ष्य 2030 तक 2020 के स्तर से 30 प्रतिशत कटौती करना है; भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- 20 वर्षों में मीथेन CO2 की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन केवल लगभग एक दशक तक बनी रहती है।
- मानव-जनित मीथेन में जीवाश्म ईंधन का योगदान 38 प्रतिशत, कृषि का 42 प्रतिशत और अपशिष्ट का 20 प्रतिशत है।
- इस आह्वान में नौ कार्रवाइयाँ हैं, जिनमें नियमित फ्लेयरिंग और वेंटिंग पर प्रतिबंध तथा खुले में कचरा फेंकने को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना शामिल है।

भारत के 103 रामसर स्थल: राज्यवार मानचित्र और तथ्य

संदर्भ: भारत में अब रामसर अभिसमय के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्व की 103 आर्द्रभूमियाँ हैं, जो 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। नीचे दिया गया मानचित्र स्थलों को उनके प्रकार के अनुसार, राज्यवार संख्या और पूरी सूची के साथ दर्शाता है।



First sites (1981): Chilika Lake and Keoladeo National Park • Most sites: Tamil Nadu (20), then Uttar Pradesh (14) • Largest: Sundarban Wetland (West Bengal) • Smallest: Vembannur Wetland Complex (Tamil Nadu)

Tamil Nadu (20)
Gulf of Mannar, Point Calimere, Pichavaram Mangrove, Pallikaranai Marsh, Vellode Bird Sanctuary, Koonthankulam Bird Sanctuary, Karikili Bird Sanctuary, Udhayamarthandapuram BS, Vedanthangal Bird Sanctuary, Vembannur Wetland Complex, Chitrangudi Bird Sanctuary, Vaduvur Bird Sanctuary, Kanjirankulam Bird Sanctuary, Suchindram-Theroor Wetland, Karaivetti Bird Sanctuary, Longwood Shola Reserve Forest, Nanjarayan Bird Sanctuary, Kazhuveli Bird Sanctuary, Sakkarakottai Bird Sanctuary, Therthangal Bird Sanctuary

Jammu & Kashmir (5)
Wular Lake, Hokera Wetland, Surinsar-Mansar Lakes, Shallbugh Wetland, Hygam Wetland

Karnataka (4)
Ranganathittu Bird Sanctuary, Ankasamudra Bird Conservation Reserve, Aghanashini Estuary, Magadi Kere Conservation Reserve

Ladakh (2)
Tso Moriri, Tso Kar Wetland Complex

Arunachal Pradesh (1)
Glaw Lake

Chhattisgarh (1)
Kopra Reservoir

Manipur (1)
Loktak Lake

Tripura (1)
Rudrasagar Lake

Uttar Pradesh (14)
Upper Ganga River, Haiderpur Wetland, Bakhira Wildlife Sanctuary, Samaspur Bird Sanctuary, Parvati Arga Bird Sanctuary, Saman Bird Sanctuary, Sur Sarovar, Sandi Bird Sanctuary, Nawabganj Bird Sanctuary, Sarsai Nawar Jheel, Patna Bird Sanctuary, Shekha Jheel, Surha Tal (JP Narayan BS), Sauj Lake

Gujarat (5)
Nalsarovar Bird Sanctuary, Thol Lake, Wadhvana Wetland, Khijadia Bird Sanctuary, Chhari Dhand

Madhya Pradesh (5)
Bhoj Wetland, Sakhya Sagar, Sirpur Wetland, Yashwant Sagar, Tawa Reservoir

Himachal Pradesh (3)
Pong Dam Lake, Chandertal Wetland, Renuka Wetland

Maharashtra (3)
Nandur Madhameshwar, Lonar Lake, Thane Creek

West Bengal (2)
Sundarban Wetland, East Kolkata Wetlands

Assam (1)
Deepor Beel

Goa (1)
Nanda Lake

Mizoram (1)
Pala Wetland

Uttarakhand (1)
Asan Conservation Reserve

Bihar (6)
Kabartal Wetland, Nagi Bird Sanctuary, Nakti Bird Sanctuary, Gokul Jalashay, Udaipur Lake, Gogabil Lake

Odisha (6)
Chilika Lake, Satkosia Gorge, Bhitarkanika Mangroves, Hirakud Reservoir, Tampara Lake, Ansupa Lake

Punjab (6)
Beas Conservation Reserve, Harike Lake, Ropar Wetland, Keshopur-Miani Community Reserve, Kanjli Wetland, Nangal Wildlife Sanctuary

Rajasthan (5)
Sambhar Lake, Keoladeo National Park, Khichan Wetland, Menar Wetland Complex, Siliserh Lake

Kerala (3)
Vembanad-Kol Wetland, Ashtamudi Wetland, Sasthamkotta Lake

Haryana (2)
Bhindawas Wildlife Sanctuary, Sultanpur National Park

Andhra Pradesh (1)
Kolleru Lake

Chandigarh (1)
Sukhna Wetland

Jharkhand (1)
Udhwa Lake Bird Sanctuary

Sikkim (1)
Khecheopalri Wetland

□ मुख्य बिंदु

➤ भारत में कुल रामसर स्थल: 103।

➤ सर्वाधिक स्थल: तमिलनाडु (20), उसके बाद उत्तर प्रदेश (14)।

➤ भारत के पहले रामसर स्थल (1981): चिल्का झील (ओडिशा) और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)।

➤ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल: सुंदरबन आर्द्रभूमि (पश्चिम बंगाल)।

- सबसे छोटा: वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर (तमिलनाडु)।
- हाल के जोड़: पटना पक्षी अभयारण्य और छारी-ढांड, शेखा झील, सुरहा ताल, ग्लॉ झील (अरुणाचल प्रदेश का पहला), सुखना आर्द्रभूमि और सौज झील।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार रामसर स्थल (संख्या)

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	स्थल
तमिलनाडु	20
उत्तर प्रदेश	14
बिहार	6
ओडिशा	6
पंजाब	6
गुजरात	5
जम्मू और कश्मीर	5
मध्य प्रदेश	5
राजस्थान	5
कर्नाटक	4
हिमाचल प्रदेश	3
केरल	3
महाराष्ट्र	3
हरियाणा	2
लद्दाख	2
पश्चिम बंगाल	2
आंध्र प्रदेश	1
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	1
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	1
गोवा	1
झारखंड	1
मणिपुर	1
मिज़ोरम	1
सिक्किम	1
त्रिपुरा	1
उत्तराखंड	1

भारत में पहुँच और लाभ साझाकरण ढाँचा

संदर्भ: जून 2026 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत का पहुँच और लाभ साझाकरण ढाँचा चर्चा में रहा, जिसके तहत ₹266 करोड़ से अधिक जुटाए गए और लगभग ₹145 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए गए। प्राप्ति में रक्त चंदन का हिस्सा 45 प्रतिशत है। यह ढाँचा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से कार्य करता है, तथा जैविक विविधता (ABS) विनियम 2025 ने 2014 के नियमों का स्थान लिया।

□ **मुख्य बिंदु**

- ABS प्राप्ति में रक्त चंदन का हिस्सा 45 प्रतिशत, बीज क्षेत्र का 32.3 प्रतिशत तथा औषधि एवं आयुष का 13.8 प्रतिशत है।
- जैव विविधता अभिसमय (CBD) के अंतर्गत नागोया प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ।
- त्रि-स्तरीय संरचना में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ शामिल हैं।
- जैविक विविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियम 2025 ने 2014 के नियमों का स्थान लिया और यह डिजिटल अनुक्रम सूचना को भी शामिल करता है।
- COP16 में शुरू किया गया कैली फंड डिजिटल अनुक्रम सूचना से होने वाले लाभ के साझाकरण में सहायता करता है।

□ **उदाहरण**

- TBGRI ने जीवनी औषधि के लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी का 50 प्रतिशत कानी जनजाति के साथ साझा किया।
- भारत ने पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण का उपयोग करके हल्दी और नीम पर दिए गए विदेशी पेटेंट रद्द करवाए।
- दिव्य फार्मेसी बनाम भारत संघ (2018) में घरेलू कंपनियों के लाभ-साझाकरण दायित्वों को बरकरार रखा गया।
- FAO के अंतर्गत 2004 से लागू ।ITPGRFA अपनी बहुपक्षीय प्रणाली में 64 फसलों को शामिल करता है।

वैश्विक रसायन निगरानी कार्यक्रम शुरू

संदर्भ: जून 2026 में UNEP और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) ने स्टॉकहोम और मिनामाता अभिसमयों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए वैश्विक रसायन निगरानी कार्यक्रम शुरू किया। यह GEF द्वारा वित्तपोषित 23.5 मिलियन डॉलर की पहल है, जिसे 50 मिलियन डॉलर के सह-वित्तपोषण का समर्थन प्राप्त है, और यह विकासशील देशों की खतरनाक रसायनों की निगरानी की क्षमता का निर्माण करती है। स्टॉकहोम अभिसमय POPs से और मिनामाता पारे से संबंधित है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह कार्यक्रम GEF द्वारा वित्तपोषित 23.5 मिलियन डॉलर की पहल है, जिसे 50 मिलियन डॉलर के सह-वित्तपोषण का समर्थन प्राप्त है।
- यह विकासशील देशों की खतरनाक रसायनों की निगरानी की क्षमता का निर्माण करता है।

□ **अभिसमय**

- POPs पर स्टॉकहोम अभिसमय 22 मई 2001 को अपनाया गया और 17 मई 2004 को लागू हुआ; भारत ने 2006 में ऑप्ट-आउट खंड के साथ इसकी पुष्टि की।
- पारे पर मिनामाता अभिसमय 10 अक्टूबर 2013 को कुमामोतो, जापान में अपनाया गया और 16 अगस्त 2017 को लागू हुआ।

- प्लैनेटगोल्ड (PlanetGOLD) पारा-मुक्त शिल्पकार स्वर्ण खनन के लिए GEF द्वारा समर्थित कार्यक्रम है।
- UNEP की स्थापना 1972 में हुई और इसका मुख्यालय नैरोबी में है; GEF की स्थापना 1991 में हुई, जिसमें विश्व बैंक न्यासी है।

सौज झील (मैनपुरी): उत्तर प्रदेश का 14वाँ रामसर स्थल

संदर्भ: मैनपुरी जिले की सौज झील को 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या 14 हो गई है, जो तमिलनाडु के बाद देश में सर्वाधिक है। यह गंगा-यमुना दोआब में एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। मैनपुरी में पहले से समान पक्षी अभयारण्य है, इसलिए अब जिले में दो रामसर आर्द्रभूमियाँ हैं।

□ मुख्य बिंदु

- सौज झील गंगा-यमुना दोआब के मैनपुरी जिले में स्थित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है।
- मैनपुरी में पहले से समान पक्षी अभयारण्य है, इसलिए अब जिले में दो रामसर आर्द्रभूमियाँ हैं।
- उत्तर प्रदेश के स्थलों में ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर, बखिरा, सूर सरोवर, सुरहा ताल, पटना और शेखा आदि शामिल हैं।

CAFE-III मानदंडों का मसौदा

संदर्भ: सरकार ने यात्री वाहनों के लिए संशोधित कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) III मानदंडों का मसौदा जारी किया, जिसे CAFE-II के स्थान पर 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है। जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

□ मुख्य बिंदु

- CAFE मानदंड प्रत्येक निर्माता के लिए बेड़े की औसत ईंधन दक्षता या CO2 लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इनका प्रशासन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो करता है।
- प्रस्तावित बेड़ा लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 के लिए 3.996 लीटर प्रति 100 किमी (94.76 ग्राम CO2/किमी) है, जो वित्त वर्ष 2032 तक कठोर होकर 3.327 लीटर प्रति 100 किमी (78.90 ग्राम CO2/किमी) हो जाएगा।
- ये चालक के अतिरिक्त अधिकतम आठ सीटों वाले M1 यात्री वाहनों पर लागू होते हैं, दो या तीन पहिया वाहनों अथवा वाणिज्यिक वाहनों पर नहीं।
- BEV, PHEV, रेंज-एक्सटेंडेड EV, इथेनॉल या जैव ईंधन वाहनों और ईंधन-बचत प्रौद्योगिकियों के लिए सुपर क्रेडिट दिए जाते हैं।
- CAFE-I 2017-2022 तक चला और CAFE-II 2022-2027 के लिए है।

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और E20 पर बहस

संदर्भ: सरकार ने इंजन की अनुकूलता, माइलेज और बीमा संबंधी चिंताओं के बावजूद E20 पेट्रोल (20 प्रतिशत इथेनॉल) को पूरे देश में लागू करने का बचाव किया। भारत ने 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य 2025 में, यानी निर्धारित समय से पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया।

□ मुख्य बिंदु

- अप्रैल 2026 से सभी BS-VI पेट्रोल वाहनों को E20 मानकों का पालन करना होगा।
- सरकार मानती है कि कई पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता में 3-5 प्रतिशत की गिरावट आएगी।
- केवल इसलिए बीमा दावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि E20 का उपयोग किया गया था।
- अभी 20 प्रतिशत से अधिक मिश्रण को अनिवार्य करने का कोई निर्णय नहीं है; अधिक मिश्रण के लिए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की आवश्यकता होगी।
- जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E100 ईंधन के लिए एक नियामकीय ढाँचे को मंज़ूरी दी, जो इसे लागू करने की अनिवार्यता नहीं है।

□ समयरेखा

- 2001 में इथेनॉल मिश्रण का पायलट परीक्षण; 2003-04 में औपचारिक शुरुआत।
- 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति ने कच्चे माल का दायरा मक्का और अधिशेष अनाज तक बढ़ाया तथा इथेनॉल पर GST को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया।
- 2021 में 2020-25 के लिए नीति आयोग का रोडमैप; 2022 में E10 की प्राप्ति; 2023 में चुनिंदा आउटलेट पर E20 ईंधन की शुरुआत।

चर्चा में हिमालयी पैंगोलिन और मालवी ऊँट

संदर्भ: जुलाई 2026 में हिमालयी पैंगोलिन (मैनिस ऑरिटा) की एक अलग प्रजाति के रूप में पुष्टि हुई, जिसे पहले चीनी पैंगोलिन की उप-प्रजाति माना जाता था, और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ने मालवी ऊँट के लिए प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया। दोनों पैंगोलिन वंश लगभग 18 लाख वर्ष पहले अलग हुए थे। मालवा क्षेत्र के नाम पर रखा गया मालवी ऊँट सफेद रंग का है और 2019 की पशुधन गणना में इसे संकटग्रस्त सूचीबद्ध किया गया था।

□ हिमालयी पैंगोलिन

- मैनिस ऑरिटा को पहले चीनी पैंगोलिन, मैनिस पेंटाडैक्टाइला, की उप-प्रजाति माना जाता था।
- दोनों वंश प्रारंभिक प्लिस्टोसीन में लगभग 18 लाख वर्ष पहले अलग हुए।
- यह नेपाल, दक्षिणी तिब्बत और असम सहित पूर्वोत्तर भारत की दक्षिणी हिमालयी तलहटी में पाया जाता है।

➤ विश्व में पैंगोलिन की आठ प्रजातियाँ हैं, जिनमें भारतीय पैंगोलिन मैनिस क्रैसिकॉडेटा भी शामिल है।

□ **मालवी ऊँट**

➤ भारत की नौ मान्यता प्राप्त ऊँट नस्लों में से एक, जिसका नाम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर रखा गया है।

➤ यह सफेद रंग का, भारत की सबसे छोटी नस्ल है और 2019 की पशुधन गणना में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है।

थार में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्थिति

संदर्भ: जुलाई 2026 में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राजस्थान के जैसलमेर के थार भू-परिदृश्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्थिति और प्रवृत्ति रिपोर्ट जारी की, जो इसका अंतिम गढ़ है। इसकी आबादी 130 ± 21 आँकी गई है, जो 2017-18 से स्थिर है। यह पक्षी अत्यधिक संकटग्रस्त है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I में है और राजस्थान का राज्य पक्षी है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह IUCN सूची में अत्यधिक संकटग्रस्त, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I और CITES परिशिष्ट I में है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है।

➤ आबादी 130 ± 21 आँकी गई है, जो 2017-18 से स्थिर है।

➤ खतरों में बिजली की लाइनें, कृषि बाड़बंदी, सड़कें और सौर संयंत्र शामिल हैं, जिनसे विखंडन और टकराव होते हैं।

➤ संरक्षण प्रयासों में संरक्षण प्रजनन, आवास की बहाली और आक्रामक प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हटाना शामिल हैं।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026

संदर्भ: जुलाई 2026 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 177 देशों में से 22.46 अंक के साथ 176वें स्थान पर रहा, जो विश्व में दूसरा सबसे निचला स्थान है और केवल लाओस से ऊपर है, जबकि एस्टोनिया 74.79 अंक के साथ शीर्ष पर रहा। EPI का द्विवार्षिक प्रकाशन येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के CIESIN के साथ किया जाता है, और इसमें 3 नीतिगत उद्देश्य, 12 मुद्दा श्रेणियाँ और 47 संकेतक हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ एस्टोनिया 74.79 अंक के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा।

➤ EPI का द्विवार्षिक प्रकाशन येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के CIESIN के साथ किया जाता है।

➤ इस ढाँचे में 3 नीतिगत उद्देश्य, 12 मुद्दा श्रेणियाँ और 47 संकेतक हैं।

➤ उद्देश्य हैं: पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारितंत्र जीवंतता और जलवायु परिवर्तन।

पश्चिमी घाट में प्रस्तावित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र

संदर्भ: एक प्रस्तावित केंद्रीय अधिसूचना में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पश्चिमी घाट के 56,825.7 वर्ग किमी को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की बात कही गई है, जो काफी हद तक कस्तूरीरंगन समिति का अनुसरण करती है। अंतिम अधिसूचना उन राज्यों पर लागू होगी जहाँ सहमति बन चुकी है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ निषिद्ध: नया खनन और उत्खनन, ताप विद्युत संयंत्र, नए लाल श्रेणी के उद्योग, तथा 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक की बड़ी निर्माण परियोजनाएँ और 50 हेक्टेयर से अधिक की टाउनशिप।

➤ विनियमित: वे अवसंरचना परियोजनाएँ जिन्हें पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है।

➤ अनुमत: कृषि, वृक्षारोपण, बागवानी, मानकों के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन और मौजूदा बस्तियाँ।

राज्य-वार प्रस्तावित ESA

राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
गुजरात	449
महाराष्ट्र	17,340
गोवा	1,461
कर्नाटक	20,668
तमिलनाडु	6,914
केरल	9,993.7

पुगा घाटी में भारत के पहले भूतापीय कुएँ

संदर्भ: जुलाई 2026 में भारत ने लद्दाख की पुगा घाटी में 14,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर अपने पहले दो भूतापीय कुएँ चालू किए, जो पहली 1 मेगावाट की पायलट भूतापीय विद्युत परियोजना की दिशा में एक कदम है। प्रत्येक कुआँ लगभग 1,000 मीटर गहरा है और 400 मीटर पर अधिकतम तापमान 135 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ONGC एनर्जी सेंटर इसे लद्दाख प्रशासन के साथ मिलकर क्रियान्वित कर रहा है।

□ **पुगा परियोजना**

➤ प्रत्येक कुआँ लगभग 1,000 मीटर गहरा है।

➤ 400 मीटर पर अधिकतम तापमान 135 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

➤ ONGC एनर्जी सेंटर इसे लद्दाख प्रशासन और LAHDC लेह के साथ मिलकर क्रियान्वित कर रहा है; MNRE नोडल मंत्रालय है।

➤ परियोजना के लिए एक समझौते की घोषणा 2021 में की गई थी।

□ **भारत में भूतापीय क्षमता**

➤ GSI ने 381 गर्म झरनों और 10 भूतापीय प्रांतों का मानचित्रण किया है, जिनमें 42 संभावनाशील स्थल हैं।

- सैद्धांतिक क्षमता लगभग 10.6 GW है।
- राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति, 2025 अनुसंधान, भू-स्रोत ताप पंपों और परित्यक्त तेल कुओं के पुन: उपयोग को समर्थन देती है।
- 2025 के अंत तक वैश्विक स्थापित क्षमता 15.67 GW तक पहुँच गई।
- 2015 में पेरिस में COP21 में शुरू किए गए वैश्विक भूतापीय गठबंधन के भारत सहित 56 सदस्य हैं।

बाघों के सक्रिय प्रबंधन हेतु रोड मैप जारी

संदर्भ: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन हेतु रोड मैप जारी किया, जो उपयुक्त भू-परिदृश्यों में बाघों की आबादी बहाल करने का एक वैज्ञानिक ढाँचा है।

□ मुख्य बिंदु

- इसकी त्रि-स्तरीय संरचना है: आधारभूत स्तर, सक्रिय प्रबंधन स्तर और भविष्य सहनीयता स्तर। यह कोर, बफर और प्रभाव क्षेत्र में स्रोत और सिंक भू-परिदृश्यों को मानता है।
- सिफारिशों में शिकार प्रजातियों की बहाली (गौर, बारहसिंगा का स्थानांतरण), गलियारों की पुनर्स्थापना और GIS-आधारित नियोजन शामिल हैं।
- निगरानी में रेडियो टेलीमेट्री और M-STrIPES का उपयोग किया जाता है।

□ बाघों की स्थिति

- भारत में 18 राज्यों में 58 बाघ अभयारण्य हैं, जो देश के लगभग 2.6 प्रतिशत क्षेत्र में फैले हैं।
- 2022 का अनुमान 3,682 बाघों का है, जो वैश्विक जंगली बाघ आबादी का लगभग 70 प्रतिशत है।
- कम घनत्व वाले अभयारण्यों में बक्सा, अचानकमार, उदंती-सीतानदी, इंद्रावती और पलामू शामिल हैं।

बोरजुली आर्द्रभूमि जैव विविधता विरासत स्थल बनी

संदर्भ: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने असम के सोनितपुर जिले की बोरजुली आर्द्रभूमि को जंगली चावल, ओराइज़ा रुफिपोगोन, जो कृषि में उगाए जाने वाले चावल (ओराइज़ा सटाइवा) का जंगली पूर्वज है, के संरक्षण हेतु जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) के रूप में अधिसूचित किया।

□ मुख्य बिंदु

- BHS की घोषणा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और राज्य जैव विविधता बोर्ड से परामर्श के बाद राजपत्र के माध्यम से की जाती है। मानदंडों में प्रजाति समृद्धि, स्थानिकता, संकटग्रस्त प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ, कृषित प्रजातियों के जंगली पूर्वज और जीवाश्म स्तर शामिल हैं।
- यह अधिसूचना सोनितपुर में 2022 से चल रही जंगली चावल के स्वस्थाने संरक्षण की एक परियोजना के बाद आई है, जिसे राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण ने वित्तपोषित किया और ICAR-NBPGR ने क्रियान्वित किया।
- जंगली चावल कीट और रोग प्रतिरोध, बाढ़ और लवणता सहनशीलता तथा जलवायु-सहनशील किस्मों के लिए गुण प्रदान करता है।
- असम के अधिसूचित BHS अब माजुली, बोरजुली जंगली चावल और हाजोंग कछुआ झील हैं।

भारतीय कार्बन बाजार और उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य

संदर्भ: जुलाई 2026 में बेंगलुरु के एक थिंक टैंक ने कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियमों के मसौदे का मूल्यांकन किया। यह योजना 2023 में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचित की गई थी और इसका प्रशासन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो करता है। लक्ष्य प्रति इकाई उत्पादन उत्सर्जन पर आधारित हैं, और इन्हें पार करने वाली इकाइयों को व्यापार-योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिलते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- यह ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचित कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 के अंतर्गत कार्य करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसका प्रशासन करता है और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रजिस्ट्री का प्रबंधन करता है।
- CERC व्यापार का विनियमन करता है और शासन की जिम्मेदारी भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के पास है।
- लक्ष्य निरपेक्ष सीमाओं के बजाय प्रति इकाई उत्पादन उत्सर्जन पर आधारित हैं।
- अपने लक्ष्य को पार करने वाली इकाइयों को व्यापार-योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिलते हैं।

राज्य मूल्यांकन निकायों के लिए EIA अधिसूचना में संशोधन

संदर्भ: जुलाई 2026 में पर्यावरण मंत्रालय ने EIA अधिसूचना, 2006 में संशोधन कर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दो स्थायी निकाय बनाए, ताकि मूल्यांकन निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर परियोजना मूल्यांकन न रुके। एक स्थायी प्राधिकरण (SAEIA) SEIAA के कार्य संभालेगा, और एक स्थायी समिति (SCEIA) राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का स्थान लेगी। कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है।

□ मुख्य बिंदु

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी 2006 की अधिसूचना में चार चरण हैं: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन परामर्श और मूल्यांकन। श्रेणी A की परियोजनाओं को केंद्रीय मंजूरी की आवश्यकता होती है; श्रेणी B की परियोजनाओं को SEIAA से मंजूरी की आवश्यकता होती है।

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर स्थायी प्राधिकरण (SAEIA) SEIAA के कार्य संभालेगा।
- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर स्थायी समिति (SCEIA) राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का स्थान लेगी।
- SEIAA और SEAC का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है।
- SEIAA की अनुपस्थिति में श्रेणी B के प्रस्तावों को केंद्रीय EAC को सौंपने वाला प्रावधान हटा दिया गया है।
- EAC या SEAC की सदस्यता सदस्य सचिव सहित अधिकतम 15 तक सीमित है।
- अंतरिम निकाय छह माह के लिए कार्य कर सकते हैं, जिसे छह माह और बढ़ाया जा सकता है।
- परिवेश (PARIVESH) एकल-खिड़की पोर्टल है।

UNCCD COP17 में घास के मैदानों की मार्गदर्शिका और संबंधित संरक्षण समाचार

संदर्भ: भारत ने मंगोलिया के उलानबाटर में UNCCD COP17 में घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की अपनी पहली मार्गदर्शिका जारी की। अन्य संरक्षण समाचारों में तितलियों और पतंगों की राष्ट्रीय सूची, एक तैरती सौर योजना और धुंधला तेंदुआ मिशन शामिल थे।

□ मुख्य बिंदु

- इसमें घास के मैदान, सवाना, झाड़ीदार भूमि, मरुस्थल, बीहड़, चट्टानी पठार और तटीय खुले पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं।
- उदाहरणों में कच्छ के बन्नी घास के मैदान, थार मरुस्थल, दक्कन के सवाना, यमुना-चंबल के बीहड़ और मध्य निकोबार के घास के मैदान शामिल हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व के लिए 10 किमी का खनन बफ़र

संदर्भ: अगस्त 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व पर लागू 10 किमी की खनन सुरक्षा को देश भर के अन्य आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्वों तक बढ़ा दिया। फरवरी 2024 में न्यायालय ने NBWL की स्थायी समिति या MoEFCC की पूर्व अनुमति के बिना आसन रिज़र्व के 10 किमी के भीतर खनन पर रोक लगाई थी। यह सिद्धांत पूर्व अनुमति की आवश्यकता का है, पूर्ण प्रतिबंध का नहीं।

□ मुख्य बिंदु

- आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व देहरादून के निकट आसन और यमुना के संगम पर स्थित एक रामसर स्थल है, जिसका निर्माण आसन बैराज (1967) से हुआ। फरवरी 2024 में न्यायालय ने NBWL की स्थायी समिति या MoEFCC की पूर्व अनुमति के बिना आसन रिज़र्व के 10 किमी के भीतर खनन पर रोक लगाई थी।
- नया सिद्धांत समान सुरक्षा प्रदान करता है और यह पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं।
- यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 2005 में संरक्षण रिज़र्व बना।
- यह 2020 में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना।

गंगा बाढ़ मैदान: प्रतिबंध की जगह त्रि-स्तरीय क्षेत्र-निर्धारण

संदर्भ: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी गंगा (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में संशोधन कर निर्माण-मुक्त क्षेत्र के सामान्य प्रतिबंध की जगह बाढ़-जोखिम के आधार पर तीन क्षेत्रों का वर्गीकरण लागू किया।

□ मुख्य बिंदु

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 2016 के आदेश में बाढ़ मैदान को 100 वर्ष की बाढ़ के आधार पर परिभाषित किया गया था, लेकिन सक्रिय बाढ़ मैदान को कभी परिभाषित नहीं किया गया।
- नया ढाँचा सामान्य प्रतिबंध को समाप्त करता है।

□ तीन क्षेत्र

- सक्रिय बाढ़ मैदान में कम से कम 5 वर्ष में एक बार बाढ़ आती है; अस्थायी संरचनाओं के लिए सीमित छूट के साथ निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- विनियामक क्षेत्र में 5 से 25 वर्ष में एक बार बाढ़ आती है; मंज़ूरियों के साथ निर्माण की अनुमति है।
- चेतावनी क्षेत्र में 25 से 100 वर्ष में एक बार बाढ़ आती है; मंज़ूरियों के साथ निर्माण की अनुमति है।

गंगा बाढ़ मैदान के क्षेत्र

क्षेत्र	बाढ़ की आवृत्ति	निर्माण
सक्रिय बाढ़ मैदान	कम से कम 5 वर्ष में एक बार	पूर्णतः प्रतिबंधित
विनियामक क्षेत्र	5 से 25 वर्ष में एक बार	मंज़ूरियों के साथ अनुमत
चेतावनी क्षेत्र	25 से 100 वर्ष में एक बार	मंज़ूरियों के साथ अनुमत

ग्लॉ झील: भारत का 101वाँ रामसर स्थल

संदर्भ: अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की ग्लॉ झील को भारत का 101वाँ रामसर स्थल और राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। यह पूर्वी हिमालय में 1,168 मीटर की ऊँचाई पर कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और कमलांग नदी सहित बारहमासी नदियों व धाराओं से पोषित होती है। यहाँ धुंधला तेंदुआ और सफ़ेद पेट वाला बगुला पाए जाते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- यह पूर्वी हिमालय में 1,168 मीटर की ऊँचाई पर कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है।

- यह कमलांग नदी सहित बारहमासी नदियों और धाराओं से पोषित होती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित में मिलती है।
- यह झील धुंधला तेंदुआ और सफ़ेद पेट वाला बगुला जैसी प्रजातियों का आश्रय है।

FAO की वानिकी समिति (COFO 28) में भारत

संदर्भ: रोम में FAO की वानिकी समिति के 28वें सत्र में भारत ने वन पुनर्स्थापन और जलवायु कार्रवाई में अपनी प्रगति को रेखांकित किया। भारत ने भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के अंतर्गत अपने पहले प्रमाण (PRAMAAN) प्रमाणपत्र भी जारी किए।

□ मुख्य बिंदु

- भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 82.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो उसके क्षेत्रफल का 25.17% है।
- FAO वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार वन क्षेत्र में भारत विश्व में 9वें और वार्षिक वन-क्षेत्र वृद्धि में 3रे स्थान पर है।
- इसका लक्ष्य 2035 तक 3.5-4 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना है।
- अरावली ग्रीन वॉल के अंतर्गत 6.45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है, और एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत 3.5 अरब से अधिक पौधे लगाए गए।
- भारत ने वनरोपण और पुनर्वनीकरण के लिए प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र दशक (2027-36) का समर्थन किया।

□ PRAMAAN प्रमाणन

- PRAMAAN का पूर्ण रूप है: कृषि-वानिकी और प्राकृतिक वन संसाधनों के लिए सतत प्रबंधन पद्धतियों की मान्यता और प्रत्यायन कार्यक्रम।
- इसे 2023 में IFWCS के अंतर्गत शुरू किया गया था और इसका संचालन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान करता है।
- लेखा-परीक्षण (ऑडिट) भारतीय गुणवत्ता परिषद के NABCB के अंतर्गत तृतीय-पक्ष द्वारा किए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 पर आधारित मानकों का उपयोग होता है।

NCR के लिए पराली जलाने पर सख़्त नियम प्रस्तावित

संदर्भ: केंद्र ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्रों के लिए सख़्त नियम प्रस्तावित किए हैं, जिनमें पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध भू-राजस्व अभिलेखों में 15 महीने के लिए लाल प्रविष्टि शामिल है।

□ मुख्य बिंदु

- बार-बार पराली जलाने या मुआवज़ा न चुकाने पर लाल प्रविष्टि को 15 महीने और बढ़ाया जा सकता है।
- जुर्माना 2 एकड़ से कम पर ₹5,000, 2 से 5 एकड़ से कम पर ₹10,000 और 5 एकड़ से अधिक पर ₹30,000 है।
- अदत्त जुर्माने की वसूली 30 दिन बाद भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकती है।
- लाल प्रविष्टि से भूमि की बिक्री, सरकारी योजनाओं और MSP पर खरीद पर रोक लग सकती है।
- जुर्माने की राशि का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से फसल-अवशेष मशीनरी, फसल विविधीकरण और बायोमास भंडारण में सहायता के लिए किया जाएगा।

पराली जलाने पर प्रस्तावित जुर्माने

भू-जोत	जुर्माना
2 एकड़ से कम	₹5,000
2 से 5 एकड़ से कम	₹10,000
5 एकड़ से अधिक	₹30,000

UNEP की सीमित ओवरशूट रिपोर्ट 2026

संदर्भ: UNEP की 2026 की सीमित ओवरशूट रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि का 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार करना अब लगभग अपरिहार्य है, और यह ओवरशूट के आकार तथा अवधि को न्यूनतम रखने तथा फिर तापमान को 1.5 डिग्री से नीचे लाने का आग्रह करती है।

□ मुख्य बिंदु

- वर्तमान नीतियों से 2100 तक लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि का संकेत मिलता है।
- यदि सभी NDC और नेट-ज़ीरो लक्ष्य पूरे हो जाएँ, तो तापमान वृद्धि लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस पर चरम पर पहुँचेगी।
- ओवरशूट, चरम और गिरावट के मार्ग के लिए अभी उत्सर्जन में भारी कटौती, चरम पर नेट-ज़ीरो CO2 और उसके बाद नेट-नेगेटिव CO2 की आवश्यकता है।
- मीथेन वर्तमान तापमान वृद्धि में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस का योगदान देती है।
- 159 देश मीथेन को 2030 तक 2020 के स्तर से 30% घटाने के लिए वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और ओडिशा का ओरांगउटान

संदर्भ: पर्यावरण मंत्रालय ने ओडिशा के बालासोर में एक ओरांगउटान के रहस्यमय ढंग से मिलने के पीछे अंतरराष्ट्रीय संगठित वन्यजीव अपराध की संभावित कड़ी की जाँच के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की चार सदस्यीय टीम गठित की।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह MoEFCC के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38Y के अंतर्गत की गई और यह 2008 से कार्यरत है। इसमें पुलिस, वन, सीमा शुल्क और खुफ़िया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में हैं।
- यह CITES के अंतर्गत भारत के दायित्वों को लागू करता है और INTERPOL तथा विश्व सीमा शुल्क संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है।

□ **ओरांगउटान के तथ्य**

- मलय भाषा में ओरांगउटान का अर्थ है 'वन का मनुष्य'।
- इसकी तीन प्रजातियाँ हैं: बोर्नियन (लगभग 104,700), सुमात्राई (14,000 से कम) और तापनुली (800 से कम), जो सभी अत्यधिक संकटग्रस्त हैं।
- तापनुली सबसे अधिक संकटग्रस्त वानर (ग्रेट एप) है।

विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति रिपोर्ट

संदर्भ: सितंबर 2026 में ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति की 7वीं रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि प्रवाल विरंजन (ब्लीचिंग) अधिक बार हो रहा है, जिससे भित्तियों को उबरने का बहुत कम समय मिल रहा है। 1980 से 2024 के बीच देखे गए 36,886 भित्ति स्थलों पर आधारित इस रिपोर्ट में पाया गया कि वैश्विक कठोर प्रवाल आवरण 1980-2009 के आधार स्तर से लगभग 9.5% घटा है और 2023-25 की विरंजन घटना सबसे तेज़ और सबसे व्यापक रही।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रवाल ज़ूज़ैन्थेली शैवाल के साथ सहजीवन में रहते हैं, जो उन्हें भोजन और रंग देते हैं। ताप-तनाव से प्रवाल शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे विरंजन होता है और लंबे समय तक रहने पर उनकी मृत्यु हो जाती है।
- रिपोर्ट 1980 से 2024 के बीच देखे गए 36,886 भित्ति स्थलों के आँकड़ों पर आधारित है।
- वैश्विक कठोर प्रवाल आवरण 1980-2009 के आधार स्तर से लगभग 9.5% घटा है और 2023-24 में इसमें 8.9% की गिरावट आई।
- 2010 के बाद से बड़ी विरंजन घटनाएँ लगभग दशक में एक बार होने के बजाय हर 4-6 वर्ष में दोहराई जा रही हैं।
- 2024 में 87% भित्तियों को अभूतपूर्व ताप-तनाव का सामना करना पड़ा।
- 1998 से अब तक चार वैश्विक विरंजन घटनाएँ हो चुकी हैं, और 2023-25 की घटना सबसे तेज़ और सबसे व्यापक रही।
- 2024 में कैरेबियाई कठोर प्रवाल आवरण औसतन केवल 7.1% रहा, और ROPME सागर क्षेत्र ने 2020-24 में अपने कठोर प्रवाल आवरण का लगभग 50% खो दिया।

IBCA: सऊदी अरब, घाना और बांग्लादेश शामिल हुए

संदर्भ: सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के 2026 के दौरान तीन नए सदस्यों के जुड़ने के बाद अब 29 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब मई 2026 में, बांग्लादेश जून 2026 में और घाना अक्टूबर 2026 में शामिल हुआ। प्रश्न गठबंधन के उद्देश्य, उसके भारत से संबंध और उसके नवीनतम सदस्यों के बारे में पूछे जा सकते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- IBCA सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया गठबंधन है।
- सऊदी अरब 22 मई 2026 को शामिल हुआ।
- बांग्लादेश जून 2026 में शामिल हुआ।
- घाना 7 अक्टूबर 2026 को शामिल हुआ।
- कुल सदस्यता 29 देशों की है।

पर्यावरण पहलें: वनजीवी दीदी और हरित दिवाली

संदर्भ: 2026 में समुदाय-आधारित संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। पलामू टाइगर रिज़र्व के दक्षिणी प्रभाग ने फरवरी 2026 में वनजीवी दीदी की शुरुआत की, जिसमें 17 गाँवों की शिक्षित महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह के साथ राजदूत के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि WWF-इंडिया के EIACP संसाधन भागीदार ने अक्टूबर 2026 में पर्यावरण मंत्रालय के साथ देशव्यापी हरित दिवाली अभियान शुरू किया। वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह को अगस्त 2026 में ISO 50001:2018 प्रमाणन भी मिला।

□ **पलामू टाइगर रिज़र्व**

- दक्षिणी प्रभाग ने फरवरी 2026 में वनजीवी दीदी की शुरुआत की, जिसमें 17 गाँवों की शिक्षित महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह के प्रोत्साहन के साथ PTR के राजदूत के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

□ **हरित दिवाली अभियान**

- WWF-इंडिया के EIACP संसाधन भागीदार ने पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर 20 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक देशव्यापी अभियान चलाया।

□ **बंदरगाह**

- वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (तूतीकोरिन) अगस्त 2026 में ISO 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना।

भूगोल

समसामयिक नोट्स

जलमार्ग और बंदरगाह: वाराणसी, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और कामराजर में पहली उपलब्धियाँ

संदर्भ: नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाह से जुड़ी कई उपलब्धियाँ दर्ज की गईं, जो स्थान-आधारित प्रश्नों के लिए उपयोगी हैं। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत दिसंबर 2025 में वाराणसी में वाणिज्यिक संचालन में आया, गेटवे ऑफ गुवाहाटी तैरता टर्मिनल नवंबर 2025 में ब्रह्मपुत्र पर खोला गया, और कामराजर बंदरगाह जुलाई 2026 में 18 मीटर ड्राफ्ट वाला दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना।

□ अंतर्देशीय जलमार्ग

- वाराणसी (नमो घाट): भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2025 में शुरू हुआ।
- गुवाहाटी: ब्रह्मपुत्र पर गेटवे ऑफ गुवाहाटी तैरता टर्मिनल और जेटी नवंबर 2025 में खोली गई; लागत ₹304.95 करोड़; असम अंतर्देशीय जल परिवहन विकास सोसाइटी द्वारा निर्मित।
- डिब्रूगढ़ (असम): स्वतंत्रता के बाद किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली माल-परिवहन यात्रा अक्टूबर 2026 में यहीं से रवाना हुई।

□ बंदरगाह

- कामराजर बंदरगाह (तमिलनाडु) विशाखापत्तनम के बाद 18 मीटर ड्राफ्ट उपलब्ध कराने वाला दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना (जुलाई 2026); यह 1.70 लाख DWT तक के जहाज़ों को संभाल सकता है।
- कांडला (दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात): भारत के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला सितंबर 2026 में असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (नामरूप) के साथ संयुक्त रूप से रखी गई।
- दादरी (उत्तर प्रदेश): भारत में निर्मित पहला निर्यात-आयात कंटेनर जुलाई 2026 में मेर्स्क-कॉनकॉर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में प्रस्तुत किया गया।

□ समुद्री संसाधन

- अंडमान सागर: भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन परियोजना जनवरी 2026 में शुरू की गई।

शक्सगाम घाटी और डिएगो गार्सिया

संदर्भ: भारत ने शक्सगाम घाटी में चीनी अवसंरचना परियोजनाओं पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया, और यूनाइटेड किंगडम द्वारा चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को लौटाने पर सहमत होने के बाद रणनीतिक डिएगो गार्सिया आधार के भविष्य पर चर्चा होने लगी।

□ मुख्य बिंदु

- शक्सगाम घाटी लद्दाख में काराकोरम जलविभाजक के उत्तर में स्थित है और भारत का अभिन्न अंग है। यह 1947 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में थी, और पाकिस्तान ने 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत इसे चीन को सौंप दिया।
- इसे ट्रांस-काराकोरम क्षेत्र भी कहा जाता है और यह शक्सगाम नदी के दोनों ओर स्थित है।
- यह उत्तर में कुनलुन पर्वतों और दक्षिण में काराकोरम पर्वतमाला से घिरी है, और सियाचिन ग्लेशियर के बहुत निकट स्थित है।
- डिएगो गार्सिया मध्य हिंद महासागर में एक प्रवाल एटॉल है और चागोस द्वीपसमूह का हिस्सा है।
- चागोस द्वीप 1965 से ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र के रूप में यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में थे।
- मई 2025 में यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस इस बात पर सहमत हुए कि संपूर्ण द्वीपसमूह पर संप्रभुता मॉरीशस के पास होगी, जबकि यूनाइटेड किंगडम डिएगो गार्सिया को 99 वर्ष के पट्टे पर अपने पास रखेगा।
- डिएगो गार्सिया में एक संयुक्त ब्रिटेन-अमेरिका सैन्य अड्डा है, जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंताएँ जताईं।

ग्रेट निकोबार मेगा अवसंरचना परियोजना

संदर्भ: फरवरी 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ग्रेट निकोबार मेगा अवसंरचना परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखा, और इसके रणनीतिक महत्व तथा ICRZ एवं CRZ मानदंडों के अनुपालन का हवाला दिया। अंडमान और निकोबार समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप पर स्थित इस परियोजना में ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, रक्षा केंद्र, टाउनशिप, विद्युत संयंत्र और दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा बनाने की योजना है, और यह मलक्का जलडमरूमध्य की ओर स्थित है। चिंताएँ शोम्पेन और निकोबार मेगापोड पर केंद्रित हैं।

□ मुख्य बिंदु

- यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप में है, जो अंडमान और निकोबार समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
- इसमें ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, रक्षा केंद्र, टाउनशिप, 450 MVA गैस और सौर विद्युत संयंत्र तथा दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा बनाने की योजना है।
- लगभग 130 वर्ग किमी उष्णकटिबंधीय वर्षावन को परिवर्तित किया जाना है, जिसमें लगभग दस लाख पेड़ काटे जाएँगे।

- चिंताओं में शोम्पेन, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, और निकोबार मेगापोड पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।
- यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य की ओर स्थित है, और भारत का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों पर संभाला जाता है।

थ्वाइट्स ग्लेशियर: प्रलय का ग्लेशियर

संदर्भ: पश्चिमी अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे प्रलय का ग्लेशियर (डूम्सडे ग्लेशियर) कहा जाता है, फरवरी 2026 में चर्चा में रहा क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह अभूतपूर्व दर से पिघल रहा है, जिससे पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर को खतरा है। यह वार्षिक वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि में लगभग 4 प्रतिशत योगदान देता है, और इसके ढहने से पूरी बर्फ की चादर के माध्यम से 3 मीटर से अधिक की वृद्धि हो सकती है। यह समुद्र-तल से नीचे स्थित आधार-चट्टान पर टिका है, जिससे समुद्री बर्फ चादर अस्थिरता संभव होती है।

□ मुख्य बिंदु

- यह वार्षिक वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि में लगभग 4 प्रतिशत योगदान देता है।
- इसके पूरी तरह पिघलने से समुद्र का स्तर लगभग 65 सेमी बढ़ेगा, और इसके ढहने से पूरी बर्फ की चादर के माध्यम से 3 मीटर से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
- यह समुद्र-तल से नीचे, भीतरी भाग की ओर ढलान वाली आधार-चट्टान पर टिका है, जिससे समुद्री बर्फ चादर अस्थिरता संभव होती है।
- ज्वार द्वारा ग्राउंडिंग रेखा के नीचे धकेला गया गर्म समुद्री जल तीव्र आधारीय पिघलन का कारण बनता है।
- विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है।
- भारत का भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 उसके स्टेशनों भारती और मैत्री को नियंत्रित करता है।

प्रौद्योगिकी और उद्योग में पहली उपलब्धियाँ: चिप, बैटरी और AI सुविधाएँ

संदर्भ: 2025-26 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रौद्योगिकी अवसंरचना संबंधी घोषणाएँ स्थान-वार सूचीबद्ध हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसी पहली उपलब्धियों के बारे में अक्सर 'कहाँ' पूछा जाता है। गुरुग्राम को मार्च 2026 में देश का पहला LPG ATM मिला, अप्रैल 2026 में भुवनेश्वर में भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी गई, और केरल ने मई 2026 में स्वतंत्र AI विभाग बनाया, जो ऐसा करने वाला पहला राज्य है।

□ मुख्य बिंदु

- गुरुग्राम: BPCL द्वारा देश का पहला LPG ATM (गैस वेंडिंग मशीन), मार्च 2026।
- विशाखापत्तनम स्टेशन: रेलवे द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोट 'ASC ARJUN' की शुरुआत, जनवरी 2026।
- पारनूर टोल प्लाज़ा (तांबरम-तिंडिवनम): तमिलनाडु की पहली बहु-लेन मुक्त प्रवाह टोल प्रणाली, अक्टूबर 2026।
- महाराष्ट्र: समर्पित रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) क्लिनिक खोलने वाला पहला राज्य (जनवरी 2026)।

□ अर्धचालक (सेमीकंडक्टर)

- भुवनेश्वर (इन्फो वैली): भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला अप्रैल 2026 में रखी गई।
- जेवर, ग्रेटर नोएडा: प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2026 में YEIDA क्षेत्र में HCL-फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखी।
- साणंद (गुजरात): CG सेमी की OSAT (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) सुविधा का उद्घाटन जुलाई 2026 में हुआ।

□ ऊर्जा भंडारण और कार्बन अवशोषण

- NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा: भारत की पहली मेगावाट-घंटा (MWh) स्तर की वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (3 MWh) का उद्घाटन नवंबर 2025 में हुआ।
- भोपाल (स्वामी विवेकानंद पार्क): कार्बन अवशोषण के लिए भारत का पहला 'एल्गी ट्री' मई 2026 में स्थापित किया गया।

□ AI और डिजिटल

- तिरुवनंतपुरम: MeitY का इंडियाAI AI उत्कृष्टता केंद्र सितंबर 2026 में उद्घाटित हुआ।
- केरल ने मई 2026 में स्वतंत्र AI विभाग बनाया, जो ऐसा करने वाला पहला राज्य है।
- गुवाहाटी: पहली AI-संचालित 'फिजिटल' बैंक शाखा (स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक) मई 2026 में खुली।
- इंडोनेशिया: जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास ने सांस्कृतिक, यात्रा और वाणिज्य-दूतावासीय जानकारी के लिए 'देवी' नामक AI अवतार शुरू किया।

भारत की अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली

संदर्भ: फरवरी 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विजयनगर, स्वराज द्वीप पर अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करके भारत की सुनामी निगरानी को उन्नत करने की दिशा में कदम उठाया, जिसमें INCOIS हैदराबाद नोडल एजेंसी है। INCOIS हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता है।

□ मुख्य बिंदु

- विजयनगर, स्वराज द्वीप पर अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र।
- कमजोर सतही बॉय की जगह लेने के लिए अंडमान-सुमात्रा अधोगमन क्षेत्र के साथ 270 किमी की समुद्र-नीचे केबल।
- पनडुब्बी भूस्खलन, बैरन द्वीप पर ज्वालामुखीय गतिविधि और ध्वनिक संकेतों जैसे गैर-भूकंपीय स्रोतों का पता लगाना।

➤ UNESCO-IOC मानकों का अनुपालन।

➤ बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।

□ **INCOIS की सेवाएँ**

➤ INCOIS की स्थापना 1999 में MoES के अंतर्गत हुई थी और यह हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता है।

➤ नई सेवाएँ जेलीफ़िश के झुंड के लिए JellyAIIP, SAMUDRA 2.0 मोबाइल ऐप और स्वेल सर्ज बाढ़ के लिए SIVAS हैं।

➤ SIVAS केरल तट पर कल्लक्कडल को कवर करता है और इसका पूर्व-चेतावनी समय 3 दिन है।

➤ INCOIS ने फरवरी 2026 में ISRO के स्पेस एप्लिकेशन्स सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

समाचारों में स्थान: राष्ट्रीय स्थल

संदर्भ: फरवरी 2026 में समाचारों में रहे भारतीय स्थलों का एक समूह, जम्मू और कश्मीर की जलविद्युत परियोजनाओं से लेकर बाघ अभयारण्यों और आर्द्रभूमियों तक। भारत ने रामबन में चिनाब पर 1,856 मेगावाट की सावलकोट परियोजना पर कार्य शुरू किया, जो सिंधु जल संधि को स्थगित रखे जाने के बाद स्वीकृत पहली नई परियोजना है, और जम्मू-कश्मीर तुलबुल नौवहन परियोजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत ने रामबन में चिनाब पर 1,856 मेगावाट की सावलकोट परियोजना पर कार्य शुरू किया, जो सिंधु जल संधि को स्थगित रखे जाने के बाद स्वीकृत पहली नई परियोजना है।

➤ जम्मू-कश्मीर तुलबुल नौवहन परियोजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे वूलर बैराज भी कहा जाता है; यह 1984 में शुरू हुई थी और पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद रोक दी गई थी।

➤ तुलबुल का उद्देश्य झेलम में एक समान प्रवाह बनाए रखने के लिए वूलर झील में 30,000 एकड़-फुट पानी का भंडारण करना था।

➤ मन्नार की खाड़ी में वान द्वीप की 10 वर्षीय कृत्रिम भित्ति (रीफ) पुनर्स्थापना से ₹61.67 करोड़ के लाभ प्राप्त हुए; मन्नार की खाड़ी को 1989 में समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।

समाचारों में राष्ट्रीय स्थान

स्थान	मुख्य तथ्य
सावलकोट जलविद्युत परियोजना	चिनाब, रामबन (जम्मू-कश्मीर); रन-ऑफ-द-रिवर; 1,856 मेगावाट
तुलबुल परियोजना	वूलर झील पर झेलम; कार्य 1984 में शुरू
त्सोमगो झील	पूर्वी सिक्किम; हिमनद झील; 2,700 से अधिक पर्यटकों को बचाया गया
मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य	निचली दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश; मेहाओ झील के नाम पर
पलामू बाघ अभयारण्य	झारखंड; प्रोजेक्ट टाइगर के पहले 9 अभयारण्यों में से एक (1973); वनजीवी दीदी पहल
पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान	गोदावरी, आंध्र प्रदेश; ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत बाघ का पुनर्वास
पाखल वन्यजीव अभयारण्य	वारंगल, तेलंगाना; नई प्रजाति डिक्लिप्टेरा पाखलिका
भद्रा बाघ अभयारण्य	कर्नाटक; 25वाँ प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य (1998)
कोले आर्द्रभूमि	केरल; 2002 से रामसर स्थल; पिग्मी टिड्डे की 12 प्रजातियाँ
वान द्वीप	मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु; 10,600 रीफ मॉड्यूल

समाचारों में खाड़ी स्थल और जलडमरूमध्य

संदर्भ: मार्च 2026 में पश्चिम एशिया संघर्ष ने खाड़ी के ऊर्जा केंद्रों और अवरोध बिंदुओं (चोकपॉइंट) को सुर्खियों में ला दिया। कतर का रास लफ़ान विश्व का सबसे बड़ा LNG निर्यात केंद्र है, जिसकी वैश्विक LNG आपूर्ति में लगभग 20% हिस्सेदारी है, साउथ पार्स विश्व का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है, और फुजैराह होर्मुज़ के बाहर स्थित है। होर्मुज़, बाब अल-मंदेब और मलक्का जैसे जलडमरूमध्य तथा डिएगो गार्सिया प्रारंभिक परीक्षा के मानक मानचित्र-आधारित विषय हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ कतर का रास लफ़ान विश्व का सबसे बड़ा LNG निर्यात केंद्र है, जिसकी वैश्विक LNG आपूर्ति में लगभग 20% हिस्सेदारी है।

➤ साउथ पार्स विश्व का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है, जो कतर के नॉर्थ फील्ड के साथ साझा है।

➤ होर्मुज़ के बाहर स्थित फुजैराह हबशान-फुजैराह पाइपलाइन से जुड़ा है।

➤ डिएगो गार्सिया चागोस द्वीपसमूह में एक अमेरिका-ब्रिटेन अड्डा है; यूनाइटेड किंगडम ने मई 2025 में संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित की और अड्डे को 99 वर्षों के लिए वापस पट्टे पर ले लिया।

समाचारों में जलडमरूमध्य

जलडमरूमध्य	जोड़ता है	टिप्पणी
होर्मुज़	फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी	वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20%
बाब अल-मंदेब	लाल सागर और अदन की खाड़ी	स्वेज नहर की ओर जाता है
मलक्का	हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर	सबसे व्यस्त नौवहन मार्ग
पाक जलडमरूमध्य	बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी	भारत और श्रीलंका
केर्च	काला सागर और आज़ोव सागर	केर्च पुल
डार्डेनेल्स	एजियन सागर और मरमरा सागर	मोंट्रो अभिसमय, 1936

समाचारों में राष्ट्रीय स्थान

संदर्भ: मार्च 2026 में समाचारों में रहे भारतीय स्थलों का एक समूह। चीन के साथ लिपुलेख दर्रे से व्यापार जून 2026 में फिर शुरू होने वाला है, साउथ ल्होनक GLOF से हुई क्षति के बाद गुरुडोंगमार झील पर पर्यटन पुनर्जीवित हो रहा है, और वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत में चीतों का तीसरा घर बनने वाला है। यूनेस्को ने अघनाशिनी रामसर मुहाने के निकट नदी-जोड़ो परियोजना को विश्व धरोहर मानदंडों के अनुरूप रखने की भी सलाह दी।

□ मुख्य बिंदु

- चीन के साथ लिपुलेख दर्रे से व्यापार जून 2026 में फिर शुरू होने वाला है।
- साउथ ल्होनक GLOF से हुई क्षति के बाद गुरुडोंगमार झील पर पर्यटन पुनर्जीवित हो रहा है।
- वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत में चीतों का तीसरा घर बनने वाला है।
- अघनाशिनी मुहाना एक रामसर स्थल है; यूनेस्को ने सलाह दी कि नदी-जोड़ो परियोजना विश्व धरोहर मानदंडों के अनुरूप हो।

समाचारों में स्थान

स्थान	स्थान	मुख्य तथ्य
लिपुलेख दर्रा	पिथौरागढ़, उत्तराखंड	भारत-नेपाल-चीन त्रिसंधि, लगभग 5,334 मीटर
गुरुडोंगमार झील	उत्तरी सिक्किम	लगभग 5,430 मीटर, तीस्ता बेसिन
बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य	सोनितपुर, असम	लाओखोवा-बुराचापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा
वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य	सागर, दमोह, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश	नौरादेही तथा दुर्गावती अभयारण्य
कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य	आंध्र प्रदेश	मैंग्रोव, ओलिव रिडले कछुओं का घोंसला स्थल
कोलेरू झील	आंध्र प्रदेश	अभयारण्य 1999, रामसर 2002
मुंद्रा बंदरगाह	कच्छ की खाड़ी, गुजरात	अदाणी पोर्ट्स द्वारा संचालित

समाचारों में स्थान: होकरसर, पचपदरा, लोअर लेक और अन्य

संदर्भ: अप्रैल 2026 में समाचारों में रहे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्थलों का एक समूह, जिनके मुख्य तथ्य मानचित्र-आधारित प्रश्नों के लिए उपयोगी हैं। इनमें राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी, जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोरसायन परिसर है, भोपाल की लोअर लेक (भोज आर्द्रभूमि रामसर स्थल का हिस्सा), किर्गिस्तान की इस्सिक-कुल झील और दक्षिण चीन सागर का स्कारबोरो शोल शामिल हैं।

□ मुख्य बिंदु

- राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोरसायन परिसर है, जिसे HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड विकसित कर रही है।
- भोपाल की लोअर लेक (छोटा तालाब) अपर लेक के साथ भोज आर्द्रभूमि रामसर स्थल का हिस्सा है और पातरा नाले तथा हलाली नदी के माध्यम से बेतवा में प्रवाहित होती है।
- बिहार के मधुबनी में स्थित बलिराजगढ़, जो प्राचीन विदेह साम्राज्य से जुड़ा है, ASI के उत्खनन के अधीन है और इसे 1938 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था।
- असम के कोकराझार में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत-भूटान सीमा पर स्थित है; गोल्डन लंगूर बोडोलैंड का शुभंकर है।
- शिलांग के निकट उमियम झील 1965 में उमियम उमत्रू जलविद्युत परियोजना के अंतर्गत बनाई गई थी, जो पूर्वोत्तर भारत की पहली जलविद्युत परियोजना है।
- उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान गंगा का स्रोत क्षेत्र और हिम तेंदुए का आवास है।
- किर्गिस्तान की इस्सिक-कुल झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च-तुंगता वाली झील और एक रामसर स्थल है।
- दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल पर चीन और फिलीपींस दावा करते हैं और 2012 से यह चीन के नियंत्रण में है।

समाचारों में चयनित स्थान

स्थान	स्थान	मुख्य बिंदु
पचपदरा रिफाइनरी	बालोतरा, राजस्थान	पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोरसायन परिसर
लोअर लेक	भोपाल, मध्य प्रदेश	भोज आर्द्रभूमि रामसर स्थल का हिस्सा
बलिराजगढ़	मधुबनी, बिहार	प्राचीन विदेह प्रशासनिक केंद्र
रायमोना राष्ट्रीय उद्यान	कोकराझार, असम	गोल्डन लंगूर; भूटान के साथ सीमापारीय
उमियम झील	शिलांग के निकट, मेघालय	1965 में निर्मित; पूर्वोत्तर की पहली जलविद्युत परियोजना
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	उत्तरकाशी, उत्तराखंड	गंगा का स्रोत क्षेत्र
इस्सिक-कुल झील	किर्गिस्तान	दूसरी सबसे बड़ी उच्च-तुंगता वाली झील
स्कारबोरो शोल	दक्षिण चीन सागर	चीन और फिलीपींस के बीच विवादित

किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध और चिनाब परियोजनाएँ

संदर्भ: छह राज्यों में सहमति बन गई है और वे यमुना के पुनरुद्धार के लिए लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए हैं। अलग से,

चिनाब पर कीरथाई-II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी मिली, जो सिंधु जल संधि को स्थगित रखे जाने के बाद तीसरी मंजूरी है।

□ **किशाऊ बाँध**

➤ छह राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान हैं।

➤ यह उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित है।

➤ यह 236 मीटर ऊँचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट गुरुत्व बाँध है, जिसकी क्षमता 660 मेगावाट और वार्षिक उत्पादन लगभग 1,379 मिलियन यूनिट है।

➤ पेयजल, औद्योगिक और सिंचाई उपयोग के लिए जीवंत भंडारण लगभग 1,324 मिलियन घन मीटर होगा।

➤ यह निचले प्रवाह की विद्युत परियोजनाओं में लगभग 472 MU जोड़ेगा और बाढ़ नियंत्रण में सहायता करेगा।

□ **वित्तपोषण व्यवस्था**

➤ केंद्र जल घटक की लागत का 90% केंद्रीय सहायता के रूप में देगा; शेष 10% छह राज्य साझा करेंगे।

➤ हिमाचल प्रदेश अपना जल हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को देगा, इसके बदले वे उसके विद्युत घटक की लागत साझा करेंगे।

□ **चिनाब परियोजनाएँ**

➤ कीरथाई-II एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है; सावलकोट और दुलहस्ती-II चिनाब की अन्य दो स्वीकृत परियोजनाएँ हैं।

मानसून में विराम और सुपर अल नीनो की आशंकाएँ

संदर्भ: जल्दी आगमन के पूर्वानुमानों के बाद, पाँच प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मानसून लंबे समय तक रुका रहा। बाद में यह अधिक शक्तिशाली सोमाली जेट और बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के साथ फिर सक्रिय हुआ, हालाँकि अल नीनो के कारण कमी की आशंका है।

□ **पाँच कारक**

➤ अल नीनो भूमध्यरेखीय प्रशांत में विकसित हुआ और वॉकर परिसंचरण को कमजोर करता है।

➤ मैडेन-जूलियन दोलन कमजोर था या हिंद महासागर से दूर था।

➤ पश्चिम एशिया से आई शुष्क पश्चिमी हवाएँ उत्तर-पश्चिम भारत में घुस आईं, जिससे लू चली।

➤ सोमाली जेट, जो अरब सागर के ऊपर निम्न स्तर की अंतर-भूमध्यरेखीय जेट धारा है, कमजोर था।

➤ हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) तटस्थ रहा; धनात्मक IOD सामान्यतः अल नीनो के प्रभाव को संतुलित करता है।

□ **पुनर्प्राप्ति**

➤ मानसूनी हवाएँ अधिक शक्तिशाली सोमाली जेट और बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब प्रणाली के साथ फिर सक्रिय हुईं।

➤ सुपर अल नीनो की आशंका के कारण अभी भी कमी का पूर्वानुमान है।

वेनेज़ुएला भूकंपीय युग्म (डबलेट)

संदर्भ: जून 2026 में पश्चिमी वेनेज़ुएला में काराकास से लगभग 160 किमी पश्चिम में यूमारे के निकट 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए, जो एक भूकंपीय युग्म (डबलेट) था। डबलेट समान तीव्रता के वे भूकंप होते हैं जो अलग-अलग किंतु संबंधित भंगों से तेजी से एक के बाद एक आते हैं, जहाँ पहला भंग पास के भ्रंश खंड पर तनाव स्थानांतरित करता है। वेनेज़ुएला कैरिबियन-दक्षिण अमेरिकी प्लेट सीमा पर स्थित है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ डबलेट समान तीव्रता के वे भूकंप होते हैं जो अलग-अलग किंतु संबंधित भंगों से तेजी से एक के बाद एक आते हैं।

➤ पहला भंग पास के भ्रंश खंड पर तनाव स्थानांतरित करता है और दूसरे को प्रेरित करता है।

➤ वेनेज़ुएला कैरिबियन-दक्षिण अमेरिकी प्लेट सीमा पर स्थित है, जहाँ बोकोनो और सैन सेबेस्टियन जैसी नतिलंब-सर्पण (स्ट्राइक-स्लिप) प्रणालियाँ हैं।

➤ प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में प्रशांत अग्निवलय, अल्पाइड पट्टी, पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी और सैन एंड्रियास भ्रंश शामिल हैं।

कृषि, निर्यात और स्वास्थ्य में स्थान-वार पहली उपलब्धियाँ

संदर्भ: 2025 के अंत से 2026 तक की राज्य-विशिष्ट कृषि और कल्याण संबंधी उपलब्धियाँ परीक्षा के लिए स्थान-वार सूचीबद्ध हैं। मिज़ोरम को दिसंबर 2025 में 'भारत की अदरक राजधानी' नाम दिया गया, असम जुलाई 2026 में वाणिज्यिक रूप से माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना, और पश्चिम बंगाल जून 2026 में आयुष्मान भारत PM-JAY लागू करने वाला 36वाँ राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बना। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे भी जुलाई 2026 में खुला।

□ **कृषि और निर्यात**

➤ मिज़ोरम को 'भारत की अदरक राजधानी' नाम दिया गया (दिसंबर 2025)।

➤ असम चोटा तिंगराई एस्टेट, तिनसुकिया में वाणिज्यिक रूप से माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना (जुलाई 2026)।

➤ पूर्णिया (बिहार): 1 मीट्रिक टन मखाना की पहली खेप ग्रीस को निर्यात की गई।

➤ दरभंगा (बिहार): मूल्य-वर्धित मखाने की पहली समुद्री खेप कनाडा भेजी गई (जुलाई 2026)।

➤ जोरहाट: रौरिया स्थित CSB रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र में ग्रेनेज भवन और शीत भंडारण का उद्घाटन हुआ।

□ **मौसम और स्वास्थ्य**

➤ लखनऊ को भारत का 8वाँ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मिला (जून 2026); जम्मू को भी एक नया RMC मिला।

➤ पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत PM-JAY लागू करने वाला 36वाँ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना (जून 2026)।

➤ पटना: देश का पहला पीड़ित अधिकार केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में खोला गया (सितंबर 2026)।

➤ कर्नाटक ने 10 अगस्त 2026 से एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू/निकोटीन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया।

□ **अवसंरचना**

➤ लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (63 किमी, छह लेन) जुलाई 2026 में उन्नाव के झाऊ खेड़ा में खुला; यह स्वचालित मशीन-निर्देशित निर्माण से बना पहला एक्सप्रेसवे है।

➤ दमन: नमो हवाई अड्डे का संचालन दमन-दिल्ली उड़ान के साथ शुरू हुआ (जुलाई 2026)।

➤ कोलकाता: अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही संयंत्र का भूमि पूजन।

पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े चर्चित स्थान 2025-26

संदर्भ: 2025-26 में विभिन्न राज्यों से संरक्षित क्षेत्रों, प्रमाणनों और हरित रिकॉर्डों की सूचना मिली, जिन्हें स्थान-वार सूचीबद्ध किया गया है। ओंकारेश्वर अभयारण्य की घोषणा नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश के 27वें अभयारण्य के रूप में की गई, ओडिशा के सुनापुर और पुरी समुद्र तटों ने 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन बरकरार रखा, और अहमदाबाद ने जुलाई 2026 में एक घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज़ रिकॉर्ड बनाया। स्थान से जुड़े पर्यावरण संबंधी तथ्य अक्सर पूछे जाते हैं।

□ **संरक्षित क्षेत्र और प्रमाणन**

➤ ओंकारेश्वर अभयारण्य (मध्य प्रदेश) की घोषणा राज्य के 27वें अभयारण्य के रूप में की गई (नवंबर 2025)।

➤ ओडिशा के सुनापुर और पुरी समुद्र तटों ने 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन बरकरार रखा।

➤ मिज़ोरम विश्वविद्यालय (आइज़ोल) का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के अंतर्गत भारत का 21वाँ अभिहित भंडार (डेज़िग्नेटेड रिपॉज़िटरी) बना।

➤ थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य (महाराष्ट्र): भारत का पहला AI-संचालित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र प्रस्तावित है।

□ **जलवायु और हरित रिकॉर्ड**

➤ किलाई (कुड्डालोर) राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु का पहला पूर्णतः संचालित जलवायु-अनुकूल गाँव बना (जुलाई 2026)।

➤ अहमदाबाद ने मियावाकी पद्धति से एक घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज़ रिकॉर्ड बनाया (जुलाई 2026)।

➤ नई दिल्ली: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर अठारह नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया गया।

➤ वैज्ञानिकों ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21-23 किमी की ऊँचाई पर असामान्य रूप से उच्च ओज़ोन सांद्रता का पता लगाया (अगस्त 2026)।

□ **अपशिष्ट**

➤ शिवरी संयंत्र में तीसरी प्रसंस्करण इकाई खुलने के बाद लखनऊ नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना (जनवरी 2026)।

ब्रह्मपुत्र महाबाँध के नीचे पाइझेन भ्रंश

संदर्भ: जुलाई 2026 में एक अध्ययन में पाया गया कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के नीचे एक सक्रिय भ्रंश, पाइझेन भ्रंश, स्थित है और यह उसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यह भ्रंश पूर्वी हिमालय में भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर से बने विवर्तनिक भ्रंशों के एक जाल का हिस्सा है, और आदि प्लिस्टोसीन काल से सक्रिय है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह पूर्वी हिमालय में विवर्तनिक भ्रंशों के एक जाल का हिस्सा है। यह भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर से बना था।

➤ यह आदि प्लिस्टोसीन काल से सक्रिय है और होलोसीन में भी अत्यंत सक्रिय बना हुआ है।

विरासत और संस्कृति से जुड़े चर्चित स्थान: संग्रहालय, स्मारक और नाम परिवर्तन

संदर्भ: 2025-26 के दौरान संग्रहालयों, संरक्षित स्मारकों, मूर्तियों और स्थान-नाम परिवर्तनों की सूचना मिली, जिन्हें त्वरित पुनरावृत्ति के लिए स्थान-वार सूचीबद्ध किया गया है। भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय 'म्यूज़ियम ऑफ वर्ड' का पहला चरण जुलाई 2026 में कोलकाता में खुला, परिछा बैराज (झाँसी) को 2026 में ICID से विश्व धरोहर सिंचाई संरचना की मान्यता मिली, और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में जलालाबाद (शाहजहाँपुर) का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया।

□ **संग्रहालय और विरासत**

➤ कोलकाता (राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर हाउस): भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय 'म्यूज़ियम ऑफ वर्ड' का पहला चरण जुलाई 2026 में खुला।

- गांधीनगर (कोबा तीर्थ): सम्राट संप्रति संग्रहालय, एक जैन विरासत संग्रहालय, महावीर जयंती पर मार्च 2026 में खोला गया।
- मथुरा: पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में देश के पहले राष्ट्रीय 'गो संस्कृति' संग्रहालय की घोषणा की गई।
- इंदौर: कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहला आभासी (वर्चुअल) चिड़ियाघर।
- चाँदनी चौक, दिल्ली: ऐतिहासिक टाउन हॉल को ग्लोबल हेरिटेज सेंटर में बदलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए (सितंबर 2026)।
- लद्दाख: 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया (जुलाई 2026)।

□ **जल विरासत**

- परिछा बैराज (झाँसी, उत्तर प्रदेश), जो लगभग 140 वर्ष पुराना है, को 2026 में ICID से विश्व धरोहर सिंचाई संरचना (WHIS) की मान्यता मिली।

□ **मूर्तियाँ**

- गोवा (पर्तगाली मठ, गोकर्ण): प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में भगवान राम की 77 फुट ऊँची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।
- गांधीनगर: छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण फरवरी 2026 में किया गया।

□ **नाम परिवर्तन**

- पाकयोंग हवाई अड्डे (सिक्किम) का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा किया जाएगा (विधानसभा प्रस्ताव, मार्च 2026)।
- जलालाबाद (शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश) का नाम उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में बदलकर परशुरामपुरी कर दिया।
- अरुणाचल प्रदेश: 27 स्थानों/विशेषताओं को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों पर मानक आधिकारिक नाम दिए गए (अगस्त 2026)।

समाचारों में महत्वपूर्ण स्थान: मोंगला, सबांग, मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया

संदर्भ: जुलाई 2026 में अंतरराष्ट्रीय समाचारों में रहे कई स्थान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के बंदरगाहों से लेकर राष्ट्रपति द्वारा भ्रमण किए गए दो यूरोपीय देशों तक। चीन और बांग्लादेश ने मोंगला बंदरगाह के निकट आर्थिक क्षेत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, भारत और इंडोनेशिया सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमत हुए, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्राएँ कीं।

□ **बंदरगाह**

- मोंगला बंदरगाह चटगाँव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है, जो कोलकाता से 188 किमी दूर और सुंदरबन के निकट है; चीन और बांग्लादेश ने इसके निकट आर्थिक क्षेत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- सबांग बंदरगाह सुमात्रा के उत्तरी छोर पर मलक्का जलडमरूमध्य के निकट आचेह प्रांत में वेह द्वीप पर स्थित है; भारत और इंडोनेशिया इसे संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमत हुए।

□ **राष्ट्रपति की यात्राएँ**

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 1992 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद मोल्दोवा की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनीं। मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ है और यह यूक्रेन तथा रोमानिया से सीमा साझा करता है।
- उन्होंने उत्तरी मैसेडोनिया की भी किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा की, जिसकी राजधानी स्कोप्जे है और जो कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान और अल्बानिया से घिरा स्थलरुद्ध देश है।

समाचारों में स्थान: अंतरराष्ट्रीय

संदर्भ: जुलाई 2026 में समाचारों में रहे कई विदेशी स्थान, फ़ॉकलैंड द्वीप विवाद से लेकर मोल्दोवा और पनामा तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 1992 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद मोल्दोवा की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनीं। अन्य स्थानों में ओकिनोटोरी द्वीप, अरल सागर, मानसरोवर झील और प्रम्बानन मंदिर शामिल हैं, जो सभी मानचित्र-आधारित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्नों के लिए उपयोगी हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- फ़ॉकलैंड द्वीप: दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर से लगभग 480 किमी उत्तर-पूर्व में दक्षिण अटलांटिक का एक द्वीपसमूह, जिसमें दो मुख्य द्वीप और 776 छोटे द्वीप हैं; ब्रिटेन ने 1833 में नियंत्रण पुनः स्थापित किया, अर्जेंटीना ने 1982 में आक्रमण किया जिससे 74 दिन का युद्ध हुआ, और 2013 के जनमत संग्रह में ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र बने रहने के पक्ष में मत पड़ा।
- ओकिनोटोरी द्वीप: जापान का सबसे दक्षिणी क्षेत्र और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जापान का एकमात्र क्षेत्र; जापान 200 नॉटिकल मील के EEZ का दावा करता है जिसे चीन चुनौती देता है, क्योंकि उसका तर्क है कि UNCLOS के अनुसार ओकिनोटोरी एक चट्टान है।
- मोल्दोवा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 1992 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनीं; यह प्रुत और नीस्टर नदियों के बीच स्थित है और इसकी राजधानी चिसिनाउ है।
- अरल सागर: अमु दरिया और सिर दरिया से पोषित, यह 1980 के दशक तक अपने आयतन का लगभग 80 प्रतिशत खो चुका था; इसके सूखे तलों से 200 टेराग्राम से अधिक कार्बन उत्सर्जित हुआ है।
- मानसरोवर झील: तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट, खारे पानी की राक्षसताल झील से सटी हुई, और सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र तथा करनाली के स्रोतों के निकट स्थित है।
- प्रम्बानन मंदिर: इंडोनेशिया में योग्याकार्ता के निकट यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल (1991), जिसे 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश ने बनवाया था और जो शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा को समर्पित है।

समाचारों में स्थान: राष्ट्रीय

संदर्भ: जुलाई 2026 में भारत की कई आर्द्रभूमियाँ, अभयारण्य और नदियाँ चर्चा में रहीं। असम के बोरनदी वन्यजीव अभयारण्य में कैमरा ट्रैप में ढोल (जंगली कुत्ते) दर्ज हुए, सियोम नदी पर 1,000 मेगावाट की नेयिंग जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी मिली, और MoEFCC की एक समिति ने शेर-पूँछ वाले मकाक (लायन-टेल्ड मकाक) अभयारण्य पर प्रभाव को देखते हुए 2,000 मेगावाट की शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को अस्वीकार करने की सिफारिश की। मानसबल, कवल और पल्लीकरनई भी चर्चा में रहे।

□ **मुख्य बिंदु**

- गांदरबल (जम्मू और कश्मीर) की मानसबल झील लगभग 13 मीटर गहराई के साथ भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है और ड्रेजिंग तथा सीवेज उपचार के माध्यम से इसमें सुधार हुआ है।
- असम का बोरनदी वन्यजीव अभयारण्य, जो 1980 में पिग्मी हॉग और हिस्पिड हेयर (बालदार खरगोश) के लिए स्थापित हुआ था, में कैमरा ट्रैप में ढोल दर्ज हुए।
- अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग में स्थित सियोम (योमगो) नदी ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की सहायक नदी है; 1,000 मेगावाट की नेयिंग जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी मिली।
- खावथलांगतुइपुई कर्णफुली नदी का मिज़ो नाम है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच की एक सीमापारीय नदी है।
- तेलंगाना में गोदावरी पर स्थित कवल टाइगर रिज़र्व को NTCA ने बाघ पुनर्बहाली के लिए प्राथमिकता वाले प्राप्तकर्ता स्थल के रूप में चिह्नित किया।
- MoEFCC की एक समिति ने शरावती घाटी शेर-पूँछ वाले मकाक अभयारण्य पर प्रभाव को देखते हुए 2,000 मेगावाट की शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को अस्वीकार करने की सिफारिश की।
- चेन्नई के निकट पल्लीकरनई दलदली भूमि को 65 आर्द्रभूमियों से जल मिलता है और इसका जल ओक्कियम मडवु तथा कोवलम क्रीक के माध्यम से बाहर निकलता है।
- पश्चिम बंगाल ने महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को 5 किमी से घटाकर 1 किमी करने का निर्णय लिया।

स्लीमनाबाद सुरंग और नर्मदा नदी

संदर्भ: जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश की स्लीमनाबाद सुरंग, जो बरगी डायवर्जन परियोजना का हिस्सा है, के पूर्णता के निकट होने की सूचना मिली। यह भारत की सबसे लंबी भूमिगत जल-परिवहन सुरंग है और 197 किमी लंबी दायीं तट मुख्य नहर का हिस्सा है। यह नर्मदा का जल गुरुत्व बल से बरगी जलाशय से सूखा-प्रवण विंध्य क्षेत्र और सोन बेसिन तक पहुँचाएगी।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है, जिसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला है। यह मैकल पहाड़ियों में अमरकंटक से निकलती है और रिफ्ट घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है।
- सहायक नदियों में तवा, बंजर, दूधी, हिरन और कोलार शामिल हैं।

□ **स्लीमनाबाद सुरंग**

- यह बरगी डायवर्जन परियोजना की 197 किमी लंबी दायीं तट मुख्य नहर का हिस्सा है।
- यह नर्मदा का जल गुरुत्व बल से बरगी जलाशय से सूखा-प्रवण विंध्य क्षेत्र और सोन बेसिन तक पहुँचाएगी।

कोलंबिया भूकंप और ज़ांस्कर हिमनदों की धीमी गति

संदर्भ: अगस्त 2026 में पश्चिमी कोलंबिया में सैन होसे डेल पालमार के निकट 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए, और एक अध्ययन से पता चला कि लद्दाख के ज़ांस्कर हिमालय के हिमनद पतले होने के साथ धीमे पड़ रहे हैं। यह भूकंप 21वीं सदी में कोलंबिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसकी मध्यम गहराई लगभग 103 से 107 किमी थी, जबकि ज़ांस्कर अध्ययन में 1992 से 2023 तक के उपग्रह आँकड़ों का उपयोग करके 12 हिमनदों को शामिल किया गया।

□ **कोलंबिया भूकंप**

- अधिकेंद्र सैन होसे डेल पालमार के निकट था और 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
- गहराई लगभग 103 से 107 किमी थी, जो मध्यम गहराई है।
- यह 21वीं सदी में कोलंबिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप था; यह देश प्रशांत महासागर के अग्नि वलय (रिंग ऑफ फायर) में स्थित है।

□ **ज़ांस्कर हिमनद**

- द क्रायोस्फियर में प्रकाशित अध्ययन में 1992 से 2023 तक के उपग्रह आँकड़ों का उपयोग करके 12 हिमनदों को शामिल किया गया।
- ज़ांस्कर क्षेत्र लगभग 7,000 वर्ग किमी में फैला है और इसमें लगभग 1,755 हिमनद हैं।
- हिमनद का वेग प्रति दशक लगभग 2.43 मीटर प्रति वर्ष घटा।
- सतह का विरल होना 2000-2005 में 0.22 मीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 2015-2020 में 0.57 मीटर प्रति वर्ष हो गया।

चर्चित स्थान: अगस्त 2026

संदर्भ: अगस्त 2026 में कई भौगोलिक स्थान समाचारों में रहे, जिनमें शिपकी ला सीमा व्यापार का पुनः खुलना, तमिलनाडु में नदी को व्यक्तित्व का दर्जा और अंतरराष्ट्रीय हिमनद संबंधी घटनाएँ शामिल हैं। किन्नौर में शिपकी ला के रास्ते चीन के साथ सीमा व्यापार छह वर्ष बाद 1 अगस्त 2026 को फिर शुरू हुआ, मद्रास उच्च न्यायालय ने ताम्रपर्णी नदी को

कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया, और ग्रीनलैंड के पीटरमैन हिमनद से 76.4 वर्ग किमी का एक हिमखंड टूटकर अलग हुआ।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ ग्रीनलैंड के पीटरमैन हिमनद से 76.4 वर्ग किमी का एक हिमखंड टूटा, जो 2020 के बाद आर्कटिक की सबसे बड़ी हिमनद-विखंडन घटना है।

➤ माउंट अरारात तुर्किये की सबसे ऊँची चोटी है; कनलाओन फिलीपींस के नीग्रोस द्वीप पर स्थित है।

➤ पुतिन ने कुरील द्वीपसमूह के इतुरुप द्वीप की यात्रा की, जिस पर जापान अपने उत्तरी क्षेत्र के रूप में दावा करता है।

□ **राष्ट्रीय**

➤ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शिपकी ला के रास्ते चीन के साथ सीमा व्यापार छह वर्ष बाद 1 अगस्त 2026 को फिर शुरू हुआ; वहाँ व्यापार मुख्यतः वस्तु-विनिमय पर आधारित है।

➤ सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में लूनी की एकमात्र दाहिने तट की सहायक नदी जोजरी नदी के 100 मीटर के भीतर निर्माण पर रोक लगा दी।

➤ मद्रास उच्च न्यायालय ने ताम्रपर्णी नदी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया; यह पोथिगई पहाड़ियों में अगस्त्यकूडम से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है।

➤ केरल की पंपा नदी, जिसे दक्षिण भागीरथी कहा जाता है, से पथनमथिट्टा में बाढ़ आई; यह केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है।

➤ बकिंघम नहर का निर्माण 1806 में बेसिल कोक्रेन ने कराया था और 1878 में इसका नाम ड्यूक ऑफ बकिंघम एंड चांडोस के नाम पर रखा गया।

लांगटांग हिमनद का ध्वस्त होना और नेपाल की अचानक बाढ़ें

संदर्भ: नेपाल में अचानक आई बाढ़ को पहले 4.4 तीव्रता के भूकंप से जोड़ा गया, लेकिन विश्लेषण से पता चला कि भूकंपीय संकेत एक विशाल हिमनद और आधारशैल के ध्वस्त होने से आया था। भारत ने राहत सामग्री के साथ प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में सहायता की।

□ **घटना**

➤ यह ध्वसन नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट लांगटांग लिरुंग के उत्तरी ढलान पर हुआ।

➤ प्रवाह ल्हेंदे खोला में प्रवेश कर गया, जो भोटे कोशी और त्रिशूली नदी तंत्र से मिलती है।

➤ अचानक आई उच्च-ऊर्जा बाढ़ की लहर के कारण इसकी तुलना भूमि पर आई सुनामी से की गई।

□ **भारत की प्रतिक्रिया**

➤ भारत ने 68.5 टन से अधिक राहत सामग्री और विशेषज्ञ बचाव दल भेजे।

➤ भारत ने नेपाल द्वारा माँगे गए 42 बेली पुलों के लिए सहायता की पेशकश की।

राष्ट्रीय चर्चित स्थान: त्सो कर, बखिरा और अन्य

संदर्भ: सितंबर 2026 में भारत की कई झीलें, नदियाँ, अभयारण्य और किले चर्चा में रहे, जिनमें लद्दाख की एक झील के पुनरुद्धार की परियोजना और उत्तर प्रदेश की एक रामसर आर्द्रभूमि शामिल हैं। लद्दाख ने लगभग 32 करोड़ लीटर प्रतिदिन हिमनदीय जल मोड़कर त्सो कर झील के पुनरुद्धार की परियोजना शुरू की, जबकि बखिरा झील, जो राप्ती की एक चापाकार (ऑक्सबो) आर्द्रभूमि है, 2022 में घोषित रामसर स्थल है। देबरीगढ़ में भारतीय गौर की संख्या 2026 में बढ़कर 848 हो गई।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ लद्दाख ने रूप्शो खरनक धारा से लगभग 32 करोड़ लीटर प्रतिदिन हिमनदीय जल मोड़कर त्सो कर झील के पुनरुद्धार की परियोजना शुरू की।

➤ त्सो कर लद्दाख की तीन प्रमुख उच्च-तुंगता वाली झीलों में सबसे छोटी है, अन्य दो पैंगोंग त्सो और त्सो मोरीरी हैं; यह 2020 से रामसर स्थल है।

➤ उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की बखिरा झील राप्ती नदी की एक चापाकार (ऑक्सबो) आर्द्रभूमि है और 2022 में घोषित रामसर स्थल है।

➤ ओडिशा के बरगढ़ में देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय गौर की आबादी 2024 में 659 से बढ़कर 2026 में 848 हो गई।

➤ रंगीत नदी सिक्किम में माउंट काबरू के एक हिमनद से निकलती है और तीस्ता बाज़ार में तीस्ता से मिलती है।

➤ भीमा नदी भीमाशंकर की पहाड़ियों से निकलती है, रायचूर के निकट कृष्णा से मिलती है, और पंढरपुर में इसे चंद्रभागा कहा जाता है।

➤ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गूटी का किला, जिसे रावदुर्ग भी कहा जाता है, में 15 आपस में जुड़े किले हैं।

➤ कर्नाटक के चामराजनगर में बिलिगिरि रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिज़र्व को 2011 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।

➤ रामजक (6,318 मीटर) हिमाचल प्रदेश के लाहौल में एक चोटी है, जिस पर पहली बार 2002 में चढ़ाई की गई थी।

हिमनद और उत्तराखंड की GLOF पूर्व चेतावनी प्रणाली

संदर्भ: 2026 के एक नेचर अध्ययन ने गढ़वाल हिमालय के अलकनंदा बेसिन में 219 लटकते हिमनदों की पहचान की, जिससे हिम-स्खलन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) की चिंताएँ बढ़ गई हैं। उत्तराखंड

चमोली के वसुंधरा ताल में वास्तविक-समय GLOF निगरानी शुरू कर रहा है।

□ **मुख्य बिंदु**

- लटकते हिमनद खड़ी ढलानों और चट्टानों पर स्थित बर्फ़ के पिंड होते हैं, जो अक्सर संरचनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं।
- इनके टूटने से हिमस्खलन, नदी अवरोध, GLOF और बाढ़ आ सकती है, जो एक क्रमिक (कैस्केडिंग) खतरा है।
- NDMA ने उत्तराखंड में 13 उच्च-जोखिम वाली हिमनद झीलों की पहचान की है, जिनमें से 5 श्रेणी A की हैं।
- सेंसर जल स्तर, मौसम, बर्फ़ की गहराई, प्रवाह, कंपन और भूमि की गति पर नज़र रखेंगे।
- सौर ऊर्जा से चलने वाली यह प्रणाली उपग्रह के माध्यम से आँकड़े भेजती है, क्योंकि वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है।
- लाहौल-स्पीति की घेपन हिमनद झील, जिसे तीन लटकते हिमनदों से जल मिलता है, में भी GLOF जोखिम के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय चर्चित स्थान: कुरील द्वीपसमूह, लेबनान, कैलिफ़ोर्निया और अन्य

संदर्भ: जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच कई विदेशी स्थान समाचारों में रहे। पुतिन ने कुरील द्वीपसमूह की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की, लेबनान मृत्युदंड समाप्त करने वाला पहला अरब देश बना, और कैलिफ़ोर्निया ने विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की। न्यूयॉर्क, स्कोप्जे, बाकू और बिश्केक में भारत से जुड़ी घटनाएँ भी सुर्खियों में रहीं, जिससे यह स्थान और घटना की पुनरावृत्ति का समूह बन जाता है।

□ **राजनीति और कानून**

- कुरील द्वीपसमूह: रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहली आधिकारिक यात्रा की (अगस्त 2026); इन द्वीपों का प्रशासन रूस के पास है, लेकिन जापान इन पर दावा करता है।
- लेबनान: संसद ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया (अगस्त 2026), ऐसा करने वाला पहला अरब देश, और इसके स्थान पर कठोर श्रम सहित आजीवन कारावास का प्रावधान किया।
- कैलिफ़ोर्निया: असेंबली बिल 1267 के अनुसार 1 जनवरी 2027 से विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।

□ **भारत से जुड़ी घटनाएँ**

- न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त 2026 को 'भारत स्वतंत्रता दिवस' घोषित किया।
- स्कोप्जे: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गॉर्डाना सिल्यानोव्स्का-डावकोवा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया (जुलाई 2026)।
- बाकू: भारतीय दूतावास में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर स्थायी प्रदर्शनी खोली गई।
- बिश्केक: अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र 'मानस और महाभारत' का उद्घाटन हुआ (जुलाई 2026)।

समाचारों में लद्दाख: नए जिले, उच्च न्यायालय पीठ और सीमावर्ती गाँव

संदर्भ: लद्दाख में 2026 में प्रशासनिक और विकासात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला देखी गई, जिनमें नवीनतम अक्टूबर में हुई। सांकू केंद्रशासित प्रदेश का आठवाँ जिला बना, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ का उद्घाटन लेह में हुआ, और जीवंत गाँव कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मॉडल सीमावर्ती गाँव चुमुर में शुरू किया गया। ये परिवर्तन लद्दाख के प्रशासनिक मानचित्र को नया रूप देते हैं और स्थैतिक विषयों से जुड़े सामान्य प्रश्न हैं।

□ **प्रशासन**

- सांकू लद्दाख का आठवाँ जिला बना (अक्टूबर 2026); पाँच जिले (शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर, द्रास) अप्रैल 2026 में बनाए गए थे।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ का उद्घाटन लेह में हुआ (अक्टूबर 2026)।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2027-28 से लेह में लद्दाख के पहले मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी दी।

□ **सीमा और विकास**

- चुमुर: जीवंत गाँव कार्यक्रम के अंतर्गत पहले मॉडल सीमावर्ती गाँव की आधारशिला रखी गई (जून 2026)।
- रोंगटोंग (स्पीति, हिमाचल): काज़ा में राज्य की पहली बैटरी भंडारण वाली सौर परियोजना; केलांग: ICMR उच्च तुंगता चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखी गई (अक्टूबर 2026)।
- लद्दाख का पहला उच्च तुंगता स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र इस प्रयास का हिस्सा है।

□ **दिल्ली**

- जंतर मंतर को निर्दिष्ट विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचना-मुक्त कर दिया गया (अक्टूबर 2026); इसके स्थान पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD ग्राउंड शाहदरा को नामित किया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समसामयिक नोट्स

DRDO ने पूर्ण-स्तरीय स्क्रैमजेट इंजन का भू-परीक्षण किया

संदर्भ: DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने पूर्ण-स्तरीय, सक्रिय रूप से शीतलित, दीर्घ-अवधि स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक भू-परीक्षण किया, जो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

□ मुख्य बिंदु

- अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत स्क्रैमजेट इंजन उड़ान परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश है।
- स्क्रैमजेट एक सुपरसोनिक दहन रैमजेट है जो मैक 5 से ऊपर की हाइपरसोनिक गति पर कुशलता से कार्य करता है।
- रैमजेट एक वायु-श्वसन इंजन है जो बिना घूमने वाले कंप्रेसर के आने वाली वायु को संपीडित करने के लिए यान की अग्र गति का उपयोग करता है।
- यह सामान्यतः हाइड्रोजन को ईंधन और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करता है, और इसमें कोई गतिशील पुर्ज़ा नहीं होता।
- यह शून्य वायु-गति पर प्रणोद उत्पन्न नहीं कर सकता और कार्यकारी गति तक पहुँचने के लिए इसे रॉकेट या टर्बोजेट बूस्टर की आवश्यकता होती है।

□ हाइपरसोनिक हथियार

- ये मैक 5 से ऊपर की गति से चलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से नीचे उड़ते हैं और अत्यधिक गतिशील होते हैं, जिससे इनका पता लगाना कठिन होता है।
- हाइपरसोनिक ग्लाइड यान रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं और फिर ऊपरी वायुमंडल में ग्लाइड करते हैं।
- हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें स्व-चालित, सटीक-निर्देशित हथियार हैं जो नियंत्रित उड़ान बनाए रखती हैं।

PSLV-C62 विसंगति और भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल

संदर्भ: ISRO का PSLV-C62/EOS-N1 मिशन, जो PSLV की 64वीं उड़ान थी, तीसरे चरण में विसंगति का शिकार हुआ। अलग से, पिक्सेल के नेतृत्व वाले संघ ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल के लिए IN-SPACe के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

□ मुख्य बिंदु

- यह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा संचालित 9वाँ समर्पित वाणिज्यिक मिशन था, जिसकी स्थापना 2019 में ISRO की वाणिज्यिक शाखा के रूप में हुई थी।
- इसमें EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और 15 सह-यात्री उपग्रह थे।
- इसमें स्पेन के स्टार्ट-अप का पेलोड KID भी था, जो एक छोटा पुनः-प्रवेश प्रोटोटाइप है और दक्षिण प्रशांत में उतरने के लिए बनाया गया था।
- PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और तरल चरणों वाला भारत का पहला यान है; यह 600 किमी सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में 1,750 किग्रा तक ले जाता है।
- PSLV ने 2017 में एक मिशन में 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

भारत का रक्षा उद्योग: उत्पादन, निर्यात, सुधार

संदर्भ: रक्षा मंत्री ने जनवरी 2026 में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 में ₹46,425 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹1.51 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जिसमें रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान लगभग 77 प्रतिशत रहा; इसे iDEX, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों और दो रक्षा औद्योगिक गलियारों का समर्थन मिला।

□ मुख्य बिंदु

- घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 में ₹46,425 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹1.51 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
- रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का उत्पादन में योगदान लगभग 77 प्रतिशत है।
- भारत 100 से अधिक देशों को निर्यात करता है; 2023-24 में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख खरीदार थे।
- सैन्य-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण 2016 में ₹27 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹1,653 करोड़ हो गया।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे, जो 11 नोड्स में फैले हैं।
- आयात घटाने के लिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ।
- अप्रैल 2018 में शुरू की गई iDEX, MSME, स्टार्टअप और नवप्रवर्तकों को ₹1.5 करोड़ तक का अनुदान देकर सहायता करती है।

- 74 प्रतिशत तक FDI स्वचालित मार्ग से और 100 प्रतिशत तक सरकारी अनुमोदन से अनुमत है।
- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना आठ नई ग्रीनफील्ड परीक्षण सुविधाओं के लिए धन उपलब्ध कराती है, और प्रौद्योगिकी विकास कोष मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता को समर्थन देता है।

समाचारों में रक्षा प्रणालियाँ: प्रलय, LR-AShM, सूर्यास्त्र

संदर्भ: जनवरी 2026 में कई स्वदेशी रक्षा प्लेटफ़ॉर्म और परीक्षण चर्चा में रहे, जिनमें DRDO के प्रलय प्रक्षेपण और गणतंत्र दिवस परेड में हाइपरसोनिक जहाज-रोधी मिसाइल का प्रदर्शन शामिल हैं। DRDO ने ओडिशा तट से दो प्रलय अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइलें प्रक्षेपित कीं, जबकि लंबी दूरी की हाइपरसोनिक जहाज-रोधी मिसाइल (LR-AShM) को 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में दिखाया गया, और सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

□ मुख्य बिंदु

- DRDO ने ओडिशा तट से दो प्रलय मिसाइलें प्रक्षेपित कीं; प्रलय एक स्वदेशी, कम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक सीमा 150 से 500 किमी है।
- लंबी दूरी की हाइपरसोनिक जहाज-रोधी मिसाइल (LR-AShM), भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, को 77वीं गणतंत्र दिवस परेड (2026) में प्रदर्शित किया गया और इसकी मारक सीमा लगभग 1,500 किमी है।
- LR-AShM मैक 10 तक पहुँच सकती है, स्किपिंग के माध्यम से औसतन मैक 5 की गति रखती है, और द्वि-चरणीय ठोस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है।
- सेना ने सूर्यास्त्र के लिए NIBE लिमिटेड के साथ ₹293 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए; यह भारत का पहला मेड इन इंडिया सार्वभौमिक बहु-कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी मारक सीमा 300 किमी और सटीकता 5 मीटर के भीतर है।
- DRDO ने तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) का गतिशील लक्ष्य के विरुद्ध उड़ान परीक्षण किया; यह इमेजिंग इन्फ्रारेड होमिंग सीकर का उपयोग करती है।
- ध्रुव-NG, HAL के ALH ध्रुव का नई पीढ़ी का नागरिक संस्करण, ने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान पूरी की।
- वडोदरा की एयरबस-टाटा लाइन में बन रहा भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 परिवहन विमान सितंबर 2026 से पहले तैयार होना है।

रक्षा प्रणालियाँ एक नज़र में

प्रणाली	मुख्य विवरण
प्रलय	कम दूरी की सतह से सतह मिसाइल, 150-500 किमी
LR-AShM	हाइपरसोनिक ग्लाइड, लगभग 1,500 किमी, मैक 10 तक
सूर्यास्त्र	सार्वभौमिक रॉकेट लॉन्चर, 300 किमी, ₹293 करोड़ का अनुबंध
MPATGM	तीसरी पीढ़ी की मैन-पोर्टेबल टैंक-रोधी मिसाइल
ध्रुव-NG	नई पीढ़ी का नागरिक हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में पहली उड़ान
C-295	मध्यम सामरिक परिवहन विमान, 11 घंटे तक उड़ान, STOL

सैन्य क्वांटम मिशन नीति रूपरेखा

संदर्भ: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जनवरी 2026 में सैन्य क्वांटम मिशन नीति रूपरेखा जारी की, जो सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए नीति और क्रियान्वयन रोडमैप वाला दस्तावेज़ है। यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अनुरूप है, जिसका 2023-24 से 2030-31 के लिए बजट लगभग ₹6,000 करोड़ है, और इसमें नेविगेशन, संवेदन, सुरक्षित संचार तथा इमेजिंग में अनुप्रयोग शामिल हैं।

□ मुख्य बिंदु

- इसकी परिकल्पना तीनों सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय और प्रौद्योगिकी-संचालित युद्ध के लिए तत्परता है।
- यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के अनुरूप है, जिसका 2023-24 से 2030-31 के लिए बजट लगभग ₹6,000 करोड़ है।
- NQM चार स्तंभों को प्राथमिकता देता है: क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संवेदन एवं मापविज्ञान, तथा क्वांटम सामग्री एवं उपकरण।

□ सैन्य अनुप्रयोग

- नेविगेशन: अति-शीतलित परमाणुओं के साथ परमाण्विक व्यतिकरणमापी GPS पर निर्भरता घटाता है, जिसे जाम या स्पूफ किया जा सकता है।
- संवेदन: SQUID जैसे क्वांटम चुंबकत्वमापी और गुरुत्वमापी जलमग्न पनडुब्बियों या भूमिगत संरचनाओं का पता लगा सकते हैं।
- सुरक्षित संचार: क्वांटम कुंजी वितरण ऐसी एन्क्रिप्शन कुंजियाँ बनाता है जो सैद्धांतिक रूप से हैक नहीं की जा सकतीं।
- क्वांटम इमेजिंग कोहरे, धुएँ या अंधेरे में भी स्पष्ट चित्र दे सकती है।
- क्वांटम संवेदक माइक्रोचिप को नुकसान पहुँचाए बिना उनमें छिपे हार्डवेयर ट्रोजन की जाँच कर सकते हैं।

AI सामग्री लेबलिंग और 3 घंटे में हटाने के नियम

संदर्भ: MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 के माध्यम से IT नियम, 2021 में संशोधन किया, जिसमें AI-जनित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य की गई और सामग्री हटाने की समय-सीमा को काफी घटाया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्लेटफ़ॉर्मों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न चित्रों और वीडियो पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना होगा।
- 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्लेटफ़ॉर्मों को उपयोगकर्ता घोषणाएँ प्राप्त करनी होंगी और प्रकाशन से पहले तकनीकी सत्यापन करना होगा।
- स्वचालित रूप से रीटच किए गए स्मार्टफ़ोन फ़ोटो और फ़िल्म के विशेष प्रभाव इससे बाहर हैं।
- प्रतिबंधित सामग्री में बाल यौन शोषण सामग्री, जाली दस्तावेज़, विस्फोटक बनाने की जानकारी और वास्तविक लोगों का रूप धरने वाले डीपफ़ेक शामिल हैं।
- सभी ऑनलाइन सामग्री के लिए हटाने का समय 24-36 घंटे से घटकर 2-3 घंटे रह गया है।

DRDO ने ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट का प्रदर्शन किया

संदर्भ: DRDO ने फरवरी 2026 में ओडिशा तट के पास एकीकृत परीक्षण रेंज से ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट (SFDR) प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया, जिससे भारत इस क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया। SFDR वायु-श्वसन मिसाइल प्रणोदन है, जो ठोस ईंधन जलाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए निरंतर सुपरसोनिक गति तथा अधिक मारक सीमा सक्षम करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- SFDR वायु-श्वसन मिसाइल प्रणोदन है, जो ठोस ईंधन जलाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है।
- यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए निरंतर सुपरसोनिक गति और अधिक मारक सीमा सक्षम करता है।
- इसमें ठोस-ईंधन बूस्टर, रैमजेट इंजन, तथा प्रणोद नियमन के लिए प्रवाह नियंत्रक सहित नोज़ल-रहित बूस्टर होता है।

INS अंजदीप और सैन्य अभ्यास

संदर्भ: भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में तीसरे पनडुब्बी-रोधी युद्ध उथले जल पोत INS अंजदीप को कमीशन किया, और कई अभ्यास हुए। GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित और कर्नाटक के कारवार के पास एक द्वीप के नाम पर रखे गए इस पोत में पतवार-आरोपित सोनार अभय और स्वदेशी ASW हथियार हैं। समाचारों में आए अभ्यासों में MILAN, भारत द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, और वायुसेना का वायु शक्ति शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- INS अंजदीप GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित है और इसका नाम कर्नाटक के कारवार के पास एक द्वीप पर रखा गया है।
- इसमें पतवार-आरोपित सोनार अभय और स्वदेशी ASW हथियार हैं।
- MILAN भारत द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है; वायु शक्ति वायुसेना का मारक क्षमता प्रदर्शन है।

LIGO-इंडिया और लद्दाख दूरबीनें

संदर्भ: L&T ने महाराष्ट्र के हिंगोली में LIGO-इंडिया बनाने का अनुबंध जीता, और बजट में फरवरी 2026 में लद्दाख में दो दूरबीनें स्वीकृत की गईं। LIGO-इंडिया एक गुरुत्वीय-तरंग वेधशाला है, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग और DST अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के साथ मिलकर लागू कर रहे हैं, जबकि लद्दाख की परियोजनाएँ मेराक में राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन और हानले में 13.7 मीटर की राष्ट्रीय विशाल प्रकाशीय दूरबीन हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- LIGO-इंडिया को परमाणु ऊर्जा विभाग और DST अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के साथ मिलकर हिंगोली जिले के औंढा में लागू कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन लद्दाख के मेराक में 2 मीटर की दूरबीन है; कोडाइकनाल (1899) और उदयपुर (1975) मौजूदा सौर वेधशालाएँ हैं।
- राष्ट्रीय विशाल प्रकाशीय दूरबीन 13.7 मीटर की, खंडित दर्पण वाली है, जो लद्दाख के हानले में स्थित होगी।

चंद्रयान-4 अवतरण क्षेत्र: मॉन्स मूटन

संदर्भ: ISRO के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स मूटन को भारत के पहले चंद्र नमूना वापसी मिशन चंद्रयान-4 के अवतरण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया। लगभग 6 किमी का यह पर्वत दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन के किनारे पर स्थित है, इसकी चोटी समतल है जहाँ लंबे समय तक धूप रहती है, और यह स्थायी रूप से छायाग्रस्त गड्ढों के निकट है जिनमें जल-बर्फ हो सकती है। मिशन 2027 के लिए नियोजित है।

□ **मुख्य बिंदु**

- मॉन्स मूटन लगभग 6 किमी का पर्वत है, जो सबसे बड़े और सबसे पुराने चंद्र प्रहार बेसिन, दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन, के किनारे पर स्थित है।
- इसका नाम NASA की गणितज्ञ मेल्बा रॉय मूटन के नाम पर रखा गया है।
- इसकी अपेक्षाकृत समतल चोटी पर लंबे समय तक धूप रहती है और पृथ्वी के साथ सीधी दृष्टि-रेखा में संचार संभव है।
- यह स्थायी रूप से छायाग्रस्त गड्ढों के निकट है जिनमें जल-बर्फ हो सकती है।
- चंद्रयान-4 2027 के लिए नियोजित है और चंद्रमा के नमूने वापस लाएगा।

भारत का संप्रभु AI पारितंत्र: भारत जेनएआई, सर्वम, वॉइसेरा और इंडिया AI स्टैक

संदर्भ: फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान और उसके आसपास हुए कई प्रक्षेपणों ने भारत की संप्रभु AI क्षमता को मज़बूत किया। इनमें IIT बॉम्बे में TIH फ़ाउंडेशन द्वारा संचालित भारत जेनएआई, इंडिया AI मिशन के अंतर्गत सर्वम AI के मॉडल, भाषिणी (BHASHINI) का ओपन-सोर्स वॉइस AI स्टैक वॉइसेरा, और पाँच-परत वाला इंडिया AI स्टैक शामिल हैं, साथ ही स्वास्थ्य और कौशल संबंधी AI पहलें भी हैं।

□ मॉडल और प्लेटफ़ॉर्म

- भारत जेनएआई, अंतर-विषयक साइबर-भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत और IIT बॉम्बे में TIH फ़ाउंडेशन द्वारा संचालित, 15 भाषाओं का समर्थन करता है और सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखता है।
- सर्वम AI को इंडिया AI मिशन के अंतर्गत ₹246.72 करोड़ का सहयोग मिला; इसके उत्पादों में बुलबुल (टेक्स्ट-टू-स्पीच, 11 भाषाएँ) और सारस (स्पीच-टू-टेक्स्ट, 22 भाषाएँ) शामिल हैं।
- MeitY के भाषिणी प्रभाग द्वारा शुरू किया गया वॉइसेरा एक ओपन-सोर्स एंड-टू-एंड वॉइस AI स्टैक है।
- इंडिया AI स्टैक की पाँच परतें हैं: अनुप्रयोग, मॉडल, कंप्यूट, डेटा और नेटवर्क, तथा ऊर्जा।

□ स्वास्थ्य और कौशल

- SAHI स्वास्थ्य सेवा में AI की राष्ट्रीय रणनीति है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ IIT कानपुर द्वारा निर्मित BODH स्वास्थ्य AI मॉडलों का बेंचमार्किंग करता है।
- इंडिया AI मिशन के अंतर्गत युवा AI फॉर ऑल का लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों के लिए AI साक्षरता है, और इसने कौशल रथ मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की।
- MoSPI ने eसांख्यिकी पोर्टल के लिए बीटा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर शुरू किया।

स्वास्थ्य विज्ञान समाचार: राज्य सूक्ष्मजीव और अंगदान

संदर्भ: केरल फरवरी 2026 में बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला पहला राज्य बना, और भारत में अंग प्रत्यारोपण एक दशक में लगभग चार गुना बढ़ गए। प्रत्यारोपण 2013 में 5,000 से कम से बढ़कर 2025 में लगभग 20,000 हो गए, जिनमें लगभग 18 प्रतिशत मृत दाताओं से थे; यह मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 तथा इसके NOTTO, ROTTO और SOTTO नेटवर्क के अंतर्गत है।

□ मुख्य बिंदु

- अंग प्रत्यारोपण 2013 में 5,000 से कम से बढ़कर 2025 में लगभग 20,000 हो गए, जिनमें लगभग 18 प्रतिशत मृत दाताओं से थे।
- मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत NOTTO, ROTTO और SOTTO हैं।

LPG के विकल्प के रूप में डाइमिथाइल ईथर

संदर्भ: मार्च 2026 में चर्चा में, CSIR-NCL LPG आयात निर्भरता घटाने के लिए डाइमिथाइल ईथर (DME) प्रौद्योगिकी को औद्योगिक प्रदर्शन स्तर तक बढ़ाने के लिए तैयार है। DME (CH_3OCH_3) मेथनॉल के उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण से बनता है, और चूँकि भारत अपनी लगभग 60-65% LPG आयात करता है, मिश्रण से सालाना लगभग ₹9,500 करोड़ की बचत हो सकती है। वर्तमान पैमाना लगभग 250 किग्रा प्रतिदिन का अर्ध-पायलट है।

□ मुख्य बिंदु

- DME (CH_3OCH_3) मेथनॉल के उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण से बनता है।
- भारत अपनी लगभग 60-65% LPG आयात करता है; मिश्रण से सालाना लगभग ₹9,500 करोड़ की बचत हो सकती है।
- वर्तमान पैमाना लगभग 250 किग्रा प्रतिदिन का अर्ध-पायलट है।
- DME की लागत मेथनॉल की कीमत की लगभग 1.8 गुना है।

अंतरिक्ष संक्षेप: DART, क्षुद्रग्रह 2024 YR4 और आकाशा300

संदर्भ: मार्च 2026 में अंतरिक्ष समाचारों में DART के व्यापक प्रभाव, NASA द्वारा क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के 2032 में चंद्रमा से टकराने की संभावना को खारिज करना, और ISRO के लिए केरल में बना 3D प्रिंटर शामिल थे। DART ने 2022 में डिमॉर्फोस से टकराकर उसकी कक्षा लगभग 33 मिनट घटा दी, जबकि IIST और केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा विकसित आकाशा300 को तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र में तैनात किया गया।

□ मुख्य बिंदु

- DART (2021) ने 2022 में डिमॉर्फोस से टकराकर उसकी कक्षा लगभग 33 मिनट घटा दी।
- 2024 YR4 अपोलो-प्रकार का निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह है, जिसकी खोज 2024 में हुई थी।
- आकाशा300 को IIST और केरल स्टार्टअप मिशन ने विकसित किया और इसे तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र में तैनात किया गया।
- SWOT, जिसे 2022 में NASA और CNES ने प्रक्षेपित किया, KaRIn रडार का उपयोग करता है।

आंतरिक सुरक्षा में AI और डिजिटल अरेस्ट ठगी

संदर्भ: मार्च 2026 की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट साइबर अपराध नियंत्रण में गृह मंत्रालय द्वारा AI के उपयोग का वर्णन करती है, जबकि गृह मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामलों में प्रयुक्त उपकरणों को ब्लॉक करने को कहा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) 1930 हेल्पलाइन के लिए AI-सहायता प्राप्त शिकायत प्रणाली लागू कर रहा है और म्यूल खातों के लिए संदिग्ध स्कोर की संभावना तलाश रहा है, और दिसंबर 2025 में गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने व्हाट्सऐप से बैठक की।

□ मुख्य बिंदु

- I4C 1930 हेल्पलाइन के लिए AI-सहायता प्राप्त शिकायत प्रणाली लागू कर रहा है।
- I4C और IIT बॉम्बे म्यूल खातों के लिए संदिग्ध स्कोर की संभावना तलाश रहे हैं; RBIH का Mulehunter.ai एकीकृत किया जा रहा है।
- दिसंबर 2025 में गठित एक उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय समिति ने व्हाट्सऐप से बैठक की।
- दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2025 में ऐप्स को सिम बाइंडिंग लागू करने का निर्देश दिया।

महासागर प्रौद्योगिकी संक्षेप: डार्क ऑक्सीजन, LTTD और फ़्लोटिंग लिडार

संदर्भ: मार्च 2026 में समुद्री विज्ञान से जुड़े विषयों में डार्क ऑक्सीजन की खोज, कवरत्ती का LTTD संयंत्र और NIOT का फ़्लोटिंग लिडार बॉय शामिल थे। डार्क ऑक्सीजन क्लेरियन-क्लिपर्टन क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडों द्वारा उत्पन्न होती है, निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण लक्षद्वीप के एक संयंत्र में गहरे ठंडे जल का उपयोग करता है, और NIOT ने तमिलनाडु के मुट्टम के पास बॉय का परीक्षण किया, जो 300 मीटर तक की हवाओं को मापता है।

□ मुख्य बिंदु

- डार्क ऑक्सीजन क्लेरियन-क्लिपर्टन क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसकी खोज 2013 में हुई थी।
- निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण गहरे ठंडे जल का उपयोग फ़्लैश-वाष्पित गर्म सतही जल को संघनित करने के लिए करता है; एक संयंत्र कवरत्ती, लक्षद्वीप में संचालित है।
- NIOT ने तमिलनाडु के मुट्टम के पास फ़्लोटिंग लिडार बॉय का परीक्षण किया, जो 300 मीटर तक की हवाओं को मापता है।

INS अरिधमान: तीसरी SSBN सेवा में शामिल

संदर्भ: भारत ने अप्रैल 2026 में विशाखापत्तनम में अपनी तीसरी परमाणु-चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमान को स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरि के साथ सेवा में शामिल किया। INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद अब भारत के पास तीन परिचालन SSBN हैं। SSBN भारत के परमाणु पहले उपयोग न करने (No First Use) के सिद्धांत के अंतर्गत विश्वसनीय दूसरी-प्रहार क्षमता प्रदान करती हैं।

□ मुख्य बिंदु

- दो SSN स्वदेशी रूप से बनाई जाएँगी और एक 2027-28 तक रूस से पट्टे पर ली जाएगी। चौथी SSBN निर्माणाधीन है और इसमें अधिक K-4 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं।
- INS अरिहंत (2016) और INS अरिघात (2024) की तरह, इसका सेवा-प्रवेश भी शांत रहा और कोई औपचारिक कमीशनिंग घोषणा नहीं हुई।
- SSBN भारत के परमाणु पहले उपयोग न करने के सिद्धांत के अंतर्गत विश्वसनीय दूसरी-प्रहार क्षमता प्रदान करती हैं।
- INS अरिहंत को 2009 में लॉन्च किया गया, इसने 2018 में अपना पहला निवारक गश्ती अभियान पूरा किया और अक्टूबर 2022 में SLBM दागी।
- INS अरिघात का विस्थापन 6,000 टन है; अरिहंत और अरिघात 83 MW के दाबित हल्के-जल रिएक्टरों का उपयोग करती हैं।
- जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और मझगांव डॉक के साथ प्रोजेक्ट-75I के तहत भारत में छह AIP पनडुब्बियाँ बनाई जाएँगी।

IOS सागर और भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा रणनीति 2026

संदर्भ: भारतीय नौसेना ने INS सुनयना को हिंद महासागर पोत (IOS) सागर के रूप में रवाना किया, जिससे महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण को क्रियान्वित किया गया। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा रणनीति (INMSS-2026) भी जारी की गई।

□ मुख्य बिंदु

- INS सुनयना सरयू-श्रेणी का गश्ती पोत है जिसका नाम बदलकर IOS सागर किया गया।
- महासागर (MAHASAGAR) का पूर्ण रूप है क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions), जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में प्रस्तुत किया था।
- यह पूर्ववर्ती सागर (SAGAR) पहल को हिंद महासागर से आगे बढ़ाकर ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित करता है।
- कई देशों के कर्मी एक ही पोत पर एक दल के रूप में साथ सेवा करते हैं।
- INMSS-2026 अगले दशक के लिए समुद्री प्राथमिकताओं की रूपरेखा देती है और भारतीय नौसेना विज़न 2047 के अनुरूप है।

आर्टेमिस II: चालक दल सहित चंद्र फ्लाईबाई पूरी हुई

संदर्भ: नासा के आर्टेमिस II का चालक दल ऐतिहासिक चंद्र फ्लाईबाई के बाद पृथ्वी पर लौट आया। यह आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला चालक दल सहित मिशन था और पाँच दशकों से अधिक समय में पहली बार मनुष्य निम्न-पृथ्वी कक्षा से आगे गए।

□ **मुख्य बिंदु**

- चीन और रूस के अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की घोषणा 2021 में की गई थी। नासा का वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था।
- चालक दल में ओरियन अंतरिक्ष यान पर रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन शामिल थे।
- मिशन लगभग 10 दिनों तक चला और इसमें फ्री-रिटर्न प्रक्षेप पथ का उपयोग किया गया।
- पुनः प्रवेश की गति लगभग 11-12 किमी/सेकंड थी।
- आर्टेमिस I (2022) चालक दल रहित था; आर्टेमिस III लगभग 2027 में और आर्टेमिस IV 2028 में चालक दल सहित चंद्र अवतरण के लिए नियोजित हैं।
- 2020 में 8 देशों के साथ शुरू हुए आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) के अब 64 हस्ताक्षरकर्ता हैं; भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- चीन का चांग'ई-7 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करता है।
- भारत 2023 में चंद्रयान-3 के बाद लगभग 2040 तक चालक दल सहित चंद्र मिशन की योजना बना रहा है।

जैव-विनिर्माण के लिए BioE3 नीति

संदर्भ: सरकार ने राज्यसभा को BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के बारे में बताया, जिसे 2024 में उच्च-निष्पादन जैव-विनिर्माण और चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा BIRAC के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है।
- यह राष्ट्रीय महत्व के छह विषयगत क्षेत्रों के इर्द-गिर्द संगठित है।
- त्रि-स्तरीय ढाँचे में डिस्कवरी रिसर्च नेटवर्क, ब्रिजिंग द गैप पहलें और बायो-एनेबलर्स पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
- बायो-एनेबलर्स में बायो-AI हब, बायोफाउंड्री और जैव-विनिर्माण हब शामिल हैं।
- बजट का दस प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित है और असम तथा सिक्किम में राज्य BioE3 प्रकोष्ठ मौजूद हैं।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली क्रांतिकता प्राप्त की

संदर्भ: तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में पहली क्रांतिकता (क्रिटिकैलिटी) प्राप्त की, जिससे भारत अपने त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में पहुँच गया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा यूरेनियम-प्लूटोनियम MOX ईंधन का उपयोग करके विकसित यह रिएक्टर भारत को रूस के बाद वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दूसरा देश बना देगा।

□ **मुख्य बिंदु**

- परमाणु क्षमता लगभग 8.78 गीगावाट है, जो भारत की बिजली का लगभग 3 प्रतिशत है, और 2031-32 तक इसके लगभग 22.38 गीगावाट तक पहुँचने की अपेक्षा है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट है और यह लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित करता है, जिसमें 2033 तक पाँच स्वदेशी SMR शामिल हैं।
- भारत रूस के बाद वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दूसरा देश होगा।
- PFBR को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है और यह पुनर्संसाधित PHWR प्रयुक्त ईंधन से बने यूरेनियम-प्लूटोनियम MOX ईंधन का उपयोग करता है।
- चरण I में प्राकृतिक यूरेनियम वाले PHWR का उपयोग होता है; चरण II में फास्ट ब्रीडर का; चरण III में यूरेनियम-233 से चलने वाले थोरियम-आधारित रिएक्टरों का।
- त्रि-चरणीय योजना की परिकल्पना डॉ. होमी जे. भाभा ने की थी।
- तरल सोडियम शीतलक जोखिम उत्पन्न करता है, जैसा कि जापान के मोन्जू में 1995 के सोडियम रिसाव और आग से देखा गया।
- BARC, BSMR-200, SMR-55 और हाइड्रोजन के लिए उच्च-तापमान गैस-शीतित रिएक्टर विकसित कर रहा है।
- शांति अधिनियम, 2025 परमाणु कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण करता है और सीमित निजी भागीदारी की अनुमति देता है।
- भारत के 18 देशों के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते हैं।

भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ पर पहुँचा

संदर्भ: अप्रैल 2026 में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष से 62.66% बढ़कर रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ तक पहुँच गया। निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 के ₹23,622 करोड़ से ₹14,802 करोड़ बढ़ा और पाँच वर्षों में लगभग तिगुना हो गया है। रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान 54.84% और निजी क्षेत्र का 45.16% रहा, तथा निर्यात 80 से अधिक देशों तक पहुँच रहा है।

□ **मुख्य बिंदु**

- निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 के ₹23,622 करोड़ से ₹14,802 करोड़ बढ़ा और पाँच वर्षों में लगभग तिगुना हो गया है।
- DPSU का योगदान 54.84% (₹21,071 करोड़) और निजी क्षेत्र का 45.16% (₹17,353 करोड़) रहा।
- DPSU निर्यात में 151% की वृद्धि हुई जबकि निजी क्षेत्र में 14% की वृद्धि हुई।
- निर्यात 80 से अधिक देशों तक पहुँचता है और निर्यातकों की संख्या 128 से बढ़कर 145 हो गई।
- 2013-14 में निर्यात ₹686 करोड़ था; 2024-25 में निजी क्षेत्र का योगदान ₹15,233 करोड़ और DPSU का ₹8,389 करोड़ रहा।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन: क्वांटम वैली और 1,000 किमी नेटवर्क

संदर्भ: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत ने स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स की स्वदेशी तकनीक से 1,000 किमी क्वांटम संचार नेटवर्क का प्रदर्शन किया, जो 2,000 किमी के लक्ष्य का आधा है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली की आधारशिला भी रखी गई, जिसका लक्ष्य 2026 में भारत का पहला 133-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करना है।

□ **मिशन के तथ्य**

- NQM को 2023 में 2023-31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है।
- लक्ष्यों में आठ वर्षों में 50-1000 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर तथा उपग्रह सहित 2,000 किमी के QKD नेटवर्क शामिल हैं।
- चार विषयगत हब: IISc बेंगलुरु में कंप्यूटिंग, IIT मद्रास में संचार, IIT बॉम्बे में संवेदन एवं मापविज्ञान, और IIT दिल्ली में सामग्री।
- हब, स्पोक और स्पाइक के साथ समन्वय करते हैं, जिससे हब-स्पोक-स्पाइक मॉडल बनता है।
- सरकारी सहायता का दायरा बढ़कर 17 क्वांटम स्टार्टअप तक हो गया है।
- C-DoT QKD और पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी उपकरण विकसित कर रहा है।

□ **क्वांटम वैली और उपलब्धियाँ**

- अमरावती की क्वांटम वैली सरकार, उद्योग (IBM, TCS, L&T) और शिक्षा जगत के ट्रिपल हेलिक्स मॉडल का पालन करती है।
- 2022 में DRDO और IIT दिल्ली ने प्रयागराज और विंध्याचल के बीच, 100 किमी की दूरी पर, QKD लिंक का प्रदर्शन किया।
- बेंगलुरु स्थित क्यूपाई-एआई ने 25-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर क्यूपाई-एआई-इंडस लॉन्च किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपलब्धियाँ: कुष्ठ रोग, ट्रेकोमा, मलेरिया और अमेरिका का बाहर निकलना

संदर्भ: 2025-26 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई निर्णय रोग उन्मूलन के सत्यापन, एक नई मलेरिया दवा और एक प्रमुख सदस्य देश के अलग होने से संबंधित हैं। अमेरिका जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया और अर्जेंटीना ने मार्च 2026 में अपने अलग होने की सूचना दी। चिली को मार्च 2026 में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया गया, जो अमेरिकी महाद्वीपों में पहला है, और फिजी को अक्टूबर 2025 में ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए मान्यता दी गई। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े विशिष्ट तथ्य हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2-5 किग्रा वज़न वाले नवजात और शिशुओं के लिए बनाए गए पहले मलेरिया उपचार को पूर्व-अर्हता प्रदान की (अप्रैल 2026)।
- बुंदीबुग्यो वायरस के लिए पहला आणविक नैदानिक परीक्षण 2 जुलाई 2026 को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल हुआ।
- अमेरिका 22 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया; अर्जेंटीना ने मार्च 2026 में अपने अलग होने की सूचना दी।
- मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के अंतर्गत डीआर कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया।

□ **उन्मूलन सत्यापन**

- चिली को मार्च 2026 में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया गया; वह अमेरिकी महाद्वीपों में पहला और विश्व में दूसरा देश है।
- फिजी को अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए मान्यता दी गई।

DRDO के परीक्षण: तारा (TARA), NASM-SR और ULPGM-V3

संदर्भ: DRDO ने कई हथियार परीक्षण किए: तारा ग्लाइड किट का पहला परीक्षण, NASM-SR जहाज-रोधी मिसाइल की हेलीकॉप्टर से पहली सैल्वो फायरिंग, और ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण।

□ **तारा (TARA)**

- TARA का अर्थ है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (Tactical Advanced Range Augmentation), जो एक मॉड्यूलर रेंज विस्तार किट और भारत की पहली ग्लाइड हथियार प्रणाली है।

➤ यह बिना निर्देशन वाले वारहेड को सटीक-निर्देशित गोला-बारूद में बदल देती है और इसे रिसर्च सेंटर इमारत, हैदराबाद ने विकसित किया।

□ **NASM-SR**

➤ नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को ओडिशा तट के पास हेलीकॉप्टर से दो मिसाइलों की सैल्वो में दागा गया, जो भारत के लिए पहली बार है।

➤ इसमें द्वि-मार्गी डेटा लिंक के माध्यम से मैन-इन-लूप मार्गदर्शन और जलरेखा पर प्रहार करने की क्षमता है।

➤ इसका उद्देश्य 1980 के दशक की ब्रिटिश सी ईगल मिसाइल को प्रतिस्थापित करना है, जिसका वजन लगभग 580 किग्रा है।

□ **ULPGM-V3**

➤ इसका परीक्षण वायु-से-भूमि और वायु-से-वायु दोनों मोड में किया गया।

➤ इसकी विशेषताओं में द्वि-चैनल सीकर, द्वि-मार्गी डेटा लिंक और तीन वारहेड विकल्प शामिल हैं: कवच-भेदी, भेदन-सह-विस्फोट और पूर्व-विखंडन।

ICMR और ICAR का मिशन सेहत (SEHAT)

संदर्भ: ICMR और ICAR ने मई 2026 में कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोड़ने के लिए संयुक्त रूप से मिशन सेहत (SEHAT: कृषि रूपांतरण के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्टता) लॉन्च किया। यह संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण अपनाने वाला मिशन-मोड कार्यक्रम है, जिसे कुपोषण के साथ-साथ बढ़ते उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर का समाधान करने के लिए बनाया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण अपनाने वाला मिशन-मोड कार्यक्रम है।

➤ यह कुपोषण के साथ-साथ बढ़ते उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर का समाधान करता है।

अंतरिक्ष विज्ञान: स्माइल (SMILE), साइकी और चंद्रयान-3 हॉप

संदर्भ: मई 2026 में एक यूरोपीय-चीनी अंतरिक्ष मौसम मिशन प्रक्षेपित हुआ, नासा के साइकी ने मंगल की तस्वीर ली, और चंद्रयान-3 के हॉप प्रयोग से नए निष्कर्ष सामने आए। SMILE ESA और चीनी विज्ञान अकादमी का संयुक्त मिशन है, जो मृदु एक्स-किरणों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (मैग्नेटोस्फीयर) की इमेजिंग करेगा, जबकि चंद्रयान-3 के हॉप ने ऊपरी 3 सेमी के नीचे परतदार, अधिक सघन रेगोलिथ का पता लगाया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ SMILE (सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर) ESA और चीनी विज्ञान अकादमी का संयुक्त मिशन है, जिसे वेगा-C पर प्रक्षेपित किया गया और जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मृदु एक्स-किरण इमेजिंग करता है।

➤ नासा का साइकी, जिसे 2023 में प्रक्षेपित किया गया था, मंगल के गुरुत्वीय सहायता (ग्रैविटी असिस्ट) के बाद 2029 में क्षुद्रग्रह 16 साइकी तक पहुँचेगा।

➤ चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव के निकट ऐसा करने वाला पहला देश बना।

➤ हॉप प्रयोग में विक्रम लगभग 50 सेमी ऊपर उठा और ChaSTE जाँच-यंत्र को पुनः डाला गया, जिससे ऊपरी 3 सेमी के नीचे परतदार, अधिक सघन रेगोलिथ का पता चला।

ऑपरेशन सिंदूर का एक वर्ष: रक्षा प्राथमिकताएँ

संदर्भ: 7 मई 2025 को पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों के साथ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष बाद, सशस्त्र बलों ने भूमिगत अवसंरचना और राष्ट्रीय वायु रक्षा कवच को संघर्ष-पश्चात की प्राथमिकताओं के रूप में निर्धारित किया है।

□ **प्राथमिकताएँ**

➤ भूमिगत कमान एवं नियंत्रण केंद्र बनाए जाएँगे, जिनकी शुरुआत सेना कमान और कोर मुख्यालय स्तर से होगी, तथा C4I2SR नेटवर्क सभी सेवाओं के बीच साझा होंगे।

➤ अन्य भूमिगत सुविधाओं में चिकित्सा केंद्र, आवासीय बंकर, गोला-बारूद और ईंधन भंडारण, तथा 3D-प्रिंटेड बंकर शामिल हैं, जिनमें पश्चिमी सीमा पर विशेष जोर है।

➤ सुदर्शन चक्र मिशन का उद्देश्य व्यापक राष्ट्रीय वायु रक्षा कवच बनाना है; DRDO ने पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

➤ आकाशतीर सेना की स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है, जो वायुसेना की IACCS और नौसेना की ट्राइगुन (TRIGUN) के साथ एकीकृत होती है।

➤ पुरानी L/70 तोपों के साथ एकीकरण सहित बड़े पैमाने पर काउंटर-UAS की खरीद की योजना है।

➤ भारत ने 7 मई को लगभग 300 किमी दूर एक बड़े पाकिस्तानी हवाई मंच को नष्ट करने की जानकारी दी।

□ **दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना**

➤ वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर Su-30MKI, जगुआर, मिराज 2000 और C-295 विमानों का उपयोग करके आपातकालीन लैंडिंग फील्ड अभ्यास किया।

➤ कई सीमावर्ती हवाई अड्डों को नागरिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है।

गैलेक्सआई का दृष्टि और प्रोजेक्ट गरुड़

संदर्भ: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप मई 2026 में सुर्खियों में रहे: गैलेक्सआई ने दुनिया का पहला ऑप्टोSAR उपग्रह मिशन दृष्टि लॉन्च किया, और ध्रुव स्पेस ने प्रोजेक्ट गरुड़ के लिए ₹105 करोड़ जुटाए। दृष्टि सभी मौसम में, दिन-रात इमेजिंग के लिए ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार को जोड़ता है, जबकि गरुड़ 500 किग्रा श्रेणी का फ्लैट-पैक संचार उपग्रह मंच है, जिसे अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष के अंतर्गत वित्तपोषित किया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- अग्निकुल ने अग्निलेट विकसित किया, जो दुनिया का पहला एकल-खंड 3D-प्रिंटेड इंजन है।
- 2020 में स्थापित IN-SPACe निजी भागीदारी के लिए एकल-खिड़की एजेंसी है।

□ **मिशन दृष्टि**

- इसे कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 पर प्रक्षेपित किया गया और इसका वजन लगभग 190 किग्रा है; यह भारत का सबसे बड़ा निजी रूप से निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- यह सभी मौसम में, दिन-रात इमेजिंग के लिए एक ही मंच पर ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार को जोड़ता है।

□ **प्रोजेक्ट गरुड़**

- ध्रुव स्पेस को अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष के अंतर्गत ₹105 करोड़ प्राप्त हुए।
- गरुड़ 500 किग्रा श्रेणी का फ्लैट-पैक संचार उपग्रह मंच है, जिसका लक्ष्य प्रतिदिन दो उपग्रह तक बनाना है।

पाकिस्तान ने पहली हंगोर-श्रेणी की पनडुब्बी शामिल की

संदर्भ: पाकिस्तान ने मई 2026 में चीन के सान्या में अपनी पहली हंगोर-श्रेणी की पनडुब्बी को कमीशन किया, जो चीन से प्राप्त की जा रही आठ पनडुब्बियों में पहली है। इसका डिजाइन चीन के टाइप 039A (युआन श्रेणी) पर आधारित है और यह टॉरपीडो तथा जहाज-रोधी मिसाइलों से लैस है, तथा लंबे समय तक जलमग्न रहने के लिए इसमें वायु-निरपेक्ष प्रणोदन (AIP) है। आठ पनडुब्बियों का बेड़ा हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक संतुलन को बदल देगा।

□ **मुख्य बिंदु**

- इसका डिजाइन चीन के टाइप 039A (युआन श्रेणी) पर आधारित है।
- यह टॉरपीडो और जहाज-रोधी मिसाइलों से लैस है तथा लंबे समय तक जलमग्न रहने के लिए इसमें वायु-निरपेक्ष प्रणोदन है।
- आठ पनडुब्बियों का बेड़ा हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक संतुलन को बदल देगा।

बच्चों में मधुमेह संबंधी दिशानिर्देश और जननी (JANANI) प्लेटफ़ॉर्म

संदर्भ: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मई 2026 में बच्चों में मधुमेह के प्रबंधन के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय ढाँचा जारी किया और मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जननी (JANANI) लॉन्च किया। इस ढाँचे में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक मधुमेह जाँच की परिकल्पना है। जननी (प्रसवपूर्व, प्रसव और नवजात एकीकृत देखभाल की यात्रा) RCH पोर्टल को उन्नत करता है, जिसमें अभिलेख ABHA से जुड़े होते हैं।

□ **बच्चों में डायबिटीज मेलिटस पर मार्गदर्शन दस्तावेज**

- यह बाल्यावस्था मधुमेह की जाँच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए पहला संरचित राष्ट्रीय ढाँचा है।
- इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक मधुमेह जाँच की परिकल्पना है।
- इसका उद्देश्य SDG 3 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को सहायता देना है।

□ **जननी (JANANI)**

- JANANI का अर्थ है प्रसवपूर्व, प्रसव और नवजात एकीकृत देखभाल की यात्रा (Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care)।
- यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल का उन्नत संस्करण है।
- यह महिलाओं और बच्चों के लिए ABHA से जुड़े दीर्घकालिक डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तैयार करता है।
- यह प्रवासी आबादी के लिए देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करता है और दोहरे अभिलेखों को कम करता है।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन: गुजरात में दो और इकाइयों को मंज़ूरी

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत दो और चिप परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिससे कुल स्वीकृत परियोजनाएँ 12 हो गईं। दोनों गुजरात में हैं, जिनमें लगभग ₹3,936 करोड़ का निवेश है: गैलियम नाइट्राइड पर आधारित भारत की पहली वाणिज्यिक मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले सुविधा, और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर के लिए असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग इकाई। यह इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- 5 मई 2026 को मंज़ूरी मिली; दोनों गुजरात में स्थित हैं, जिनमें लगभग ₹3,936 करोड़ का निवेश और 2,230 कुशल रोज़गार हैं।
- एक इकाई गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत की पहली वाणिज्यिक मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले सुविधा है।

➤ दूसरी डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर के लिए असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग इकाई है।

➤ स्वीकृत परियोजनाओं में संचयी निवेश लगभग ₹1.64 लाख करोड़ है।

□ **इलेक्ट्रॉनिक्स की पृष्ठभूमि**

➤ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ₹1.90 लाख करोड़ (2014-15) से बढ़कर लगभग ₹13.11 लाख करोड़ (2025-26) हो गया।

➤ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ 2025-26 में 47.96 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गईं।

➤ इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू मूल्य संवर्धन 15% से बढ़कर 23% हो गया।

मिशन मौसम: C-ART, स्काईकास्ट, ब्लॉक मानसून पूर्वानुमान

संदर्भ: मई 2026 में मिशन मौसम के अंतर्गत कई पहलें चर्चा में रहीं, जिनमें तटीय अनुसंधान परीक्षण-स्थल, भारत की पहली विमानन मौसम प्रणाली और ब्लॉक-स्तरीय AI मानसून पूर्वानुमान शामिल हैं। IITM पुणे ने आंध्र विश्वविद्यालय में तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण-स्थल (Coastal Atmospheric Research Testbed) स्थापित किया, दिल्ली के हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट तैनात किया गया, और IMD ने 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 ब्लॉकों को कवर करने वाला साप्ताहिक पूर्वानुमान शुरू किया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण-स्थल को IITM पुणे ने आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम में चक्रवात पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता सुविधा के रूप में स्थापित किया।

➤ दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित स्काईकास्ट भारत की पहली एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है; भारत इसे तैनात करने वाला 19वाँ देश है।

➤ स्काईकास्ट 2015 में शुरू हुए शीतकालीन कोहरा प्रयोग (WiFEX) पर आधारित है, और अगला स्काईकास्ट उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे पर लगाने की योजना है।

➤ IMD ने AI-आधारित ब्लॉक-स्तरीय मानसून पूर्वानुमान शुरू किया, जो हर बुधवार को चार सप्ताह तक के अग्रिम समय के साथ जारी किया जाता है और 15 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 ब्लॉकों को कवर करता है।

➤ IITM पुणे ने WISE-2026 बैठक के साथ NEAT पहल के अंतर्गत मौसम और जलवायु स्टार्टअप के लिए एक इनक्यूबेशन केंद्र खोला।

रक्षा अपडेट: नए CDS, आईएनएस महेंद्रगिरि और अभ्यास

संदर्भ: सरकार ने मई 2026 में सशस्त्र बलों के नए प्रमुखों के नाम घोषित किए, नौसेना को आईएनएस महेंद्रगिरि मिला, और भारत ने पहले प्रगति 2026 सहित कई अभ्यासों में भाग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि जनरल अनिल चौहान के उत्तराधिकारी के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे, और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के उत्तराधिकारी के रूप में नौसेना प्रमुख बनेंगे।

□ **नियुक्तियाँ और शामिल किया जाना**

➤ लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि जनरल अनिल चौहान के उत्तराधिकारी के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे।

➤ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के उत्तराधिकारी के रूप में नौसेना प्रमुख बनेंगे।

□ **अभ्यास और स्मारक**

➤ मेघालय के उमरोई में आयोजित प्रगति 2026, 13 देशों का पहला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था; PRAGATI का अर्थ है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी (Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region)।

➤ भारत और अल्जीरिया ने नई दिल्ली में अपनी पहली संयुक्त रक्षा आयोग बैठक आयोजित की।

➤ सियोल के इमजिंगक पार्क में, भारतीय संरक्षक बल (Custodian Force of India) द्वारा 1954 में स्थापित हिंद नगर के स्थल पर एक भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया।

➤ खुले आसमान के नीचे बने नौसैनिक संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में एकाना स्टेडियम के निकट किया गया।

रोग प्रकोप: इबोला PHEIC, हंटावायरस, CDV और बेबेसिया

संदर्भ: WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में इबोला प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति (PHEIC) घोषित किया, जबकि हंटावायरस, कैनाइन डिस्टेंपर और बेबेसिया के कारण एक क्रूज जहाज पर, बाघों में और शेर के शावकों में मौतें हुईं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ इबोला का प्रकोप बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के कारण है, जिसके लिए कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है।

➤ PHEIC अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के अंतर्गत घोषित किया जाता है, जो 196 देशों को कवर करता है।

➤ डच क्रूज जहाज MV हॉन्डियस पर हंटावायरस के प्रकोप से तीन लोगों की मौत हुई; हंटावायरस कृंतकों से फैलते हैं और केवल एंडीज वायरस मनुष्यों के बीच फैलता है।

➤ संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाँच बाघों की मौत हो गई।

➤ संदिग्ध बेबेसिया, जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने वाला किलनी-जनित परजीवी है, से गिर परिदृश्य में आठ शेर के शावकों की मौत हो गई।

स्वास्थ्य विज्ञान: उम्मीद (UMMID), इंडियाAI-ICMR समझौता ज्ञापन और PMOS

संदर्भ: भारत ने उम्मीद (UMMID) जीनोमिक कार्यक्रम और डैशबोर्ड शुरू किया, इंडियाAI और ICMR ने जिम्मेदार स्वास्थ्य-सेवा AI पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, और मई 2026 में PCOS का नाम बदलकर PMOS कर दिया गया। UMMID जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यक्रम है जो वंशानुगत विकारों के निदान और परामर्श के लिए है, और PMOS (पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम) दर्शाता है कि यह स्थिति केवल अंडाशय को नहीं, बल्कि कई हार्मोनों और चयापचय को प्रभावित करती है।

□ मुख्य बिंदु

- UMMID (वंशानुगत विकारों के प्रबंधन की अनूठी पद्धतियाँ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यक्रम है जो वंशानुगत विकारों के निदान और परामर्श के लिए है, जिसके लगभग 30 निदान केंद्र (NIDAN Kendra) हैं।
- इंडियाAI-ICMR समझौता ज्ञापन के अंतर्गत MIDAS ढाँचे के तहत AIKosh प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डेटासेट साझा किए जाएँगे और रियायती GPU कंप्यूट उपलब्ध कराया जाएगा।
- इंडियाAI MeitY का मिशन है, जिसका लक्ष्य PPP के माध्यम से 10,000 से अधिक GPU उपलब्ध कराना है।
- PCOS को अब पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम (PMOS) कहा जाता है, क्योंकि यह केवल अंडाशय को नहीं, बल्कि कई हार्मोनों और चयापचय को प्रभावित करता है।

DRDO के बहु-स्तरीय BMD और NASM-MR परीक्षण

संदर्भ: DRDO ने दीर्घ-दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध बहु-स्तरीय रक्षा और मध्यम दूरी पर जहाज-रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया, तथा जून 2026 में चरण-II बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) परीक्षण पूरा किया। चरण-II में 5,000 किमी श्रेणी की मिसाइलों के विरुद्ध AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर का उपयोग किया गया, जबकि NASM-MR स्वदेशी, सभी मौसम में काम करने वाली क्षितिज-पार (ओवर-द-हॉराइजन) क्रूज मिसाइल है जिसने समुद्र-सतह के निकट उड़ान (सी-स्किमिंग) का प्रदर्शन किया।

□ मुख्य बिंदु

- भारत का BMD कार्यक्रम DRDO ने 1999 में शुरू किया था।
- चरण-I 2,000 किमी तक के खतरों से सुरक्षा देता है, जिसमें बाह्य-वायुमंडलीय पृथ्वी रक्षा वाहन (Prithvi Defence Vehicle) और अंतः-वायुमंडलीय उन्नत वायु रक्षा (Advanced Air Defence) इंटरसेप्टर का उपयोग होता है।
- जून 2026 में, AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर के साथ चरण-II परीक्षण ने 5,000 किमी श्रेणी की मिसाइलों के विरुद्ध क्षमता दिखाई।
- चरण-III के इंटरसेप्टर AD-AH और AD-AM का लक्ष्य हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और MIRV हैं।
- NASM-MR स्वदेशी, सभी मौसम में काम करने वाली क्षितिज-पार क्रूज मिसाइल है जिसने समुद्र-सतह के निकट उड़ान का प्रदर्शन किया।

□ मिसाइल श्रेणियाँ

- लघु-दूरी की मिसाइलें 1,000 किमी से कम की होती हैं, जैसे पृथ्वी-II।
- मध्यम-दूरी की मिसाइलें 1,000 से 3,000 किमी की होती हैं, जैसे अग्नि-II।
- मध्यवर्ती-दूरी की मिसाइलें 3,000 से 5,500 किमी की होती हैं, जैसे अग्नि-IV।
- ICBM 5,500 किमी से अधिक दूरी की होती हैं, जैसे अग्नि-V।

SIPRI ईयरबुक 2026 के निष्कर्ष

संदर्भ: जून में जारी SIPRI ईयरबुक 2026 ने परमाणु हथियारों में वृद्धि और विश्व के रिकॉर्ड सैन्य व्यय की जानकारी दी। जनवरी 2026 तक विश्व में लगभग 12,187 परमाणु हथियार थे, जिनमें भारत के पास अनुमानित 190, चीन के पास 620 और पाकिस्तान के पास 170 हैं। 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचा, जिसमें भारत 5वाँ सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश रहा।

□ मुख्य बिंदु

- जनवरी 2026 तक विश्व में लगभग 12,187 परमाणु हथियार थे।
- भारत के पास अनुमानित 190 हथियार हैं, चीन के पास 620 और पाकिस्तान के पास 170।
- 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचा, जो लगातार 11वीं वार्षिक वृद्धि है।
- भारत 92.1 अरब डॉलर के व्यय के साथ 5वाँ सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश रहा; अमेरिका ने 954 अरब डॉलर खर्च किए।
- भारत लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा।
- अंतर-राज्यीय सशस्त्र संघर्ष 2024 में 3 से दोगुने होकर 2025 में 6 हो गए।

नौसेना के तीन पोतों का एक साथ कमीशन और चौथी S-400 स्क्वाड्रन

संदर्भ: नौसेना ने जून 2026 में कोलकाता में INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रे को एक साथ कमीशन किया। भारत को रूसी S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली की चौथी स्क्वाड्रन भी प्राप्त हुई। तीनों पोत GRSE द्वारा 75% से अधिक स्वदेशी घटकों के साथ बनाए गए थे, और 5.43 अरब डॉलर का S-400 सौदा 2018 में पाँच रेजिमेंटों के लिए हस्ताक्षरित हुआ था।

□ **तीन पोत**

- तीनों को GRSE, कोलकाता ने 75% से अधिक स्वदेशी घटकों के साथ बनाया।
- INS दुनागिरि प्रोजेक्ट 17A का स्टील्थ निर्देशित-मिसाइल फ्रिगेट है, जिसकी लंबाई 149 मीटर और भार 6,670 टन है।
- INS संशोधक संध्यायक श्रेणी का चौथा और अंतिम सर्वेक्षण पोत है।
- INS अग्रे अर्णाला श्रेणी का पनडुब्बी-रोधी उथले जल का पोत है, जिसकी लंबाई 77 मीटर और भार 900 टन है।

□ **S-400**

- 5.43 अरब डॉलर का S-400 सौदा 2018 में पाँच रेजिमेंटों के लिए हस्ताक्षरित हुआ था।
- तीन स्क्वाड्रन पहले शामिल की जा चुकी हैं और पाँचवीं के 2027 में आने की उम्मीद है।
- भारत सुदर्शन चक्र पहल के अंतर्गत एक स्वदेशी वायु रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित कर रहा है।

भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएँ: प्रमुख योजनाएँ

संदर्भ: भारत का लक्ष्य अगले दशक में 40 से 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का है, और चंद्र, सौर तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन एवं सुधार इस लक्ष्य को आकार दे रहे हैं, जैसा कि जून 2026 में चर्चा की गई। नियोजित मिशनों में चंद्रयान-4 नमूना वापसी, JAXA के साथ LUPEX, 2028 में शुक्र ऑर्बिटर मिशन और 2028 में पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल शामिल हैं, जिन्हें IN-SPACe और NSIL का समर्थन प्राप्त है।

□ **मिशन**

- चंद्रयान-4 एक नमूना वापसी मिशन है और LUPEX (चंद्रयान-5) चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर JAXA के साथ सहयोग है।
- शुक्र ऑर्बिटर मिशन 2028 के लिए नियोजित है।
- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 के लिए निर्धारित है।

□ **पारिस्थितिकी तंत्र**

- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप 2014 में 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गए।
- भारत ने 399 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं और 61 देशों के साथ 300 से अधिक समझौते किए हैं।
- सुधारों में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, IN-SPACe और NSIL शामिल हैं; नाविक (NavIC), भुवन और वेदास (VEDAS) नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहन और E100

संदर्भ: मारुति सुज़ुकी ने जून 2026 में भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार लॉन्च की, जो E20 से E100 तक किसी भी एथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर चल सकती है। यह तब हुआ जब भारत ने E100 ईंधन को पूर्ण कानूनी मान्यता दी। एक ईंधन सेंसर एथेनॉल अनुपात का पता लगाता है और इंजन कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन तथा इग्निशन टाइमिंग को समायोजित करती है। लगभग 80 प्रतिशत फ्लेक्स-फ्यूल वाहन बेड़े वाला ब्राज़ील संदर्भ मॉडल है।

□ **मुख्य बिंदु**

- एक ईंधन सेंसर एथेनॉल अनुपात का पता लगाता है और इंजन कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन तथा इग्निशन टाइमिंग को समायोजित करती है।
- एथेनॉल का ऑक्टेन मान पेट्रोल से अधिक किंतु ऊर्जा घनत्व कम होता है, इसलिए माइलेज घटता है।
- चिंताओं में खाद्य बनाम ईंधन की प्रतिस्पर्धा और गन्ने से जल संकट शामिल हैं।
- लगभग 80 प्रतिशत फ्लेक्स-फ्यूल वाहन बेड़े वाला ब्राज़ील संदर्भ मॉडल है।
- भारत में डीज़ल के साथ आइसोब्यूटेनॉल, जो चार कार्बन वाला एल्कोहल है, के मिश्रण की शुरुआत होने की संभावना है।

रक्षा प्रौद्योगिकी: नेत्र FOC, ब्रह्मोस, रुद्रएम-II, LRLACM

संदर्भ: DRDO ने नेत्र AEW&C प्रणाली के लिए अंतिम परिचालन मंजूरी (FOC) प्राप्त की, और भारत ने जून 2026 में शांगरी-ला डायलॉग में वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सौदे पर हस्ताक्षर किए; नई मिसाइल परीक्षणों की भी सूचना मिली। नेत्र एम्ब्रेयर EMB-145I पर AESA रडार के साथ स्वदेशी वायु-जनित पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जबकि परीक्षणों में वायु-से-सतह मिसाइल रुद्रएम-II और लंबी दूरी की भूमि-आक्रमण क्रूज मिसाइल शामिल थीं।

□ **मुख्य बिंदु**

- नेत्र को 2015 में प्रारंभिक परिचालन मंजूरी (IOC) मिली थी और 2017 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था।
- यह ब्राजील के एम्ब्रेयर EMB-145I पर लगा है और AESA रडार का उपयोग करता है; भारत स्वदेशी AEW&C क्षमता वाला पाँचवाँ देश है।
- सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने छह और AEW&C Mk-1A प्रणालियों को मंजूरी दी।
- ब्रह्मोस 2.8 मैक की गति और 290 किमी मारक दूरी वाली सुपरसोनिक मिसाइल है; वियतनाम सौदे पर सिंगापुर में IISS द्वारा आयोजित शांगरी-ला डायलॉग में हस्ताक्षर हुए।
- वायु-से-सतह मिसाइल रुद्रएम-II का उड़ान परीक्षण किया गया; इसे रिसर्च सेंटर इमारत, हैदराबाद ने विकसित किया है।
- लंबी दूरी की भूमि-आक्रमण क्रूज मिसाइल, जो निर्भय की उत्तराधिकारी है, की रिपोर्ट के अनुसार मारक दूरी 1,000 किमी है, और ADE बेंगलुरु इसकी नोडल प्रयोगशाला है।
- रूस ने भारत को संयुक्त उत्पादन के साथ पाँचवीं पीढ़ी का Su-57 देने की पेशकश की।

□ **अभ्यास**

➤ भारत मंगोलिया में आयोजित होने वाले 23वें खान क्वेस्ट में भाग लेगा।

विज्ञान अपडेट: सिंथेटिक बायोलॉजी, IMI सरसों, स्काईकास्ट, JWST

संदर्भ: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कई घटनाक्रमों में IMI-प्रतिरोधी सरसों संकर, IIT मद्रास का ब्रेनस्टेम एटलस ANCHOR, धूमकेतु 3I/ATLAS पर JWST द्वारा मीथेन की पहचान और HIV/AIDS पर संयुक्त राष्ट्र की नई घोषणा शामिल थे।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ उत्परिवर्तन प्रजनन (म्यूटेशन ब्रीडिंग) से विकसित IMI-प्रतिरोधी सरसों संकर ALS एंज़ाइम को बाधित करने वाले शाकनाशियों का प्रतिरोध करते हैं और परजीवी खरपतवार ओरोबैंकी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

➤ भारत ने 2024-25 में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य का करीब 16 मिलियन टन खाद्य तेल आयात किया।

➤ JWST ने पहली बार अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS पर मीथेन की पहचान की; यह लैग्रेंज बिंदु 2 की परिक्रमा करता है।

➤ IIT मद्रास ने ANCHOR बनाया, जो मानव ब्रेनस्टेम का 3D एटलस है और जिसमें 200 से अधिक केंद्रक तथा तंतु पथ हैं।

➤ ICAR-IIOR ने जैव-बहुलक आधारित स्मार्ट बीज लेपन प्रौद्योगिकी विकसित की।

➤ संयुक्त राष्ट्र महासभा की HIV/AIDS घोषणा 2030 के लिए 95-95-95 लक्ष्यों को बनाए रखती है।

विश्व की सबसे बड़ी BESS और हाइड्रोजन संबंधी घटनाक्रम

संदर्भ: अदाणी ग्रीन ने गुजरात के खावड़ा में चीन के बाहर विश्व की सबसे बड़ी एकल-स्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) चालू की, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया; भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से हरी झंडी दिखाई गई।

□ **BESS**

➤ खावड़ा परियोजना 3.37 GWh की है और लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग करती है।

➤ भारत का लक्ष्य 2032 तक 47 GW BESS का है, और इसकी VGF योजना 2030-31 तक 4,000 MWh को समर्थन देती है।

➤ भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

□ **ग्रीन हाइड्रोजन**

➤ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में वित्त वर्ष 2029-30 तक ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।

➤ ग्रीन हाइड्रोजन को ऐसे हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उत्सर्जन 12 महीनों के औसत में प्रति किलोग्राम H2 पर 2 किलोग्राम CO2e से अधिक न हो।

➤ SIGHT इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है; SHIP ₹400 करोड़ की अनुसंधान एवं विकास योजना है।

➤ 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' के अंतर्गत पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद से हरी झंडी दिखाई गई।

➤ जर्मनी की कोराडिया आईलिंट 2018 में विश्व की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन थी।

सेमीकंडक्टर के लिए नीति आयोग का रोडमैप

संदर्भ: नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने जून 2026 में 'फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री' शीर्षक से 10 वर्षीय रोडमैप जारी किया। इसमें 2035 तक 120 से 150 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला की परिकल्पना है, जिसमें भारत उन्नत पैकेजिंग और OSAT में शीर्ष 3 में होगा; यह पाँच स्तंभों पर आधारित है और भारत की 13 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर निर्मित है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ दृष्टिकोण 2035 तक 120 से 150 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का है, जिसमें भारत उन्नत पैकेजिंग और OSAT में शीर्ष 3 में होगा।

➤ इसमें दशक भर में 135 से 180 अरब डॉलर के संचयी निवेश का लक्ष्य है।

➤ यह पाँच स्तंभों पर आधारित है: अग्रणी पहल, नीति और निवेश, उत्पादन, लोग और साझेदारी।

➤ इसमें एक स्वायत्त राष्ट्रीय नोडल एजेंसी और एकल खिड़की मंजूरी का प्रस्ताव है।

➤ भारत में 13 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाएँ हैं और DHRUV64, SHAKTI, AJIT, VIKRAM तथा THEJAS जैसे स्वदेशी प्रोसेसर हैं।

➤ SPECS इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन देता है।

2035 तक जैव-अर्थव्यवस्था के लिए नीति आयोग का रोडमैप

संदर्भ: नीति आयोग ने जुलाई 2026 में 'रोडमैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज़ अ लीडिंग बायोइकोनॉमी पावरहाउस बाय 2035' शीर्षक से एक खाका लॉन्च किया। भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 195.3 अरब डॉलर हो गई, जो GDP का लगभग 4.8

प्रतिशत है, और रोडमैप का लक्ष्य 2035 तक 691 अरब डॉलर है। यह छह राष्ट्रीय बायो-मिशनों और ₹50,000 करोड़ के जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष की अनुशंसा करता है।

□ **स्थिति और लक्ष्य**

➤ जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 195.3 अरब डॉलर हो गई, जो GDP का लगभग 4.8 प्रतिशत है।

➤ लक्ष्य: 2030 तक 392 अरब डॉलर, 2035 तक 691 अरब डॉलर और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन डॉलर।

➤ भारत में लगभग 12,000 बायोटेक स्टार्ट-अप हैं।

□ **अनुशंसाएँ**

➤ छह समर्पित राष्ट्रीय बायो-मिशन।

➤ अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) के ढाँचे के अंतर्गत ₹50,000 करोड़ का जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष।

➤ जैव-विनिर्माण PLI योजना और एक नियामकीय सैंडबॉक्स।

➤ एक राष्ट्रीय बायो-डेटा परिषद और एक जैव-अर्थव्यवस्था निवेश एवं नीति मंच।

□ **विद्यमान पहलें**

➤ BioE3 नीति, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और बायोटेक-किसान।

BFSI के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26

संदर्भ: MeitY, CERT-In, CSIRT-Fin और SISA ने जुलाई 2026 में भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (BFSI) क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 का दूसरा संस्करण जारी किया। भारत में 2025 में 2.9 मिलियन साइबर घटनाएँ दर्ज हुईं, जो 2021 के लगभग 1.4 मिलियन से अधिक हैं, और रिपोर्ट AI फिशिंग, डीपफेक तथा 'चुराओ, बाद में डिक्रिप्ट करो' हमलों के प्रति चेतावनी देती है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत में 2025 में 2.9 मिलियन साइबर घटनाएँ दर्ज हुईं, जो 2021 के लगभग 1.4 मिलियन से अधिक हैं।

➤ आक्रामक AI क्षमताएँ रक्षात्मक क्षमताओं की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही हैं।

➤ खतरों में AI फिशिंग, डीपफेक, कृत्रिम पहचानें, API दुरुपयोग और क्विशिंग शामिल हैं।

➤ 'चुराओ, बाद में डिक्रिप्ट करो' में एन्क्रिप्टेड डेटा चुराया जाता है ताकि भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों से उसे भेदा जा सके।

➤ उल्लंघन तब होते हैं जब चार कमियाँ एक साथ मिलती हैं: डिज़ाइन, प्रवर्तन, संकेत और प्रतिक्रिया।

□ **अनुशंसाएँ**

➤ लचीलापन, पहचान आश्वासन और सतत सत्यापन को प्राथमिकता दें।

➤ DPDP अधिनियम 2023 और DPDP नियम 2025 को लागू करें।

➤ भारत साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय, 2001 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

DRDO ने कुशा लंबी दूरी की SAM का परीक्षण किया

संदर्भ: DRDO ने ओडिशा तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कुशा लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया। इसने एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को भेदा, जो तीव्र गति और अधिक ऊँचाई के खतरे का अनुकरण करता था।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ लंबी दूरी की SAM की मारक सीमा सामान्यतः 200 किमी से अधिक होती है; रूसी S-400 की सीमा 400 किमी है।

➤ कुशा S-400 का पूरक होगी, उसकी जगह नहीं लेगी।

➤ सभी तत्व, मिसाइलें, रडार और कमान एवं नियंत्रण, स्वदेशी हैं।

➤ यह पिछले वर्ष के IADWS परीक्षण पर आधारित है, जो मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है, जो अगले दशक में नियोजित एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा कवच है।

➤ कुशा के तीन इंटरसेप्टर रूप हैं, जिनकी मारक सीमा 150 किमी, 250 किमी और 350-400 किमी है, और यह सुदर्शन चक्र वायु रक्षा छत्र का हिस्सा होगी।

➤ इस परियोजना को हैदराबाद स्थित DRDL के उन्नत हथियार प्रणाली परिसर में S-400 जैसी विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता घटाने वाली परियोजना के रूप में रेखांकित किया गया।

GAGAN के माध्यम से भारत की पहली उपग्रह-आधारित लैंडिंग

संदर्भ: DGCA ने जुलाई 2026 में उदयपुर हवाई अड्डे पर GAGAN का उपयोग करते हुए इंडिगो एयरबस A320 पर भारत की पहली उपग्रह-आधारित लैंडिंग प्रणाली अप्रोच संचालित की। ISRO और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित GAGAN (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) एक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, जो नागरिक उड्डयन के लिए GPS की सटीकता को बढ़ाती है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन ISRO और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। यह नागरिक उड्डयन के लिए GPS की सटीकता बढ़ाने हेतु वास्तविक समय में सुधार और अखंडता संबंधी जानकारी प्रदान करती है।

➤ इसके तत्वों में संदर्भ केंद्र (INRES), मास्टर नियंत्रण केंद्र (INMCC) और अपलिंक केंद्र (INLUS) शामिल हैं।

➤ GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 GAGAN पेलोड वहन करते हैं।

➤ यह अमेरिका की WAAS, यूरोप की EGNOS और जापान की MSAS के साथ अंतर-संचालनीय है।

□ **GAGAN बनाम नाविक (NavIC)**

➤ GAGAN GPS के लिए एक संवर्धन प्रणाली है, जबकि नाविक एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।

➤ नाविक भारत और उसकी सीमा से 1,500 किमी आगे तक के क्षेत्र को कवर करता है।

INS महेंद्रगिरि और INS मालवण कमीशन किए गए

संदर्भ: भारतीय नौसेना ने जुलाई 2026 में विशाखापत्तनम में स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि और कारवार में पनडुब्बी-रोधी उथले जल के पोत INS मालवण को कमीशन किया। INS महेंद्रगिरि प्रोजेक्ट 17A की सात नीलगिरि श्रेणी की फ्रिगेटों में छठी है, जिसे मझगाँव डॉक ने 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया है, जबकि INS मालवण माहे श्रेणी का दूसरा पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है।

□ **INS महेंद्रगिरि**

➤ यह प्रोजेक्ट 17A की सात नीलगिरि श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेटों (CODOG प्रणोदन) में छठी है, जिन्हें डेढ़ वर्ष में शामिल किया गया, और इसे मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स ने बनाया है।

➤ इसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री है, 200 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं, इसका विस्थापन लगभग 6,670 टन है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट है।

➤ यह ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है और इसका नाम पूर्वी घाट की महेंद्रगिरि पर्वत-चोटी के नाम पर रखा गया है।

□ **आईएनएस मालवण**

➤ यह माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी-रोधी युद्धक उथले जल का पोत (ASW-SWC) है, जिसे कोचीन शिपयार्ड ने 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों के साथ बनाया है।

➤ इसका आदर्श वाक्य 'साइलेंट क्लॉज़' (मौन पंजे) है और इसके प्रतीक चिह्न में बाघ नख दर्शाया गया है।

➤ रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2013 में ऐसे 16 पोतों को मंज़ूरी दी, जो कोचीन शिपयार्ड (माहे श्रेणी) और जीआरएसई (अर्नाला श्रेणी) के बीच बाँटे गए।

ISRO का SOLVE मोटर परीक्षण

संदर्भ: ISRO ने श्रीहरिकोटा के स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी में प्रयोगों के लिए उप-कक्षीय प्रक्षेपण यान (SOLVE) के ठोस मोटर का भू-परीक्षण किया। SOLVE गगनयान क्रू मॉड्यूल प्रणालियों के सत्यापन के लिए एक परीक्षण मंच है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ इसका ठोस चरण PSLV के स्ट्रैप-ऑन मोटर से व्युत्पन्न है।

➤ यह क्रू मॉड्यूल को 10-17 किमी की ऊँचाई तक ले जाता है ताकि पलायन, प्रणोदन, पैराशूट अवरोहण और समुद्र में अवतरण का परीक्षण किया जा सके।

➤ गगनयान की मंदन प्रणाली चार प्रकार के 10 पैराशूटों का उपयोग करती है: 2 एपेक्स कवर पृथक्करण, 2 ड्रोग, 3 पायलट और 3 मुख्य।

➤ एकीकृत वायु अवपात परीक्षण में एक डमी क्रू मॉड्यूल को IAF के चिनूक से समुद्र के ऊपर लगभग 3 किमी की ऊँचाई से गिराया जाता है।

WAICO और AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन

संदर्भ: चीन ने जुलाई 2026 में शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (WAICO) की शुरुआत की, जबकि ITU के नेतृत्व वाले AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन ने अपने संस्थापक सदस्यों के नाम घोषित किए। WAICO के 29 सदस्य हैं, जिनमें रूस और पाकिस्तान शामिल हैं, और भारत सदस्य नहीं है। कमीशन के 40 से अधिक संस्थापक सदस्य हैं, जो राष्ट्राध्यक्षों, उद्योग और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हैं।

□ **WAICO**

➤ इसकी औपचारिक स्थापना 16 जुलाई 2026 को हुई, जिसका मुख्यालय शंघाई में है।

➤ इसके 29 सदस्य हैं, जिनमें इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं; भारत सदस्य नहीं है।

➤ इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ की पहुँच के साथ AI सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक AI विनियमन को आकार देना है।

➤ चीन की मूनशॉट AI ने किमी K3 भी प्रस्तुत किया, जो 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर वाला ओपन-वेट मॉडल है।

□ **AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन**

➤ इसके 40 से अधिक संस्थापक सदस्य हैं, जो राष्ट्राध्यक्षों, उद्योग और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से लिए गए हैं, और इसका नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ करता है।

➤ ITU संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1865 में हुई और जिसका मुख्यालय जिनेवा में है।

अंतरिक्ष क्षेत्र: IN-SPACe का पुनः-प्रवेश नियम और पुनरुपयोगी रॉकेट

संदर्भ: IN-SPACe ने जुलाई 2026 में किसी अंतरिक्ष वस्तु के नियोजित पुनः-प्रवेश के लिए अपनी स्वीकृति अनिवार्य कर दी, जबकि जापान की JAXA ने एक पुनरुपयोगी रॉकेट प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। यह नियम भारतीय और गैर-भारतीय संस्थाओं पर, भारतीय क्षेत्र के भीतर या बाहर, लागू होता है, जिसमें अपेक्षित हताहत जोखिम 10,000 में 1 से कम होना चाहिए। IN-SPACe अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त एकल-खिड़की एजेंसी है।

□ **IN-SPACe**

- पुनः-प्रवेश भारतीय क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, भारतीय और गैर-भारतीय संस्थाओं से स्वीकृति आवश्यक है।
- यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एकल-खिड़की एजेंसी है, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है।
- यह ISRO और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करती है।
- अपेक्षित हताहत जोखिम 10,000 में 1 से कम होना चाहिए, और NOTAM तथा NAVAREA चेतावनियों की व्यवस्था 45 दिन पहले करनी होगी।

□ **पुनरुपयोगी रॉकेट**

- JAXA ने पुनरुपयोगी रॉकेट प्रोटोटाइप का पहला लिफ्ट-ऑफ और लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया, और चीन ने अपनी पहली पुनरुपयोगी रॉकेट लैंडिंग हासिल की।
- स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 के साथ परिचालन स्तर पर पुनरुपयोग की अग्रणी शुरुआत की।
- ISRO के RLV कार्यक्रम ने RLV-LEX के माध्यम से स्वायत्त रनवे लैंडिंग का प्रदर्शन किया है।

आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए नीति आयोग का रोडमैप

संदर्भ: नीति आयोग ने जुलाई 2026 में आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप जारी किया। आयुर्वेद निर्यात 2014 में 1.09 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 2.16 अरब डॉलर हो गया, जो लगभग 150 देशों तक पहुँचा, और आयुर्वेद WHO के ICD-11 (मॉड्यूल 2) में शामिल है। रोडमैप वैश्विक आयुर्वेद रजिस्टर, अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों और आयुष वीज़ा पैकेजों की अनुशंसा करता है।

□ **दर्जा**

- निर्यात 2014 में 1.09 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 2.16 अरब डॉलर हो गया और लगभग 150 देशों तक पहुँचा।
- आयुर्वेद WHO के ICD-11 (मॉड्यूल 2) में शामिल है और लगभग 30 देशों में मान्यता प्राप्त है।

□ **अनुशंसाएँ**

- WHO-अनुरूप प्रमाण-पत्रों के साथ एक वैश्विक आयुर्वेद रजिस्टर।
- अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र।
- इकाइयों का WHO-GMP उन्नयन और एक अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेदिक फार्माकोपिया।
- चिकित्सा मूल्य यात्रा केंद्र और आयुष वीज़ा पैकेज।

कलपक्कम में नाभिकीय प्रक्रिया ऊष्मा हाइड्रोजन सुविधा

संदर्भ: परमाणु ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2026 में कलपक्कम में विश्व की पहली नाभिकीय प्रक्रिया ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा के रूप में वर्णित सुविधा का उद्घाटन किया। यह BARC की कॉपर-क्लोरीन ताप-रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करने वाला प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है, जिसमें ऊष्मा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से ली जाती है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह BARC द्वारा विकसित कॉपर-क्लोरीन ताप-रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करने वाला प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है।
- यह कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करता है।
- IGCAR की स्थापना 1971 में हुई थी; FBTR ने 500 MWe प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विकास में सहायता की।
- Cu-Cl चक्र अपेक्षाकृत कम तापमान पर उच्च दक्षता के साथ जल को विघटित करता है।

क्यूडेंगा, ज़ायनिच और कोशिका-जीन थेरेपी नियम

संदर्भ: भारत ने टाकेडा की क्यूडेंगा को मंज़ूरी दी, जो उसका पहला डेंगू टीका है, और औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया गया ताकि उन्नत कोशिका और जीन थेरेपी को एकसमान विनियमन के अंतर्गत लाया जा सके। वॉकहार्ट की ज़ायनिच मई 2026 में अमेरिकी एफडीए की मंज़ूरी पाने वाली पहली ऐसी नई रासायनिक इकाई बनी, जिसे किसी भारतीय दवा कंपनी ने पूरी तरह खोजा, विकसित और व्यावसायीकृत किया।

□ **क्यूडेंगा**

- क्यूडेंगा एक जीवित-क्षीणित चतुर्संयोजी टीका है, जिसे जर्मनी की टाकेडा जीएमबीएच ने पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी से विकसित किया है; यह वेरो कोशिकाओं में DENV-2 आधार पर बनाया जाता है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व-अर्हता प्राप्त है।
- यह 4-60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है, तीन माह के अंतर पर दो खुराकों में दिया जाता है, इसके लिए टीकाकरण-पूर्व जाँच आवश्यक नहीं है, और इसने चारों सीरोटाइप के विरुद्ध 7 वर्ष तक सुरक्षा दिखाई।
- मंज़ूरी डीसीजीआई/सीडीएससीओ से मिली।

□ **औषधि नियम संशोधन**

- कोशिका या स्टेम कोशिका से व्युत्पन्न उत्पाद, जीन चिकित्सीय उत्पाद और ज़ेनोग्राफ्ट अब सीडीएससीओ के केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण ढाँचे के अंतर्गत आते हैं।
- इस ढाँचे में पहले से टीके, बड़ी मात्रा वाले पैरेंटेरल और r-DNA दवाएँ शामिल हैं।

□ **ज़ायनिच**

➤ यह सेफेपाइम और ज़िडेबैक्टम का संयोजन है, जो बीटा-लैक्टम एन्हांसर वर्ग का अंतःशिरा एंटीबायोटिक है।

➤ यह बहुऔषधि-प्रतिरोधी ग्राम-ऋणात्मक जीवाणुओं से होने वाले जटिल मूत्र मार्ग संक्रमणों का उपचार करता है।

डेंगू टीके को मंज़ूरी, निजी टर्बोफैन और क्वांटम चिप

संदर्भ: 2026 के मध्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ सामने आईं। CDSCO ने जुलाई 2026 में टाकेडा की क्यूडेंगा को विपणन प्राधिकरण प्रदान किया, जो भारत में स्वीकृत पहला डेंगू टीका है, और पाणिनियन इंडिया ने यंतुर का अनावरण किया, जो 4.5 kN का टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम है और माना जाता है कि अपनी श्रेणी में भारत का पहला निजी रूप से विकसित टर्बोफैन है। माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2026 में मेजराना 2 टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप प्रस्तुत की।

□ **स्वास्थ्य**

➤ CDSCO ने जुलाई 2026 में टाकेडा की क्यूडेंगा को विपणन प्राधिकरण प्रदान किया, जो चतुर्संयोजी जीवित-क्षीणित टीका है; यह भारत में स्वीकृत पहला डेंगू टीका है।

➤ NABL ने 10 अगस्त 2026 को मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एक प्रत्यायन योजना शुरू की।

□ **प्रौद्योगिकी**

➤ पाणिनियन इंडिया ने यंतुर का अनावरण किया, जो 4.5 kN का टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम है और माना जाता है कि अपनी श्रेणी में भारत का पहला निजी रूप से विकसित टर्बोफैन है।

➤ माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2026 में मेजराना 2 टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप प्रस्तुत की, जिसमें पिछली पीढ़ी की तुलना में विश्वसनीयता में 1,000 गुना वृद्धि का दावा किया गया है।

➤ स्पेसएक्स ने 15 अगस्त 2026 को केवल 38 मिनट के अंतराल पर दो फाल्कन 9 रॉकेट प्रक्षेपित किए, जो किसी एक प्रदाता के लिए रिकॉर्ड है; पिछला रिकॉर्ड 65 मिनट का था।

➤ चीन के नॉर्थवेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने 116 स्वायत्त जलमग्न वाहनों को एक साथ संचालित किया, जो गिनीज़ रिकॉर्ड है।

पिनाका LRGR, अस्त्र और नौसेना अभ्यास

संदर्भ: DRDO ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का परीक्षण किया, इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइलों का पहला खरीदार बना और नौसेना ने जुलाई 2026 में एक बहुराष्ट्रीय तत्परता अभ्यास की मेज़बानी की। पिनाका LRGR का परीक्षण ITR चांदीपुर में 60 किमी पर किया गया, अस्त्र Mk1 दृश्य-सीमा से परे की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 कोच्चि में CTF 154 के अंतर्गत आयोजित हुआ।

□ **रॉकेट और मिसाइल**

➤ पिनाका LRGR का परीक्षण ITR चांदीपुर में 60 किमी पर किया गया; इसकी मारक सीमा 60-120 किमी है।

➤ अस्त्र Mk1 दृश्य-सीमा से परे की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक सीमा 80-110 किमी और गति मैक 4.5 है; इंडोनेशिया इसके लिए अनुबंध करने वाला पहला देश है।

□ **अभ्यास**

➤ नौसेना ने कोच्चि में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की मेज़बानी की, जो भारत में इसका पहला संस्करण है, और यह संयुक्त समुद्री बलों के साथ CTF 154 के अंतर्गत आयोजित हुआ।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

संदर्भ: भारतीय रेलवे ने हरियाणा में उत्तर रेलवे के जींद-सोनीपत खंड पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री ट्रेन शुरू की, जो गैर-विद्युतीकृत मार्गों को कार्बन-मुक्त करने की दिशा में एक कदम है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ इसमें दो हाइड्रोजन चालक शक्ति कार और आठ यात्री डिब्बे हैं, जिनकी क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों की है।

➤ इसकी परिचालन गति लगभग 75 किमी/घंटा है।

➤ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बिजली उत्पन्न करता है; इसका एकमात्र उत्सर्जन जलवाष्प और ऊष्मा है।

➤ लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी अतिरिक्त ऊर्जा और पुनर्योजी ब्रेकिंग से प्राप्त ऊर्जा को संग्रहीत करती है।

➤ जींद में हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और ईंधन भरने की सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।

विक्रम-1: भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट

संदर्भ: स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1, जो भारत का पहला निजी रूप से विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है, ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया। इसका पहला मिशन आगमन था।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह 2022 के उप-कक्षीय विक्रम-S के बाद आया है, जो लगभग 89 किमी तक पहुँचा था।

➤ विक्रम-1 चार चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें तीन ठोस चरण और एक पुनः आरंभ होने योग्य द्रव ऊपरी चरण है।

➤ यह LEO तक 350 किग्रा या सूर्य-समकालिक कक्षा तक 260 किग्रा ले जा सकता है, जिसका लक्ष्य 450 किमी की कक्षा है।

➤ इसकी संरचना पूर्णतः कार्बन संमिश्र (कंपोज़िट) की है और द्रव इंजन 3D-प्रिंटेड हैं।

➤ पेलोड में ग्राहा स्पेस का SOLARAS क्यूबसैट और जर्मनी की डीक्यूब्ड GmbH के कक्षा-प्रदर्शक शामिल थे।

➤ अमेरिका और चीन के बाद भारत निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता दिखाने वाला तीसरा देश बन गया है।

संशोधित एनीमिया मुक्त भारत और SUMAN रोडमैप 2030

संदर्भ: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2026 में एनीमिया मुक्त भारत के परिचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया और मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के लिए SUMAN रोडमैप 2030 लॉन्च किया। 2018 में शुरू की गई संशोधित रणनीति 6x6x6 से बढ़कर 7x7x7 हो गई है, जिसमें कम जन्म भार वाले शिशुओं को सातवें समूह के रूप में जोड़ा गया है, जबकि रोडमैप का लक्ष्य 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 से नीचे लाना है।

□ एनीमिया मुक्त भारत

➤ 2018 में शुरू की गई रणनीति 6x6x6 से बढ़कर 7x7x7 हो गई है, जिसमें कम जन्म भार वाले शिशु (0-6 माह) सातवें समूह के रूप में हैं।

➤ इसमें अंतःशिरा आयरन चिकित्सा और आयरन-प्रबलित खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

➤ एनीमिया 6-59 माह के 67.1 प्रतिशत बच्चों, 59.1 प्रतिशत किशोरियों और 52.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं (15-49 वर्ष) को प्रभावित करता है।

□ SUMAN रोडमैप 2030

➤ इसका लक्ष्य 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 से नीचे लाना है; वर्तमान MMR 87 (2022-24) है।

➤ वर्तमान IMR 24 और NMR 18 है।

➤ यह उत्तर प्रदेश सहित 13 उच्च-प्राथमिकता वाले राज्यों के 130 जिलों को लक्षित करता है।

➤ PMSMA हर माह की 9 तारीख को निःशुल्क प्रसवपूर्व जाँच प्रदान करता है।

इसरो को नासा का मून बेस निमंत्रण

संदर्भ: अगस्त 2026 में बेंगलुरु में 9वीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह बैठक में नासा ने इसरो को आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। भारत 2023 में इन समझौतों का 27वाँ हस्ताक्षरकर्ता बना था। मून बेस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट दीर्घकालिक चौकी बनाना है, जहाँ स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में जल-बर्फ हो सकती है।

□ मुख्य बिंदु

➤ आर्टेमिस समझौते 2020 में स्थापित हुए; भारत 2023 में 27वाँ हस्ताक्षरकर्ता बना और मॉरीशस जुलाई 2026 में 70वाँ।

➤ मून बेस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट दीर्घकालिक चौकी बनाना है, जहाँ स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में जल-बर्फ हो सकती है।

➤ चरण: पहुँच और अधिगम (2029 तक), निर्माण और विस्तार (2029-2032) तथा रहना और कार्य करना (2032 से आगे)।

➤ इसरो चंद्रयान, चंद्रयान-4 नमूना वापसी और गगनयान के माध्यम से योगदान दे सकता है; भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन की योजना बना रहा है।

➤ चीन और रूस अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की योजना बना रहे हैं।

जीसैट-1ए और इसरो की उड़ान में वापसी

संदर्भ: पीएसएलवी-सी61 और सी62 की लगातार विफलताओं के बाद सात माह के अंतराल के पश्चात, इसरो ने अगस्त 2026 में जीएसएलवी-एफ17 पर जीसैट-1ए (ईओएस-05) के साथ प्रक्षेपण फिर शुरू करने की तैयारी की। यह लगभग 36,000 किमी पर भूस्थिर कक्षा से भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है और यह जीसैट-1 (ईओएस-03) का स्थान लेगा, जो 2021 में कक्षा में पहुँचने में विफल रहा था। इसके अनुप्रयोगों में आपदा निगरानी, कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग शामिल हैं।

□ मुख्य बिंदु

➤ यह लगभग 36,000 किमी पर भूस्थिर कक्षा से भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है, जिसका मिशन जीवन 10 वर्ष है। जीएसएलवी-एफ17 श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी की 19वीं उड़ान है।

➤ एक अध्ययन में पाया गया कि 2025 में भारत की प्रक्षेपण लागत निम्न भू-कक्षा (LEO) तक लगभग 13,302 डॉलर प्रति किलोग्राम थी, जबकि वैश्विक औसत 3,868 डॉलर था।

➤ भारत ने 2025 में केवल 5 प्रक्षेपण किए।

➤ यह जीसैट-1 (ईओएस-03) का स्थान लेता है, जो 2021 में कक्षा में पहुँचने में विफल रहा था।

➤ इसके अनुप्रयोगों में आपदा निगरानी, कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग शामिल हैं।

निजी अंतरिक्ष उपलब्धियाँ: एवरेस्ट और पावरबैंक-50

संदर्भ: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने उपलब्धियाँ हासिल कीं। एस्ट्रोबेस ने एवरेस्ट का अनावरण किया, जो देश का पहला निजी रूप से निर्मित पूर्ण-प्रवाह चरणबद्ध दहन इंजन है, और टेकमी2स्पेस के पावरबैंक-50 ने उड़ान अनुभव प्राप्त किया।

□ एवरेस्ट

➤ यह 800 kN का एलओएक्स-मीथेन इंजन है, जिससे भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद एफएफएससी प्रौद्योगिकी वाला चौथा देश बन गया।

➤ यह 70 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी है और इसमें बड़े पैमाने पर 3डी प्रिंटिंग का उपयोग होता है।

- आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हॉट-फायर परीक्षण की योजना है, और पहली उड़ान का लक्ष्य दिसंबर 2028 है।
- इन-स्पेस प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि ₹500 करोड़ की योजना है, जो स्टार्टअप और एमएसएमई को 60 प्रतिशत तक वित्तपोषण देती है, जिसकी सीमा ₹25 करोड़ है।

□ **पावरबैंक-50**

- यह उपग्रह बैटरी पैक 50 Wh से अधिक ऊर्जा संग्रहीत करता है और इसका वज़न 380 ग्राम है।
- इसने आगमन मिशन के दौरान स्काईरूट के विक्रम-1 पर उड़ान अनुभव प्राप्त किया।

भारत से विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार

संदर्भ: भारतीय संस्थानों ने अगस्त 2026 में पशु स्वास्थ्य, वाक् प्रौद्योगिकी और प्रणोदन अनुसंधान में प्रगति की सूचना दी। आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल ने भारत का पहला स्वदेशी जीवित-क्षीणित अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका विकसित किया, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) ने 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए श्रवाणी वाक् पहचान मॉडल बनाया, और डी-प्रोपल्स ने हैदराबाद में डीआरडीओ की एक सुविधा में घूर्णी विस्फोट इंजन का प्रदर्शन किया।

□ **मुख्य बिंदु**

- आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल ने एमए-104 कोशिका रेखा पर आधारित भारत का पहला स्वदेशी जीवित-क्षीणित अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका विकसित किया।
- एएसएफ का भारत में पहली बार 2020 में पता चला था और इसमें मृत्यु दर लगभग 100 प्रतिशत है।
- आईआईएससी की स्पायर लैब ने आर्टपार्क और गूगल के साथ मिलकर श्रवाणी बनाया, जो 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए वाक् पहचान मॉडल है।
- डी-प्रोपल्स ने हैदराबाद में डीआरडीओ की एक सुविधा में घूर्णी विस्फोट इंजन का प्रदर्शन किया।
- हैदराबाद विश्वविद्यालय ने हाइडेरासीन का पेटेंट कराया, जो ठोस रॉकेट प्रणोदकों के लिए बहुलक दहन-दर उत्प्रेरक है।

□ **वैश्विक विज्ञान**

- नासा का नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप 30 अगस्त 2026 को फाल्कन हेवी रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ; इसका दर्पण 2.4 मीटर का है।
- भारत के सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने जर्मनी के डार्मस्टाट स्थित फेयर सुविधा के लिए बीम कैचर डिज़ाइन किए।

रक्षा खरीद और स्वदेशीकरण संबंधी अद्यतन

संदर्भ: भारत ने अग्नि-4 मिसाइल का परीक्षण किया, जैवलिन मिसाइलों के सौदे किए और एमक्यू-9बी ड्रोन पट्टे पर लिए, तथा अगस्त 2026 में नई स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की। सामरिक बल कमान ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि-4 (मारक क्षमता 4,000 किमी तक) का परीक्षण किया, और छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में ₹3,070 करोड़ मूल्य की 405 मदें हैं।

□ **मिसाइलें और मंच**

- सामरिक बल कमान ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि-4 का परीक्षण किया; इसकी मारक क्षमता 4,000 किमी तक है, इसमें दो चरणों वाला ठोस प्रणोदन है और 1,000 किग्रा का पेलोड है।
- भारत ने जैवलिन टैंक-रोधी मिसाइल खरीदने पर सहमति दी, जो दागो और भूल जाओ प्रणाली है, जिसकी प्रभावी मारक दूरी 2.5 किमी है और इसमें 150 मीटर तक ऊपर चढ़ने वाला शीर्ष-प्रहार मोड है।
- रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन 30 माह के लिए पट्टे पर लेने हेतु जनरल एटॉमिक्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ की पारंपरिक मिसाइलों की प्रौद्योगिकी का निजी उद्योग को हस्तांतरण करने की मंज़ूरी दी।

□ **स्वदेशीकरण**

- छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में ₹3,070 करोड़ मूल्य की 405 मदें हैं।
- पिछली पाँच सूचियों में 5,012 मदें थीं, जिनमें से 3,200 पहले ही स्वदेशी हो चुकी हैं।

आईएनएस निपुण और डाइविंग सपोर्ट वेसल

संदर्भ: भारतीय नौसेना ने सितंबर 2026 में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण को कमीशन किया। पहला, आईएनएस निस्तार, जुलाई 2025 में कमीशन हुआ था। डाइविंग सपोर्ट वेसल पनडुब्बी बचाव और निरीक्षण जैसे जटिल जलमग्न अभियानों को सहारा देता है, और 9,000 टन का यह पोत पश्चिमी नौसेना कमान की गहरे समुद्र में गोताखोरी की क्षमता को मज़बूत करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- डाइविंग सपोर्ट वेसल पनडुब्बी बचाव और जलमग्न निरीक्षण जैसे जटिल जलमग्न अभियानों को सहारा देता है।
- 9,000 टन का यह पोत पश्चिमी नौसेना कमान की गहरे समुद्र में गोताखोरी की क्षमता को मज़बूत करेगा।
- नौसेना पहले रूसी मूल के पनडुब्बी बचाव पोतों और तटीय गोताखोरी इकाइयों पर निर्भर थी।

एआई-जनित कृतियों और लेखकत्व पर कॉपीराइट कार्यालय

संदर्भ: भारत के कॉपीराइट कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी एआई प्रणाली को विधिक लेखक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, भले ही एआई-जनित कृति कॉपीराइट के लिए मौलिकता की आवश्यकता पूरी

करती हो। यह निर्णय एआई प्रणाली डेबस (DABUS) से संबंधित था और मौलिकता को लेखकत्व तथा स्वामित्व से अलग करता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- धारा 13 मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों को संरक्षण देती है, लेकिन अधिनियम में मौलिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डी.बी. मोदक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी कृति का नवीन होना आवश्यक नहीं है, परंतु उसमें न्यूनतम स्तर की रचनात्मकता दिखनी चाहिए।
- धारा 2(d)(vi) कंप्यूटर-जनित कृति के लेखक को वह व्यक्ति मानती है जो कृति का सृजन कराता है।
- धारा 17 लेखक को प्रथम स्वामी बनाती है, और धाराएँ 18-19 वैध करारों के माध्यम से कॉपीराइट के समनुदेशन की अनुमति देती हैं।
- चूँकि डेबस का कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं है, वह कॉपीराइट धारण या हस्तांतरित नहीं कर सकता।
- सूर्यास्त मामले में कॉपीराइट कार्यालय ने कलाकार अंकित साहनी के साथ राघव एआई पेंटिंग ऐप को सह-लेखक के रूप में पंजीकृत किया था; बाद में इस पंजीकरण पर प्रश्न उठाया गया।
- अमेरिका में कॉपीराइट के लिए सामान्यतः मानव लेखकत्व आवश्यक है, इसलिए पूर्णतः एआई-जनित कृतियाँ संरक्षित नहीं हैं।
- यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड कंप्यूटर-जनित कृतियों के लेखकत्व को उस व्यक्ति से जोड़ते हैं जो सृजन की व्यवस्था करता है।
- चीन उन एआई-जनित कृतियों को संरक्षण दे सकता है जिनमें मानवीय बौद्धिक निवेश दिखता हो, लेकिन एआई को लेखक नहीं मानता।

ऑस्ट्रेल बेसिन: चंद्रमा का छिपा प्रभाव बेसिन

संदर्भ: अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने सितंबर 2026 में चंद्रयान-1 पर नासा के मून मिनरलॉजी मैपर के आँकड़ों का उपयोग करके पहले से अज्ञात चंद्र प्रभाव बेसिन, ऑस्ट्रेल बेसिन, की पहचान की। यह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा के दक्षिण-पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसके किनारे के अपरदन के कारण पारंपरिक इमेजिंग में छूट गया था, और चंद्रयान-4 जैसे नमूना-वापसी मिशनों का मार्गदर्शन कर सकता है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा के दक्षिण-पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
- समय के साथ इसका किनारा अपरदित हो गया, इसलिए पारंपरिक इमेजिंग इसे नहीं पकड़ सकी।
- यह लगभग 4 अरब वर्ष पुराने दक्षिण ध्रुव-ऐटकेन बेसिन से भी पुराना हो सकता है।
- इसमें कम कैल्शियम वाले, मैग्नीशियम-समृद्ध बेसाल्ट और वृत्ताकार व्यवस्था में 248 छोटे बेसाल्ट तालाब हैं।
- यह चंद्रयान-4 जैसे नमूना-वापसी मिशनों का मार्गदर्शन कर सकता है।

तृष्णा मिशन और सागर मंथन अनुसंधान पोत

संदर्भ: पीएसएलवी अगले वर्ष भारत-फ्रांस के तृष्णा पृथ्वी-प्रेक्षण उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है, जबकि जीआरएसई ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के लिए स्वदेशी महासागर अनुसंधान पोत सागर मंथन लॉन्च किया।

□ **तृष्णा**

- तृष्णा (TRISHNA) का पूर्ण रूप है: उच्च-विभेदन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए तापीय अवरक्त इमेजिंग उपग्रह (Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment)।
- यह इसरो और फ्रांस के सीएनईएस का संयुक्त मिशन है, जो भू-सतह तापमान, वाष्पोत्सर्जन और वनस्पति की निगरानी करेगा।
- सीएनईएस तापीय अवरक्त पेलोड विकसित करता है और इसरो वीएनआईआर-एसडब्ल्यूआईआर पेलोड विकसित करता है।

□ **सागर मंथन**

- इस पोत की लागत ₹840 करोड़ है और इसके 2028 के आरंभ में मिलने की उम्मीद है।
- यह 6 किमी गहराई तक अनुसंधान कर सकता है, जिसमें भूकंपीय और मल्टीबीम सर्वेक्षण तथा सीटीडी प्रोफ़ाइलिंग शामिल हैं।
- यह एयूवी और आरओवी छोड़ेगा तथा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी महासागर को कवर करेगा।

दूरसंचार विभाग का वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक

संदर्भ: दूरसंचार विभाग का वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई), जो मई 2025 में शुरू हुआ, सितंबर 2026 में दी गई सूचना के अनुसार 15 माह में ₹5,000 करोड़ से अधिक के संदिग्ध साइबर-धोखाधड़ी नुकसान को रोकने में सहायक रहा है। एफआरआई मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या अत्यंत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है, ताकि बैंक और यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म संदिग्ध लेन-देन पर चेतावनी दे सकें, उसे विलंबित कर सकें, चिह्नित कर सकें या अस्वीकार कर सकें।

□ **मुख्य बिंदु**

- एफआरआई आई4सी, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, चक्षु, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त इनपुट का उपयोग करके मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या अत्यंत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है।
- इसे 2024 में शुरू हुए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- बैंक और यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म संदिग्ध लेन-देन पर चेतावनी दे सकते हैं, उसे विलंबित कर सकते हैं, चिह्नित कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं।

➤ यह धोखाधड़ी प्रबंधन को प्रतिक्रियात्मक वसूली से सक्रिय रोकथाम की ओर ले जाता है।

राष्ट्रीय औषधि संग्रह (नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया) का 7वाँ संस्करण और जैव-सतर्कता कार्यक्रम

संदर्भ: केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सितंबर 2026 में भारत के रोगी-सुरक्षा तंत्र को व्यापक बनाने के लिए राष्ट्रीय औषधि संग्रह (एनएफआई) का 7वाँ संस्करण जारी किया और जैव-सतर्कता कार्यक्रम की घोषणा की। एनएफआई 2026 में राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची के अनुरूप 653 औषधि मोनोग्राफ हैं, जबकि भारतीय फार्माकोपिया आयोग जैविक उत्पादों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी करने वाले कार्यक्रम का नेतृत्व करेगा।

□ राष्ट्रीय औषधि संग्रह (नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया)

➤ यह पहली बार 1960 में प्रकाशित हुआ था और 2009 से भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है।

➤ एनएफआई 2026 में 34 अध्याय, 20 परिशिष्ट और 653 औषधि मोनोग्राफ हैं, जिनमें 42 निश्चित-खुराक संयोजन और 30 प्रतिरक्षात्मक उत्पाद शामिल हैं।

➤ मोनोग्राफ राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची के अनुरूप हैं।

➤ यह एनएफआई ऑनलाइन के रूप में डिजिटल रूप में उपलब्ध है।

□ जैव-सतर्कता कार्यक्रम

➤ भारतीय फार्माकोपिया आयोग इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेगा।

➤ यह अंग और ऊतक प्रत्यारोपण में प्रयुक्त जैविक उत्पादों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी करता है।

➤ यह दवाओं के लिए फार्माकोविजिलेंस और चिकित्सा उपकरणों के लिए मटेरियोविजिलेंस का पूरक है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर आईसीएमआर का अध्ययन

संदर्भ: 20 तृतीयक-स्तरीय देखभाल अस्पतालों में 2022 से 2025 के बीच भर्ती 1.59 लाख रोगियों को शामिल करने वाला आईसीएमआर का अध्ययन कार्बापेनेम-प्रतिरोधी ग्राम-ऋणात्मक जीवाणुओं से बढ़ते खतरे को रेखांकित करता है।

□ मुख्य बिंदु

➤ रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब सूक्ष्मजीव अपने विरुद्ध प्रयुक्त दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं।

➤ प्रमुख कारकों में एंटीबायोटिक का अविवेकपूर्ण उपयोग, कमजोर संक्रमण नियंत्रण, खराब स्वच्छता और पशुधन में रोगाणुरोधी का उपयोग शामिल हैं।

➤ भारत की प्रतिक्रिया में एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0, आईसीएमआर एएमआर निगरानी नेटवर्क और एनसीडीसी का समन्वय शामिल हैं।

➤ भारत 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण अपनाता है, जो मानव, पशु और पर्यावरण क्षेत्रों को जोड़ता है।

➤ विश्व आर्थिक मंच का एएमआर पर दावोस कॉम्पैक्ट 2050 तक 10 करोड़ से अधिक जीवन बचाने का लक्ष्य रखता है।

➤ प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख भारतीय प्रतिरोधी संक्रमणों से मरते हैं; एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 वर्ष 2025-2029 तक चलेगी।

➤ नैफिथ्रोमाइसिन, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक, 2024 में लॉन्च किया गया।

वैध माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026

संदर्भ: उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने वैध माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित किए, जिससे 'एक राष्ट्र, एक समय' की अवधारणा के तहत आईएसटी आधिकारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय समय संदर्भ बन गया।

□ मुख्य बिंदु

➤ संबंधित प्रणालियों, विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, को आईएसटी से अनुरेखणीय समय का उपयोग करना होगा।

➤ सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला परमाणु घड़ियों के साथ भारत का आधिकारिक समय यूटीसी (एनपीएलआई) के रूप में बनाए रखती है; आईएसटी यूटीसी (एनपीएलआई) में 5 घंटे 30 मिनट जोड़ने के बराबर है।

➤ समय को एनटीपी, पीटीपी, नाविक उपग्रह संपर्कों और व्हाइट रैबिट फाइबर प्रौद्योगिकी के माध्यम से आगे प्रसारित किया जाता है।

➤ वैध माप विज्ञान विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएँ द्वितीयक समय मापक्रमों को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से अनुरेखणीय बनाए रखती हैं।

➤ ये नियम मुख्यतः वित्त, दूरसंचार, विद्युत, रक्षा और अंतरिक्ष को प्रभावित करते हैं, तथा जीपीएस और विदेशी समय सर्वरों पर निर्भरता कम करते हैं।

➤ सर्न द्वारा विकसित व्हाइट रैबिट एकल प्रकाशीय फाइबर पर नैनोसेकंड से भी कम का समकालन प्रदान करता है; बेंगलुरु की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला में एक प्रदर्शन आईएसटी नेटवर्क का उद्घाटन किया गया।

➤ आईएसटी 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो मिर्ज़ापुर से गुज़रता है।

संस्कृति एवं पर्यटन

समसामयिक नोट्स

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और भद्रकाली अभिलेख

संदर्भ: जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जो 1026 ई. में महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के 1,000 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। गुजरात में वेरावल के निकट प्रभास पाटन स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है, और स्थल पर 1169 ई. का भद्रकाली अभिलेख भीमदेव सोलंकी द्वारा इसके निर्माण का उल्लेख करता है।

□ मुख्य बिंदु

- यह गुजरात में वेरावल के निकट प्रभास पाटन में कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है।
- वर्तमान मंदिर मारु-गुर्जर (चालुक्य या सोलंकी) शैली का है, जिसमें गर्भगृह, सभामंडप और नृत्यमंडप, 150 फीट ऊँचा शिखर तथा 10 टन का कलश है।
- कालिदास के रघुवंश, अलबरूनी की किताब-उल-हिंद और अमीर खुसरो की खजाइन-उल-फुतूह में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है।

□ इतिहास

- महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के शासनकाल में 1026 ई. में इस मंदिर पर आक्रमण किया।
- इसे 1297, 1394 और 1706 (औरंगजेब के आदेश पर) में पुनः नष्ट किया गया, और कुल मिलाकर 17 बार लूटा गया।
- अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 1783 में वहाँ एक मंदिर का पुनर्निर्माण कराया।
- सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1947 के बाद इसका पुनर्निर्माण आरंभ कराया और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इसका उद्घाटन किया।

□ भद्रकाली अभिलेख

- प्रभास पाटन में प्राचीन भद्रकाली मंदिर की दीवार में लगा 1169 ई. का एक अभिलेख।
- यह सोलंकी राजा कुमारपाल के आध्यात्मिक गुरु आचार्य भाव-बृहस्पति की प्रशस्ति है।
- इसमें उल्लेख है कि भीमदेव सोलंकी ने मंदिर को सोने, चाँदी, लकड़ी और अंत में पत्थर से बनवाया।

2026-2029 के लिए घोषित संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वर्ष

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र ने 2026 से 2029 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्षों की एक श्रृंखला घोषित की है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष तथा सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी है, 2027 सतत और लचीले पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा, और 2029 क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा।

□ मुख्य बिंदु

- 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है।
- 2026 सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी है।
- 2027 सतत और लचीले पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा।
- 2029 क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा।
- अंतरराष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है।

देवनीमोरी अवशेष, ओल चिकी शताब्दी समारोह और बस्तर पंडुम

संदर्भ: फरवरी 2026 की सांस्कृतिक घटनाओं में श्रीलंका में देवनीमोरी के बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी, स्मारक सिक्के और डाक टिकट के साथ ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह तथा बस्तर पंडुम उत्सव शामिल थे। ये अवशेष गुजरात के अरावली जिले में शामलाजी के निकट देवनीमोरी स्थल से प्राप्त हुए हैं, और मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत में 'दशबल शरीर निलय' अंकित है। बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ में राज्य द्वारा आयोजित एक जनजातीय उत्सव है।

□ देवनीमोरी अवशेष

- ये अवशेष गुजरात के अरावली जिले में शामलाजी के निकट देवनीमोरी स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिसकी पहली खोजबीन 1957 में एस.एन. चौधरी ने की थी।
- मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में 'दशबल शरीर निलय' अंकित है।

□ ओल चिकी और उत्सव

- शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया।
- बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ में राज्य द्वारा आयोजित एक जनजातीय उत्सव है, जिसमें बारह विधाओं के 700 से अधिक कलाकार भाग लेते हैं।

➤ थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती से वेल (भाला) प्राप्त हुआ था।

भारत के राष्ट्रीय दिवस: तिथियाँ और विषय

संदर्भ: भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों को उनकी तिथियों और 2025-26 के विषयों के साथ यहाँ त्वरित पुनरावृत्ति के लिए संकलित किया गया है, क्योंकि ये मिलान वाले प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) स्वामी विवेकानंद को समर्पित है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रतीक है।

□ मुख्य बिंदु

➤ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है; राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को।

➤ राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) स्वामी विवेकानंद को समर्पित है; राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रतीक है।

➤ राष्ट्रीय गणित दिवस (22 दिसंबर) श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है।

➤ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को पड़ता है।

राष्ट्रीय दिवस

दिवस	तिथि	विषय / टिप्पणी
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस	7 नवंबर	-
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	11 नवंबर	-
संविधान दिवस	26 नवंबर	-
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस	2 दिसंबर	हरित भविष्य के लिए टिकाऊ जीवन
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	14 दिसंबर	-
राष्ट्रीय गणित दिवस	22 दिसंबर	-
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस	24 दिसंबर	-
सुशासन दिवस	25 दिसंबर	-
राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी	स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें
राष्ट्रीय बालिका दिवस	24 जनवरी	टिकाऊ भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तीकरण
राष्ट्रीय मतदाता दिवस	25 जनवरी	मेरा भारत, मेरा वोट
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस	25 जनवरी	-
सुरक्षित इंटरनेट दिवस	10 फरवरी	स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प: AI का सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	28 फरवरी	विज्ञान में महिलाएँ: विकसित भारत को गति देना
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस	29 जून	विकास के लिए आँकड़े
कारगिल विजय दिवस	26 जुलाई	-
राष्ट्रीय ध्वज दिवस	22 जुलाई	-
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	7 अगस्त	-
भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस	20 अगस्त	-
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस	23 अगस्त	विकसित भारत की ओर: नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा
राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त	खेलो इंडिया संवाद - खेल की बात पीएम के साथ
राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस	30 अगस्त	-
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस	5 सितंबर	-

भारत जीआई, मिस्र में तमिल ब्राह्मी और ओल चिकी

संदर्भ: फरवरी 2026 में चर्चा में रहीं तीन विरासत संबंधी बातें: भारत जीआई, जो भारत के जीआई उत्पादों के वैश्विक प्रदर्शन के लिए डीपीआईआईटी की एक समग्र पहल है, का अनावरण किया गया; मिस्र की राजाओं की घाटी में पहली से तीसरी शताब्दी ई. के तमिल ब्राह्मी अभिलेख मिले, जिनमें चिकाई कोर्रन जैसे व्यापारियों के नाम हैं; और ओल चिकी लिपि, जिसे रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली के लिए विकसित किया था, ने 100 वर्ष पूरे किए।

□ मुख्य बिंदु

➤ भारत जीआई जीआई उत्पादों के वैश्विक प्रदर्शन के लिए डीपीआईआईटी की एक समग्र पहल है।

➤ मिस्र में मिले तमिल ब्राह्मी अभिलेख पहली से तीसरी शताब्दी ई. के हैं और उनमें चिकाई कोर्रन जैसे व्यापारियों के नाम हैं।

➤ तमिल ब्राह्मी का प्रयोग 300 ई.पू. से 100 ई. के बीच होता था।

➤ ओल चिकी को रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली भाषा के लिए विकसित किया था।

➤ संथाली ऑस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की भाषा है और इसे 92वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।

सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल: एक नज़र में

संदर्भ: सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों, उनकी अवस्थिति, उत्खननकर्ताओं और विशिष्ट विशेषताओं की त्वरित तुलना, जिसे फरवरी 2026 में पुनरावृत्ति के लिए संकलित किया गया। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, हिसार का राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग नहीं था और लोथल में विश्व का सबसे प्राचीन गोदी (डॉकयार्ड) है।

□ मुख्य बिंदु

➤ हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था और यहाँ ताबूत में शवाधान मिलते हैं।

- हिसार का राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है।
- धोलावीरा तीन भागों में विभाजित है और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
- चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग नहीं था।
- लोथल में विश्व का सबसे प्राचीन गोदी (डॉकयार्ड) है।

सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल

स्थल	अवस्थिति और उत्खननकर्ता	प्रमुख विशेषता
हड़प्पा	रावी, पाकिस्तान; दयाराम साहनी (1921)	सबसे पहले खोजा गया स्थल; छह अन्नागार
कालीबंगन	घग्घर, हनुमानगढ़; बी.बी. लाल और बी.के. थापर	सबसे प्राचीन जुता हुआ खेत; अग्निवेदियाँ
बनावली	फतेहाबाद, हरियाणा; आर.एस. बिष्ट (1974)	अरीय (रेडियल) नियोजन; व्यवस्थित जल निकासी का अभाव
राखीगढ़ी	हिसार, हरियाणा	सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल; 350 हेक्टेयर से अधिक
मोहनजोदड़ो	सिंधु, लरकाना; आर.डी. बनर्जी (1922)	विशाल स्नानागार; नर्तकी की मूर्ति
चन्हूदड़ो	सिंध; एन.जी. मजूमदार (1931)	दुर्ग नहीं; मनका निर्माण
सुतकागेन डोर	दश्त नदी, मकरान	सबसे पश्चिमी स्थल; तटीय बंदरगाह
धोलावीरा	खादिर बेट, कच्छ; आर.एस. बिष्ट	तीन भागों वाला नगर; 16 जलाशय
सुरकोटदा	कच्छ; जे.पी. जोशी (1964)	घोड़े की हड्डियाँ
लोथल	खंभात की खाड़ी; एस.आर. राव (1954)	गोदी (डॉकयार्ड); फारस की खाड़ी की मुहर

चपचार कुट और तिरुमंगई आळवार की प्रतिमा की वापसी

संदर्भ: मार्च 2026 में मिज़ोरम ने अपना वसंत उत्सव चपचार कुट मनाया, जो झूम की सफाई के बाद आयोजित होता है, और एशमोलियन संग्रहालय ने संत तिरुमंगई आळवार की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा लौटाई। तिरुमंगई आळवार बारह आळवारों में अंतिम हैं, और उनकी प्रमुख रचना पेरिय तिरुमोळि में 1084 स्तुतियाँ हैं, जो 4,000 स्तुतियों वाले दिव्य प्रबंधम का भाग है।

□ मुख्य बिंदु

- चपचार कुट मिज़ोरम का वसंत उत्सव है, जो झूम की सफाई के बाद मनाया जाता है; इसकी थीम 'ज़ो नुन ज़े मावी - इनरेम्ना' है।
- तिरुमंगई आळवार बारह आळवारों में अंतिम हैं; उनकी प्रमुख रचना पेरिय तिरुमोळि है, जिसमें 1084 स्तुतियाँ हैं।
- दिव्य प्रबंधम में 4,000 तमिल स्तुतियाँ हैं।

विश्व दिवस जनवरी-मार्च 2026: तिथियाँ और विषय

संदर्भ: 2026 की पहली तिमाही में मनाए गए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय दिवसों के नए विषय थे, जिनका उपयोग मिलान वाले प्रश्नों में नियमित रूप से होता है। विश्व जल दिवस (22 मार्च) का केंद्र जल और लैंगिकता है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस (21 मार्च) का केंद्र वन और अर्थव्यवस्थाएँ हैं, और विश्व वन्यजीव दिवस औषधीय एवं सुगंधित पौधों को समर्पित है। ऐसे दिवसों की तिथियाँ और विषय परीक्षा के मानक तथ्य हैं।

□ मुख्य बिंदु

- विश्व जल दिवस (22 मार्च) 2026 का केंद्र जल और लैंगिकता है; अंतरराष्ट्रीय वन दिवस (21 मार्च) का केंद्र वन और अर्थव्यवस्थाएँ हैं।
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का विषय सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई है।
- विश्व वन्यजीव दिवस 2026 औषधीय एवं सुगंधित पौधों को समर्पित है।
- विश्व हिंदी दिवस (10 जनवरी) हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

जनवरी-मार्च 2026 के दिवस

दिवस	तिथि	विषय
विश्व हिंदी दिवस	10 जनवरी	हिंदी: पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक
अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस	24 जनवरी	शिक्षा के सह-सृजन में युवाओं की शक्ति
विश्व कुष्ठ रोग दिवस	25 जनवरी	कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है, असली चुनौती कलंक है
विश्व आर्द्रभूमि दिवस	2 फरवरी	आर्द्रभूमियाँ और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का उत्सव
विश्व कैंसर दिवस	4 फरवरी	विशिष्टता से एकजुट
अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस	4 फरवरी	विभाजन के बजाय संवाद
महिला जननांग विकृति (FGM) के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस	6 फरवरी	2030 की ओर: निरंतर प्रतिबद्धता और निवेश के बिना FGM का अंत नहीं
विश्व दलहन दिवस	10 फरवरी	विश्व की दालें: विनम्रता से उत्कृष्टता तक
विश्व रेडियो दिवस	13 फरवरी	रेडियो और AI: AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं
अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	21 फरवरी	बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़
दुर्लभ रोग दिवस	28 फरवरी	आपकी कल्पना से कहीं अधिक
विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस	1 मार्च	लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरणीय जोखिमों का प्रबंधन
विश्व वन्यजीव दिवस	3 मार्च	औषधीय और सुगंधित पौधे:

		स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण
विश्व मोटापा दिवस	4 मार्च	मोटापे के विरुद्ध कार्रवाई के 8 अरब कारण
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च	अधिकार। न्याय। कार्रवाई। सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए
विश्व निद्रा दिवस	13 मार्च	अच्छी नींद लें, बेहतर जिएँ
अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस	14 मार्च	गणित और आशा
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	15 मार्च	सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता
अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस	20 मार्च	सोशल मीडिया और प्रसन्नता
अंतरराष्ट्रीय वन दिवस	21 मार्च	वन और अर्थव्यवस्थाएँ
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस	21 मार्च	अकेलेपन के विरुद्ध एकजुट
नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस	21 मार्च	राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाना: स्मरणोत्सव के 60 वर्ष
विश्व जल दिवस	22 मार्च	जल और लैंगिकता
विश्व मौसम विज्ञान दिवस	23 मार्च	आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा
विश्व क्षय रोग (TB) दिवस	24 मार्च	हाँ! हम TB को समाप्त कर सकते हैं

पिपरहवा अवशेष और कपिलवस्तु

संदर्भ: पवित्र पिपरहवा अवशेष अप्रैल 2026 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेह पहुँचे। ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरहवा से मिले थे, जिसकी पहचान व्यापक रूप से शाक्य गणराज्य की राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु से की जाती है। इनकी खोज 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने की थी, और इनसे जुड़े रत्न जुलाई 2025 में एक ब्रिटिश परिवार से वापस लाए गए।

□ **मुख्य बिंदु**

- पिपरहवा नेपाल सीमा के निकट स्थित है और इसकी पहचान व्यापक रूप से शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से की जाती है।
- इन अवशेषों की खोज 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने एक स्तूप की खुदाई के दौरान की थी।
- एक मंजूषा पर अंकित ब्राह्मी अभिलेख संकेत देता है कि शाक्यों ने ये अवशेष स्थापित किए थे।
- 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की खुदाई में और अवशेष मिले तथा यह प्रमाणित हुआ कि स्तूप का विस्तार किया गया था, संभवतः मौर्य काल में।
- अवशेषों से जुड़े रत्न और भेंट जुलाई 2025 में एक ब्रिटिश परिवार से वापस लाए गए।

भारत की शैलकृत गुफाएँ

संदर्भ: भारत में मौर्य काल से लेकर प्रारंभिक मध्यकाल तक शैलकृत (चट्टान काटकर बनाए गए) स्थापत्य की समृद्ध परंपरा रही है। प्रमुख गुफा स्थल धर्म, काल और अवस्थिति में भिन्न हैं और विरासत संबंधी प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- बराबर की गुफाएँ (जहानाबाद, बिहार, लगभग 250 ई.पू.) चमकदार दीवारों वाली सबसे प्राचीन शैलकृत गुफाएँ हैं और आजीविक संप्रदाय से संबंधित हैं।
- जोगीमारा गुफाओं (सरगुजा, छत्तीसगढ़, तीसरी शताब्दी ई.पू.) में प्रारंभिक भित्तिचित्र और देवदासी सुतनुका का उल्लेख करने वाला ब्राह्मी अभिलेख है।
- राजा खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख ओडिशा के खुर्दा में उदयगिरि-खंडगिरि में है।
- नासिक की पांडवलेणी गुफाओं में सातवाहनों से संबंधित गौतमी बलश्री का अभिलेख है।
- अजंता गुफाएँ 1983 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और इनमें पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है।
- मुंबई बंदरगाह में स्थित एलीफेंटा गुफाओं में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति है और ये यूनेस्को स्थल हैं।

प्रमुख शैलकृत गुफाएँ

गुफा	स्थान	काल / धर्म	प्रमुख विशेषता
बाघ	धार, मध्य प्रदेश	5वीं-7वीं शताब्दी ई.; महायान बौद्ध धर्म	जातक कथाओं के भित्तिचित्र
उदयगिरि (मध्य प्रदेश)	विदिशा, मध्य प्रदेश	4थी-5वीं शताब्दी ई.; हिंदू धर्म	गुफा 5 में वराह अवतार की मूर्ति
अजंता	छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र	दूसरी शताब्दी ई.पू.-6ठी शताब्दी ई.; अधिकांशतः बौद्ध धर्म	जातक कथाओं के भित्तिचित्र; यूनेस्को 1983
पांडवलेणी	नासिक, महाराष्ट्र	पहली शताब्दी ई.पू.-तीसरी शताब्दी ई.; हीनयान	गौतमी बलश्री का अभिलेख
एलीफेंटा	मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र	5वीं-8वीं शताब्दी ई.; शैव धर्म	त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति
बादामी	बागलकोट, कर्नाटक	6ठी शताब्दी ई.; हिंदू और जैन धर्म	चालुक्यकालीन नक्काशी
बराबर	जहानाबाद, बिहार	लगभग 250 ई.पू.; आजीविक	चमकदार ग्रेनाइट की दीवारें
उदयगिरि-खंडगिरि	खुर्दा, ओडिशा	पहली-दूसरी शताब्दी ई.पू.; जैन धर्म	हाथीगुम्फा अभिलेख
जोगीमारा	सरगुजा, छत्तीसगढ़	तीसरी शताब्दी ई.पू.	सबसे प्राचीन भित्तिचित्र; ब्राह्मी अभिलेख

उंडावल्ली	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	4थी-5वीं शताब्दी ई.	एक ही शिला से बनी शयन मुद्रा में विष्णु

चर्चा में जीआई-टैग वाले उत्पाद: पीलीभीत बाँसुरी से सेलम साबूदाना तक

संदर्भ: मई 2026 में समाचारों में रहे भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों का एक समूह, जिनमें उत्तर प्रदेश की पीलीभीत बाँसुरी शामिल है, जो हस्तनिर्मित बाँस की बाँसुरी है और जिसे 2024 में जीआई टैग मिला। भारत में 650 से अधिक पंजीकृत जीआई टैग हैं, जिनमें तमिलनाडु 56 के साथ अग्रणी है। अन्य उत्पादों में सुलई शहद, मूगा रेशम, वसमत हल्दी, पोंडुरु खादी और सेलम साबूदाना शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- उत्तर प्रदेश की पीलीभीत बाँसुरी को 2024 में जीआई टैग मिला और यह हस्तनिर्मित बाँस की बाँसुरी है।
- जम्मू और कश्मीर के रामबन का सुलई शहद 2021 में टैग प्राप्त कर चुका है।
- जोहा चावल (2017) और मूगा रेशम (2007) असम के उत्पाद हैं; मूगा रेशम को स्वर्ण रेशम कहा जाता है।
- ताई खामती वस्त्र (अरुणाचल प्रदेश) और त्रिपुरा रिसा वस्त्र को 2024 में टैग मिला।
- महाराष्ट्र की वसमत हल्दी (2024) में करक्यूमिन की मात्रा 3-8 प्रतिशत है।
- कोल्हापुर का हुपरी चाँदी शिल्प (2021) घुँघरू और पायल के लिए प्रसिद्ध है।
- आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की पोंडुरु खादी (2025) में कपास की सफाई के लिए वलुगा मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग होता है।
- तमिलनाडु का सेलम साबूदाना (2023) टैपिओका स्टार्च के दाने हैं।

जीआई उत्पाद और राज्य

उत्पाद	राज्य	जीआई वर्ष
पीलीभीत बाँसुरी	उत्तर प्रदेश	2024
सुलई शहद	जम्मू और कश्मीर	2021
जोहा चावल	असम	2017
मूगा रेशम	असम	2007
ताई खामती वस्त्र	अरुणाचल प्रदेश	2024
त्रिपुरा रिसा वस्त्र	त्रिपुरा	2024
वसमत हल्दी	महाराष्ट्र	2024
हुपरी चाँदी शिल्प	महाराष्ट्र	2021
पोंडुरु खादी	आंध्र प्रदेश	2025
सेलम साबूदाना	तमिलनाडु	2023

रू-सोम बेंत पुल, अलगोज़ा और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

संदर्भ: मई 2026 की सांस्कृतिक खबरों में यूनेस्को द्वारा सिक्किम के लेप्चा समुदाय द्वारा बनाए गए रू-सोम बेंत और बाँस के पुलों का दस्तावेजीकरण, अलगोज़ा वादक तगा राम भील को पद्म श्री, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शामिल थे। यह पर्व महमूद गजनवी के 1026 के आक्रमण के 1,000 वर्ष और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में सोमनाथ के पुनः उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

□ **मुख्य बिंदु**

- रू-सोम खंगचेंदज़ोंगा जैवमंडल रिज़र्व में लेप्चा समुदाय द्वारा बनाए गए बेंत और बाँस के पुल हैं; कई पुल 2023 की हिमनद झील विस्फोट बाढ़ में भी टिके रहे।
- अलगोज़ा राजस्थान और पंजाब का एक दोहरी बाँसुरी वाला लोक वाद्य है, जिसे बजाने के लिए वृत्ताकार श्वसन (सर्कुलर ब्रीदिंग) आवश्यक है।
- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महमूद गजनवी के 1026 के आक्रमण के 1,000 वर्ष और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में पुनः उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
- गुजरात में वेरावल के निकट प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है और मारु-गुर्जर (चौलुक्य) शैली में निर्मित है।

उदंत मार्तंड, ह्वेनसांग और सांस्कृतिक पुरस्कार

संदर्भ: हिंदी पत्रकारिता दिवस ने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का स्मरण कराया, भारत और चीन ने ह्वेनसांग के यात्रा-वृत्तांत के लिए संयुक्त यूनेस्को नामांकन पर चर्चा की, और संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कारों की घोषणा की।

□ **मुख्य बिंदु**

- हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, जो कानपुर के अधिवक्ता पंडित जुगल किशोर शुक्ल के अधीन 1826 में कलकत्ता में शुरू हुए उदंत मार्तंड की स्मृति में है।
- ह्वेनसांग ने भारत में 16 वर्ष बिताए, हर्षवर्धन के दरबार में गए, नालंदा में शीलभद्र के अधीन अध्ययन किया और पश्चिमी क्षेत्रों पर 'ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स' (सी-यू-की) लिखा।
- संगीत नाटक अकादमी (स्थापना 1953) ने 2024 और 2025 के लिए फेलोशिप, पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की घोषणा की।
- वीरता पुरस्कार: युद्धकाल के लिए परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र; शांतिकाल के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र।
- मध्य प्रदेश के मांडू की खुरासानी इमली (बाओबाब) को झारखंड के भगैया रेशम, कुचाई रेशम, मुंडा आभूषण और बाँस शिल्प के साथ जीआई टैग मिला।

ज्ञान भारतम मिशन और पांडुलिपि सर्वेक्षण

संदर्भ: जून 2026 में बताया गया कि ज्ञान भारतम पांडुलिपियों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने देशभर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का मानचित्रण कर लिया है। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में 2025 से 2031 के लिए ₹491.66 करोड़ के परिव्यय के साथ की गई थी, जिसका नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है, और कृति संपदा भंडार (रिपॉज़िटरी) पर 44.07 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ दर्ज हैं।

□ मुख्य बिंदु

- इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में 2025 से 2031 के लिए ₹491.66 करोड़ के परिव्यय के साथ की गई थी।
- संस्कृति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है; राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (2003) का पुनर्गठन कर उसे इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में समाहित किया गया है।
- कृति संपदा भंडार (रिपॉज़िटरी) पर 44.07 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ दर्ज हैं।
- पांडुलिपि कम से कम 75 वर्ष पुरानी होनी चाहिए; पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 ऐसी पांडुलिपियों के निजी निर्यात पर रोक लगाता है।

□ यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड

- ऋग्वेद की पांडुलिपियाँ 2007 में सूचीबद्ध की गईं।
- भारत की सबसे प्राचीन गिलगित पांडुलिपियाँ 2017 में सूचीबद्ध की गईं।
- भरतमुनि के नाट्यशास्त्र और भगवद्गीता की पांडुलिपियाँ 2025 में सूचीबद्ध की गईं।

झारखंड के 11 नए जीआई टैग

संदर्भ: जून 2026 में झारखंड के ग्यारह पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिले, जिनमें वस्त्र, शिल्प, चित्रकला और एक मिठाई शामिल हैं। सूची में भोया साड़ी, कुचाई रेशम साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा शिल्प, तुमका चादर, बारोनी चित्रकला, मुंडा आभूषण, झारखंड बाँस शिल्प, तसर रेशम और साड़ियाँ, जादोपटिया चित्रकला तथा पंचो साड़ी और कपड़ा शामिल हैं।

□ मुख्य बिंदु

- कुचाई रेशम सरायकेला-खरसावाँ जिले में तसर रेशम से बनाया जाता है।
- केसरिया कलाकंद कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया से जुड़ा है।
- जादोपटिया शब्द जादू और पट (पटचित्र/स्क्रॉल) से बना है।

□ नए टैग प्राप्त

- भोया साड़ी और कपड़ा, कुचाई रेशम साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा शिल्प और तुमका चादर।
- बारोनी चित्रकला, मुंडा आभूषण, झारखंड बाँस शिल्प, तसर रेशम और साड़ियाँ, जादोपटिया चित्रकला तथा पंचो साड़ी और कपड़ा।

राखीगढ़ी उत्खनन के निष्कर्ष

संदर्भ: जून 2026 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हरियाणा के राखीगढ़ी से मिले लगभग 5,000 वर्ष पुराने कंकालों को वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा। इस अध्ययन का उद्देश्य हड़प्पावासियों की मृत्यु का कारण, वंश, ऊँचाई, सामाजिक स्थिति और चेहरे की बनावट का पता लगाना है। उत्खनन में चित्रित मृद्भांड और बहुउद्देशीय मिट्टी के स्टैंड भी मिले, और कुछ कब्रों में 40 तक मृद्भांड भेंट के रूप में रखे थे, जो पहले के उच्चतम 22 से अधिक है।

□ मुख्य बिंदु

- अध्ययनों से बीमारियों, वंश, ऊँचाई और सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जाएगा।
- चेहरे का पुनर्निर्माण एक प्रमुख उद्देश्य है।
- चित्रित मृद्भांड और बहुउद्देशीय मिट्टी के स्टैंड मिले।
- कुछ कब्रों में 40 तक मृद्भांड भेंट के रूप में रखे थे, जो पहले के उच्चतम 22 से अधिक है।

विश्व दिवस अप्रैल-जून 2026: तिथियाँ और विषय

संदर्भ: अप्रैल से जून 2026 तक मनाए गए अंतरराष्ट्रीय दिवसों के नए विषय थे, जो तिथि-और-विषय वाले प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल) स्वास्थ्य के लिए एकजुटता और विज्ञान के साथ खड़े होने पर बल देता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई) का विषय 'वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य' है, और विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) का विषय 'प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए।' है।

□ मुख्य बिंदु

- विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल) 2026 स्वास्थ्य के लिए एकजुटता और विज्ञान के साथ खड़े होने पर बल देता है।
- अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई) का विषय 'वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य' है।
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) 2026 का विषय: प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए।
- विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस (17 जून) का केंद्र चारागाह भूमियाँ हैं।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) 2026: स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।

अप्रैल-जून 2026 के दिवस

दिवस	तिथि	विषय
विकास और शांति के लिए खेल का अंतरराष्ट्रीय दिवस	6 अप्रैल	खेल: सेतु बनाना, बाधाएँ तोड़ना
विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल	स्वास्थ्य के लिए एकजुट। विज्ञान के साथ खड़े हों

अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल	हमारी शक्ति, हमारा ग्रह
विश्व मलेरिया दिवस	25 अप्रैल	मलेरिया समाप्त करने को संकल्पित: अब हम कर सकते हैं। अब हमें करना होगा
विश्व टीकाकरण सप्ताह	24-30 अप्रैल	हर पीढ़ी के लिए, टीके कारगर हैं
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	26 अप्रैल	-
श्रम दिवस / मई दिवस	1 मई	-
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	3 मई	शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण: मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा
विश्व अस्थमा दिवस	6 मई	अस्थमा से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूजन-रोधी इन्हेलर तक पहुँच
विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस	8 मई	मानवता में एकजुट
विश्व थैलेसीमिया दिवस	8 मई	थैलेसीमिया देखभाल के लिए एकजुट: समानता, पहुँच और आशा
अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस	12 मई	हमारी नर्सें। हमारा भविष्य। सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस	17 मई	उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें
विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस	17 मई	डिजिटल जीवन-रेखाएँ: जुड़े हुए विश्व में लचीलापन मज़बूत करना
अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस	18 मई	विभाजित विश्व को जोड़ते संग्रहालय
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	22 मई	वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य
विश्व तंबाकू निषेध दिवस	31 मई	आकर्षण का पर्दाफ़ाश - निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला
विश्व दुग्ध दिवस	1 जून	महिला किसानों का सम्मान
विश्व साइकिल दिवस	3 जून	हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाएँ
विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून	प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस	7 जून	बोझ से समाधान तक - हर जगह सुरक्षित भोजन
विश्व महासागर दिवस	8 जून	पुनर्कल्पना: हमारे ज्ञात विश्व से परे, महासागर के साथ एक नया संबंध
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस	12 जून	बाल श्रम को रेड कार्ड: बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक कार्य
विश्व रक्तदाता दिवस	14 जून	मानवता की एक बूँद। रक्त दें। जीवन बचाएँ
वैश्विक पवन दिवस	15 जून	हमारी हवा, हमारा समुदाय
विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस	17 जून	चारागाह भूमियाँ: पहचानें। सम्मान करें। पुनर्स्थापित करें
ऑटिस्टिक प्राइड डे	18 जून	ऑटिज़्म चर्चा में है। अब कुछ कर दिखाइए
विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस	19 जून	उत्तरजीविता का अंतर पाटना: सिकल सेल रोग में समानता
विश्व शरणार्थी दिवस	20 जून	तब तक जुड़े रहें जब तक सब सुरक्षित न हो जाएँ
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	21 जून	स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग
विश्व संगीत दिवस	21 जून	एक ऐसा दिन जो हमें एक साथ लाता है
विश्व जलमापन विज्ञान दिवस	21 जून	महासागरीय आँकड़ों को साझा करने के तरीके में बदलाव

हड़प्पाई कलाकृतियाँ और नर्तकी की मूर्ति

संदर्भ: जून 2026 में एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की एक पाठ्यपुस्तक में हड़प्पाई नर्तकी के मूल चित्र को बदला और फिर पुनः बहाल किया, जिससे हड़प्पाई कलाकृतियाँ चर्चा में आ गईं। नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की एक मूर्ति है, जिसका काल लगभग 2600 से 1900 ई.पू. है और जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। अन्य प्रमुख कलाकृतियों में पुरोहित-राजा, पशुपति मुहर और धोलावीरा का खेल-पट्ट शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की एक मूर्ति है, जिसका काल लगभग 2600 से 1900 ई.पू. है; यह जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1926 में खोजी गई थी और नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है।
- मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित-राजा की मूर्ति सेलखड़ी (स्टेटाइट) से बनी है।
- पशुपति मुहर में पशुओं से घिरे एक तीन मुख वाले देवता को दर्शाया गया है।
- मुहरों पर एक अपठित चित्रात्मक लिपि अंकित है, जो बूस्ट्रोफेडन शैली (एक पंक्ति दाएँ से बाएँ, अगली बाएँ से दाएँ) में लिखी गई है।
- कालीबंगन और लोथल में अग्निवेदियाँ मिली हैं; चन्हूदड़ो और लोथल में कार्नेलियन (सुलेमानी) मनके बनाए जाते थे।
- धोलावीरा में पत्थर पर उकेरा हुआ एक खेल-पट्ट मिला है।

जोधपुर मोजड़ी और हिमाचल के उत्पादों को जीआई टैग

संदर्भ: केंद्र ने राजस्थान की लगभग 200 वर्ष पुरानी जोधपुर मोजड़ी को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किया। अलग से, स्पीति सीबकथॉर्न और हिमाचल प्रदेश के सात अन्य पारंपरिक उत्पादों को भी जीआई टैग मिले।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ जीआई का नियमन वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा होता है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में है और पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, जिसका नवीनीकरण हो सकता है।

□ **जोधपुर मोजड़ी**

➤ यह राजस्थान के जोधपुर की हस्तनिर्मित चमड़े की पादुका है, जो जटिल कढ़ाई और मुड़े हुए अग्रभाग के लिए जानी जाती है।

➤ इसे मुख्यतः जिंगर समुदाय बनाता है, जो परंपरागत रूप से काठी बनाने वाले हैं।

□ **हिमाचल के जीआई उत्पाद**

➤ हिमाचल के जीआई: स्पीति सीबकथॉर्न (छरमा), सलूनी सफेद मक्का, चंबा धातु कला, सिरमौरी लोइया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपुवड़ी, किन्नौरी सेब और किन्नौरी आभूषण।

➤ सीबकथॉर्न को हिमालय की स्वर्णिम झाड़ी कहा जाता है; यह 2,500-4,500 मीटर की ऊँचाई पर उगती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और मृदा अपरदन रोकती है।

देवरिया ताल से हड़प्पा के पतन पर पराग अध्ययन

संदर्भ: जुलाई 2026 में बीएसआईपी के वैज्ञानिकों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का पता लगाने के लिए गढ़वाल हिमालय के देवरिया ताल की तलछट में मौजूद पराग का विश्लेषण किया। अध्ययन इंगित करता है कि कमजोर पड़ता भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून सिंधु क्षेत्र में लंबे सूखे और नदी प्रवाह में कमी का कारण बना, जिससे आबादी धीरे-धीरे गंगा के मैदानों की ओर चली गई। यह सभ्यता लगभग 2,000 स्थलों में फैली है, जिसका परिपक्व चरण 2600-1900 ई.पू. का है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह लगभग 2,000 स्थलों में फैली है; भारत में प्रमुख नगरों में राखीगढ़ी और धोलावीरा शामिल हैं। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर सबसे पूर्वी और जम्मू का मांडा सबसे उत्तरी स्थल है।

➤ कमजोर पड़ते भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के कारण सिंधु क्षेत्र में लंबा सूखा पड़ा और नदी प्रवाह घट गया।

➤ आबादी पानी और उपजाऊ भूमि के लिए धीरे-धीरे गंगा के मैदानों की ओर चली गई।

➤ बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त संस्थान है।

➤ चरण: प्रारंभिक 6000-2600 ई.पू., परिपक्व 2600-1900 ई.पू. और उत्तर 1900-1300 ई.पू.।

समरस्य संकल्प अभियान: संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष

संदर्भ: संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती का वर्ष समरस्य संकल्प अभियान के माध्यम से मनाया जाएगा, जो 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा से अगले वर्ष 20 फरवरी को उनकी जयंती तक चलने वाला राष्ट्रीय अभियान है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ रविदास का जन्म 1377 ई. में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, और उन्हें रैदास, रोहिदास और रुहिदास भी कहा जाता है।

➤ रविदास जयंती माघ पूर्णिमा को पड़ती है।

➤ उनके लगभग 41 पद सिख धर्म के आदि ग्रंथ में हैं।

➤ उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और उन्हें रविदासिया धर्म का संस्थापक तथा मीराबाई का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है।

प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेख

संदर्भ: दस प्रमुख प्राचीन अभिलेखों का संकलन, जिसमें शासकों, स्थानों, लिपियों और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया गया है; अगस्त 2026 में संकलित यह सामग्री प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का बार-बार आने वाला स्रोत है। उदाहरणों में गोरखपुर का सोहगौरा ताम्रपत्र, हरिषेण द्वारा समुद्रगुप्त के लिए रचित प्रयाग प्रशस्ति, रविकीर्ति द्वारा पुलकेशिन द्वितीय पर रचित ऐहोल अभिलेख और चोल ग्राम प्रशासन पर उत्तरमेरूर अभिलेख शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ गोरखपुर का सोहगौरा ताम्रपत्र भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख है और इसमें अकाल राहत के लिए राजकीय अन्न भंडारों का उल्लेख है।

➤ प्रयागराज स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिषेण ने की थी और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है।

➤ रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में नर्मदा तट पर पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का वर्णन है।

➤ मस्की अभिलेख में स्पष्ट रूप से 'देवानांपिय असोक' नाम का प्रयोग हुआ है।

➤ उत्तरमेरूर अभिलेख चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन और कुडवोलई गुप्त मतदान प्रणाली का वर्णन करते हैं।

चयनित अभिलेख

अभिलेख	शासक	स्थान
मेहरौली लौह स्तंभ	राजा चंद्र	मेहरौली, दिल्ली
सोहगौरा ताम्रपत्र	मौर्य काल	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
प्रयाग प्रशस्ति	समुद्रगुप्त	प्रयागराज
बेसनगर स्तंभ	हेलियोडोरस	विदिशा, मध्य प्रदेश
जूनागढ़ अभिलेख	रुद्रदामन प्रथम	जूनागढ़, गुजरात
हाथीगुम्फा	खारवेल	उदयगिरि, ओडिशा

कलिंग शिलालेख	अशोक	धौली और जौगढ़, ओडिशा
ऐहोल अभिलेख	पुलकेशिन द्वितीय	ऐहोल, कर्नाटक
मस्की अभिलेख	अशोक	मस्की, कर्नाटक
उत्तरमेरूर अभिलेख	चोल (परांतक प्रथम)	उत्तरमेरूर, तमिलनाडु

विश्व दिवस जून-अगस्त 2026: तिथियाँ और विषय

संदर्भ: जून के अंत से अगस्त 2026 तक के अंतरराष्ट्रीय दिवसों के नए घोषित विषय थे, जो तिथि-और-विषय वाले प्रश्नों के लिए उपयोगी हैं। ओलंपिक दिवस (23 जून) का विषय 'आप यह कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ें।' है, विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) का केंद्र युवाओं की आशाएँ और आकांक्षाएँ हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को पड़ता है, जबकि विश्व सिंह दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाए जाते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- ओलंपिक दिवस (23 जून) 2026: आप यह कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ें।
- मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस (26 जून) विश्व की नशीले पदार्थों की समस्या और अवैध तस्करी से संबंधित है।
- विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) का केंद्र युवाओं की आशाएँ और आकांक्षाएँ हैं।
- अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई), विश्व सिंह दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस (दोनों 10 अगस्त) संरक्षण और ऊर्जा से जुड़ी तिथियाँ हैं।
- अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस (12 अगस्त) का विषय: भिन्न संदर्भ, साझा आकांक्षाएँ।

जून के अंत से अगस्त 2026 के दिवस

दिवस	तिथि	विषय / टिप्पणी
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस	23 जून	सार्वजनिक संस्थाओं का रूपांतरण: नवाचार, भागीदारी और समावेशन को बढ़ावा
ओलंपिक दिवस	23 जून	आप यह कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ें
अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस	23 जून	-
मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस	26 जून	विश्व की नशीले पदार्थों की समस्या: बनी रहने वाले मुद्दे, नई चुनौतियाँ, नवोन्मेषी प्रतिक्रियाएँ
संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस	27 जून	MSME की भावी पीढ़ी; AI-संचालित भविष्य
अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिवस	29 जून	-
अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस	30 जून	-
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस	1 जुलाई	मास्क के पीछे: उपचारकर्ताओं को कौन स्वस्थ करता है?
विश्व ज़ूनोसिस (पशुजन्य रोग) दिवस	6 जुलाई	एक विश्व, एक स्वास्थ्य: ज़ूनोसिस की रोकथाम करें
विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई	आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना
मलाला दिवस	12 जुलाई	-
विश्व युवा कौशल दिवस	15 जुलाई	साझा भविष्य के लिए कौशल
अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस	17 जुलाई	-
नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस	18 जुलाई	-
अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस	20 जुलाई	एक खेल। अनंत संभावनाएँ
अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस	20 जुलाई	एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस / विश्व हेपेटाइटिस दिवस	28 जुलाई	-
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस	29 जुलाई	-
अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस	30 जुलाई	-
विश्व फेफड़ों के कैंसर का दिवस / वर्ल्ड वाइड वेब दिवस	1 अगस्त	-
विश्व के आदिवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस	9 अगस्त	आदिवासी दाइयों का सम्मान: जीवन और कल्याण की रक्षा
विश्व सिंह दिवस / विश्व जैव ईंधन दिवस	10 अगस्त	-
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस	12 अगस्त	भिन्न संदर्भ, साझा आकांक्षाएँ
विश्व हाथी दिवस	12 अगस्त	हाथियों की सहायता के लिए विश्व को एकजुट करना
विश्व अंगदान दिवस	13 अगस्त	-
विश्व फ़ोटोग्राफ़ी दिवस	19 अगस्त	घर
विश्व मानवीय दिवस	19 अगस्त	#मानवता_के_लिए_कार्य_करें
विश्व मच्छर दिवस	20 अगस्त	कोई एकल आधिकारिक विषय नहीं
दास व्यापार और उसके उन्मूलन का स्मरण	23 अगस्त	-
विश्व संस्कृत दिवस	28 अगस्त	-

समाचारों में स्वतंत्रता सेनानी और बौद्ध विरासत

संदर्भ: अगस्त 2026 में ध्वज-निर्माता पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती, गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण और उज्जैन के वैश्य टेकरी में नई खुदाई ने सांस्कृतिक इतिहास को चर्चा में ला दिया। वेंकैया (1876-1963) ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की, उत्कलमणि गोपबंधु दास (1877-1928) ने सत्यवादी विद्यालय की स्थापना की, और मध्य प्रदेश ने 1938-39 की पहली खुदाई के बाद स्तूप स्थल पर नई खुदाई शुरू की।

□ **व्यक्तित्व**

➤ पिंगली वेंकैया (1876-1963) ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की; उन्होंने 1921 के बेज़वाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को एक डिज़ाइन प्रस्तुत किया।

➤ गांधी जी ने सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया; ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया।

➤ उत्कलमणि गोपबंधु दास (1877-1928) ने सत्यवादी विद्यालय और 1919 में समाचार पत्र 'द समाज' की स्थापना की।

□ **वैश्य टेकरी, उज्जैन**

➤ मध्य प्रदेश ने 1938-39 की पहली खुदाई के बाद नई खुदाई शुरू की।

➤ अनुमान है कि स्तूप लगभग 100 फुट ऊँचा है, जो सांची के 54 फुट ऊँचे महान स्तूप से बड़ा है।

➤ स्थानीय परंपरा इस स्थल को देवी से जोड़ती है, जिनसे अशोक विदिशा में मिले थे और जो महेंद्र तथा संघमित्रा की माता बनीं।

नामे डोगरा अक्खर लिपि का पुनरुद्धार

संदर्भ: सितंबर 2026 में जम्मू में नए सार्वजनिक साइनबोर्डों पर देवनागरी और रोमन के साथ नामे डोगरा अक्खर लिपि में भी क्षेत्रों के नाम दिखाए जाने लगे, जो डोगरी लिपि को पुनर्जीवित करने के प्रयास का हिस्सा है। डोगरी 2003 में आठवीं अनुसूची में शामिल हुई और 2020 में जम्मू-कश्मीर की राजभाषा बनी। नामे डोगरा अक्खर टाकरी का परिवर्तित रूप है, जो डोगरी की मूल लिपि थी।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ डोगरी पश्चिमी पहाड़ी समूह की एक इंडो-आर्य भाषा है, जो मुख्यतः जम्मू के डोगरा लोगों द्वारा बोली जाती है।

➤ यह 2003 में आठवीं अनुसूची में शामिल हुई और 2020 में जम्मू-कश्मीर की राजभाषा बनी।

➤ नामे डोगरा अक्खर टाकरी का परिवर्तित रूप है, जो डोगरी की मूल लिपि थी।

➤ 1856 में शासक बने महाराजा रणबीर सिंह के अधीन इसे बनाने के लिए देवनागरी से स्वर-चिह्न लिए गए।

➤ बाद में इसे फ़ारसी के साथ-साथ दरबारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अपनाया गया।

शेखावाटी हवेलियाँ यूनेस्को की संभावित सूची में

संदर्भ: राजस्थान की शेखावाटी हवेलियों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जो विश्व धरोहर का दर्जा पाने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। अलग से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने तेलंगाना के गोल्ला गुड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया।

□ **शेखावाटी हवेलियाँ**

➤ इस सूची में मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर, झुंझुनू और चूरू सहित 14 कस्बों की धरोहर संपत्तियाँ शामिल हैं।

➤ मुख्यतः व्यापारी परिवारों द्वारा बनवाई गई ये हवेलियाँ अपने अग्रभागों, आँगनों और प्रवेश द्वारों पर बने चित्रित भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं।

➤ इन भित्तिचित्रों में धार्मिक विषय, व्यक्ति-चित्र, दैनिक जीवन तथा 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में परिवहन और जीवनशैली में आए बदलाव दर्शाए गए हैं।

□ **गोल्ला गुड़ी मंदिर**

➤ यह तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट में, यूनेस्को स्थल रामप्पा मंदिर के निकट स्थित है और काकतीय काल का है।

➤ यह एक त्रिकूटालय है, जिसमें पूर्वमुखी मंडप तीन गर्भगृहों से घिरा हुआ है।

➤ राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षण प्राप्त होता है।

➤ रामप्पा (रुद्रेश्वर) मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में गणपति देव के सेनापति रेचर्ला रुद्र ने कराया था।

कला प्रदर्शनी और साक्षरता पुरस्कार 2026

संदर्भ: 2026 में सांस्कृतिक पुरस्कार और प्रदर्शनियाँ चर्चा में रहीं। ललित कला अकादमी की 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में 2,495 कलाकारों की 6,175 कलाकृतियाँ प्राप्त हुईं, और राष्ट्रपति मुर्मू ने अक्टूबर 2026 में तीसरे प्रिंट बिएननेल इंडिया के साथ पुरस्कार प्रदान किए। यूनेस्को ने सितंबर 2026 में मेक्सिको के चियापास में छह देशों के छह साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मानित किया, जिसमें किंग सेजोंग पुरस्कार ने मातृभाषा परियोजनाओं को मान्यता दी।

□ **65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी**

➤ ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित; 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,495 कलाकारों की 6,175 कलाकृतियाँ प्राप्त हुईं।

➤ राष्ट्रपति मुर्मू ने 21 अक्टूबर 2026 को डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में तीसरे प्रिंट बिएननेल इंडिया के साथ पुरस्कार प्रदान किए।

□ **यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2026**

➤ 8-9 सितंबर 2026 को मेक्सिको के चियापास में छह देशों के छह कार्यक्रमों को सम्मानित किया गया; विषय: लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता।

➤ किंग सेजोंग पुरस्कार ने कोलंबिया, नीदरलैंड और नाइजीरिया की मातृभाषा परियोजनाओं को मान्यता दी।

विश्व दिवस सितंबर-दिसंबर 2026: तिथियाँ और विषय

संदर्भ: सितंबर से दिसंबर 2026 तक के अंतरराष्ट्रीय दिवसों के नए घोषित विषय थे, जो साक्षरता, शांति, पर्यटन, मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 सितंबर) का विषय 'लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता' है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस (21 सितंबर) का 'शांति में निवेश करें', और विश्व शिक्षक दिवस (5 अक्टूबर) शिक्षकों की

स्थिति संबंधी सिफारिश के 60 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। तिथियाँ और विषय परीक्षा के सामान्य तथ्य हैं।

□ मुख्य बिंदु

- ➤ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 सितंबर): लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता।
- ➤ विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) का केंद्र पर्यटन के पुनर्निर्माण के लिए डिजिटल एजेंडा और AI है।
- ➤ अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस (21 सितंबर): शांति में निवेश करें - सबके लिए, हर जगह, हर दिन।
- ➤ विश्व शिक्षक दिवस (5 अक्टूबर) शिक्षकों की स्थिति संबंधी सिफारिश के 60 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
- ➤ अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस (15 सितंबर) और मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख दिवस हैं।

सितंबर-दिसंबर के दिवस

दिवस	तिथि	विषय
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितंबर	लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस	10 सितंबर	आत्महत्या पर विमर्श बदलना
विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस	12 सितंबर	प्रवासन संदर्भों में प्राथमिक चिकित्सा
अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस	15 सितंबर	मानवाधिकारों को केंद्र में लाएँ
विश्व ओज़ोन दिवस	16 सितंबर	अधिक ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई
विश्व रोगी सुरक्षा दिवस	17 सितंबर	गैर-संचारी रोगों के लिए सुरक्षित देखभाल
अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस	21 सितंबर	शांति में निवेश करें - सबके लिए, हर जगह, हर दिन
विश्व अल्ज़ाइमर दिवस	21 सितंबर	जितनी जल्दी जानेंगे, उतना अधिक कर पाएँगे
विश्व गैंडा दिवस	22 सितंबर	पाँचों को जीवित रखें
विश्व समुद्री दिवस	24 सितंबर	नीति से व्यवहार तक: समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना
विश्व गर्भनिरोधक दिवस	26 सितंबर	कोई बाधा नहीं, केवल विकल्प
विश्व पर्यटन दिवस	27 सितंबर	पर्यटन के पुनर्निर्माण के लिए डिजिटल एजेंडा और AI
विश्व हृदय दिवस	29 सितंबर	एक भी धड़कन न चूकें
अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस	30 सितंबर	भाषाई विविधता और भाषा अधिकार
अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस	2 अक्टूबर	शांति और विकास के साधन के रूप में अहिंसा
विश्व पशु दिवस	4 अक्टूबर	उनकी आँखों से दुनिया देखें
विश्व शिक्षक दिवस	5 अक्टूबर	शिक्षकों के साथ खड़े: पेशे की रक्षा के 60 वर्ष
विश्व डाक दिवस	9 अक्टूबर	एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएँ
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस	10 अक्टूबर	जीवित अनुभवों को सुना गया: वास्तविक आवाज़ें, वास्तविक बदलाव
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस	11 अक्टूबर	बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करें
अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस	13 अक्टूबर	लचीलेपन की शुरुआत घर से होती है
विश्व मानक दिवस	14 अक्टूबर	बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि: SDG 7 पर ध्यान
अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस	15 अक्टूबर	प्रकृति माता की देखभाल करती ग्रामीण महिला किसान
विश्व खाद्य दिवस	16 अक्टूबर	आज नवाचार करें। कल का पोषण करें
अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस	17 अक्टूबर	सबके लिए सुरक्षित घर
विश्व पोलियो दिवस	24 अक्टूबर	पोलियो को इतिहास बना दें
विश्व दयालुता दिवस	13 नवंबर	डिजिटल विश्व में दयालुता
विश्व बाल दिवस	20 नवंबर	मेरा दिन, मेरे अधिकार
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन दिवस	25 नवंबर	महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध डिजिटल हिंसा समाप्त करने के लिए UNiTE
विश्व एड्स दिवस	1 दिसंबर	व्यवधान पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन
अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस	7 दिसंबर	सबके लिए सुरक्षित आकाश और टिकाऊ भविष्य
अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी दिवस	9 दिसंबर	भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट
मानवाधिकार दिवस	10 दिसंबर	मानवाधिकार, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस	12 दिसंबर	वहन से बाहर स्वास्थ्य खर्च
अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस	18 दिसंबर	मेरी महान कहानी: संस्कृतियाँ और विकास

खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व, पुस्तकें एवं रिपोर्ट

समसामयिक नोट्स

56वाँ IFFI गोवा और अन्य फ़िल्म महोत्सव सम्मान

संदर्भ: 2025-26 के दौरान भारत से संबंधित फ़िल्म महोत्सवों के विजेताओं की घोषणा हुई। पणजी में 56वें IFFI (नवंबर 2025) में गोल्डन पीकॉक वियतनाम की 'स्किन ऑफ़ यूथ' को मिला, जिसकी निर्देशक ऐश मेफ़ेयर हैं; नगा फ़िल्मकार थेजा रियो की 'आंग' ने TIFF 2026 में प्लैटफ़ॉर्म पुरस्कार जीता, जो भारत के लिए पहली बार है, और इलैयाराजा को अजंता-एलोरा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में पद्मपाणि पुरस्कार के लिए चुना गया। विजेता परीक्षा के मानक तथ्य हैं।

□ मुख्य बिंदु

- इलैयाराजा को अजंता-एलोरा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (जनवरी-फरवरी 2026) में पद्मपाणि पुरस्कार के लिए चुना गया।
- नगा फ़िल्मकार थेजा रियो की 'आंग' ने TIFF 2026 में प्लैटफ़ॉर्म पुरस्कार जीता, जो भारत के लिए पहली बार है।
- जेम्स ग्रे को 79वें लोकार्नो फ़िल्म महोत्सव (5-15 अगस्त 2026) में कॅरियर पुरस्कार मिला।

□ 56वाँ IFFI, पणजी (20-28 नवंबर 2025)

- गोल्डन पीकॉक: 'स्किन ऑफ़ यूथ' (वियतनाम), निर्देशक ऐश मेफ़ेयर।
- सिल्वर पीकॉक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: संतोष दावखर, 'गोंधल' (मराठी) के लिए।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष): उबेइमार रियोस ('ए पोएट'); (महिला): जारा सोफिया ओस्टान ('लिटिल ट्रबल गर्ल्स')।
- सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़: बंदिश बैंडिट्स सीज़न 2।

नए लोगो: MoSPI और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

संदर्भ: सांख्यिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने प्रत्येक ने नई दृश्य पहचान जारी की। MoSPI ने जनवरी 2026 में अपना लोगो और एक शुभंकर (मैस्कॉट) 'डेटा फ़ॉर डेवलपमेंट' टैगलाइन के साथ जारी किया, और वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) प्रणाली के पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2025 में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक सामान्य लोगो जारी किया। प्रतीकवाद और टैगलाइन संक्षिप्त तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए पसंदीदा हैं।

□ MoSPI का लोगो और शुभंकर (मैस्कॉट)

- 1 जनवरी 2026 को अनावरण; टैगलाइन 'डेटा फ़ॉर डेवलपमेंट'।
- अशोक चक्र सत्य और सुशासन का प्रतीक है; रुपये का चिह्न नियोजन में सांख्यिकी की भूमिका को दर्शाता है।
- रंग: केसरिया, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला; ऊपर की ओर बढ़ती वृद्धि पट्टी प्रगति का संकेत देती है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की NSS शाखा द्वारा जन-संपर्क के लिए नागरिक-अनुकूल शुभंकर (मैस्कॉट) का उपयोग किया जाएगा।

□ RRB के लिए सामान्य लोगो

- वित्त मंत्रालय ने RRB प्रणाली के पुनर्गठन के बाद 18 दिसंबर 2025 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक एकल लोगो जारी किया।
- गहरा नीला रंग वित्त और विश्वास का तथा हरा रंग जीवन और वृद्धि का द्योतक है।

पद्म पुरस्कार 2026 और वीरता पुरस्कार

संदर्भ: जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को मंज़ूरी दी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं, तथा सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे और बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) मामले के अनुसार ये अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ नहीं हैं। वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार होती है।

□ पद्म पुरस्कार

- सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार हैं।
- इसमें 19 महिलाएँ, विदेशी, NRI, PIO या OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं।
- पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।
- 1954 में स्थापित; पद्म विभूषण, भूषण और श्री नाम 1955 में आए; 1978-79 और 1993-97 में पुरस्कार नहीं दिए गए।
- बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ नहीं हैं।
- वार्षिक सीमा 120 पुरस्कार है, जिसमें मरणोपरांत और विदेशी मामले शामिल नहीं हैं।

□ वीरता पुरस्कार

- युद्धकालीन पुरस्कार: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जिनकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई।
- शांतिकालीन पुरस्कार: अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, जिनकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई और 1967 में नाम बदले गए।
- वरीयता क्रम: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र।
- वर्ष में दो बार, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किए जाते हैं।

महिला कबड्डी विश्व कप 2025 और डेफलिम्पिक्स 2025

संदर्भ: भारत ने 17 से 24 नवंबर 2025 तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित दूसरे महिला कबड्डी विश्व कप को जीतकर अपना दूसरा खिताब हासिल किया। नवंबर 2025 में टोक्यो में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत 9 स्वर्ण सहित कुल 20 पदकों के साथ छठे स्थान पर रहा। मेजबान शहर, विजेता और पदक स्थिति अक्सर पूछे जाते हैं।

□ **महिला कबड्डी विश्व कप 2025**

➤ दूसरा संस्करण, ढाका (बांग्लादेश), 17-24 नवंबर 2025।

➤ भारत चैंपियन (दूसरा खिताब); चीनी ताइपे उपविजेता; बांग्लादेश और ईरान ने कांस्य जीता।

➤ सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी (MVP): संजू देवी।

□ **25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025**

➤ टोक्यो, जापान में आयोजित, 15-26 नवंबर 2025।

➤ शीर्ष तीन: यूक्रेन (32 स्वर्ण, कुल 100), अमेरिका, जापान; भारत 9 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य (20) के साथ छठे स्थान पर।

➤ स्वर्ण पदक विजेताओं में दीक्षा डागर (गोल्फ), महित संधू और धनुष श्रीकांत, अनुया प्रसाद, अभिनव देशवाल और प्रांजलि धुमल (निशानेबाजी) तथा सुमित दहिया (कुश्ती 97 किग्रा) शामिल थे।

वैश्विक रिपोर्टें: GEP, ILO ट्रेंड्स और UNCTAD इन्वेस्टमेंट मॉनिटर

संदर्भ: जनवरी 2026 में जारी तीन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में विकास, रोज़गार और विदेशी निवेश पर भारत-विशिष्ट आँकड़े दिए गए। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत अनुमानित है, ILO की एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 वैश्विक अनौपचारिक कार्य को कवर करती है, और UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर दर्शाती है कि 2025 में भारत में FDI 73 प्रतिशत बढ़कर 47 अरब डॉलर हो गया।

□ **ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स (विश्व बैंक)**

➤ वर्ष में दो बार, जनवरी और जून में प्रकाशित होती है।

➤ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो जून 2025 में अनुमानित 6.3 प्रतिशत से अधिक है; इसका कारण मज़बूत घरेलू माँग, उच्च निजी उपभोग, कर सुधार और ग्रामीण वास्तविक आय में वृद्धि है।

➤ वैश्विक व्यापार वृद्धि 2025 में 3.4 प्रतिशत से घटकर 2026 में 2.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

➤ उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी ऋण बढ़कर GDP के लगभग 70 प्रतिशत हो गया है, जो 55 वर्षों में सर्वाधिक है।

□ **एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 (ILO)**

➤ 2015 से 2025 के बीच कामकाजी लोगों में अत्यधिक गरीबी में केवल 3.1 प्रतिशत की कमी आई।

➤ 2026 में विश्व भर में लगभग 2.1 अरब श्रमिकों के अनौपचारिक रोज़गार में होने की उम्मीद है।

➤ वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत है।

□ **वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर (UNCTAD)**

➤ 2025 में भारत में FDI 73 प्रतिशत बढ़कर 47 अरब डॉलर हो गया।

➤ यह वृद्धि वित्त, IT और अनुसंधान एवं विकास (R&D) जैसी सेवाओं में बड़े निवेश, विनिर्माण निवेश में वृद्धि तथा भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने वाली नीतियों से आई।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 और यूनिवर्सिटी गेम्स 2025

संदर्भ: खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत दो बहु-खेल आयोजन हुए: लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विंटर गेम्स, और राजस्थान में यूनिवर्सिटी गेम्स। विंटर गेम्स 2026 जनवरी में लेह और फरवरी में गुलमर्ग में आयोजित हुए, जिनमें सेना पदक तालिका में शीर्ष पर रही। यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए। मेजबान, तिथियाँ और शीर्ष टीमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

□ **खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026**

➤ दो चरणों में आयोजित: लेह (लद्दाख), 20-26 जनवरी 2026, और गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर), 23-26 फरवरी 2026।

➤ शीर्ष तीन: सेना (9 स्वर्ण, कुल 23), हिमाचल प्रदेश (6 स्वर्ण), हरियाणा (4 स्वर्ण)।

□ **खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025**

➤ राजस्थान में आयोजित, 24 नवंबर-5 दिसंबर 2025।

➤ शुभंकर: दो ऊँट, खम्मा और घणी।

➤ शीर्ष तीन: चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (42 स्वर्ण), लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (32 स्वर्ण, 78 पदक), गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (32 स्वर्ण)।

ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 और बूंग के लिए बाफ्टा

संदर्भ: फरवरी 2026 में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी ने 139 देशों से प्राप्त 5,000 से अधिक नामांकनों में से चुने जाने के बाद 10 लाख डॉलर का ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जीता, और मणिपुरी फिल्म बूंग ने लंदन में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता। उनका फाउंडेशन भारत भर में 800 से अधिक केंद्र चलाता है। यह पुरस्कार 2014 में स्थापित हुआ था और GEMS एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।

□ **ग्लोबल टीचर प्राइज़**

➤ उन्हें 139 देशों से प्राप्त 5,000 से अधिक नामांकनों में से चुना गया।

- उनका फाउंडेशन भारत भर में 800 से अधिक केंद्र चलाता है और 'लिविंग वॉल्स ऑफ़ लर्निंग' का उपयोग करता है।
- यह पुरस्कार 2014 में स्थापित हुआ था और GEMS एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे वारके फाउंडेशन और यूनेस्को के साथ मिलकर स्थापित किया गया था।

□ **बाफ्टा**

- बूंग ने यह पुरस्कार लंदन में जीता।
- बाफ्टा ऑस्कर का ब्रिटिश समकक्ष है।

भारत में मृत्युदंड: वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट

संदर्भ: फरवरी 2026 में स्क्वायर सर्कल क्लिनिक ने 'द डेथ पेनल्टी इन इंडिया: एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट (2016-2025)' जारी की, जिसमें मृत्युदंड के दस वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण है। 2016 से 2025 के बीच सत्र न्यायालयों ने 1,279 व्यक्तियों को 1,310 मृत्युदंड सुनाए, और दिसंबर 2025 तक 574 व्यक्ति मृत्युदंड की प्रतीक्षा में थे, जो 2016 के बाद सर्वाधिक है। 2023 से सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की है।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2016 से 2025 के बीच सत्र न्यायालयों ने 822 मामलों में 1,279 व्यक्तियों को 1,310 मृत्युदंड सुनाए।
- दिसंबर 2025 तक 574 व्यक्ति मृत्युदंड की प्रतीक्षा में थे, जो 2016 के बाद सर्वाधिक है।
- उच्च न्यायालयों ने विचार किए गए 842 दंडादेशों में से केवल 70 की पुष्टि की; सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित 153 मामलों में से 19 की पुष्टि की।
- 2023 से सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की है, और उसने 2025 में मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे 10 कैदियों को बरी किया।
- 364 व्यक्तियों को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और बाद में बरी किया गया, जिन्होंने औसतन लगभग 9.4 वर्ष जेल में बिताए।
- 2025 में दस महिलाओं को मृत्युदंड सुनाया गया, जो 2016 के बाद सर्वाधिक है।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 और पावर गैप इंडेक्स

संदर्भ: भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत 39 अंक के साथ 96वें से सुधरकर 91वें स्थान पर पहुँच गया। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स से तैयार पावर गैप इंडेक्स दर्शाता है कि भारत अपनी रणनीतिक क्षमता से नीचे है।

□ **भ्रष्टाचार बोध सूचकांक**

- इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (अत्यंत स्वच्छ) के पैमाने पर जारी किया जाता है।
- डेनमार्क 89 अंक के साथ लगातार आठवीं बार शीर्ष पर रहा।
- वेनेज़ुएला को 10 अंक मिले, जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान को 9-9 अंक मिले।
- सूचकांक में कर धोखाधड़ी, अवैध वित्तीय प्रवाह, धन शोधन और निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार शामिल नहीं हैं।

□ **पावर गैप इंडेक्स**

- यह ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स से लिया गया है, जो 8 विषयगत मापदंडों में 131 संकेतकों पर 27 देशों की रैंकिंग करता है।
- 2025 संस्करण में भारत का पावर गैप स्कोर -4.0 है।

सी. राजगोपालाचारी: राष्ट्रपति भवन में प्रतिमा

संदर्भ: फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो एडविन लुटियंस की प्रतिमा (बस्ट) के स्थान पर लगाई गई है। 1878 में कृष्णगिरि के थोराप्पल्ली में जन्मे राजाजी ने अप्रैल 1930 में दक्षिण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, 1944 में राजाजी फ़ॉर्मूला प्रस्तुत किया और 1948 में माउंटबेटन के उत्तराधिकारी के रूप में गवर्नर-जनरल बने। उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला।

□ **मुख्य बिंदु**

- जन्म 1878 में तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले के थोराप्पल्ली में हुआ।
- अप्रैल 1930 में उन्होंने त्रिची से वेदारण्यम तक दक्षिण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
- 1944 के राजाजी फ़ॉर्मूले में पाकिस्तान पर जनमत संग्रह से जुड़े कांग्रेस-मुस्लिम लीग समझौते का प्रस्ताव रखा गया।
- 1938 में मद्रास के प्रधानमंत्री (प्रीमियर) के रूप में उन्होंने कुओं, विद्यालयों और नौकरियों तक पहुँच में भेदभाव को दंडनीय बनाने वाले कानून का समर्थन किया।
- 1948 में वे माउंटबेटन के उत्तराधिकारी के रूप में गवर्नर-जनरल बने तथा 1950-51 में गृह मंत्री और 1952-54 में मद्रास के मुख्यमंत्री रहे।
- उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला, उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की शुरुआत की और 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता।

आईसीसी प्रतियोगिताएँ 2025-26: टी20 विश्व कप, अंडर-19 और महिला विश्व कप

संदर्भ: भारत ने एक वर्ष के भीतर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, पुरुष अंडर-19 विश्व कप और महिला वनडे विश्व कप जीते। भारत और श्रीलंका ने फरवरी से मार्च 2026 तक 10वें पुरुष टी20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी की, और भारत ने अहमदाबाद में फाइनल में न्यूज़ीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरा खिताब जीता। इंग्लैंड में हुआ महिला टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता।

□ **आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026**

➤ 10वाँ संस्करण, भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त मेजबानी, 7 फरवरी-8 मार्च 2026; 20 टीमें, 55 मैच।

➤ भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में फाइनल में न्यूज़ीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरा खिताब जीता।

➤ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: संजू सैमसन (24 छक्के); फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच: जसप्रीत बुमराह।

➤ सबसे तेज़ अर्धशतक: अभिषेक शर्मा (18 गेंद); सर्वोच्च स्कोर: युवराज समरा (कनाडा, 110)।

□ **आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2026**

➤ ज़िम्बाब्वे और नामीबिया, 15 जनवरी-6 फरवरी; भारत ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 6ठा खिताब जीता; सीरीज़ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: वैभव सूर्यवंशी।

□ **आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025**

➤ 13वाँ संस्करण, भारत द्वारा मेजबानी, 30 सितंबर-2 नवंबर 2025; फाइनल डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में।

➤ भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला खिताब जीता।

□ **आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026**

➤ इंग्लैंड और वेल्स, 12 जून-5 जुलाई; 12 टीमों तक विस्तार; नीदरलैंड ने पदार्पण किया।

➤ ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराकर 7वाँ खिताब जीता; टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेथ मूनी।

ऑस्कर 2026 (98वाँ अकादमी पुरस्कार)

संदर्भ: 98वाँ अकादमी पुरस्कार समारोह मार्च 2026 में लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ, जिसकी मेज़बानी कॉनन ओ'ब्रायन ने की। 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने छह पुरस्कार जीतकर दबदबा बनाया, 'सिनर्स' ने चार और 'फ्रेंकस्टीन' ने तीन पुरस्कार जीते। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि नीरज घेवन की 'होमबाउंड' थी। विजेता, मेज़बान और भारत की प्रविष्टि परीक्षा में फ़िल्म पुरस्कारों के विशिष्ट प्रश्न हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने छह, 'सिनर्स' ने चार और 'फ्रेंकस्टीन' ने तीन पुरस्कार जीते।

➤ भारत की आधिकारिक प्रविष्टि नीरज घेवन की 'होमबाउंड' थी।

प्रमुख विजेता

श्रेणी	विजेता
सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म	वन बैटल आफ्टर अनदर
निर्देशक	पॉल थॉमस एंडरसन
अभिनेता	माइकल बी. जॉर्डन (सिनर्स)
अभिनेत्री	जेसी बकले (हैमनेट)
एनिमेटेड फ़ीचर	के-पॉप डेमन हंटर्स
अंतरराष्ट्रीय फ़ीचर	सेंटिमेंटल वैल्यू (नॉर्वे)
मूल संगीत (ओरिजिनल स्कोर)	लुडविग गोरांसन (सिनर्स)
छायांकन	ऑटम ड्यूरल्ड आर्कापॉ (सिनर्स)
वृत्तचित्र फ़ीचर	मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन

खाद्य सुरक्षा सूचकांक और मार्च 2026 की अन्य रिपोर्टें

संदर्भ: मार्च 2026 में IIED ने 162 देशों का खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, और UNEP ने अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित निपटान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। सूचकांक में वैश्विक औसत स्कोर 6.74 है और भारत का आधार स्कोर 5.31 है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर घटकर 4.96 रहने का अनुमान है। आइसलैंड 9.26 के साथ शीर्ष पर और सोमालिया 1.29 के साथ सबसे नीचे है।

□ **खाद्य सुरक्षा सूचकांक**

➤ वैश्विक औसत स्कोर 6.74 है; भारत का आधार स्कोर 5.31 है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर 4.96 और 2 डिग्री सेल्सियस पर 4.52 रहने का अनुमान है।

➤ आइसलैंड 9.26 के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बेल्जियम हैं; सोमालिया 1.29 के साथ सबसे नीचे है।

□ **UNEP रिपोर्ट**

➤ चार स्तंभ: अपशिष्ट की रोकथाम, वापसी (टेक-बैक) प्रणालियाँ, कानूनी समर्थन और जागरूकता।

➤ भारत के CDSCO दिशानिर्देशों में 17 दवाओं की फ्लश सूची शामिल है।

खेल पुरस्कार 2025-26: नमन, हॉकी इंडिया, लॉरियस, फीफा, विजडन, एफपीएआई

संदर्भ: दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच वार्षिक खेल सम्मानों की घोषणा की गई। कार्लोस अल्कारेज और आर्यना सबालेंका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2026 जीता, उस्मान देम्बेले और ऐताना बोनमती ने द बेस्ट फीफा अवार्ड्स 2025 जीते, और बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुए। पुरस्कारों के नाम और विजेता परीक्षा के मानक तथ्य हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026: कार्लोस अल्कारेज; स्पोर्ट्सवुमन: आर्यना सबालेंका।

➤ द बेस्ट फीफा अवार्ड्स 2025 (16 दिसंबर 2025): उस्मान देम्बेले (पुरुष) और ऐताना बोनमती (महिला)।

➤ विजडन 2026: मिचेल स्टार्क (अग्रणी पुरुष क्रिकेटर), दीप्ति शर्मा (अग्रणी महिला), अभिषेक शर्मा (अग्रणी टी20)।

➤ एफपीएआई अवार्ड्स 2026: लालियनज़ुआला छांगटे (भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर) और मनीषा कल्याण (महिला)।

□ **बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 (15 मार्च, नई दिल्ली)**

➤ पॉली उमरीगर अवार्ड (सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, पुरुष 2024-25): शुभमन गिल।

➤ सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला): स्मृति मंधाना।

➤ कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़।

➤ महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: मिताली राज।

□ **हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 (8वाँ संस्करण, 27 मार्च 2026)**

➤ बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर: हार्दिक सिंह (पुरुष) और नवनीत कौर (महिला)।

➤ बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर: बिछु देवी खरीबम।

➤ मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: जफर इकबाल।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और IOC पात्रता नीति

संदर्भ: मार्च 2026 में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में सात पदक खेलों के साथ आयोजित हुए, और IOC ने 2028 ओलंपिक से महिला स्पर्धाओं को SRY जीन परीक्षण से सत्यापित जैविक महिलाओं तक सीमित कर दिया। IOC की यह नीति अमेरिकी दबाव के बाद आई है। खेलों का शुभंकर (मैस्कॉट) मोरवीर है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ ट्राइबल गेम्स रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में सात पदक खेलों के साथ आयोजित हुए; शुभंकर मोरवीर है।

➤ IOC की नीति 2028 ओलंपिक से प्रभावी होगी और अमेरिकी दबाव के बाद आई है।

पुस्तकें और लेखक: संस्मरण और राजनीतिक जीवनियाँ

संदर्भ: हाल में जारी संस्मरणों, आत्मकथाओं और राजनीतिक जीवनियों का समूह 2025-26 के दौरान चर्चा में रहा और परीक्षा के 'पुस्तकें और लेखक' खंड के लिए उपयोगी है। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा एक छोटे गाँव से राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा का वर्णन करती है, सोनिया गांधी के संस्मरण का शीर्षक 'बिलॉनिंग' है और जनरल एम. एम. नरवणे ने 'फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी' लिखी। पुस्तक-लेखक युग्म एक सामान्य प्रश्न प्रकार हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ रामनाथ कोविंद की आत्मकथा में उनके जीवन और एक छोटे गाँव से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा का वर्णन है; इसका एक हिंदी संस्करण भी आया।

➤ सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलॉनिंग' सार्वजनिक सेवा में उनके जीवन का व्यक्तिगत वृत्तांत है।

➤ पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे ने 'फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी' लिखी, जिसमें उन्होंने अपने सैन्य जीवन का वर्णन किया है।

➤ शिखर धवन की 'द वन' एक क्रिकेट संस्मरण है; हरिंदर बावेजा की कृति संघर्ष क्षेत्रों में उनकी पत्रकारिता का वर्णन करती है।

संस्मरण और जीवनियाँ

पुस्तक	लेखक / संपादक	विषय
ट्रायम्फ ऑफ़ द इंडियन रिपब्लिक: माई लाइफ, माई स्ट्रगल्स	रामनाथ कोविंद	पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा
बिलॉनिंग: ए जर्नी ऑफ़ लव	सोनिया गांधी	संस्मरण
फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी	मनोज मुकुंद नरवणे	पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा
जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू: उदयगिरि से उपराष्ट्रपति तक	यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद	पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी
अग्नि सरस्सुलो विकसिंचिना कमलं द्रौपदी मुर्मु	यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद	राष्ट्रपति मुर्मू की जीवनी (तेलुगु)
अटल बिहारी वाजपेयी: द इटरनल स्टेट्समैन	विजय गोयल	कॉफ़ी-टेबल पुस्तक
एम. एस. स्वामीनाथन: द मैन हू फेड इंडिया	प्रियम्बदा जयकुमार	हरित क्रांति के वैज्ञानिक की जीवनी
इंदिरा गांधी एंड द इयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया	श्रीनाथ राघवन	जीवनी
ए डिफरेंट काइंड ऑफ़ पावर	जैसिंडा अर्डर्न	न्यूज़ीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री का संस्मरण
द वन: क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर	शिखर धवन	क्रिकेट संस्मरण
दे विल शूट यू, मैडम - माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट	हरिंदर बावेजा	पत्रकार का संस्मरण
रामानुजन: जर्नी ऑफ़ ए ग्रेट मैथमेटिशियन	अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा	जीवनी
अपनापन: नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव	शिवराज सिंह चौहान	प्रधानमंत्री के साथ अनुभव
जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा	बंडारू दत्तात्रेय	हरियाणा के राज्यपाल की आत्मकथा
द लाइब्रेरी मैन ऑफ़ इंडिया	पी. पी. सत्यन	पी. एन. पणिक्कर का जीवन
गन्ड डाउन - मर्डर ऑफ़ एन ओलंपिक चैंपियन	संदीप मिश्रा	खेल आधारित गैर-काल्पनिक पुस्तक

मार्च 2026 में नियुक्त राज्यपाल और उपराज्यपाल

संदर्भ: मार्च 2026 में आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राज्यपालों और उपराज्यपालों के फेरबदल की घोषणा की गई। नियुक्तियों में पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि, दिल्ली में तरणजीत सिंह संधू, लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना और बिहार में ले. जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन शामिल थे। राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्तियाँ समसामयिकी का एक मानक प्रश्न हैं।

मार्च 2026 की नियुक्तियाँ

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	नाम
तेलंगाना	शिव प्रताप शुक्ल
पश्चिम बंगाल	आर.एन. रवि
हिमाचल प्रदेश	कविंदर गुप्ता
नगालैंड	नंद किशोर यादव
बिहार	ले. जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन
दिल्ली	तरणजीत सिंह संधू
लद्दाख	विनय कुमार सक्सेना
महाराष्ट्र	जिष्णु देव वर्मा

वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन

संदर्भ: 2026 में विमानन क्षेत्र की दो रैंकिंग जारी की गईं। सिंगापुर चांगी ने मार्च 2026 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में 13वीं बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता, और एतिहाद एयरवेज़ को AirlineRatings.com द्वारा 2026 की विश्व की सबसे सुरक्षित पूर्ण-सेवा एयरलाइन घोषित किया गया, जो इस सूची में शीर्ष पर रहने वाली पहली खाड़ी एयरलाइन है। ऐसे रैंकिंग-शीर्षक विजेता पुरस्कार एवं रैंकिंग खंड में सामान्यतः पूछे जाते हैं।

□ चांगी

- सिंगापुर चांगी ने 18 मार्च 2026 को लंदन में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता, जो उसकी 13वीं जीत है।

□ एतिहाद

- एतिहाद एयरवेज़ को AirlineRatings.com द्वारा 2026 की विश्व की सबसे सुरक्षित पूर्ण-सेवा एयरलाइन घोषित किया गया, जो इसमें शीर्ष पर रहने वाली पहली खाड़ी एयरलाइन है।

साहित्य पुरस्कार 2025: ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी

संदर्भ: मार्च 2026 में आर. वैरामुथु ने ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जीता, रामकुमार मुखोपाध्याय ने बांग्ला उपन्यास हर पार्वती कथा के लिए सरस्वती सम्मान 2025 जीता, और साहित्य अकादमी ने अपने 2025 के पुरस्कारों की घोषणा की। वैरामुथु ज्ञानपीठ जीतने वाले तीसरे तमिल लेखक और कविता के लिए यह पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक हैं। नवतेज सरना ने अंग्रेज़ी में क्रिमसन स्प्रिंग के लिए पुरस्कार जीता।

□ मुख्य बिंदु

- वैरामुथु अकिलन (1975) और जयकांतन (2002) के बाद ज्ञानपीठ जीतने वाले तीसरे तमिल लेखक और कविता के लिए यह पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक हैं।
- ज्ञानपीठ में ₹11 लाख और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है; पहले प्राप्तकर्ता 1965 में जी. शंकर कुरुप थे।
- सरस्वती सम्मान बांग्ला उपन्यास हर पार्वती कथा को मिला; इसमें ₹15 लाख दिए जाते हैं और इसे 1991 में के.के. बिड़ला फाउंडेशन ने स्थापित किया था।
- नवतेज सरना ने अंग्रेज़ी में क्रिमसन स्प्रिंग के लिए पुरस्कार जीता; ममता कालिया ने संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए जीता।

चंद्रशेखर शताब्दी का आरंभ; भारत ट्राइब्स फेस्ट; ब्रेकथ्रू पुरस्कार

संदर्भ: अप्रैल 2026 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 100वें जन्मदिवस वर्ष की शुरुआत हुई, नई दिल्ली में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 आयोजित हुआ, और 2026 के ब्रेकथ्रू पुरस्कारों की घोषणा की गई। चंद्रशेखर नवंबर 1990 से जून 1991 तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। भारत ट्राइब्स फेस्ट का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय ने TRIFED के साथ किया और RISA ब्रांड की शुरुआत की।

□ मुख्य बिंदु

- चंद्रशेखर नवंबर 1990 से जून 1991 तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे और उनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बलिया के इब्राहिमपट्टी गाँव में हुआ था।
- वे 'यंग तुर्क' के सदस्य थे, आपातकाल के दौरान जेल गए और 1983-84 में भारत यात्रा की।
- भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय ने TRIFED के साथ किया और RISA ब्रांड की शुरुआत की।
- ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026 में 30-30 लाख डॉलर के छह पुरस्कार दिए गए; इनकी स्थापना 2013 में मार्क ज़करबर्ग, प्रिसिला चैन, सर्गेई ब्रिन, ऐन वोजिट्स्की तथा यूरी और जूलिया मिल्नर ने की थी।
- महिला भौतिकविदों के लिए एक नए वेरा रुबिन न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार की घोषणा की गई।

पुस्तकें और लेखक: राजनीति, शासन और रक्षा

संदर्भ: लोकतंत्र, न्यायपालिका, लेखा परीक्षा, परिसीमन और रक्षा तैयारियों पर पुस्तकें 2025-26 के दौरान जारी की गईं और वे 'पुस्तकें और लेखक' खंड में आती हैं। कैलाश सत्यार्थी ने 'करुणा: द पावर ऑफ़ कम्पैशन' लिखी, सुधा मूर्ति की 'टाइड्स ऑफ़ टाइम' संसद भवन के भित्तिचित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास बताती है और CDS जनरल अनिल चौहान ने 'रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ।।' लिखी। पुस्तकों का लेखकों से मिलान करना सामान्य है।

□ मुख्य बिंदु

- नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने 'करुणा: द पावर ऑफ़ कम्पैशन' लिखी।

- सुधा मूर्ति की 'टाइड्स ऑफ़ टाइम' संसद भवन के भित्तिचित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास बताती है।
- ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्मारक ग्रंथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया।
- CDS जनरल अनिल चौहान की 'रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट II' भविष्य के लिए तैयार बल के निर्माण से संबंधित है।
- 'द इमरजेंसी डायरीज़' का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया; 'सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ़ स्टूडेंट्स' का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने।

राजनीति, शासन और रक्षा संबंधी शीर्षक

पुस्तक	लेखक / संपादक	विषय
व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स: सिलेक्टेड स्पीचेज़	न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़	न्यायिक भाषण
द वॉइस ऑफ़ जस्टिस: जस्टिस गवई स्पीक्स	संपादक: एस. शिवकुमार	न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के भाषण
डेमोग्राफी, रिप्रेज़ेंटेशन, डिलिमिटेशन: द नॉर्थ-साउथ डिवाइड इन इंडिया	रवि के. मिश्रा	परिसीमन पर बहस
वीआईपी कल्चर इन इंडिया: पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी	नबाम रेबिया और संदीप कुमार	वीआईपी संस्कृति
व्हेन ऑडिट मैटर्स: CAG इंटरवेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस	संपादक: विनोद राय	CAG की भूमिका
इन प्रेज़ ऑफ़ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज़ ऑन इंडियन डेमोक्रेसी	मनोज कुमार झा	गठबंधन की राजनीति
PMO: प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स	हिमांशु रॉय	प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अध्ययन
फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़: आदिवासी हिस्ट्रीज़ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ़ पावर	उमर खालिद	जनजातीय राजनीति
एडवांटेज इंडिया: रीशेपिंग द फ्यूचर फॉर एन इक्विटेबल वर्ल्ड	अनिल के. एंटनी	विदेश नीति और अर्थव्यवस्था
ए सिक्स्थ ऑफ़ ह्यूमैनिटी: इंडिपेंडेंट इंडियाज़ डेवलपमेंट ओडिसी	देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यन	विकास का इतिहास
रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट II: शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स	जनरल अनिल चौहान (CDS)	सैन्य आधुनिकीकरण
टाइड्स ऑफ़ टाइम: संसद के भित्तिचित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास	सुधा मूर्ति	संसद के भित्तिचित्र
दापान: कश्मीर के संघर्ष की कहानियाँ	इप्सिता चक्रवर्ती	कश्मीर
मोदी की नीति शास्त्र: पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में	आदिश सी. अग्रवाला	विदेश नीति
द चीफ़ मिनिस्टर एंड द स्पाई	अमरजीत सिंह दुलत	खुफिया संस्मरण (पूर्व रॉ प्रमुख)
संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय	प्रभात ओझा और राम बहादुर राय द्वारा संकलित	संस्कृति पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण

NCRB की भारत में अपराध 2024 और ADSI रिपोर्ट

संदर्भ: NCRB की भारत में अपराध (Crime in India) 2024 रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल अपराध दर लगभग 6 प्रतिशत घटी, जबकि साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ा। इसकी सहयोगी रिपोर्ट भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएँ (ADSI) 2024 में 1,70,746 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं।

□ भारत में अपराध 2024

- कुल संज्ञेय अपराध 2023 के 62.41 लाख से घटकर 2024 में लगभग 58.86 लाख रह गए, और प्रति लाख जनसंख्या अपराध दर 448.3 से घटकर 418.9 हो गई।
- इस गिरावट का मुख्य संबंध भारतीय न्याय संहिता, 2023 से है, जिसके अंतर्गत साधारण चोट असंज्ञेय हो गई; चोट के मामले 30.58 प्रतिशत घटकर 6.36 लाख से 4.41 लाख रह गए।
- साइबर अपराध के मामले 17.9 प्रतिशत बढ़कर 86,420 से 1,01,928 हो गए, और प्रति लाख दर 6.2 से बढ़कर 7.3 हो गई; लगभग 72.6 प्रतिशत मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी के थे।
- आर्थिक अपराध 4.6 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.14 लाख मामले हो गए, जिनमें जालसाज़ी, छल और धोखाधड़ी लगभग 90 प्रतिशत हैं।
- केरल (94.5 प्रतिशत), पुदुचेरी (91.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (90.6 प्रतिशत) में आरोप-पत्र दाखिल करने की दर सबसे अधिक रही।
- नगालैंड में अपराध दर सबसे कम दर्ज की गई।

□ ADSI 2024 और सड़क दुर्घटनाएँ

- आत्महत्या दर मामूली रूप से घटकर 12.2 प्रति लाख जनसंख्या हो गई।
- लगभग 10 में से 7 पीड़ित पुरुष थे, और दैनिक वेतनभोगी लगभग 31 प्रतिशत (52,910) के साथ सबसे बड़ा समूह थे।
- दहेज से संबंधित आत्महत्याएँ 6.7 प्रतिशत बढ़कर 1,693 हो गईं।
- नशीली दवाओं की अधिक मात्रा से मौतें 50 प्रतिशत बढ़कर 978 हो गईं, जिनमें तमिलनाडु और पंजाब सबसे ऊपर रहे।
- सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.99 लाख लोगों की मृत्यु हुई, यानी प्रतिदिन लगभग 546; सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हुईं; तेज़ गति सबसे बड़ा कारण रही।

नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष 2025-26

संदर्भ: नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कई देशों ने नए राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष चुने, जिनमें बोलीविया, जापान, नीदरलैंड और चिली शामिल हैं। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं, और रॉब जेटेन नीदरलैंड के सबसे युवा तथा पहले खुले तौर पर समलैंगिक

प्रधानमंत्री बने। कौन-सा पद किसके पास है, यह करेंट अफेयर्स का नियमित प्रश्न है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं।

➤ रॉब जेटेन नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं।

शपथ लेने वाले नेता

देश	नेता	पद	समय
बोलीविया	रोड्रिगो पाज़ परेरा	राष्ट्रपति	नवंबर 2025
तंज़ानिया	सामिया सुलुहु हसन	राष्ट्रपति (दूसरा कार्यकाल)	नवंबर 2025
कैमरून	पॉल बिया	राष्ट्रपति (आठवाँ कार्यकाल)	नवंबर 2025
चेक गणराज्य	आंद्रेज बाबिश	प्रधानमंत्री	दिसंबर 2025
जापान	साने ताकाइची	105वें प्रधानमंत्री	2026
यमन	शाया मोहसेन अल-ज़िंदानी	प्रधानमंत्री	जनवरी 2026
नीदरलैंड	रॉब जेटेन	प्रधानमंत्री	फरवरी 2026
चिली	जोसे एंटोनियो कास्ट	38वें राष्ट्रपति	मार्च 2026
मंगोलिया	उचराल न्यामोसोर	प्रधानमंत्री	मार्च 2026
इराक	निज़ार अमेदी	राष्ट्रपति	अप्रैल 2026
वियतनाम	तो लाम	राष्ट्रपति (5 वर्ष का कार्यकाल)	अप्रैल 2026
म्यांमार	मिन आंग ह्लाइंग	राष्ट्रपति	अप्रैल 2026
जिबूती	इस्माइल उमर गुएल्लेह	राष्ट्रपति (छठा कार्यकाल, 97.81%)	अप्रैल 2026
हंगरी	पीटर मैगयार (तिस्ज़ा पार्टी)	प्रधानमंत्री	मई 2026
बुल्गारिया	रूमेन रादेव	प्रधानमंत्री	मई 2026
बेनिन	रोमुआल्ड वाडाग्री	राष्ट्रपति (तालोन के उत्तराधिकारी)	मई 2026
युगांडा	योवेरी मुसेवेनी	राष्ट्रपति (सातवाँ कार्यकाल)	मई 2026
डेनमार्क	मेटे फ्रेडरिक्सन	प्रधानमंत्री (तीसरा कार्यकाल)	जून 2026
स्लोवेनिया	यानेज़ यांशा	प्रधानमंत्री (चौथा कार्यकाल)	जून 2026
दक्षिण कोरिया	हान सेओंग-सूक	प्रधानमंत्री	जून 2026
यूनाइटेड किंगडम	एंडी बर्नहम	प्रधानमंत्री (स्टार्मर के उत्तराधिकारी)	जुलाई 2026
यूक्रेन	सेर्ही कोरेत्स्की	प्रधानमंत्री (स्विरिदेंको के उत्तराधिकारी)	जुलाई 2026
पेरू	केइको फुजिमोरी	राष्ट्रपति	जुलाई 2026
हंगरी	आंद्रास बाका	राष्ट्रपति	अगस्त 2026
कोलंबिया	अबेलार्दो दे ला एस्प्रिएला	राष्ट्रपति (2026-30)	अगस्त 2026
बांग्लादेश	मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर	23वें राष्ट्रपति	अगस्त 2026
ज़ाम्बिया	हाकैंडे हिचिलेमा	राष्ट्रपति (दूसरा कार्यकाल)	सितंबर 2026
मोरक्को	फ़ातिमा ज़हरा अल-मंसूरी	पहली महिला प्रधानमंत्री	सितंबर 2026

पर्यावरण एवं विज्ञान पुरस्कार 2026

संदर्भ: 2026 में पारिस्थितिकी और विज्ञान की उपलब्धियों को सम्मानित करने वाले पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिनमें भारतीय विजेता भी रहे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार (ग्रीन नोबेल) पहली बार पूरी तरह महिलाओं को मिला, जो अप्रैल 2026 में सैन फ्रांसिस्को में प्रदान किया गया, और एक भारतीय टीम ने पहली बार द अर्थ प्राइज़ जीता। चंद्रयान-3 ने 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार जीता, और महेश काकडे (IISc) ने युवा गणितज्ञों के लिए 2026 का रामानुजन पुरस्कार जीता।

□ **पर्यावरण**

➤ गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 (ग्रीन नोबेल) पहली बार पूरी तरह महिलाओं को मिला; 20 अप्रैल 2026 को सैन फ्रांसिस्को में प्रदान किया गया।

➤ टायलर पुरस्कार: टोबी कीयर्स को भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध के लिए (जनवरी 2026)।

➤ द अर्थ प्राइज़ 2026: विवान छाछड़िया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, पहली भारतीय टीम, सूक्ष्म प्लास्टिक हटाने वाले 'प्लास-स्टिक' के लिए।

➤ व्हिटली अवार्ड्स (ग्रीन ऑस्कर) 2026: परवीन शेख और बरखा सुब्बा छह विजेताओं में शामिल थीं; प्रत्येक को 50,000 पाउंड मिलते हैं।

□ **विज्ञान**

➤ चंद्रयान-3 ने AIAA से 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार जीता।

➤ महेश काकडे (IISc) ने युवा गणितज्ञों के लिए 2026 का रामानुजन पुरस्कार जीता, जो पाँचवें भारतीय पुरस्कार विजेता हैं (10,000 डॉलर; ICTP और IMU)।

➤ दीपक धर को 2026 का ICTP डिराक पदक मिला।

➤ भारत ने रोमानिया में 2026 अंतरराष्ट्रीय भाषाविज्ञान ओलंपियाड में 1 स्वर्ण, 3 कांस्य और एक सराहनीय उल्लेख जीता।

➤ 36वें इग नोबेल पुरस्कार ज्यूरिख में कवक (फफूंद) विषय के साथ आयोजित हुए।

पुस्तकें और लेखक: कथा-साहित्य, अध्यात्म और अन्य कृतियाँ

संदर्भ: 2025-26 के दौरान साहित्यिक, आध्यात्मिक और विविध कृतियाँ चर्चा में रहीं और वे 'पुस्तकें और लेखक' खंड में शामिल हैं। किरण देसाई की 'द लोनलीनेस ऑफ़ सोनिया एंड सनी' इस वर्ष के प्रमुख उपन्यासों में से एक है, क्रिस्चियन डेवनपोर्ट की 'रॉकेट ड्रीम्स' मस्क और बेज़ोस की नई वाणिज्यिक अंतरिक्ष होड़ पर आधारित है, और कई कृतियाँ इस्कॉन के

संस्थापक श्रील प्रभुपाद के जीवन पर केंद्रित हैं। पुस्तक-लेखक का मिलान करना परीक्षा में पूछा जाने वाला सामान्य प्रश्न-प्रकार है।

□ **मुख्य बिंदु**

- किरण देसाई की 'द लोनलीनेस ऑफ़ सोनिया एंड सनी' इस वर्ष के प्रमुख उपन्यासों में से एक है।
- क्रिस्चियन डेवनपोर्ट की 'रॉकेट ड्रीम्स' मस्क और बेज़ोस की नई वाणिज्यिक अंतरिक्ष होड़ पर आधारित है।
- कई कृतियाँ इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के जीवन और विरासत पर केंद्रित हैं।
- 'जेन वी बनो और महात्मा' का विमोचन केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया।

अन्य कृतियाँ

पुस्तक	लेखक	टिप्पणी
द लोनलीनेस ऑफ़ सोनिया एंड सनी	किरण देसाई	उपन्यास
अंतिम दिन ('द लास्ट डे' का हिंदी अनुवाद)	यारोस्लावस मेलनिकास	अनूदित उपन्यास
रॉकेट ड्रीम्स	क्रिस्चियन डेवनपोर्ट	अंतरिक्ष होड़
करुणा: द पावर ऑफ़ कम्पैशन	कैलाश सत्यार्थी	करुणा और सक्रियता
डिफ़रेंट बट नो लेस	अनुपम खेर	संस्मरण
डांसिंग विद जॉय	डॉ. आनंद शंकर जयंत	नृत्य
विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद	डॉ. उषा उपाध्याय	आध्यात्मिक जीवनी
सिंग, डांस एंड लीड	हिंडोल सेनगुप्ता	प्रभुपाद से नेतृत्व के सबक
महात्मा: ए ग्रेट कम्युनिकेटर	डॉ. धीरज काकड़िया	संप्रेषक के रूप में गांधी
हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड	प्रेम प्रकाश	इतिहास
पलानीवेलु गट्स	डॉ. सी. पलानीवेलु	सर्जन की आत्मकथा
कन्फ़ेशंस ऑफ़ ए शेक्सपियर एडिक्ट	वी. एस. रवि	साहित्यिक निबंध
विन द बैटल ऑफ़ योर माइंड इन द एज ऑफ़ सोशल मीडिया	रीता रामामूर्ति गुप्ता	आत्म-सुधार
क्लुक्ड सीड्स	कैरेन जेनिंग्स	उपन्यास
जॉन एंड पॉल: ए लव स्टोरी इन सॉन्ग्स	इयान लेस्ली	संगीत

भारत के शतरंज ग्रैंडमास्टर 2026 और युवा उपलब्धिधारी

संदर्भ: भारत ने 2025-26 में कई नए ग्रैंडमास्टर जोड़े, जिससे उसकी कुल संख्या लगभग 100 हो गई। आर्यन वार्ष्णेय जनवरी 2026 में 92वें GM बने, मयंक चक्रवर्ती 94वें और असम तथा पूर्वोत्तर के पहले GM बने, और गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज़ जून 2026 में 96वें GM बने। इंग्लैंड की बोधना शिवानंदन 11 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंडमास्टर बनीं।

□ **मुख्य बिंदु**

- आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें GM बने (जनवरी 2026); मयंक चक्रवर्ती 94वें और असम/पूर्वोत्तर के पहले GM बने।
- एथन वाज़ (गोवा, 14 वर्ष) जून 2026 में 96वें GM बने; जी.बी. हर्षवर्धन 97वें, अश्वथ एस. 98वें, वी.एस. रथनवेल 99वें।
- बोधना शिवानंदन (इंग्लैंड, आयु 11 वर्ष) सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंडमास्टर बनीं।

भारत में जेल सांख्यिकी 2024

संदर्भ: मई 2026 में NCRB ने भारत में जेल सांख्यिकी 2024 (Prison Statistics India 2024) जारी की, जिसमें जेलों में लगातार भीड़भाड़ और विचाराधीन कैदियों के उच्च अनुपात की जानकारी है। 2024 में भारत में 1,333 जेलें थीं, राष्ट्रीय अधिभोग (ऑक्यूपेंसी) लगभग 112.7 प्रतिशत था जिसमें दिल्ली 194.6 प्रतिशत के साथ सर्वोच्च रही, और विचाराधीन कैदी लगभग 74 प्रतिशत थे।

□ **मुख्य बिंदु**

- 2024 में भारत में 1,333 जेलें थीं।
- राष्ट्रीय अधिभोग लगभग 112.7 प्रतिशत था, और दिल्ली में यह सर्वाधिक 194.6 प्रतिशत था।
- विचाराधीन कैदी लगभग तीन-चौथाई (लगभग 74 प्रतिशत) थे।
- लगभग 95.8 प्रतिशत कैदी पुरुष थे और महिलाएँ लगभग 4.14 प्रतिशत थीं।
- झारखंड में जेल कर्मचारियों के रिक्त पद 60 प्रतिशत से अधिक रहे।

भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025

संदर्भ: मई 2026 में MoSPI ने लैंगिक आधार पर विभाजित आँकड़ों को संकलित करने वाली 'भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025' (Women and Men in India 2025) का 27वाँ संस्करण जारी किया। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से सुधरकर 2021-23 में 917 हो गया, और अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक (1085) है, जबकि झारखंड (899) और बिहार (900) में सबसे कम है। मातृ मृत्यु अनुपात 2004-06 में 254 से घटकर 2021-23 में 88 हो गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से सुधरकर 2021-23 में 917 हो गया।
- अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक (1085) है, उसके बाद नगालैंड (1007) और गोवा (973) हैं; झारखंड (899) और बिहार (900) में सबसे कम है।
- शहरी कुल प्रजनन दर (TFR) 2019 में 1.7 से घटकर 2023 में 1.1 हो गई।
- महिलाओं की विवाह की औसत आयु शहरी क्षेत्रों में 24.3 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 22.4 वर्ष है।

➤ मातृ मृत्यु अनुपात 2004-06 में 254 से घटकर 2021-23 में 88 हो गया।

भारतीय फुटबॉल 2025-26: आईएसएल, आईएफएल, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी

संदर्भ: 2025-26 का भारतीय घरेलू फुटबॉल सत्र समाप्त हुआ, जिसमें ईस्ट बंगाल एफसी ने फरवरी से मई 2026 तक चले 12वें सत्र में अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। ईस्ट बंगाल ने इंडियन विमेंस लीग और डूरंड कप 2026 भी जीता, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी जीती, और भारत ने गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीती।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ आईएसएल का 12वाँ सत्र: 14 फरवरी-21 मई 2026; ईस्ट बंगाल एफसी ने अपना पहला आईएसएल खिताब जीता।

➤ इंडियन विमेंस लीग 2025-26 (कोलकाता और कल्याणी): ईस्ट बंगाल एफसी (दूसरा खिताब)।

➤ इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26 (27 फरवरी-23 मई): डायमंड हार्बर एफसी।

➤ सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 (मडगाँव, गोवा, 25 मई-6 जून): भारत ने बांग्लादेश को हराकर 6वाँ खिताब जीता; एमवीपी संफिदा नोंग्रुम; शीर्ष स्कोरर अवेका सिंह (4 गोल)।

भारतीय फुटबॉल विजेता

टूर्नामेंट	विजेता	उपविजेता
आईएसएल 2025-26	ईस्ट बंगाल एफसी (पहला खिताब)	दर्ज नहीं
डूरंड कप 2026	ईस्ट बंगाल एफसी	मोहन बागान सुपर जायंट
संतोष ट्रॉफी 2025-26	सर्विसेज (8वाँ खिताब)	केरल
सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 (पुरुष)	बांग्लादेश (दूसरा खिताब)	भारत
सैफ महिला चैंपियनशिप 2026	भारत (6ठा खिताब)	बांग्लादेश

यूरोपीय और विश्व फुटबॉल 2025-26: यूएफा कप और फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप

संदर्भ: 2025-26 की यूएफा क्लब प्रतियोगिताओं और फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप के विजेता तय हुए। पेरिस सेंट-जर्मेन ने दूसरी बार चैंपियंस लीग खिताब जीता और एस्टन विला ने पहली बार यूरोपा लीग जीती। सितंबर 2026 में पोलैंड में हुए फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप में स्पेन ने उत्तर कोरिया को हराकर दूसरा खिताब जीता।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2026, पोलैंड में, 5-27 सितंबर: स्पेन (दूसरा खिताब) ने उत्तर कोरिया को हराया।

➤ पेरिस सेंट-जर्मेन ने दूसरी बार चैंपियंस लीग खिताब जीता।

➤ एस्टन विला ने पहली बार यूरोपा लीग जीती।

यूएफा प्रतियोगिताएँ 2025-26

प्रतियोगिता	विजेता	उपविजेता
चैंपियंस लीग	पेरिस सेंट-जर्मेन (दूसरा खिताब)	आर्सेनल
यूरोपा लीग	एस्टन विला (पहला खिताब)	एससी फ्राइबर्ग
महिला चैंपियंस लीग	एफसी बार्सिलोना फेमेनी (चौथा खिताब)	ओलंपिक लियोनेस

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025

संदर्भ: मई 2026 में पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया। कर्नाटक ने सबसे अधिक (6) पुरस्कार जीते, उसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा (5-5) रहे; प्रोत्साहन राशि ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पंचायतों को प्रोत्साहन (Incentivization of Panchayats) घटक के अंतर्गत आते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ कर्नाटक ने सबसे अधिक (6) पुरस्कार जीते, उसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा (5-5) रहे।

➤ प्रोत्साहन राशि ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक है।

➤ दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार SDG के स्थानीयकरण की 9 विषयवस्तुओं में ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करता है।

➤ नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ जिला, खंड और ग्राम पंचायतों को सम्मानित करता है।

➤ विशेष श्रेणियों में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार और आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार शामिल हैं।

➤ ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पंचायतों को प्रोत्साहन (Incentivization of Panchayats) घटक के अंतर्गत आते हैं।

स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ: नीति आयोग की रिपोर्ट 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन हेतु कालिक विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप' में पाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पहुँच लगभग सार्वभौमिक है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को रोके रखने और सीखने के परिणामों में कमजोरी है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत में 14.71 लाख स्कूल और 24.69 करोड़ विद्यार्थी हैं, जिनमें 7.3 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं लेकिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केवल 1.64 लाख हैं।

- लगभग 10 में से 4 विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्तर से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं, और केवल 5.4 प्रतिशत स्कूल कक्षा 1-12 तक निरंतर शिक्षा प्रदान करते हैं।
- लगभग 7,993 स्कूलों में नामांकन शून्य है, जो पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में सबसे अधिक है।
- कक्षा 8 में पठन दक्षता 2014 में 74.7 प्रतिशत से घटकर 2024 में 71.1 प्रतिशत रह गई।
- परख (PARAKH) NCERT के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, जिसकी स्थापना NEP 2020 के तहत की गई है।
- UDISE+ 2024-25 के अनुसार 1.19 लाख स्कूलों में बिजली नहीं है, 14,505 में पेयजल नहीं है और 59,829 में हाथ धोने की सुविधा नहीं है।
- एक-तिहाई स्कूलों में इंटरनेट नहीं है।

AB-PMJAY ने राष्ट्रव्यापी कवरेज हासिल किया

संदर्भ: जून 2026 में पश्चिम बंगाल के योजना में शामिल होने के बाद आयुष्मान भारत PM-JAY ने राष्ट्रव्यापी कवरेज प्राप्त कर लिया। सितंबर 2018 में शुरू की गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित इस योजना में 12 करोड़ परिवार, लगभग 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस कवर मिलता है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से सार्वभौमिक कवर मिलता है।

□ मुख्य बिंदु

- योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जाती है।
- इसमें 12 करोड़ परिवार, लगभग 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस कवर मिलता है।
- 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से सार्वभौमिक कवर मिलता है।
- इसमें 27 विशेषज्ञताओं के 1,961 पैकेज शामिल हैं।
- फरवरी 2026 तक 43.52 करोड़ कार्ड जारी किए गए और 36,229 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए।
- ₹1.73 लाख करोड़ मूल्य का कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है।

NFHS-6: प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य के निष्कर्ष

संदर्भ: स्वास्थ्य मंत्रालय ने NFHS-6 जारी किया, जो IIPS, मुंबई द्वारा 2023-24 के दौरान मणिपुर को छोड़कर 715 जिलों के 6.79 लाख परिवारों को कवर करते हुए किया गया। यह COVID-19 महामारी के बाद का पहला दौर है और इसमें प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे, बच्चों में बौनेपन में कमी और स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि दिखती है, लेकिन विशिष्ट स्तनपान में गिरावट भी दिखती है।

□ मुख्य बिंदु

- यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई को नोडल एजेंसी बनाकर कराया।
- कुल प्रजनन दर 2.0 पर बनी रही, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।
- 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का हिस्सा 26.5 प्रतिशत से घटकर 25.5 प्रतिशत हो गया, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु का हिस्सा 11.8 प्रतिशत से बढ़कर 12.9 प्रतिशत हो गया।
- 18 वर्ष से पहले विवाह करने वाली महिलाएँ 23.3 प्रतिशत से घटकर 20.1 प्रतिशत रह गईं।

□ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

- संस्थागत प्रसव 88.6 प्रतिशत से बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गए, जबकि सिजेरियन प्रसव 21.5 प्रतिशत से बढ़कर 27.2 प्रतिशत हो गए।
- पहली तिमाही में प्रसवपूर्व पंजीकरण 70.0 प्रतिशत से बढ़कर 76.2 प्रतिशत हो गया, और चार या अधिक ANC जाँचें 58.5 प्रतिशत से बढ़कर 65.2 प्रतिशत हो गईं।
- कम से कम 180 दिनों तक आयरन-फोलिक एसिड लेने वाली माताएँ 26.0 प्रतिशत से बढ़कर 37.8 प्रतिशत हो गईं।
- बौनापन 35.5 प्रतिशत से घटकर 29.3 प्रतिशत और गंभीर दुबलापन 7.7 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत हो गया; कम वज़न 31.8 प्रतिशत रहा।
- 12-23 माह के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 83.8 प्रतिशत से बढ़कर 87.1 प्रतिशत हो गया; रोटावायरस टीके का कवरेज 36.4 से बढ़कर 85.4 प्रतिशत हो गया।
- छह माह से कम आयु के बच्चों में विशिष्ट स्तनपान 63.7 प्रतिशत से घटकर 55.8 प्रतिशत रह गया, और 6-23 माह के केवल 15.3 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त विविध आहार मिलता है।

□ सामाजिक-आर्थिक संकेतक

- इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएँ 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गईं।
- अपना बैंक खाता स्वयं संचालित करने वाली महिलाएँ 89.0 प्रतिशत तक पहुँच गईं।
- परिवारों में स्वास्थ्य बीमा कवरेज 41.0 प्रतिशत से बढ़कर 60.2 प्रतिशत हो गया।

NFHS-5 बनाम NFHS-6

संकेतक	NFHS-5	NFHS-6
बौनापन	35.5%	29.3%
पूर्ण टीकाकरण	83.8%	87.1%
संस्थागत प्रसव	88.6%	90.6%
इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएँ	33.3%	64.3%
सिजेरियन प्रसव	21.5%	27.2%

PMSMA के 10 वर्ष, डिजिटल स्वास्थ्य और NHA अनुमान

संदर्भ: जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने 10 वर्ष पूरे किए, जबकि भारत ने 90 करोड़ से अधिक ABHA खाते और नए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान दर्ज किए। PMSMA सार्वजनिक सुविधाओं में प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क विशेषज्ञ प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है। NHA 2022-23 दर्शाता है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP के 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 1.43 प्रतिशत हो गया और जेब से होने वाला व्यय 64.2 प्रतिशत से घटकर 43.4 प्रतिशत रह गया।

□ PMSMA

- PMSMA सार्वजनिक सुविधाओं में प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क विशेषज्ञ प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।
- 7.5 करोड़ से अधिक जाँचें की गईं, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान की गई।
- मातृ मृत्यु अनुपात 130 (SRS 2014-16) से घटकर 87 प्रति लाख जीवित जन्म (SRS 2022-24) हो गया।
- केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक ने 70 के SDG लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

□ डिजिटल स्वास्थ्य और NHA

- भारत ने 90 करोड़ से अधिक ABHA खाते और 100 करोड़ से अधिक जुड़े हुए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए हैं।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में शुरू हुआ; PM-ABHIM के लिए ₹64,180 करोड़ का प्रावधान है।
- NHA 2022-23: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP के 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 1.43 प्रतिशत हो गया और जेब से होने वाला व्यय 64.2 प्रतिशत से घटकर 43.4 प्रतिशत रह गया।

QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027

संदर्भ: जून 2026 में QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत के 52 विश्वविद्यालय शामिल थे, जो विश्व में पाँचवीं सबसे अधिक संख्या है, और IIT दिल्ली ने 118वीं रैंक के साथ भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त की। IIT बॉम्बे 134वें और IIT मद्रास 170वें स्थान पर है, किंतु वैश्विक शीर्ष 100 में कोई भारतीय संस्थान नहीं है। MIT लगातार 15वें वर्ष प्रथम स्थान पर है।

□ मुख्य बिंदु

- IIT दिल्ली 118वें, IIT बॉम्बे 134वें और IIT मद्रास 170वें स्थान पर है।
- वैश्विक शीर्ष 100 में कोई भारतीय संस्थान नहीं है।
- कमजोर पक्ष अंतरराष्ट्रीयकरण और संकाय-छात्र अनुपात हैं।
- MIT लगातार 15वें वर्ष प्रथम स्थान पर है।

अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियाँ: कॉर्पोरेट, सुरक्षा और वैश्विक निकाय

संदर्भ: नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पदों पर नियुक्तियाँ हुईं। लुकास फिलिप इंटरपोल महासभा के अध्यक्ष बने, बांग्लादेश के खलीलुर रहमान 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने गए, और कतर के शेख जोआन बिन हमद अल थानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया के अध्यक्ष बने। कॉर्पोरेट और सुरक्षा नेतृत्व में बदलाव, जैसे एप्पल के नए CEO, की भी घोषणा की गई।

□ वैश्विक निकाय

- लुकास फिलिप इंटरपोल महासभा के अध्यक्ष चुने गए (नवंबर 2025), वे संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नासिर अल-रईसी के उत्तराधिकारी हैं।
- कतर के शेख जोआन बिन हमद अल थानी ताशकंद में 46वीं महासभा में ओलंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया के अध्यक्ष चुने गए (जनवरी 2026)।
- बांग्लादेश के खलीलुर रहमान 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने गए (जून 2026)।
- नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर 1 अक्टूबर 2026 से विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री बने।
- तवेंग्वा मुकुहलानी (जिम्बाब्वे) को नवंबर 2027 तक ICC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

□ सुरक्षा और रक्षा

- पाकिस्तान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद सृजित किया; फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया (दिसंबर 2025)।
- रोमन गोफमैन को इज़राइल की मोसाद का प्रमुख नामित किया गया (अप्रैल 2026)।
- ले. जनरल सूज़न कॉयल ऑस्ट्रेलियाई सेना की पहली महिला प्रमुख बनीं (जुलाई 2026 में कार्यभार संभाला)।
- मेहरदाद अखलाघी को ईरान के रक्षा मंत्री के रूप में स्वीकृति दी गई (अक्टूबर 2026)।

□ कॉर्पोरेट

- जॉन टर्नस 1 सितंबर 2026 से टिम कुक की जगह एप्पल के CEO बने।
- दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को मेटा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) नामित किया गया (जनवरी 2026)।
- अनिल चक्रवर्ती को एडोबी का CEO नामित किया गया (1 दिसंबर 2026 से कार्यकारी अध्यक्ष)।
- तेवोल्दे गेब्रेमरियम कैंपबेल विल्सन के उत्तराधिकारी के रूप में एयर इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक बने (अगस्त 2026); विली वॉल्श ने इंडिगो के CEO का कार्यभार संभाला।
- शैलेश चंद्रा OICA के अध्यक्ष बने (नवंबर 2025)।

➤ कनिष्क नारायण (भारतीय मूल) को यूनाइटेड किंगडम का AI राज्य मंत्री नियुक्त किया गया (जुलाई 2026)।

क्रिकेट लीग और घरेलू 2026: आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, एशिया कप, दलीप ट्रॉफी

संदर्भ: 2026 में प्रमुख घरेलू और क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के परिणाम पूरे हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मार्च से मई 2026 तक चले 19वें आईपीएल के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब जीता, और टाटा डब्ल्यूपीएल 2026 भी जीता। भारतीय महिला टीम ने दुबई में एसीसी महिला टी20 एशिया कप जीता, और पूर्वी क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी 2026-27 जीती।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ एसीसी महिला टी20 एशिया कप 2026 (दुबई): भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता; शेफाली वर्मा टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (236 रन), दीप्ति शर्मा ने 14 विकेट लिए।

➤ दलीप ट्रॉफी 2026-27: पूर्वी क्षेत्र (तीसरा खिताब)।

□ **आईपीएल 2026**

➤ 19वाँ संस्करण, 28 मार्च-31 मई 2026, 13 स्थल, 10 टीमें, 74 मैच।

➤ फाइनल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराया (आरसीबी का दूसरा खिताब)।

➤ ऑरेंज कैप और एमवीपी: वैभव सूर्यवंशी (776 रन); पर्पल कैप: कगिसो रबाडा (29 विकेट); सबसे तेज़ शतक: सूर्यवंशी (36 गेंद); सबसे तेज़ अर्धशतक: उर्विल पटेल (13 गेंद)।

□ **टाटा डब्ल्यूपीएल 2026**

➤ आरसीबी चैंपियन (दूसरा खिताब), दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता।

➤ एमवीपी और पर्पल कैप: सोफी डिवाइन; ऑरेंज कैप: स्मृति मंधाना; हैट्रिक: नंदनी शर्मा।

खेल श्रद्धांजलि 2026: रणधीर सिंह, जसपाल राणा और अन्य

संदर्भ: 2026 में कई भारतीय खेल हस्तियों का निधन हुआ। इनमें 1980 मास्को ओलंपिक में आठ गोल करने वाले दविंदर सिंह गरचा, 1978 में एशियाई खेलों में शूटिंग का स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज़ रणधीर सिंह और निशानेबाज़ जसपाल राणा शामिल हैं। उनकी उपलब्धियाँ, सम्मान और धारित पद खेल हस्तियों से संबंधित प्रश्नों का सामान्य आधार हैं।

खेल श्रद्धांजलि

व्यक्ति	उपलब्धि	तिथि
दविंदर सिंह गरचा	हॉकी, मास्को 1980 में 8 गोल, भारत का आठवाँ और अंतिम ओलंपिक हॉकी स्वर्ण (73)	10 जनवरी 2026
आई.एस. बिंद्रा	BCCI के पूर्व अध्यक्ष 1993-96 (84)	
सी.डी. गोपीनाथ	भारत के सबसे वृद्ध टेस्ट क्रिकेटर (96)	9 अप्रैल 2026
गुरबख्श सिंह ग्रेवाल	हॉकी कांस्य, मेक्सिको सिटी 1968 (84)	24 अप्रैल 2026
विजय कुमार	गोल्फर, इंडियन ओपन 2002 के विजेता, चार बार ऑर्डर ऑफ मेरिट (57)	28 अप्रैल 2026
रणधीर सिंह	निशानेबाज़, एशियाई खेलों में शूटिंग का स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय (बैंकॉक 1978, ट्रैप), अर्जुन पुरस्कार 1979, OCA अध्यक्ष 2024 (79)	27 मई 2026
जसपाल राणा	निशानेबाज़, राष्ट्रमंडल खेलों में 15 पदक (9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य) 1994-2006 (49)	12 जून 2026

छात्र मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा पर पैनल की रिपोर्टें

संदर्भ: जून 2026 में सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय कार्यबल (नेशनल टास्क फोर्स), जिसका गठन 2025 में अमित कुमार बनाम भारत संघ मामले में किया गया था, ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर रिपोर्ट दी। कार्यबल ने उल्लेख किया कि सर्वेक्षण किए गए 2,119 संस्थानों में से 65 प्रतिशत में कोई मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं है, जबकि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP का लगभग 4.12 प्रतिशत है, जबकि NEP का लक्ष्य 6 प्रतिशत है।

□ **कार्यबल (टास्क फोर्स)**

➤ सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में अमित कुमार बनाम भारत संघ मामले में NTF का गठन किया।

➤ छात्र आत्महत्याएँ कुल आत्महत्याओं का 7.6 प्रतिशत थीं (NCRB 2022)।

➤ सर्वेक्षण किए गए 2,119 संस्थानों में से 65 प्रतिशत में कोई मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं है।

□ **संसदीय समिति**

➤ शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP का लगभग 4.12 प्रतिशत है, जबकि NEP का लक्ष्य 6 प्रतिशत है।

➤ प्रस्तावित 20 उत्कृष्टता संस्थानों (इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस) में से केवल 12 को अधिसूचित किया गया है।

➤ शिक्षक शिक्षा पर 380वीं रिपोर्ट के परिणामस्वरूप 613 DIET को उन्नत करने की ₹9,195 करोड़ की योजना बनी।

बिमल पटेल ITLOS के न्यायाधीश निर्वाचित; विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष

संदर्भ: जून 2026 में भारतीय विधिवेत्ता बिमल पटेल अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि अधिकरण (ITLOS) के न्यायाधीश निर्वाचित हुए और संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल पेरिस में FATF पूर्णाधिवेशन (प्लेनरी) के समापन पर नियुक्त होकर FATF के पहले भारतीय उपाध्यक्ष बने। ITLOS की स्थापना UNCLOS 1982 द्वारा हुई थी, इसका मुख्यालय जर्मनी में है और इसके 21 स्वतंत्र सदस्य हैं। अग्रवाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक कार्यरत रहेंगे।

□ ITLOS

- ITLOS की स्थापना UNCLOS 1982 द्वारा हुई थी और इसका मुख्यालय जर्मनी में है।
- इसके 21 स्वतंत्र सदस्य हैं, जिन्हें राज्य पक्षकार निर्वाचित करते हैं।
- भारत की नीरू चड्ढा इसकी उपाध्यक्ष हैं।

□ FATF

- विवेक अग्रवाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक कार्यरत रहेंगे।
- उन्हें पेरिस में FATF पूर्णाधिवेशन (प्लेनरी) के समापन पर नियुक्त किया गया।

भारत और क्षेत्र में एशियाई आयोजन 2026: फेंसिंग, ब्रिज, सांडा, बीच गेम्स

संदर्भ: 2026 में कई महाद्वीपीय खेल आयोजन हुए, जिनमें भारत ने जून में नई दिल्ली में पहली बार एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की। एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप गोवा में, IWUF सांडा विश्व कप मई में मकाऊ में और छठे एशियाई बीच गेम्स अप्रैल में सान्या, चीन में आयोजित हुए। भारत ने सांडा विश्व कप और बीच गेम्स में स्वर्ण जीता।

□ एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप 2026

- नई दिल्ली में आयोजित, 19-24 जून 2026, भारत की पहली बार मेजबानी।
- शीर्ष: जापान (6 स्वर्ण), दक्षिण कोरिया (4), कज़ाखस्तान (2)।

□ एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026

- पाँचवाँ संस्करण, गोवा, 21-27 जून 2026।
- शीर्ष: ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, चीन (प्रत्येक 2 स्वर्ण); भारत 3 रजत और 1 कांस्य के साथ छठे स्थान पर।

□ IWUF सांडा विश्व कप 2026

- 11वाँ संस्करण, मकाऊ, चीन में 13-15 मई 2026; चीन अग्रणी (7 स्वर्ण), वियतनाम दूसरे और भारत 2 स्वर्ण (अपर्णा दहिया 52 किग्रा, शिवानी 75 किग्रा) के साथ तीसरे स्थान पर।

□ एशियाई बीच गेम्स 2026

- छठा संस्करण, सान्या, चीन में 22-30 अप्रैल 2026; चीन 24 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर।
- भारत छठे स्थान पर (3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य): महिला बीच कबड्डी, तथा कुश्ती में पुष्पा यादव (60 किग्रा) और प्रिया मलिक (70+ किग्रा)।

एशियाई बीच गेम्स 2026 शीर्ष तीन

रैंक	देश	स्वर्ण	कुल
1	चीन	24	55
2	थाईलैंड	10	28
3	ईरान	9	10

मुक्केबाजी 2025-26: वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, फ्यूचर्स कप और एशियाई चैंपियनशिप

संदर्भ: भारतीय मुक्केबाजों ने 2025-26 में वर्ल्ड बॉक्सिंग आयोजनों में मजबूत प्रदर्शन किया। भारत नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में 9 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, और उलानबातर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा। छोटी जीतें मार्च में बैंकॉक में फ्यूचर्स कप और जून 2026 में गुइयांग में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चरण 2 में मिलीं।

□ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025

- ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित, 16-20 नवंबर 2025।
- भारत 9 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य (20) के साथ शीर्ष पर रहा।
- स्वर्ण: मीनाक्षी हुड्डा, निखत जरीन, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, नुपुर शेओरान, परवीन हुड्डा, सचिन सिवाच, हितेश गुलिया।

□ वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 (बैंकॉक, 8-15 मार्च)

- उज्बेकिस्तान शीर्ष पर; भारत 1 स्वर्ण (चंद्रिका पुजारी, 51 किग्रा) के साथ चौथे स्थान पर।

□ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चरण 2, 2026 (गुइयांग, चीन, 15-21 जून)

- चीन शीर्ष पर रहा; भारत 1 स्वर्ण (ज्योति गुलिया, 48 किग्रा), 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पाँचवें स्थान पर रहा।

□ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 (उलानबातर, 30 मार्च-10 अप्रैल)

- कज़ाखस्तान 6 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर; भारत 5 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- स्वर्ण पदक विजेता: मीनाक्षी हुड्डा (48), प्रीति पवार (54), प्रिया घनघस (60), अरुंधति चौधरी (70), विश्वनाथ सुरेश (पुरुष 50)।

विस्थापन पर UNHCR की वैश्विक प्रवृत्ति रिपोर्ट (ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट)

संदर्भ: जून 2026 में UNHCR की बलपूर्वक विस्थापन पर वैश्विक प्रवृत्ति रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 के अंत तक 11.78 करोड़ (117.8 मिलियन) लोग विस्थापित थे, जो एक दशक में पहली गिरावट है और विश्व में प्रत्येक 70 में से एक व्यक्ति के बराबर है। दस में से सात शरणार्थी अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यूक्रेन और वेनेज़ुएला से आए थे। रोहिंग्या, 18 लाख (1.8 मिलियन) के साथ, सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी हैं और भारत ने 22,700 को शरण दी।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह विश्व में प्रत्येक 70 में से एक व्यक्ति के बराबर है।
- दस में से सात शरणार्थी अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यूक्रेन और वेनेज़ुएला से आए थे।
- रोहिंग्या, 18 लाख (1.8 मिलियन) के साथ, सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी हैं; भारत ने 22,700 को शरण दी।
- शरणार्थियों में 39 प्रतिशत बच्चे हैं।
- UNHCR की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।

सेना प्रमुख की नियुक्ति और NDA की महिला अधिकारी

संदर्भ: जून 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया और NDA से प्रशिक्षित 17 महिला कैडेटों के पहले बैच को कमीशन प्रदान किया गया। महिला कैडेट अगस्त 2021 के सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद जुलाई-अगस्त 2022 में 148वें पाठ्यक्रम के अंतर्गत NDA में शामिल हुई थीं। सेठ को 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन मिला था।

□ **मुख्य बिंदु**

- सेठ को 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन मिला था।
- लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई NSCS के सैन्य सलाहकार बने, जो इस पद पर पहले सेवारत अधिकारी हैं।
- 17 महिला कैडेट जुलाई-अगस्त 2022 में 148वें पाठ्यक्रम के अंतर्गत NDA में शामिल हुई थीं।
- उनका प्रवेश अगस्त 2021 के सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद हुआ था।

23वें राष्ट्रमंडल खेल, ग्लासगो 2026

संदर्भ: 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में शुरू हुए, जिनमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती सहित नौ खेलों को हटा दिए जाने के बाद केवल 10 खेलों का काफ़ी सीमित कार्यक्रम है। पिछला संस्करण 2022 में बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। खेलों की शुरुआत 1930 में ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के रूप में हुई थी, जिससे मेज़बान शहर और खेलों की सूची परीक्षा का बार-बार पूछा जाने वाला विषय हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- हटाए गए खेल: बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलॉन, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवेन्स।
- शेष खेलों में एथलेटिक्स, मुक्केबाज़ी, लॉन बाउल्स, तैराकी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन और पैरा-पावरलिफ्टिंग, जूडो तथा 3x3 बास्केटबॉल शामिल हैं।
- खेलों की शुरुआत 1930 में ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के रूप में हुई थी और इनकी देखरेख राष्ट्रमंडल खेल महासंघ करता है।

72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

संदर्भ: 2024 की फ़िल्मों के लिए 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की घोषणा जुलाई 2026 में मलयालम फ़िल्मकार जयराज की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा की गई, साथ ही तीन वर्षों के दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भी घोषित किए गए। 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म का पुरस्कार मिला, ममूटी और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती (2022), मोहनलाल (2023) और अनंत नाग (2024) को दिया गया।

□ **मुख्य बिंदु**

- सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म: आर्टिकल 370; सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: ममूटी (ब्रह्मयुगम) और कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) को संयुक्त रूप से; सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: यामी गौतम (आर्टिकल 370)।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशन: राजकुमार पेरियासामी (अमरन); निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फ़िल्म: स्वातंत्र्य वीर सावरकर (रणदीप हुड्डा)।
- सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म: कल्कि 2898 एडी; बाल फ़िल्म: 35 - चिन्ना कथा काडू।
- संगीत: शाश्वत सचदेव (गीत), जी.वी. प्रकाश कुमार (पार्श्व संगीत); गीत-रचना: मनोज मुंतशिर; नृत्य-संयोजन: विजय गांगुली (स्त्री 2)।

□ **फाल्के पुरस्कार**

- 2022 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार: मिथुन चक्रवर्ती; 2023 का: मोहनलाल; 2024 का: अनंत नाग।

ICC ने मॉरीशस को 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया

संदर्भ: ICC बोर्ड ने जुलाई 2026 में मॉरीशस को अपना 111वाँ सदस्य स्वीकृत किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सदस्य संख्या 111 हो गई। ICC का मुख्यालय दुबई में है। अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों की सदस्यता में ऐसे विस्तार, मुख्यालय सहित, परीक्षा के खेल खंड में प्रायः पूछे जाते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सदस्य संख्या बढ़कर 111 हो गई।

➤ ICC का मुख्यालय दुबई में है।

UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट और WIPO अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026

संदर्भ: UNCTAD ने अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसमें 2025 में वैश्विक FDI में वृद्धि दिखाई गई, जबकि WIPO और इटली के लुइस बिज़नेस स्कूल ने विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की। 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत में अमूर्त निवेश सबसे तेज़ी से बढ़ा। परीक्षा के लिए भारत की बेहतर FDI रैंक (अंतर्वाह में 11वीं, बहिर्वाह में 18वीं) और प्रत्येक रिपोर्ट के प्रकाशक को याद रखें।

□ **विश्व निवेश रिपोर्ट 2026**

➤ 2025 में वैश्विक FDI 6 प्रतिशत बढ़कर 1.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया; विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 11 प्रतिशत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

➤ भारत अंतर्वाह FDI में 13वें से 11वें और बहिर्वाह FDI में 20वें से 18वें स्थान पर पहुँचा।

□ **विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026**

➤ इसे WIPO और इटली के लुइस बिज़नेस स्कूल द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

➤ 2008 के बाद से अमूर्त निवेश मूर्त निवेश की तुलना में तीन गुना से अधिक तेज़ी से बढ़ा है।

➤ अमेरिका कुल अमूर्त निवेश में और स्वीडन निवेश की तीव्रता में अग्रणी है; भारत में सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

फीफा विश्व कप 2026 के कीर्तिमान और मेसी का संन्यास

संदर्भ: 2026 के फीफा विश्व कप में कई कीर्तिमान बने, और लियोनेल मेसी ने 31 अगस्त 2026 को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। किलियन एम्बाप्पे लगातार दो विश्व कपों में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने, और टूर्नामेंट में चार हैट्रिक बनीं। मेसी 208 मैचों और 126 गोलों के बाद रिकॉर्ड आठ बैलोन डी'ओर पुरस्कारों के साथ सेवानिवृत्त हुए।

□ **विश्व कप**

➤ किलियन एम्बाप्पे लगातार दो विश्व कपों (2022 और 2026) में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने।

➤ चार हैट्रिक: मेसी, जोनाथन डेविड, उस्मान देम्बेले और बुकायो साका।

□ **मेसी**

➤ लियोनेल मेसी ने 208 मैचों और 126 गोलों के बाद 31 अगस्त 2026 को अंतरराष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की; क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे स्थान पर; रिकॉर्ड 8 बैलोन डी'ओर।

□ **अन्य**

➤ लैंडो नॉरिस ने 2025 का F1 खिताब जीता; रोजर फेडरर 2026 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने गए।

फीफा विश्व कप 2026: स्पेन बना चैंपियन

संदर्भ: 23वाँ पुरुष फीफा विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला गया और यह तीन देशों, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहला तथा 48 टीमों वाला पहला विश्व कप था। स्पेन ने 19 जुलाई को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर 2010 के बाद अपना दूसरा खिताब जीता। मेज़बान, प्रारूप में बदलाव, शुभंकर और पुरस्कार विजेता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

□ **टूर्नामेंट के तथ्य**

➤ मेज़बान: कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका; मैच 16 मेज़बान शहरों में।

➤ टीमों की संख्या 32 (1998-2022) से बढ़कर 48 हो गई; कुल मैच 64 से बढ़कर 104 हो गए।

➤ सेमीफाइनलिस्ट: स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड; तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया।

➤ फाइनल: स्पेन बनाम अर्जेंटीना, न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में 19 जुलाई 2026 को; स्पेन ने 2010 के बाद अपना दूसरा खिताब जीता।

□ **शुभंकर**

➤ तीन शुभंकर: मेपल (मूस, गोलकीपर, कनाडा), ज़ायू (जगुआर, स्ट्राइकर, मेक्सिको) और क्लच (गंजा चील, मिडफील्डर, अमेरिका)।

फीफा विश्व कप 2026 के पुरस्कार

पुरस्कार	विजेता
गोल्डन बॉल	रोड्रि (स्पेन)
गोल्डन बूट	किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)
गोल्डन ग्लव	उनाई सिमोन (स्पेन)
सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी	पाउ क्यूबार्सी (स्पेन)
फेयर प्ले ट्रॉफी	नीदरलैंड

फील्ड्स मेडल 2026 के विजेता

संदर्भ: फील्ड्स मेडल 2026 की घोषणा की गई, जिसमें चार गणितज्ञों ने यह पुरस्कार जीता, जो हर चार वर्ष में 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। यू देंग और हांग वांग इसे जीतने वाले पहले चीनी नागरिक बने और हांग वांग तीसरी महिला विजेता हैं। जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन अन्य विजेता थे। विजेता और आवृत्ति स्थैतिक विषयों से जुड़े सामान्य प्रश्न हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- अन्य विजेता जॉन पार्डन (अमेरिका) और जैकब सिमरमैन (सोवियत मूल के कनाडाई) हैं।
- हांग वांग मरियम मिर्ज़ाख़ानी और मरीना व्याज़ोव्स्का के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं।
- दोनों चीनी विजेता अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, किंतु चीनी नागरिक बने हुए हैं।

भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय GDP के 0.8 प्रतिशत के पार

संदर्भ: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी 2025-26 के अनुसार भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय 2010 के बाद पहली बार GDP के 0.8 प्रतिशत के पार पहुँच गया। 2023-24 में अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय ₹2.45 लाख करोड़ (0.84 प्रतिशत) रहा और निजी क्षेत्र हिस्सेदारी में सरकार से आगे निकल गया। यह GERD, ANRF और RDI कोष से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।

□ **मुख्य बिंदु**

- GERD 2019-20 में ₹1.33 लाख करोड़ (GDP का 0.66 प्रतिशत) से बढ़कर 2023-24 में ₹2.45 लाख करोड़ (0.84 प्रतिशत) हो गया।
- निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 33.8 प्रतिशत से बढ़कर 51.8 प्रतिशत हो गई और वह सरकार से आगे निकल गया।
- उच्च शिक्षा की हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई।
- प्रेरक कारकों में ANRF और ₹1 लाख करोड़ का RDI कोष शामिल हैं।

भारतीय खेल उपलब्धिधारी 2026

संदर्भ: भारतीय खिलाड़ियों ने 2026 के दौरान कई कीर्तिमान और जीत दर्ज कीं। हरमनप्रीत कौर 356 मैचों के साथ महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनीं, ईशा सिंह ने म्यूनिख में ISSF विश्व कप में महिला 25 मीटर पिस्टल में विश्व-कीर्तिमान स्कोर बनाया, और कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 32वीं बार एवरेस्ट पर चढ़े। प्रज्ञान ओझा ने अक्टूबर 2026 में अजीत अगरकर की जगह BCCI के मुख्य चयनकर्ता का पद भी संभाला।

□ **मुख्य बिंदु**

- हरमनप्रीत कौर महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनीं (356 मैच)।
- शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी पुरस्कार 2025 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर चुना गया।
- ईशा सिंह ने म्यूनिख में ISSF विश्व कप में विश्व-कीर्तिमान स्कोर के साथ महिला 25 मीटर पिस्टल का स्वर्ण जीता।
- नीरू ढांडा ने लोनाटो में ISSF शॉटगन विश्व कप में महिला ट्रैप का स्वर्ण जीता।
- अनाहत सिंह स्क्वैश की पहली भारतीय जूनियर विश्व चैंपियन बनीं।
- सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक का अपना विश्व कीर्तिमान सुधारकर 74.82 मीटर किया।
- गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर में 10.09 सेकंड का राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया।
- अक्षरा गुप्ता ने अंडर-19 महिला एकदिवसीय मैच में नाबाद 306 रन बनाए।
- कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 32वीं बार एवरेस्ट पर चढ़े।
- काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनीं।
- गुरजंत सिंह ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया; शोर्ड मारिन को महिला हॉकी टीम का कोच पुनः नियुक्त किया गया।
- प्रज्ञान ओझा ने अक्टूबर 2026 में अजीत अगरकर की जगह BCCI के मुख्य चयनकर्ता का पद संभाला।

शूटिंग विश्व कप 2025-26

संदर्भ: भारत ने 2025-26 के आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कपों में पदक जीते। दिसंबर 2025 में दोहा में हुए विश्व कप फाइनल में भारत 2 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और मई 2026 में म्यूनिख में भी यही स्थिति रही। जुलाई 2026 में हांगझोउ में भारत तीसरे स्थान पर रहा, जहाँ ईशा सिंह ने महिला 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण जीता। तीनों प्रतियोगिताओं में चीन शीर्ष पर रहा।

□ **मुख्य बिंदु**

- विश्व कप फाइनल (दोहा, 4-9 दिसंबर 2025): चीन पहले स्थान पर; भारत 2 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर (सुरुचि इंदर सिंह - 10 मीटर एयर पिस्टल; सिमरनप्रीत कौर बरार - 25 मीटर पिस्टल)।
- विश्व कप म्यूनिख (24-31 मई 2026): चीन पहले स्थान पर; भारत 2 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर (सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह)।
- विश्व कप हांगझोउ (20-29 जुलाई 2026): चीन पहले स्थान पर; भारत तीसरे स्थान पर, ईशा सिंह ने महिला 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण जीता।

आईएसएसएफ प्रतियोगिताएँ 2025-26 (शीर्ष देश)

आयोजन	पहला	भारत
विश्व कप फाइनल दोहा 2025	चीन (4 स्वर्ण)	दूसरा, 2 स्वर्ण
विश्व कप म्यूनिख 2026	चीन (4 स्वर्ण)	दूसरा, 2 स्वर्ण
विश्व कप हांगझोउ 2026	चीन (7 स्वर्ण)	तीसरा, 1 स्वर्ण

समुद्र प्रदक्षिणा: त्रि-सेवा महिला परिक्रमा

संदर्भ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले त्रि-सेवा सर्व-महिला परिक्रमा नौयान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को पूरा करने पर नौ महिला अधिकारियों को सम्मानित किया। थलसेना, नौसेना और वायुसेना की इन अधिकारियों ने IASV त्रिवेणी पर सवार होकर 314 दिनों में चार महासागरों में लगभग 25,500 समुद्री मील की यात्रा की। पोत, दूरी और भूमध्य रेखा

को दो बार पार करने जैसी उपलब्धियाँ तथ्य-आधारित प्रश्नों के लिए संभावित हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ दल ने IASV त्रिवेणी पर सवार होकर 314 दिनों में चार महासागरों में लगभग 25,500 समुद्री मील की यात्रा की।

➤ उन्होंने सभी याम्योत्तरों, भूमध्य रेखा को दो बार और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया तथा ड्रेक जलडमरूमध्य सहित तीनों महान अंतरीपों (ग्रेट केप) का चक्कर लगाया।

➤ अधिकारी थलसेना, नौसेना और वायुसेना से हैं।

साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार 2026

संदर्भ: 2026 में लेखन और मीडिया पुरस्कारों की घोषणा हुई। यांग शुआंग-ज़ी ने 'ताइवान ट्रैवलॉग' के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 जीता, जिसका अनुवाद लिन किंग ने किया है, और 2027 से इसका नाम बदलकर बुखमैन इंटरनेशनल बुकर कर दिया जाएगा। आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा ने परियोजना 'trAPPed' के लिए चित्रित रिपोर्टिंग एवं टिप्पणी श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 जीता, और डॉ. आशुतोष परिड़ा ने 47वाँ सरला पुरस्कार जीता।

□ **साहित्य**

➤ यांग शुआंग-ज़ी ने 'ताइवान ट्रैवलॉग' के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 जीता, जिसका अनुवाद लिन किंग ने किया; 2027 से इसका नाम बदलकर बुखमैन इंटरनेशनल बुकर कर दिया जाएगा।

➤ डॉ. आशुतोष परिड़ा ने ओड़िया कविता संग्रह 'बिश्वास दे पृथ्वी' के लिए 47वाँ सरला पुरस्कार जीता।

□ **पत्रकारिता**

➤ आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा ने नेटली ओबिको पियर्सन के साथ परियोजना 'trAPPed' के लिए चित्रित रिपोर्टिंग एवं टिप्पणी श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 जीता।

➤ 20वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित हुए।

2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

संदर्भ: राष्ट्रपति ने अगस्त 2026 में विज्ञान भवन में 115 कलाकारों को 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फ़ेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अकादमी पुरस्कार 1952 से दिए जा रहे हैं। फ़ेलो में रामलाल बरेठ, ए.वी. आनंद, रीता गांगुली और सुधारानी रघुपति शामिल थे, जबकि पुरस्कार विजेताओं में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, भरतनाट्यम, कथक, छऊ और अन्य कलारूपों के कलाकार शामिल थे। कलारूप से जुड़े विजेता प्रायः पूछे जाते हैं।

□ **फ़ेलो**

➤ रामलाल बरेठ, ए.वी. आनंद, रीता गांगुली, पुरु दाधीच, चित्तरंजन ज्योतिषी, पसुमर्थी रत्तैया शर्मा और सुधारानी रघुपति।

□ **2024 के चयनित पुरस्कार विजेता**

➤ हिंदुस्तानी गायन: अरुण नागेश कशालकर; ध्रुपद: निर्मल्य डे; तबला: संजय मुखर्जी; कर्नाटक गायन: कृष्ण वागेश और एन. विजय शिवा।

➤ नृत्य: राजेश्वरी साईनाथ (भरतनाट्यम), बिपुल चंद्र दास (कथक), वीणा मूर्ति विजय (कुचिपुड़ी), नृपेन साहिस (छऊ)।

□ **2025 के चयनित पुरस्कार विजेता**

➤ रोजा कन्नन (भरतनाट्यम), कृष्ण मोहन मिश्र तिकड़ी (कथक), इरेंगबाम नलिनी देवी (मणिपुरी), मल्लिका कंदाली (सत्रिया), गिरिजा चंद्रन (मोहिनीअट्टम), पगुलू जेना (छऊ), इलियाना सिटारिस्टी (ओडिसी)।

➤ संगीत: कृष्ण मोहन पाठक (ध्रुपद), शैलेश भागवत (शहनाई), ज्योति गणपति हेगड़े (रुद्र वीणा)।

सफ़दर हाशमी और बी.एम. शाह पुरस्कार

वर्ष	सफ़दर हाशमी	बी.एम. शाह
2021	मनोज कुमार मिश्र, रीवा	सतीश आनंद, दिल्ली
2022	राजेश सिंह, नई दिल्ली	कमल जैन, भोपाल
2023	अजय कुमार, गाज़ियाबाद	रविशंकर खरे, गोरखपुर
2024	शुभदीप राहा, लखनऊ	संजय मेहता, भोपाल

80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 पर शौर्य पुरस्कार

संदर्भ: राष्ट्रपति ने अगस्त 2026 में 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 शौर्य पुरस्कारों (13 मरणोपरांत) और 89 शौर्य उल्लेखों (मेंशन-इन-डिस्पैचेस) को स्वीकृति दी। शांतिकाल का दूसरा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कीर्ति चक्र घोषित किया गया सर्वोच्च सम्मान था, और मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र पर बार मिला। शौर्य पुरस्कारों का क्रम और प्राप्तकर्ता परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ शांतिकाल का दूसरा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कीर्ति चक्र घोषित किया गया सर्वोच्च सम्मान था; प्राप्तकर्ताओं में लेफ्टिनेंट कर्नल मानेओ फ्रांसिस पीएफ, मेजर जितेंद्र राठी और गृह मंत्रालय (MHA) के कई मरणोपरांत कर्मी शामिल थे।

➤ मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र पर बार प्राप्त हुआ।

➤ शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं में मेजर परमवीर, मेजर तरुण वासुदेवन, लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार और लांस नायक नरेंद्र सिंधु (मरणोपरांत) शामिल थे।

अन्य टेनिस 2026: मास्टर्स, डेविस कप और भारतीय आयोजन

संदर्भ: यानिक सिनर और आर्यना सबालेंका दोनों ने मार्च 2026 में एक ही वर्ष में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जीतकर 'सनशाइन डबल' पूरा किया। डेविस कप, बिली जीन किंग कप और भारत में आयोजित टूर्नामेंटों जैसे डब्ल्यूटीए मुंबई ओपन, एटीपी दिल्ली ओपन और एटीपी चेन्नई चैलेंजर सहित अन्य गैर-स्लैम आयोजनों के परिणाम भी चर्चा में रहे।

□ सनशाइन डबल

- एक ही वर्ष में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन दोनों जीतना सनशाइन डबल कहलाता है।
- मार्च 2026 में यानिक सिनर और आर्यना सबालेंका दोनों ने इसे पूरा किया।

□ टीम और भारतीय आयोजन

- डेविस कप फाइनल्स 2025: इटली चैंपियन (चौथा खिताब)।
- बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2026, शेनझेन: चेक गणराज्य ने यूक्रेन को हराया।
- डब्ल्यूटीए मुंबई ओपन 2026 महिला एकल: मननचाया सवांगकाएव (थाईलैंड)।
- एटीपी दिल्ली ओपन 2026: स्टेफानोस साकेलारिडिस (पुरुष एकल); सिद्धांत बांठिया और अलेक्जेंडर दोंस्की (युगल)।
- एटीपी चेन्नई चैलेंजर 2026: फ्रेडरिको फरेरा सिल्वा ने एकल जीता; प्रुचया इसारो और निकी पूनाचा ने युगल जीता।
- एटीपी बॉन ओपन 2026: जान चोइंस्की ने एकल जीता; विजय सुंदर प्रशांत और रामकुमार रामनाथन (भारत) ने युगल जीता।

टेनिस टूर्नामेंट 2026

टूर्नामेंट	पुरुष एकल	महिला एकल
इंडियन वेल्स	यानिक सिनर (उपविजेता डेनिल मेदवेदेव)	आर्यना सबालेंका (एलेना रयबाकिना)
मियामी ओपन	यानिक सिनर (यिरी लेहेचका)	आर्यना सबालेंका (कोको गॉफ)
मैड्रिड ओपन	यानिक सिनर (अलेक्जेंडर ज्वेरेव)	मार्टा कोस्त्युक (मीरा एंड्रीवा)
इटैलियन ओपन	यानिक सिनर (कैस्पर रूड)	एलिना स्विटोलिना (कोको गॉफ)
सिनसिनाटी ओपन	आर्थर फिल्स (फ्रांसेस टियाफो)	कोको गॉफ (जेसिका पेगुला)

एथलेटिक्स 2026: U20 विश्व चैंपियनशिप, एशियाई U23, एशियाई रिले और 24 घंटे की दौड़

संदर्भ: भारत ने 2026 में जूनियर और महाद्वीपीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अगस्त में यूजीन, अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में भारत ने तीन पदक जीते, और जुलाई में ओर्डोस, चीन में उद्घाटन एशियाई अंडर-23 चैंपियनशिप में वह चौथे स्थान पर रहा। मई में भारत ने हिरोसाकी, जापान में IAU 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में पुरुषों के व्यक्तिगत पोडियम पर क्लीन स्वीप भी किया।

□ विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2026

- यूजीन, ओरेगन (अमेरिका), 5-9 अगस्त 2026; भारत ने 3 पदक (2 रजत, 1 कांस्य) जीते और 27वें स्थान पर रहा।
- रजत: आशीष यादव (भाला फेंक) और बसंत कुमार मेघवाल (ऊँची कूद); कांस्य: शाहनवाज खान (लंबी कूद)।

□ एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026

- उद्घाटन संस्करण, ओर्डोस, चीन में 9-12 जुलाई 2026।
- चीन (23 स्वर्ण) शीर्ष पर रहा; भारत 3 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य (कुल 16) के साथ चौथे स्थान पर।
- स्वर्ण: मिश्रित 4x400 मीटर रिले, आनंद सिंह (भाला फेंक) और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले।

□ एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026

- शाओशिंग, चीन, 20-21 जून 2026; भारत ने एक स्वर्ण (महिला 4x100 मीटर), एक रजत और एक कांस्य जीता।

□ IAU 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप 2026

- हिरोसाकी, जापान, 23-24 मई 2026; भारत ने पुरुषों के व्यक्तिगत पोडियम पर क्लीन स्वीप सहित पाँच पदक जीते: अमर सिंह देवांडा स्वर्ण (282.881 किमी), जीनो एंटनी रजत और सौरव कुमार रंजन कांस्य।
- पुरुष टीम स्वर्ण; महिला टीम कांस्य।

कुश्ती 2026: U20 विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप और पीडब्ल्यूएल

संदर्भ: भारतीय पहलवानों ने 2026 में कई आयोजनों में भाग लिया। अगस्त में ब्रातिस्लावा में U20 विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 6 पदक जीते, जिनमें काजल ढोचक का महिला 76 किग्रा स्वर्ण शामिल है, जो उनका लगातार दूसरा U20 विश्व खिताब है। भारत ने अप्रैल में बिश्केक में एशियाई चैंपियनशिप में भी 17 पदक जीते, और 5वीं प्रो रेसलिंग लीग जनवरी और फरवरी में नोएडा में आयोजित हुई।

□ U20 विश्व चैंपियनशिप (ब्रातिस्लावा, 16-23 अगस्त 2026)

- भारत ने 6 पदक (1 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य) जीते।
- काजल ढोचक ने महिला 76 किग्रा स्वर्ण जीता, जो उनका लगातार दूसरा U20 विश्व खिताब है।

□ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप (बिश्केक, 6-12 अप्रैल 2026)

- भारत ने 17 पदक (2 स्वर्ण, 6 रजत, 9 कांस्य) जीते।
- स्वर्ण: सुजीत कलकल (65 किग्रा) और अभिमन्यु मंडवाल (70 किग्रा)।

□ **प्रो रेसलिंग लीग 2026**

➤ 5वाँ संस्करण, नोएडा (उत्तर प्रदेश), 15 जनवरी-1 फरवरी 2026।

➤ चैंपियन हरियाणा थंडर्स; उपविजेता दिल्ली दंगल वॉरियर्स।

भारोत्तोलन, राष्ट्रमंडल फेंसिंग और विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026

संदर्भ: 2026 में भारोत्तोलन, फेंसिंग और योग के आयोजन हुए, जिनमें प्रमुख रहा भारत का पहला समग्र राष्ट्रमंडल फेंसिंग खिताब, जो अगस्त में लागोस में रिकॉर्ड 35 पदकों के साथ जीता गया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप मई में गांधीनगर में और उद्घाटन विश्व योगासन चैंपियनशिप जून में अहमदाबाद में हुई, जहाँ भारत 102 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा।

□ **एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026**

➤ गांधीनगर, गुजरात में आयोजित, 11-17 मई 2026।

➤ चीन पहले (21 स्वर्ण), उत्तर कोरिया दूसरे, चीनी ताइपे तीसरे स्थान पर; भारत 10 पदकों के साथ 11वें स्थान पर, जिनमें ज्ञानेश्वरी यादव (महिला 53 किग्रा) का कुल भार में एक रजत शामिल है।

□ **राष्ट्रमंडल युवा/जूनियर भारोत्तोलन और यूनिवर्सल कप 2026**

➤ एपिया, समोआ, 27 अप्रैल-2 मई 2026।

➤ भारत ने सीनियर यूनिवर्सल कप में 15 पदक (6 स्वर्ण, 8 रजत, 1 कांस्य) जीते।

□ **राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप 2026**

➤ लागोस, नाइजीरिया, 9-19 अगस्त 2026।

➤ भारत ने रिकॉर्ड 35 पदकों (13 स्वर्ण, 8 रजत, 14 कांस्य) के साथ अपना पहला समग्र खिताब (U23 और सीनियर) जीता।

➤ इससे उसे सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के लिए विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी मिली।

□ **विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026**

➤ उद्घाटन संस्करण अहमदाबाद, गुजरात में 4-8 जून 2026; भारत 102 स्वर्ण और कुल 114 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा।

विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 पदक तालिका

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	भारत	102	9	3	114
2	जापान	3	3	5	11
3	अर्जेंटीना	2	3	0	5
4	सिंगापुर	2	2	3	7
5	नेपाल	1	36	15	52

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष: 2026 के बदलाव

संदर्भ: 2026 में राज्य स्तर के संवैधानिक पदों पर बदलाव हुए। डी.के. शिवकुमार जून में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने, युमनाम खेमचंद सिंह फरवरी में मणिपुर के मुख्यमंत्री बने, और सुनेत्रा पवार जनवरी में महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं। अक्टूबर 2026 में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए और नए अध्यक्ष चुने गए, इसलिए नाम और पद प्रमुख पुनरावृत्ति बिंदु हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री की शपथ ली (फरवरी 2026); उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन और लोसी दिखो।

➤ डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने (जून 2026); जी. परमेश्वर उपमुख्यमंत्री।

➤ सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं (जनवरी 2026)।

➤ दिनेश शर्मा ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 14वें उपराज्यपाल की शपथ ली।

➤ थिरुवंचूर राधाकृष्णन केरल की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए; रंजीत कुमार दास असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए।

➤ हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्य सभा के उपसभापति चुने गए।

अक्टूबर 2026 में नियुक्त राज्यपाल

राज्य	राज्यपाल
केरलम	ओम प्रकाश माथुर
तमिलनाडु	राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
ओडिशा	ब्रज मोहन राम
कर्नाटक	डॉ. सुधा यादव
उत्तराखंड	डॉ. ढाल सिंह बिसेन
सिक्किम	दुष्यंत गौतम

विज्ञान पुरस्कार 2025

संदर्भ: 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान सम्मान, विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की गई। विज्ञान रत्न भौतिकी के लिए प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरांत मिला, विज्ञान टीम कृषि विज्ञान के लिए CSIR की अरोमा मिशन टीम को मिला, और विज्ञान श्री के. थंगराज, प्रदीप थलप्पिल और महान एमजे सहित आठ वैज्ञानिकों को दिया गया। पुरस्कार की श्रेणियाँ और विजेता परीक्षा के मानक तथ्य हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ विज्ञान रत्न: प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर (मरणोपरांत), भौतिकी।

➤ विज्ञान टीम: CSIR की अरोमा मिशन टीम, कृषि विज्ञान।

➤ विज्ञान श्री: ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यूसुफ़ मोहम्मद शेख, के. थंगराज, प्रदीप थलप्पिल, अनिरुद्ध पंडित, एस. वेंकट मोहन, महान एमजे और जयन एन.।

शतरंज प्रतियोगिताएँ 2025-26: परिणाम तालिका

संदर्भ: 2025-26 की प्रमुख आमंत्रण और लीग शतरंज प्रतियोगिताएँ संपन्न हुईं, जिनमें आर. प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज़ और नॉर्वे चेस 2026 जीता। टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 जनवरी में कोलकाता में आयोजित हुआ। ग्लोबल चेस लीग और सिंकेफील्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता पुनरावृत्ति के लिए संकलित किए गए हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ आर. प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज़ और नॉर्वे चेस 2026 जीता।

➤ टाटा स्टील चेस इंडिया 2026, कोलकाता में, 7-11 जनवरी।

शतरंज प्रतियोगिताओं के परिणाम

आयोजन	विजेता	उपविजेता
ग्लोबल चेस लीग सीज़न 3 (मुंबई, दिसंबर 2025)	अल्पाइन एसजी पाइपर्स	त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स
टाटा स्टील मास्टर्स 2026 (वाइक आन ज़ी, 88वाँ)	नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव	जावोखिर सिंदारोव
नॉर्वे चेस 2026	आर. प्रज्ञानानंद	वेस्ली सो
सिंकेफील्ड कप 2026	वेस्ली सो	आर. प्रज्ञानानंद
सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज़ 2026	आर. प्रज्ञानानंद	जावोखिर सिंदारोव
चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026	अलीरेज़ा फिरोज़ा	दिमित्री आंद्रेइकिन
ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स 2026	आर. प्रज्ञानानंद	फैबियानो कारुआना
एशियाई रैपिड एंड ब्लिट्ज़ 2026 (ओपन रैपिड)	अलेक्सेई ग्रेबनेव	गौतम कृष्णा एच.

समाचारों में भारतीय हस्तियाँ: सम्मान, प्रथम और कीर्तिमान

संदर्भ: नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच कई भारतीयों को सम्मान मिला या वे समाचारों में रहे। विश्वनाथन आनंद जुलाई 2026 में FIDE के अंतरिम अध्यक्ष बने, जो इस पद पर पहुँचने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि एल. सुब्रमण्यम को श्रीलंका का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। कई महिला अधिकारियों ने सशस्त्र बलों और पुलिस में प्रथम उपलब्धियाँ भी दर्ज कीं, जो 'पहला कौन' जैसे सामान्य प्रश्न हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ विश्वनाथन आनंद FIDE के अंतरिम अध्यक्ष बने (जुलाई 2026), इस पद पर पहुँचने वाले पहले भारतीय।

➤ रघुराम राजन अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की बैलेंस शीट नीति पर कार्यबल के सह-प्रमुख हैं।

➤ डी.वाई. चंद्रचूड़ को रूस ने ओशादबैंक संधि विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया।

➤ एन. चंद्रशेखरन फरवरी 2027 के बाद टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में एक और कार्यकाल नहीं चाहेंगे।

□ **सम्मान और मान्यता**

➤ एल. सुब्रमण्यम को श्रीलंका का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया (जुलाई 2026)।

➤ मेजर अभिलाषा बराक ने 2025 का संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता; मेजर स्वाति शांता कुमार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार 2025 जीता।

➤ शर्मिला मोना सिन्हा को अमेरिका के नेशनल वीमेन्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, वे इंद्रा नूयी के बाद दूसरी भारतीय मूल की महिला हैं।

➤ स्मृति मंधाना UNICEF इंडिया की सेलेब्रिटी एडवोकेट बनीं (अक्टूबर 2026) और उन्हें खेल क्षेत्र में TIME के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया।

□ **प्रथम**

➤ स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत: वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर।

➤ कैप्टन हंसजा शर्मा: रुद्र हेलीकॉप्टर पर प्रशिक्षित पहली महिला सेना पायलट।

➤ मेजर नव्या शेखावत: राष्ट्रपति की ADC बनने वाली पहली महिला सेना अधिकारी।

➤ संजुक्ता पराशर: कोबरा (CoBRA) की पहली महिला IG।

➤ सबा शॉल: कश्मीर की पहली महिला जेल अधीक्षक।

➤ मेनका गुरुस्वामी: भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद (अप्रैल 2026)।

स्क्वैश 2025-26: विश्व कप और अन्य आयोजन

संदर्भ: भारत ने 9 से 14 दिसंबर 2025 तक चेन्नई में आयोजित अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता, फाइनल में हांगकांग, चीन को हराकर। भारतीय टीम में जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, अनाहत सिंह और वेलवन सेंथिलकुमार शामिल थे। भारतीय खिलाड़ियों ने 2026 के दौरान बुडापेस्ट ओपन और एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप सहित कई अन्य अंतरराष्ट्रीय खिताब भी जीते।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ तुआंकु मुहरिज ट्रॉफी (सेरेम्बन, मलेशिया): अभय सिंह ने पुरुष वर्ग जीता।

➤ बुडापेस्ट ओपन (हंगरी, 24-28 अगस्त): वेलवन सेंथिलकुमार ने जीता।

➤ एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप (सारावाक, 18-21 जून): वेलवन सेंथिलकुमार और अभय सिंह ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष युगल जीता।

➤ ग्रासहॉपर कप: करीम गवाद (पुरुष), शिवशंगरी सुब्रमण्यम (महिला)।

□ **स्क्वैश विश्व कप 2025**

➤ पाँचवाँ संस्करण, चेन्नई, 9-14 दिसंबर 2025; मिश्रित टीम स्पर्धा में 12 देश।

➤ भारत चैंपियन (पहला खिताब), हांगकांग, चीन उपविजेता।

➤ भारतीय टीम: जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, अनाहत सिंह, वेलवन सेंथिलकुमार।

हॉकी 2025-26: विश्व कप, प्रो लीग और अन्य प्रतियोगिताएँ

संदर्भ: 2025-26 के हॉकी परिणाम संपन्न हुए, जिनमें अगस्त 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 शामिल है। जर्मनी ने पुरुष खिताब और अर्जेंटीना ने महिला खिताब जीता। भारत ने ऑकलैंड में महिला नेशंस कप, जूनियर एशिया कप और पुरुष अंडर-18 एशिया कप जीता, और पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में तीसरे स्थान पर रहा।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ भारत ने पुरुष अंडर-18 एशिया कप (तीसरा खिताब) और जूनियर एशिया कप (पुरुष 6ठा, महिला तीसरा खिताब) जीता।

➤ ऑकलैंड में महिला नेशंस कप भारत ने जीता (दूसरा खिताब); शीर्ष स्कोरर एशली सेसा और दीपिका सहरावत (6-6 गोल)।

➤ भारत पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 (चेन्नई और मदुरै) में तीसरे स्थान पर रहा, जिसे जर्मनी ने जीता (8वाँ खिताब)।

□ **एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026**

➤ बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, 15-30 अगस्त 2026।

➤ जर्मनी ने पुरुष खिताब (चौथा) जीता; अर्जेंटीना ने महिला खिताब (तीसरा) जीता।

हॉकी परिणाम 2025-26

आयोजन	विजेता	उपविजेता
पुरुष प्रो लीग 2025-26	बेल्जियम (दूसरा)	इंग्लैंड
महिला प्रो लीग 2025-26	नीदरलैंड (6ठा)	अर्जेंटीना
पुरुष नेशंस कप (केप टाउन)	फ्रांस (पहला)	दक्षिण अफ्रीका
पुरुष हॉकी इंडिया लीग	वेदांता कलिंगा लांसर्स (दूसरा)	रांची रॉयल्स
महिला हीरो एचआईएल (रांची)	एसजी पाइपर्स	श्राची बंगाल टाइगर्स
पुरुष जूनियर विश्व कप 2025	जर्मनी (8वाँ)	स्पेन
सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 (31वाँ)	बेल्जियम (पहला)	भारत
यूथ हॉकी 5एस एशिया (मस्कट)	भारत अंडर-18 पुरुष	पाकिस्तान
विश्व कप 2026 पुरुष	जर्मनी	स्पेन
विश्व कप 2026 महिला	अर्जेंटीना	नीदरलैंड

PMRBP 2025, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और शासन पुरस्कार

संदर्भ: दिसंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच राष्ट्रीय नागरिक सम्मानों की एक श्रृंखला प्रदान की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिसंबर 2025 में 20 बच्चों को दिया गया, सितंबर 2026 में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिले, और पंचायत उन्नति सूचकांक ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता। पुरस्कार प्राप्त राज्य और श्रेणियाँ प्रायः पूछी जाती हैं।

□ **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025**

➤ 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा 20 बच्चों को प्रदान किया गया।

➤ वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में व्योमा प्रिया (मरणोपरांत, तमिलनाडु), कमलेश कुमार (मरणोपरांत, बिहार), मुहम्मद सिदान पी (केरल) और अजय राज (उत्तर प्रदेश) शामिल थे; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्राप्तकर्ता ऐशी प्रिशा बोरा (असम) और अर्णव अनुप्रिया महर्षि (महाराष्ट्र) थे।

□ **राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026**

➤ 5 सितंबर 2026 को विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों (26 पुरुष, 22 महिलाएँ) को सम्मानित किया गया।

□ **शासन**

➤ पंचायत उन्नति सूचकांक ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता।

➤ जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार (18 नवंबर 2025): तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शीर्ष तीन राज्य रहे; नगरीय निकायों में रायपुर नगर निगम शीर्ष पर रहा।

➤ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष किशोर मकवाना को मिला।

➤ अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया; शांतनु मोइत्रा को 2026 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान मिला।

V-Dem लोकतंत्र रिपोर्ट 2026 और भारत

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कथित मतदाता बहिष्करण पर चिंता जताई, जो नवीनतम V-Dem रिपोर्ट की टिप्पणियों के अनुरूप है, जिसमें भारत को निरंकुशता की ओर बढ़ने वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ V-Dem रिपोर्ट प्रतिवर्ष स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्थित वैरायटीज़ ऑफ़ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की जाती है।

- भारत निर्वाचन लोकतंत्र सूचकांक में 179 देशों में 106वें स्थान पर है और उसका स्कोर 0.38 है।
- भारत उदार लोकतंत्र सूचकांक में 105वें स्थान पर है और 2017 से निर्वाचन निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत है।
- भारत लोकतांत्रिक पतन से गुज़र रहे 44 देशों में शामिल है।
- अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान दक्षिण एवं मध्य एशिया के अन्य निरंकुशता की ओर बढ़ने वाले देश हैं।

गोल्डन ग्लोब, ग्रैमी, बाफ्टा और एमी 2026

संदर्भ: 2026 में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन पुरस्कार प्रदान किए गए। जनवरी में 83वें गोल्डन ग्लोब में ड्रामा श्रेणी में 'हैमनेट' और म्यूज़िकल या कॉमेडी श्रेणी में 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को पुरस्कार मिला, फरवरी में 68वें ग्रैमी में एल्बम ऑफ़ द ईयर बैड बनी को मिला, और फरवरी में 79वें बाफ्टा में 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म घोषित किया गया। सितंबर में 78वें एमी में 'विडोज़ बे' ने 14 पुरस्कार जीते।

□ 83वाँ गोल्डन ग्लोब (11 जनवरी 2026)

- ड्रामा: हैमनेट; म्यूज़िकल या कॉमेडी: वन बैटल आफ्टर अनदर; एनिमेटेड: के-पॉप डेमन हंटर्स; निर्देशक: पॉल थॉमस एंडरसन।

□ 68वाँ ग्रैमी (1 फरवरी 2026)

- एल्बम ऑफ़ द ईयर: बैड बनी, 'डेबी तिरार मास फ़ोतोस'; रिकॉर्ड: केंड्रिक लामर और सीज़ा, 'ल्यूथर'; गीत: बिली आइलिश, 'वाइल्डफ्लावर'; न्यू आर्टिस्ट: ओलिविया डीन।

□ 79वाँ बाफ्टा (22 फरवरी 2026)

- सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: वन बैटल आफ्टर अनदर; उत्कृष्ट ब्रिटिश फ़िल्म: हैमनेट; प्रमुख अभिनेता: रॉबर्ट अरामायो (आई स्वियर); प्रमुख अभिनेत्री: जेसी बकले।

□ 78वाँ एमी (14 सितंबर 2026)

- कॉमेडी सीरीज़: विडोज़ बे (मुख्य अभिनेता मैथ्यू रीस), मुख्य अभिनेत्री जीन स्मार्ट (हैक्स); ड्रामा सीरीज़: द पिट (नोआ वाइल); लिमिटेड सीरीज़: डीटीएफ़ सेंट लुइस; बॉब होप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड: माइकल जे. फ़ॉक्स; विडोज़ बे ने सबसे अधिक 14 पुरस्कार जीते।

टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026: युगल और मिश्रित युगल

संदर्भ: 2026 के ग्रैंड स्लैम सत्र में युगल और मिश्रित युगल के चैंपियन भी सामने आए। कैटेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों में महिला युगल जीता, जबकि क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुप्स्की ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में पुरुष युगल जीता। परीक्षा में स्लैम के अनुसार विजेता पूछे जाते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- कैटेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों में महिला युगल जीता।
- क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुप्स्की ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में पुरुष युगल जीता।

ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन 2026

स्लैम	पुरुष युगल	महिला युगल	मिश्रित युगल
ऑस्ट्रेलियन ओपन	क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुप्स्की	एलिस मर्टेंस और झांग शुआई	ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स
फ्रेंच ओपन	मार्सेल ग्रानोलर्स और होरासियो ज़ेबालोस	कैटेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड	सारा एरानी और आंद्रेया वावासोरी
विंबलडन	हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन	हान्यू गुओ और क्रिस्टीना म्लादेनोविच	मार्सेलो अरेवालो और येलेना ओस्टापेंको
यूएस ओपन	क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुप्स्की	कैटेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड	कैरोलिना मुचोवा और याकूब मेन्सिक

टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026: विजेता तालिका

संदर्भ: 2026 के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में अलग-अलग चैंपियन सामने आए। कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यानिक सिनर ने विंबलडन जीता, जबकि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों जीते। महिलाओं में एलेना रयबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन और लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन जीता।

□ मुख्य बिंदु

- कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता; यानिक सिनर ने विंबलडन जीता।
- अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों जीते।
- एलेना रयबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीता; मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन जीता; लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन जीता।

ग्रैंड स्लैम एकल 2026

स्लैम	पुरुष एकल (उपविजेता)	महिला एकल (उपविजेता)
ऑस्ट्रेलियन ओपन	कार्लोस अल्कारेज (नोवाक जोकोविच)	एलेना रयबाकिना (आर्यना सबालेंका)
फ्रेंच ओपन	अलेक्जेंडर ज्वेरेव (फ्लावियो कोबोली)	मीरा एंड्रीवा (माया च्वालिंस्का)
विंबलडन	यानिक सिनर (अलेक्जेंडर ज्वेरेव)	लिंडा नोस्कोवा (कैरोलिना मुचोवा)
यूएस ओपन	अलेक्जेंडर ज्वेरेव (बेन शेल्टन)	एलेना रयबाकिना (आर्यना सबालेंका)

टेबल टेनिस 2026: डब्ल्यूटीटी श्रृंखला और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप

संदर्भ: भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने 2026 में डब्ल्यूटीटी आयोजनों और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। मानुष शाह ने वडोदरा, मस्कट और लागोस के डब्ल्यूटीटी आयोजनों में खिताब जीते, और श्रीजा

अकुला ने सितंबर में डब्ल्यूटीटी फीडर प्यूर्टो प्रिंसेसा में महिला एकल जीता। भारत ने जुलाई से अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाएँ जीतीं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ मानुष शाह और दिया चितले ने डब्ल्यूटीटी कंटेंडर मस्कट और लागोस में मिश्रित युगल जीता।

➤ मानव ठक्कर और मानुष शाह ने लागोस में पुरुष युगल जीता।

➤ श्रीजा अकुला ने डब्ल्यूटीटी फीडर प्यूर्टो प्रिंसेसा में महिला एकल जीता; अंकुर भट्टाचार्जी ने डब्ल्यूटीटी फीडर ओलोमौक में पुरुष एकल जीता।

□ **राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप**

➤ 22वाँ संस्करण, त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली, 27 जुलाई-2 अगस्त 2026।

➤ भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाएँ जीतीं, प्रत्येक फाइनल में मलेशिया को हराया।

डब्ल्यूटीटी आयोजन 2026 (भारतीय विजेता)

आयोजन	परिणाम
डब्ल्यूटीटी फीडर वडोदरा (जनवरी)	मानुष शाह ने पुरुष एकल जीता; पायस जैन और सिंड्रेला दास ने मिश्रित युगल जीता
डब्ल्यूटीटी कंटेंडर मस्कट (जनवरी)	मानुष शाह और दिया चितले ने मिश्रित युगल जीता
डब्ल्यूटीटी कंटेंडर लागोस (मई)	पुरुष युगल: मानव ठक्कर और मानुष शाह; मिश्रित: मानुष शाह और दिया चितले
डब्ल्यूटीटी फीडर इस्तांबुल II (जुलाई)	महिला युगल: स्वस्तिका घोष और तनीषा कोटेचा
डब्ल्यूटीटी फीडर ओलोमौक (अगस्त)	अंकुर भट्टाचार्जी ने पुरुष एकल और (आकाश पाल के साथ) पुरुष युगल जीता
डब्ल्यूटीटी फीडर प्यूर्टो प्रिंसेसा (सितंबर)	श्रीजा अकुला ने महिला एकल जीता

तीरंदाजी 2026: विश्व कप चरण, फाइनल और एशिया कप

संदर्भ: 2026 की तीरंदाजी विश्व कप श्रृंखला में भारतीय तीरंदाजों ने हर चरण में पदक जीते। भारत ने अप्रैल में प्यूब्ला, मेक्सिको में चरण 1 में महिला कंपाउंड टीम स्वर्ण, मई में शंघाई में चरण 2 में महिला रिकर्व टीम स्वर्ण जीता, और धीरज बोम्मदेवरा ने सितंबर में साल्टिलो, मेक्सिको में विश्व कप फाइनल में पुरुष रिकर्व स्वर्ण जीता। भारत बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप चरण 1 में भी दूसरे स्थान पर रहा।

□ **चरण 1 (प्यूब्ला, मेक्सिको, 7-12 अप्रैल)**

➤ चीन शीर्ष पर; भारत महिला कंपाउंड टीम (मधुरा धमनगांवकर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रगति) में 1 स्वर्ण के साथ पाँचवें स्थान पर।

□ **चरण 2 (शंघाई, 5-10 मई)**

➤ तुर्किये शीर्ष पर; भारत 1 स्वर्ण, 1 कांस्य के साथ छठे स्थान पर।

➤ महिला रिकर्व टीम स्वर्ण: अंकिता भकत, दीपिका कुमारी, कुमकुम मोहोड़।

□ **तीरंदाजी विश्व कप फाइनल (साल्टिलो, मेक्सिको, 12-13 सितंबर 2026)**

➤ भारत, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और अमेरिका ने प्रत्येक ने एक स्वर्ण जीता।

➤ धीरज बोम्मदेवरा ने पुरुष रिकर्व स्वर्ण जीता।

□ **तीरंदाजी एशिया कप चरण 1 (बैंकॉक, 21-28 मार्च 2026)**

➤ कज़ाखस्तान 3 स्वर्ण; भारत 2 स्वर्ण और 10 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर।

दादासाहेब फाल्के 2024, तेनज़िंग नोर्गे पुरस्कार और तीरंदाज़ी में स्वर्ण

संदर्भ: अभिनेता अनंत नाग को 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला, तेनज़िंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई और धीरज बोम्मदेवरा ने तीरंदाज़ी विश्व कप फ़ाइनल में स्वर्ण जीता।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है, जो पहली बार 1969 में दिया गया था और इसकी पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थीं।

➤ इसमें स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और नकद पुरस्कार शामिल हैं।

➤ तेनज़िंग नोर्गे पुरस्कार थल, जल और वायु साहसिक कार्य तथा जीवनपर्यंत उपलब्धि को शामिल करते हैं, जिनमें प्रत्येक के साथ ₹15 लाख मिलते हैं।

➤ पुरस्कार विजेताओं में बलजीत कौर और स्कलज़ैंग रिगज़िन (थल), रिमो साहा (जल) तथा शिव प्रसाद चमोली (जीवनपर्यंत उपलब्धि) शामिल हैं।

➤ धीरज बोम्मदेवरा मेक्सिको में जापान के नाकानिशी जुन्या को हराकर तीरंदाज़ी विश्व कप फ़ाइनल में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज़ बने।

➤ डोला बनर्जी ने 2007 में महिला व्यक्तिगत खिताब जीता था, जो भारत का एकमात्र अन्य स्वर्ण है।

बैडमिंटन 2025-26: टूर्नामेंट विजेता

संदर्भ: 2025-26 में प्रमुख बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न हुए, जिनमें महिला एकल में एन से यंग का दबदबा रहा। चीन ने डेनमार्क में थॉमस कप 2026 जीता और दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीता, जबकि नई दिल्ली ने अगस्त 2026 में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। पी.वी. सिंधु ने जापान ओपन जीता, और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स पुरुष युगल जीता।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ थॉमस कप 2026 (डेनमार्क, 24 अप्रैल-3 मई): चीन ने फ्रांस को हराया।

➤ उबेर कप 2026: दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया।

- बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली में, 17-23 अगस्त।
- पी.वी. सिंधु ने जापान ओपन जीता; तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन जीता; अस्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स जीता; देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स जीता।
- सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स पुरुष युगल जीता।

बीडब्ल्यूएफ एकल विजेता 2026

टूर्नामेंट	पुरुष एकल	महिला एकल
थाईलैंड मास्टर्स	मोह. ज़की उबैदिल्लाह	देविका सिहाग
ऑल इंग्लैंड	लिन चुन-यी (लक्ष्य सेन उपविजेता)	वांग ज़ी यी
एशिया चैंपियनशिप (निंगबो)	शी यू ची (आयुष शेट्टी उपविजेता)	एन से यंग
यूएस ओपन	सू ली यांग	लाइन क्रिस्टोफरसन
जापान ओपन	क्रिस्टो पोपोव	पी.वी. सिंधु
ताइपे ओपन	युदाई ओकिमोतो	तन्वी शर्मा
कोरिया मास्टर्स	झू शुआन चेन	अस्मिता चालिहा
सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 (लखनऊ)	जेसन गुणावान	हिना अकेची

भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्तियाँ 2026

संदर्भ: भारत ने मई से अक्टूबर 2026 के बीच राजदूतों और उच्चायुक्तों के एक नए समूह की घोषणा की। पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम का उच्चायुक्त, विक्रम के. दोराईस्वामी को चीन का राजदूत और दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश का 18वाँ उच्चायुक्त नामित किया गया। यूक्रेन, उत्तर कोरिया, कतर, मलेशिया, क्यूबा, इराक और नेपाल के लिए भी तैनातियों की घोषणा की गई।

राजनयिक तैनातियाँ

देश	राजदूत
यूनाइटेड किंगडम (उच्चायुक्त)	पेरियासामी कुमारन
चीन	विक्रम के. दोराईस्वामी
बांग्लादेश (उच्चायुक्त)	दिनेश त्रिवेदी (18वें)
यूक्रेन	अंजनी कुमार
उत्तर कोरिया	संजीव जैन
कतर	के. श्रीकर रेड्डी
मलेशिया (उच्चायुक्त)	सोमनाथ घोष
क्यूबा	हंसराज सिंह वर्मा
इराक	अजय ए. कुमार
नेपाल	सुधाकर दलेला

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 के विजेता

संदर्भ: 2026 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो सिंगापुर के टॉमी कोह, म्यांमार के बो क्यी और बांग्लादेश की रुना खान को दिए गए। कोह को अंतरराष्ट्रीय संवाद और विधि के शासन को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया, उन्होंने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जिसने 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय को अपनाया था। यह पुरस्कार एशिया का प्रमुख सम्मान है, इसलिए विजेता और उनके क्षेत्र पूछे जाते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- टॉमी कोह को अंतरराष्ट्रीय संवाद और विधि के शासन को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया और उन्होंने उस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसने 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय को अपनाया था।
- बो क्यी ने म्यांमार की सेना द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों का विरोध करने के कारण सात वर्ष जेल में बिताए।
- रुना खान ने सबसे गरीब लोगों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद करने के लिए 2002 में फ्रेंडशिप बांग्लादेश की स्थापना की।
- इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार समतुल्य माना जाता है।
- इसके लिए धन रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के न्यासियों ने दिया था।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026: भारत की स्थिति

संदर्भ: विश्व आर्थिक मंच ने 145 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने वाला अपना वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 जारी किया, जिसमें भारत 64.5% लैंगिक समानता के साथ अपनी 131वीं रैंक पर बना रहा, जो 69.2% के वैश्विक औसत से कम है। सूचकांक की शुरुआत 2006 में हुई थी और यह आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तीकरण को मापता है। भारत की रैंक और उप-सूचकांक स्कोर परीक्षा के मानक तथ्य हैं।

□ मुख्य बिंदु

- सूचकांक की शुरुआत 2006 में हुई थी और यह आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तीकरण को मापता है।
- भारत में आर्थिक भागीदारी समानता 41.2%, श्रम-बल समानता 44.1% और विधायकों, अधिकारियों एवं प्रबंधकों की समानता 13.1% है।
- भारत में शैक्षिक उपलब्धि समानता 96.6% और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता समानता 95.6% है।
- राजनीतिक सशक्तीकरण (24.5%) रैंक की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ उप-सूचकांक है, जिसमें वैश्विक रैंक 67वीं है।

➤ भारत में मंत्री पदों पर समानता 5.9% है, जबकि 2019 में इसका सर्वश्रेष्ठ स्तर 30% था।

शतरंज 2025-26: विश्व कप, कैंडिडेट्स और ओलंपियाड

संदर्भ: 2025-26 में प्रमुख शतरंज प्रतियोगिताएँ आयोजित हुईं, जिनमें सितंबर 2026 में समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने लगातार तीसरी बार गाप्रिंदाश्विली ट्रॉफी जीती। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 अक्टूबर से नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित हुआ, और उज़्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने 19 वर्ष की आयु में सबसे युवा चैंपियन के रूप में इसे जीता। उन्होंने 2026 में कैंडिडेट्स भी जीता, जिससे उन्हें गुकेश दोम्माराजू के साथ खिताबी मुकाबला खेलने का अवसर मिला।

□ **फिडे शतरंज विश्व कप 2025**

➤ गोवा में 31 अक्टूबर-27 नवंबर 2025 को आयोजित; 2002 के बाद भारत में दूसरी बार; 11वाँ संस्करण।

➤ जावोखिर सिंदारोव (उज़्बेकिस्तान) ने वेई यी को हराकर खिताब जीता और 19 वर्ष की आयु में सबसे युवा चैंपियन बने।

➤ इस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी है।

□ **फिडे कैंडिडेट्स 2026 (पेगेया, साइप्रस, 28 मार्च-16 अप्रैल)**

➤ जावोखिर सिंदारोव विजेता रहे और उन्हें गुकेश दोम्माराजू के साथ खिताबी मुकाबला खेलने का अवसर मिला।

➤ महिला कैंडिडेट्स की विजेता वैशाली रमेशबाबू का सामना जू वेनजुन से होगा।

□ **46वाँ शतरंज ओलंपियाड (समरकंद, 15-27 सितंबर 2026)**

➤ ओपन: उज़्बेकिस्तान (दूसरा खिताब), भारत उपविजेता, जर्मनी को कांस्य। महिला: चीन, कज़ाखस्तान, भारत को कांस्य।

➤ भारत ने सर्वश्रेष्ठ संयुक्त रेटिंग के लिए नोना गाप्रिंदाश्विली ट्रॉफी जीती, जो 2022 और 2024 के बाद लगातार तीसरी बार है।

सिविल सेवा और अर्थव्यवस्था संबंधी नियुक्तियाँ 2025-26

संदर्भ: नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच शीर्ष नौकरशाही, नियामक और कॉर्पोरेट पदों की घोषणा की गई। कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और विदेश सचिव को 2027 तक विस्तार दिया गया, और अनुराग जैन अगस्त 2026 में नीति आयोग के CEO बने। धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद प्रह्लाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया, और अनूप बागची को HDFC बैंक का CEO नामित किया गया।

□ **सेवा विस्तार**

➤ कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को 30 अगस्त 2027 तक विस्तार।

➤ गृह सचिव गोविंद मोहन को 22 अगस्त 2027 तक विस्तार।

➤ विदेश सचिव विक्रम मिस्री को 14 जुलाई 2027 तक विस्तार।

➤ CBDT अध्यक्ष रवि अग्रवाल को दिसंबर 2026 तक विस्तार।

□ **नए पद**

➤ अनुराग जैन: नीति आयोग के CEO (अगस्त 2026), दो वर्ष का कार्यकाल।

➤ धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद प्रह्लाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

➤ दीप्ति गौर मुखर्जी: उच्च शिक्षा सचिव।

➤ मनदीप भंडारी: CBSE अध्यक्ष।

➤ लव अग्रवाल: विदेश व्यापार महानिदेशक।

➤ वीर विक्रम यादव: DGCA।

➤ सौरभ विजय: CEO, इंडियाAI मिशन।

□ **वित्त**

➤ अनूप बागची: 27 अक्टूबर 2026 से HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO।

➤ रवि रंजन: SBI के प्रबंध निदेशक (दिसंबर 2025)।

➤ विनय टोंसे: यस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO (अप्रैल 2026)।

➤ संजय खन्ना: BPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

➤ उदय कोटक: गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष।

➤ RBI के कार्यकारी निदेशक: उषा जानकीरामन, रवि शंकर, मोनिषा चक्रवर्ती।

➤ के.वी. रमना मूर्ति: SEBI के पूर्णकालिक सदस्य।

सौंदर्य प्रतियोगिताएँ 2025-26

संदर्भ: 2025-26 के दौरान प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ताज पहनाया गया। मेक्सिको की फ़ातिमा बॉश ने नवंबर 2025 में थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 जीता, और डोमिनिकन गणराज्य की जोहेइरी मोला ने वियतनाम के न्हा ट्रांग में मिस वर्ल्ड 2026 जीता, जहाँ भारत की निकिता पोरवाल शीर्ष 40 में पहुँचीं। साध्वी सतीश सेल (गोवा) ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जीता। विजेता और मेज़बान परीक्षा के विशिष्ट तथ्य हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ मेक्सिको की फ़ातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 जीता (21 नवंबर 2025, थाईलैंड)।

➤ डोमिनिकन गणराज्य की जोहेइरी मोला ने वियतनाम के न्हा ट्रांग में मिस वर्ल्ड 2026 जीता; भारत की निकिता पोरवाल शीर्ष 40 में पहुँचीं।

➤ साध्वी सतीश सेल (गोवा) ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जीता।

➤ काज़िया लिज़ मेजो (केरल) ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 जीता; वैष्णवी गणेश (तमिलनाडु) मिस इंटरनेशनल इंडिया 2026 रहीं।

अंतरराष्ट्रीय श्रद्धांजलि 2025-26

संदर्भ: नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच विश्व की कई उल्लेखनीय हस्तियों का निधन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई थे, जो 1989 से पद पर थे और फरवरी 2026 में इज़राइल और अमेरिका के हमले में मारे गए। अभिनेता, लेखक, वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्राध्यक्षों का भी निधन हुआ, और परीक्षा में व्यक्तियों से उनके प्रसिद्धि-क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है।

□ मुख्य बिंदु

➤ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (1989 से सर्वोच्च नेता) फरवरी 2026 में इज़राइल और अमेरिका के हमले में मारे गए।

अंतरराष्ट्रीय श्रद्धांजलि

व्यक्ति	प्रसिद्धि का क्षेत्र	तिथि	आयु
ली सून-जे	दक्षिण कोरियाई अभिनेता	25 नवंबर 2025	91
डेविड जे. फार्बर	'इंटरनेट के दादा'	7 फरवरी 2026	91
रॉबर्ट डुवाल	अमेरिकी अभिनेता; टेंडर मर्सीज़ (1983) के लिए ऑस्कर	15 फरवरी 2026	95
अली खामेनेई	ईरान के सर्वोच्च नेता 1989-2026	फरवरी 2026	-
जेफ्री आर्चर	ब्रिटिश उपन्यासकार	30 मार्च 2026	67 (जैसा बताया गया)
माल एंडरसन	ऑस्ट्रेलियाई टेनिस चैंपियन	10 मई 2026	91
सॉनी रॉलिंस	जैज़ सैक्सोफोन वादक	24 मई 2026	95
हमद बिन खलीफा अल थानी	कतर के अमीर 1995-2013	12 जुलाई 2026	74
चंद्रिकाप्रसाद संतोखी	सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति (2020-25)	2026	-

आगामी प्रमुख खेल आयोजन और मेज़बान

संदर्भ: कई भावी वैश्विक खेल आयोजनों के मेज़बान तय हो चुके हैं। ICC पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, राष्ट्रमंडल खेल 2030 अहमदाबाद में, और फीफा विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित होगा। आयोजन-और-मेज़बान की जोड़ियाँ प्रारंभिक परीक्षा में स्थिर-संबद्ध प्रश्नों का मुख्य आधार हैं।

भावी मेज़बान

आयोजन	मेज़बान
ICC पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2027	दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया
ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028	ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड
ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2029	भारत
ICC एकदिवसीय विश्व कप 2031	भारत और बांग्लादेश
AFC एशियन कप 2027	सऊदी अरब
फीफा महिला विश्व कप 2027	ब्राज़ील
फीफा विश्व कप 2030	मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन
फीफा विश्व कप 2034	सऊदी अरब
ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026	डकार
राष्ट्रमंडल खेल 2030	अहमदाबाद
एशियाई खेल 2030 और 2034	दोहा; रियाद
ओलंपिक 2028 और 2032	लॉस एंजिल्स; ब्रिस्बेन
शतरंज ओलंपियाड 2028	अबू धाबी
राष्ट्रीय खेल 2027	मेघालय
UCI रोड विश्व चैंपियनशिप 2032	पुणे

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 और 2025

संदर्भ: संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 और 2025 के लिए अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली के रवींद्र भवन में गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 106 युवा कलाकारों को प्रदान किया गया। 2024 के लिए 51 और 2025 के लिए 55 प्राप्तकर्ता थे, जिनमें नम्रता राय (कथक) और कुना सामल (सरायकेला छऊ) शामिल हैं। यह पुरस्कार युवा प्रदर्शनकारी कलाकारों के लिए है, इसलिए कलारूप महत्वपूर्ण हैं।

□ मुख्य बिंदु

➤ 2024 के लिए 51 और 2025 के लिए 55 प्राप्तकर्ता थे।

➤ 2024 के उल्लेखनीय प्राप्तकर्ता: नम्रता राय (कथक), कुना सामल (सरायकेला छऊ), गजेंद्र सिंह (नौटंकी, उत्तर प्रदेश), विजेश एन.वी. (मुडियेट्टु), ईशर सिंह नामधारी (तार शहनाई)।

➤ 2025 के उल्लेखनीय प्राप्तकर्ता: सुभाश्री स्वैन (मयूरभंज छऊ), सोमनाथ महतो (पुरुलिया छऊ), शिलू सिंह राजपूत (उत्तर प्रदेश लोक संगीत), विपिन विश्वनाथ पुलवर (कठपुतली, केरल)।

एशियाई खेल 2026 में भारत: रिकॉर्ड और स्वर्ण पदक विजेता

संदर्भ: भारत जापान के आइची-नागोया में 2026 एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहा, उसे 21 स्वर्ण सहित कुल 85 पदक मिले, जो 2022 के बाद उसका दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन है। कई पहली उपलब्धियाँ दर्ज हुईं, जैसे प्रणवी उर्स का व्यक्तिगत गोल्फ स्वर्ण और जय मीना का पहला सॉफ्ट टेनिस पदक। विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में पी.टी. उषा का 42 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा।

□ समारोह

➤ उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक: मनु भाकर (निशानेबाजी) और पवन सहरावत (कबड्डी)।

➤ समापन समारोह में नीरू ढांडा (निशानेबाजी) ने ध्वज थामा।

□ पहली उपलब्धियाँ और रिकॉर्ड

➤ तीरंदाजी में पाँच स्वर्ण सहित नौ पदक मिले।

- प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- कुमकुम मोहोड़ एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- जय मीना ने भारत का पहला सॉफ्ट टेनिस पदक जीता।
- विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य जीता और पी.टी. उषा का 42 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।
- बरानिका इलंगोवन ने एशियाई खेलों में भारत का पहला पोल वॉल्ट पदक जीता; सावन बरवाल ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ मैराथन में रजत जीता।
- अनाहत सिंह इन खेलों में स्क्वैश एकल में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- एथलेटिक्स में 24 पदक मिले, लेकिन केवल एक स्वर्ण।

□ चयनित स्वर्ण पदक विजेता

- नीरू ढांडा (ट्रैप), लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी 75 किग्रा), परवीन हुड्डा (मुक्केबाजी 65 किग्रा), अंकुश पंघाल (मुक्केबाजी 80 किग्रा)।
- सुजीत कलकल और अमन सहरावत (फ्रीस्टाइल कुश्ती), प्रणवी उर्स (गोल्फ)।
- टीम स्वर्ण: महिला और पुरुष क्रिकेट, महिला और पुरुष कबड्डी, महिला और पुरुष हॉकी, महिलाओं की 4x400 मीटर रिले, कई तीरंदाजी कंपाउंड और रिकर्व टीमें।

एशियाई खेल 2026: आइची-नागोया

संदर्भ: 20वें एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची-नागोया में आयोजित हुए, जिसमें चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। टोक्यो और हिरोशिमा के बाद नागोया मेजबानी करने वाला जापान का तीसरा शहर है, और 43 खेलों में 46 टीमों ने भाग लिया। शुभंकर, नारा, पहली बार शामिल खेल और पदक तालिका परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।

□ मुख्य बिंदु

- टोक्यो (1958) और हिरोशिमा (1994) के बाद नागोया मेजबानी करने वाला जापान का तीसरा शहर है।
- शुभंकर: होनोहोन (अर्थ 'ज्वाला'); नारा: 'इमेजिन वन एशिया'।
- 46 टीमों ने भाग लिया (45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ और OCA शरणार्थी टीम); 43 खेल।
- पहली बार शामिल खेल: फ्रीस्टाइल बीएमएक्स, मिश्रित मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेकबॉल और वर्चुअल तायक्वोंडो।

एशियाई खेल 2026 पदक तालिका (शीर्ष 5)

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	चीन	169	89	83	341
2	जापान	83	95	91	269
3	दक्षिण कोरिया	39	43	68	150
4	भारत	21	27	37	85
5	उज़्बेकिस्तान	21	25	24	70

प्रधानमंत्री मोदी: सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित सरकार प्रमुख और विदेशी सम्मान

संदर्भ: नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष निरंतर पूरे किए, जिसकी गणना अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से की जाती है। मार्च 2026 में वे भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख बने, और जून 2026 में उन्होंने लगातार कार्यकालों में सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया। उन्हें इथियोपिया, ओमान, स्वीडन और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से विदेशी सम्मान भी प्राप्त हुए।

□ मुख्य बिंदु

- 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूरे किए (7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री; 2014 से प्रधानमंत्री)।
- 22 मार्च 2026 को वे 8,931 दिनों के साथ भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख बने।
- 10 जून 2026 को उन्होंने लगातार कार्यकालों में सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ा (26 मई 2014 से 4,399 दिन)।

प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी सम्मान

सम्मान	देश	तिथि
ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया	इथियोपिया	दिसंबर 2025
ऑर्डर ऑफ ओमान (प्रथम श्रेणी)	ओमान	दिसंबर 2025
नेसेट पदक	इज़राइल	फरवरी 2026
रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ग्रैंड क्रॉस	स्वीडन	मई 2026
रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट	नॉर्वे	मई 2026
एग्रीकोला पदक	FAO	मई 2026
ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी	स्लोवाकिया	जून 2026
गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न	सेशेल्स	जून 2026
बिंतांग अदिपुर्णा	इंडोनेशिया	जुलाई 2026
ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट फ्रेंडशिप (ओलि दराजली दोस्तलिक)	उज़्बेकिस्तान	अगस्त 2026

प्रमुख मैराथन 2026: विजेता

संदर्भ: 2026 की प्रमुख सड़क दौड़ों में उल्लेखनीय परिणाम रहे, जिनमें लंदन में पुरुषों का नया मैराथन विश्व रिकॉर्ड भी शामिल है। केन्या के सेबेस्टियन सावे ने 1:59:30 में लंदन मैराथन जीता, जबकि कार्तिक करकेरा ने पुरुषों की नई दिल्ली मैराथन जीती। बर्लिन, बोस्टन, शिकागो और टोक्यो जैसी प्रमुख मैराथनों के विजेताओं को पुनरावृत्ति के लिए संकलित किया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

- सेबेस्टियन सावे (केन्या) ने लंदन मैराथन 1:59:30 में जीती, जिसे नए विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया।
- कार्तिक करकेरा ने पुरुषों की नई दिल्ली मैराथन जीती।

मैराथन विजेता 2026

दौड़	पुरुष	महिला
शिकागो	अमोस किप्रुटो (केन्या)	हावी फेयसा गेजिया (इथियोपिया)
बर्लिन	गुये अदोला (इथियोपिया)	टिग्स्ट असेफा (इथियोपिया)
केप टाउन	मोहम्मद एसा (इथियोपिया)	डेरा दिदा यामी (इथियोपिया)
लंदन	सेबेस्टियन सावे (केन्या)	टिग्स्ट असेफा (इथियोपिया)
बोस्टन	जॉन कोरिर (केन्या)	शेरोन लोकेदी (केन्या)
टोक्यो	तादेसे ताकेले (इथियोपिया)	ब्रिगिड कोसगेई (केन्या)
लिस्बन हाफ	जैकब किप्लिमो (युगांडा)	त्सिगे गेब्रेसेलामा (इथियोपिया)
टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु	रोड्रिग क्विजेरा (बुरुंडी)	फ्लोरेंस न्यीयोनकुरु (रवांडा)
नई दिल्ली	कार्तिक करकेरा (भारत)	निर्मलाबेन ठाकोर (भारत)
मुंबई	ताडू अबाते (इथियोपिया)	येशी चेकोले (इथियोपिया)
लॉस एंजिल्स	नैथन मार्टिन (अमेरिका)	प्रिस्का चेरोनो (केन्या)

भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान 2026

संदर्भ: 2026 में विदेशों में भारतीयों को सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को फ्रांस का लीजन ऑफ़ ऑनर (नाइट श्रेणी) मिला, कैप्टन स्मित मछर को फ्लाईदुबई FZ1073 घटना के बाद इज़राइल के नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चुना गया, और मेजर अभिलाषा बराक ने सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में 2025 का संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार जीता। सम्मान और देश के जोड़े प्रायः पूछे जाते हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- सुनील भारती मित्तल को फ्रांस का लीजन ऑफ़ ऑनर (नाइट श्रेणी) मिला।
- कैप्टन स्मित मछर को 30 सितंबर 2026 की फ्लाईदुबई FZ1073 घटना के बाद इज़राइल के नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चुना गया।
- मेजर अभिलाषा बराक ने 2025 का संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार जीता; वे सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं।
- सेतुरमन पंचनाथन आर्थर एम. ब्यूके पुरस्कार (NAE) जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं।
- दो भारतीय महिलाएँ, ज़ेडटी लालरिथंगी (मिज़ोरम) और प्रियंका महेश शेल्के (महाराष्ट्र), FAO की '100 महिला नायिकाएँ' पहल में शामिल की गईं।
- सोमा मंडल ने दक्षिण एशिया के लिए 2026 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जीता।
- UNMISS ने 210 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया; भारत 4,200 से अधिक कर्मियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा वर्दीधारी योगदानकर्ता है।

रक्षा और सुरक्षा प्रमुखों की नियुक्तियाँ 2026

संदर्भ: 2026 के दौरान भारत के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के नेतृत्व में बदलाव हुए। जनरल धीरज सेठ जून 2026 में 31वें थल सेना प्रमुख बने, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर 2026 को 29वें वायु सेना प्रमुख बने, और महेश दीक्षित ने खुफिया ब्यूरो के निदेशक का पदभार संभाला। NIA, ITBP, BSF और RPF के लिए भी नए महानिदेशक नामित किए गए।

सुरक्षा नियुक्तियाँ

पद	अधिकारी	तिथि
थल सेना प्रमुख (31वें)	जनरल धीरज सेठ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी	30 जून 2026
उप थल सेना प्रमुख	ले. जनरल संदीप जैन	1 जुलाई 2026
वायु सेना प्रमुख (29वें)	एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ए.पी. सिंह के उत्तराधिकारी	31 अक्टूबर 2026
निदेशक, खुफिया ब्यूरो	महेश दीक्षित, तपन डेका के उत्तराधिकारी	30 जून 2026
महानिदेशक, NIA	राकेश अग्रवाल	जनवरी 2026
महानिदेशक, ITBP	शत्रुजीत सिंह कपूर	जनवरी 2026
महानिदेशक, BSF	प्रवीण कुमार	जनवरी 2026
महानिदेशक, RPF	जितेंद्र कुमार (मार्च 2030 तक)	अक्टूबर 2026
निदेशक, NCRB	अमित गर्ग	जुलाई 2026
पुलिस आयुक्त, दिल्ली	अनुराग कुमार	जुलाई 2026
निदेशक, ED	राहुल नवीन (अगस्त 2027 तक विस्तार)	अगस्त 2026
कमांडर-इन-चीफ, अंडमान और निकोबार कमान	विनीत मैकार्टी (20वें)	जून 2026
DCNS	वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद	अगस्त 2026
महानिदेशक, GSI	वर्षा अशोक अगलावे, 176 वर्षों में पहली महिला	जुलाई 2026

राष्ट्रीय श्रद्धांजलि 2025-26: कला, साहित्य और सार्वजनिक जीवन

संदर्भ: कला, साहित्य और सार्वजनिक जीवन की कई प्रमुख भारतीय हस्तियों का नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच निधन हुआ। इनमें आशा भोसले, तीजन बाई, एस. जानकी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल हैं, जिनकी बारामती में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके सम्मान, जैसे पद्म पुरस्कार, और उनके प्रसिद्धि-क्षेत्र के बारे में प्रारंभिक परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है।

□ मुख्य बिंदु

- ➤ आशा भोसले: पद्म श्री 1997, पद्म विभूषण 2008।
- ➤ तीजन बाई: पद्म श्री 1988, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019।
- ➤ एस. जानकी ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार चार बार जीता।
- ➤ अजीत पवार की बारामती में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई; वे महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवारत उपमुख्यमंत्री थे।

राष्ट्रीय श्रद्धांजलि

व्यक्ति	क्षेत्र और टिप्पणी	तिथि
अंदेश्री	तेलुगु कवि और गीतकार	10 नवंबर 2025
कामिनी कौशल	आरंभिक दौर की हिंदी फिल्म अभिनेत्री (98)	13 नवंबर 2025
धर्मेंद्र	अभिनेता, पद्म भूषण 2012 (89)	24 नवंबर 2025
स्वराज कौशल	वरिष्ठ अधिवक्ता, मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल	4 दिसंबर 2025
राम वी. सुतार	स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार (100)	18 दिसंबर 2025
ज्ञानरंजन	हिंदी लेखक, 'पहल' के संपादक (90)	7 जनवरी 2026
अजीत पवार	महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री	28 जनवरी 2026
गीता पटनायक	ओड़िया पार्श्वगायिका (68)	15 फरवरी 2026
मणि शंकर मुखर्जी ('शंकर')	बंगाली लेखक (92)	20 फरवरी 2026
के.एन. पणिक्कर	इतिहासकार	9 मार्च 2026
हरमन कुल्के	भारतविद्, ओडिशा का इतिहास	10 मार्च 2026
विजयपत सिंघानिया	रेमंड के पूर्व अध्यक्ष (87)	28 मार्च 2026
आशा भोसले	पार्श्वगायिका (92)	12 अप्रैल 2026
भुवन चंद्र खंडूड़ी	उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री (91)	19 मई 2026
बशीर बद्र	उर्दू कवि, पद्म श्री 1999, साहित्य अकादमी 1999 (91)	28 मई 2026
सुमन कल्याणपुर	गायिका (89)	31 मई 2026
तीजन बाई	पंडवानी लोक गायिका (70)	5 जुलाई 2026
एस. जानकी	पार्श्वगायिका (88)	11 जुलाई 2026
एम.पी. परमेश्वरन	परमाणु वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक (91)	11 अगस्त 2026
सोलोमन पापैया	तमिल वक्ता	11 सितंबर 2026
नाना पाटेकर	अभिनेता, पद्म श्री 2013 (75)	8 अक्टूबर 2026
गुरुवायूर दोरई	मृदंगम वादक, पद्म श्री 2025 (91)	10 अक्टूबर 2026
ए.वी.एस. राजू	NCC लिमिटेड के संस्थापक, पद्म श्री 2010 (89)	13 अक्टूबर 2026

संवैधानिक और वैधानिक नियुक्तियाँ 2025-26

संदर्भ: नवंबर 2025 के बाद संवैधानिक और वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति की गई। सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली, और अक्टूबर 2026 में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश नियुक्त किए गए। सूचना आयोग, सतर्कता आयोग और कई राष्ट्रीय आयोगों के लिए भी नए प्रमुख नामित किए गए, इसलिए पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का नियमित विषय हैं।

□ न्यायपालिका

- ➤ सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली; वे 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।
- ➤ अक्टूबर 2026 में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश नियुक्त किए गए: सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और अपरेश कुमार सिंह।
- ➤ महेश चंद्र त्रिपाठी बॉम्बे उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने; वी. कामेश्वर राव पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

□ आयोग

- ➤ राज कुमार गोयल: मुख्य सूचना आयुक्त (दिसंबर 2025)।
- ➤ प्रवीण वशिष्ठ: सतर्कता आयुक्त (जनवरी 2026)।
- ➤ प्रकाश राजपुरोहित: अप्रैल 2030 तक उप चुनाव आयुक्त।
- ➤ रंजना प्रकाश देसाई: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष।
- ➤ साध्वी निरंजन ज्योति: NCBC की अध्यक्ष (मार्च 2026)।
- ➤ हरजीत सिंह ग्रेवाल: NCM के अध्यक्ष (जुलाई 2026)।
- ➤ भगवत प्रसाद मकवाना: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष।
- ➤ लता गुप्ता: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष।
- ➤ मोहसिन रज़ा: उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष।

उत्तर प्रदेश विशेष

समसामयिक नोट्स

2026 में शिक्षा और कौशल विकास में उत्तर प्रदेश के प्रथम

संदर्भ: जनवरी 2026 के आसपास उत्तर प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कई 'भारत में प्रथम' और 'राज्य में प्रथम' संस्थानों की घोषणा की गई या उन्हें शुरू किया गया। भारत के पहले AI-सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का पायलट 28 जनवरी 2026 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शुरू हुआ, और राज्य का पहला राज्य-स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय लखनऊ में खुला। गोरखपुर में एक वन विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित है।

□ शिक्षा और संस्थान

- भारत के पहले AI-सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का पायलट 28 जनवरी 2026 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शुरू हुआ, जिसमें MSDE, गूगल क्लाउड और प्लेसकॉम शामिल हैं।
- भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में लगभग ₹500 करोड़ के निवेश से स्थापित किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश का पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (SIHM) गोरखपुर में बनेगा।
- पहला राज्य-स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय 4 जनवरी 2026 को डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में खुला, जिसमें 4,000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें हैं।
- आगरा की 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं।
- पहली नगरपालिका स्पेस लैब कुशीनगर के पडरौना में स्थापित की गई।

□ विमानन कौशल विकास

- कानपुर के NSTI में वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा (प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित भारत-फ्रांस सहयोग)।

उत्तर प्रदेश दिवस 2026: गौरव सम्मान और एक जनपद-एक व्यंजन

संदर्भ: 24 जनवरी को मनाया जाने वाला उत्तर प्रदेश दिवस 2026 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान और एक जनपद-एक व्यंजन के शुभारंभ के साथ मनाया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए शुभांशु शुक्ला सहित पाँच सम्मानितों को ₹11 लाख प्रत्येक दिए गए, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। यह व्यंजन पहल एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) की पूरक है।

□ उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26

- 24 जनवरी 2026 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ में प्रदान किए गए।
- पाँच सम्मानित व्यक्ति, प्रत्येक को ₹11 लाख, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल दिया गया।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे।

□ एक जनपद-एक व्यंजन

- जिलों की स्थानीय खान-पान पहचान को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर शुरू किया गया, जो एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) का पूरक है।

□ राष्ट्र प्रेरणा स्थल

- अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लखनऊ में उद्घाटन किया गया।

गौरव सम्मान 2025-26 के सम्मानित व्यक्ति

सम्मानित व्यक्ति	क्षेत्र
शुभांशु शुक्ला	अंतरिक्ष विज्ञान
अलख पांडेय	शिक्षा
डॉ. हरि ओम पंवार	साहित्य
रश्मि आर्या	महिला सशक्तीकरण
डॉ. सुधांशु सिंह	कृषि

उत्तर प्रदेश में खेल आयोजन: वॉलीबॉल, सांसद खेल महाकुंभ, विश्व मुक्केबाजी कप, एवरेस्ट साइक्लिंग

संदर्भ: उत्तर प्रदेश ने नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की। विश्व मुक्केबाजी कप नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जनवरी 2026 में वाराणसी में, और तीसरा सांसद खेल महाकुंभ अप्रैल 2026 में लखनऊ में शुरू हुआ। गोरखपुर की दिव्या सिंह एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनीं।

□ आयोजन

- 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप: वाराणसी, 4-11 जनवरी 2026, 58 टीमें।
- तीसरा सांसद खेल महाकुंभ अप्रैल 2026 में लखनऊ में शुरू हुआ।
- विश्व मुक्केबाजी कप: ग्रेटर नोएडा, 13-24 नवंबर 2025।

□ **दिव्या सिंह**

➤ गोरखपुर की शिक्षिका दिव्या सिंह 14 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में 'सोलर ऑन ट्रैक'

संदर्भ: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने 13 नवंबर 2025 को गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली पर भारत की पहली 'सोलर ऑन ट्रैक' प्रणाली शुरू की। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में नमो भारत द्रुत रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का भी उद्घाटन किया। यह परियोजना सतत परिवहन में राज्य-स्तरीय प्रथम है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 13 नवंबर 2025 को गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में शुरू की गई।

➤ भारत की किसी भी क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली में ऐसी प्रणाली की पहली स्थापना।

➤ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा संचालित।

□ **नमो भारत और मेरठ मेट्रो**

➤ प्रधानमंत्री मोदी ने 22 फरवरी 2026 को मेरठ में नमो भारत द्रुत रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन किया।

पटना पक्षी विहार और छारी-ढांड रामसर स्थल बने

संदर्भ: जनवरी 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दो नए रामसर स्थलों की घोषणा की, उत्तर प्रदेश के एटा जिले का पटना पक्षी विहार और गुजरात के कच्छ का छारी-ढांड, जिससे भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 हो गई। पटना पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1991 में हुई, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, जबकि छारी-ढांड बन्नी घास के मैदानों और कच्छ के रण के लवणीय दलदलों के बीच स्थित है।

□ **पटना पक्षी विहार**

➤ उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और 1991 में स्थापित हुआ।

➤ यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है।

➤ यहाँ आने वाले पक्षियों में लेसर व्हिसलिंग डक (छोटी सिल्ही), ग्रेलैग गूज (बड़ा हंस), कॉम्ब डक (नकटा), रडी शेल्डक (सुरखाब), गैडवाल (मोटिया), यूरेशियन विजन (चैता), इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक (गुगराल), नॉर्दर्न शॉवलर (तिदारी) और नॉर्दर्न पिनटेल (सींखपर) शामिल हैं।

□ **छारी-ढांड आर्द्रभूमि रिज़र्व**

➤ गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदानों और कच्छ के रण के लवणीय दलदलों के बीच स्थित है।

➤ कच्छी भाषा में 'छारी' का अर्थ खारा और 'ढांड' का अर्थ उथली आर्द्रभूमि है।

➤ यह डालमेशियन पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर (दरियाई सर्पग्रीव), काली गर्दन वाले सारस और इंडियन स्किमर का आवास है।

➤ बन्नी घास के मैदानों में अंधेरी रातों में दिखने वाली 'चीर बत्ती' या भूतिया रोशनी की घटना के लिए प्रसिद्ध है।

पद्म श्री 2026 और अन्य सम्मानों में उत्तर प्रदेश

संदर्भ: 2026 के 113 पद्म श्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं में उत्तर प्रदेश की हस्तियाँ शामिल थीं, और उत्तर प्रदेश की एन. राजम (कला) पाँच पद्म विभूषण सम्मान प्राप्तकर्ताओं में से थीं। उत्तर प्रदेश के सम्मानितों में अनिल कुमार रस्तोगी (कला), अशोक कुमार सिंह (विज्ञान), बुद्ध रश्मि मणि (पुरातत्व) और मंगला कपूर (साहित्य) शामिल थे। पूजा (उत्तर प्रदेश) और अजय राज भी पीएमआरबीपी 2025 के सम्मानितों में थे, जो राज्य-स्तरीय प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हैं।

□ **पद्म विभूषण**

➤ उत्तर प्रदेश की एन. राजम (कला) पाँच पद्म विभूषण सम्मान प्राप्तकर्ताओं में से थीं।

□ **सम्मानित व्यक्ति**

➤ उत्तर प्रदेश के पद्म श्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं में अनिल कुमार रस्तोगी (कला), अशोक कुमार सिंह (विज्ञान), बुद्ध रश्मि मणि (पुरातत्व), मंगला कपूर (साहित्य), प्रवीण कुमार (खेल), राजेंद्र प्रसाद और श्याम सुंदर (चिकित्सा), तथा रघुपत सिंह (कृषि, मरणोपरांत) शामिल थे।

➤ पीएमआरबीपी 2025 के सम्मानितों में पूजा (उत्तर प्रदेश) को पर्यावरण में और अजय राज को वीरता में सम्मानित किया गया।

पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित

संदर्भ: केंद्र सरकार ने 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) अधिसूचित किया। ESZ का उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना और अभयारण्य के आसपास जिम्मेदार पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। ESZ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाते हैं, जो इस विषय की मुख्य स्थैतिक कड़ी है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है।

➤ ESZ जैव विविधता की रक्षा और जिम्मेदार पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित किया गया।

➤ ESZ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

फिरोजाबाद काँच संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक परियोजनाएँ

संदर्भ: पर्यटन और पारंपरिक शिल्पों के लिए उत्तर प्रदेश में नए संग्रहालयों और विरासत-आधारित परियोजनाओं की घोषणा की गई। भारत का पहला समर्पित काँच संग्रहालय भारत के काँच नगर फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है, और मथुरा में राष्ट्रीय गोसंस्कृति संग्रहालय प्रस्तावित है। अप्रैल 2026 में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में 700 किलोग्राम की विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया।

□ **काँच संग्रहालय**

➤ भारत का पहला समर्पित काँच संग्रहालय भारत के काँच नगर फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है।

□ **राष्ट्रीय गोसंस्कृति संग्रहालय**

➤ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा में भारत के पहले ऐसे संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

□ **विक्रमादित्य वैदिक घड़ी**

➤ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भेंट की गई 700 किलोग्राम की वैदिक घड़ी का अप्रैल 2026 में काशी विश्वनाथ मंदिर में अनावरण किया गया।

□ **वेदारण्यम**

➤ भारत के पहले पर्यावरण-आध्यात्मिक पार्क के रूप में वर्णित, जो सीतापुर के नैमिषारण्य के निकट ठाकुरनगर में विकसित किया जा रहा है।

लखनऊ में राज भवन का नाम बदलकर जन भवन किया गया

संदर्भ: लखनऊ में राज्यपाल के आधिकारिक निवास राज भवन का नाम राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से बदलकर जन भवन कर दिया गया। यह नामकरण उसी सप्ताह हुआ जब उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने लखनऊ के विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया, और इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ नाम परिवर्तन 21 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ।

➤ लखनऊ का राज भवन जन भवन बन गया।

➤ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।

□ **86वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन**

➤ उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा 19 से 21 जनवरी 2026 तक विधान भवन, लखनऊ में आयोजित।

➤ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताज़ा कचरा डंप शहर

संदर्भ: 2026 की शुरुआत में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत लखनऊ को उत्तर प्रदेश के पहले शून्य ताज़ा कचरा डंप शहर के रूप में मान्यता दी गई। इस अवधारणा का अर्थ है कि कोई भी ताज़ा ठोस नगरपालिका कचरा डंपिंग स्थलों तक नहीं पहुँचता, क्योंकि उसका प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण कर लिया जाता है। यह पुरस्कार शहरी स्वच्छता योजनाओं और राज्य के प्रथम से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ उत्तर प्रदेश के पहले शून्य ताज़ा कचरा डंप शहर के रूप में मान्यता मिली।

➤ स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के अंतर्गत पुरस्कृत।

➤ अवधारणा: कोई भी ताज़ा ठोस नगरपालिका कचरा डंपिंग स्थलों तक नहीं पहुँचता; कचरे का प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण किया जाता है।

वाराणसी में भारत की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी

संदर्भ: भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन-सेल यात्री पोत 11 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद वाराणसी में गंगा पर चालू हुआ। यह नमो घाट से संचालित होता है और हरित समुद्री पहल का हिस्सा है। वाराणसी राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) पर स्थित है, जिससे यह स्थैतिक विषय से जुड़ा एक सामान्य प्रश्न-विषय बन जाता है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को हरी झंडी दिखाई।

➤ नमो घाट, वाराणसी से संचालित होता है।

➤ यह देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन-सेल यात्री पोत है, जो हरित समुद्री पहल का हिस्सा है।

➤ वाराणसी राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) पर स्थित है।

उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: क्षेत्रक और अवसंरचना

संदर्भ: उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के क्षेत्रकवार निष्कर्ष फरवरी 2026 में जारी किए गए और इनमें कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों में वृद्धि दिखाई गई है। 2024-25 में कृषि GVA ₹6.95 लाख करोड़ तक पहुँच गया, और उत्तर प्रदेश 7 चालू एक्सप्रेसवे के साथ एक्सप्रेसवे की राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। सर्वेक्षण में हवाई अड्डों के विस्तार, वन आवरण और बिजली उत्पादन के आँकड़े भी दर्ज हैं।

□ **कृषि**

➤ कृषि GVA ₹2.96 लाख करोड़ (2016-17) से बढ़कर ₹6.95 लाख करोड़ (2024-25) हो गया, जो 11.2% की CAGR है।

➤ उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है (33.6% की वृद्धि)।

➤ अंडा उत्पादन में 167% की वृद्धि हुई; 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 9.9% बढ़कर 737.4 लाख टन हो गया।

□ **उद्योग और सेवाएँ**

➤ द्वितीयक क्षेत्रक का GVA ₹3.34 लाख करोड़ से बढ़कर ₹7.60 लाख करोड़ हो गया।

➤ सेवा क्षेत्र का GVA ₹5.95 लाख करोड़ से बढ़कर ₹13.10 लाख करोड़ हो गया (CAGR 10.4%)।

➤ उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण: 2023-24 में औद्योगिक GVA 25% बढ़ा, जो प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है।

□ **अवसंरचना**

➤ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे की राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है: 7 चालू और 3 निर्माणाधीन।

➤ 12 घरेलू और 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे; जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने पर उत्तर प्रदेश पाँच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा।

➤ वाराणसी में भारत की पहली शहरी रज्जुमार्ग (रोपवे) परियोजना बन रही है।

➤ उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि और इंटरनेट उपभोक्ताओं में पहले स्थान पर है।

□ **वन आवरण**

➤ वन और वृक्ष आवरण 23,437.53 वर्ग किमी (2021) से बढ़कर 23,996.72 वर्ग किमी (2023) हो गया; उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: समष्टि चित्र

संदर्भ: उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया और इसमें एक ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार GSDP 2016-17 में ₹13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹30.25 लाख करोड़ हो गई, और उत्तर प्रदेश का भारत के GDP में लगभग 9.1 प्रतिशत योगदान है। सर्वेक्षण के समष्टि-आर्थिक संकेतक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

□ **वृद्धि**

➤ वर्तमान कीमतों पर GSDP 2016-17 के ₹13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹30.25 लाख करोड़ हो गई, जो 10.8 प्रतिशत की CAGR है।

➤ उत्तर प्रदेश का भारत के GDP में लगभग 9.1 प्रतिशत योगदान है।

➤ भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

□ **प्रति व्यक्ति आय और जनांकिकी**

➤ शुद्ध प्रति व्यक्ति आय 2016-17 के ₹54,564 से बढ़कर 2024-25 में ₹1,09,844 हो गई, जो लगभग 9.1% की CAGR है।

➤ मार्च 2026 तक जनसंख्या 25.19 करोड़ (भारत का 17.8%); यदि यह एक देश होता, तो उत्तर प्रदेश भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद पाँचवें स्थान पर होता।

➤ कुल प्रजनन दर 2.7 (NFHS-4) से घटकर 2.4 (NFHS-5) हो गई।

➤ 2011 में जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 100 बालिकाओं पर 111 बालक था।

➤ 2051 तक अनुमानित जीवन प्रत्याशा: पुरुषों की 73.2 और महिलाओं की 77.1 वर्ष।

□ **वित्त**

➤ सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात 29.3% (2016-17) से घटकर 28.0% (2024-25) हो गया, जो राष्ट्रीय स्तर के 81.3% से काफी कम है।

➤ राज्य का अपना कर राजस्व ₹0.86 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.09 लाख करोड़ हो गया।

➤ केंद्रीय अंतरणों पर निर्भरता 56% से घटकर 2025-26 में 46.4% रह गई।

2024-25 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों का हिस्सा

क्षेत्र	हिस्सेदारी
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	24.9%
रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ	13.9%
निर्माण	12.9%
विनिर्माण	11.7%
व्यापार और होटल	8.3%
परिवहन और संचार	7.4%

उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: प्रमुख आँकड़े

संदर्भ: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, जो विकास-केंद्रित बजट है और जिसमें राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर रखा गया, जो 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा है। कुल व्यय ₹9,12,696 करोड़ है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 27 प्रतिशत अधिक है। घाटे, प्राप्तियों और ऋण से संबंधित इसके प्रमुख आँकड़ों की नियमित रूप से परीक्षा में जाँच होती है।

□ **कुल आकार**

➤ कुल व्यय ₹9,12,696 करोड़ है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 27 प्रतिशत अधिक है।

➤ ऋण चुकौती लगभग ₹61,795 करोड़ है; शुद्ध व्यय लगभग ₹8,50,901 करोड़ है।

➤ उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 2024-25 में स्थिर कीमतों पर 9 प्रतिशत बढ़ा; प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹1,24,366 था (राष्ट्रीय ₹2,34,859)।

□ **घाटे**

➤ राजस्व अधिशेष ₹64,458 करोड़ (जीएसडीपी का 1.6%)।

➤ राजकोषीय घाटा ₹1,18,481 करोड़ (जीएसडीपी का 3%), जो 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा है।

➤ प्राथमिक घाटा ₹49,560 करोड़ (जीएसडीपी का 1.2%)।

□ **प्राप्तियाँ**

➤ राजस्व प्राप्तियों का लगभग आधा भाग राज्य के अपने स्रोतों से आता है।

➤ स्वयं का कर राजस्व ₹3,34,491 करोड़; राज्य जीएसटी स्वयं के कर राजस्व का लगभग 45 प्रतिशत अनुमानित है।

➤ स्टांप एवं पंजीकरण ₹43,802 करोड़; गैर-कर राजस्व ₹26,754 करोड़।

□ **व्यय और ऋण**

➤ राजस्व व्यय ₹6,64,471 करोड़; पूंजीगत परिव्यय ₹1,77,744 करोड़ (संशोधित अनुमान से 11% अधिक)।

➤ 2026-27 के अंत में बकाया देनदारियाँ जीएसडीपी का 23.1 प्रतिशत अनुमानित हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 27.6 प्रतिशत से कम है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग में दहेज संबंधी निर्देश

संदर्भ: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग (2025) में, जो फरवरी 2026 में रिपोर्ट हुआ, उच्चतम न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए। 2023 में उत्तर प्रदेश में दहेज के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए, जब दहेज संबंधी अपराधों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। न्यायालय ने प्रशिक्षित दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 498-क के अंतर्गत, जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 और 85 हैं, लंबित मामलों की समीक्षा का निर्देश दिया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ राजबीर बनाम हरियाणा राज्य (2010) में दहेज मृत्यु के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ने का निर्देश दिया गया। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में 498-क के मामलों में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई।

➤ 2023 में दहेज संबंधी अपराधों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें 15,000 से अधिक मामले और 6,100 से अधिक मौतें दर्ज हुईं।

➤ दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में थे, उसके बाद बिहार और कर्नाटक का स्थान रहा।

➤ न्यायालय ने सार्वजनिक की गई संपर्क जानकारी के साथ प्रशिक्षित दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया।

➤ उच्च न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 498-क के अंतर्गत, जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 और 85 हैं, लंबित मामलों की समीक्षा करनी होगी।

➤ पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चलाएँगे।

एनजीटी ने सुआव को नदी के रूप में बहाल करने का आदेश दिया

संदर्भ: फरवरी 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि राप्ती की प्रमुख सहायक नदी सुआव को आधिकारिक अभिलेखों और गजेटियर में 'नाले' से बदलकर पुनः 'नदी' के रूप में दर्ज किया जाए। राप्ती घाघरा की प्रमुख बाएँ तट की सहायक नदी है, जिसे प्राचीन काल में इरावती कहा जाता था, और यह नेपाल में महाभारत श्रेणी के रुकुमकोट के निकट से निकलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ राप्ती घाघरा की प्रमुख बाएँ तट की सहायक नदी है, जिसे प्राचीन काल में इरावती कहा जाता था। यह नेपाल में महाभारत श्रेणी के रुकुमकोट के निकट से निकलती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।

➤ इसकी मुख्य सहायक नदियाँ बूढ़ी राप्ती और रोहिणी हैं।

नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री ने भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का उद्घाटन किया, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मेरठ को जोड़ने वाली अर्ध-उच्च गति की यात्री सेवा है। यह रेल-आधारित प्रणाली है, जिसकी गति 180 किमी प्रति घंटे तक है और जो इस गलियारे में यात्रा समय को लगभग 3 घंटे से घटाकर 60 मिनट कर देती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह रेल-आधारित यात्री प्रणाली है, जिसकी गति 180 किमी प्रति घंटे तक है।

➤ क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम है, जो केंद्र तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का संयुक्त उपक्रम है।

➤ दिल्ली-मेरठ गलियारा यात्रा समय को लगभग 3 घंटे से घटाकर 60 मिनट कर देता है।

➤ ट्रेन संचालकों और स्टेशन नियंत्रण कर्मचारियों में महिलाएँ बहुमत में हैं।

बजट 2026-27: उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजनाएँ

संदर्भ: फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश को सीधे लाभ पहुँचाने वाली कई घोषणाएँ थीं, जिनमें वाराणसी तक उच्च गति रेल तथा सारनाथ और हस्तिनापुर में विरासत स्थलों का विकास शामिल है। सात उच्च गति रेल गलियारों में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं, और वाराणसी तथा पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जाएगा। सारनाथ और हस्तिनापुर विकसित किए जाने वाले 15 पुरातात्विक स्थलों में शामिल हैं।

□ **मुख्य बिंदु**

- सात उच्च गति रेल गलियारों में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं।
- वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- सारनाथ और हस्तिनापुर उन 15 पुरातात्विक स्थलों में शामिल हैं जिन्हें सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के माध्यम से एक जनपद-एक उत्पाद पहल को समर्थन।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और कृषि के प्रथम: एआई क्लिनिक, बासमती फार्म, बरेली हवाई अड्डा

संदर्भ: मार्च 2026 के आसपास उत्तर प्रदेश में नई संस्थाओं और रैंकिंग की चर्चा रही। भारत का पहला सरकारी अस्पताल-आधारित एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के जिम्स (GIMS) में खुला, और एपीडा (APEDA) ने पीलीभीत में भारत के पहले एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन फार्म के लिए 70 वर्ष का पट्टा समझौता किया। बरेली हवाई अड्डा भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर रहा और राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर रहा।

□ **स्वास्थ्य**

- भारत का पहला सरकारी अस्पताल-आधारित एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के जिम्स (GIMS) में खुला।

□ **कृषि**

- एपीडा (APEDA) ने पीलीभीत में भारत के पहले एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन फार्म के लिए 70 वर्ष का पट्टा समझौता किया।

□ **अवसंरचना**

- बरेली हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर रहा और राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर रहा।
- बरेली में राज्य के पहले मीडिया टावर को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश की स्वच्छ वायु योजना के समर्थन हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता।

कालिंजर किले की पहाड़ियाँ राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित

संदर्भ: मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के बाँदा में कालिंजर किले के आसपास की पहाड़ियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित किया गया। यह किला गुप्त काल का है, लगभग चौथी से छठी शताब्दी का, और इसमें मंदिर तथा बावड़ियाँ हैं, जिनमें नीलकंठ मंदिर भी शामिल है।

□ **मुख्य बिंदु**

- यह किला गुप्त काल का है, लगभग चौथी से छठी शताब्दी का।
- इसमें मंदिर और बावड़ियाँ हैं, जिनमें नीलकंठ मंदिर भी शामिल है।

निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर सांसद निधि कार्य: 84% निधि उत्तर प्रदेश को

संदर्भ: मार्च 2026 में एक विश्लेषण में पाया गया कि 21 सांसदों ने अपने राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर ₹18 करोड़ से अधिक के सांसद क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड्स) कार्यों की अनुशंसा की, जिनमें से 84% उत्तर प्रदेश के जिलों को गए। एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रत्येक सांसद प्रति वर्ष ₹5 करोड़ के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है, और सामान्य क्षेत्र के बाहर प्रति वर्ष ₹50 लाख तक के कार्यों की, जिस सीमा को अप्रैल 2023 में संशोधित किया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) नोडल मंत्रालय है।

□ **मुख्य बिंदु**

- प्रत्येक सांसद प्रति वर्ष ₹5 करोड़ के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। सामान्य क्षेत्र के बाहर प्रति वर्ष ₹50 लाख तक के कार्यों की अनुशंसा की जा सकती है (पहले ₹25 लाख, अप्रैल 2023 में संशोधित)।
- एमओएसपीआई नोडल मंत्रालय है; ई-साक्षी पोर्टल अप्रैल 2023 से इस योजना का प्रबंधन कर रहा है।
- मनोनीत सांसद भारत में कहीं भी कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

निवेश मित्र 3.0 और औद्योगिक योजनाएँ

संदर्भ: उत्तर प्रदेश ने 24 मार्च 2026 को नया निवेशक पोर्टल निवेश मित्र 3.0 शुरू किया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया। औद्योगिक स्थान तैयार करने के लिए नई योजनाएँ भी प्रस्तुत की गईं, जैसे उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक पार्क विकास योजना 2025 और प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड योजना। अगस्त 2026 में जेवर के निकट 500 एकड़ के जापान सिटी की योजना बनाई गई।

□ **मुख्य बिंदु**

- UP-जापान निवेश बैठक 2026 (नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026): जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट YEIDA सेक्टर 5A में 500 एकड़ के जापान सिटी की योजना।

□ **शुभारंभ**

➤ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मार्च 2026 को निवेश मित्र 3.0 शुरू किया।

➤ निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने वाला एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।

□ **प्रस्तुत योजनाएँ**

➤ उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक पार्क विकास योजना 2025।

➤ प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड योजना।

उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी संशोधन, 2026

संदर्भ: उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2026 में अंतरिम कदम के रूप में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया। अधिसूचना 17 अप्रैल 2026 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जारी की गई। राज्य को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है, जिनमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद श्रेणी । में हैं, और मजदूरी में मूल राशि तथा परिवर्तनीय महँगाई भत्ता (VDA) शामिल है।

□ **अधिसूचना**

➤ 17 अप्रैल 2026 को 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जारी की गई।

➤ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, संयुक्त प्रांत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की शक्तियों का उपयोग करते हुए।

➤ मजदूरी में मूल राशि तथा परिवर्तनीय महँगाई भत्ता (VDA) होता है।

□ **श्रेणियाँ**

➤ श्रेणी I: गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद।

➤ श्रेणी II: नगर निगम वाले जिले।

➤ श्रेणी III: शेष जिले।

➤ श्रेणी । की मासिक मजदूरी: अकुशल ₹13,690, अर्ध-कुशल ₹15,059, कुशल ₹16,868।

गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई जिले में 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो मेरठ से प्रयागराज तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इसकी आधारशिला दिसंबर 2021 में शाहजहाँपुर में रखी गई थी, और इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर ₹36,230 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है। यह 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिससे यह राज्य की अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण विषय है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 29 अप्रैल 2026 को हरदोई जिले में उद्घाटन किया गया।

➤ आधारशिला 18 दिसंबर 2021 को शाहजहाँपुर में रखी गई; निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ।

➤ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल।

➤ 594 किमी लंबा नियंत्रित-प्रवेश ग्रीनफील्ड गलियारा; छह लेन, जिन्हें आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है; डिज़ाइन गति 120 किमी/घंटा।

➤ अनुमानित लागत ₹36,230 करोड़।

□ **मार्ग**

➤ मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरता है, जैसा कि तालिका में सूचीबद्ध है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर स्थित जिले

क्षेत्र	जिले
पश्चिम	मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल
मध्य	बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली
पूर्व	प्रतापगढ़, प्रयागराज

नवयुग पालिका योजना

संदर्भ: नवयुग पालिका योजना पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित योजना है, जिसे 2026 में छोटे शहरी निकायों को स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाओं से युक्त करने के लिए शुरू किया गया। यह 58 जिला मुख्यालयों के शहरी निकायों को शामिल करती है और 2025-26 से 2029-30 तक पाँच वर्षों के लिए इसका परिव्यय ₹2,916 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई वित्तपोषण नहीं है। यह योजना डिजिटल शासन और ई-सेवाओं को बढ़ावा देती है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 58 जिला मुख्यालयों के शहरी निकायों को शामिल करती है: 55 नगर पालिका परिषदें, तीन नगर पंचायतें और गौतम बुद्ध नगर की दादरी नगर पालिका परिषद।

➤ प्रतिवर्ष ₹583.20 करोड़; पाँच वर्षों (2025-26 से 2029-30) में ₹2,916 करोड़।

➤ केंद्र सरकार का कोई वित्तपोषण नहीं।

➤ डिजिटल शासन और ई-सेवाओं को बढ़ावा देती है।

नोएडा के फैक्ट्री श्रमिकों के प्रदर्शन और वेतन असंतोष

संदर्भ: नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों के बड़े प्रदर्शन कई दिनों बाद हिंसक हो गए, जो उत्तर भारत के औद्योगिक केंद्रों में व्यापक श्रम असंतोष का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर तथा कल्याणकारी उपायों से इसका जवाब दिया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ मुख्य कारण अधिक वेतन की माँग थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पड़ोसी हरियाणा के बीच वेतन का अंतर था।

➤ श्रमिकों ने अनियमित भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान न होने और खराब श्रम मानकों की भी शिकायत की।

- संविदा और अनौपचारिक श्रम सामाजिक सुरक्षा और सौदेबाजी की शक्ति को सीमित करता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया तथा ओवरटाइम और समय पर भुगतान के प्रावधानों में सुधार किया।
- श्रम विवादों से निपटने के लिए विशेष औद्योगिक प्रकोष्ठ बनाए गए और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी की गई।

शेखा झील रामसर स्थल घोषित; उत्तर प्रदेश में अब 12

संदर्भ: अप्रैल 2026 में अलीगढ़ के निकट शेखा झील पक्षी विहार को रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 12 और भारत में कुल 99 हो गई। यह मीठे पानी की झील अलीगढ़ से लगभग 17 किमी दूर है और ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से जुड़ी है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई उड़ान पथ का हिस्सा है।

□ मुख्य बिंदु

- यह उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लगभग 17 किमी दूर है। यह मीठे पानी की झील और पक्षी विहार है, जो ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से जुड़ा है।
- यह प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई उड़ान पथ का हिस्सा है।
- इस जुड़ाव से रामसर स्थलों की राष्ट्रीय संख्या 99 हो गई है।

उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर: पीएम सूर्य घर में अग्रणी

संदर्भ: उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर संस्थापनाओं में देश में अग्रणी है। जून 2026 में, मई 2026 के लिए उत्तर प्रदेश उच्च उपभोक्ता आधार श्रेणी में 64,734 संस्थापनाओं के साथ प्रथम स्थान पर रहा, और अक्टूबर 2026 तक यह 3,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के साथ 9 लाख संस्थापनाओं को पार कर गया। लखनऊ शीर्ष जिला है, इसलिए यह योजना राज्य-स्तरीय ऊर्जा प्रश्नों के लिए एक नियमित विषय है।

□ पुरस्कार (जून 2026)

- उत्तर प्रदेश मई 2026 के लिए उच्च उपभोक्ता आधार श्रेणी में प्रथम रहा: 1,02,035 उपभोक्ता आवेदन, 64,734 संस्थापनाएँ और 779 विक्रेता पंजीकरण।
- लखनऊ शीर्ष जिला है, जिसने 1 लाख संस्थापनाओं को पार किया।
- DISCOM निरीक्षण में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा।

□ अक्टूबर 2026 की स्थिति

- उत्तर प्रदेश ने 3,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के साथ 9 लाख रूफटॉप संस्थापनाओं को पार किया।
- 20 अक्टूबर 2026 तक लगभग 9.14 लाख संस्थापनाएँ, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम।
- लखनऊ में 1.56 लाख से अधिक संस्थापनाएँ दर्ज की गईं।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ और प्रकृति ज्ञान धाम

संदर्भ: वर्ष 2026 में लखनऊ में नई विज्ञान और मौसम संबंधी सुविधाएँ शुरू हुईं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन 8 जून 2026 को जितेंद्र सिंह और योगी आदित्यनाथ ने किया, और यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान प्रदान करता है। प्रकृति ज्ञान धाम, लखनऊ के बंथरा (सीएसआईआर-एनबीआरआई) में स्थित एक पर्यावरण-शैक्षिक केंद्र है, जो अगस्त 2026 में शुरू हुआ।

□ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र

- 8 जून 2026 को जितेंद्र सिंह और योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन।
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- डॉप्लर मौसम रडार 2014 में 17 से बढ़कर जून 2026 में 50 हो गए; मिशन मौसम के अंतर्गत 50 और प्रस्तावित हैं।

□ प्रकृति ज्ञान धाम (अगस्त 2026)

- महर्षि पराशर जैव संसाधन केंद्र, बंथरा, लखनऊ (सीएसआईआर-एनबीआरआई) में स्थित पर्यावरण-शैक्षिक केंद्र।
- इसमें पावन पथ विरासत पथ, दुर्लभ पौधों के लिए विभव एन्क्लेव, राज्य पौधों के लिए भैरव एन्क्लेव और 43 बाँस प्रजातियों वाला बैम्बूसेटम शामिल हैं।

लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग और शहरी अग्नि जोखिम

संदर्भ: जून 2026 में लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर वाली इमारत में लगी आग में कम से कम 15 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई और शहरी अग्नि सुरक्षा की कमियाँ उजागर हुईं। अग्निशमन सेवाएँ अनुच्छेद 243W के अंतर्गत बारहवीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य हैं। 15वें वित्त आयोग ने अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए ₹5,000 करोड़ की सिफारिश की, और भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के स्थान पर राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 लागू किए।

□ मुख्य बिंदु

- अग्निशमन सेवाएँ अनुच्छेद 243W के अंतर्गत बारहवीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य हैं।
- 15वें वित्त आयोग ने अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए ₹5,000 करोड़ की सिफारिश की।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के स्थान पर राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 लागू किए।

लखनऊ: गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर और ईट राइट एयरपोर्ट

संदर्भ: लखनऊ को 2026 में यूनेस्को और एफएसएसएआई की मान्यता मिली। यूनेस्को ने 58 नए रचनात्मक शहर घोषित किए, जिनमें लखनऊ अपनी अवधी पाक विरासत के लिए गैस्ट्रोनॉमी के रचनात्मक शहर के रूप में शामिल हुआ, और लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जून 2026 में तीन-सितारा रेटिंग के साथ भारत का पहला एफएसएसएआई-प्रमाणित ईट राइट कैंपस बना। इस तरह के उत्तर प्रदेश के विषय राज्य-स्तरीय खंड में अपेक्षित रहते हैं।

□ UNESCO

- यूनेस्को ने 58 नए रचनात्मक शहर घोषित किए; लखनऊ अपनी अवधी पाक विरासत के लिए गैस्ट्रोनॉमी के रचनात्मक शहर के रूप में शामिल हुआ।

□ हवाई अड्डा

- लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तीन-सितारा रेटिंग के साथ भारत का पहला एफएसएसएआई-प्रमाणित ईट राइट कैंपस (जून 2026) बना, जो मार्च 2028 तक मान्य है।
- पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने 20 अगस्त 2026 को गोंडा से अपनी पहली 'अवध महाशक्ति' मालगाड़ी चलाई।

सुरहा ताल: भारत का 100वाँ रामसर स्थल

संदर्भ: जून 2026 में उत्तर प्रदेश के बलिया में सुरहा ताल स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार को भारत का 100वाँ रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या 13 हो गई। यह गंगा और घाघरा के संगम के निकट एक प्राकृतिक बारहमासी गोखुर झील है, जो घाघरा के विसर्पण से बनी है, और मध्य एशियाई उड़ान पथ पर प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन आवास है।

□ मुख्य बिंदु

- यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक प्राकृतिक बारहमासी गोखुर झील है।
- यह गंगा और घाघरा के संगम के निकट है और घाघरा के विसर्पण तथा मार्ग परिवर्तन से बनी थी।
- इसे 1991 में 45 गाँवों की भूमि से सुरहा ताल के रूप में समेकित किया गया और 2002 में जय प्रकाश नारायण के नाम पर इसका नाम बदला गया।
- इसका क्षेत्रफल लगभग 3,432 हेक्टेयर है, जो मानसून में बढ़कर लगभग 25,000 हेक्टेयर हो जाता है।
- यह मध्य एशियाई उड़ान पथ पर प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन आवास है।
- उल्लेखनीय मछलियों में संकटग्रस्त (सुभेद्य) वैलागो अट्टू और बैगेरियस बैगेरियस शामिल हैं, और यह सुभेद्य मछुआ बिल्ली (फिशिंग कैट) को भी आकर्षित करती है।
- यह सिंचाई और भूजल पुनर्भरण का स्रोत है।

उत्तर प्रदेश की सामाजिक कल्याण योजनाएँ: पीएमएमवीवाई, विधवा पेंशन, शिक्षक कैशलेस योजना

संदर्भ: वर्ष 2026 के मध्य में उत्तर प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति हुई या उनकी शुरुआत हुई। 31 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026-27 के लिए पीएमएमवीवाई पंजीकरण लक्ष्य का 102.14 प्रतिशत हासिल कर लिया, और मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना 8 जुलाई 2026 को वाराणसी में शुरू की गई, जिसमें प्रति परिवार ₹5 लाख तक का कैशलेस उपचार मिलता है। उत्तर प्रदेश 4,226 जन औषधि केंद्रों के साथ देश में पहले स्थान पर भी है।

□ पीएमएमवीवाई

- 31 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2026-27 के पंजीकरण लक्ष्य का 102.14% हासिल किया: 3,97,567 के लक्ष्य के विरुद्ध 4,06,058।
- डीबीटी के माध्यम से 2,61,369 किस्तों में ₹286.55 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया।
- लाभ: पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में ₹5,000 और दूसरी बालिका के लिए ₹6,000।

□ निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन

- डीबीटी के माध्यम से ₹1,000 प्रति माह, सामान्यतः त्रैमासिक ₹3,000।
- पात्रता: उत्तर प्रदेश का निवासी, आयु 18+ वर्ष, पति की मृत्यु हो चुकी हो, वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख से कम हो।

□ मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना

- 8 जुलाई 2026 को वाराणसी में शुरू; प्रति परिवार ₹5 लाख तक का कैशलेस उपचार।
- अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा बीमा के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता ज्ञापन।

□ जन औषधि

- 30 जून 2026 तक 4,226 जन औषधि केंद्रों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है।
- मार्च 2027 तक 25,000 केंद्रों का राष्ट्रीय लक्ष्य।

उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पुलिसिंग: प्रतिबिंब और ऑपरेशन साइ-वज्र

संदर्भ: उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध डेटा-आधारित उपकरणों और राज्यव्यापी अभियानों का उपयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश

के DGP राजीव कृष्ण ने 7 जुलाई 2026 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में साइबर अपराधियों को पकड़ने और ठगी की गई राशि वापस पाने के लिए ऑपरेशन साइ-वज्र शुरू किया। प्रयागराज पुलिस साइबर अपराध का पता लगाने के लिए प्रतिबिंब प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करती है, और नोएडा ने सितंबर 2026 में ₹217 करोड़ की सेफ सिटी परियोजना की घोषणा की।

□ **ऑपरेशन साइ-वज्र**

➤ 7 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण द्वारा पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में शुरू किया गया।

➤ इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों को पकड़ना, ठगी की गई राशि वापस पाना और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

□ **प्रतिबिंब प्लेटफ़ॉर्म**

➤ प्रयागराज पुलिस द्वारा साइबर अपराध का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

➤ धोखाधड़ी समूहों की पहचान के लिए FIR, मोबाइल टावर डेटा, IP पते, वित्तीय लेनदेन और व्यवहार-प्रतिरूपों को एकीकृत करता है।

□ **सेफ सिटी, नोएडा**

➤ नोएडा प्राधिकरण ने निगरानी, अपराध रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ₹217 करोड़ की सेफ सिटी परियोजना की घोषणा की (सितंबर 2026)।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और स्टार्टअप खरीद योजना

संदर्भ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी, जो एक ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का समर्थन करती है। इसमें निर्वाह भत्ता बढ़ाकर दो वर्षों के लिए ₹20,000 प्रति माह और बीज निधि बढ़ाकर ₹15 लाख की गई। इसके बाद अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप खरीद योजना आई, जिसमें ₹50 लाख तक की एकल-निविदा खरीद की अनुमति है।

□ **स्टार्टअप नीति 2026**

➤ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6 जुलाई 2026 को स्वीकृत।

➤ 1 ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का समर्थन करती है।

➤ निर्वाह भत्ता एक वर्ष के लिए ₹17,500 प्रति माह से बढ़ाकर दो वर्षों के लिए ₹20,000 प्रति माह किया गया।

➤ प्रोटोटाइप अनुदान ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया।

➤ बीज निधि ₹7.5 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख की गई, जिसे असाधारण मामलों में ₹50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।

➤ डीप-टेक स्टार्टअप (AI, रोबोटिक्स, क्वांटम, अंतरिक्ष) प्रोटोटाइप के लिए ₹20 लाख तक और बीज निधि के रूप में ₹30 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं।

□ **उत्तर प्रदेश स्टार्टअप खरीद योजना 2026**

➤ 9 अक्टूबर 2026 को स्वीकृत; शासनादेश 12 अक्टूबर को जारी।

➤ UP स्टार्टअप मिशन नोडल एजेंसी है, और GeM पर एक स्टार्टअप मॉड्यूल है।

➤ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के अंतर्गत DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए खुली है, जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हो या 50% कार्यबल उत्तर प्रदेश में हो।

➤ ₹50 लाख तक की एकल-निविदा खरीद, उदीयमान क्षेत्रकों के लिए ₹1 करोड़।

➤ भुगतान: खरीद आदेश पर 30%, आपूर्ति के बाद 60%, वारंटी के बाद 10%।

कौशल सेतु, कौशल सारथी और कौशल संपर्क

संदर्भ: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) ने वर्ष 2026 में डिजिटल पोर्टल और एक फीडबैक टूल शुरू किया। कौशल सेतु और कौशल सारथी 15 जुलाई 2026 को, विश्व युवा कौशल दिवस पर, लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा शुरू किए गए। कौशल सेतु प्रशिक्षण भागीदारों का कागज रहित पंजीकरण संभव बनाता है, और कौशल संपर्क, एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक पहल, 15 अगस्त 2026 को शुरू की गई।

□ **पोर्टल**

➤ 15 जुलाई 2026 (विश्व युवा कौशल दिवस) को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा शुरू किए गए।

➤ कौशल सेतु: प्रशिक्षण भागीदारों का कागज रहित पंजीकरण और पैनल में शामिल किया जाना।

➤ कौशल सारथी: प्रशिक्षण केंद्रों और पाठ्यक्रमों का जिलावार मानचित्र।

□ **कौशल संपर्क**

➤ UPSDM द्वारा 15 अगस्त 2026 को शुरू की गई क्यूआर कोड पहल।

➤ प्रशिक्षणार्थी केंद्रों पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करके फीडबैक और शिकायतें देते हैं।

□ **माई भारत सम्मेलन**

➤ जुलाई 2026 में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन, जिसे मनसुख मांडविया ने संबोधित किया।

डिजी रोवर भूमि सर्वेक्षण और प्रोजेक्ट गंगा

संदर्भ: उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 के मध्य में प्रौद्योगिकी-आधारित भूमि सर्वेक्षण और एक ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई 2026 को सहारनपुर से डिजी रोवर अभियान शुरू किया, जिसमें सभी तहसीलों में सटीक भूमि माप के लिए जीएनएसएस (GNSS) आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट गंगा (गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट), जो 9

जून 2026 को शुरू हुआ, का लक्ष्य 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों को हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है।

□ **डिजी रोवर अभियान**

➤ 1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सहारनपुर से शुरू किया गया।

➤ 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक सभी तहसीलों में चलेगा।

➤ सटीक भूमि माप के लिए जीएनएसएस (GNSS) आधारित डिजी रोवर उपकरणों का उपयोग।

□ **प्रोजेक्ट गंगा**

➤ गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, 9 जून 2026 को शुरू।

➤ 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों को हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

➤ न्याय पंचायत स्तर पर 8,000-10,000 डिजिटल सेवा प्रदाता, जिनमें लगभग आधी महिलाएँ।

➤ ब्रांड नाम: गंगा फाइबर।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

संदर्भ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 21 जुलाई 2026 को ₹400 करोड़ के बजट के साथ रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मेधावी स्नातक महिलाओं को निःशुल्क स्कूटर देना है। इसमें 50,000 लाभार्थी शामिल हैं: वर्ष 2025-26 में स्नातक करने वाली उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाएँ, जो शीर्ष 5 प्रतिशत में हों और जिनकी पारिवारिक आय ₹2 लाख तक हो। स्कूटरों की खरीद जेम (GeM) के माध्यम से की जाती है और उन्हें बेचा नहीं जा सकता।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 21 जुलाई 2026 को मंत्रिमंडल द्वारा ₹400 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत।

➤ 50,000 लाभार्थी: वर्ष 2025-26 में स्नातक करने वाली उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाएँ, जो शीर्ष 5% में हों और जिनकी पारिवारिक आय ₹2 लाख तक हो।

➤ लाभ: निःशुल्क स्कूटर, आरटीओ पंजीकरण, बीमा, आईएसआई हेलमेट, सहायक सामग्री और 4 लीटर पेट्रोल।

➤ दिव्यांग, निराश्रित या शहीदों की पुत्रियों को अंकों में 10% तक की छूट मिलती है।

➤ जेम (GeM) के माध्यम से खरीद; स्कूटरों को बेचा नहीं जा सकता।

राम मंदिर दान प्रबंधन और बार का बहिष्कार

संदर्भ: अयोध्या में राम मंदिर की दान प्रणाली में गबन के आरोपों ने पारदर्शी मंदिर वित्त पर बहस छेड़ दी है। अयोध्या (फैजाबाद) बार एसोसिएशन ने भी प्रस्ताव पारित किया कि कोई सदस्य आठ अभियुक्तों का बचाव नहीं करेगा, और ऐसा करने वाले किसी भी वकील पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया, जिससे संवैधानिक प्रश्न उठे।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ कई पुराने प्रमुख मंदिर समर्पित कानूनों के अंतर्गत चलते हैं, जबकि राम मंदिर न्यास विलेख के अंतर्गत कार्य करता है और अनिवार्य सरकारी लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं है।

➤ कानूनों के उदाहरण: तिरुमला-आंध्र प्रदेश धर्मार्थ एवं हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम; श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम; जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ अधिनियम; उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम।

➤ सुझाए गए सुधारों में वार्षिक स्वतंत्र लेखा-परीक्षा, वास्तविक समय डिजिटल लेखांकन, यूपीआई दान, कीमती वस्तुओं की आरएफआईडी टैगिंग, सीसीटीवी, प्रकाशित लेखा-परीक्षित विवरण और व्हिसलब्लोअर माध्यम शामिल हैं।

लखनऊ में भारत का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग

संदर्भ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के कमांड अस्पताल (मध्य कमान) में, चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) के अंतर्गत, भारत के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ इसका उद्देश्य युद्धकालीन चिकित्सा तत्परता, अनुसंधान और स्वदेशी सिद्धांतों को सुदृढ़ करना है।

➤ इसकी शुरुआत शैक्षणिक कार्यक्रमों से होगी और बाद में मानवीय सहायता, आपदा राहत तथा सीबीआरएनई रक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र जोड़े जाएँगे।

➤ इसमें आघात देखभाल, युद्ध मनोचिकित्सा और युद्धक्षेत्र चिकित्सा शामिल हैं, जिनमें एआई, पहनने योग्य उपकरणों और पूर्वानुमान विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में रक्षा: एके-203 शेर, ड्रोन हब और अग्निवीर आरक्षण

संदर्भ: वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश में रक्षा विनिर्माण और भर्ती से जुड़े घटनाक्रम हुए। पहली 100 प्रतिशत स्वदेशीकृत एके-203 'शेर' असॉल्ट राइफल का परीक्षण-फायर अगस्त 2026 में किया गया, जिसे अमेठी की कोरवा आयुध निर्माणी में इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। सितंबर 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने परिवहन प्रवर्तन आरक्षी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी दी।

□ **एके-203 शेर**

➤ पहली 100% स्वदेशीकृत एके-203 'शेर' असॉल्ट राइफल का अगस्त 2026 में परीक्षण-फायर किया गया।

➤ अमेठी की कोरवा आयुध निर्माणी में इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित।

□ **राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब**

➤ आईआईटी कानपुर में प्रस्तावित; 14 अक्टूबर 2026 को राजनाथ सिंह ने कहा कि मंजूरी अंतिम चरण में है।

□ **पूर्व अग्निवीर**

➤ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2026 को परिवहन प्रवर्तन आरक्षी पदों में 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी।

➤ चार वर्ष की सेवा के बाद तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट।

परिछा बैराज को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता

संदर्भ: अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग (ICID) ने झाँसी के 140 वर्ष पुराने परिछा बैराज को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी। यह पुरस्कार 14 अक्टूबर 2026 को मार्सिले में 26वीं आईसीआईडी कांग्रेस में प्रदान किया गया। यह बैराज बेतवा नदी पर बना है, 1,174 मीटर लंबा है और बुंदेलखंड में सिंचाई में सहायक है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ बेतवा नदी पर निर्मित; 1,174 मीटर लंबा; बुंदेलखंड की सिंचाई में सहायक।

➤ अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग द्वारा विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता प्राप्त।

➤ 14 अक्टूबर 2026 को मार्सिले में 26वीं आईसीआईडी कांग्रेस में पुरस्कार।

बुलंदशहर मामले से पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पर निर्णय

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपराधों की स्वतंत्र रूप से जाँच नहीं कर सकती, भले ही वे संज्ञेय हों। यह मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अस्पताल में कथित अवैध लिंग निर्धारण से उत्पन्न हुआ।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ यह अधिनियम लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित करता है; 2003 के संशोधन ने गर्भधारण-पूर्व लिंग चयन को जोड़ा।

➤ जिला मजिस्ट्रेट ने, समुचित प्राधिकारी के रूप में, डिकॉय ऑपरेशन, छापे और प्राथमिकी को अधिकृत किया; अभियुक्तों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आरोपपत्र को चुनौती दी।

➤ न्यायालय ने कहा कि जाँच का अधिकार धारा 17 के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी के पास है।

➤ मजिस्ट्रेट केवल पुलिस आरोपपत्र के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकता; धारा 28 के अंतर्गत शिकायत आवश्यक है।

➤ पुलिस उसी घटना से जुड़े भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के अलग अपराधों की जाँच अब भी कर सकती है।

➤ समुचित प्राधिकारी में अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक, किसी महिला संगठन की एक प्रतिष्ठित महिला और विधि विभाग का एक अधिकारी शामिल होते हैं।

पीसी-पीएनडीटी निर्णय

मुद्दा	निर्णय
जाँच कौन करता है	समुचित प्राधिकारी (धारा 17)
न्यायालय का संज्ञान	धारा 28 के अंतर्गत शिकायत मार्ग
अलग भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता अपराध	पुलिस जाँच कर सकती है

लखनऊ के आयोजन: नौसेना शौर्य वाटिका और ब्रिक्स सांख्यिकी बैठक

संदर्भ: लखनऊ ने वर्ष 2026 में रक्षा विरासत और ब्रिक्स से जुड़े आयोजनों की मेजबानी की। सेवामुक्त युद्धपोत आईएनएस गोमती पर केंद्रित नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन 30 मई 2026 को राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने किया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स एनएसओ प्रमुखों की बैठक वहीं 3-4 अगस्त 2026 को हुई, और मई में फल सम्मेलन, फ्रूट होराइजन 2026, आयोजित हुआ।

□ **नौसेना शौर्य वाटिका**

➤ 30 मई 2026 को राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन।

➤ मुख्य आकर्षण: सेवामुक्त युद्धपोत आईएनएस गोमती।

□ **ब्रिक्स एनएसओ प्रमुखों की बैठक**

➤ भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 3-4 अगस्त 2026 को लखनऊ में आयोजित।

➤ सांख्यिकी ट्रैक की थीम: परिवर्तन के वाहक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी।

□ **फ्रूट होराइजन 2026**

➤ उत्तम गुणवत्ता के फल उत्पादन और निर्यात पर 6-7 मई 2026 को लखनऊ में सम्मेलन।

सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित

संदर्भ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया। यह भारत की 45वीं और उत्तर प्रदेश की चौथी विश्व धरोहर संपत्ति है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, दिया; लुंबिनी जन्म, बोधगया ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर महापरिनिर्वाण का स्थल है। इस स्थल को ऋषिपत्तन, इसिपतन और मृगदाव के नाम से जाना जाता था।

➤ सारनाथ 1998 से भारत की अस्थायी सूची में था और नामांकन जनवरी 2025 में प्रस्तुत किया गया था।

➤ भारत की 45 संपत्तियों में 37 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल हैं; भारत विश्व में छठे स्थान पर है।

➤ उत्तर प्रदेश के अन्य स्थल ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी हैं।

➤ इस अंकन में चौखंडी स्तूप और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं, जिनमें धमेख स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, मूलगंधकुटी विहार और अशोक स्तंभ आते हैं।

➤ इसे मानदंड (iii) और (vi) के अंतर्गत अंकित किया गया।

➤ लुंबिनी, बोधगया और सारनाथ अब सूचीबद्ध हैं; कुशीनगर नहीं है।

➤ यह लगभग सोलह शताब्दियों में विकसित हुआ, चौथी-तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक।

➤ यहाँ से प्राप्त अशोक का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय चिह्न है, जिसमें चार सिंह, 24 तीलियों वाला चक्र और फलक पर हाथी, बैल, घोड़ा तथा सिंह हैं।

➤ सारनाथ कला शैली गुप्त काल में चुनार के हल्के पीले बलुआ पत्थर का उपयोग करते हुए फली-फूली।

➤ ह्वेनसांग और फाह्यान ने इस स्थल का वर्णन किया; सारनाथ में 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जैन मंदिर भी है।

□ **यूनेस्को सूची**

➤ जुलाई 2026 तक 173 देशों में 1,273 संपत्तियाँ हैं: 991 सांस्कृतिक, 240 प्राकृतिक और 42 मिश्रित।

उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में अग्रणी; विजिट माई स्टेट और नीम करोली सर्किट

संदर्भ: पर्यटन डेटा संकलन 2026 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वर्ष 2025 में महाकुंभ सहित 155.74 करोड़ पर्यटक यात्राओं के साथ घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष पर रहा। इसके बाद नई पहलें हुईं, जैसे 13 मई 2026 को शुरू की गई विजिट माई स्टेट, जिसमें बच्चों और परिवारों के लिए संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश है। सितंबर 2026 में नीम करोली बाबा सर्किट भी शुरू किया गया, जो चार स्थलों को जोड़ता है।

□ **पर्यटन डेटा संकलन 2026**

➤ उत्तर प्रदेश वर्ष 2025 में महाकुंभ सहित 155.74 करोड़ घरेलू यात्राओं के साथ प्रथम स्थान पर रहा।

➤ इसके बाद: तमिलनाडु 36.30 करोड़, आंध्र प्रदेश 35.39 करोड़, पश्चिम बंगाल 29.43 करोड़।

➤ प्रमुख केंद्र: अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, विंध्याचल।

□ **विजिट माई स्टेट**

➤ 13 मई 2026 को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा शुरू किया गया।

➤ राज्य संग्रहालय दो महीने तक बच्चों और परिवारों को निःशुल्क प्रवेश देते हैं।

□ **नीम करोली बाबा सर्किट**

➤ सितंबर 2026 में शुरू, चार स्थलों को जोड़ता है: अकबरपुर (फिरोजाबाद, जन्मस्थान), नीम करोली आश्रम (फर्रुखाबाद), हनुमान सेतु मंदिर (लखनऊ) और समाधि मंदिर (वृंदावन)।

□ **थारू संग्रहालय**

➤ थारू जनजाति संग्रहालय, इमलिया कोडर, बलरामपुर ने आईसीआरटी भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता।

लखनऊ में रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण

संदर्भ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान को श्रद्धांजलि दी। वे 1831 से 1858 तक जीवित रहीं और वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित रामगढ़ की रानी थीं, जो अपने नाबालिग पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन करती थीं। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रखे जाने को अस्वीकार कर दिया, जिससे यह 1857 और उत्तर प्रदेश से जुड़ा संभावित प्रश्न बन जाता है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ वे 1831 से 1858 तक जीवित रहीं और वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित रामगढ़ की रानी थीं। अपने पति राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी के बीमार पड़ने और निधन के बाद उन्होंने अपने नाबालिग पुत्रों की ओर से रानी-संरक्षिका के रूप में शासन किया।

➤ अंग्रेजों ने रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रख दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

➤ 1857 में उन्होंने लगभग 4,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया और मंडला के निकट खेरी के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया।

➤ मार्च 1858 में पराजय का सामना करते हुए उन्होंने बलिदान दे दिया।

9 अक्टूबर 2026 के उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय: खरीद और माफी

संदर्भ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 9 अक्टूबर 2026 को कई निर्णय लिए, जिनमें धान और मोटे अनाज की खरीद नीतियों तथा कर ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी गई। सामान्य श्रेणी के धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, जिसका लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन है। मंत्रिमंडल ने तीन वर्षों में ₹1,725 करोड़ की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को भी मंजूरी दी।

□ **धान खरीद 2026-27**

➤ MSP सामान्य श्रेणी ₹2,441 प्रति क्विंटल और ग्रेड-A ₹2,461।

➤ लगभग 4,500 केंद्रों और आठ एजेंसियों के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य।

➤ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक।

➤ किसानों को 48 घंटों के भीतर भुगतान।

□ **मोटे अनाज 2026-27**

➤ खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक।

➤ MSP: मक्का ₹2,410, बाजरा ₹2,900, संकर ज्वार ₹4,023, मालदंडी ज्वार ₹4,073 प्रति क्विंटल।

➤ लक्ष्य: बाजरा 2.20 लाख मीट्रिक टन (33 जिले), ज्वार 50,000 मीट्रिक टन (13 जिले), मक्का 15,000 मीट्रिक टन (25 जिले)।

➤ बायोमेट्रिक सत्यापन और सीधा बैंक भुगतान।

□ **ब्याज माफी योजना 2026**

➤ 9 अक्टूबर को स्वीकृत, 16 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित; 31 दिसंबर 2025 तक के कर बकाया को शामिल करती है।

➤ माफी: ₹10 लाख तक के मूलधन पर 100%; ₹10 लाख-1 करोड़ पर 90%; ₹1-5 करोड़ पर 75%; ₹5 करोड़ से अधिक पर 50%।

➤ 75 जिलों में तीन महीने के लिए मान्य।

□ **कौशल क्षेत्र योजना**

➤ सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना: तीन वर्षों में ₹1,725 करोड़।

UP AI मिशन (UP-AIM) और लखनऊ AI सिटी

संदर्भ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 9 अक्टूबर 2026 को पाँच वर्षीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) को मंजूरी दी, जिसका 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹2,000 करोड़ का परिव्यय है। इसका लक्ष्य 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना, कम से कम 100 AI स्टार्टअप को सहयोग देना और सभी 75 जिलों में जिला AI केंद्र स्थापित करना है। जनवरी 2026 में लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन के बाद लखनऊ को AI सिटी के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ राष्ट्रीय AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की पूर्वपीठिका के रूप में 12-13 जनवरी 2026 को लखनऊ में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन आयोजित किया गया। लखनऊ को AI सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है: लगभग ₹10,732 करोड़ की योजना, जिसमें 10,000 GPU, बहुविध (मल्टीमॉडल) भाषा मॉडल, AI नवाचार केंद्र और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ शामिल हैं।

➤ 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना और 50,000 AI पेशेवर तैयार करना।

➤ कम से कम 100 AI स्टार्टअप को सहयोग देना और 100 से अधिक AI-आधारित समाधान विकसित करना।

□ **अनुमोदन और परिव्यय**

➤ 9 अक्टूबर 2026 को 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹2,000 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय के साथ स्वीकृत।

➤ पहले वर्ष 2026-27 के लिए ₹225 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

➤ यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत संचालित होता है।

□ **घटक**

➤ सभी 75 जिलों में जिला AI केंद्र प्रस्तावित हैं।

➤ प्रत्येक जिले में एक AI फेलो, जिसे एक वर्ष तक ₹40,000 प्रति माह दिए जाएँगे।

➤ 200 से अधिक AI कौशल प्रयोगशालाएँ, जिनका लक्ष्य 1 लाख तकनीकी शिक्षार्थियों को प्रमाणित करना है।

भदोही: इंडिया कार्पेट एक्सपो और नाम परिवर्तन योजना

संदर्भ: स्वर्ण जयंती 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2026 को भदोही के कार्पेट एक्सपो मार्ट में हुआ, और इस अवसर पर जिले का नाम बदलने की घोषणा की गई। भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ₹1,340 करोड़ से अधिक की 112 परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया, और मिर्जापुर में एक यार्न प्रसंस्करण संयंत्र की घोषणा की गई।

□ **इंडिया कार्पेट एक्सपो**

➤ 50वें संस्करण का 4 अक्टूबर 2026 को भदोही के कार्पेट एक्सपो मार्ट में उद्घाटन।

➤ मुख्यमंत्री ने ₹1,340 करोड़ से अधिक की 112 परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया।

□ **नाम परिवर्तन**

➤ भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही किया जाएगा।

□ **मिर्जापुर यार्न संयंत्र**

➤ कालीन उद्योग की सेवा के लिए मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जाएगा।

वाराणसी में भारतीय वायुसेना का विंग्स ओवर गंगा एयर शो

संदर्भ: भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर 2026 में अपनी 94वीं वर्षगाँठ वाराणसी के नमो घाट पर एक एयर शो के साथ मनाई। 'विंग्स ओवर गंगा' नामक तीन दिवसीय शो गंगा के ऊपर 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुआ। वर्षगाँठ की थीम थी: अचूक, अभेद्य और सटीक।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ गंगा के ऊपर 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को तीन दिवसीय शो।

➤ शीर्षक: विंग्स ओवर गंगा।

➤ वर्षगाँठ की थीम: अचूक, अभेद्य और सटीक।

सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति, 2026

संदर्भ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 9 अक्टूबर 2026 को सतत विमानन ईंधन (SAF) विनिर्माण नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य को कृषि अवशेषों से बने SAF का केंद्र बनाना है। कच्चे माल में धान की भूसी, गेहूँ का भूसा और गन्ने की खोई शामिल हैं, और UPNEDA नोडल एजेंसी है। नीति पाँच वर्षों के लिए वैध है और स्टांप शुल्क में राहत तथा विद्युत शुल्क में छूट जैसे प्रोत्साहन देती है।

□ **मुख्य बिंदु**

➤ 9 अक्टूबर 2026 को स्वीकृत।

➤ कच्चा माल: धान की भूसी, गेहूँ का भूसा और गन्ने की खोई।

➤ UPNEDA नोडल एजेंसी है; पाँच वर्षों के लिए वैध।

➤ प्रोत्साहन: स्टांप शुल्क में राहत, ब्याज अनुदान, SGST की प्रतिपूर्ति और 10 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क में छूट।

पूंजी निवेश के आधार पर इकाइयों का वर्गीकरण

श्रेणी	निवेश
वृहद	₹200-500 करोड़
मेगा	₹500-1,500 करोड़
अल्ट्रा-मेगा	₹1,500 करोड़ से अधिक

255 समसामयिकी MCQ

उत्तर कुंजी सहित अभ्यास प्रश्न

अध्याय 1: राजव्यवस्था, शासन एवं न्यायपालिका

1. 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की?

(A) वाई वी रेड्डी
(B) एन के सिंह
(C) अरविंद पनगढ़िया
(D) विजय केलकर

2. 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए विभाज्य पूल का कितना हिस्सा निर्धारित किया (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण)?

(A) 40 प्रतिशत
(B) 41 प्रतिशत
(C) 42 प्रतिशत
(D) 45 प्रतिशत

3. 2022 के परिसीमन आयोग के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से कश्मीर में कितनी हैं?

(A) 43
(B) 45
(C) 50
(D) 47

4. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या कितनी है?

(A) 34
(B) 38
(C) 35
(D) 40

5. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है, जैसा केरल से केरलम के लिए किया गया?

(A) अनुच्छेद 3
(B) अनुच्छेद 2
(C) अनुच्छेद 4
(D) अनुच्छेद 368

6. भारत की प्रथम समकालिक जनगणना, 1881, किसके अधीन संपन्न हुई थी?

(A) लॉर्ड मेयो
(B) एच एच रिज़ले
(C) जे एच हटन
(D) डब्ल्यू सी प्लाउडन

7. भारत ने किस वर्ष लैंगिक बजटिंग को औपचारिक रूप से अपनाया?

(A) 2000-01
(B) 2004-05
(C) 2010-11
(D) 1996-97

8. प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए PRAGATI प्लेटफ़ॉर्म किस वर्ष शुरू किया गया था?

(A) 2015
(B) 2014
(C) 2016
(D) 2017

9. पोषण अभियान का लक्ष्य प्रति वर्ष एनीमिया को कितना कम करना है?

(A) 1 प्रतिशत
(B) 2 प्रतिशत
(C) 3 प्रतिशत
(D) 5 प्रतिशत

10. उल्लास योजना किस आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों के लिए है?

(A) 15 वर्ष और उससे अधिक
(B) 6 वर्ष और उससे अधिक
(C) 18 वर्ष और उससे अधिक
(D) 14 वर्ष और उससे अधिक

11. PGI 2.0, 2025-26 में कौन-सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष प्रदर्शनकर्ता रहा, जो उत्तम-3 ग्रेड में एकमात्र था?

(A) केरल
(B) दिल्ली
(C) चंडीगढ़
(D) पंजाब

12. अमरावती राजधानी कानून किस तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव रखता है?

(A) 1 अप्रैल 2024
(B) 2 जून 2024
(C) 15 अगस्त 2024
(D) 26 जनवरी 2025

13. लेख के अनुसार 2026 में भारत की कितनी जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थी?

(A) 19.0 प्रतिशत
(B) 50.2 प्रतिशत
(C) 68.4 प्रतिशत
(D) 90.0 प्रतिशत

14. संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 में राज्यों से लोकसभा सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या का प्रावधान था?

(A) 815
(B) 530
(C) 850
(D) 550

15. वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं और सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
2. अनुच्छेद 275 भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

16. परिसीमन आयोग के आदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्हें किसी भी न्यायालय में बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से चुनौती दी जा सकती है।
2. वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

17. भारत में जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनगणना संघ सूची का विषय है और जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित है।
2. जनसंख्या गणना प्रथम चरण है और मकान सूचीकरण द्वितीय चरण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

18. ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के प्रावधान को बनाए रखता है।
2. चिकित्सा बोर्ड की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

19. लोकसभा में सीटों के स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 42वें संशोधन (1976) ने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के आवंटन को स्थिर कर दिया।
2. 84वें संशोधन (2001) ने इस स्थिरीकरण को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

20. अनुच्छेद 3 के विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।
2. राष्ट्रपति विधेयक पर राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

21. सर्वोच्च न्यायालय की संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1950 में न्यायाधीशों की संख्या 11 थी।
2. 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 34 थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

22. उल्लास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
2. यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों के लिए है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

23. निम्नलिखित में से कौन-सा 16वें वित्त आयोग द्वारा क्षैतिज हस्तांतरण के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है?

(A) आय अंतर
(B) जनसांख्यिकीय प्रदर्शन
(C) GDP में योगदान
(D) कर या राजकोषीय प्रयास

24. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रहार आतंकवाद-रोधी रणनीति के सात स्तंभों में से एक नहीं है?

(A) खुफिया-आधारित रोकथाम
(B) कट्टरता-उन्मूलन और सामुदायिक सहभागिता
(C) पुनर्प्राप्ति और सहनशीलता
(D) पड़ोसी राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध

25. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(A) अनुच्छेद 270 - करों का विभाज्य पूल
(B) अनुच्छेद 275 - विवेकाधीन अनुदान
(C) अनुच्छेद 282 - करों का विभाज्य पूल
(D) अनुच्छेद 81 - प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन

26. परिसीमन आयोग निम्नलिखित सभी वर्षों में गठित किए गए हैं, सिवाय:

(A) 1952
(B) 1963
(C) 2002
(D) 1991

27. निम्नलिखित में से कौन-सा जनगणना डिजिटल उपकरण सही सुमेलित नहीं है?

(A) HLBC - मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करता है
(B) HLO ऐप - गणनाकारों के लिए ऑफ़लाइन ऐप
(C) SE पोर्टल - SE ID उत्पन्न करता है
(D) CMMS - गणनाकारों के लिए ऑफ़लाइन मोबाइल ऐप

28. 2025 में संशोधित राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

(A) खेलों में डोपिंग-रोधी राष्ट्रीय बोर्ड सलाहकारी और पर्यवेक्षी है
(B) NADA तलाशी और जब्ती की शक्तियों वाला एक सांविधिक निकाय है
(C) 2025 के संशोधन के बाद अपील पैनल का गठन राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है
(D) CrPC के संदर्भों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है

29. 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की, जिसकी पंचाट अवधि 2026-27 से 2030-31 तक है?

(A) डॉ. अरविंद पनगढ़िया
(B) टी रबी शंकर
(C) मनोज पांडा
(D) सौम्य कांति घोष

30. 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत पर रखा गया है।
2. जनसंख्या की गणना 2011 की जनगणना के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

31. निम्नलिखित में से कौन मार्च 2026 में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO द्वारा सत्यापित किए जाने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बना?

(A) ब्राज़ील
(B) चिली
(C) मेक्सिको
(D) पेरू

32. 7 अक्टूबर 2026 को घाना के शामिल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के अब कितने सदस्य देश हैं?

(A) 25
(B) 27
(C) 29
(D) 31

33. भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 5 मई 2026 को स्वीकृत दो और परियोजनाएँ, जिनसे कुल स्वीकृत परियोजनाएँ 12 हो गईं, किस राज्य में स्थित हैं?

(A) गुजरात
(B) असम
(C) तमिलनाडु
(D) उत्तर प्रदेश

34. सुखना आर्द्रभूमि के शामिल होने से किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को अपना पहला रामसर स्थल मिला?

(A) हरियाणा
(B) पंजाब
(C) चंडीगढ़
(D) हिमाचल प्रदेश

35. भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है।
2. मैनपुरी की सौज झील उत्तर प्रदेश का 14वाँ रामसर स्थल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

36. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन-सा है?

(A) चिल्का झील
(B) सुंदरबन आर्द्रभूमि
(C) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
(D) वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर

37. उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजकोषीय घाटा GSDP के कितने प्रतिशत पर रखा गया?

(A) 2 प्रतिशत
(B) 3 प्रतिशत
(C) 3.5 प्रतिशत
(D) 4 प्रतिशत

38. भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन-सेल यात्री जलयान (वॉटर टैक्सी) किस स्थान से संचालित होता है?

(A) दशाश्वमेध घाट, वाराणसी
(B) नमो घाट, वाराणसी
(C) संगम, प्रयागराज
(D) गुप्तार घाट, अयोध्या

39. 29 अप्रैल 2026 को उद्घाटित 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया?

(A) मेरठ
(B) शाहजहाँपुर
(C) हरदोई
(D) प्रयागराज

40. उत्तर प्रदेश की सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कच्चे माल में धान की भूसी, गेहूँ का भूसा और गन्ने की खोई शामिल हैं।
2. UPNEDA नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

41. ICID द्वारा विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता प्राप्त परिछा बैराज झाँसी में किस नदी पर बना है?

(A) केन
(B) बेतवा
(C) धसान
(D) यमुना

42. जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कितनी महिला स्नातकों को निःशुल्क स्कूटर दिए जाने हैं?

(A) 10,000
(B) 25,000
(C) 50,000
(D) 1,00,000

अध्याय 2: अंतरराष्ट्रीय समाचार

43. नई दिल्ली में उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक (Responsible Nations Index - RNI) किस संगठन ने जारी किया?

(A) वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन
(B) नीति आयोग
(C) विश्व आर्थिक मंच
(D) ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

44. उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी?

(A) छठा
(B) 16वाँ
(C) 36वाँ
(D) 66वाँ

45. गाजा के लिए शांति बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किस प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त है?

(A) प्रस्ताव 2231 (2015)
(B) प्रस्ताव 1973 (2011)
(C) प्रस्ताव 2803 (2025)
(D) प्रस्ताव 2758 (2024)

46. सेशेल्स के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स के लिए कितने के पैकेज की घोषणा की?

(A) 7.5 करोड़ डॉलर
(B) 27.5 करोड़ डॉलर
(C) 50 करोड़ डॉलर
(D) 17.5 करोड़ डॉलर

47. हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 2008
(B) 1998
(C) 2001
(D) 2015

48. न्यू स्टार्ट संधि के अंतर्गत आयुध (वारहेड) की सीमा क्या है?

(A) 800
(B) 1,700
(C) 1,550
(D) 6,000

49. नई दिल्ली में 2026 के एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के बाद 2027 का एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा?

(A) पेरिस, फ्रांस
(B) सियोल, दक्षिण कोरिया
(C) ब्लेचली पार्क, यूके
(D) जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

50. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ओपेक में किस वर्ष शामिल हुआ?

(A) 1960
(B) 1967
(C) 1973
(D) 1975

51. प्रेस नोट 3 में आंशिक ढील के अंतर्गत, FDI प्रस्तावों का कितने दिनों के भीतर निपटारा किया जाना है?

(A) 30 दिन
(B) 45 दिन
(C) 60 दिन
(D) 90 दिन

52. 14वाँ विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) किस शहर में बिना आम सहमति के समाप्त हुआ?

(A) याउंडे, कैमरून
(B) जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
(C) अबू धाबी, यूएई
(D) नैरोबी, केन्या

53. न्यू स्टार्ट संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस पर 2010 में ओबामा और मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे।
2. इसने आयुधों की सीमा 1,550 निर्धारित की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

54. WTO MC14 के विकास के लिए निवेश सुविधा (IFD) समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे 166 सदस्यों में से 129 का समर्थन प्राप्त था।
2. केवल चीन ने इसे WTO में शामिल किए जाने से रोका।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

55. भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यूरोपीय संघ और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए समझौतों में डेयरी को शामिल किया गया था।
2. भारतीय निर्यातकों द्वारा FTA का उपयोग कम है, 5 से 25 प्रतिशत के बीच।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

56. प्रेस नोट 3 (2020) में आंशिक ढील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमि-सीमा वाले देशों से 10% तक लाभकारी स्वामित्व की अनुमति स्वचालित मार्ग से है।
2. अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) जैसे संवेदनशील क्षेत्र प्रतिबंधित बने रहेंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

57. सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सेशेल्स कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का सातवाँ सदस्य बनेगा।
2. सेशेल्स ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल होने से इनकार कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

58. उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक (RNI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे केवल विश्व आर्थिक मंच ने विकसित किया।
2. सूचकांक में भारत पहले स्थान पर रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

59. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) के अंतर्गत शामिल नहीं है?

(A) सीमेंट
(B) एल्युमीनियम
(C) उर्वरक
(D) वस्त्र

60. वाशिंगटन डीसी में महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में शुरू किया गया FORGE किस पूर्ववर्ती समूह का स्थान लेता है?

(A) पैक्स सिलिका
(B) प्रोजेक्ट वॉल्ट
(C) खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)
(D) हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF)

61. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(A) भारत-यूके CETA - दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित
(B) भारत-ओमान CEPA - दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित
(C) भारत-EFTA TEPA - जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित
(D) भारत-यूरोपीय संघ FTA - मार्च 2024 में संपन्न

62. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रधानमंत्री मोदी की इज़राइल यात्रा का परिणाम नहीं है?

(A) पाँच वर्षों में अधिकतम 50,000 भारतीय कामगारों का कोटा
(B) भारत-इज़राइल मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
(C) इज़राइल में UPI को सक्षम बनाने का समझौता
(D) भारत में साइबर सुरक्षा में भारत-इज़राइल उत्कृष्टता केंद्र

63. निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो वर्ष का अस्थायी कार्यकाल आरंभ किया?

(A) अल्जीरिया
(B) बहरीन
(C) स्लोवेनिया
(D) गुयाना

64. भारत और IMO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत 2026-27 के लिए IMO परिषद में श्रेणी ख में पुनः निर्वाचित हुआ।
2. श्रेणी ख में अंतरराष्ट्रीय नौवहन सेवाएँ प्रदान करने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले राज्य शामिल हैं।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

65. कौन-सा देश 10 दिसंबर 2025 से प्रभावी, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना?

(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) ऑस्ट्रेलिया
(C) कनाडा
(D) न्यूज़ीलैंड

66. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बांग्लादेश ने अप्रैल 2026 में अपने पहले परमाणु संयंत्र में यूरेनियम ईंधन डालना आरंभ किया।
2. NIPL ने कंबोडिया में UPI शुरू करने के लिए ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

67. जुलाई 2026 में विशाखापत्तनम के बाद 18 मीटर ड्राफ्ट की सुविधा देने वाला दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन-सा बना?

(A) कामराजर बंदरगाह
(B) दीनदयाल बंदरगाह
(C) पारादीप बंदरगाह
(D) मोरमुगाओ बंदरगाह

68. सितंबर 2026 में भारत के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई?

(A) कांडला (दीनदयाल बंदरगाह)
(B) कोच्चि
(C) तूतीकोरिन
(D) हल्दिया

69. मई 2026 में कौन-सा राज्य भारत में स्वतंत्र एआई विभाग बनाने वाला पहला राज्य बना?

(A) कर्नाटक
(B) तेलंगाना
(C) केरल
(D) आंध्र प्रदेश

70. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महाराष्ट्र जनवरी 2026 में समर्पित रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) क्लिनिक खोलने वाला पहला राज्य बना।
2. भारत का पहला एलपीजी एटीएम मार्च 2026 में गुरुग्राम में बीपीसीएल द्वारा स्थापित किया गया।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

71. नवंबर 2025 में घोषित ओंकारेश्वर अभयारण्य मध्य प्रदेश का कौन-सा अभयारण्य है?

(A) 25वाँ
(B) 26वाँ
(C) 27वाँ
(D) 28वाँ

72. जुलाई 2026 में तिनसुकिया के छोटा तिंग्राई एस्टेट में माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन-सा बना?

(A) पश्चिम बंगाल
(B) असम
(C) सिक्किम
(D) तमिलनाडु

73. अक्टूबर 2026 में लद्दाख का आठवाँ जिला कौन-सा बना?

(A) द्रास
(B) नुब्रा
(C) सांकू
(D) ज़ांस्कर

74. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लेबनान अगस्त 2026 में मृत्युदंड समाप्त करने वाला पहला अरब देश बना।
2. पुतिन ने अगस्त 2026 में कुरील द्वीप समूह की पहली आधिकारिक यात्रा की, जो रूस द्वारा प्रशासित हैं परंतु जिन पर जापान दावा करता है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

75. निम्नलिखित में से कौन-सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2026 का विषय-आधारित 'अंतरराष्ट्रीय वर्ष' है?

(A) अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष
(B) अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता वर्ष
(C) अंतरराष्ट्रीय सतत एवं सहनशील पर्यटन वर्ष
(D) अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष

अध्याय 3: अर्थव्यवस्था

76. भारत के 18वें रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे, का मुख्यालय किस राज्य में अधिसूचित किया गया है?

(A) तेलंगाना
(B) ओडिशा
(C) तमिलनाडु
(D) आंध्र प्रदेश

77. प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश के अंतर्गत केंद्र ने किस अधिनियम का प्रयोग किया?

(A) विद्युत अधिनियम, 2003
(B) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
(C) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
(D) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

78. MoSPI द्वारा जारी नई GDP श्रृंखला में आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया गया है:

(A) 2021-22
(B) 2023-24
(C) 2020-21
(D) 2022-23

79. कोकिंग कोयले को एक महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज के रूप में MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के किस भाग में जोड़ा गया है?

(A) भाग B
(B) भाग A
(C) भाग D
(D) भाग C

80. स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, और इस तिथि को किस वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया:

(A) 2020
(B) 2022
(C) 2018
(D) 2024

81. स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS 1.0) का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है?

(A) नाबार्ड
(B) SIDBI
(C) एक्जिम बैंक
(D) IDBI

82. भारत-न्यूज़ीलैंड FTA के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने युवा भारतीयों को वर्किंग हॉलिडे वीज़ा प्रदान किया जाता है?

(A) 1,000
(B) 5,000
(C) 500
(D) 2,000

83. बजट में घोषित समर्पित दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक गलियारे (कॉरिडोर) राज्यों के किस समूह में विकसित किए जाने हैं?

(A) झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम
(B) महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु
(C) ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
(D) गुजरात, राजस्थान, केरल और कर्नाटक

84. कोयला एक्सचेंज नियम 2026 के अंतर्गत कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिसंबर 2025 में किस प्राधिकरण को नामित किया गया?

(A) कोयला नियंत्रक संगठन
(B) SEBI
(C) विद्युत मंत्रालय
(D) कोल इंडिया लिमिटेड

85. सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एवं विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकास योजना, सेमीकॉन 2.0, का वित्तीय परिव्यय कितना है?

(A) ₹76,000 करोड़
(B) ₹50,000 करोड़
(C) ₹10,000 करोड़
(D) ₹1,27,500 करोड़

86. लखपति दीदी पहल 2023 में किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी?

(A) PMEGP
(B) DAY-NRLM
(C) स्टैंड-अप इंडिया
(D) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

87. भारत का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र किस बंदरगाह पर शुरू किया गया है?

(A) मुंद्रा बंदरगाह
(B) दीनदयाल बंदरगाह, कांडला
(C) पारादीप बंदरगाह
(D) कोच्चि बंदरगाह

88. भव्य-रसायन (BHAVYA-Rasayan) योजना के अंतर्गत, राज्य के न्यूनतम ₹500 करोड़ के अंशदान की शर्त पर, केंद्र प्रति रसायन पार्क अधिकतम कितनी राशि देता है?

(A) ₹500 करोड़
(B) ₹1,500 करोड़
(C) ₹1,000 करोड़
(D) ₹2,000 करोड़

89. भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र, जिसके लिए DoT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, कहाँ स्थापित किया जाना है:

(A) नोएडा
(B) ग्वालियर
(C) श्रीपेरुंबुदूर
(D) हैदराबाद

90. RBI द्वारा 2025-26 में स्वर्ण का प्रत्यावर्तन कितने टन था, जिसके परिणामस्वरूप उसका 77 प्रतिशत स्वर्ण घरेलू स्तर पर रखा गया है?

(A) 103.68
(B) 107.21
(C) 168.06
(D) 880.52

91. स्टार्टअप की मान्यता और फंड ऑफ फंड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी इकाई को 10 वर्ष तक स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जाती है यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका टर्नओवर ₹200 करोड़ से अधिक नहीं हुआ है।
2. डीप-टेक स्टार्टअप को ₹300 करोड़ की टर्नओवर सीमा के साथ 20 वर्ष के लिए मान्यता दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

92. निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पहला संस्करण 2020 में प्रकाशित हुआ था।
2. इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 5 श्रेणियाँ हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

93. नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का 84 संकेतकों पर मूल्यांकन करता है।
2. संकेतकों को 10 स्तंभों के अंतर्गत समूहित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

94. WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2022 में 11वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था।
2. यह अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन के लिए सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

95. नई IIP और WPI श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IIP का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित कर 2018-19 कर दिया गया है।
2. IIP की टोकरी 1,042 से घटाकर 839 उत्पादों की कर दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

96. वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना 2004 में वित्तीय आसूचना प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने वाली केंद्रीय एजेंसी के रूप में की गई थी।
2. यह वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद को सीधे रिपोर्ट करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

97. परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (VRRR) नीलामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. VRRR के अंतर्गत बैंक अपनी अधिशेष निधि RBI के पास एक निश्चित दर पर रखते हैं।
2. इनका उपयोग बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

98. CAG की राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 2023-24 में घटकर 21.34 प्रतिशत रह गई।
2. 2023-24 में सभी 28 राज्यों में राजस्व अधिशेष था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

99. पॉलिमर बैंकनोटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इन्हें ₹10 और ₹20 के मूल्यवर्ग के लिए प्रस्तावित किया गया है।
2. इनकी निर्माण लागत कागजी नोटों से कम होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

100. प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी पिछले छह माह की औसत आपूर्ति का 100% प्राप्त करने वाली प्राथमिकता श्रेणी नहीं है?

(A) CNG
(B) घरेलू PNG
(C) उर्वरक संयंत्र
(D) घरेलू LPG उत्पादन और पाइपलाइन की आवश्यकताएँ

101. निम्नलिखित पर्यटन योजनाओं का उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए:

A. स्वदेश दर्शन 1. तीर्थ स्थलों का उन्नयन
B. प्रसाद (PRASHAD) 2. विषयगत, सतत गंतव्य
C. SASCI 3. 40 प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र

(A) A-2, B-1, C-3
(B) A-1, B-2, C-3
(C) A-2, B-3, C-1
(D) A-3, B-1, C-2

102. निम्नलिखित में से कौन-सा उन क्षेत्रों में शामिल नहीं है जिनके लिए नई WPI श्रृंखला में सेवा PPI शुरू किया गया है?

(A) दूरसंचार
(B) कृषि
(C) बीमा
(D) बैंकिंग

103. रिलीफ (RELIEF) निर्यात योजना के अंतर्गत निम्नलिखित का मिलान कीजिए:

A. घटक 1 1. ₹159 करोड़

B. घटक 2 2. ₹56 करोड़

C. योजना का कुल परिव्यय 3. ₹497 करोड़

(A) A-2, B-1, C-3

(B) A-1, B-2, C-3

(C) A-3, B-1, C-2

(D) A-2, B-3, C-1

104. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत-न्यूज़ीलैंड FTA से लाभान्वित होने वाले सूचीबद्ध क्षेत्रों में शामिल नहीं है?

(A) परिधान

(B) रत्न एवं आभूषण

(C) जूते-चप्पल

(D) डेयरी उत्पाद

105. PM E-DRIVE के संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

(A) ई-तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी 31 जुलाई 2026 तक उपलब्ध

(B) कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़

(C) ई-तिपहिया वाहनों के लिए ₹2.5 लाख की मूल्य सीमा

(D) ई-दोपहिया वाहनों के लिए ₹1.5 लाख की मूल्य सीमा

106. वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक (GFCI) 2026 के 40वें संस्करण में भारत का कौन-सा केंद्र सर्वोच्च रैंक पर है?

(A) मुंबई

(B) गिफ्ट सिटी

(C) नई दिल्ली

(D) बेंगलुरु

107. कथन:

1. GFCI का प्रकाशन चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर Z/Yen पार्टनर्स द्वारा किया जाता है।

2. GFCI 2026 में सिंगापुर तीसरे और हांगकांग चौथे स्थान पर रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

108. IMF के विश्व आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2026 के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी है?

(A) 6.5%

(B) 6.8%

(C) 7.0%

(D) 7.4%

109. कथन:

1. वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक UNDP और OPHI द्वारा जारी किया जाता है।

2. 2026 के अद्यतन में, 2010 के बाद पहली बार वैश्विक स्तर पर बहुआयामी निर्धनता बढ़ी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

110. वैश्विक MPI में जीवन स्तर आयाम को कितने संकेतकों द्वारा मापा जाता है?

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 10

111. हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है?

(A) मध्यम रूप से स्वतंत्र

(B) अधिकांशतः स्वतंत्र

(C) अधिकांशतः अस्वतंत्र

(D) दमित

112. कथन:

1. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का FDI अंतर्वाह बढ़कर 81.04 अरब डॉलर हो गया।

2. राज्यों में इक्विटी अंतर्वाह का सबसे अधिक हिस्सा कर्नाटक को प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

113. संशोधित ढाँचे (2026 का प्रेस नोट 2) के अंतर्गत, भू-सीमा साझा करने वाले देश का कोई निवेशक, जिसका गैर-नियंत्रणकारी लाभार्थी स्वामित्व किस सीमा तक है, स्वचालित मार्ग का उपयोग कर सकता है?

(A) 5 प्रतिशत

(B) 10 प्रतिशत

(C) 26 प्रतिशत

(D) 49 प्रतिशत

114. 2026-27 के लिए सभी खरीफ फसलों में किस फसल का MSP सबसे अधिक है?

(A) कपास
(B) रामतिल
(C) तिल
(D) अरहर

115. कथन:

1. MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (A2+FL) के कम से कम 1.5 गुना पर निर्धारित किया जाता है।
2. 2026-27 की खरीफ फसलों में बाजरे में लागत से अधिक अनुमानित मार्जिन सबसे अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

116. तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2025-26 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना है?

(A) 357.732 मिलियन टन
(B) 366.120 मिलियन टन
(C) 376.563 मिलियन टन
(D) 386.500 मिलियन टन

117. SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर (IMR) कितनी है?

(A) 18
(B) 24
(C) 29
(D) 39

118. कथन:

1. आयकर अधिनियम, 2025 निर्धारण वर्ष और पूर्व वर्ष की अवधारणाओं को एकल 'कर वर्ष' से प्रतिस्थापित करता है।
2. फॉर्म 130, TDS प्रमाणपत्र के रूप में फॉर्म 16 का स्थान लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

119. अक्टूबर 2026 में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% से बढ़ाकर किस स्तर पर किया?

(A) 5.40%
(B) 5.50%
(C) 5.75%
(D) 6.00%

अध्याय 4: पर्यावरण

120. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 किस तिथि से पूर्णतः लागू होंगे?

(A) 1 जनवरी 2026
(B) 1 अप्रैल 2026
(C) 1 अक्टूबर 2026
(D) 2 अक्टूबर 2026

121. भारत का 101वाँ रामसर स्थल घोषित ग्लॉ झील किस राज्य में कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है?

(A) असम
(B) नगालैंड
(C) अरुणाचल प्रदेश
(D) मेघालय

122. पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में कौन-सा देश शीर्ष पर रहा?

(A) एस्टोनिया
(B) डेनमार्क
(C) फिनलैंड
(D) लक्ज़मबर्ग

123. भारत के पहले दो भूतापीय कुएँ किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में चालू किए गए?

(A) हिमाचल प्रदेश
(B) उत्तराखंड
(C) सिक्किम
(D) लद्दाख

124. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जो भारत का एकमात्र त्रि-राज्यीय नदी संरक्षित क्षेत्र है, किन राज्यों में फैला है?

(A) राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश
(B) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
(C) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार
(D) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान

125. भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के अंतर्गत PRAMAAN प्रमाणपत्रों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है?

(A) भारतीय वन सर्वेक्षण
(B) भारतीय वन्यजीव संस्थान
(C) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
(D) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद

126. भारत के अद्यतन NDC (2031-2035) के अंतर्गत 2005 के स्तर से 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता घटाने का लक्ष्य कितना है?

(A) 47%
(B) 35%
(C) 52%
(D) 60%

127. कांडला स्थित दीनदयाल पत्तन पर बनाए जा रहे भारत के पहले हरित मेथनॉल संयंत्र में किस कच्चे माल का उपयोग होगा?

(A) लैंटाना कैमारा
(B) जलकुंभी
(C) पार्थेनियम
(D) प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा

128. MNRE की तैरती सौर क्षमता आकलन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, कौन-सा राज्य 16.28 गीगावाट की क्षमता के साथ अग्रणी है?

(A) मध्य प्रदेश
(B) महाराष्ट्र
(C) कर्नाटक
(D) गुजरात

129. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका प्रशासन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है।
2. विद्युत क्षेत्र इसके उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों में शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

130. गंगा के बाढ़ मैदानों के संशोधित ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नया ढाँचा 2016 के आदेश के निर्माण-मुक्त क्षेत्र के सामान्य प्रतिबंध को बनाए रखता है।
2. सक्रिय बाढ़ मैदान में अस्थायी संरचनाओं के लिए सीमित छूट के साथ निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

131. EIA अधिसूचना, 2006 में संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक स्थायी प्राधिकरण SEIAA के कार्य अपने हाथ में लेता है।
2. SEIAA और SEAC का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

132. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर-सांविधिक निकाय है।
2. इसकी स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38Y के अंतर्गत की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

133. NCR के लिए प्रस्तावित पराली जलाने संबंधी नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध भू-राजस्व अभिलेखों में 15 महीने के लिए लाल प्रविष्टि प्रस्तावित है।
2. 2 से 5 एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर जुर्माना ₹30,000 है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

134. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए:

सूची-I (अभिसमय/प्रोटोकॉल) सूची-II (लागू होने का वर्ष)

A. स्टॉकहोम अभिसमय 1. 2017
B. मिनामाता अभिसमय 2. 2004
C. नागोया प्रोटोकॉल 3. 2014

सही उत्तर चुनिए:

(A) A-1, B-2, C-3
(B) A-2, B-3, C-1
(C) A-2, B-1, C-3
(D) A-3, B-1, C-2

135. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025 के अंतर्गत जोड़े गए चार नए क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से कौन-सा एक नहीं था?

(A) पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ
(B) पेट्रोरसायन
(C) वस्त्र
(D) सीमेंट

136. पश्चिमी घाट के लिए प्रस्तावित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रतिबंधित नहीं है?

(A) कृषि
(B) नया खनन और उत्खनन
(C) ताप विद्युत संयंत्र
(D) नए लाल-श्रेणी के उद्योग

137. पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक ढाँचे के तीन नीतिगत उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन-सा एक नहीं है?

(A) पर्यावरणीय स्वास्थ्य
(B) पारितंत्र जीवंतता
(C) संसाधन दक्षता
(D) जलवायु परिवर्तन

अध्याय 5: भूगोल

138. सिंधु जल संधि को स्थगित रखे जाने के बाद स्वीकृत पहली नई परियोजना सावलकोट जलविद्युत परियोजना (1,856 मेगावाट) किस नदी पर स्थित है?

(A) झेलम
(B) चिनाब
(C) रावी
(D) ब्यास

139. जम्मू और कश्मीर में तुलबुल नौवहन परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है?

(A) किशनगंगा बैराज
(B) बगलिहार बैराज
(C) वूलर बैराज
(D) सलाल बैराज

140. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत INCOIS की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1995
(B) 2004
(C) 2007
(D) 1999

141. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, जिसकी गहराई लगभग 13 मीटर है?

(A) मानसबल झील
(B) वुलर झील
(C) डल झील
(D) नगीन झील

142. प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध किस नदी पर स्थित है?

(A) गिरी
(B) यमुना
(C) टोंस
(D) अगलर

143. जापान का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन-सा है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित एकमात्र जापानी क्षेत्र भी है?

(A) इतुरुप
(B) ओकिनोटोरी द्वीप
(C) मिनामिटोरीशिमा
(D) योनागुनी

144. शिपकी ला, जहाँ अगस्त 2026 में चीन के साथ सीमा व्यापार पुनः शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?

(A) लाहौल-स्पीति
(B) चंबा
(C) कुल्लू
(D) किन्नौर

145. ग्रेट निकोबार मेगा-अवसंरचना परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इसकी पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखा।
2. यह परियोजना लिटिल अंडमान द्वीप पर स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

146. किशाऊ बाँध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 236 मीटर ऊँचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी बाँध है।
2. केंद्र जल घटक की लागत का 90% केंद्रीय सहायता के रूप में देगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

147. मानसून विराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) सामान्यतः अल नीनो के प्रभाव को संतुलित कर देता है।
2. अल नीनो वॉकर परिसंचरण को सुदृढ़ करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

148. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. थ्वाइट्स ग्लेशियर पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है।
2. विश्व ग्लेशियर दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

149. सिंधु जल संधि को स्थगित रखे जाने के बाद स्वीकृत चिनाब जलविद्युत परियोजनाओं में से निम्नलिखित में से कौन-सी परियोजना नहीं है?

(A) सावलकोट
(B) किरथाई-II
(C) दुलहस्ती-II
(D) तुलबुल

150. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म असुमेलित है?

(A) पलामू बाघ अभयारण्य - झारखंड
(B) पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान - कर्नाटक
(C) पाखल वन्यजीव अभयारण्य - तेलंगाना
(D) भद्रा बाघ अभयारण्य - कर्नाटक

151. निम्नलिखित में से कौन-सा जलडमरूमध्य उन जलाशयों के साथ सही सुमेलित है जिन्हें वह जोड़ता है?

(A) होर्मुज़ - लाल सागर और अदन की खाड़ी
(B) डार्डानेल्स - काला सागर और आज़ोव सागर
(C) बाब-अल-मंदब - लाल सागर और अदन की खाड़ी
(D) केर्च - एजियन सागर और मरमरा सागर

अध्याय 6: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

152. चंद्रयान-4 का प्रस्तावित लैंडिंग क्षेत्र, मॉन्स मूटन, किस व्यक्ति के नाम पर है?

(A) कैथरीन जॉनसन, नासा की भौतिक विज्ञानी
(B) विक्रम साराभाई, भारतीय भौतिक विज्ञानी
(C) कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री
(D) मेल्बा रॉय मूटन, नासा की गणितज्ञ

153. DRDO द्वारा ओडिशा तट के पास परीक्षण की गई प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है?

(A) 150-500 किमी मारक क्षमता वाली कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल
(B) 400 किमी मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
(C) 1,500 किमी मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक जहाज-रोधी क्रूज़ मिसाइल
(D) 80-110 किमी मारक क्षमता वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल

154. स्क्रैमजेट इंजन उड़ान परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत किन देशों के समूह के बाद चौथा देश बना?

(A) अमेरिका, रूस और फ्रांस
(B) अमेरिका, रूस और चीन
(C) अमेरिका, चीन और जापान
(D) रूस, चीन और इज़राइल

155. LIGO-इंडिया, जिसके निर्माण का अनुबंध L&T को मिला, किस जिले में स्थित है?

(A) हानले, लद्दाख
(B) कोडईकनाल, तमिलनाडु
(C) हिंगोली, महाराष्ट्र
(D) उदयपुर, राजस्थान

156. बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला पहला राज्य कौन-सा बना?

(A) कर्नाटक
(B) तमिलनाडु
(C) गुजरात
(D) केरल

157. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा:

(A) ₹38,424 करोड़
(B) ₹23,622 करोड़
(C) ₹21,071 करोड़
(D) ₹1.51 लाख करोड़

158. प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसने पहली क्रांतिकता प्राप्त की, कहाँ स्थित है:

(A) तारापुर, महाराष्ट्र
(B) कलपक्कम, तमिलनाडु
(C) कुडनकुलम, तमिलनाडु
(D) नरोरा, उत्तर प्रदेश

159. कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोड़ने वाला मिशन सेहत संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया?

(A) ICMR और DBT
(B) ICAR और नीति आयोग
(C) ICMR और ICAR
(D) AIIMS और ICMR

160. मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए डिजिटल मंच JANANI का पूर्ण रूप क्या है?

(A) Joint Action for Neonatal and Natal Infant Care (नवजात और प्रसवकालीन शिशु देखभाल के लिए संयुक्त कार्रवाई)
(B) Journey of Adolescent, Natal and Neonatal Immunisation Care (किशोर, प्रसवकालीन और नवजात टीकाकरण देखभाल की यात्रा)
(C) Janani Antenatal and Neonatal Information (जननी प्रसवपूर्व और नवजात सूचना)
(D) Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care (प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और नवजात एकीकृत देखभाल की यात्रा)

161. भारत में स्वीकृत पहला डेंगू टीका क्यूडेंगा किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है?

(A) जर्मनी की टाकेडा जीएमबीएच

(B) सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

(C) भारत बायोटेक

(D) सनोफी पाश्चर

162. आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत भारत 2023 में कौन-सा क्रम वाला हस्ताक्षरकर्ता बना?

(A) 20वाँ

(B) 27वाँ

(C) 35वाँ

(D) 70वाँ

163. DRDO द्वारा कुशा लंबी दूरी की SAM का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया?

(A) श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश

(B) पोखरण, राजस्थान

(C) ओडिशा के तट पर स्थित ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप

(D) कार निकोबार द्वीप

164. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा प्राथमिकता दिए गए चार स्तंभों में से एक नहीं है?

(A) क्वांटम संचार

(B) क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी

(C) क्वांटम सामग्री और उपकरण

(D) क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग

165. SIPRI ईयरबुक 2026 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा अनुमान सही नहीं है?

(A) पाकिस्तान के पास लगभग 220 वारहेड हैं

(B) भारत के पास लगभग 190 वारहेड हैं

(C) चीन के पास लगभग 620 वारहेड हैं

(D) जनवरी 2026 में विश्व में लगभग 12,187 वारहेड थे

166. निम्नलिखित में से कौन-सा पोत GRSE, कोलकाता द्वारा निर्मित नहीं है?

(A) आईएनएस दुनागिरि

(B) आईएनएस महेंद्रगिरि

(C) आईएनएस संशोधक

(D) आईएनएस अग्रे

167. अभ्यास का मिलान साझेदार देश से कीजिए:

A. खंजर

B. धर्म गार्जियन

C. वज्र प्रहार

1. संयुक्त राज्य अमेरिका

2. जापान

3. किर्गिस्तान

(A) A-2, B-3, C-1

(B) A-1, B-2, C-3

(C) A-3, B-2, C-1

(D) A-3, B-1, C-2

168. DRDO प्रणाली का मिलान उसके विवरण से कीजिए:

A. तारा

B. SFDR

C. प्रलय

D. नेत्र

1. अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल

2. AEW&C प्रणाली

3. वायु-श्वसन ठोस ईंधन युक्त नलिकायुक्त रैमजेट प्रणोदन

4. ग्लाइड किट जो अनिर्देशित बमों को सटीक-निर्देशित बनाती है

(A) A-3, B-4, C-2, D-1

(B) A-4, B-1, C-3, D-2

(C) A-1, B-3, C-4, D-2

(D) A-4, B-3, C-1, D-2

169. भारत के रक्षा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. iDEX अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था।

2. रक्षा में 100 प्रतिशत तक FDI की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

170. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2023 में ₹6,003.65 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

2. क्वांटम संचार के लिए थीमैटिक हब IIT दिल्ली में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

171. एनीमिया मुक्त भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2018 में शुरू किया गया था।
2. संशोधित रणनीति 6x6x6 से बढ़कर 7x7x7 हो गई है, जिसमें कम वज़न वाले नवजात शिशुओं को सातवें समूह के रूप में जोड़ा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

172. DRC और युगांडा में इबोला प्रकोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के कारण होता है, जिसके लिए एक स्वीकृत टीका उपलब्ध है।
2. PHEIC की घोषणा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के अंतर्गत की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

173. गगन (GAGAN) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे ISRO और DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया था।
2. इसका उपयोग करके उपग्रह-आधारित लैंडिंग अप्रोच का भारत में पहला संचालन दिल्ली हवाई अड्डे पर किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

174. भारत में AI-निर्मित कृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कॉपीराइट कार्यालय ने कहा है कि AI प्रणाली को विधिक लेखक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
2. ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डी.बी. मोदक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी कृति का नवीन होना आवश्यक नहीं है, परंतु उसमें न्यूनतम रचनात्मकता होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

175. आईएनएस अरिधमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत की तीसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है।
2. आईएनएस अरिहंत को 2009 में लॉन्च किया गया था और उसने 2018 में अपना पहला निवारक गश्त पूरा किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

अध्याय 7: संस्कृति एवं पर्यटन

176. महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर पहली बार किस वर्ष आक्रमण किया था?

(A) 1026 ई.
(B) 1297 ई.
(C) 1394 ई.
(D) 1706 ई.

177. संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि, जिसने 2025 में 100 वर्ष पूरे किए, किसके द्वारा विकसित की गई थी?

(A) जुगल किशोर शुक्ल
(B) पिंगली वेंकैया
(C) पंडित रघुनाथ मुर्मू
(D) दयाराम साहनी

178. सिंधु घाटी सभ्यता का कौन-सा स्थल सबसे पश्चिमी है?

(A) सुरकोटदा
(B) लोथल
(C) कालीबंगन
(D) सुतकागेन डोर

179. केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का 2025 से 2031 के लिए परिव्यय कितना है?

(A) ₹291.66 करोड़
(B) ₹491.66 करोड़
(C) ₹691.66 करोड़
(D) ₹891.66 करोड़

180. हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड की स्मृति में मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 30 अप्रैल
(B) 30 मई
(C) 30 जून
(D) 30 जुलाई

181. कुडवोलै गुप्त मतदान प्रणाली का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है?

(A) ऐहोल अभिलेख
(B) जूनागढ़ अभिलेख
(C) उत्तरमेरूर अभिलेख
(D) मस्की अभिलेख

182. डोगरी के लिए पुनर्जीवित की जा रही लिपि नमे डोगरा अक्खर किस लिपि का संशोधित रूप है?

(A) टाकरी
(B) ब्राह्मी
(C) खरोष्ठी
(D) फ़ारसी

183. पिपरहवा अवशेषों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये अवशेष 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा एक स्तूप की खुदाई करते समय खोजे गए थे।
2. पिपरहवा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

184. भारत में भौगोलिक संकेतकों (GI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. GI का नियमन वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा होता है।
2. GI पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है और नवीकरणीय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

185. प्राचीन अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना रविकीर्ति ने की थी।
2. ऐहोल अभिलेख में नर्मदा तट पर पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

186. सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हड़प्पा की खुदाई आर.डी. बनर्जी ने 1921 में की थी।
2. कालीबंगन हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

187. सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल अपने उत्खननकर्ता/खोजकर्ता के साथ सही सुमेलित नहीं है?

(A) हड़प्पा - दयाराम साहनी
(B) मोहनजोदड़ो - आर.डी. बनर्जी
(C) लोथल - एस.आर. राव
(D) धोलावीरा - जे.पी. जोशी

188. निम्नलिखित में से कौन-सा GI उत्पाद अपने राज्य के साथ सही सुमेलित नहीं है?

(A) पोंडूरु खादी - केरल
(B) पीलीभीत बांसुरी - उत्तर प्रदेश
(C) मूगा रेशम - असम
(D) सेलम साबूदाना - तमिलनाडु

189. निम्नलिखित में से कौन-सी शैलकृत गुफा अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है?

(A) बाघ - धार, मध्य प्रदेश
(B) उंडावल्ली - गुंटूर, आंध्र प्रदेश
(C) जोगीमारा - खुर्दा, ओडिशा
(D) पांडवलेणी - नासिक, महाराष्ट्र

अध्याय 8: खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व, पुस्तकें एवं रिपोर्ट

190. किस देश ने लगातार आठवीं बार 89 अंक के साथ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया?

(A) डेनमार्क
(B) फिनलैंड
(C) सिंगापुर
(D) न्यूज़ीलैंड

191. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी?

(A) 85वीं
(B) 96वीं
(C) 88वीं
(D) 91वीं

192. पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितने पद्म भूषण पुरस्कार शामिल थे?

(A) 13
(B) 5
(C) 19
(D) 113

193. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ नहीं हैं?

(A) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

(B) बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996)

(C) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ

(D) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ

194. ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसने जीता?

(A) नवतेज सरना

(B) रामकुमार मुखोपाध्याय

(C) आर. वैरामुथु

(D) ममता कालिया

195. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत निःशुल्क विशेषज्ञ प्रसवपूर्व देखभाल प्रत्येक माह की किस तारीख को प्रदान की जाती है?

(A) पहली

(B) 5वीं

(C) 15वीं

(D) 9वीं

196. एनएफएचएस-6 के लिए कौन-सा संस्थान नोडल एजेंसी था?

(A) अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई

(B) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

(C) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, दिल्ली

(D) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई

197. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली की रैंक क्या है, जो भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ है?

(A) 134वीं

(B) 118वीं

(C) 170वीं

(D) 101वीं

198. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के पहले भारतीय उपाध्यक्ष कौन बने?

(A) नीरू चड्ढा

(B) बिमल पटेल

(C) विवेक अग्रवाल

(D) राजीव घई

199. त्रि-सेवा महिला परिक्रमण अभियान समुद्र प्रदक्षिणा के दल ने किस पोत का उपयोग किया?

(A) आईएनएस तारिणी

(B) आईएनएसवी म्हादेई

(C) आईएएसवी सागर

(D) आईएएसवी त्रिवेणी

200. निम्नलिखित में से कौन-सा शांतिकाल का वीरता पुरस्कार नहीं है?

(A) परमवीर चक्र

(B) अशोक चक्र

(C) कीर्ति चक्र

(D) शौर्य चक्र

201. रिपोर्ट का मिलान उसे प्रकाशित करने वाली संस्था से कीजिए:

A. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स

B. एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026

C. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर

D. वर्ल्ड इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026

1. विश्व बैंक

2. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

3. अंकटाड (UNCTAD)

4. वाइपो (WIPO) और लुइस बिज़नेस स्कूल

(A) A-2, B-1, C-3, D-4

(B) A-1, B-2, C-3, D-4

(C) A-1, B-3, C-2, D-4

(D) A-3, B-2, C-1, D-4

202. ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से हटाए गए खेलों में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं था?

(A) बैडमिंटन

(B) हॉकी

(C) मुक्केबाजी

(D) कुश्ती

203. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 के विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(A) टॉमी कोह - सिंगापुर

(B) बो क्यी - म्यांमार

(C) रुना खान - फ्रेंडशिप बांग्लादेश की संस्थापक

(D) रुना खान - म्यांमार

204. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. परख (PARAKH) एनसीईआरटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्थापित किया गया।

2. एआईएसएचई (AISHE) सभी संस्थानों से अनिवार्य, आधिकारिक रूप से सत्यापित आँकड़े एकत्र करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

205. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई थी।

2. ज्ञानपीठ पुरस्कार में ₹11 लाख और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

206. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वी-डेम रिपोर्ट गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की जाती है।
2. निर्वाचन लोकतंत्र सूचकांक पर भारत 179 देशों में 106वें स्थान पर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

207. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2024 में भारत में जेलों की अधिभोग दर सबसे अधिक झारखंड में थी।
2. 2024 में विचाराधीन कैदी कुल कैदियों का लगभग एक-चौथाई थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

208. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
2. यह प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस कवर प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

209. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की शुरुआत 2010 में हुई।
2. राजनीतिक सशक्तीकरण इसके द्वारा मापे जाने वाले चार उप-सूचकांकों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

210. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसने जुलाई 2026 में मॉरीशस को अपना 111वाँ सदस्य बनाया, का मुख्यालय कहाँ है?

(A) लंदन
(B) दुबई
(C) मुंबई
(D) सिंगापुर

211. 2026 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे ने 13वीं बार 'एयरपोर्ट ऑफ द ईयर' का पुरस्कार जीता?

(A) दोहा हमद
(B) टोक्यो हानेदा
(C) सिंगापुर चांगी
(D) इंचियोन

212. 98वें अकादमी पुरस्कार (2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता।
2. जेसी बकले ने 'हैमनेट' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

213. 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन-सी थी, जिसके निर्देशक नीरज घेवन हैं?

(A) होमबाउंड
(B) सिनर्स
(C) हैमनेट
(D) सेंटिमेंटल वैल्यू

214. 2026 में एतिहाद एयरवेज़ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. इसे एयरलाइनरेटिंग्स.कॉम द्वारा विश्व की सबसे सुरक्षित पूर्ण-सेवा एयरलाइन घोषित किया गया।
2. यह इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पहली खाड़ी देशों की एयरलाइन थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

215. 22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख बने; इस समय उनके कितने दिन हुए थे?

(A) 4,399
(B) 6,250
(C) 8,931
(D) 9,500

216. दिसंबर 2025 में ओमान द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को निम्नलिखित में से कौन-सा विदेशी सम्मान प्रदान किया गया?

(A) ऑर्डर ऑफ ओमान (प्रथम श्रेणी)
(B) ग्रेट ऑनर निशान
(C) नेसेट पदक
(D) बिंतांग अदिपुर्णा

217. फीफा विश्व कप 2026 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह तीन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहला विश्व कप था।
2. इसमें 48 टीमें और 104 मैच शामिल थे।
3. अर्जेंटीना ने फाइनल में स्पेन को हराकर खिताब जीता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

218. फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल किसने जीता?

(A) किलियन एम्बाप्पे
(B) रोड्रि
(C) पाउ क्यूबार्सी
(D) उनाई सिमोन

219. किलियन एम्बाप्पे लगातार दो विश्व कपों में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। ये कौन-से वर्ष थे?

(A) 2018 और 2022
(B) 2018 और 2026
(C) 2022 और 2026
(D) 2014 और 2018

220. 20वें एशियाई खेल (2026) आइची-नागोया में आयोजित हुए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. नागोया, टोक्यो और हिरोशिमा के बाद इन खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा जापानी शहर है।
2. भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

221. 2026 में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों में पुरुष एकल किसने जीता?

(A) कार्लोस अल्कारेज
(B) यानिक सिनर
(C) अलेक्जेंडर ज्वेरेव
(D) नोवाक जोकोविच

222. किस केन्याई एथलीट ने 2026 लंदन मैराथन 1:59:30 में जीती, जिसे नए विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया?

(A) सेबेस्टियन साबे
(B) जॉन कोरिर
(C) अमोस किप्रूतो
(D) जैकब किप्लिमो

223. महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह ढाका, बांग्लादेश में आयोजित हुआ।
2. भारत ने अपना दूसरा खिताब जीता, जिसमें चीनी ताइपे उपविजेता रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

अध्याय 9: उत्तर प्रदेश विशेष

224. लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग और शहरी अग्नि सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बीआईएस ने राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 को राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 से प्रतिस्थापित कर दिया।
2. अग्निशमन सेवाएँ बारहवीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

225. पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत जाँच का अधिकार समुचित प्राधिकारी के पास है?

(A) धारा 17
(B) धारा 28
(C) धारा 4
(D) धारा 23

226. सारनाथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यहाँ मिला अशोक का सिंह स्तंभशीर्ष भारत का राष्ट्रीय चिह्न है।
2. सारनाथ कला शैली गुप्त काल में चुनार के पीले बलुआ पत्थर का उपयोग करके फली-फूली।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

227. अग्निशमन सेवाएँ बारहवीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

(A) अनुच्छेद 243G
(B) अनुच्छेद 243W
(C) अनुच्छेद 243P
(D) अनुच्छेद 243ZD

228. निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है?

(A) कुशीनगर
(B) फतेहपुर सीकरी
(C) आगरा का किला
(D) ताजमहल

229. विश्व धरोहर समिति का 48वाँ सत्र, जिसने सारनाथ को अंकित किया, कहाँ आयोजित हुआ था?

(A) पेरिस, फ्रांस
(B) नई दिल्ली, भारत
(C) बुसान, दक्षिण कोरिया
(D) बॉन, जर्मनी

230. बुद्ध के जीवन की घटनाओं का उनके स्थानों से मिलान कीजिए:

A. जन्म
B. ज्ञान प्राप्ति
C. प्रथम उपदेश

सूची II:
1. सारनाथ
2. लुंबिनी
3. बोधगया
4. कुशीनगर

(A) A-3, B-2, C-1
(B) A-2, B-1, C-3
(C) A-2, B-3, C-1
(D) A-4, B-3, C-1

231. लखनऊ में उद्घाटित भारत का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग किस प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य कर रहा है?

(A) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (वायु)
(B) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
(C) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(D) चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (थल सेना)

232. पटना पक्षी अभयारण्य और छारी-ढांड के जुड़ने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए?

(A) 96
(B) 97
(C) 98
(D) 99

233. बुलंदशहर मामले से आए पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पुलिस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की स्वतंत्र रूप से जाँच कर सकती है।
2. मजिस्ट्रेट केवल पुलिस आरोप-पत्र पर संज्ञान ले सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

234. राप्ती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह घाघरा की दाएँ तट की सहायक नदी है।
2. इसका प्राचीन नाम इरावती था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

235. दहेज से संबंधित अपराधों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में थे, उसके बाद बिहार और कर्नाटक का स्थान था।
2. वर्ष 2023 में दहेज से संबंधित अपराधों में 14 प्रतिशत की कमी आई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

236. रामसर स्थलों का उनके जिलों से मिलान कीजिए:

A. पटना पक्षी अभयारण्य
B. शेखा झील

C. सुरहा ताल

सूची II:

1. अलीगढ़
2. एटा
3. बलिया
4. बाँदा

(A) A-1, B-2, C-3
(B) A-2, B-3, C-1
(C) A-3, B-1, C-2
(D) A-2, B-1, C-3

237. सुरहा ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह गंगा के विसर्पण से बनी एक गोखुर झील है।
2. यह मध्य एशियाई उड़ान पथ पर प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन आश्रय स्थल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

238. मामलों का उनके निर्णयों से मिलान कीजिए:

A. राजबीर बनाम हरियाणा राज्य (2010)
B. अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)
C. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग (2025)

सूची II:

1. 498-ए के मामलों में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगाई
2. दहेज मृत्यु के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ने का निर्देश दिया
3. प्रशिक्षित दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया
4. अभियुक्तों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देश दिया

(A) A-1, B-2, C-3
(B) A-2, B-3, C-1
(C) A-2, B-1, C-3
(D) A-3, B-1, C-2

239. सांसद क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रत्येक सांसद प्रति वर्ष ₹5 करोड़ के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है।
2. मनोनीत सांसद केवल अपने गृह राज्य के भीतर ही कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

240. किस निकाय ने बाँदा में कालिंजर किले के आसपास की पहाड़ियों को राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित किया?

(A) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
(B) राष्ट्रीय हरित अधिकरण
(C) भारतीय वन्यजीव संस्थान
(D) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

241. अभियुक्त के बचाव पर संवैधानिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 14 में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है।
2. कोई व्यक्तिगत अधिवक्ता मामला लेने से इनकार कर सकता है, किंतु बार एसोसिएशन सामूहिक रूप से अपने सदस्यों को किसी अभियुक्त की ओर से पेश होने से रोक नहीं सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

242. सारनाथ के अंकन के बाद भारत में कितनी विश्व धरोहर संपत्तियाँ हैं?

(A) 43
(B) 44
(C) 46
(D) 45

243. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार देता है?

(A) अनुच्छेद 21
(B) अनुच्छेद 14
(C) अनुच्छेद 39A
(D) अनुच्छेद 22(1)

244. सारनाथ के अंकन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे मानदंड (i) और (ii) के अंतर्गत अंकित किया गया।

2. नामांकन 1998 में प्रस्तुत किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

245. रानी अवंती बाई लोधी, जिनकी प्रतिमा का लखनऊ में अनावरण किया गया, किस राज्य की रानी थीं?
(A) झाँसी
(B) रामगढ़
(C) गढ़ा
(D) मंडला

246. नमो भारत क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह रेल-आधारित यात्री परिवहन प्रणाली है, जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।
2. इसे एनसीआरटीसी द्वारा लागू किया जाता है, जो केंद्र तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का संयुक्त उद्यम है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

247. किस स्थल को भारत का 100वाँ रामसर स्थल घोषित किया गया?
(A) सुरहा ताल स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार
(B) शेखा झील पक्षी अभयारण्य
(C) पटना पक्षी विहार
(D) छारी-ढांड आर्द्रभूमि रिज़र्व

248. निम्नलिखित में से कौन-सा अंकन में शामिल सारनाथ के पुरातात्विक अवशेषों का भाग नहीं है?
(A) धमेख स्तूप
(B) नीलकंठ मंदिर
(C) धर्मराजिका स्तूप
(D) मूलगंधकुटी विहार

249. निम्नलिखित में से कौन-सा छारी-ढांड की आवासी प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध पक्षी नहीं है?
(A) कॉम्ब डक (नकटा)
(B) डालमेशियन पेलिकन
(C) ओरिएंटल डार्टर (दरियाई सर्पग्रीव)
(D) ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क (काली गर्दन वाला सारस)

250. नमो भारत क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली को कौन-सी एजेंसी लागू करती है?
(A) रेल विकास निगम लिमिटेड
(B) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
(C) दिल्ली मेट्रो रेल निगम
(D) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन

251. सुरहा ताल को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं?
(A) 11
(B) 13
(C) 12
(D) 14

252. उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन-सा है, जो एटा जिले में स्थित है?
(A) शेखा झील पक्षी अभयारण्य
(B) जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार
(C) कालिंजर पक्षी अभयारण्य
(D) पटना पक्षी विहार

253. सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किन मानदंडों के अंतर्गत अंकित किया गया?
(A) मानदंड (i) और (iv)
(B) मानदंड (ii) और (v)
(C) मानदंड (iii) और (vi)
(D) मानदंड (iv) और (vi)

254. दिल्ली-मेरठ नमो भारत गलियारा यात्रा समय को घटाकर लगभग कितने मिनट कर देता है?
(A) 60 मिनट
(B) 30 मिनट
(C) 90 मिनट
(D) 120 मिनट

255. MPLADS योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
(A) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
(B) वित्त मंत्रालय
(C) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(D) संसदीय कार्य मंत्रालय

उत्तर कुंजी

1–C 2–B 3–D 4–B 5–A 6–D 7–B 8–A 9–C 10–A 11–C 12–B 13–C 14–A 15–C 16–B 17–A 18–D 19–C 20–A 21–B 22–B 23–D 24–D 25–A 26–D 27–D 28–C 29–A 30–C 31–B 32–C 33–A 34–C 35–C 36–B 37–B 38–B 39–C 40–C 41–B 42–C 43–A 44–B 45–C 46–D 47–A 48–C 49–D 50–B 51–C 52–A 53–C 54–A 55–B 56–C 57–D 58–D 59–D 60–C 61–B 62–B 63–B 64–A 65–B 66–C 67–A 68–A 69–C 70–C 71–C 72–B 73–C 74–C 75–A 76–D 77–D 78–D 79–C 80–B 81–B 82–A 83–C 84–A 85–D 86–B 87–B 88–C 89–B 90–C

91–C 92–A 93–A 94–B 95–D 96–C 97–D 98–D 99–A 100–C 101–A 102–B 103–A 104–D 105–A 106–B 107–A 108–C
109–C 110–C 111–C 112–A 113–B 114–C 115–A 116–C
117–B 118–C 119–B 120–B 121–C 122–A 123–D 124–B
125–C 126–A 127–D 128–B 129–A 130–B 131–C 132–D
133–A 134–C 135–D 136–A 137–C 138–B 139–C 140–D
141–A 142–C 143–B 144–D 145–A 146–C 147–A 148–D
149–D 150–B 151–C 152–D 153–A 154–B 155–C 156–D
157–A 158–B 159–C 160–D 161–A 162–B 163–C 164–D
165–A 166–B 167–C 168–D 169–A 170–A 171–C 172–B
173–D 174–B 175–C 176–A 177–C 178–D 179–B 180–B
181–C 182–A 183–A 184–C 185–B 186–D 187–D 188–A
189–C 190–A 191–D 192–A 193–B 194–C 195–D 196–A
197–B 198–C 199–D 200–A 201–B 202–C 203–D 204–A
205–B 206–C 207–D 208–C 209–B 210–B 211–C 212–C
213–A 214–C 215–C 216–A 217–B 218–B 219–C 220–A
221–C 222–A 223–C 224–C 225–A 226–C 227–B 228–A
229–C 230–C 231–D 232–C 233–D 234–B 235–A 236–D
237–B 238–C 239–A 240–D 241–B 242–D 243–D 244–D
245–B 246–C 247–A 248–B 249–A 250–B 251–B 252–D
253–C 254–A 255–A

ForumPCS